

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

#∘ 21]

मई बिल्ली, शनिवार, मई 21, 1977/वैशाख 31, 1899

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21, 1977/VAISAKHA 31, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II-- खण्ड 3-- उप-खण्ड (ii)

PART II -- Section 3-Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई विल्ली, 5 मई, 1977

का जा 1485 — ने द्रीय सरकार, विदेशी घिभदाय (विनियमन) श्रिधिन्यम, 1976 (1976 का 49) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को ऐसे प्राधिकरण के रूप में विनिद्धिट करती हैं जो उस प्रधिनियम के प्रधीन दण्डनीय किसी प्रपराध का श्रन्वेषण कर सकता है।

[सं० [I/21022/2/77-एफ० सी० झार० ए०-I] आर० के० वर्षरा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th May, 1977

S.O. 1485.—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), the Central Government hereby specifies the Delhi Special Police Establishment as the authority which may investigate any offence punishable under that Act.

[No. II/21022/2/77-FCRA-I]

R. K. WADEHRA. Director

(वित्त मंत्रालप)

(राजस्य ग्रीर वैक्ति विभाग)

(राजस्य पक्ष)

नई विल्ली, 2 मार्च, 1977

माय-कर

का० आ० 1486.—सर्वेसाधारण की जानकारी के लिए श्रिधसूजित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, श्रर्थात्, सिजय, विज्ञान श्रीर प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्निविद्यत संगठन की श्रायकर श्रिधिनयम, 1961 की श्रारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए, श्रन्य प्राकृतिक या श्रनुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र मे निम्निविद्यत शर्तों पर श्रनुमोदित किया है, श्रथान्:—

- (1) यह कि झावेर भाई पटेल अनुमन्धान केन्द्र, मुम्बई, प्राक्कृतिक और अनुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगा।
- (2) जक्त केन्द्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रपने वैज्ञानिक धनु-सक्षान सम्बन्धी किया कलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 प्रप्रैल, तक ऐसे प्रकृषों में प्रस्तुत करेगा जी इस प्रयोजन के लिए प्रक्षिकिषत किए जाए ग्रीर उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

सावेर भाई पटेल अनुसन्धान केन्द्र, सुम्बई।

यह प्रधिसूचना 1 दिसम्बर, 1976 से तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी ।

[सं० 1675/फा॰ सं० 203/189/76—माई० टी॰ ए॰ **[**[]]

जे॰ पी॰ शर्मा, उप सन्तिक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

(Revenue Wing)

New Delhi, the 2nd March, 1977

INCOME-TAX

- S.O. 1486.—It is hereby notified for general information that the association mentioned below has been approved by the Secretary, Department of science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions:—
 - (i) That the Jhaverbhai Patel Research Central, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences.
 - (ii) That the said Centre will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year by 30th April, in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose.

ASSOCIATION

Jhaverbhai Patel Research Centre, Bombay.

This notification will be effective for a period of three years with effect from 1st December, 1976.

[No. 1675/F. No. 203/189/76-I.T.A. II] J. P. SHARMA, Dy. Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई विल्ली, 19 मार्च, 1977

ग्राय-कर

का आ 1487.— मर्वनाधारण की जानकारी के लिए यह मधि-सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बीर्ड ने भाय-कर मधिनियम, 1961 की धारा 35व की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए मनुमोदित किया है।

संस्वा

मैसर्स केल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, सुम्बई।
यह प्रनुमोदन 17 सितम्बर, 1975 से प्रभावी है।
[सं० 1679/फा० से० 203/121/76-प्रा०का० प्र-II]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 19th March, 1977

INCOMF-TAX

S.O. 1487.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause (a) of sub-section (2) of section 35-D of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

M/s, Kiell (India) Private Ltd., Bombay.

The approval takes effect from 17th September, 1975.

[No. 1679/F. No. 203/121/76-ITA,II]

कार आर 1488. मर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रधि-सूचित किया जाता है कि निम्निलिखत संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्राय-कर प्रधिनियस, 1961 की धारा 35थ की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए धनुमोदित किया है।

संस्था

जिक केमिकल इंजीनियर्स प्राहवेट लिमिटेड, मुम्बर्ड। यह भनुमोदन 5 फरवरी, 1976 से प्रभावी है।

[स॰ 1680/फा॰ स॰ 203/18/76-ग्रा॰ का॰ ग्र-II]

जे० पी० शर्मा, सचिव

S.O. 1488.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause (a) of sub-section (2) of Section 35-D of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Knik Chemical Engineers Pvt. Ltd., Bombay.

The approval takes effect from 5th February, 1976.

[No. 1680/F. No. 203/18/76-11 A. II]

J. P. SHARMA, Secy.

राजस्व और वैं िकग विभाग

(बैंकिंग पका)

नई दिल्ली, 14 सम्तूबर, 1976

का० गा० 1489— जुलाई, 1975 से 30 जून 1976 तक के वर्ष के लिये रिजर्व बैंक धाफ इण्डिया के काम-काज धीर भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति भीर प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट ।

भारतीय रिजर्व बैंक ऐस्ट, 1934 (1934 का 2) की धारा 53 की उप-धारा (2) के अनुमार केन्द्रीय निर्वेशक बोर्ड ने, भारत सरकार को 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के काम-काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति पर वाषिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्भुत की जाती है :---

1:--अर्थ-व्यवस्था--एक अध्ययन : 1975-76

प्रस्ताबनाः समग्र मृत्याकन

वर्ष 1974-75 एक ऐसे वर्ष के रूप मे स्मरण किया जाएगा जब ग्रर्थ-व्यवस्था में पुनः सामान्य स्थिति लायी गयी । पिछले दो वर्षों में ग्रर्थ-व्यवस्था को भ्रमामान्य रूप से मुद्रास्फीति की उच्च दरों की गोचनीय स्थिति से गुजरना पड़ा था । इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1975-76 को एक ऐसे वर्ष के रूप में स्थीकार किया जा सकता है जब ग्रर्थ ब्यवस्था को पूनः भ्रपने सामान्य विकास पथ पर पहुचना संभव हो सका था। 1975-76 में इस प्रकार सामान्य विकास की जो स्थिति पुनः लायी गयी वह केवल 5.5 प्रतिशत के मासपास की प्रनुसानित वृद्धि माम्र की ग्रोतक नही है हालांकि उक्त वृद्धि निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय स्थिति है। वास्तव में भौद्योगिक उत्पादन के हाल ही के भाकडो से यह विवित हुआ है कि 1975-76 में भौद्योगिक विकास की वास्तविक दर प्रत्यानित दर से जन्मतर रही है ; भनः भ्रयं व्यवस्था के विकास की समग्र दर 5.5 प्रतिशत से थोड़ी बहुत उच्चतम ही होगी । समग्र वृद्धि दर के भ्रलावा 1975-76 में ऐसी तीन निशेषताएं पामी गयी जिनके कारण बीच में पायी गयी मुद्रास्फीति की मभूतपूर्व दरों के पत्रवात् अर्थ ब्यवस्था में पुन: सामान्य विकास संभव हो सका । उक्त विशेषताएं इस प्रकार हैं : मूरुय में स्थायिता, देशी बजन और निवेश की दरों में उल्लेखनीय युद्धि तथा इसके परिणामस्वरूप सणक्त निवेशी भुगतान स्थिति का निर्माण ।

2. मूल्य पृद्धि का भवरोध 1975-76 की उल्लेखनीय उपलक्षिध है। 1975-76 में न केंबल मूल्य वृद्धि का भवरोध किया गया, बल्कि मूल्यों में 6.0 प्रतिणत की वास्तविक गिरावट भी हुई। $(^1)$ सारे विश्व में प्राय. मुद्रास्फीति की उच्च दरे विद्यमान रही हैं । ग्रतः उक्त उपलब्धि कोई सामान्य बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रारक्षिक ग्रनुमानो से यह संकेश मिलता है कि वेशी बचत ग्रौर कुल निवेश की दरें जहाँ 1974-75 में कमणः 13.1 प्रतिशत भीर 14.8 प्रतिशत थी बहाँ 1975-76 में बढ़कर कमश: 14.5 प्रतिशत और 16.0 प्रतिशत हो गयी । यस्युतः चौथी योजना के प्रारंभ के पश्चात् बचत भीर निवेश की उच्चतम दरें रही है। तीसरी बात यह है कि विदेशी क्यापार के क्षेत्र में दूसरे वर्ष भी काफी माला में घाटा विद्यमान रहने के बावजूद समग्र भुगनान की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार पाया गया । देश की प्रारक्षित बिदेशी मुद्रा निधियों मे ग्रभूतपूर्व वृद्धि हुई । इसका प्रमुख कारण प्रदृश्य लेखों में पासा गया सुधार था । वास्तव में कुछ ऐसे सकेन उपलब्ध है जिनसे यह विदित होता है कि दीर्घकालीन भूगतान संतुलन की सभावनाएं बढ़ गयी है । कुल मिलाकर ये सारी विशेषनाएं इस बात की द्योतक है कि 1975-76 मे एक ऐसी प्रर्थ ध्यवस्था का निर्माण हुआ है जिसरो पांचनी योजना के गोष वर्षों मे विकास को बनाये रखने के लिए सणक्त ग्राधार उपलब्ध हो सकता है।

3. 1975-76 की धर्य व्यवस्था का मूल्यांकन धर्य व्यवस्था के प्रबंध में हुए विशिष्ट धनुभव का उल्लेख किये बिना धधूरा होगा । 1975 के मध्य में धांतरिक धापानकाल की घोषणा और नये धार्षिक कार्यकम के कार्यान्वयन से मामान्यतः धार्षिक प्रशासन में मुधार घाया धौर विशेष ममयबद्ध कार्यकमों का कार्यान्वयन हुआ। इससे धर्ष व्यवस्था का काफी ध्रधिक विकास हुआ है।

 सबसे पहले यह स्मरण होगा कि 1971-72 से ही प्रर्थ व्यवस्था का सामान्य विकास पथ विचलित हो गया था । इसका प्रमुख कारण यह था कि 1971-72 फ्रीर 1972-73 के दो वर्षों में कृषि क्षेत्र को गंभीर प्राघात पहुचा था । इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक मुद्रा-म्फीति हुई ग्रौर भारत के निर्यात-ग्रायात मूल्यांक में नाटकीय रूप से ह्यास की स्थित उत्पन्न हो गयी । श्रतः परवर्ती वर्ष में देण के भीतर मुद्रास्फीति के बढ़ते हुए इन दबावों को समाप्त करने ग्रीर विदेशी भुगतान समस्याम्रो के म्रनुरूप व्यवस्थाएं करने का कार्य प्रत्यावश्यक हो गया । झतः विकास की निर्धारित दरो तक पहुंचने की झावश्यकता का महत्य कम करना ही पड़ा। विकास की प्रक्रिया में इस प्रकार जो बाधा उपस्थित हुई उसका परिणाम यह या कि चौथी योजना भवधि के दौरान वार्थिक शिकास दर श्रीसतन केवल 3,3 प्रतिशत तक पहुंच सकी । पांचनी योजना के पहले वर्ष प्रथात् 1974-75 में भी नास्तविक विकास दर केवल 0.2 प्रतिशत थी । इसके विपरीत 1975-76 के दौरान भनुमानित वृद्धि 5.5 प्रनिशत से मधिक हो गयी । कम से कम पाचनी याजना के दूसरे वर्ष में न केवल विकास की निर्धारित दर तक बल्कि उससे आगे बढ़ना भी मभव हुआ है । मूल्य स्थायिता के नातावरण में सामान्य विकास का पुनः बनाये रखने की दृष्टि से 1975-76 को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है।

5. क्षेत्रीय दुष्टि से देखने पर 1975-76 में हुई बुद्धि भाफी श्रममान थी ; कृषि क्षेत्र में जहां 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां भौद्योगिक क्षेत्र मे लगभग 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।(2) कृषि क्षेत्र की ध्रपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि दर से यह मागंका उत्पन्न हो सकती है कि 1975-76 में कृषि की परंपरागत रूप से प्रभावित करने वाले ग्राकस्मिक तस्बो में समग्र वृद्धि कही घतिरंजित तो नही हुई है। यद्यपि मौसमी कारणों से कृषि क्षेत्र की विकास प्रवृति निण्चित रूप से प्रभावित होती है फिर भी ऐसे संकेत भी उपलब्ध हैं कि 1975-76 में झाकस्मिक तस्बो से भिन्न निवेश प्रधान विकास घटक काफी महत्वपूर्ण रहा । 1975-76 में मौसमी परिस्थितियां काफी ग्रनुकुल थी । यह इस बात से स्पष्ट है कि कृषि में काम ब्रानेवाले उर्वरक, बिजली ब्रौर पानी जैसी मूलभूप बस्तुचो में पर्याप्त वृद्धि हुई । यह कहना भी ग्रधिक उपयुक्त होगा कि अपेक्षाकृत न्यूनतर भौद्योगिक विकास के कारण समग्र विकास बहुत कम हो गया है। यह इस कारण हुआ कि यद्यपि कोयले, बिजली, लोहे बौर इस्पास, सीमेंट, नाइट्रोजनीय उर्वरकों भ्रांदि के उद्योग जैसे कोड़ क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में 10 प्रतिशत से प्रधिक बृद्धि हुई फिर भी कपड़ों, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुम्रो, चाय म्रादि के उद्योगों में वास्तव में गिरावट ग्रायी । हालांकि मूल वस्तुग्रों, विशेषकर विजली ग्रीर कज्चे माल की कमियों के कारण श्रीधोगिक विकास में कोई बाधा नहीं पड़ी, फिर भी देशी फ्रीर जिदेशों को त्रांकी मार्गमें उत्पन्न कमी के कारण कसिपम उप-क्षेत्र प्रतिकृत रूप से प्रभावित होने लगे ; क्योंकि कुछ-उप-क्षेत्रों में पुत्रीगत उपकरणों भीर प्रबंध के प्राधुनिकीकरण की समस्याएं काफी महत्त्वपूर्ण होने लगी।

6 विशुद्ध रूप से मूल्य की स्थायिता का विश्लेषण करने पर ग्रह स्पष्ट होता है कि चाहे मूल्यों के स्पर की सुलता श्रलग-श्रलग श्रंको के श्राधार पर श्रथवा मासिक श्रीमतों के श्राधार पर की जाये, सामान्य प्रशृति गिरावट की श्रोप ही थी। उदाहरण के लिए जून 1975 के श्रत श्रौर जून 1976 के श्रत के बीच में मूल्यों में 3.0 प्रतिकात की गिरावट पार्या गयी। इसके विपरीत 1972-73 श्रौर 1973-74 में क्रमणः

⁽¹⁾ जुलाई 1975 जून 1976 के मासिक भीमतों पर भाधारित।

⁽²) 1975 के कैलेंडर वर्ष की विकास वर केवल 3.9 प्रतिणत थी।

21.5 प्रतिशत ग्रीर 27.8 प्रतिशत की भारी बृद्धि तथा 1974-75 में 0.7 प्रतिशत की सामान्यतम वृद्धि पायी गयी थी । यदि मासिक क्रीसतों के स्परो को देखा जाये, तब भी इसी प्रकार की प्रवृति परि-स्रक्षित होती है भर्थात् जहां 1974-75 में उन मे 16.8 प्रतिशत की नास्तिविक बुद्धि हुई थी, वहां 1975-76 (जुलाई—जुन) के दौरान 6.0 मितिमत की गिरावट पायी गयी । मूल्य की स्थिति मे इस प्रकार जो नाटकीय परिवर्तन हुमा, वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि मार्च 1976 के **बीच में** मूरूप स्तर दो वर्ष पहले विद्यमान स्तर तक पहुच गया था । मुख्य स्थिति में जो यह परिवर्तन हुन्ना वह ग्रवश्य ही मूलतः पूर्ति एवं माग के बीच के संसुलन में, विशेष रूप से कृषिजन्य वस्तुष्रों के सदर्भ में पाये गमें सुधार के कारण हुआ। खाधात्मों के उत्पत्म में 1160 लाख मी० टन का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ ग्रौर निलहनो का उत्पादन भी एक नये सिकार कर पहुच गया । किन्तु वस्तुमों की पूर्ति से इस प्रकार जो वृद्धि हुई, केवल उसी से मूल्यो की कमी का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं हो जाता। संपूर्ण स्पष्टीकरण निम्नलिखित तथ्य से प्राप्त किया जा सकता है : पूर्ति की स्विति में एक ग्रीर मांग प्रबधन के लिए निर्दिष्ट मुद्रागन एवं राजकोषीय नीतियों का जारी रखने से भीर दूसरी मोर जमाखोरी भीर बेहिसाकी धन के उपयोग को रोकने के लिए दी गयी प्रशासनिक कार्रवाइयो सं **युधार भा**या ।

🤈 पहले राजकोषीय नीति परविचार कियाजाय । 1975-76 में केन्द्रीय सरकार ग्रीर राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियो के विकास को बढ़ाने हुए मूल्य स्थायिता को बनाये रखने की दिणा मे सशक्त किया गया । वि.तीय साधनों को जुटाने के लिए पिछले वर्षों में किये गये प्रयामों को भौर तीव्र किथा गया । केन्द्रीय सरकार ग्रौर राज्य सरकारो द्वारा विनरित की गयी कुल राशि में 21 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1974-75 में हुई वृद्धि के लगभग बराबर थी ; उन्हें प्राप्त कुल राणियो में अहां इस वर्ष 23.9 प्रतिशत की बृद्धि हुई वहां पिछले वर्ष 19.9 प्रतिभत की वृद्धि हुई थी । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ग्रौर राज्य सरकारो की प्राप्तियों में जा बृद्धि हुई, वह उनके द्वारा ग्रतिरिक्त कर ब्राप्त करने के लिए किए गये प्रयासों, बेहनर कर प्रशासन ग्रीर ग्राय तथा सपत्ति के स्वैच्छिक प्रकटन योजना की सफलता का संचित परिणाम थी । फलस्वरूप संयुक्त बजट घाटे की राणि काफी कम होकर ∡68 करोड़ रुपये (परिगोधित घनुमान) हो गयी जब कि 1974-75 मे उक्त राणि 752 करोड़ रुपये थी । वस्तुनः बाद में उपलब्ध ग्राकड़ों से विवित होता है कि 1975-76 के सयुक्त बाटे की राणि छौर कम होकर 351 करोड़ रुपये हो गयी । केन्द्रीय सकरकार की स्थिति को ग्रासग से देखने पर बजट घाटे की राशि केवल 367 करोड़ रुपये थी जो 490 करोड़ क्ष्यों के परिशोधित मनुमान से कम थी। 1975-76 का बाटा 1974-75 की सुलना में काफी कम था। इस प्रकार बजट घाटेकी मात्रा को सुरक्षित सीमाग्रो के भीतर नियन्नित करना संभव हुन्ना।

8. मुद्रागत घौर ऋण नीति के क्षेत्र में थांड़ा-सा प्रलग दृष्टिकोण अपमान की प्रावण्यकता थी। ऋण नीति का मूलभून मुद्रास्फीनि विरोधी दृष्टिकोण प्रपर्वितित रहा। साथ ही ब्याजदरों के वर्तमान विन्यास, रिजर्ब बैक की नियंत्रित विसीय महायना और महेबाजी के उद्देश्य से स्टाक जमा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये बनाये गये ऋण मंबंधी निर्देशक मिद्धांतों के कार्यान्ययन को भी जारी रखा गया। इसके विपरीन कृषि और भौद्योनिक बस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होने की जो प्रत्याभा थी, उस के कारण इस संदर्भ में थोड़ा-मा लचीला दृष्टिकोण अपनान की प्रावश्यकता थी। यतः 1975-76 की ऋण मीति इस प्रमुख उद्देश्य से प्रेरित थी कि अर्थ व्यवस्था में उच्चतर विकास हो मके, और इसके प्रलावा मुद्रागत नियंत्रण के मूलभूत उपकरणों में कोई प्रधिक बाधा न पष्टे। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित विभिन्न कार्रवाड्यां की गयी वाणिज्य वकों ने भारी मात्रा में खाद्यान्तों की बसूली का विस्तिपण किया, मार्जिन सर्वधी अपेकाणों में खाद्यान्तों प्रावा

धौर स्टाक सबंधी मानवंडों को चयनात्मक रूप से उदार बनाया गया तथा ऋण संबंधी क्याज दरों के लिए उच्चनम सीमा निर्धारित की गर्या । मूल्य स्थायिता को भ्राधान पहुचाये बिना ऋण नीति मे जो लचीलापन लाया जा मका है, उपर्युक्त कार्रवाइयां उसके पर्याप्त प्रमाण है ।

9. इस प्रकार के लचीले दृष्टिकोण का प्रभाव 1975-76 (जुलाई-जून) के दौरान ऋण की प्रवृत्तियों में परिलक्षित होता है। प्रमुख्ति वाणिज्य मैं को द्वारा विये गये ऋण में 2509 करोड़ कपयों की जूदि (28.0 प्रतिशत) हुई जो पिछले वर्ष की उसी प्रविध में हुई 1007 करोड़ कपयों की वृद्धि (14.0 प्रतिशत) की दुगुनी से भ्रधिक थी। इससे स्पष्ट विदित होता है कि ऋण नीति कठोर नहीं थी और उससे लचीलापन लाया गया। यद्यपि खाद्य भीर खाद्येतर क्षेत्रों के ऋण में वृद्धि हुई, फिर भी खाद्य ऋण में हुई 1390 करोड़ कपयों की वृद्धि पिछले वर्ष की अपेका (272 करोड़ कपयें) काफ़ी अधिक थी। उक्त ऋण की वृद्धि कुल ऋण वृद्धि का 55.7 प्रतिशत थी। उक्त ऋण की वृद्धि कुल वर्ष केवल 24.8 प्रतिशत थी। ऋण-जमा अनुपात 25 जून, 1976 को 76.1 प्रतिशत थी। ऋण-जमा अनुपात 25 जून, 1976 को 76.1 प्रतिशत थी। ऋण-जमा अनुपात एक का पहले के 65.1 प्रतिशत की कुलना में स्थ्नतर अर्थात् 61 6 प्रतिशत था।

10. 1975-76 में बकों के ऋण विस्तार की माला का बध्ययम करने समय यह उल्लेख करना अधिक महस्वपूर्ण हो जाता है कि बैका के निजी वित्तीय साधनों में काफी सीत्र वृद्धि पायी गयी । अनुसूचित वाणिज्य बैको की कुल जमाराणियों में 2512 करोड़ रुपयों भणवा 20.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि 1974-75 में उनमें 1788 करोड रुपयों भणवा 16.6 प्रतिणत की बृद्धि हुई थी । सपूर्ण दृष्टि से देखने पर 1975-76 में हुई वृद्धि अब तक हुई मर्वाधिक वृद्धि थी । यथि मांग और मियादी जमाराणियों में वृद्धि हुई फिर भी मीयादी जमाराणियों की वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक थी । 1975-76 में मीयादी जमाराणियों में 1698 करोड़ रुपयों (23.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबिक उनमें पिछले वर्ष 1179 करोड़ रुपयों (19.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । 1975-76 में व्याज की मामान्य उच्च दरों को बनाये रखने का तास्पर्य यह है कि बास्तविक व्याज दरें मूस्यों की गिराबट के संदर्भ में बढ़ गयी हैं । मीयादी जमाराणियों में मसामान्य रूप से जो उच्च वृद्धि हुई वह भायव इसी तथ्य की प्रतिक्रिया के रूप में हुई ।

11. वैंको द्वारा दिये जाने वाले ऋण में भ्रपेक्षाकृत अधिक माल्ला में जो वृद्धि हुई उसका प्रभाव जनता के पास मुदा उपलब्धि में परिलक्षित होता है। 1975-76 (जुलाई--जून) में उक्त मुद्रा उपलब्धि में 1375 करोड़ रुपयो अध्यवा 11.3 प्रतिणत की वृद्धि हुई। वृद्धि की यह माल्ला 1974-75 में हुई 6.4 प्रतिभान की भ्रमेक्षा काफी अधिक थी। यह स्मरण होगा कि मुद्रा उपलम्धिकी वृद्धिकी दरको 1974-75 में थोड़ा सासीमित किया गया। इसका एक विणोष कारण यह था कि म्रांतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ओ राशि निकाली गयी उससे सहायता प्राप्त हुई । इसके संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में चर्चा की गयी थी। ग्रतः मुद्रा उपलब्धि में 1975-76 में हुई। बृद्धि की तुलना 1974-75 के साथ करना उचिन नहीं होगा। यदि इसकी सुलना 1971-72 से 1973-74 तक के सीम वर्षों नक की भवधि के वौरान हुई 15 प्रतिणत की भौसन वार्षिक बुद्धि दर से की जाए तो 1975-76 की वृद्धि दर काफी कम थी । अधिक महत्वपूर्ण बान यह है कि 1975-76 मौर उसके पूर्व वर्षों में मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि के स्वरूप में गुणात्मक परिवर्तन पाया गया । 1975-76 मे बास्तविक राष्ट्रीय झाय में हुई 5.5 प्रतिकात की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा उपलब्धि में उक्त वृद्धि हुई । किन्तु पिछले वर्षों में, सिवाय 1973-74 के ऐसे समय में मुद्रा उपलब्धि में बृद्धि हुई जब राष्ट्रीय ग्राय बिल्क्सल ही ग्रुक्तल थी। एक भ्रौर महत्त्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन इस वृद्धि के कारणभून तस्वो म पाया जाता है। बैकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा ग्रास्तियां धीर वाणिज्य क्षेत्र को बैको हारा दिया जाने वाला ऋण-दो ऐसे महस्वपूर्ण तस्य थे जिनके कारण 1975-76 में मुझा उपलब्धि में बृद्धि हुई । बैकिंग कोत्र की शृद्ध विदेशी मुद्रा ग्रास्तियों में 969 करोड रुपयों की श्रभूतपूर्व वृद्धि पायी गयी । जिस सीमा तक ऐसी ग्रास्तियों को मुद्रा उपलब्धि में स्थायिता लानेबाल तस्वों के रूप में माना जा सकता है उस सीमा तक उपर्यक्त तस्व को मुद्रा उपलब्धि की उन्नतर बृद्धि को रोकते वाले एक महस्त्रपूर्ण बटक के रूप में स्थीकार किया जा सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थित मांग करे तो प्रारक्षित निधयों से मुद्रा उपलब्धि की मान्ना को बढ़ाने के उद्देश्य से राणि निकाली जा सकती है । दूसरी बात यह है कि बैंकों हारा दिये जाने वाले ऋण में हुई वृद्धि की मान्ना 1975-76 में भोक्षाकृत श्रिष्ठक थी । किंतु यह बृद्धि ग्रिधकांगत खाद्य ऋण में पायी गयी । ऋणों में जो वृद्धि हुई उसकी पूर्ति जमाराणियों से श्रिष्ठक वृद्धि होने के कारण रिजर्व बैक से प्राप्त उधारों की श्रेपेक्षा बैक श्रपने ही विसीय साधनों से काफी श्रीष्ठक मान्ना तक कर सके । इसके परिणामस्वरूप इस बदक से जो मुद्रास्फीति संभव थी उसे कुछ हद तक कन कर हिया गया।

- 12 मुद्रा उपलब्धि में हाने नाली वृद्धि के स्वरूप में पाये गये गुणारमक परिवर्तन और पहले ही उल्लिखित मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि 11.6 प्रतिभात की मुद्रागत वृद्धि के बावजूद 1975-76 में मूल्यों में क्यों गिराबट श्रायी।
- 13 1975-76 में पिछले वर्षों के विपरीत श्रर्थव्यवस्था में विवेश व्यापार की जो सलोवजनक स्थिति पायी गयी वह अर्थ-व्यवस्था की अमता के प्रतिमान प्रस्तुत करती है । इस क्षमना के फलस्वरूप देण की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में 881 करोड़ रुपयों (3) की अप्रत्याशित वृद्धि हुई । हालाकि दूसरे वर्ष भी व्यापार क्षेत्र में काफ़ी ग्रधिक मात्रा में घाटा विद्यमान था । 1975-76 में नियत्ति में केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष उनमें 32 प्रतिभात की बुद्धि हुई थी । यद्धपि भायानो में हुई 11 प्रतिशत की वृद्धि भी 1974-75 में हुई 53 प्रतिशत वृद्धि की अप्रेक्षा काफी कम थी, फिर भी 1155 करोड़ रुपयो का व्यापार बाटा 1189 करोड रुपयों के स्तर पर ही प्राय अपरिवर्तित रहा I यद्यपि भूगतान संसुलन के निस्तृत ग्राकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारक्षित निधियाँ प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में प्राप्त चिदेशी सहायता भ्रौर श्रदृश्य लेनदेनों की प्राप्तियो विशेषकर विवेशों से प्राप्त हुई राणियों की बुद्धि के कारण बढ़ गयी । वस्सुतः यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि 1975-76 में प्राप्त विदेणी सहायता में जो बुद्धि हुई वह काफ़ी अधिक मीमा तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कांग्य से न्युन मास्रा में निकाली गयी राशियों में समायोजित हो गयी । फिर भी यह स्पष्ट है कि प्रारक्षित निधियों की क्षमता का बढाने में प्रदृश्य लेनदेनो की प्राप्तियों का मक्रत्वपूर्ण स्थान रहा है । गलत तरीके से बाहर जानेवाली विदेशी मुद्रा को पोक देने में अधिकाणत यह मुधार हा सका है।
- 14. तिदेणी क्षेत्र की एक दूमरी महस्वपूर्ण घटना यह थी कि 25 सिसम्बर 1975 से रुपयें की पीड-स्टिनिंग से असबद्ध कर दिया गया। इस के बाद रुपयें का विदेशी मूल्य भारत के प्रमुख व्यापार माझेदार देशों की मुदाओं के संदर्भ में निर्धारित किया जा रहा है। इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ है कि भारतीय स्पयें का मृत्य स्टिलिंग से किन्त दूसरी मुद्राओं की तुलना में स्थिर हा गया और स्टिलिंग की दृष्टि में रुपयें की क्य-शक्ति बढ़ गयी। इसमें श्रायातित वस्तुओं और मेयाओं के मृत्य में होने वाली वृद्धि रोकी गयी और इस कारण कुछ हद तक मृत्यों में स्थिरता अर सकी।
- 15. श्रंत में श्रर्थ व्यवस्था पर श्रातिरक श्रापात स्थिति तथा बीस सूत्रीय श्राधिक कार्यत्रम के सर्वांगीण प्रभाव का सकेत करना उचित होगा ।

यह प्रभाव निम्नलिखिन बातो में परिलक्षित होता है। श्रीकोणिक क्षेत्र में मौहार्दपूर्ण वासायरण निर्मित हुआ, सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए की जानेवाली जमाखोरी और मृल्यों के क्षेत्र में बेहिसाबी धन के उपयोग में कभी लागी गयी। सामान्य रूप से प्रशासन में श्रीर विशेष रूप से सार्थजिमक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा कर प्रशासन की क्षमता को बढ़ाया गया और श्रंत में विदेशी क्षेत्र में नम्करी विरोधी कार्रवाइयों से प्रारक्षित निधियों की स्थिति मजबूत हुई।

16. आगे के पृष्टों मे क्षेत्रीय विकास, राजकोषीय और मुद्रागत नीतिओं, मूल्या, अचन धीर निवेश की प्रवृत्तियों तथा विदेशी क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा की गयी है। श्रीतम खड मे उपलब्ध संकेशों के श्राक्षार पर 1976-77 में विकास की संभावनाओं का मूल्याकन करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय भाग भीर कृषि एवं भीकोगिक विकास

राष्ट्रीय ग्राय

- 17. केन्द्रीय सास्थिकीय संगठन के प्रश्नित प्राप्त भिक्तान के भनुसार राष्ट्रीय ग्राय (1960-61 के मूल्यों के श्रनुसार) में 1974-75 में 0.2 प्रतिणत की वृद्धि हुई जब कि पूर्व प्राक्तलन के श्रनुसार उक्त वृद्धि 2 0 प्रतिणत की । यह स्थिति 1973-74 में राष्ट्रीय श्राय में हुई 5 0 प्रतिणत की आरी वृद्धि के विपरीत थी । 1974-75 में राष्ट्रीय श्राय में केवल नाममाल की जो वृद्धि हुई उसका कारण यह था कि कृषि केव के शुद्ध देशी उत्पादन में 4.3 प्रतिशत की गिरावट पायी गर्यी ।
- 18 इस सीमान वृद्धि के विपरीत 1975-76 में (1960-61 के मूस्यों के मनुसार) राष्ट्रीय भाय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का भनुमान लगाया गया है। इस प्रकार कम से कम पांचवी योजना के दूसरे वर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाय में निर्धारित माला तक वृद्धि लाना संभव हो सका है। वस्तुन: 1969-70 के बाद यही पहला वर्ष था जब राष्ट्रीय भाय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कृषि उत्पादन

19. 1975-76 में राष्ट्रीय भाग में जो महत्त्वपूर्ण बृद्धि हुई वह प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र में हुई 8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई । कृषि क्षेत्र की अपेक्षाकृत उच्च युद्धि वर से यह आशंका होती है कि कही कृषि को परंपरायत रूप से प्रभावित करने वाले भाकस्मिक तस्को ने 1975-76 में समग्र वृद्धि को ग्रानिरजिल लो नहीं कर दिया है। किल्लु ऐसे संकेत उपलब्ध है कि प्राकस्मिक घटक से भिन्म निवेश प्राधारित वृद्धि का घटक, उवाहरण के लिए उर्वरको धौर पानी के उपयोग के संदर्भ में 1975-76 में काफ़ी उल्लेखनीय था। यह संभव है कि उर्वरको की खपत में पिछले दो वर्षों से अधिक वृद्धि हुई जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे : उर्वरको की पूर्ति में सुधार, उनके मूल्यों में कमी भीर विजली तथा सिचाई की सुविधायों की देहतर उपलब्धि । मूलतः प्रनुकुल मौसर्म। परिस्थितियों से उर्बरकों के मधिक उपयोग में सुविधा हुई । किन्सु इन भ्रमुकूल स्थितियों के यावजूद नाइट्रोजनीय उर्वरकों की खपत की मा**ला** बार्षिक योजना में निर्धारित 25 लाख मी० टन के लक्ष्य से काफ़ी कम भ्रथित् 22 लाख मी० टन के ग्रासपास होने की संभावना है। इसके ग्रालाका उत्तम बीजों ग्रीर कीटनाशक दवाइयो जैसी ग्रन्य मूलभूत वस्तुन्त्रों की पूर्ति में काफ़ी सुधार पाया गया । सारणी 1 में प्रस्तुत किये गये श्रांकड़ों से यह स्पप्ट होता है।

³यह ग्राकडा देण की सकल प्रारक्षित निधियों का द्योतक है जब कि पूर्वो-स्लिखित ग्राकड़ा बैकिंगक्षेत्र की णुद्ध विदेणी मुद्रा ग्रास्तियों का धोलक है।

सारणी 1 : कृषि कार्यकर्मों को प्रगति

कार्यक्रम	इकाई	1971-72	1972-71	1973-74	1974-75	1975-76+	197	G-77+
						लक्ष्य	सभाव्य उपल ब्धि यां	लक्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निम्नलिश्वित के अन्तर्गंस आनेवाला सकल क्षेत्र								
मधिक उपज वाली किस्मे	दस लाख हेफ्टेयर	18 2	22.1	25 9	27 1	30 0	31 0	33 0
पौष्ठ संरक्षण	n	58.0	52.0	63 0	64.0	_	70.0	····
मिट्टी का सरक्षण@	"	1 5	2.1	1.6	0 6	0.8	1.0	0.7
जर्बरको ग्रौर कीटनाशक दवाइयो की खपत नाइट्रोजनीय (एन) (पोषक)	दसलाखामी टन	1.8	1.8	1 8	1 8	2 50	2 15	2.65
फास्फेटिक (पी ² फो ⁵)	n	0 6	0 6	0 7	0.5	0 70	0 47	0 60
पोटमिक (के ⁹ ग्रो)	13	0.3	0 4	0.4	0 3	0.40	0,28	0 35
कीटनाशक दवाइयां	हजार मी०टन	धनु०	धनु०	प्रम् ०	0 47	0.56	0 53	0 60
सिंचाहुग्रा सकल <i>शेव</i>	दम लाख हेक्टेयर	38.5	41 0	43.1	43.8		45 1	47 4
फसल उगायेगये क्षेत्रमे सिचे हुए सकल क्षेत्रकाप्रतिकत		23.5	अनु०	ग्रनु०	25.9		26.5	27.3
मध्याविध/दीर्घाविधि ऋण (प्रत्यक्ष* झौर परोक्ष\$)								
(क) जारी किये गये ऋण जून के श्रन्तमे)	करोड़ रुपये	276.18	415 35	393.87	477.36‡	581.09		
(ख) बकाया ऋण (जून के ब्रन्स मे)	करोड़ रुपये	1231,05	1558 72	1737.93	2041.78	2541 81		

⁺वार्षिक योजना, 1976-77

\$भ्रनुसूचित वाणिष्य बैंको भीर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के।

‡अनितम

क्रोत: (1) कृषि मत्रालय, भारत मरकार, ग्रौर (2) भारतीय उर्वरक सच।

20. खाद्याकों के उत्पादन की स्थिति विशेष रूप में उल्लेखनीय थी। आशा है कि खाद्याका के उत्पादन के सन्दर्भ में 1160 लाख मी० टन(4) का अभूतपूर्व कीतिमान स्थापित होगा जब कि इस वर्ष के लिए 1140 लाख मी० टन का लक्ष्य निर्धारित था। इस प्रकार खाद्याकों के उत्पादन की माला में 1970-71 में स्थापित 1084 लाख मी० टन के कीर्तिमान से 7 प्रतिशत की बुद्धि होगी। हाल ही के वर्षों में चुने हुए पण्यो का जो उत्पादन हुआ उसके आकड़े सारणी 2 में दिए गये हैं। 1975-76 की खरीक फसला के लिए वर्ष और मौसम की स्थितियां अधिक अनुकूल

थी। जिनके कारण खरीफ खाद्याओं के उत्पादन की माला 700-710 लाख मी० टन हो गयी। इस प्रकार उक्त माला 1970-71 में हुए 690 लाख मी० टन के शिखर जन्पादन में प्रधिक थी। वाबल के उत्पादन की माला 1973-74 के मौभम के 140 लाख मी० टन से काफी प्रधिक बहकर 480 लाख मी० टन हा जाने का प्रमुमान है। रबी की बुआई प्रमुक्त मौभमी स्थितियों में शुरू की गयी। उसके लिए जाड़े की वर्षा विलम्ब से हाने के बावजूद लाभदायक सिद्ध हुई। इसके परिणामस्वस्प रबी खाद्याक्षों के उत्पादन की माला 450 लाख मी० टन तक पहुच जाने की भी संभावना है। 280 लाख मी० टन के गेहू का उत्पादन 1971-72 के 264 लाख मी० टन में काफी प्रधिक भीर पिछले वर्ष के उत्पादन में 38 लाख मी० टन प्रधिक है।

[@]इस वर्ष के दौरान अतिरिक्त संरक्षण कार्य

प्र**नु**० = प्रनुपलब्ध

^{*}प्राथमिक कृषि ऋण समितियो, भूमि विकास बैंको ग्रौर ग्रनुसूचित वाणिज्य बैंको के।

⁽⁴⁾ परवर्ती श्राधिकारिक अनुमानो के अनुभार उत्पादन की माला 1180 लाख मी०टन तक पहुचने की सभावना है।

सारणी 2: कृषि उत्पादनधुने हुए प

	इकार्ड	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
1	2	3	4	5	6	7
कुल खाद्यांच	दस लाख मी० टन	105,2	97.0	104.7	101.1	116.0
खरीक खादाल	n	63.0	58,6	67.9	60.3	70.0-71.0
रवी खासास	n	42.2	38.1	36.8	10.8	45.0
वालों से भिन्न ऋनाज	1)	94,1	87.1	91.7	90.7	
चावल	n	43.1	39, 2	44.1	40.3	19.0*
गेहं	"	26.4	24.7	21.8	24.2	28 0*
वाले	D	11.1	9.9	10.0	10,4	
चाचेतर वस्तुएं						
1	दस काख गांठों,					
	प्रति गाठ 170 । कलोग्रा म	7.0	5.7	6.3	7.1	6.70
जृट ग्रीर मेस्ना	वस लाख ग ठिं,					
	प्रति गांठ 180 किलोग्राम	6.8	6.1	7.7	5,8	5.8
तिसहन	य स लाखा मी० टन	8.7	6.9	8 8	8.4	10.6**
मूंगफली	n	6,2	4.1	5.9	5.1	7.0
गन्ना (गुड़ के रूप में)	n	11.6	12.8	14.4	14.3	

^{*}प्रेस रिपोर्टें

21. किन्तु खाखेनर पण्यो की फ्रमलों की स्थिति केवल निलहमों को छोड़कर उननी संतोषजनक नहीं है। व्यापार क्षेत्र के प्राक्कलमों के प्रनुसार 5 प्रमुख निलहनों के उत्पादन की माला 1975-76 में 106 लाख मी० टन ग्रमुमानित है जबकि 1975-76 की वार्षिक योजना में 100 लाख मी० टन का लक्ष्य निर्धारित था। अनुमान है कि मूंगफली का उत्पादन 70 लाख मी० टन होगा जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 36.8 प्रतिशत बृद्धि का क्योतक है। प्रक्रिल भारतीय तृतीय प्राक्कलनों के प्रनुसार कपास उत्पा-दक क्षेत्र 1974-75 के 73.1 लाख हेक्टेयर के ग्रनुमान के विपरीत 1975-76 में 72.8 लाख हेक्टेयर होगा। प्रतिकृत मौसमी स्थितियो के कारण विणेष रूप से महाराष्ट्र में कपास की फ़सल बुरी तरह से प्रभावित प्रतीत होती है। कपास की स्थिति काफ्नी भनिश्चित है क्योंकि उसके उत्पादन के विश्वसनीय प्राक्कलम ग्रम तक उपलब्ध नही हुए है। दिसम्बर 1975 में कपास सलाहकार मण्डल ने उसके उत्पादन की साला को 69 लाख गांठों के भासपास अनुमानित किया, किन्तु जून 1976 में उस ने अपने पूर्व प्राक्कलन को कम कर 66 5 लाख गांठे कर दिया। गैन-मन्कारी प्राक्कलन के प्रनुसार उक्त मात्रा 65 लाख गांठों से 68 लाख गांठी तक होगी। पटमन भौर मेम्ला का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर पर स्थिर रहा। ग्रानुमान है कि उनके उत्पादन की माला 1975-76 में 58,29 लाखा गांठें होगी जबकि 1974-75 में वह 58.33 साख गाटे थी। वस्तुत: 1975-76 का उत्पादन 1969-70 के बाद न्यूनतम होगा। 1975-76 में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र 27 लाख हेक्टेयर था जो 1974-75 की तुलना में 26 लाख हेक्टेयर से थोड़ा बहुन अधिक होगा। परंतु चीनी के उत्पादन के संबंध में यह धनुमान है कि उसकी मात्रा 1974-75 मे स्थित 48 लाख मी० टन से घटकर 43-40 लाख मी० टन होगी।

वसूली, बसूली की नीति ध्रौर सार्वजनिक वितरण

- 22 बीम सुत्रीय ग्राधिक कार्यक्रम में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए भन्यावण्यक वस्तुओं की बसूली में तीम्रता लाने और उनकी विनरण प्रणाली को मुख्यवस्थित करने पर विशेष और दिया गया है। खाद्याक्षों की ससूली की सरकारी नीति इस समग्र ढांचे में बनायी गयी। इसके भनावा इसके वो भीर लक्ष्य भी हैं: भारी मात्रा में समीकरण भंजार तैयार करना ग्रीर ग्राधार मूल्यों द्वारा उत्पादकों के हित की रक्षा करना।
- 23- 1975-76 (नवस्वर-प्रक्तूबर) के विपणन मौसम के दौरान खरीफ खाद्याओं की वसूली की नीति में कोई प्रमुख परिवर्तन नही हुआ। धान की मानक किस्स का वसूली मूख्य पिछले वर्ष के स्तर पर ही प्रति क्थिटल क० 74 रखा गया और वालों में भिन्न दूसरे मोटे ग्रनाओं के मूक्यों की भी यही स्थित रही।
- 24. 1975-76 में की गयी समग्र वसूली के कार्य ग्रीर बाजार में खाद्याशों के श्रागमन की प्रवृक्ति भीर सार्वजनिक विनरण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध खाद्याशों की प्रवृक्ति से समान्यत. खाद्याशों की श्रपेक्षाकृत संतोषजनक स्थित प्रकाण में ग्राती है। यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है कि खाद्याशों की यसूली मूल्य संबंधी सहायता कार्यों के श्रंण के रूप में करनी पड़ी।
- 25. 1975-76 के मौसम के दौरान चानल की ससूली के संबंध में कृषि नृत्य श्रायोग ने 53 लाख भी०टन के लक्ष्य की सिकारिय की थी, किन्तु सरकार ने 46 लाख भी०टन का लक्ष्य निर्धारित किया। बास्तय में श्राय तक 60 लाख मी०टन की बसूली हो जाने से बसूली के लक्ष्य की धूर्ति ध्रपेक्षा से काफी अधिक हो गयी है। मोटे ध्रनाजो के खिए बसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नही किया गया, हालांकि कृषि मूल्य आयोग ने 13 लाख मी०टन सुक्षाया था। मूल्य संबंधी

⁽ळे ६६ सलाहकार मंडल द्वारा दिया गया।

^{**}अधापार क्षेत्र के **धनु**मान ।

सहायता कार्यों के अंश के रूप में अब तक 3 लाख मी०टन के मोटे अनाजो की बसूसी की गयी है।

26. किन्धु चावल के बसूली मूल्य को भूसा निकालने/पिसाई के प्रमु-पातो, सांविधिक प्रभारों की वृद्धि ग्रीर प्रन्य प्रासंगिक खर्जों पर ध्यान देते हुए 1975-76 के मौसम के लिए प्रति क्विटल ६० 115.78-125 से बढ़ाकर ६० 117-127 कर दिया गया। इस वृद्धि के बावजूद चावल की सभी किल्मों ध्रीर मोटे ग्रनाजों का जो निर्गम मूल्य 1 जनवरी 1975 को निरिचत किया गया था उसे मुद्रास्फीति के चटकों को नियंग्नित करने के उट्टेब्स से अपरिवर्तित रहने दिया गया।

27. गेहूं के संबंध में 1975-76 के विपणन मौसम (भ्राप्रैल-मार्च) के लिए बसूली मूल्य को प्रति क्षित्रटल पिछले वर्ष के रु० 105 के स्तरपर क्रनावे रचा गया। यह स्मरण होगा कि गेहूं का बसुली मूल्य 1973-74 में जहा प्रति क्विटल २० 71 से 74 तक (लाल किस्म का देशी गेहं) था अहां 1974-75 में उसे बढ़ाकर रु० 105 कर दिया गया था। इसके भ्रष्टाबा बसूली को प्रधिकतम बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को गेहें की पूर्ति करने के लिए एक प्रोत्साहन बोनस योजना शुरू की गयी जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को असूली कार्य के अनुरूप विभिन्न दरों पर बोनस अवा किया जाएगा। श्रौसन बोनस वर प्रति क्विटल ६० 4.74 **बी ग्रीर इस प्रकार बसूल की गयी राग्नि को प्रमुख रूप से किसानों के** हित के लिए विकास कार्यों में निवेश करने के निमित्त राज्य सरकारें काम में लाएंगी। राज्य सरकारें भपने विवेक के धनुसार किमानों को रियायती दरो पर खेली की कतिषय मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए भी बोनस का उपयोग कर सकती हैं। किल्तु किसानी को काई नकव राशि ग्रवा नहीं की जाएगी। केन्द्रीय भंडार से सार्वजिनिक बितरण के लिए निक ले गये गेहू के निर्गम मूल्य को ६० 125 ही रखा गया।

28. 1975-76 के मौसम के दौरान 1974-75 की गेहूं की फ़सरा से 41 लाख मी०टन भी बसूली का गयी जब कि 1974-75 में 20 लाख मी०टन की बसूनी को गयी थी। {

29. 1976-77 के मौमम (ध्रप्रैल-मार्च) के लिए भी गेहूं के बसूली मूल्य मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रिंग क्विटल के 1.5 के संसूची मूल्य और बोनस योजना को जिसा परिवर्तन के रखा गया है। बसूची का लक्ष्य 52 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है, किन्तु कास्त्रविक समूची मूनिण्यित स्तर से 12 लाख मी० टन घ्रधिक हो गयी है। (5)

30. बाजार में चायल और गहुं की जा मन्त्रा ग्राने लगी बह भी सुधरी हुई पूर्ति की स्थित की बोतक है। बर्तमान निपणन मौसम (1975-76) में चुने हुए बाजारों में पिछले मौसम से काफी प्रधिक मान्ना में बाजल का प्रागमन हुआ। 1975-76 के गेह निपणन मौसम (ग्रिजैल-मार्च) के दौरान चुने हुए 317 बाजारों में 228 लाख मी० टन गेहूं भाषा, जबकि पिछले मौसम में 173 लाख मी० टन गेहूं भाषा था। यह मान्ना 31 8 प्रतिशत की वृद्धि की खोतक है। 1976-77 के गेहूं निपणम मौसम के दौरान भी बाजार में गेहूं के आगमन की प्रवृत्ति में (6) ब्रौर बृद्धि हुई है। इस भवधि में 158 लाख मी० टन का गेहूं बाजार में श्राया, जबकि पिछले मौसम की उसी भवधि में 10 3 लाख मी० टन गेह श्राया था।

31. खाद्याकों की भारी फसल के बावजूद सरकार ने 1975-76 मे ग्रिधिक स्तर पर आयात करने का निश्चय किया ताकि काफ़ी बड़ी माला में समीकरण भंडारों का निर्माण किया जा सके। इस प्रकार के भंडारों का निर्माण मृख्य स्थायिता की बनाए रखने की पूर्विपक्षा है। 1975-76 (जुलाई-जुन) के दौरान 74 लाख मी० टन के खाद्याकों के ग्रायात किये गये, जबकि 1974-75 की उसी भविध में 58 लाख मी० टन के खाद्याओं के भावात किये गये थे।

32. खाखाओं की पूर्ति में जो कमी आयी वह इस बात से भी स्पष्ट होती है कि सार्वजनिक बितरण प्रणाली से प्राप्त खाखाओं की माला में गिराबट धायी। 1975-76 (जुलाई-मई) के दौरान सार्वजनिक जितरण प्रणाली से प्राप्त किये गये खाखाओं का मासिक औमत पिछले वर्ष के 9.2 लाख मी० टन के भौमत से बटकर 7.8 लाख मी० टन हो गया। नवस्वर 1975—मई 1976 के दौरान खाखाओं की कुल खरीवी की माला 47.6 लाख मी० टम थी जबकि पिछले वर्ष की उसी धविध में उक्त माला 65.9 लाख टन थी। कुल खरीदी की माला के माला के सपण्ट सूचक है कि सार्वजनिक बसूली की प्रणाली में जो मांग होती थी वह प्रव बदलकर शहरी क्षेत्रों में खुने बाजार के अयापार के लिए होने लग गयी थी। नगरेतर क्षेत्रों विशेषकर भामीण क्षेत्रों में जो खरीदी होतो है उसमें भी उत्पादन की वृद्धि से छोटे किमानो के पास विद्यमान खाद्याओं के स्टाकों की पूर्ति के कारण गिराबट आगयी है।

33: बाबाओं के अपेकाकुत ग्रधिक आयातो, उच्यतर बसूली धौर सार्वजितक जितरण प्रणाली से बरीदी गयी माता में गिरावट के फलस्बस्प मरकार के पास रहने बाले बाबाओं के स्टाकों में भारी वृद्धि हुई। उक्त स्टाक जहां मई 1975 के अन्त में 44 लाख मी० टन थे वहां मई 1976 के अन्त में क्षकर 144 लाख मी० टन हो गये। इस प्रकार स्टाकों के बढ़ जाने से जुलाई 1976 के अन्त तक लगभग 150 लाख मी० टन के समीकरण भंडार बनाने के सरकारी लक्ष्य की पूर्ति होने में सहायता मिलेगी।

भौद्योगिक उत्पादन

34. 1975 के कैलेडर वर्ष में औद्योगिक क्रेब की स्थिति मिली जुली थी। जहां कोयले, विजली, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट ग्रीर श्रलीह धातू जैसे कोड़ उद्यो^गी में 10 प्रतिशत से ग्रधिक वृद्धि पायी गयी वहां सुनी बस्त्र भीर धार्गे तथा फुछ टिकाऊ उपभोकता बस्तुओं के कतिपय उपक्षेत्रों के प्रत्यादन में बास्तव में गिराबट श्रायी। इसके परिणामस्त्रस्य श्रीद्योगिक क्षेत्र की समग्रवृद्धि दर 4 प्रतिशत से भोड़ी सी श्रिक्षिक थी। यद्यपि समग्र वृद्धिः दर 1974 में हुई केवल 2 2 प्रतिणत की ऋषेक्षा काफी क्राधिक थी फिर भी उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कतिपय उपक्षेत्रों के उत्पादन में यदि गिराबट नहीं श्रायी होती तो समग्र वृद्धि दर बहुत ही प्रधिक होती। श्रीबोगिक क्षेत्र की गोचनीय स्थिति यह थी कि कुछ उपक्षेत्रो पर देशी धीर विदेशी कारणों से भाग में आयी मंदी के कारण प्रतिकृत प्रभाव पड़ता रहा। साथ ही कुछ उपक्षेत्रों में प्ंजीगत उपकरणों धीर पबन्ध तत्र के धार्धानकीकरण की समस्याएं भी उत्पन्न हो गयी थी। इसमे संदेह नही है कि उन प्रवृ-त्तियों की सुधारने के लिए नीति संबंधी कई उपाय प्रारम्भ किये जा जुके हैं; किन्तु इन उपायों का प्रभाव जो गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुकृत रक्षान पर ग्रंणत. ग्राक्षारित होगा, थोडे समय के बाद ही समग्र विकास पर देखा जाएगा।

35. घोद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में मासिक घोसत स्तर में 1975 में (प्राधार वर्ष 1970) 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1974 में उसमें 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1975 के उक्तरार्ध में 5.6 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वह पूर्वार्ध में हुई 2 3 प्रतिशत की तुलना में काफ़ी घाषक थी। मूल रूप में बिजली घोर कोयले, इस्पास घौर सीमेंट जैमी किनप्य महत्वपूर्ण मूलभून बस्तुघो की पूर्ति में काफ़ी सूखार पाया गया। इसके प्रलावा घापातकाल घोर नये प्रथिक कार्यक्रम के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाये गये वर्ड कदमों से 1975 के

^{(&}lt;sup>5</sup>) जून 1976 के प्रन्त तक ।

^{(&}lt;sup>6</sup>) 11 जून 1976 नक।

उल्लंश में श्रीवोगिक विधास में वंजी धार्या। श्रीवोगिक लाइसेसीकरण नीति की उदार बनाया गया ताकि वर्तमाम क्षमता का पूर्ण उपयोग हों श्रीर प्राथमिकता प्राप्त केवों में निजेश को बढाया जाए। गैर-रिहायशी भारतीयों को श्रीबोगिक प्रतिष्टान स्थापित करने के लिए विधिन्न सुविधाएं वी गयी है। उसी प्रकार 1975-76 की निर्योग एवं श्रायान नीति को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि निर्योग प्रधान उद्योगों को दुर्मभ कच्चे माल और मृलभृत बस्तुएं पर्याप्त माला में समय पर उपलब्ध हो सकें। श्रीबोगिक संबंधों में भी उत्लेखनीय मुधार श्राया जिसका यह प्रमाण वा कि जुलाई—विसम्बर 1975 के दौरान जहां बेकार गये श्रम दिनों में 45 लाख की गिरावट श्रायी बहा 1974 की उसी श्रवधि में उनमें 99 लाख गिरावट श्रायी थी।

ರ್ಷ, ಆದ್ಯ ಅರ್ಥ ಚಾರ್ ಅನ್ನಡ ಕರ್

36 सार्वजनिक क्षेत्र के उच्चमी का कार्य विशेष रूप से संतोषजनक रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की भ्रौसन दर राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सिलों को छोडकर समग्र रूप से खप्रैल—विसम्बर, 1975 में 1974 की मुलना में बहुत प्रधिक अर्थात् 15 प्रतिशत श्री।

37 इसके विपरीत सूती बस्कों धौर धामे के अद्योगों तथा जीप, मोटर, नातानुकूलन यज्ञ, रेडियों रिमीनर, बिजली के पंको, सूर्व मेल ध्रादि टिकाऊ उपभोक्ता बस्तुओं के उद्योगों के उत्पादन में उल्लेबनीय शिरावट खायी। इन श्रीखोगिक वस्सुआ जी माग में जो मदी आयी उसके कई कारण थे। उत्तम किस्मों के कपड़ों की मांग की कसी के लिए उच्च मृत्यों के प्रति उपभोक्तायों का बिरोध कारण रहा होगा भीर तियंतिन वस्त्र के मामले में उपके विलरण को दुबंल व्यवस्था महत्वपूर्ण कारण थी। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुयों के मामले में अप्रत्याशित रूप से बहुत प्रधिक मृत्य बढ़ जाने से उनके प्रति उत्पन्न विरोध एक कारण रहा होगा। वहां कई और जुट से बनी हुई बस्तुयों के अवांगों के मामले में उनके निर्यात की मांग से गिरावट भा जाना एक महत्वपूर्ण कारण वा बहां इन उवांगों और कुछ दूसरे उदांगों में निर्यात की मांग में बायी गिरावट का दूसरा कारण स्टाकों का नमायोजन भी हो सकता है। इनमें से बुख उवांगों में मांग को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1975 के अन्त में बुछ कवम उठायें जैसे, निर्माण कार्य पर लगाये गये प्रतिवन्धों में बील, निर्यावस करारे के बितरण की नीति में संशोवन, वर्ड टिकाऊ उपभोक्ता सस्तुमों के मामले में उत्पादन गुरुकों में कमी।

38 उन्होंनों के कुछ उपक्षेत्रों की लिश-फिल विकास वरों की स्नूल विकास वरों की स्नूल विकास वरों की स्नूल विकास वरों की स्नूल विकास वर्ग के प्रांककों से की जा सकती है। 1975 में हुई 3 9 प्रतिणत की समग्र केलीय वृद्धि के बावज्य उत्पाधन में वृद्धि विकास वाले अवोगों का कुल वजन 1974 के 48 जितान से बहकर 1975 में 41 प्रतिणत हो गया। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि जिन अपमोत्का वस्तुओं के उच्चोगों के उत्पादन में वृद्धि होती है उनका कुल बजन में जो श्रंग रहता है वह 1974 के 16 जितान से बहकर 1975 में 7 प्रतिणत हो गया। इनके बिपरीत जिन उक्षोगों के छत्यादन में गिरावट होती है उनका कुल श्रण 19 प्रतिणत से बढ़कर 26 जितान हो गया।

सारणी 3 : बृद्धि धरों के अनुसार चुने हुए उद्योगों का वर्गीकरण

·		मामान्य सूचकांक के बखन के प्रमुसार								.,
वृद्धि दरों का स्वरूप ^{क्ष}	सभी नमूह		मूल उद्योग		पूंजी <i>नम</i> बस्तुझों के उच्चोग		मध्यवर्ती बस्तुची के उस्तोग		उपमोक्सा बस्तुवीं के उचीग	
	1974	1975@	1974	1975@	1974	1975@	1974	1975@	1974	1975@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(अ) गृहिः								N	und ed .g. sq. n2 42	·
1. सामान्यः 5 प्रतिशत से कम	21.7	8 7.04	4 4	3 0.57	0.35	0 35	8 00	3 08	8.44	3.04
2 उल्लेखनीय: 5 प्रतिशत और प्रक्रिक	26 3	34,14	15.59	21.94	1 12	5.18	1.78	2.80	7.90	4.23
उसमें से 10 प्रतिशत श्रीर प्रधिक	, 7 10) 32 76	0.09	21.72	1.12	4.11	0.23	2.71	5.65	4.22
3. वजन (t -2)	48 1	5 41.18	20.51	22.51	1.47	5 53	9 84	5 88	16.34	7 26
(ब्रा) कमी:										
4. सामान्य : 5 प्रतिणत से कम	4 41	12.00	1.97	0 61	1.09	-~	0 09	6.61	1.26	4.78
 उस्लेखनीय: 5 प्रतिभक्त भौर श्रक्तिक उसमे से: 	14 62	13,72	1.31	0 67	6.25	3.28	2.95	0.39	4.11	9.38
10 प्रतिशत भौर अधिक	5 35	7.53	1.31	0 67	2 21	3 18	0 24	0 33	1 5)	3. 35
6. वजान (4 + 5)	19.03	25 72	3.28	1 24	7.34	3 28	3.04	7 00	5 37	14.18
(इ) स्वाधी:		0.29								0.29
कुल बजन (ध्र $+$ धा)	67 19	67 19	23.79	23.79	8.81	8 81	12.88	12.88	21.71	21.71

टिप्पणी . सारजी झलग-झलग उद्योगों के बास्सविक उत्पादन पर श्राक्षारित है, क्योंकि धलग-झलग उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन के सूत्रकांक उत्पादन पर श्राक्षारित है।
* वृद्धि की दरें संबंधित पूर्व वर्ष की तुलमा में उत्पादन में हुई प्रतिकान वृद्धि की खोलक है।

⁽a)धनन्तिम

39 मूल पृंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं धौर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्तियों का मुनिष्चित रूप से विश्लेषण करना सभय नहीं है क्योंकि विभिन्न वर्षों धौर प्रलग-प्रलग उद्योगों के उत्पादन के सुषकांकों के धांकड़े प्रव तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। किन्तु वजन के लिए समायोजित न किये गये वास्तविक उत्पादन के घांधार पर एक स्यूल चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। मूख उद्योगों के वर्ष में सीमेंट, तैयार इस्पात, नाइट्रोजनीय उर्वरक, कास्फेटिक उर्वरक, विजली धौर कोयले

जैसे सभी प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 10 7 प्रतिगत भीर 37.5 प्रतिगत के बीज वृद्धि हुई (सारणी 4)। सल्प्यूरिक भ्रम्ल, कॉस्टिक सोडा भीर सोडा राख जैसी रासायनिक प्रस्तुओं के उत्पादन में केवल सीमान्त वृद्धि हुई। इसके विपरीत इस्पात की ढली वस्तुओं, एल्प्मिनियम चहरों भीर वृत्तों तथा पीतल की चहरों भीर वृत्तों के उत्पादन में गिराबट भायी।

सारणी 4 : चुने हुए उद्योगों के उत्पादन की प्रवृक्तियां--समूहवार

				उत्पादन		घटवढ का		
समूह/ उद्यो ग	वजन	लेखा इकाई	1973	1974	1975@	1973 की तुलना में 1974	1974 की नुत्रना में 1975	
1	2	3	4	5	6	7	8	
मूल उद्योग :								
1. सीमेंट	1.17	हजार मी० टन	15006	14265	16185	-4.9	+13 5	
2. कास्टिक सोद्या	0.32	17	418	428	442	+24	+3 3	
 तैमार द्रस्पात 	3.13	"	4828	4952	5641	+2.6	+13	
 एल्युमिनियम की चहुरें और वृक्त 	0 36	n	5.4	4 5	38	-16.7	-15.	
 नाइट्रोमनीय उर्वरक ('एन' तत्तव युक्त) 	0.87	11	1083	1101	1410	- - 1 . 7	+28	
6. फास्फेटिक उ बं रक (पी2 म्रो5)	0.52	31	338	293	403	-13.3	+37.	
7. बिजली	9 23	लाख किलो बॉट	638559	682120	755168	+6.8	+10	
8. कोयला	6 04	वस लाख मी० टन	80 4	86.9	98 7	+8.1	+13.	
 कच्चा लोहा 	0.76	हजार मी०टन	7341.3	7253.8	8343.3	-1.2	+15.	
जी गत बस्तुओं के उद्योग		*						
कारत बस्युका के उक्कार 1. रेल्बों के भाल डिक्बों	1.07	संख्या हजारों में	12	11	12	-8.3	+9.	
2. मोटर गाड़ियां	2 97	।। अञ्चल क्षित्र च	92	84	70	-8 7	-16	
2. नाटर नाज्या 3. बिजली पावर परिणामिस (यंत्र)	1 48	हजार किलो बाँट	11809		11161	-23.8	+ 24	
 माजला पावर पार्यालक (पल) माज ग्रीर पल्प की मशीनें 	0.08	हुआ र स्थला माट्र लाखा रुपये		9002		+100.0	+ 24 + 95	
4. कागज आर पर्य का समात् 5. बोजल इंजन£	0.08	ला च रापय संख्याएं	450 136025	900 115057	1761 138918	+100.0 -15 4	+ 20	
6. रेस्बे इंजन	1.09	संख्याए संख्याएं	136025	115057	128	-15 4 -4.5	+ 50	
	1.00	Andt."	0.9	0.3	120	-4.0	-1 30	
ह्यवर्ती बस्तुमों के उद्योग	0.22	संख्यादम लाखामे		0.5.5	7. 10	1 - 0		
1. सूचे सेल	033		603	635	543	+5.3	-14.	
2 टायर—मोटर गाड़ियां	1.00	मंख्या हजार में	4414	4736	4884	+7.3	+3.	
3. सूत की कलाई 	6.24	दस हजार कि०मा०	9953	10069	9906	+1 2	- 1	
4. जूट से बनी वस्तुएं	2.71	हजारमी, टन	1037	947	1114	-8 7	+17	
 पेट्रोलियम भीर परिष्करणशालाभ्यों में बनी 		n				1 .		
हुई वस्तुएं	1.62		19123	19397	20182	+1.4	+4	
पन्नोक्ता बस्तुमों के उद्योग								
1. रेडियो रिमीवर	0.97	संख्या हजार मे	1656	2095	1542	+26 5	-26	
2. सामिक्सें	0.36	"	2541	2511	2209	-1 .2	-12	
3. सिगारेट	2.21	सङ्यादस लाखा मे	64450	60541	60064	- 6 1	 ()	
4. वनस्पति	0.68	हजार विवटल	4661	3541	4583	~24.1	+29	
5. सा बु म	0 61	हजार मी०टन	214	213	269	-0 5	+26	
6. वियामलाई	0.26	दस लाख तिलिया	215951	215555	186317	-0 2	-13	
7. बिजली के पंखे	0 24	संख्या हजार में	2261	2336	2091	+3.3	-10	
8. कांच और कांच की चीजें (कांच की चहरें)	0 11	लाख वर्गमी०	141	94	158	-33.3	+68.	
9. ची नी	2.79	हजार मी० टन	3685	4133	4646	+12.2	+12	
10 चाय	2.57	,,,	468	490	481	· [4 . 7	-1.	
11. सूस की बुनाई मिल क्षेत्र	5.34	दम लाख मीटर	4148	4316	4079	+4.1	-5	
12. कागज भीर कागज के गरी	2.17	हजार मी० टन	748	804	813	+7.5	十1.	
(अव्यवारी कागज को छोड़कर)								

[£]बाहुम इंजर्ने भीर भचल इंजर्ने । @भनितम।

- 40 पूजीगत थस्तुम्रों के उद्योगों के वर्ग में रेल-माल डिब्बो, पाथर परिणामिन्नों, मणीनी पूजीं, डीजल इजनों, कागज और परूप की मणीनों भीर रेल इंजनों के उत्पादन में उत्लेखनीय युद्धि हुई। उक्त वृद्धि रेल-माल डिब्बों के उत्पादन में जहां 9.1 प्रतिशत थी बही कागज और परूप की मणीनों के मामलों में 95.7 प्रतिशत थी घगर इस वर्ग में किसी प्रमुख उद्योग के उत्पादन में कमी भ्रायी है तो वह केवल माटर गांडियों (16 7 प्रतिशत) का उद्योग था।
- 41 मध्यवर्ती वस्तुधो के उद्योगों के वर्ग में मृती कताई उद्योग के उत्पादन में गिराबट (1 6 प्रतिशत) धायी। किन्तु जूट में बनी वस्तुधों, परिष्कृत पेट्रोलियम वस्तुधों, मोटर टायरो धौर ट्यूबो तथा मचायत बैटरियों के उत्पादन में वृद्धि हुई।
- 1. उपभोक्ता बरन् उद्याग के बर्ग में रेडियो रिसीबर, सायिकल, सिगरेट, सूती बुनाई, दियासलाई और हरीकेन लालटेन के उत्पादन में बहुत श्रीधक गिराबट आयी। सिल क्षेत्र में सृती बुनाई में 5.5 प्रतियात की गिराबट आयी। क्ष्मके विपरीत वनस्पति, साक्षुन, जुले (चमडेके) और कांच एवं कांच की बनी जीजों तथा कींच की जहरों के उत्पादन में युद्धि हुई। जहां साक्षुन के उत्पादन में 26 3 प्रतियात की वृद्धि हुई बहां कांच और कांच की बनी चीजों के उत्पादन में 68.1 प्रतिशत की वृद्धि तहां कांच ग्रीर कांच की बनी चीजों के उत्पादन में 68.1 प्रतिशत की वृद्धि तहां कांच ग्रीर कांच की बनी चीजों के उत्पादन में 68.1 प्रतिशत की वृद्धि तहां कांच ग्रीर कांच की बनी चीजों के उत्पादन में 68.1

ग्रीद्योगिक विकास की संभावनाएं

4) हाल ही के वर्षों में मूल वस्तुओं विशेष कर कच्चे माल और बिजनी की कमी से श्रीद्योगिक विकास में बाधा पड़ी । श्रधिकांशन इस कमी का भारी माझा में उत्पन्त कृषि फसल धीर देश में बिजली की उपलब्धता में हुई युद्धि के कारण दूर कर दिया गया है। साथ ही कम से कम कुछ उपक्षेत्रो मे **भौद्यो**गिक वस्तुभो के बाजार के श्रपर्याप्त विकास के रूप में एक नयी बाधा उत्पन्न हो रही है। वास्तव में मांग बढ़ाने या मामान्यत. श्रीद्योगिक कार्यकलापो मे पुन मुखार लाने के लिए कई उपाय गुरू किये जा चुके हैं। प्रारम्भ में 1976-77 के योजना परिकाय में 31 4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र का निवेण सामान्यतः निजी क्षेत्र के लिए प्रेरक सिद्ध होता है। अतः यह अनुमान लगाना उचिन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में होने वाली वृद्धि सेग्नर्थ ब्यवस्था के कुल निवेश में व्यापकता ग्राएगी। निजी क्षेत्र के निवेशों को बढ़ाने के लिए किये गये दूसरे उपायो में निम्मलिखिन शामिल है: लाइसेसीकरण पद्धति में सुधार, लाभाग की घोषणा मौर बोनस णेयरो के निर्गम पर लगाये गये प्रतिबन्धों में ढील, उत्पादन मुल्कों में चयनात्मक कटौती, मौलिक श्राय ग्रीर मपत्ति कर में कटौती, निवेण को श्रोत्साहित करने के लिए रियायने और विकास प्रधान भाषान नीति । इस प्रकार निजी क्षेत्र में भारी निवेण के लिए उपयुक्त वाशावरण निर्मित हा गया। इसके प्रकावा मांग की मदी से प्रभावित उद्योगों में पुन. सुधार क्रान के कम से कम दो क्रीर कारण है। 1975-76 में क्रुपि घ्राय में जो भारी वृद्धिः हुई उससे वस्त्रः जैसी कुछ वस्तुम्रा की ग्रामीण माग बढ़ आयेगी। दूसरी बात यह है चृकि विकसित देशों में पायी गयी संदी में थोड़ा मा सुधार होने वाला है ग्रतः भारतीय ग्रीग्रोगिक वस्तुग्री के निर्यात की मांग बढ़ने की संभावना है। वस्तुत. पहले से ही इस बात के सकेत विश्वमान है कि 1976 के पहले चार महीनों में घीडांगिक बृद्धि की गति में लेजी थ्रा चुकी है। जनवरी--श्रप्रैल 1976 के दौरान 1975 की उसी भ्रवधि की भ्रपेक्षा ग्रीद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत यह भी स्वीकार करना होगा कि 1975 में क्रोड़ क्षेत्र के कुछ उद्योगों में जिस दर पर वृद्धि हुई उससे ग्रधिक दर पर 1976 में वृद्धि नहीं हा सकेगी। फिर

भी स्थूल रूप से 1976 में लगभग 6 से 7 प्रतिशत तक की घौद्योगिक वृद्धि की प्राणा करना उचित प्रतीत होता है।

राजकोवीय नीति

44 पिछले वर्ष की तरह मांग प्रबन्धन के कारण राजकोषीय नीति संनोषजनक रही। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने 1975-76 में भाषिक विकास के साथ-साथ मूल्य की स्थिरता को बनाये रखने की दिणा में भपनी नीतियों को सणक्त बनाया। विलीय साधनों को जुटाने और बजट घाटे की माला को कम करने के लिए 1974-75 में गुरू किये गये प्रयन्तों को ध्राय और सपिन की स्वैचिछक प्रकटन योजना की सफलना और कड़ाई में कर प्रणासन का अनुपालन किये जाने से और बल मिला। इन प्रयासों के समन्वित परिणाम के रूप में निवेश ब्यय का बढ़ाना और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के समन्वित बजट बाटे को कम करना संभव दुआ।

बजट घाटा : केन्द्रीय सरकार ग्रौर राज्य सरकारें

45. संघणामित क्षेत्रों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार श्रीर राज्य सरकारों के कुल वितरणों की राणि 1975-76 (परिशोधित श्रनुसात) में 21.0 प्रतिमान की युद्धि हुई जो पिछले वर्ष हुई वृद्धि के लगभग बराबर ही थी। विकासेनर परिज्यय में 1975-76 में 26.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि विकास परिव्यय में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केन्द्रीय सरकार ग्रीर राज्य सरकारों के उच्चतर व्यय के कारण ग्रागे के ग्रनुच्छेदों में श्रमंग से दिए गए है। समन्वित कुल प्राप्तियों में 1975-76 में 23 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उनमें पिछले वर्ष 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1975-76 में प्राप्तियों में जो बृद्धि हुई वह 1974-75 द्यौर 1975-76 के दौरान केन्द्रीय सरकार भ्रौर राज्य सरकारों द्वारा भ्रतिस्वित कर जुटाने के लिए किये गये प्रयासो और ग्राय तथा संपक्ति की स्वैच्छिक प्रकटन की योजना र्का सफलता का समन्वित परिणाम थी। इसके परिणामस्यरूप केन्द्रीय सरकार **ग्र**ौर राज्य **सरकारों के सम**स्वित **बजट** घाटे (") की राणि बहुत कम होकर 468 करोड़ रुपये (परिशोधित ग्रनुमान) रह गयी जबकि 1974-75 में उक्त **राशि 752 क**रोड़ रुपये थी (सारणी 5)। वास्तव में बाद के श्रांकड़ों से विदित होना है कि 1975-76 के समन्त्रित घाटे की राशि बहुत ही कम होकर 351 करोड़ रुपयो तक पहुंच गयी(⁸) ।

⁽⁷⁾ बजट घाटे (——)/म्रिधिमेथ (——) निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया जाता है। (म्र) केन्द्रीय सरकार के लिए——(i) बकाया खजाता बिलो में णुद्ध वृद्धि/कसी भ्रीर (ii) नकवी जमा से निकाली गयी राणि। नकवी जमा में बृद्धि भ्रीर (ग्रा) राज्य सरकारों के लिए राज्य सरकारों के वजटों में दिये गये निम्नलिखित भ्रांकड़े (i) प्रथापाय भ्रप्रिमो भ्रीर भ्रांकर द्वारा विये गये करूण में हुई मुद्ध वृद्धि/कमी, (ii) नकवी जमा में वृद्धि/कमी (iii) राज्य सरकारों द्वारा धपने नकदी जमा निवेश नेख में रखी हुई प्रतिभूतियों की णुद्ध विकय/क्य भ्रीर (iv) प्रारक्षित राजस्व निधियों में रखी हुई प्रतिभृतियों की णुद्ध विकय/क्य भीर (iv) प्रारक्षित राजस्व निधियों में रखी हुई प्रतिभृतियों की मुनाई/प्रतिभृतियों में निषेण।

⁽⁸⁾ उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों में 1975-76 के समित्वित पार्ट की राणि 351 करोड़ रुपये वर्णायी गयी है। उक्त घाटे में केन्द्रीय सरकार के 367 करोड़ रुपयों का बजट घाटा (अर्थात् बकाया खजाना बिलों में णुद्ध वृद्धि और नकदी जमाराणियों में कमी) और राज्य सरकारों का 16 करोड़ रुपयों का अधिशेष (अर्थात् नकदी जमाराणियों में घट-बढ़, खजाना बिल और रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थाप्य अग्निम) गामिल है।

सारणी 5 : केन्द्रीय और राज्य सरकारो की संबुक्त प्राप्तियां और वितरण

(र।णि कराइ रुपयो म)

	1974-75 (लेखे)		1975-76 (बजट प्रनुमान)\$	(प	 ।		1976-77 (बजट म्रनुमान) \$
ਸ ਰੇ	राशि	राणि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/कसी()	राग्नि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशस वृद्धि (-∤-)/कसी(—)	राणि	पिछले वर्ष की तुखना से प्रतिभात वृद्धि (
1	2	3	4	5	6	7	3
I. कुल प्राप्तिवी (श्र+ग्रा)	15503	17007	+97	19206\$\$	- 23 9	20624	
(भा) राजस्य प्राप्तियां	11616	12573	†·8 2	14007	+ 20 6	14889	+63
जनमे से कर प्राप्तिया	9206	9934	+79	10787	F-17 2	11730	+ 6 7
(भा) पूजीगत प्राप्तिया	3887	1434	+14.1	5199\$\$	+33 8	5735	-10 3
II. कुल वितरण	16255	17243	+ 6 1	14674	+21 0	20965	+6 6
उनमें से (ध) विकास परिकाय							
(क्र - च्र च) (क - च) (क) राजस्व (क्र) पूंजीयत	7846 5340 2506 (2134)**	8268 5870 2398 (2259)**	+5 4 -9 9 -4 3 (+5 9)**	9362 6251 3111 (2798)**	+19 3 +17 1 +24 1 (+31 1)**	9882 6903 2979**	+5 6 +10 4 4 2 (+6.5)***
(ग्रा) विकासेतर परिष्यव							
(市十項)	5279	6000	+13 7	6681	- 26 6	7030	+ 5 2
(क) राजस्थ	5045	5729	-13.6	6198	+ 22 9	6729	+8 6
(च) पूंजीगत	234	271	+15 9	49 1*	+106 4	301	37 7
III. समय ग्रहिशेष(- -)/							
बाटा () (I	7 52	2 3 ts		- - 469		341	

हिष्पणी -- 1 इन प्रांकड़ों में संबंशासित क्षेत्र गासिल नहीं है।

- 2 श्रतर-सरकारी श्रंतरणों के लिए राज्य सरकारी के बजटा में उपलब्ध व्याकड़ों के श्राक्षार पर समायोजित किया गया है। इन समायोजिस से संगक्त समग्र स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 3 यहा वियो गये भांकड़ों 1973-74 के पहले के क्यों की रिपार्टों में दिए गए श्राकड़ों से मेश नहीं खाने, क्योंकि 1971-75 में बजट सबधी वर्गीकरण में परिवर्णन किये गये हैं।
- 4. भाकडे अनंभितम है।
- \$ इनमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल है किल्यु 12 मई, 1976 को बजट के पण्चात् करों में वाधित की गयी रियायतों के प्रभाव शामिल नहीं है।
- 💲 इनमें 1975 में स्वैष्टिक प्रकटीकरण योजना के भ्राप्तीन जारी किये गये बाड़ों के 40 करोड़ क्षप शामिल है।
- ** इनमें 1974-75 और 1975-76 में केन्द्रीय सरकार के लेखे से प्राप्त उर्वरको और खाद्यान्तों (निदेशों से उपहार करूप में प्राप्त) के स्टाफों के मूल्य में हुई बृद्धि शामिल सही है। मार्च 1976 से उर्वरकों के मामल में किये जाने वाले लेनदेन भारतीय खाद्य निगम को ध्रतरित कर दिये गये है।
- * इनमें स्नंतरिष्ट्रीय मुद्राकोच की 'मस्य स्ननुरक्षण' व्यवस्था के स्नतर्गत उसे भ्रदा किये गये 226 6 करोड रुपए शासिल है। स्नोत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजट।

16 केस्ट्रीय सरकार के सबध में जब अलग स विचार करते हैं तब 1975-76 के बजट में 217 करोड़ राया तो समग्र श्रजट घाटा प्रत्या-शित था। परिणोधित अनुमाना से उक्त बजट घाटे की राणि बक्तर 490 करोड़ रुपए हा गयी। किर मी बाद में प्राप्त जानकारी से यह विदित हुआ है कि समग्र अजट घाट की राशि वस्तुत कवल 367 करोड़ क्षए रही है जा परिणाधित अनुमाना की तृष्ता में 123 करोड़ क्षये कम है।

17 व्यक्ति परवर्ती बज्द के समय पर ३(१ क्राइ स्पया के बजट बाटे के अनुरूप प्राप्तियो और ब्यथ के विवरण सामान्यत उपलब्ध हा जाते रे अत तिम्तिलिकित समीक्षा 1975-75 के परिणोधित अनुमानी पर आधारित है।

क बीस सरकार का स्थय 1975-76

45. ग्राधिक क्याँय विभाग क्षाण 1976-77 के केन्द्रीय सरकार से बजट का जो ग्राधिक ग्रीर कार्य संबंधी वर्गीकरण जारी किया गया उसके भ्रमुगर 1975-76 में सन्द्रीय सरकार के कुल ब्यय भी राणि 12091 कराइ रवण (परिणाधित भ्रममान) थी भ्रयीत् उसमें 1971-75 (लेख) की मुलता में 2306 नराइ रवया या 23 5 प्रतिणत की तीय्र शृद्धि हुई (सारणी 6)। 1975-76 के कुल ब्यय में हुई भागी बृद्धि वा प्रमुख कारण यह था कि बजट में की गयी योजना व्यवस्था की राणि 37 6 प्रतिणत बदकर 4050 वरार रुपये हा गयी नब कि 1971-75 में उसके राणि 2966 तराइ रुपये थी। केन्द्रीय सरवार के ब्यय और राज्या सथा भाषामानित क्षेत्रों का योजनामा के लिए दी गयी महायता इस वर्ष काफी म्राधक थीं।

सारणी 6 : केन्द्रीय सरकार का विकास ग्रीर विकासेतर क्यय

	,		.,,,	कास श्रार विकास			(राशिक	राष्ट्र रुपयो मे)
		1 97 ।- 7 इ (लेख्ये)		1		 1975-7७ (परिशाधित श्रनुमान)		 ५७६-७७ व्ह अनु मान)
गर्दे		 पिछले वर्ष की तुलना म घटवढ़ का प्रतिणत		पिछने वय की नृजना में घटबढ़ का प्रतिणत		पिछले वर्ष की तलना में घटबढ़ वा प्रतिशत	_	
		- — 	4	5		7 -	,	
कुलय्पय (ग्र. ग्रा)	9785 (100 0)	20 3	10577 (100 0)	, <u>1</u>	$-\frac{12091^{**}}{(100-0)}$	23 6	12604 (100-0	
भ्र विकास व्यथ (i+ii)	4975 (50 4)	32 5	5353 (50-6)	7 6	6356 (52-6)	27 8	6595 (52-3)	₹ 8
(i) मामाजिक मेत्राण	592 (6-0)	1 3	705 (6-7)	19 1	731 (6 1)	23 9	515 (65)	11 2
(iì) भ्राधि य सेत्राए ^अ	(11 <i>/</i>) 1381	39 ()	4618 (13-4)	6 0	5623 (46-5)	28 3	5780 (45 h)	2 5
भा विकासतरब्यस (i+ii)	4810 (19-2)	y ()	5224 (49-4)	5 11	5735 (47 1)	19 2	6009 (17 7)	1 8
(i) सामान्य मेवाए	2619 (26-8)	6 4	2810 (26-6)	7 1	3314*** (27-4)	26 6	3201 (25-4)	 } 1
(ii) म्ननिर्धारणीय व्यय	$\frac{-2192}{(224)}$	13 9	2414 (22-8)	10 1	2121 (20-0)	10 4	2808 (22-3)	16 0

टिप्पणी काष्टको में दिये गर्ये ब्रावडे कुल व्यय में प्रतिशत का दर्शाते हैं।

- 🌁 इनमें राज्यों ग्रीर संघणासित क्षेत्रा को प्रदान किये गये एकमुण्त श्रनुदान ग्रीर ऋण शासिल है।
- ** इनमें अनर्राष्ट्रीय मुद्रा काप के करार के खड़ा में की गयी मृत्य अनुरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत उसे विये गये 326 6 करोड़ रुपए णामिल है। स्रोत भारत सरकार के बिन महालय के आधिक विभाग द्वारा जारी किये गये केन्द्रीय सरकार के अजट 1976-77 का आधिक और क्रियात्मक वर्गीकरण।

बजट साधन, बचत ग्रीर पूजी निर्माण

49 1975-76 के दौरान पूजी निर्माण पर 4602 नरार स्पाया का ज्याय किया गया बड 25 2 पितणत की वृद्धि का द्यांतक था जब कि 1971-75 में उसमें 38 प्रतिणत की वृद्धि हुई थी। उद्यागी, कृषि परिवहन श्रीर सचार पर हुए पूजी निर्माण व्यय में 1971-75 के स्तरी की तुलना में कमस 50 0 पितणत 14 6 प्रतिणत और 11 8 प्रतिणत की वृद्धि हुई। इस प्रकार पूजा निर्माण 1975-76 में केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का 38 1 प्रतिणत था जो कि 1974-75 के 37 6 प्रतिणत सण में श्रांश प्रतिणत श्रांबर था।

50 क्ट्रीय सरकार के 12091 करोड़ रुपया के व्यय में स उपभोग व्यय (अथात् आल् उपयोग के लिए मजदूरी घीर क्तन तथा बस्तुधो घीर सेवाग्रो पर सीधे ही किया जान वाला व्यय) घीर प्रत्यक्ष सकल पूर्जा निर्माण (अर्थान् भवना, खान निर्माण कार्यां, मर्थाना घीर उप-करणा तथा खन्य प्रास्तिया घीर स्टाका पर किया जाने वाला निर्मेण) स सबिधित श्रिक्ति परिष्यय में 1974-75 की तृजना में 1975 76 में 576 तराष्ट्र रूपयों या 11 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई प्रधीत उसकी राशि बढ़कर 1670 कराइ रूपये हो गयी। उपभोग क्याय में 18 प्रतिशत की जा वृद्धि हुई बह जिलीय परिव्यय की बृद्धि का लगभग 90 प्रतिशत थी। उपभोग व्यय में हुई बृद्धि का लगभग प्राधा श्रण मजद्री और बेतन में गाया गया, जिसमें 211 कराड़ रूपया या 13 2 प्रतिशत की बृद्धि हुई।

51 सनल प्रत्यक्ष पृशी निर्माण में काफी बीमी गृति से 4 9 प्रति-णन की वृद्धि हुई। पिल्तु यह अधिकाणन खाद्यान्ना और उर्बरको के स्टाकों में हुई कमी की द्योतक थी। स्टाका को छाडकर प्रत्यक्ष मकल अजल पूजी निर्माण में 17 ! प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा प्रयासम्या के शृप क्षत्र का पूजी निर्माण के जिए दी जाने वाली विनीय महाया। की राणि जा अधिम पश्चिष्य में बाहर रहता है, 1975-76 में 35 4 प्रतिशत बढकर 3315 करोड़ रुपये हो गयी (सारणी 7)।

सारणी 7 पुजी निर्माण पर भारत सरकार का व्यय

			(रामि क्रोड र पया मे)			
 मद	 197 75 (चस्त्रे)	1975-76 (बजट स्रनुमान)	 1975 76 (परिशाधित ग्रनुमान)	— 1975-77 (बजर ग्रनुमान)		
	$\frac{-}{2}$	3	4	5		
	823	457	964	1092		
∏ स्टाको म वृद्धि	405 (372)	131 (140)	3	3 2(<i>a</i>) (—)		
III सृद्ध प्रत्यक्ष पत्री निर्माण (सकल पत्यक्ष प्रचत पृत्री निर्माण नवीकरणा ग्रीर प्रतिस्थापना क्ष्ययका घटान पर किन्तु स्टाको की बृद्धिको जोडन के बाद) IV पृत्री निर्माण के लिए विक्तीय सहायता	1081	862	1132	972		
(क +ख + ग)	241)	2913	3315	3791		
(क) राज्य ग्रीर सघणासित क्षेत्र	1188	1223	1380	1520		
(ख) विभागेतर त्राणिज्यिक प्रतिष्ठान	1115	1555	1753	2108		
৷ घिनीय प्रतिष्ठान	156	1 15	211	174		
े ग्रन्य	959	1420	1569	1930		
(ग) स्थानीय प्राधिकारी भ्रौर भ्रन्य पार्टियां	146	135	1 16	153		

3677

स्नात भारत सरकार के वित्त मन्नालय के आधिक कार्य विभाग द्वारा जारी किये गर्ने कर्द्राय सरकार र अजट रा आधिक ग्रीर क्रियात्मक वर्गीकरण ।

5.2 सरकारी प्रशासन की बचन ग्रीर विभागीय वाणिज्यिक प्रति टिंगों के मृत्य ह्मास की अपयस्था 1975 76 (परिणाधित ग्रनुमान) मे त्रमण 6 3 प्रतिशत ग्रीर 3 2 प्रतिशत ग्रिधिक थी (सारणी 8)। इसके साथ ही विभागीय प्रतिष्ठानी की वर्तमान हानि 1974 75 के 80 करोड रुपयो से घट कर 1975-76 में 34 करोड रुपये हो गयी। इस प्रकार

जोड ([| H+IV)

केन्द्रीय सरकार की सबल बजन की राणि एक वर्ष की श्रवधि में 11 3 प्रतिकात बढ़कर 1021 करोड रुपये हो गयी। शुद्ध बजत (नजीवरणा श्रीर प्रतिस्थापना के व्यय की धटाकर सकल बजत) में श्रपेक्षाकृत ग्राधिक वृद्धि हुई। शुद्ध बजत की राणि 1975-76 में 12 प्रतिणत बढ़कर 866 करोड रुपये हो गयी।

4602

4905

3931

सारणी ४ केन्द्रीय सरकार की बचत

				(राणि करोड़ रुपयो में)			
	1974-75	1975-76	- — 1 4 7 5- 7 6	1976 77	मट- ब ढ़	वा प्रतिणत	
मर्दे 	(तके)	(अजट ग्रनुमान)	(परिणाधित श्रनुमान)	(<i>मकट</i> श्रन्मान)	स्त्रभ ∠ की तुलना में स्तम 4 म	स्तम 4 की मृलना म स्तम 5 मे	
1	2	3	i	5	6	7	
ा गरकारी प्रशासन की राजस्व प्राप्तिया (I + II)	6158	6647	7239	7595(a)	17 6	1	
(1) वर राजस्व	5076	5411	5850	6243	15 2	6 7	
(II) करेमर राजस्व	1082	1273	1389	1352	28 4	4 2	
८ चीम् व्यय	5 117	5887	6745	6910	19 3	8 9	
3 सन्यारी प्रकासन की बचन (12)	841	500	994	645	6	3 23 .	
4 राजस्व प्राप्तिया व प्रशिष्ठत के रूप में प्रशासन की बच्चन (। क प्रतिशत के रूप म 3)	13 7	12 0	12 3	9 ()			

[@] इसमं बजट के बाद 12 मई 1976 का घोषित की गयी रियायना के प्रभाव गामित नहीं है।

कारठको म दिये गये ब्राक्ट उवरका श्रीर खाद्याला के स्टाका मे श्रुए परिवतना का दर्शात है।

⁽এ । माच ।)76 म प्रायानित नाइट्राजननीय उर्बरका की खरीद देखमाल घौर वितरण की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम का माण दी गयो है।

1	<u> </u>	3	4	5	В.	7
- — - — - — — — — — — — — — — — — — — —			-			
व्यवस्था भीर श्रभिधारित लाभ $(1+2)^{-1}$	76	2 1 1	127	376	67. I	196.1
(1) मूल्य ह्नाम व्यवस्था	156	162	161	1 4 8	3 ?	16 8
(2) ग्रभिर्धारित लाभ	40	82	3 1	188		
6 केम्द्रीय सरकार की सकल बचत (3-1⊢5)	917	1044	1021	1061	11.3	3 9
 नवीकरणो और प्रतिस्थापनो पर व्यय 	111	156	155	172	7.6	11.0
8. णुद्धः बचन (67)	773	888	866	889	12 0	2.7
 मृद्ध प्रत्यक्ष निवेश* 	712	722	819	952	15,0	16.2
10 णुद्ध प्रत्यक्ष निवेण ^क की तुलना में णुद्ध बचत मे						
ग्रधिकता(├) या कमी(──) (8──9)	61	166	47	63		

^{*} इनमें उर्बरकों और खाद्यान्तों के स्टाकों में हुई वृद्धि शामिल नहीं है। स्नोत भारत सरकार के वित्त मवालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वार कियात्मक वर्गीकरण।

स्रोत भारत सरकार के वित्त मवालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किए गण केन्द्रीय. सरकार के बजट 1976-77 का प्राधिक श्रीर

राजकोबीय नीति--1976-77

53. केन्द्रीय भरकार के 1976-77 के बजट पर विचार करने से पहले बजट से प्रतिपादित होनेवाल राजकोषीय नीति के मूलभूत दृष्टिकोण में आये कुछ परिवर्तनों को स्पाट करना आवस्यक है। 1976-77 का राजकोषीय नीति से समग्र विकास में तीव्रता लाने के लिए बचत श्रीर निवेश की वृद्धि पर जोर दिया गया है। यह तथ्य ग्रन्य बातों के साथ साथ प्रत्यक्ष कर विन्यास के औषान्यीकरण से प्रगट होता है।

54 सार्वजनिक क्षेत्र में 1976-77 के वार्षिक योजना परिव्यय मे पिछले वर्ष के मृल योजनायत अनुमान से 31 4 प्रतिशत की वृद्धि की नयी है। निवेश परिव्यय में कार्यान्वित हो रही परियोजनाधी की समान्त करने के लिए प्राथमिकता दी गयी है। निजी क्षेत्र में भारी निवेण ग्रौर क्षमता के अधिक उपयोग को बढ़ाने के लिए चने हुए उद्योगों के लिए निवेशों में छूट दी गयी है और जिन औद्योगिक उत्पादनों की माग मे मंदी रही है उनके लिए उत्पादन शुक्कों में रियायतें की गयी है। (9) इसके ग्रालाबा ग्राय ग्रीर संपत्ति करो की ग्राधिकतम दरो में कटेंनी कर निवेश और उतादक प्रयासो को प्रोत्साहस दिया गया । इन प्रत्य करो की दरों को प्राय ग्रीर संपत्ति के स्वैच्छिक प्रकटन की योजना की सफलता के संदर्भ में कम किया गया ताकि कर स्वरूप को संगत अनाया जा सके और कराधान का ग्रन्पालन बेहतर हो सके। इसके साथ ही मांग का नियन्नित करने के उद्देश्य में सरकार ने कर्म-चारियों के अतिरिक्त मंहगाई भन्ने को अवगढ़ करने के उपाय श्रीर श्राय कर-दाताको के लिए बनायी गयी अनिवार्य बचन योजना को कतिपय सशोधनों के साथ और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया।

(⁹) विमा मंत्री ने भी 1975-76 में उत्पादन णुल्क के समग्र स्वरूप विशेष कर मृख्य से जुड़े हुए कर की प्रणाली को स्वीकार करने की सभाव्यका की व्यापक समीक्षा की थी। मुक्ति इस समीक्षा से प्रकाण से ग्राई बातें अधिक जटिल पायी गयी और उनका दुरगामी प्रभाव पड़ सकता था छत उनके बजट भाषण में यह संकेत दिया गया कि उनके द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति परोक्ष कर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की समीक्षा करेगी। तदनुसार भारत सरकार ने 20 जुलाई, 1976 को मान मदस्यो की एक ममिति नियुष्टित की ओ (क) केरद्रीय राज्य स्तरीय ग्रीर स्थानीय परीक्ष करो के वर्तमान स्वरूप के सभी पहलुको की समीक्षा करेगी ग्रौर (स्त्र) दुर्लभ साधनों के ग्रार्थिक उपयोग को बढ़ाने से परोक्ष कराधान की भूमिका का निम्नलिखित संदभौ मे अध्ययन करेगी: मूल्यों श्रौर लागतों पर उत्पादन णुल्को का प्रभाव, ऐसे णुल्कों का सचयी प्रभाव, विभिन्न व्यय समुहो पर उनका प्रभाव, कर श्राधार को व्यापक बनाने ग्रीर कर प्रणाली की लोच को बढ़ाने की सभावना, मूल्य से जुड़े हुए कर की पद्धति को ग्रपनाने की संभाव्यता, क्या और कहां तेक परोक्ष करों में रियायते वेकर किसी विशेष उद्योग या उद्योग क्षेत्रों की सहायता करना उचित क्षेगा, प्रदातन व्यापार नियंत्रण की दृष्टि से आयास णुल्को का स्वरूप और स्तर, देशी उद्याग का संरक्षण और देशी उत्पादों का मुख्यन।

भया ग्राचिक कार्यक्रमः

55 1975-76 की राजकोषीय नीति का एक इसरा पहलू यह था कि उसमें 1975 के मध्य में गुरू किये गए 20 मूलीय श्राधिक कार्यक्रम के प्रभग में श्रधिक सामाजिक न्याय के साथ विकास को बढ़ाने की परिकल्पना थी। नये श्राधिक कार्यक्रम में 1975-76 में प्रत्याशित व्यय की राणि 1970 करोड़ रुपये थी। इस राणि में राज्यों और संबंधासित क्षेत्रों के लिए 1851 करोड रुपये श्रीर केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 119 करोड़ रुपये सम्मिलत थे। 1976-77 के परिव्यय की बढ़ाकर 2338 करोड़ रुपये कर विया गया है। इस राणि में राज्यों और संबंधासित क्षेत्रों के लिए 2174 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 164 करोड़ रुपये सम्मिलत थे। इस कार्यक्रम के श्रधीन श्रधिकाण परिब्यय राज्यों के क्षेत्र में श्राप्त हैं। इस सामिति की श्रीप्त श्रधिकाण परिब्यय राज्यों के क्षेत्र में श्राप्त हैं। राज्य इन वायित्सों का बहुन कर सकें, इस उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने विशेषकर बड़ी और मझौली सिकाई तथा बिजली की परियोजनाओं के क्षेत्र में राज्यों की जाने वाली सहायता को बढ़ा दिया है।

केन्द्रीय सरकार का बजट:1976-77

56. केन्द्रीय सरकार के 1976-77 के बजट प्रनुमाना में योजना के लिए भारी माल्ला में 4759 करोड़ रुपयो की व्यवस्था की गयी है जो 1975-76 (परिणोधित अनुमान) में योजना व्यय के लिए बजट में ग्राबंदिन किये गये 4080 करोड रुपयों से 16 6 प्रतिशत बृद्धि की घोतक है। योजना परिव्यय के लिए फिये गये ग्राबंटन में हुई इस वृद्धि के आवज्रद केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय 1975-76 में हुई 23 6 प्रतिमान बुद्धि की तुलना में 1976-77 में केवल 4.2 प्रतिशत बढ़कर 12604 करोड़ रुपये होने का श्रनुमान है। इक्षके प्रमुख कारण निम्न प्रकार है: पहला कारण यह है कि 1975-76 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 227 करोड़ रुपयों के "मूल्य का भूगतान करने" का यह मतलब था कि उक्त कोष में रहने वाले रुपयो के लिए पूरा समायोजन किया जायेगा। इस प्रकार के भुगतान 1976-77 में भी अवस्य ही करने होंगे; किन्तु ऐसे समायोजन का मृह्य काफी कम होने की घाणा की जा सकती है। धनः 1976-77 के बजट में इसके लिए नाममास्र की (1 करोड़ रुपये) व्यवस्था की गयी है। दूसरा कारण यह है कि ग्रव श्रायातित खाद्यान्तों श्रीर उर्वरकों का: वित्तपोषण करने का दायित्व भारतीय खाद्य निगम का है; ग्रत. उर्वरकों श्रीर खाद्यान्नों के स्टाको के वित्त-पोषण के लिए 1976-77 के बजट में कोई व्यवस्था करना भावण्यक नहीं समझा गया है । 1975-1976 में इस सवर्भ में 313 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ। तीसरा कारण यह है कि मूल्य स्थायिना के संदर्भ में मजदूरी ग्रीर वेनन पर होने बाला 33 करोड़ रुपयो का प्रतिरिक्त व्यय 1975-76 में हुए 214 करोड़ रपयों के व्यय से काफी कम है।

57. उपसोग की यम् आं और मेलाओ तथा पना निर्माण की केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष माग की राशि 1650 करोड रुपये ह जा 1976-77 में उसके मुल ज्यय का 36 9 प्रतिणत है जब कि बहु 1975-76 में 38 6 प्रतिणत था। उसके उपभोग ज्यय की बद्धि देर 1975-76 के 18 प्रतिणत से 1976-77 में तेजी में गिरकर 4 2 प्रतिणत हो जाने की ग्राशा है। उपभाग व्यय की राणि इस प्रकार 3383 कराड रुपयो में सामान्य रूप में बढ़ाकर एक वर्ष में 3526 करोड स्पये हो जायेगी।

58 उर्वरको के व्यापार को भारतीय खाद्य निगम को प्रतिरत कर देने के बाद केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष सकल पृजी निर्माण की राणि 1975-76 के 974 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1976-77 में 1124 करोड़ रुपयें से बढ़कर 1976-77 में 1124 करोड़ रुपयें हो जाने का अनुमान है; उसकी वृद्धि दर 13.8 प्रतिशत में बहुकर 15.4 प्रतिशत होंगी। 1960-61 के मृत्यों के प्रनुमार (10) प्रत्यक्ष सकल अचल पूर्जी निर्माण में 1975-76 में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जय कि 1974-75 में उसमें 10 2 प्रतिशत की गिरावट क्षायों थी। 1976-77 में ऐने पूर्णी निर्माण में 13 3 प्रतिशत की वृद्धि होंगी। इस प्रकार यग्रिप प्रत्यक्ष सकल अचल पूर्जी निर्माण में 1975-76 की प्रपेक्षा कम वृद्धि होंने की प्राणा है, फिर भी पूर्णी-स्लिखित प्रकार में कार्यन्तित हो रही परियोजनाक्षों में किये जानेवाल निर्माण पर जॉर देने के कारण प्रत्याणित पूर्जी निर्माण से उत्पादन में प्रक्षिक वृद्धि होंने की संभावना है।

59 ध्रथं व्यवस्था के शेष भाग को पृत्री तिर्माण के लिए दी जाने वाली विलीय सहायता में 14.1 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है ध्रथित् वह 1975-76 के 3315 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1976-77 में 3781 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1976-77 में 3781 करोड़ रुपये होगी (सारणी 7)। केस्ट्रीय सरकार के खजट साधनों में से सकल पूंजी निर्माण की राशि 1976-77 में 1905 करोड़ रुपये होगी जो 1975-76 के 4602 करोड़ रुपयों से 6.6 प्रतिशत बृद्धि की छोनक होगी और कुल व्यय में उसका धंश 39 प्रतिशत के ध्रासपास होगा जबकि 1975-76 में वह 38.1 प्रतिशत था।

60. केन्द्रीय सरकार के कुल क्यम में 1975-76 में हुई 23.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में 1976-77 में केवल 4 2 प्रतिशत की वृद्धि होने के संवर्भ में उसका विकास क्या 1975-76 के 6356 करोड़ रुपयों से 3 4 प्रतिशत काकर 6595 करोड़ रुपयों हो 1 4 प्रतिशत काकर 6595 करोड़ रुपयें हो जाने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष वृद्धि 27.8 प्रतिशत थी। विकास के उद्देश्यों के लिये किये जाने वाले पूर्ण निर्माण व्यय की प्रवृत्ति कुल विकास व्यय की तुलना में बेहमर होने की आशा है। विकास के उद्देश्यों के लिये काने वाले पूंजी निर्माण व्यय की राश्या है। विकास के उद्देश्यों के लिये काने वाले पूंजी निर्माण व्यय की राश्य 1976-77 से 4561 करोड़ रुपयें के 6 5 प्रतिशत बढ़कर 4858 करोड़ रुपयें होने का धानुमान है। पिछले वर्ष उक्त राशि में से 25.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

61. यह स्मरण होगा कि 1975-76 में सरकारी प्रधासन की बजत में जीनों के निर्यातों से हुए 135 करोड़ रुपयों के लाओं का (परिशोधिन अनुमान) महत्वपूर्ण योगदान था। प्रमुख रूप से 1976-77 के बजट अनुमानों में इसके लिये कोई व्यवस्था न करने से प्रधासन की बजत 1976-77 में 23.4 प्रतिशत गिरकर 685 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है यद्यपि सरकार के वर्तमान व्यय में भी 8 9 प्रतिशत की अनुमान है यद्यपि सरकार के वर्तमान व्यय में भी 8 9 प्रतिशत की वृद्धि होने की श्राणा है। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्टानों के परिचालन (10) प्रत्यक्ष सकल प्रचल पूजी निर्माण के आकड़ों को संशोधित थोक मूल्य सूचकाक के प्रयोग द्वारा अवस्फीत किया गया है। थोक मूल्य सूचकाक के प्रयोग द्वारा अवस्फीत किया गया है। थोक मूल्य सूचकाक इस प्रकार समायोजित किया गया कि उसके द्वारा केवल पेट्रोलियम वस्तुश्रो, रसायनों और निमित वस्तुश्रो, सशीनों और परिवहन उपकरणों के मूल्यों में किये गये परिवर्तन प्रतिपादित हो। इस प्रकार अवस्फीति के लिए प्रयुक्त स्वकाक मे खाद्य वस्तुएं, शराब और तमान् और श्रीवोगिक ककी सामग्री शामिल नहीं है।

परिणामों से पत्पाणित लिख के भार उनकी मृत्यहास अपवस्था सीर प्रिमिधारित लाभों की राणि लगभग तिगृती बढ़कर 376 करोड़ रुपये हो जाने के बावजद केन्द्रीय सरकार की शुद्ध बचत की राणि केवल 2 7 प्रतिशत या 23 करोड़ रुपये बढ़कर 889 करोड़ रुपये होने की प्राणा है जबिक 1975-76 में उक्त राणि 12 प्रतिशत बढ़कर 866 करोड़ रुपये हो गयी थी। बजट प्रनुमानों के अनुमार केन्द्रीय सरकार की शुद्ध बचत शुद्ध प्रत्यक्ष निवेण से 63 करोड़ रुपये या 6 6 प्रतिशत कम होगी जबिक 1975-76 में शुद्ध प्रत्यक्ष निवेण (उर्बरकों और प्रताजों के स्टाकों को छोडकर) की तुलता में शुद्ध बचत के श्रिधालें की राणि 47 करोड़ रुपये थी।

62. केन्द्रीय सरकार के कुल पृंजीगत रुप्य की राणि 1976-77 में 1069 नरोड़ कपये होने का अनुमान है। उसमें 952 करोड़ कपये का प्रत्यक्ष णुद्ध निवेश, प्रार्थ व्यवस्था के शेप क्षेत्रों को अनरित किये गये 305 करोड़ कपयों की गुद्ध पुत्री और 2812 करोड़ कपयों की विसीय अस्तियों का गुद्ध अस्तियों के तिसीय वेयताओं में 1770 करोड़ कपये की आणा है और उसकी वेशी विसीय वेयताओं में बाजार ऋण, इस वर्ष अतिवायों अचत के सभाष्य बृद्धि के आधार पर रिजर्व बैंक से लिये गये 480 करोड़ क्ष्यों के उधार, खजाना बिलो को छोड़कर अल्प बचतें और दूसरी देयतायें शामिल हैं। ग्रम: बजट बाटे की राणि 320 करोड़ रुपयें हो जाने की आणा है। 11

बजट संबंधी कार्बकलाय---राज्य सरकारें--- 1975-76

63. राज्यों के विस पर श्रम विचार किया जाए। केन्द्रीय मरकार की नरह राज्य सरकारों के 1975-76 के बिला के सबध में भी केवल परिसोधित श्रमुमान श्रम उपलब्ध है। इनसे 1974-75 (लेखे) की नुलना में स्पष्ट सुधार परिलक्षित होता है। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट होता है कि 1975-76 में बजट में जहां 22 करोड़ हपनो का श्रिधिमेच बा बहां 1974-75 में 31 करोड़ रुपयों का घाटा विचमान था। इस प्रकार श्रिधिसेय की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि कुल प्राप्तियों में 18 8 प्रतिमान की वृद्धि हुई प्रथित् उत्पन्न राणि बेक्कर 1010221 करोड़ रुपये हो गयी। इसके विपरीत कृत वितरणों की राणि थोड़ी सी प्रथित् 18.1 प्रतिमान बहकर 10199 करोड़ रुपये हुई (सारणी 9)।

64 राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रध्यक्ष रूप में लगाये घौर बसूल किये गये करों नथा केन्द्रीय सरकार के करों में में उनके क्षिस्में के रूप में प्राप्त राणि में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई घौर उसकी राणि 1974—75 के 4109 करोड़ रुपयों से बकुकर 1975—76 में 4916 करोड़ रुपयें हो गई। एक वर्ष की धविध में करों से प्राप्त राणि में 807 करों हे रुपयों की जी वृद्धि हुई उसमें 540 करों ह रुपयें राज्यों के ध्रपतं करों से प्राप्त थे घौर 267 करों इ रुपयें केन्द्रीय सरकार के करों में से राज्यों के किया के हिस्से के रूप में प्राप्त थें। कर प्राप्तियों में विलीय साधन जूटाने के लिए इस वर्ष के दौरान बजट प्रस्तुत करने समय तथा बाद में राज्य मरकारों नथा केन्द्रीय सरकार के करों में से राज्य प्रकारों नथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा किये गये ध्रतिरिक्त उपायों के कारण उक्त वृद्धि हुई। ध्रमुमान है कि केन्द्रीय सरकार के करों में से राज्यों का उनके हिस्से के रूप में प्राप्त राणि मों जो वृद्धि हुई उसके ध्राधीण का कारण ध्राय तथा सम्पत्ति की स्वैक्टिक प्रकटन योजना के

⁽¹¹⁾ इसमें 12 मई, 1976 को अजट के पश्चान् करों में जो रिया-यतें घोषित की गयी उनके प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। उनसे पूरें वर्ष में राजस्व में 9 9 करोड़ रुपयों घौर 1976→77 में 8 8 करोड़ रुपयों की हानि होगी।

संतर्गत प्रकट की गयी भ्राय में प्राप्त राणि थी। 1975—76 के दौरान राज्यों के भ्रापने श्रतिरिक्त कराधान से भी उनके द्वारा लगाये भौर बसूल किये गये करों से प्राप्त राणि में इस एक वर्ष की श्रविध में 18.7 प्रतिशत की बृद्धि होने में सहायता मिली। ये प्रयास श्रतिरिक्त कर बुटाने के लिए 1974—75 में भारी माला में किये गये प्रयासों के भ्रलावा किये गये। 1974—75 में ऐसे राजस्व में लगभग एक बीधाई बृद्धि हुई थी। राज्यों के करेतर राजस्व की राणि 1974—75 के 1300 करोड़ क्ष्यों से बढ़कर 1975—76 में 1511 करोड़ क्ष्ये हो गयी भ्रशीस् उसमें 16.2 प्रतिशत की बृद्धि हुई।

65. केन्द्रीय सरकार में प्राप्त ऋष्णों को छोड़कर राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियों की कुल गणि 1975-76 में 1279 करोड़ रुपये थी जो पिछमं वर्ष की तुलना में 183 करोड़ रुपयों की वृद्धि की छोतक थी। राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गयी कि वे बाजार ऋण जारी कर 1975-76 में 100 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि जुटायें ताकि वे 1963-64 के केन्द्रीयकृत बाजार ऋणों में केन्द्रीय सरकार के श्रंश को चृका सकें। इसका उल्लेख बाद में किया गया है। यह आलोच्य वर्ष के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों में हुई वृद्धि का विशेष कारण था।

सारणी 9 : राज्य सरकारों की समग्र बजट स्थिति

(राशि करोड़ रूपयों में)

	1974-75 (लेखे)	- "	1975-76 (बजट ध नुमान)	1975–76 (परिशोधित प्रनुमान)			1976—77 (बजट म्र नुमान)	
म र्वे	राशि	रामि	पिछले वर्ष की सुलना में घट-अक का प्रतिशत (स्तंभ 2 की नुलना में स्तंभ 3)	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत (स्तभ 2 की तुलना में स्तंभ 5)	राणि ह	पिछले वर्ष की ज़्ला में घट-ज़ब् का प्रतिशत (स्तंभ 5 की तुलना में स्तंभ 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. दुल प्राप्तियां (ग्र+ग्रा)	8602	9087 (9266)	+ 5.6 (+7.7)	10221		10740 (10889)		
ग्न. राजस्व प्राप्तियां (i $+$ ii)	6431	6819 (6998)	+6.0 (+8.8)	7620	+18.5	825 (8399)	+8.4	
(i) कर प्राप्तियों (क+-ख)	4109	4325 (4498)	+5.3 (+9.5)	4916	+19.6	5343 (5466)	+8.7 (+11.2)	
(क) राज्यों के कर	2881 1228	3001 (3133)	+4.2 (+8.7)	3421	+18.7	374 (3831)		
(खा) केल्द्रीय करों में हिस्सा		1324 (1365)	(+7.8) (+11.2)	1 195	+21.7	160: (1635)		
(ii) करेनर प्राप्तियां (ग+घ)	2322	2494 (2500)	+7.4 (-7.7)	2704	+16.5	291 (2933)		
(ग) राज्यो की करेतर प्राप्तियां	1300	1406 (1412)	+8.2 (+8.6)	1511	+16.1	1656	5 +9.6 (+10.9)	
(ध) केम्द्रीय सरकार से अनुदान	1022	1088	+6.5	1193	-{-16.7	125	+5.4	

टिप्पणिया: 1. ग्रांकड़े श्रनितम हैं 2. 1975-76 (बजट श्रनुमान) के लिए कोष्टकों में दिये गये श्रांकड़ों में राज्यों की बजट प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली श्रनुमानित राणि (83 करोड़ रुपये), केन्द्रीय सरकार के श्रानितिक्त गुढ़ कराशान में उनका हिस्सा (41 करोड़ रुपये) और केन्द्रीय बिकी कर की दर में किया गया परिवर्तन (55 करोड़ रुपये सस्मिनित है) 3. 1976-77 (बजट श्रनुमान) के लिये कोष्टकों में दिये गए श्रांकड़ों में राज्यों को बजट प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली श्रनुमानित राणि (117 करोड़ रुपये) श्रीर केन्द्रीय सरकार के श्रानितिक्त कराशान में उनका हिस्सा (32 करोड़ रुपये) मस्मिलित हैं। 25 GI/77-3

सारणी 9: राज्य सरकारों की समग्र बजद स्थिति (जारी)

(राणि करोड़ रूपयों में)

	1974-75 (लेखे)		197576 (बजट घनुमान)	(•	1975-76 (परिभोधित मनुमान)		1976—77 (धजट घनुमान)	
मर्दे	राशि	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिगत (स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 3)	राणि	पिछले वर्षे की तुलना में घट-बढ़ का प्रतियत (स्तंभ 2 की तुलना में म्तंभ 5)	राशि	पिछले वर्षे की सुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत (स्तंभ 5 की तुलना में स्तंभ 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
धा. पूंजीगत प्राप्तियां (i∔ii)	2171	2268	+4.5	2601	+19.8	2483 (2490)	-4.5 (-4.3)	
(i) राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां जनमें से	1096	1125	+2.6	1279	+16.7	1201 (1208)	-6, 1 $(-5, 6)$	
(क) बाजार ऋष (सकल)	306**	291	-4.9	275	-10.1	306	+11.3	
(ख) ऋणों भीर प्रग्निमों की वसूली	288	348	+20.8	395	+37.2	360	-8.5	
(ii) केन्द्रीय सरकारसे ऋण (सकल)	1075	1143	十6.3	1322	+23.0	1282	-3.0	
II. कुल बितरण उनमें से	8633	9255	+7.2	10199	+18.1	10910	十7.0	
(क) विकास परिष्यय* (i+ii)	5944	6213	+4.5	6934	+16.7	7466	+7.2	
(i) सामाजिक् भौर सामुदायिक सेवाएं उनमें से]	2649	2797	+5.6	3008	+13.6	3206	+6.6	
प्राक्वतिक विपश्चियों पर व्यय	115	99	-14.7	122	+5.2	53	-56.	
(ii) ग्राधिक सेवा	3295	3416	+3.7	3926	+19.2	4260	+8.	
(ख) विकासेतर परिष्यय [*]	1946	2289(2) +17.6	2344	+20.5	2642	@ +12.	
(ग) केन्द्रीय सरकार के ऋणों की चुकौशीं	505	642	+27.1	7 5 9	+ 50.3	562	-28.	
(म) श्रांतरिक ऋणों का शोधन उनमें सें,े	124	32		36	3	138		
बाक्षार ऋण	91	1			5	105	;	
III समग्र प्रधिसेथ (+) या घाटा () (I−II)	-31	-168 (+11)		+22	2	-170 (-21)		

^{*}इसमें राजम्ब और पृंजीगत लेखों पर राज्यों द्वारा किया गया व्यय तथा राज्यों द्वारा प्रवान किये गये ऋण झौर झिन्नम मिमिलित हैं।

66. 1975-76 के दौरान केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को मुद्ध रूप से अंतरित किये गये विसीय साधनों में भारी माला में वृद्धि हुई; उक्त साधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवत्त सहायता-अनुदान और ऋण सिमिलिल हैं। एक वर्ष की अधिक्ष में हुई वृद्धि 164 करोड़ रुपये या 10.3 प्रतिमत यी जबकि 1974-75 में उक्त वृद्धि 36 करोड़ रुपये या 2.3 प्रतिशत यी। दोनों धर्षों में अनुवानों के कारण पूरी वृद्धि हुई। अनुवानों में 1975-76 में 171 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और उनकी राशि बढ़कर 1193 करोड़ रुपये हो गई जबकि

पिछले वर्ष जनमें 85 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी और जनकी राशि विकर 1022 करोड़ रुपये हुई थी। इसके विपरीत कैन्द्रीय सरकार को चुकायी गयी राशि की घटाने पर केन्द्रीय सरकार से राज्यों को प्राप्त ऋणों में 1975-76 में 7 करोड़ रुपये की गिरावट मायी। वस्तुत: राज्य सरकारों को प्राप्त सकल ऋणों की राशि 247 करोड़ रुपये मधिक थी धर्मात् बहु बदकर 1322 करोड़ रुपये हो गयी: परन्तु मालोच्य वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा चुकाये गये ऋणों में 254 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई भौर जनकी राशि बदकर 759 करोड़ रुपये

[@]इसमे राजस्थान के संवर्भ में राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किये गये श्रतिरिक्त मंहगाई भले के कारण उत्पन्न सम्पूर्ण वेयता सम्मिलित है, उक्त देयता को धिकास श्रीर विकासेतर व्यय के बीच श्राबंटित नहीं किया जा सका क्योंकि ग्रपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

^{**}यहां मणिपुर के लिए जो ध्रांकक्के सम्मिलित किये गये हैं वे भारतीय रिजर्ववैबैक के स्रमिलेखों से लिये गये हैं।

हो गयी जिलाने से 100 करोड रुपये 1963-64 के केन्द्रीयकृत बाजार आहणों ने नारण जुनाये गये। राज्य सरकारों की जुन प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारां को ध्रतिरित्त किये गये गुद्ध विसीय साधनों (केन्द्रीय सरकार के अनुदान और शुद्ध ऋण) का अनुपान केन्द्रीय सरकार को जुनतये गये अहण का छोड़ वैने पर 1974-75 के 19 7 प्रतिशन से घटकर 1975-76 में 18 6 प्रतिशत हो गया।

67 राज्य सरकारों के कुल विनरणों की राशि 10199 करोड़ रुपये थी जा 1975-76 में विनरित 1566 कराड़ रुपये से अधिक थी। इस प्रकार इस वर्ष विनरित राशि में जो बृद्धि हुई वह पिछलें वर्ष उसमें हुई वृद्धि की तुलना में चौगुनी थी। विकास कायों के लिए अन्य पार्टियों को दिये गये ऋणों सहित राज्यों के कुल विकास क्यय में 16 7 प्रतिभान की वृद्धि हुई और उसकी राशि बढ़कर 6934 करोड़ रुपये हो गयी। 1975-76 में राज्यों के कुल क्यय में विकास परिव्यय का अभ 74 7 प्रतिशत था जो विकासेतर क्यय का लगभग तीन गुना था। विकासेतर क्यय की पूर्ति करने के बाद केन्द्रीय सरकार से अनिरित की गयी शुद्ध राशि से इतर राज्य सरकारों के अपने ही वित्तीय साधनों से उक्त विकास परिक्यय के 77 3 प्रतिशत का वित्तियेखण किया गया जब कि 1974-75 में 76 7 प्रतिशत का वित्तियेखण किया गया था।

बजट संबंधी कार्यकलाप राज्य सरकारें--1976-77

68 1976-77 के बजट मनुमामों को यदि देखा जाए ता ऐसाप्रतीत होता है कि 1975-76 के परियोधित धनुमानों की वुलना में राज्य सरकारों की समग्र बजट सबधी स्थिति में गिरावट मायी है। 1975-76 में पाया गया 22 करोड़ रुपयों का ग्रिधियेष लगभग उत्तनी ही माला (21 करोड़ रुपयों) में घाटे में परिवर्तित हो जायेगा। बीम सूलीय ग्राधिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रदान की गयी उच्च प्राथमिकता के मनुमार यह प्रस्ताव किया गया है कि 1976-77 में समग्र योजनागत परिवयय में 917 करोड़ रुपयों या 33 8 प्रतिशत की वृद्धि की जाए मर्यात् उक्त परिव्यय की रिशि को पिछले वर्ष के मूल योजनागत परिव्यय की सुलना में बढ़ाकर 3628 करोड़ रुपये (12) कर देने का प्रस्ताव किया गया है। यह वृद्धि मर्यव्यवस्था के कोड़ क्षेत्र मर्थात् हुपि, सिचाई और विजली में की जा रही है। इस उल्लेखनीय वृद्धि के मनुरूप वित्यय साधन जुटाने के लिए और भी कोशिया की जाएगी। राज्य सरकारों के बजट इसके प्रमाण है जिनमें लगभग 117 करोड़ रुपयों (15) के मितिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत है।

69 राज्यो के राजस्व में प्रस्थाशित वृद्धि के बावजूद उनकी कुल प्राप्तियों में 668 करोड़ रुपयों यो 6 5 प्रतिशत की वृद्धि करने ग्रर्थात्

उनकी राशि को बढ़ाकर 10889 करोड़ रुपये कर देने की व्यवस्था की गयी है, यह बुद्धि 1975-76 में हुई बुद्धि की लगभग एक तिहाई है। इस गिरावट का प्रमुख कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार से हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाले कर राजस्व तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले अनुवानों में कभी आ। गयी हैं। हिस्से के रूप में प्राप्त होने नाले कर राजस्य की युद्धि दर 1975-76 के 21 7 प्राप्तिमात से घटकर 1976-77 में 9 4 प्रतिशत रह आएगी। 1975-76 में भाग और संपत्ति की स्वैष्टिक प्रकटन योजना के भतर्गत हुई प्राप्तियों से इस राजस्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसके धलावा, राज्यो का केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हाने वाले अनुदाना में केवल 5 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो पिछले वर्षे हुई। 16 7 प्रतिशत की वृद्धि की एक तिहाई से कम होगी। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणा को छोड़कर राज्यो की श्रन्य पूजीगत प्राप्तियों में 1975-76 में हुई। 183 करोड़ रुपयों की वृद्धि की वुलना में 71 करोड़ रुपयो की गिराबट अने की आशा है, हालांकि एक वर्ष की धवधि में बाजार ऋणों में बढ़ोतरी होगी। केन्द्रीय सरकार से राज्यों को म्रतरित किये जाने वाले वित्तीय नाधन (केन्रीय सरकार के भ्रमुदान ग्रीर णुद्ध ऋष्ण) 1976-76 में 222 भरोड रुपये मधिक होगे जबकि पिछले वर्ष उन्त साधन 164 करोड रुपये मधिक थे। इस प्रकार केंद्रीय सरकार से श्रतरित मुद्ध राणि का ग्रम केन्द्रीय ऋणो की चुकौती को छोडकर राज्यो की कुल प्राप्तियों में 1975-76 में जहां 18 6 प्रतिशत या बहां 1976-77 में 19 2 प्रतिशत होगा।

70 राज्यों के कुल वितरणा में 1976-77 में 711 करोड रुपयों या 7 0 प्रतिशत की युद्धि होने का प्रनुमान है जबिक पिछले वर्ष उनमें 1566 करोड रुपयों या 18 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विकास परिज्यय में 532 करोड़ रुपयों या 7.7 प्रतिशत की वृद्धि होने प्रचात् उनत परिज्यय की राशि बढ़कर 7466 करोड रुपये हा जाने का धनुमान है यद्यपि प्राकृतिक विपत्तियों पर होने वाला ज्यय 1975-76 के 122 करोड रुपयों से घटकर 1976-77 में 53 करोड़ रुपयें रह जाने का धनुमान है। विकासेतर व्यय जहां 1975-76 में 20 5 प्रतिशत बढ़कर 2344 करोड रुपयें हो गया था वहा मालोच्य वर्ध के वौरान उसमें 298 करोड रुपयों या 12 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का प्रनुमान है। 1976-77 में प्रत्याशिल मूल्य स्थायिता के परिप्रेक्य में अतिरिक्त महगाई भत्ते पर होने बाला व्यय पिछले वर्ष की तरह नहीं होगा (सारणी 10)।

- (¹⁸) स्रोत वार्षिक योजना 1976-77
- (13) इनमें राज्य विजली बोडों तथा राज्य सड़क परिवहन निगमो द्वारा जुटाये गये किलीय साधन सम्मिलत नहीं हैं।

सारणी 10 ' राज्य सरकारों का विकास एवं विकासेतर व्यय

(राणि करोड़ रुपको मे)

					(2000 100	14 41-11 11
	197	74-75 (लेखें)	(परि	1975-76 (शोधित मनुमान)	1976-77 (बजट भ्रनुमान)	
मवे	राशि	पिछले वर्ष की सुलना मे घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना मे षट-बढ़का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की सुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत
1		3	4	5	6	7
कुल व्यय (म + मा)	7890	+96	9278	17 6	10108	+8 9
म विकास स्थाय $(1+11)$ (1) सामाजिक भौर सामुदायिक सेवाए ($i1$) प्रार्थिक सेवाए	5 944 2649 32 95	+129	6934 3008 3926	+16 7 +13 6 +19 2	7466 3206 4260	$\begin{array}{c} +7 & 7 \\ +6 & 6 \\ +8 & 5 \end{array}$
मा विकासेतर व्यय (1-∤-11) (1) सामान्य सेवाएं (i1) मन्य	1946 1885 61	+0.6 -0.7 $+74.3$	2344 2283 61	+20 5 +21 1		0 + 127 0 + 125 + 197

ॐ इसमें राजस्थान के सदर्भ मे राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किये गये झितिरिक्त महंगाई भक्ते के कारण उत्पन्न सम्पूर्ण देयता सम्मलित है, उक्त देयता को विकास और विकासतेतर व्यथ के बीच श्रावटित नहीं किया जा सका क्योंकि श्रपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं है।

71. मंतिम बात यह है कि भितिरक्त राजस्य जुटाने के प्रयास में राज्यों ने कृषि क्षेत्र की कमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया है। कृषि क्षेत्र की भारी माला में भरकारी निवेण किये जाने से पिछले कृष्ठ वर्षों में काफी सहायता मिली थी परंतु राजस्य जुटाने में इस क्षेत्र का योगदान पहले की तरह नगण्य ही रहा है। (14) साथ ही सिचाई एव बिजली से संबंधिन परियोजनाओं की लागतों में काफी प्रधिक बढ़ोतरी हुई है। फिर भी मिसाई नथा बिजली की मुविधाओं से लाभान्वित होनेवालों को चाहिए कि वे उनकी लागतों में प्रपत्ता योगदान दे तथा बिकास परिच्या का परोक्ष रूप से वित्तपोषण करे।

मुद्रा ग्रौर ऋणनीतिः

72. मुद्रा नीति पहले की तरह समग्र रूप से प्रतिबधक ही रही। यह निस्नित्वित वातो से स्पष्ट हुमा: स्याज दरो का वर्तमान स्वरूप बना रहा, रिजर्व वैंक सामान्यतः प्रतिबधक वित्तीय सहायना देता रहा और वाणिज्य बैक ऋण के विवरण में अधिक मात्रा में अनुणासन का पालन करते रहे। साथ ही कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों की पूर्ति में प्रस्थाणित वृद्धि से ऋष्ण नीति से कुछ सीमा तक लचीलापन लाने की ग्रावक्यकताहुई। ग्रत: ग्रर्थव्यवस्था में उच्चतर वृद्धि वर लाने तथा साथ ही मुद्रागत नियंज्ञण के समग्र तंत्र को प्रायः भ्रपरिवर्तित बनाये रखने के उद्देश्य से 1975-76 की ऋण नीति बनायी गयी थी। निम्नलिखित मनुष्छेदीं में जिन विभिन्न उपायों की चर्चा की गयी है वे मुख्य स्थायिता को प्रभावित किये बिना ऋण नीति में जो लचीलापन लाया जा सका है उसके प्रमाण प्रस्तुत करते है। इस संदर्भ में निम्निमिखित तथ्य उदाहरण के लिये प्रस्तुत किये आने हैं: रिजर्व बैंक की महायता से वाणिज्य बैकों द्वारा भारी मात्रा में खाद्याओं की वसूली/संग्रहण का जिल्लायण किया गया. माजिन संबंधी भपेक्षामों तथा स्टाक संबंधी मानकों को चयनात्मक रूप से उदार बनाया गया तथा न्याज दरों के संबंध मे उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी।

ज्ञाणगीति : 1975 का कम कामकाज का समय

73. 1974-75 के अधिक कामकाज के समय की प्रतिबधक ऋण नीति बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तम के 1975 के कम कामकाज के समय के दौरान भी जारी रही । स्यूल रूप से इस बान पर जोर दिया गया कि रिजर्व बैंक से ली जाने वाली सहायता की माला को स्यूनतम रखक़र बैंक प्रपत्ने ही विसीय साधनों से ऋण विस्तार में अपना योगदान वे । इस प्रकार जो विशेष विधेकाधीन पुनिवत्त सेवाएं मंजूर की गयी थी (खाद्याओं की सार्वजिमक बमूली के लिये प्रवन्त सीमाओं को छोड़कर) उन सभी को इस प्रविध के अन्त में वापस ले लेना था। मान ग्रीर मीयादी देयताओं के 1 प्रतिशत की मूलभृत पुनिवत्त सीमाएं के सबंध में भी इन बात पर पुनः जोर दिया गया कि इस सीमा को केवल अनिवार्थ भीर अस्थायी परिचालन संबधी आवश्यकताओं तक ही मीमित रखा जाए। इस बात का भी संकेत दिया गया कि खाद्याओं की व्यूली के लिये दिये जानेवाले ऋणों के पुनिवत्त के संबंध मे बैंक श्रगले श्रीधक कामकाज के समय में उननी श्री सीमा तक सहायता की ग्रंपक्षा न करें। इसके अलावा बैंको से यह कहा गया कि व श्रपने कार्यकलाभो का इस प्रकार व्यवस्थित

करें कि समग्र रूप से वर्ष 1975-76 (मई---ग्रप्नैल) में उनका ऋण विस्तार जमा मंचयन के लगभग 63-64 प्रतिगत तक ही सीमित हो।

ऋण की प्रवृत्तियां : 1975 का कम कामकाज का समय

74. इस निर्धारित नीति के परिप्रेक्ष्य मे ग्रम ऋण की बास्तविक प्रवृत्तियों का संक्षेप में पुनरीक्षण किया जाए। कम कामकाज के समय के वौरान जमा राणियो में 1142 करोड़ रूपयों (9 5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले कम कामकाज के समय के दौरान उनमें 912 करोड़ रुपयो (8.8 प्रसिधन) की वृद्धि हुई थी (सारणी 11) । भ्रधिक मान्ना में जमा मंचयन होने के बावजूद बैंक रिजर्व बैंक से लिये गये धपने उधारों में केवल 38 करोड़ रुपये की कमी ला सके जब कि 1974 के कम कामकाज के समय के दौरान वे 270 करोड़ रुपयो की कमी लाये थे। इसका कारण यह था कि बैंक ऋण में काफी प्रश्लिक वृद्धि हुई । सकल बैक ऋण (पुन. भुनाई गई हुडियो महिन) में 543 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई --- यह वृद्धि भव तक किसी भी कम कामकाज के समय में हुई वृद्धि की सुलता में सर्वाधिक थी। खाद्याओं की सार्वजनिक वसूली के लिये दिवे गये ऋण में 173 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई जबिक 1974 के कम कामकाज के समय में उसमें 169 करोड़ रुपयो की गिरावट प्रायी थी। खाद्याको की वसूली को छोड़कर भन्य केली को दिये गये अग्निमो में 450 करोड़ रुपयो की जो बृद्धि हुई वह भी पिछले कम कामकाज के समय में हुई 298 करोड़ रुपयो की वृद्धि की तुलना मे अधिक थी । इसके परिणामस्वरूप इस अवधि के अन्त मे 70 6 प्रतिमत का जो ऋण-जमा अनुपात विद्यमान था वह पिछले कम कामकाज के समय के अनंत में विद्यमान 68.9 प्रतिशत के स्तर के मुकाबस्ते में अधिक था। वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात 55 प्रतिशत था।

ऋणनीसि : 1975-76 का प्रधिक कामकाज का समय

75. 1975-76 के प्रधिक कामकाज के समय की ऋषा नीति का उद्देण्य यह रहा कि विकास को बनाए रखने तथा निवेण को प्रोत्माहन देने के निमित्त ऋण संबंधी अनुशासन में कुछ सीमा तक लखीलापन लाया जाए परंतु साथ ही मुद्रास्फीनिगत ब्यावों के पुनरुद्भव को रोकने के मूल उद्देश्य में बाधा न पड़े। कृषिजन्य बस्तुओं के उत्पादन में प्रत्याणित वृद्धि नथा कृषि आधारित उद्योगों की आवण्यकनाओं को ध्यान में रखात हुए कुछ लखीलेपन के साथ स्थनात्मक ऋण नियंत्रणों की भ्रमल में लाया गया।

76 इस बात पर जोर दिया गया कि ग्राधिक कामकाज के समय के दौरान ऋणों में होने वाली बृद्धि की पूर्ति प्रमुख रूप से बैकों के प्रपने हीं विलीय साधनों से करनी होगी ग्रीर खाधाओं की वसूली के लिये दिये जानेवाले ऋणों को छोड़कर रिजर्व बैंक द्वारः दी जाने वाली सहायता न्यूननम होगी ग्रीर भनिवार्यतः अस्पायी स्वरूप की होगी। बैकों को उनके भ्रपने विलीय साधनों के वितरण के संदर्भ में यह स्वित किया गया कि वे निविष्ट किये गये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों पर विशेष व्यान दे। निवेश को प्रोरसाहत देने के निमिक्त बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे 13 प्रतिशत में अनिधक दर पर जिममें ब्याज-कर के लिये एक प्रतिशत भी सम्मितित है, तीन वर्षों से ग्रिधिक श्रविधों के लिए ग्रिपेक्षाहृत प्रधिक माला में मीयादी ऋण प्रवान करे। उसके बाद मध्याबधि ऋणों के संबंध में ब्याज कर से जो छूट दी गयी उसके कारण बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे सान वर्षों से ग्रव्यून ग्रविध्यों के लिये प्रदान किये गये वीर्षाविध ऋणों पर । अप्रैल, 1976 से 14 प्रतिशत ने ग्रनधिक दर पर व्याज लें।

विवेकाधीन विसीय सहायसा:

77. यह सुनिश्चित करने के लिये कि बैकी द्वारा रिजर्व बैंक से ली अनेवाली सहायता राशि तथा उपयोग की श्रवधि दोंगी दृष्टियों से

^{(14) 1975-76} में राज्य सरकारों को करों से जो राशि प्राप्त हुई उसमें भृ-राजस्य ग्रीर कृषि ग्राय-कर में प्राप्त राशि का ग्रंश केवल 6.2 प्रतिगत था । इसके भ्रलावा 1975-76 में विकास परिश्यय तथा विकास कार्यों के लिए श्रन्य पार्टियों को दियें गये ऋणों में भू-राजस्व ग्रीर कृषि ग्राय-कर से प्राप्ति रागि का श्रंश केवल 3 प्रतिणत था।

न्यूनतम है, पुनिबन्त/पुनर्भुनाई सुविधामों को पहले की अपेक्षा और अधिक विवेकाधीन बना दिया गया। वैकी को उनकी (सितंबर 1975 के अनिम गुक्रवार सक की) माग और मीयादी देयनाओं के एक प्रतिशत के बराबर की माता तक मलभून पुनिवन्त सीमा प्रदान की गयी। ऐसे पुनिवन्त नथा खाद्याओं की वसूली के लिये दिये जानेवाले पुनिविन्त सीमाओं की कुल राज की निश्चित दर पर ब्याज देय था। ऐसी पुनिविन्त सीमाओं की कुल राज 139 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, खाद्याओं की वसूली के लिये विये जानेवाले ऋण के मामले मे पुनिविन्त के स्वस्प में परिवर्तन लाया गया। बैंक खाद्याओं की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये जाने वाले ऋण

में 450 करीड़ रुपयो और 600 करीड़ रुपयो के बीच होने वाली वृद्धि के 50 प्रतिशत के पुनर्वित्त का दावा कर सकते थे। पहले यह राशि 300 करीड़ रुपयो और 450 करीड़ रुपयो के बीच थी। साथ ही पहले के 450 करीड़ रुपयों के स्थान पर 600 करीड़ रुपयों के बकाया स्तर से होने वाली वृद्धि के सबध में वे पूरे पुनर्विक्त का दावा कर सकते थे। यदि खाद्याओं की बसूली के लिये दिये जाने वाले ऋण की राशि 900 करीड रुपयों से अधिक हो तो रिजर्व भीक की सहायता के स्वरूप और मान्ना का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता थी।

सारणी 11 प्रमुक्तित बाणिज्य बैकों के ग्रांकड़ों में मौसमी घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपयो मे)

मदे	कम कामकाज का समय 1972	ग्रधिक कामकाज का समय 1972-73	कम कामका ज का समय 1973	ग्रधिक कामकाज का समय 1973-74	कम काम कोज कासमय 1974	ग्नधिक कामकाज का समय 1974-75	कम कामकाज का समय 1975	अधिक कासकाज का ममय 1975-76
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 कुल जमाराणिया .	. +705	+811	+899	+ 677		+ 784	- + 1142	
(क) मांग जमाराणिया .	(- -9 ,7) +262 (- -8 3)	(+10.2) +335 (+9.8)	+252	(+7.0) +407 (-1-10.2)	(+8 8) +298 (+6.8)	(+7.0) +316 (+6.7)	(+95) +434 (+87)	-}-395
(वा) मीयादी जमाराशियां .	+443	(+9.8) +476 (+10.5)	+647	- 270	+614 (+10 3)	(+7.1)	+70.8 (+10.1)	+823
2. भेक ऋण		+897 (+17.1)	+346	+1111	+129	 ~935	+623 (+72)	+1758
3 भारतीय रिजर्व बैंक मे पृत. भुनाई गयी हंडियां	. ——1		+15	+ 24 4		+ 59	-80	+44
4 सकल बै क ऋण (2+3) .	+ 57	+916 (+17.4)	+361	+1355	42	+994 (+12.7)	$+543 \\ (+6.1)$	+1802
5 खाद्याक्षों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋण	 1	-)- 6	58	+188	169	+316	+173	+876
6. खाद्येतर बैंक ऋण (25)	+68	+891 (+17.9)	+404 (+6.9)		+298 (+4.1)	+619 $(+8.3)$	(+5.6)	+888 (+10.4)
7 सकल खाद्येतर बैंक ऋण (45)	+ 58	+910 (+18.3)	+419	+1167 $(+18.5)$	+127 (+1.7)	+678 $(+8.9)$	370 + 4.5	+93 (- -10 8
8. निवेश	. +619	-}-4	+ 282	÷ 157	- - 172	- <u></u> ⊢165	+405	+39
(क) सरकारी प्रतिभृतिया	. +519	89	+187	- - -73	- - 349	+118	225	+ 34
(का) ग्रन्य अनुमोदिन प्रतिभृतिया	+100	-+ 93	+95	+81	+123	+ 17	+180	+ 4
 तकदी ग्रीर भारतीय रिजर्व बैंक के 								
पास जमा राणि	十57	+60	+444	213	+117	79	+63	 1
(क) नकदी	. + 27	+20	+ 25	+4	+ 25	+31	11	+
(ख) भारतीय रिजर्व बैक के पास								,
र्जमाराणि	. + 30	+ 40	+419	217	+ 92	110	+-74	- - 1 1
10. माग श्रोर श्रम्य सूचना पर प्रतिवेध								
राणि	· - + 13	+ 72	4 l	96	- -61	+ 25	9	+11
 भारतीय रिजर्भ बैक से लिये गये उधार 	-16	÷ 17	+56	+253	270	+183	38	+62
12. ऋषण जमा प्रनुपात , ्.	. 66 2	70.3	67 3	73 7	68 9	72.1	70.6	76.
13. खाद्याञ्च-ऋण जमा अन्पान को छोड़कर								
%मृण 		67.0	61,9	69 6		67 4	65.0	65,
14. निवेश जमा भ्रनुपान .	36 3	33.0	32 9	32 2	33 8	33 0	33.2	33.

78. ऊपर निर्विष्ट दो श्रेणियो को छोड़कर ग्रन्य सभी पुनिवत्त लागत तमा उपलब्धता के संदर्भ में केवल रिजर्ववैंक के विवेकपर ही प्रदान किये जाने थे । ऐसी वित्तीय सहायता पर लिये आनेवाने ज्याज की दर 11.5 प्रतिशत भीर 18 प्रतिशत के बीच थी। गुढ चलमुद्रा प्रतुपात के प्राधार पर दी जाने बाली पुनर्वित्त सुविधान्नों की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया । इसके बाद विवेकाधीन पुनर्जित्त निम्नलिखित बासों को विचार में लेते हुए प्रदान किया जाना था । वैंकों द्वारा नीति संबंधी उद्देश्यों का ग्रमुपालन, उनका ऋण जमा ग्रनुपान, निर्यात संबंधी कार्य, ऋण के वितरण में क्षेत्रीय प्राथमिकताए, भारतीय ग्रौद्योगिक विकास बैक, कृषि पूर्तिक्त ग्रौर विकास निगम ग्रौर मुद्रा बाजार से वित्तीय साधनों की उपलब्धता तथा ऐसे कोई श्रन्थ सध्य जो भ्रलग भ्रलग मामलों में महत्वपूर्ण है । ऐसे पुनर्वित्त का एक ध्रम प्रत्यक्षतः वैकों के निर्यात ऋष्ण संबंधी कार्यों के न्नाधार पर देना था तथा वह 11.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकता था । प्रारम्भ में मप्रैल 1976 के भ्रंत तक बैकों को कुल 73 करोड़ रुपयों की नियति पुनर्जित्त सीमाएं मंजूर की गयी; परन्तु बाद में उन्हें 1976 के कम कामकाल के समय के भ्रंस तक जारी रखा गया । विशेष परिस्थितियो को छोड़कर भन्य मामलों में ग्रब तक पैट्रोलियम कपनियो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का वित्तपोषण करने के लिये प्रदान की गयी सारी विशेष विवेकाधीन वित्तीय सहायता को समाप्त करने का भी निश्वय किया गया ।

79. वैंको के लिये उनके द्वारा खरीधी गयी तथा पुनः भूनाई गयी कुल हुंडियों (सितम्बर 1975 के अंतिम गुकवार तक) के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक वर पर मूलभूत हुंडी पुनर्भुनाई सीमा भी पहले की तरह मंजर की गयी। वैंकों को प्रतिरिक्त हुंडी पुनर्भुनाई सीमाये रिजर्व बैंक के विवेक पर 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच की ब्याज दरों पर उपलब्ध थीं। 30 अप्रैल 1976 तक प्रारम्भ में मंजूर की गयी कुल 155 करोड़ रुपयों की मूलभूत पुनर्भुनाई सीमायों को प्रक्तूबर 1976 के अन्त तक जारी रखा जारहा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने प्रप्रैल 1976 के अन्त तक गरी रखा जारहा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने प्रप्रैल 1976 के अन्त तक गरी रखा जारहा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने प्रप्रैल 1976 के अन्त तक जारी रखा गया। 1975-76 के प्रधिक कामकाज के समय के वौरान इस प्रकार जो सहायता प्राप्त की गयी उसकी कुल राशि 181 करोड़ रुपये थी जब कि 1974-75 और 1973-74 में उक्त राशि कमण: 191 करोड़ रुपये और 279 करोड़ रुपये थी।

80. पुनिवत्त का एक धन्य स्रोत गुल्कावापसी ऋण योजना 1976 (16) से संबंधित है जो 1 फरवरी से धनल में घायी है । इस योजना धनुसार बैंक निर्यातकों को सीमा गुल्क प्राधिकारियों द्वारा धस्यायी रूप से प्रमाणित मीमा गुल्क वापसी की उनकी पान्नताओं के धाधार पर धीतम मंजूरी घीर धदायगी होने तक भिषम प्रदान करेंगे श्रीर ऐसे श्रीमों पर रिजर्व बैंक पुनिवित्त प्रदान करेगा ।

ग्रस्य परिवर्तन

81. ऋण नियंत्रक उपायो को लागू करने में कुछ लक्षीलापन लाने के उद्देश्य से जो अन्य परिवर्तन किये गये उनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि वे बैक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में गठित अध्ययन दल की सिकारिणों के ऋमिक कार्यान्वयन का एक अंश है। पहली बात यह है कि ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व ऋण प्राधिकरण के संबंध में न्यूनतम सीमा को गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्टानों के लिये 1 करोड़ रुपयों के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि वहीं ऋणों और स्टाको पर नवस्बर 1973 में लागू किये गये अपिरिकत मार्जिनों को बापम ने लिया गया। सीसरी बात यह है कि नकदी ऋण सीमाओं के अप्रयुक्त अंग पर

वार्षिक 1 प्रतिशत का वायदा प्रभार लेने की प्रणासी को वापस ले सिया गया।

82. प्रर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों पर बराबर निगरानी रखी गयी और सूंगफली, खाद्यामों तथा मुक्त बिकी की चीनी के संवर्ध में चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में उचिन छूटें दी गयी। जूट, कागज, मोटर गाड़ियों के पुर्जी नथा सून की कताई मिलों जैसे उद्योगों द्वारा ध्रनुभव की गयी किनपय विशिष्ट समस्याम्रों के प्राधार पर उनको बैको द्वारा दिये जाने वाले प्रिप्रमों के लिये निर्धारित स्टाक संबंधी मानकों में भी छूट दी गयी।

व्याज दर की उच्चतम सीमा

83. ग्रधिक कामकाज के समय के दौरान पायी गयी ऋण की प्रवृत्तियों की समीक्षा करने के पहले भालोच्य मौसम के बौरान अ्याज दर विन्यास को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख सुधार भ्रमल में लाया गया उस पर प्रकाण डालना भावण्यक है। जहां रिजर्व बैंक ने भनुसूचित वाणिज्य बैकों द्वारा भ्रपने भ्रप्रिमों पर ली जानेवाली न्युनतम ब्याज वर निर्धारित की थी वहां निर्यात ऋण की कतिपय श्रेणियों को छोड़-कर ग्रन्य मामलों में श्रव तक कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नही की गयी थी । इसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में बैक बहुत ग्रधिक ऊंची दरों पर ब्याज लेते ह्या रहे थे। उदारण के लिए यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि कुल बैक का ऋण लगभग 15 प्रतिशत ग्रंग 16 प्रतिशत से भी प्रधिक ब्याज दरों पर प्रदान किया गया । कई मामलों में ऐसी ऊंची क्याज दरों से छोटे ऋणकर्तामी त्रभावित हुए । झतः ब्याज दरों में उचित समानता लाने के निमित्त ब्याज दर विन्यास में परिवर्तन लाने की मावश्यकता थी । ग्रनः मनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ली जाने वाली भ्रधिकतम क्याज दर 15 मार्च 1976 से 16.5 प्रतिशत (इसमें ब्याज से होने वाली भामवनी पर लिया जाने वाला कर सम्मिलत है) निर्धारित की गयी । जिन बैंकों की मांग ग्रीर मीयादी देयताएं 25 करोड़ रुपयो भीर 50 करोड़ रुपयों के बीच थी उनके लिए 17.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी । 25 करोड़ रुपयों से कम मांग भीर मीयादी देयताओं वाले बैंकों को उच्चतम सीमा से छुट दी गयी । परन्तु चयनात्मक ऋण नियंक्षणों के अन्तर्रत माने वाले पण्यों से संबंधित मनियमित खातों मौर मग्रिमों पर ली जाने वाली दंडस्वरूप ब्याज वरों की ब्याज-दर की उच्चतम सीमा के क्षेत्र से बाहर रखा गया।

भूग की प्रवृत्तिया : 1975-76 का ग्रधिक कामकाभ का समय

84. 1975-76 के अधिक कामकाज के समय के दौरान संकल्प ऋण (पुन: भुनाई गयी हुंडियों सहित) में 1802 करोड़ रूपयों या 19,2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले प्रधिक कामकाज के समय के दौरान उसमें 994 करोड़ रुपमो या 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी 11 देखें) । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1975 के कम कामकाज के समय के दौरान ऋण में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, इसके ग्रलामा 1975-76 के ग्रधिक कामकाज के समय में काफी श्रधिक माल्रा में वृद्धि हुई जिसका प्रमुख कारण यह था कि खाद्याक्षी की सार्वजनिक बसूली के लिये विये गये ऋण में भारी माक्रा में वृद्धि हुई ग्रयीत् 1974-75 के अधिक कामकाज के समय में उसमें हुई 316 करोड़ रुपयों की बुद्धि के मुकाबले में इस प्रविध में 870 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई । खाद्याओं की वसूली के लिये दिये गये ऋण को छोड़कर सकल ऋण में 932 करोड़ रुपयों (10.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जब कि 1974-75 की ध्रवधि में उसमें 678 करोड़ रुपयों (४.9 प्रतिशत) की बुद्धि हुई थी। जमाराशियो में हुई 9.2 प्रतिशत की बृद्धि भी पिछले ग्रधिक कामकाज के समय में पायी गयी 7.0 प्रतिशत की वृद्धि के मुकायले में प्रधिक थी । 1974-75 के प्रधिक कामकाज के समय की तरह इस प्रवधि में भी जमाराशियों में हुई

⁽¹⁵⁾ इस योजना के विवरण इस रिपोर्ट के भाग II में दिए गए हैं।

घ्रिक्षिणांग वृद्धि मीयावी जमारागियों में पायी गयी। ध्रिक्षिक ऋण विस्तार के कारण 1975-76 के ध्रिष्ठिक कामकाज के यमय के ध्रन्त में विद्यमान 76.9 प्रतिशत का ऋण-जमा ध्रमुपात एक वर्ष पहले के 72.1 प्रतिशत के मुकाबले में काफी घ्रिष्ठिक था।

85. रिजवं बैंक से दी जाने वाली महायता (पुनिवल प्रीर पुनर्भृनाई दोनों प्रकार से) की राणि में आलोच्य अधिक कामकाज के समय के दौरान 671 करोड़ रुपयों की बृद्धि पायी गयी जब कि पिछले अधिक कामकाज के समय में उसमें 242 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। अधिकाण वृद्धि संपूर्णतः खाद्याओं की वसूली के लिये विये गये अहण (509 करोड़ रुपये) में हुई। रिजर्य बैंक से ली जाने वाली कुल सहायता की राणि इस अधिक कामकाज के समय के दौरान 1063 करोड़ रुपयों के णिखर स्तर पर पहुंच गयी। इसमें से खाद्याओं की सार्वजनिक वसूली के लिये विये गये अहण के पुनिवन की राणि 787 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार 1975-76 के शिखर स्तर की उक्त राणि 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के 656 करोड़ रुपयों के णिखर स्तर की अधिक कामकाज के समय के 656 करोड़ रुपयों के णिखर स्तर की अधिक कामकाज के समय के 656 करोड़ रुपयों के णिखर स्तर की अधिक कामकाज के समय के 656 करोड़ रुपयों के णिखर स्तर की अधिक कामकाज के समय के 656 करोड़ रुपयों जब कि एक वर्ष पहले उक्त राणि 413 करोड़ रुपये थी।

समप्र मूल्यांकन : 1975-76

86. जुलाई 1975 से जून 1976 तक के वर्ष को समग्र रूप से देखने पर यह तथ्य सामने भाना है कि इस वर्ष के दौरान बैक ऋण में हुई वृद्धि पिछले वर्ष हुई। वृद्धि से दुगुनी से भी ऋधिक थी। बैंक ऋण में पिछले वर्ष इसी प्रविध के दौरान हुई 1097 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबसे में 2509 करोड़ रुपयो की वृद्धि पायी गयी । पुनः भुनायी गयी हडियो को मिलाकर पिछले वर्ष जहां 955 करोड़ ६पयो की वृद्धि हुई थी वहां इस वर्ष 2521 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी। खाधान्नों की वसूली के लिये दिये गये ऋण को छोड़कर सकल ऋण में इस वर्ष 1131 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष इसी घवधि के दौरान ग्रमेक्साकृत बहुत कम ग्रथीत् 683 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी । कुल जमाराशियों में जहां पिछले वर्ष 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां इस वर्ष 20.0 प्रतिमान की वृद्धि हुई ग्रीर पिछले वर्ष की तरह ही अधिकांश वृद्धि मीयादी जमाराशियों में हुई । रिजर्व बैंक से ली जाने वाली सहायता (पुनर्भुनाई ग्रौर पुनर्वित——दोनों प्रकार से) में 498 करोड़ रुपयो की वृद्धि पायी गयी जब कि 1974-75 की इसी श्रविध में उसमें 289 करोड़ रुपयों की गिरावट मायी थी । 25 जुम 1976 को ऋष्ण-जमा-भ्रनुषात बढ़कर 76.1 प्रतिशत हो गया जब कि एक वर्ष पहले यह भ्रनुषात 71.4 प्रतिशत या।

ऋण का क्षेत्रीय बितरण : 1975-76 का मधिक कामकाज का समय

87. 1975-76 के अधिक कामकाज के समय में जो ऋण प्रवान विध्या गया उसके क्षेत्रीय वितरण का विक्रनेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ष मकल बैंक ऋण की वृद्धि मे खाद्याओं की बसूली के लिये दिये गये ऋण का समय 49.4 प्रतिशत था जब कि 1974-75 के अधिक कामकाज के समय मे यह भ्रम 31.2 प्रतिशत था (सारणियां 12 भीर 13)। खाद्याओं की वसूली के लिये विये गये ऋण को छोड़कर सगभग मारी वृद्धि निजी क्षेत्र में हुई। खाद्येतर ऋण में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को विये गये ऋण का अंग 37.6 प्रतिशत था (1974-75 के अधिक कामकाज के समय मे 28.7 प्रतिशत था)। नियति ऋण में 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के दौरान जहा सीमान गिरावट पायी गयी थी वहां इस वर्ष खाद्येतर ऋण में हुई वृद्धि में उसका श्रम लगभग 24.1 प्रतिशत था।

ऋणनीति : 1976 का कम कामकाज का समय

88. 1975-76 के अधिक कामकाज के समय के अन्त में 1976 के कम कामकाज के समय के लिये घोषित ऋण नीति में ध्रव तक श्रपनायी गयी प्रतिबंधात्मक नीति की दृष्टि से कोई विशेष भन्तर परिलक्षित नही हुन्ना । इस नीति में वास्तविक उत्पादन में होने वाली प्रत्यक्ष वृद्धि के बनुरूप वैंक ऋण उपलब्ध कराये आने ग्रौर मृल्यों पर गंभीर दक्षाव डाले बिना उत्पादन बढाने के लिये महायता प्रदान किये जाने पर जोर दिया गया । खाद्यान्न संबंधी पुनर्विन के सिद्धांत में किये गये संशोधन को छोड़कर रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली विसीय सहायता की सामान्य विशेषनाएं भ्रपरिवर्तिस ही रही । नये सिद्धांत के भन्तर्गत बैंकों से यह प्राप्ता की जाती है कि वे अपने ही साधनों से खाद्याओं की सा**र्वजनिक** वसूली के लिये प्रपेक्षित ऋण की पूर्ति 800 करोड़ रुपयों के प्रक्षिकतम स्तर तक करे। खाद्याओं को वसूली के लिये दिये जाने वाले ऋषामें 800 करोड़ रूपयों के स्तर से प्रधिक यृद्धि होने पर उस युद्धि का एक तिहाई। पुनर्वित्त बैंको को मिल सकता है । खाधान्नो की सार्वजनिक बसूली निर्यातों भौर उत्पादन की भनिवार्य भावप्यकताश्रों को पूरा करने के लियें बैंको को मक्षम बनाने के निमित्त रिजर्व बैंक पहले की तरह ही चयनात्मक और प्रावश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

तारणी 12: सकल बैंक ऋष का क्षेत्रीय वितरण (भारतीय रिजर्थ बैंक में पुनः भुनायो गयी हुंडियों को मिलाकर)

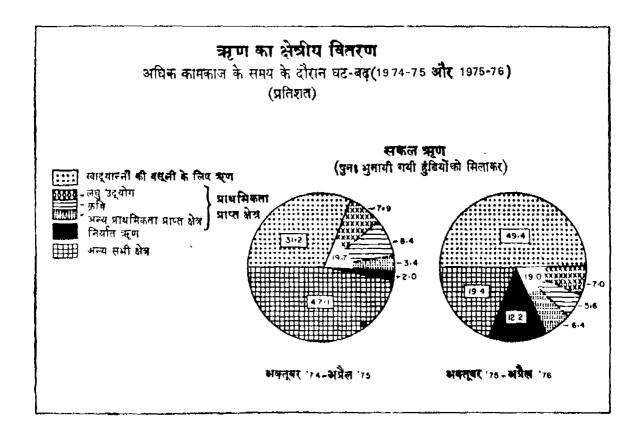
(राशि करोड़ रुपयों में)

मदें	•	श्रधिक कामका	जकासमय 1	974-75	मधिक कामकाण का समय 1975-76			
74		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	সৌত্	सरकारी क्षेत्र	मिजी क्षेत्र	जोड़	
1		2	3	4	5	6	7	
1, खाद्यान्नों की सर्विजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋण .		+306 (68.1)	_	+306 (31.2)	+864 (101.3)		+864 (49,4)	
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (इ.स.क्षेत्र को प्रदत्त निर्यात ऋण सहित)	•	+8 (1.8)	+186 (34.7)	+194 (19.7)	+1	+332 (37.0)	+333 (19.0)	

							-		
1				2	3	4	5	6	7
(क) सम्बद्धोग .	•			t (0-2)	├ 77 (14 4)	+78 (7 9)	2	+124 (13.8)	+122 (7.0)
(सा) कृषि		•	•	- - 7 (1.6)	+76 (14.2)			(10,9)	- 98 (5,6)
(ग) भ्रन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र									
3. ग्रन्य सभी क्षेत्र* (इन क्षेत्रों को प्रदत्त	निर्यात ऋण महित)			+132 (29.6)	+33 (6.1) $+350$ (65 3)		+3 (0.4) -12	-\ 110 (12 3) -\ 564 (63.0)	-113 (6 4) -+552 (31.6)
4 खाद्ये तरऋण (2+3) .		•	,		+536 (100.0)		11	+896 (100.0)	+ 885 (50.6)
5. मद 4 में से-—निर्यात ऋण		•	•	~ - 9 (2.0)	22	13	+6 (0 7	+207 (23.1)	+213 (12.2)
6 कुल सकल ऋण (1+4) .				+446 (100 0)	+536 $(100 0)$	+982 (100 0)	+853 (100.0)	+896 (100.0)	+1749 (100 0)

टिप्पणियां :-- 1 कोष्ठकों में दिये गये यांकड़े सकल बैंक ऋण में प्रनुपातों को दर्शाते हैं।

2 1975-76 के श्रीकड़े उन बैंको मे प्राप्त किये गये श्रांकड़ों पर श्राधारित हैं जिनका श्रंश कुल बैंक ऋण में 92.1 प्रतिशत है। *इनमें बड़े तथा मझौले उद्योग श्रीर थोक व्यापार शामिल है।



त्तारणी 13: बकाया सकल वैक ऋण का क्रेज़ीब विसरण (भारतीब रिश्तर्व वैक में पुनः जुनायी गयी हृष्टियों सहित)

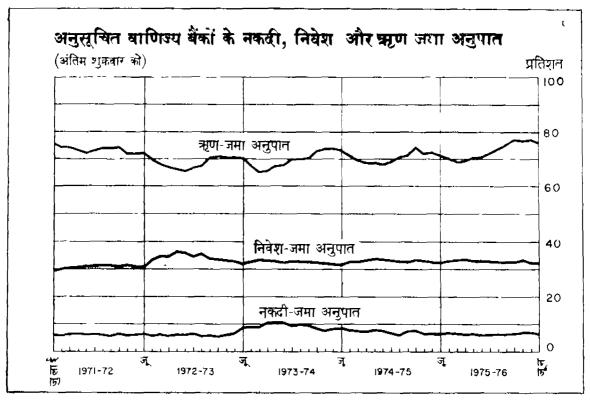
(राणि करोड़ दपयों में)

	25 सप्रैस	1975 को		30 भन्नेल 1976 को			
मवें	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	<u> সৌষ্</u>	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	
1. खाद्याक्षों की सार्वजनिक बसूली के लिये विधे गये ऋण	564.1		564.1 (6.4)	1572.8 (54.5)		1572.8 (14.3)	
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (इस क्षेत्र को प्रवस निर्मात ऋण सहित)	. 149.8	2000.3	2150.1	142.6	2630,1	2772.7	
	(8.9)	(28.2)	(24.5)	(4.9)	(32.5)	(25.3)	
(क) लघु उद्योग	. 7 7	1035.2	1042.9	8.6	1179.6	1188.2	
	(0.5)	(14.6)	(11.9)	(0.3)	(14.6)	(10.8)	
(অ) চুবি	. 136.4	648.6	785.0	125.1	916.6	1041.7	
	(8.1)	(9.1)	(8.9)	(4.3)	(11.3)	(9.5)	
(ग) घन्य प्राथमिकना प्राप्त क्षेत्र	. 5.7	316.5	322.2	8.9	543,9	542, 8	
	(0 3)	(4.5)	(3.7)	(0.3)	(6.6)	(4.9)	
3. ग्रस्थ सभी क्षेत्र* (इन क्षेत्रों को प्रदत्त निर्यात ऋण सिधृत)	. 970.5	5101.8	6072,3	1170.5	5450,6	6621,1	
	(57.6)	(71.8)	(69.1)	(40.6)	(67.5)	(60.4)	
4. बाचे तर ऋण (2+3)	1120.3	7102,1	8222, 4	1313, 1	8080.7	9393.8	
	(66.5)	(100.0)	(93.6)	(45.5)	(100.0)	(85.7)	
5. मद 4 में से निर्यात ऋण	. 90.1	659.3	749.4	72.4	908.6	981.0	
	(5.4)	(9.3)	(8.5)	(2.5)	(11.2)	(8.9)	
6. सकल बैंक अध्य (1 4)	. 1684.4 (100.0)	7102.1 (100.0)	8786.5 (100.0)	2885.9 (100.0)	8080.7 (100.0)	10966.6	

टिप्पणियाँ: 1---1976 के मांकड़े उन बैंकों से प्राप्त मांकड़ों पर माधारित हैं जिनका मंग कुल बैंक ऋण में 98.0 प्रतिशत है।

2. कोष्ठक में दिये गये प्रांकदे सकल बैंक अध्य में धनुपातों को दशति हैं।

^{*} इन में बड़े तथा मझौले उद्योग ग्रीर थोक व्यापार शामिल हैं।



ऋण की प्रवृत्तियाँ : 1976 का कम कामकाण का समय

89 1976 के कम कामकाज के समय (16 जुलाई 1976 तक) में बाराक्षों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋणों में भौर वृद्धि पायी गयी । खाद्याक्षों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋणों की राणि में 647 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि 1975 की इसी अवधि में उसमें 187 करोड़ रुपयों की वृद्धि थी। खाद्यात्रो की वसूली के लिये दिये गये ऋष्ण की बकाया राशि 9 जुलाई को 2283 करोड़ रुपयो के **प्रा**भृतपूर्व स्तर पर पहुंच गयी । 1976 के कम कामकाज के समय (16 जुलाई तक) में खादोतर बैंक ऋणों में 132 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि 1975 के कम कामकाज के समय में उसमें 16 करोड़ रुपयों की बुद्धि हुई थी । सकल ऋण की राणि में 1975 के कम कामकाज के समय में हुई 154 करोड़ रुपयों की युद्धि के मुकाबले में इस प्रविध मे 800 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इस प्रकार रिजर्व -वैंक द्वारा प्रदान की गयी सहायता से वाणिज्य वैंक खाद्यान्नों की वसूली के प्रयासों का विद्यापोषण कर सके। रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों की राशि 19 मार्च 1976 को 887 करोड़ रुपयों के पिछले शिखर स्तर को पार कर 9 जुलाई को 1104 करोड़ क्पयों के स्तर पर पहुंच गयी : इसमें से खाद्याओं की सार्वजनिक वसूली के लिये प्रवत्त पुनर्वित्त की राशि 976 करोड़ रुपये थी। रिजर्व बैंक से ली गयी कुल सहायता की राणि 16 जुलाई 1976 को 1075 करोड़ रुपये थी अब कि 1975-76 के श्रधिक कामकाज के समय में उक्त राशि 1063 करोड़ रुपयों के शिखार स्तर पर थी। कुल जमाराशियों में जहां पिछले कम कामकाज के समय में 715 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई यहां इस प्रविध में 942 करोड़ रुपयों की युद्धि हुई । इस वृद्धि का म्रिकांश भाग मीयादी जमाराशियों में पाया गया । ऋण जमा भ्रनपात 77.2 प्रतिशत या जब कि एक वर्ष पहले यह प्रनुपात 69.7 प्रतिशत था। खाधान्नों की नसूली के लिये विये गये ऋण को छोड़कर उक्त अनुपात पिछले वर्ष के 63.7 प्रतिशत से कम अर्थात् 62.4 प्रतिशत रहा ।

90. मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए कम कामकाज के समय के दौरान संवेदनशील पण्यो की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती रही, रुई और तिलहनों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को मजबूत बना विया गया।

मुद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियाँ

91. मुद्रा उपलिधि की प्रवृत्तियों में अहण नीति के इस चयनात्मक उवारीकरण का प्रभाव परिलक्षित होता है : 1975-76 (जुलाई—जून) के दौरान जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में 1375 करोड़ रुपयों या 11.3 प्रतिमत की वृद्धि पायी गयी (सारणी 14) । यद्यपि 1974-75 में हुई 737 करोड़ रुपयों या 6.4 प्रतिमत की वृद्धि से इस वर्ष हुई वृद्धि काफी भिधिक थी, फिर भी यह ध्यान रखना चाहिये कि वह वृद्धि 1971-72 से 1973-74 तक के तीन वर्षों की भ्रविधि के

दौरान पानी गयी 15 प्रतिगत की ग्रौसत वार्षिक वृद्धि वर से बहुत कम थी। ग्रिधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1975-76 के दौरान भीर उसके पूर्व वर्षों में मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि के स्वरूप में गुणात्मक भन्तर विद्यमान है : 1975-76 के दौरान जहां उक्त वृद्धि के साथ साथ बास्तविक राष्ट्रीय ग्राय में भी 5.5 प्रतिगत की वृद्धि हुई वहां 1973-74 को छोड़कर पिछले वर्षों में उक्त वृद्धि तब हुई थी जब राष्ट्रीय ग्राय बिल्कुल स्थिर रही । मुद्रा उपलब्ध की वृद्धि के कारण भून तत्वों में ग्रौर भी ग्रधिक महत्वपूर्ण गुणात्मक भ्रन्तर विद्यमान है । उक्त तत्वों पर भ्रागे विचार किया जाता है ।

92. 1975-76 में प्रारक्षित मुद्रा या घाधिक णिक्तणाली मुद्रा (18) में भी 681 करोड़ रुपयों की उल्लेखनीय बृद्धि हुई जब कि 1974-75 में उसमें काफी कम प्रधात् 82 करोड़ रुपयों की ही बृद्धि हुई थी। इसमें से जनता के पाम 590 करोड़ रुपयों की चलमुद्रा विद्यमान थी जब कि बैंकों की प्रारक्षित निधियों का ग्रंग केवल 110 करोड रुपये था। पिछले वर्ष चल मुद्रा में बहुत कम धर्यात् 104करोड़ रुपयों की बढ़ोनरी हुई थी भीर बैंको की प्रारक्षित निधियों में 39 करोड़ रुपये की वास्तविक गिराबट ग्रायी थी (सारणी 15)।

93. मुद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियों पर पुनः हम विचार करें : उसके वो घटकों में से जमा रकम में जहां इस वर्ष 785 करोड़ रुपयों या 14.3 प्रतिशत की काफी प्रधिक वृद्धि पायी गयी वहां पिछले वर्ष उसमें 633 करोड़ रुपयों या 13.1 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी थी । इसी प्रकार जनना के पास चलमुद्रा में भी 590 करोड़ रुपयों या 8.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई जो कि 1974-75 में हुई 104 करोड़ रुपयों या 1.6 प्रतिशत की वृद्धि से पांच गुणा से भी प्रधिक थी । ऐसा प्रतीत होता है कि रिजर्व कैंक द्वारा खाद्याओं की वसूली के लिये प्रधिक माला में विये गये पुनिवित्त और रिजर्व कैंक का रिवेशी धास्तियों में हुई प्रभृतपूर्व वृद्धि के कारण प्रालोच्य थयें में चलमुक्षा में भारी वृद्धि हुई ।

94. स्थूल मुद्रा या कुल मुद्रागत साधनों (17) की प्रवृत्ति की यह भी विशेषता थी कि इससे चलमुद्रा का तीन्न गति से विस्तार हुआ । इस वर्ष कुल मुद्रागत साधनों में 3103 करोड़ रुपयों या 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 1974-75 में हुई वृद्धि से 1143 करोड़ रुपये प्रधिक थी : चलमुद्रा का जो विस्तार हुआ वह ऊपर उल्लिखित मुद्रा उपलब्धि में हुई तीन्न वृद्धि भीर मीयादी जमाराशियों में तेजी से हुई बढ़ोतरी का संयुक्त परिणाम था (सारणी 14)।

⁽¹⁶⁾ ग्रधिक शक्तिशाली मुद्रा में जनता के पास रहनेवाली चलमुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की प्रारक्षित निधियाँ ग्रौर ग्रन्य जमा-राशियाँ शामिल हैं।

⁽¹⁷⁾ स्थूल मुद्रा या कुल मुद्रागन साधनों में जनता के पास मुद्रा उपलब्धि स्रौर वैंकों के पास विश्वमान सीयादी जमाराशियाँ शामिल है।

सारणी 14: मुद्रा जपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियाँ (वार्षिक)

(राशि करोड रुपयों में)

				(रतारा ग)रा क व पया म <i>)</i>
मर्थे -	निम्नलिखित वर्ष	ों में जून के म्रंत में ब	हाया राशि	घट-बढ़	
***	1974	1975	1976€	1974-75	1975-76
1	2	3	4	5	6
प्र. जनता के पास मुद्रा उपलब्धि $(1\!+\!2)$.	11,450	12,187	13,562	+737 (+6.4)	+1,375 $(+11.3)$
1. जनता के पास चलमुद्रा	6,603	6,707	7,297	+104 (+1.6)	+590 $(+8.8)$
2. जमा रकम@	4,847	5,480	6,265	+633 (+13.1)	+785 $(+14.3)$
ा. मुद्रा उपलब्धि की घट-बढ़ को प्रभावित करने वाले तत्व $(1+2+3+4+5)$					
$_{1.}$ वैंकों द्वारा सरकार को दिया गया मुद्ध ऋण (क $+$ ख)	9,102	10,506	10,779	+ 1,404	+273
(क) रिजर्व बैक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण	6,570	7, 5 1 5	7,256	+945	259
(ख) प्रन्य बैकों द्वारा मरकार को वियागया ऋण	2, 5 3 2	2,991	3,524	+459	+ 533
2् बैंको द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण (क 🕂 ख) * .	10,014	11,277	13,874	+ 1,263	+ 2,597
(क) रिजर्व बैंक द्वारा नाणिज्य क्षेत्र को दियागयाऋरण .	652	625	740	27	+115
(स्त) ध्रन्य बैंको द्वारावाणिज्य क्षेत्र को दियागयाऋर्ण .	9,362	10,652	13,134	+ 1,290	+ 2,482
 वैकिंग क्षेत्र की एक विदेशी सुद्रा धास्तियाँ 	672	310	1,279	362	+969
 अनता के प्रति सरकार की शुद्ध मुद्रा देयताएँ 	521	5 54	550	+ 33	4
5 वैंकिंग क्षेत्र की मृद्रेतर देयताएँ (क — ख — ग)	8,859	10,460	12,921	+1,601	+ 2,461
ॄं(क) बैंको के पास मीयादी जमाराशियाँ	6,459	7,682	9,411	+1,223 $(+18.9)$	+1,728 $(+22.5)$
(ऋ) भारतीय रिजर्व बैक की गुद्ध मुद्रेतर देयताएँ .	1,474	1,957	2,451	+ 483	+ 494
्र(ग) भ्रविशिष्ट	926	821	1,059	1 0 5	+ 238
इ. कुल मुद्रागत साधन (अ.—ंग्रा 5 (क)]	17,909	19,869	22,972	+1,960 (+10.9)	+3,103 (+15.6)

टिप्पणी : कोष्टकों में दिये गये झांकड़े घट-बढ़ के प्रतिशत को दशति हैं।

@भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान ग्रन्थ जमाराशियों की मिलाकर । £ग्रनंतिम ।

सारणी 15 : मुद्रागत प्रमुपास

	क्षे (जुलाईअ	्न)		बैंकों की प्रारक्षित नििंघयां\$	चल मुद्रा	भारतीय रिजर्व बैंक के पास भन्य जमाराशियौँ	_	प्रारक्षित धन 2 十 3) + 4)	ा मुद्रा उपलब्धि (3+4 +5)	मीयादी जमा- राणियाँ	कुल मुद्रागत साधन (७- - ७)	मुद्रा उपलब्धि में चलमुद्रा	मुद्रागत साधनों में चलमुद्रा
	1		·	2	3	4	5		6 7	8	9	10	11
~~~~~~ तिम शुक्रवार को बद करोइ/रुपयें)	 जया राशि		·		······································		<del>~</del>				मीसत	ध <b>नु</b> पात (!	प्रतिशत)
1971-72				560	4979	66	3478	5604	8523	4476	12999	58.4	38.3
1972-73				873	5829	41	4092	6743	9962	5491	15454	58.5	37.7
1973-74				933	6603	47	4800	7584	11450	6459	17909	57.7	36.9
1974-75				894	6707	65	5415	7666	12187	7682	19869	55.0	33.8
1975-76*				1004	7297	46	6219	8347	13562	9411	22972	53.8	31.8

^{*}घनंतिम

^{*}इसमें सरकारी क्षेत्र के उक्कमो और राज्य सरकारों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किये गये अग्निम शामिल हैं।

^{\$}बैंकों के पास रहने वाली नकवी और भारतीय रिजर्ब बैंक के पास रहने वाली बैंकों की जमाराशियाँ शामिल हैं।

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पिछले वर्षे की तुलना में वृति (करोड़ वपये)	K.	_ <b>_</b>					·····				·		मनुपास प्रतिमत)
1971-72		•		148	388	34	639	569	1061	816	1877	36.6	20.7
1972-73				313	850	25	614	1139	1439	1015	2455	59,1	34.6
1973-74		,		60	774	7	708	841	1488	968	2455	52.0	31, 5
1974-75				39	104	18	615	82	737	1223	1960	14.1	5 3
1975-76*			•	110	590	1 <b>9</b>	804	681	1375	1729	3103	42.9	19.0
<b>एक वर्ष में हुई भट-बढ़ का</b> म	तिशत												
1971-72				35.9	8.5	106.3	22.5	11.3	14.2	22.3	16.9	)	
1972-73				55.9	17, 1	39.4	17.7	20.3	16.9	22.7	18.9		
1973-74		•	i	6.9	13.3	17.5	17.3	12.5	14.9	17,6	15.9		
1974-75		•		4.2	1.6	38.3	12.8	1.1	6.4	18 9	10.8		
1975-76*			•	12.3	8.8	22.6	14.8	8.9	11.3	22.5	15.6		

थनंतिम

95. 1975-76 में मुद्रा उपलब्धि की अधिक वृद्धि का स्पष्टीकरण मुद्रा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों की प्रवक्तियों से मिल सकता है। इन सत्बों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा झास्तियाँ और बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया जानेवाला ऋष्ण को महत्वपूर्णकारणभूत तस्व थे। बैंकिंगक्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा मास्तियों में 969 करोड़ दुपये की उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी । 1974-75 में इन धास्तिमों में 362 करोड़ रुपयों की वास्तविक गिरावट हुई। थी । जिस सीमा तक विवेशी मुद्रा भ्रास्तियों को मुद्रा स्टाक में स्थायिता माने वाला तत्व भाना जा सकता है उस सीमा तक यह स्वीकार किया आ सकता है कि यह तत्व 1975-76 में परिलक्षित मुद्रागत विस्तार की काफ़ी द्राधिक दर में गिरावट लाने वाला है। वैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गमे ऋण प्रक्रिक महत्त्वपूर्ण प्रशासामी तत्त्व हैं। इस वर्ष वैकी द्वारा प्रदान किये गये ऋणों में 2597 करोड़ रुपयों की पृद्धि पायी गयी जी 1974-75 में हुई वृद्धि के मुकाबले में 1334 करोड़ रुपये अधिक थी। बैंकों द्वारा वियो गमे ऋण की कुल वृद्धि में से 96 प्रतिशत वृद्धि वाणिज्य वैंकों झीर सहकारी बैंकों द्वारा विथे गये ऋण में भीर शेष वृद्धि रिजर्व वैंक द्वारा वियों गये ऋषा में हुई। इस संदर्भ में भी फुल बेंक ऋषा में हुई वृद्धि मे से गुणवत्ता की दृष्टि से 1975-76 में प्रधिकतर भयति 56 प्रतिशत ध्रम क्षाद्याक्षों के लिए प्रदान किये गये ऋषा में पाया गया जब कि 1974-75 में उक्त मंश 21 प्रतिशत था। जमाराशियों में भारी माना में हुई वृद्धि (¹⁸) के कारण वैंक इस स्थिति में थे कि रिजर्ववैं वैंक से ऋण लेने के बजाय वे भ्रपने ही साधनों से काफी मधिक मान्ना में ऋणों में वृद्धिः कर सकें। इसके परिणामस्बरूप इस तस्ब का मंभाज्य मुद्रास्कीतिगत प्रमाव कुछ सीमा तक सीमित हो गया।

96. मुद्रा उपलब्धि पर बैकों द्वारा सरकार को विये गये मुद्ध ऋण का प्रभाव 1975-76 में अपेक्षाकृत कम था : बैकों द्वारा सरकार को विये गये मुद्ध ऋण में पिछले वर्ष की 1404 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले में 273 करोड़ रुपयों की वृद्धि कुई ! इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी बितरणों के संवर्ष में अधिक माला में आफा राजस्व और बिदेशी सहायता से आफा राजिस्व गौर

को विमे गर्मे शुद्ध ऋण में 1974-75 में पामी गर्मी 945 करोड़ रुपयों की वृद्धि के विपरीत इस वर्ष 259 करोड़ रुपयों की आस्तविक गिरावट परिलक्षित हुई ।

97. मुद्रा उपलब्धि में कमी लानेवाली मुद्रेशर देयताओं में से बैकों के पास विद्यमान मीयादी जमाराशियों में 1729 करोड़ रुपयों या 22.5 प्रतिशत की बृद्धि परिलक्षित हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 1223 करोड़ रुपयों या 18.9 प्रतिशत की बृद्धि हुई थी। इस प्रकार ये जमाराशियाँ मुद्रा उपलब्धि की बृद्धि को सर्वाधिक नियंजित करने वाले तस्त्रों के रूप में सिद्ध हुई।

## मौसभौ प्रवृत्तियाँ

#### 1975 का कम कामकाज का समय

98. दो परंपरागत मौसमों धर्णात् कम मामकाज के समय और धर्धिक कामकाज के समय के दौरान जो प्रवित्तयों वृष्टिगत हुई उन पर ग्रंब संक्षेप में विवार किया जाए। 1975 के कम कामकाज के समय में जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में 286 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी जब कि पिछले कम कामकाज के समय में इसके विपरीत 150 करोड़ रुपयों की गिराधट हुई थी। 1969 के बाद 1974 के एकमाल प्रप्याद की छोड़कर यही संभवतः पहला वर्ष है जब इस प्रकार की ध्रसामयिक प्रवृत्ति पुनः प्रकाण में ग्रामी। उक्त वृद्धि माँग जमारागियों में हुई 415 करोड़ रुपयों की वृद्धि के कारण हुई जब कि चलमुद्रा में 129 करोड़ रुपयों की गिराबट पायी गयी। उक्त वृद्धि मुक्य रूप से बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को विये जानेवाले ऋण और बैंकों द्वारा सरकार को विये जाने वाले सुद्ध ऋण के कारण हुई। इन योंनों में क्रमशः 627 करोड़ रुपयों भौर 362 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी। सुद्ध विवेशी मुद्रा ध्रास्तियों में हुई 68 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी। सुद्ध विवेशी मुद्रा ध्रास्तियों में हुई 68 करोड़ रुपयों की वोड़ी सी वृद्धि भी मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि में महायक हुई (सारणी 16)।

#### 1975-76 का ग्रधिक कामकाज का समय

99. 1975-76 के श्रधिक कामकाज के समय के वौरान 924 करोड़ कपयों का मुद्रागत विस्तार हुआ जो पिछले प्रधिक कामकाज के समय से 92 करोड़ क्षप्य श्रधिक था। इस वृद्धि में से चलमुद्रा का ग्रंग 527 करोड़ क्ष्प्य ग्रौर जमा रकम का ग्रंग 397 करोड़ क्ष्प्य था। मुद्रा उपकथ्यि की प्रभावित करने वाले सच्यो की वृष्टि से बैंकों द्वारा वाणि उस क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण में हुई 1926 करोड़ क्ष्प्यों की बृद्धि

⁽¹⁸⁾ धालोक्य वर्ष के वौरान हुई 2533 करोड़ रुपयों की वृद्धि से बैंकों के पास विद्यमान कुल जमा राशियों में 97 प्रतिशत की वृद्धि पायी गमी प्रयात उक्त जमा राशियों जून 1972 के मंत में विद्यमान 7954 करोड़ से बढ़कर जून 1976 के मंत में 15630 करोड़ रुपये हो गयी। 7676 करोड़ रुपयों की इस वृद्धि में मीवाबी मौर मांग जमाराशियों कमश: 4935 करोड़ रुपये मौर 2741 करोड़ रुपये थी

सारणी 16 : मुद्रा उपलब्धि ग्रीर मुद्रागत संव्यनीं की प्रवृत्तियां (मौसमी)

(राणि करोड़ रुपयो मे)

मदे			कम कामकाज	का समय	प्रधिक काम	र्काण का समय
			1974	1975	1974	1975
1			2	3	1	5
अ जनता के पास मुद्रा उपलब्धि (1+2)		<del></del>	150	+ 286	+832	+924
1. जनमा के पास चलस्दा			133	129	+ 177	· - 527
<b>2</b> जमा रकम@			+283	+415	+ 355	+397
आ मुद्रा उपलब्धि की घट-बढ़ को प्रमाचित करने वाले तत्व (1-	+ 2+ 3+	- 45)				
1 वीकों द्वारा सरकार को विया गया गुद्ध ऋण (क 🕂 खा)			+527	+ 362	+694	<b>+207</b>
(क) रिजर्व वैक द्वारा सरकार को विया गया भुद्ध ऋण		•	168	+129	+578	141
(खा) अस्य वैंकों द्वारासरकार को दियागया ऋषण			+ 359	+234	+116	+347
2 वैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण (क 🕂 ख *)		•	<del> </del> 251	+627	+1180	+1926
(क) रिग्नर्वं बैंक द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दियागयाऋण			76	20	+134	+85
(৩ৱ) স্নন্য वैंको द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण		•	+328	+ 647	+1046	+ 1841
3 वैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा ग्रास्तियाँ			1 62	+68	118	+367
4 जनता के प्रति सरकार की शुद्ध मुद्रा देवताएँ			+ 8	+12	+20	+4
5 <b>बैकिन क्षेत्र की मुद्रे</b> तर देयताएँ (क <del>⊹ क्वा</del> →ग) .			+774	+783	+944	+1579
<ul><li>(क) बैको के पास मीयावी जमाराशियाँ</li></ul>		•	+647	+740	+482	+823
(ख) मारतीय रिजर्व बैक की गुद्ध मुद्रेतर देयताएं			+64	+299	+433	+106
(ग) मवशिष्ट			+63	256	+29	+649
६ कुल मुद्रागत साधन [म-म्बा 5(क)] .			+498	+1026	+1313	+1748

टिप्पासी . कोष्ठको में विये गए औकड़े घट-बढ़ के प्रतिशत से संबंधित है।

1974-75 के श्रीविक कामकाज के समय में हुई बृद्धि के स्तर से 746 करोड़ रुपये प्रधिक थी। बैंकिंग क्षेत्र की गुढ़ विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1974-75 के प्रधिक कामकाज के समय की 118 करोड़ रुपयों की गिरावट के विपरीत 367 करोड़ रुपयों की काफी श्रीविक वृद्धि पायी गयी। यश्चिप सरकार की दिये जानेवाले बैंक ऋण के कारण भी मुद्रागत वृद्धि हुई फिर भी उक्त बैंक ऋण में हुई वृद्धि (207 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष के प्रधिक कामकाज के समय से एक निहाई से कम थी। इस सब तस्वों का समग्र प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रेतर देयताग्रों में हुई 1579 करोड़ रुपयों की वृद्धि से काफ़ी सीमा तक समायोजिन हो गया (सारणी 16)।

## मुख्य स्थितिः

# सामान्य प्रवृत्तियां ग्रीर कारणभूत तत्व

100. 1975-76 में भारतीय घर्ष व्यवस्था की मूल्यों के क्षेत्र में भरविक उल्लेखनीय उपलब्धि हुई। ऐसे समय में अब विज्य के प्रधिकांश वेश मुद्रास्फीती की उच्च दरों से प्रभावित थे या किमी भी हालन म उनमें कमी घाने के कोई प्रासार नजर नहीं घा रहे थे तब भारन न केवल उसे नियंत्रित कर सका, बल्कि 1972-73 ध्रौर 1973-74 के दो क्षों के दौरान घरयधिक उच्च स्तर पर बढ़े हुए मूल्यों को वास्तव में कम भी कर सका । योक मूल्यो का जो सामान्य सूचकाक (ब्राधार वर्ष 1961-62-100) 21 मितबर 1974 को 330 7 के उक्वतम स्तर पर पहुँच गया था वहाँ उसके बाद वह धीरे धीरे गिरते लगा धौर जून 1975 के घत में 311.0 के स्तर पर पहुँच गया तथा 20 मार्च 1976 को धौर कम होकर 282 3 के न्यून स्तर पर पहुँच गया । घत इस स्थित में कहा जा सकता है कि मूच्य स्तर वास्तविक स्तर से गिर कर पुनः दो वर्ष पहुले के स्तर पर पहुँच गया । उदाहरण के लिए 2 मार्च, 1974 को यह सूचकांक 282 1 के स्तर पर विद्यमान था ।

101 सितम्बर 1974 धौर मार्च 1976 की मध्याविध के बीच थोक मूल्यों के सामान्य स्तर में लगभग 14 6 प्रतिशत की गिराबट हुई। किन्तु लगातार गिराबट का यह दौर 20 मार्च 1976 को रुका। उस समय मूल्य बढ़ते लगा और जून 1976 के झत में सूचकाक 6 9 प्रतिशत बढ़कर 301.8 हो गया। इस यूद्धि के बावजूद वर्ष 1975-76 (जुलाई-जून) के दौरान मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति में गिराबट पायी गयी चाहे उनकी तुलना झलग झलग सूचकांक के झाधार पर की जाए या मासिक औसतों के आधार पर। उवाहरण के लिए जून 1975 के झत और जून 1976 के सत के बीच थोक मूल्यों में 3.0 प्रतिशत की गिराबट पाई गयी गिराबट की यह प्रवृत्ति वर्ष 1972-73 धौर 1973-74 के दौरान कमम पायी गयी 21 5 प्रतिशत और 27.8 प्रतिशत की अमूनपूर्व

^{*} इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ग्रीर राज्य सरकारों को वाणिज्यक उद्देश्यों के लिए प्रवास किये गये अग्निम ग्रामिल है।

[@] इसमें भारतीय रिजर्व बैक के पाम विद्यमान 'ग्रन्य जमाराणियां' णामिल है।

वृद्धि भीर 1974-75 में हुई 0.7 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि के विपरीत थी। यदि मासिक भ्रौसन स्तरों पर विचार किया जाए तो बेहतर चित्र सामने भाएगा: 1975-76 (जुलाई-जून) में मूल्यों में 6.0 प्रतिशत की गिरावट भागी जब कि 1974-75 में उनमें 16.8 प्रतिशत की वास्सविक वृद्धि हुई थी।

102. ब्रतः 1975-76 में मूल्यों में गिरावट की ही प्रवृत्ति निरंतर रही । इस गिरावट को 1975-76 की भारी फ़सल के कारण हुई शुद्ध मीसमी घटना के रूप में नहीं माना जा सकता, यद्यपि उदन गिरावट में यह सहायक प्रवक्ष्य हुई है। भ्रज्छी फ़सल के मलावा मुद्रागत एवं राज कोषीय ग्रनुशासन ग्रौर जमास्त्रोरी को रोकने के लिए ग्रमल में लाये गये प्रशासनिक उपायो के कारण भी मूल्यों में गिरावट की यह प्रवृत्ति स्रायी। 1975-76 के अनुभव से मूल्यों की प्रवृत्ति का एक और महत्त्रपूर्ण पक्ष काफ़ी स्पष्ट होकर सामने ग्राया है; श्रयत् भारतीय ग्रर्थ व्यवस्या के संदर्भ में मुल्यों के उनार-चढ़ाव के लिए पूर्ति ग्रीर माँग के बीच ग्राये सन्तलन का ग्रांशिक प्रभाव स्पष्ट है । संभवतः मृख्य प्रशामन पूर्ति ग्रौर मांग के बीच के ससुलनों के समान ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कि सट्टेबाजी के कार्यकलापों द्वारा प्रतिरोध माने की काफ़ी संभावना है । सट्टेबाजी की गतिविधिया, जून 1975 में की गयी ब्रातरिक ब्रापातकाल की घोषणा भीर ग्राधिक अपराधियो, काला बाजारियों भौर तस्करों की धरपकड़ तथा बेहिसाबी धन के प्रयोग को रोकने के लिए उठाये गये व्यासक उसायो द्वारा काफ़ी सीमा तक विलुप्त हो गयीं।

103. कुल मिलाकर यदि 1976-77 में क्रिय मौसम प्रच्छा रहा तो इस तर्क के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होंगे कि वर्ष 1975-76 की मूल्य स्थायिता धगले वर्ष में भी जारी रहेगी । इस तर्क के समर्थन में कम से कम दो कारण बनाये जा सकते हैं : श्रनाज के काफ़ी अधिक भंडार बनाना संभव हो गया है धौर साथ ही पर्याप्त प्रारक्षित विवेशी मुद्रा निधियौं संचित करना भी संभव हो गया है जिन्हें वेशी मुद्रास्फीती की शक्तियों को उनके पुनः उभरने का संकेत मिलने पर समाप्त करने के लिए लिया जा सकता है।

## मुस्यों में गिराबट : जून 1975 से 20 मार्च 1976 तक

104. यदि पुन. वर्ष 1975-76 के दौरान विद्यमान मूल्यों की प्रवृत्ति की देखा जाए तो उक्त प्रवृत्ति का सार्थक विश्लेषण दो स्पष्ट चरणों में किया जा सकता है. प्रथम चरण जून 1975 के ध्रांस से 20 मार्च 1976 तक का था जब मूल्यों में गिरावट ध्रायी तथा दूसरा चरण मार्च 1976 के सीसरे सप्ताह से जून 1976 के झंन तक का था जब मूल्यों में वास्तव में बढ़ोतरी ध्रायी । पहले चरण के दौरान थोक मूल्यों में 9.2 प्रतिगत की गिरावट पायी गयी । 1975-76 की भारी फ़मल तथा लगातार दो वर्षों में काफ़ी ध्रिधिक माला में किये गये खाद्याकों के श्रायातों के कारण उक्त प्रवृत्ति की भूमिका बनी होगी । इन सध्यों का प्रधाव इसके पूर्व उल्लिखित विभिन्न मुद्रास्कीतिरोधी कार्रवाहयों के कारण और तीन्न हो गया ।

#### मुल्यों में बुद्धि: 20 मार्चं से जून 1976 ग्रंत तक

105. दूसरे चरण में मूल्यों में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधिकांग वृद्धि जून 1976 में हुई : उवाहरण के लिए 5 जून ग्रीर 26 जून के बीच घोक मूल्यों मे लगभग 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह स्मरण होगा कि जून 1975 में मूल्यों में वास्तव मे सामान्य कभी पायी गयी थी । जून 1976 में मूल्यों में हुई भारी वृद्धि का कारण स्पष्टतः इस तथ्य में निहित प्रतीत होता है कि वेग के ग्रिधकांग भागों में विलंब से मानसून घा जाने के कारण मूल्य संबंधी प्रत्याशाभ्रो में परिवर्तन भागा भीर कवाचित् इस कारण सट्टेशजी के सल्व उपरे । यह स्पष्टीकरण कव्वी रुई, मृगफली जैसे कतियत्र विशिष्ट

पण्यों के मामलों में विशेष रूप से मही है जहाँ पूर्ति झौर माँग के बीच का संदुलन भ्रधिक बिगड़ नहीं गया था।

106. यहाँ इस बात का उल्लेख किया जाए कि व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ऐसी परिस्थितियों के लिए सशक्त वातावरण उपस्थित हो सकेगा।

107 समग्र रूप से इस चरण में उक्त बुद्धि के एक ग्रंश का कारण कम कामकाज के समय का ग्रागमन माना जा सकता है; परन्तु उन विशिष्ट पण्यो/वस्तुम्रों के संवर्भ में मधिक सार्थक कारण का पता लगाना होगा जिनके मूल्यो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इस वृद्धि के लिए दो प्रमुख वर्ग प्रयत् 'खाद्य वस्तुएँ' (8.9 प्रतिशन) ग्रीर 'ग्रीसोगिक कच्ची सामग्री' (23.6 प्रतिशत) जिम्मेदार थी । यहाँ यह भी उल्लेख किया जाए कि 1975-76 के पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्यों के सामान्य स्तर को निचला बनाये रकाने के लिए भी ये ही दो वर्गप्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। 'खाद्य वस्तुव्यो' के वर्ग में प्रमुख रूप से फल धौर मब्जी, मछली, ब्रांडे ग्रौर माम तथा चीनी ग्रौर उसमे सबद्ध उत्पादनो जैसी भ्रपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण वस्तुक्रों के कारण मुल्यों पर दबाव परिलक्षित हुआ परंतू खाद्याक्रों के मुख्यों में केवल 0 9 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि पायी गयी ग्रीर यह वृद्धि ज्यार भौर बाजरे के मामले में भ्रधिक सफ्द थी । खाद्य तेली के पूरुयों मे भी 16.1 प्रतिणत की बढ़ोतरी पायी गयी परनु वालों के मूल्यों में भारी मावा में गिरावट भायी। 'भ्रौधोगिक कच्ची सामग्री' के वर्ग में प्रमुख दबाय कञ्ची ६६ के कारण परिलक्षित हुआ। कञ्ची रुई के मुख्यों में लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यद्यपि ६ई के मामले में पूर्ति ग्रौर मांग के बीव धर्मजुलन विद्यमान था फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि केवल इस ग्रमनुलन के कारण ही उक्त वृद्धि नहीं हुई । इसी प्रकार, तिलहनों के मुल्यों में भी इस चरण के दौरान लगभग 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी पायी गयी।

## वर्गवार प्रवृत्तिया : 1975-76

108. प्रव 1975-76 के दौरान समग्र रूप से सूल्यों की प्रवृत्तियों का प्रिष्ठिक अ्पोरेशार विश्लेषण करने की कोशिश की जाए । 1975-76 (जुलाई-जून) के दौरान मूल्यों में 3.0 प्रतिशत की जो गिरावट श्रायी वह निम्नलिखित क्यों के कारण घायों : 'खाद्य वस्तुए' (10.2 प्रतिशत), 'रसायन' (10 4 प्रतिशत) नथा 'मशोर्ने और परिवहन उपकरण' (1.6 प्रतिशत), सामान्य सूचकांक के कुल भार का लगभग 50 प्रतिशत भंश हन वर्गों का था । इनके विपरीत, 'शराब और तमाखू' (1.7 प्रतिशत), 'ग्रौद्योगिक कच्ची सामग्री' (5.6 प्रतिशत) भ्रौर 'निर्मित वस्तुओं' (3.1 प्रतिशत) के मूल्यों में वृद्ध हुई (ईधन, पावर, बिजली और जिकनाई के प्रयाणों में' 13.1 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्ध हुई (सारणों 17) ।

109. 'खाद्य वस्तुयों' के वर्ग का सूचकांक जून 1975 के मंत में विद्यमान 368.7 के शिखर स्तर से घटकर जून 1976 के मंत में 331.0 हो गया प्रयात् उसमें 10.2 प्रतिशत की गिरावट मायी जब कि 1974-75 मौर 1973-74 में उसमें कमणः 3.2 प्रतिशत भीर 26.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। खाद्यामों के मूल्यों में मायी गिरावट 24.0 प्रतिशत बी जब कि 1974-75 मौर 1973-74 में उनमें कमशः 4.6 प्रतिशत मौर 36.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। विलवस्मी की बात यह थी कि 'खाद्यामों' में से वालों से भिन्न मनाज एवं दालों के मूल्यों में कमशः 22.1 प्रतिशत मौर 31.1 प्रतिशत की भारी गिरावट पायी गयी जब कि पिछले वर्ष के दौरान दालों में मिन्न मनाजों के मामले में 6.9 प्रतिशत की युद्धि भौर दालों के मामले में 3.4 प्रतिशत की कमी हुई थी। इसके मलावा इस वर्ष के दौरान पायी गयी प्रमृतपूर्व विशेषता यह थी कि दालों से मिन्न सभी प्रमृत्व तथा मोटे मनाजों के मूल्यों में गिरावट मायी। चावन भौर गेहूँ के मूल्यों में कमशः 23.6 प्रतिशत भौर 9.4 प्रतिशत की काफी म्राधिक गिरावट पायी गयी। जवार भौर बाजरे के

# सारणी 17: थोक मूल्यों के भूचकाकों की प्रवृत्तियां

(आधार 1961-62=100)

(प्रतिशत घट-बढ़)

								रास पद≔पकृ) . —
वर्ग/उप-वर्ग/पण्य		भार*	जून 1974 के भ्रत की तुलना मे जन 1975 के ग्रत मे	जून 1975 के श्रत की तुलना मे जून 1976 के श्रन मे	जून 1974 के धन की जुलना 22 में।चे 1975 को	22 मार्च 1975 की तुलना मे जन 1975 के ग्रत मे	गृत 1975 के भ्रत की तुलना मे 20 मार्च 1976 की	20 मार्च 1976 की सुलनामे जून 1976 के श्रतमे
1		2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य		1000	+0.7	3 0	— 0. <b>2</b>	+0.9	9.2	+6.9
I खाद्य बस्तुएं , .		413	- - 3 2		+0.2	+30	17.6	+8.9
खाणाञ्च		(35 8)	+46		+5 1			
(क) दालो से क्लिप्रधनाज						0 5	24 7	+09
		(29 3)		22 1	+7 2	—о з	25 4	+44
(i) ভাষদ .	(	16 2)	+10 4	<b>—23</b> 6	+1 0	+9 3	<del></del> 27 8	+58
(गां) गेहूं	•	(78)	2 3	9 4	+11 9	<del>-1</del> 2 7	<del></del> 5 7	<u>—</u> з 9
(111) ण्वार .		(22)	+ 1 9	<b>—12</b> 9	+29	<del></del> 1 0	28 3	+21 5
(1V) <b>बा</b> जरा		(1 1)	+33 6	44 7	+46 6	-8 9	<del></del> 53 3	+18 5
(ख) दाले 🛮		(6 5)	3 4	31 1	2 1	<b>—</b> 1 3	<b>—</b> 21 7	—12 0
फल ग्रौर सक्जियाँ		(5 7)	13 0		18 9	+7 3		
दूध ग्रौर दूध से बनी वस्तुए		(14 7)	+67		+3 0		14 6	+30 4
बाद्य तेल्⊬ .		(13 0)	+15 9		—12 7	+ 3 6 3 6	10 7	+47
मछली, श्रडे श्रौर मास	·	(4 9)	+5 (		—1 2	—3 6 +6 3	-337 $+123$	+16 1
चीनी और उससे सबद्ध उत्पाव		(15 7)	+16 3		+44	+11 4	—14 4	+83 + 225
<del>षी</del> नी		(8 9)	+62		+10 3	-3 7	+1 2	+39
II शराबस्रोरसमाख्		25	+4.2		+1.4	+28	+0.8	+0.9
III ईंधन पावर, विजली ग्रौर चिकनाई के पदार्थ.		61	+ 5.7	+13.1	+5.1	+0.6	+12.4	+0.6
IV ग्रीकोगिक कच्ची सामग्री		121	16 5	+5.6	14.0	3.9	-14.5	+23.6
रेसे		(340)	13 в	+29 5	12 5	<b>—1</b> 2	3 7	+24 9
(i) कच्ची रूर्द .	(	18 5)	-24 8	+48 2	<b>22</b> 3	3 3	+4 3	+42 0
(ii) पटसन		(9 6)	+ 26 7	+75	+166	+8 7	+156	<del></del> 7 1
तिलहन .		(43 3)	<b>—2</b> 0 3	<del>-8</del> 3	15 1	<del></del> 6 1	30 з	+309
(ti1) मूगफ्ली . <b>V रसायम</b>	(	20 8)	8 8	21 3	<b>6 4</b>	2 4	42 5	+36 7
VI मशीनें और परिवहन उपकरण	•	7	+14.9	10 4	+14.6	+0.2	<b>—5.1</b>	5 6
VII निर्मित बस्तुएं		79 294	+11.4	$\frac{-1.6}{+3.1}$	+12.6 $+0.9$	-1.1	0.1	1.4
(क) मध्यवर्ती उत्पाव	•	19 5)	12 I	+9.6	+0.9 12 7	0.3 +0.7	+0.9	+2.2
(ख) सैयार उत्पाद		80 5)	+5 1	+12	+57	= 0 6	+4 0	+54
वस्त		38 6)	-1 2	2 2	+ (नगण्य)	<del></del> 1 3	0 f	+ 1 2 1 6
(i) सूती वस्त्र		26 8)	+22	+14	+16	+06	0 з	+18
(ii) जूटके वस्तुए	•	(8 1)	8 2	+15 3	1 4	7 0	—2 J	13 3
द्यातु से बनी वस्तुएँ	(	13 0)	+13 5	+28	+13 1	+0 1	+24	+03
रसार्यानक वस्तु∘ उर्वर¥ .	•	(9.2)	+11 1	+37	+126	<del></del> 1 3	1 5	+ 5 3
94KT		(18)	+31	<del></del> 21 0	+3 5	+04	21 0	-

^{*}कोष्ठको में दिये गये <mark>मांकडे सबधित प्रमुख वर्गों के लिए निर्धारित भार के प्रतिशत वितरण को दर्शाते हैं ।</mark> स्त्रोत भाषिक परामर्शदाता, भौद्योगिक विकास मञ्जालय, भारत सरकार का कार्यालय।

मूल्मों में क्रमण 12.9 प्रतिणत और 44.7प्र तिशत की भारी गिराकट आयी। भारी माला में आयात किये जाने तथा काफी अधिक माला में खाद्याओं के समीकरण भड़ार बनाने के निर्णय का खाद्याओं के मृल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। खाध तेलों के मूल्यों में भी पिछले वर्ष भायी 15 9 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले में 24.0 प्रतिशत की भारी गिरावट आयी। खाध तेलों में से मूंगफली के तेल के मूल्यों में 32 7 प्रतिशत की तीप्र गिरावट आयी, उसके बाद वनस्पति का स्थान था श्रयित् उसके मूल्यों में 31 8 प्रतिशत की कमी पायी गयी।

110. 'भौद्योगिक कच्ची सामग्री' के वर्ग सूचकांक में जहां 1974-75 में 16.5 प्रतिशत की गिरावट धायी उसके मुकाबले इस वर्ष 5.6 प्रतिगत की वृद्धि पायी गयी । सारणी 17 से यह विदित होगा कि इस वर्ग के मृल्यों में मार्च 1976 के मध्य (जुलाई-मार्च) तक 14 5 प्रतिशत की गिरावट बायी : यह गिराबट प्रमुख रूप में 'निलहनो' (30.3 प्रतिशत) में पायी गयी । कच्ची सामग्री के मृत्यों मे प्रायी इस गिराबट भी प्रयुक्ति में बाद में परिवर्तन भाषा भौर तदतर मुख्यो में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति आभी । 20 मार्च और जून 1976 के अने के बीच 'धीचोगिक कच्ची सामग्री' के सूचकांक में 23 6 प्रतिगत की वृद्धि हुई 'कच्ची रूई' (42 प्रतिणत) भीर 'तिलहनों' (31 प्रतिणत) के मामले में यह वृद्धि स्पष्ट थी । कच्ची कई के मूल्यों में जो प्रभृत्यूर्व वृद्धि हुई उसका कारण इस प्रकार था। मिलो की माँग विशेष रूप से नयी फ़मल के सदर्भ में लगातार बनी रही भौर उच्चतर मूल्यों पर भी वित्रय का दबाव नही था। इसके ग्रलाबा रूई सलाहकार मंडल नेजून 1976 में रूई की फ़मल के ग्रानुमानों में 2.5 लाख गांठों की कमी कर उसे 66 5 लाख गांठें निर्धारित किया । 'तिलहुनों' के मामले में सट्टेबाओं के उद्देश्य से की गयी जमाखोरी तथा कतिपय राज्यों द्वारा तिलहनों, विशेष रूप से मुंगफली मीर मुंगफली के तेल की अंतर्राज्यीय भावा-जाही पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण उनके मूल्यों में वृद्धि हुई । इन पण्यो के मूल्यों में कमी लाने के लिए भव उपाय किये गये हैं। इस प्रकार 1975-76 के पूरे वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान कच्ची रूई के मूल्यों में अहाँ 48.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई वहाँ तिलहुमों के मुख्यों में केवल 8.3 प्रतिणत की गिरा-वट आयी परन्तु पटसन के मूल्यों में पटसन और मेस्ता का कम उत्पादम होने के कारण 7.5 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी।

111. 'रसायनों' के वर्ग के मूस्यों में 1975-76 में 10.4 प्रिणाल की गिराबट पायी गयी जबिक 1974-75 और 1973-74 में उनमें कमण 14.9 प्रतिणत और 36.9 प्रतिणत की वृद्धि हुई थी। इस गिराबट का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने उर्धरकों के मूस्यों में लगातार कमी की थी। इसके विपरीन मिट्टी के तेल, भट्टी के तेल और पेट्रोलियम के मूस्यों में सरकार द्वारा घोषित वृद्धि के कारण 'ईंबन, पावर, विजली और चिकनाई के पवार्यों' के वर्ग के सूचकांक में 13.1 प्रतिणत की वृद्धि हुई।

112. 'निमित वस्तुक्षों' के वर्ग में 3.1 प्रतिशत की सीमांत मूस्य वृद्धि हुई । दोनों उपवर्ग प्रथित् 'मध्यवर्ती उत्पाद' प्रौर 'तैयार उत्पाद' इस वृद्धि के उत्तरदायी थे : 'मध्यवर्ती वस्तुक्षों' के मूस्यों में पिछले वर्ष पायी गयी 12.1 प्रतिशत की गिरावर के मुकावले में इस वर्ष 9.6 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि 'तैयार उत्पादों' के मूस्यों में पिछले वर्ष की 5.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में 1.2 प्रतिशत की सीमात वृद्धि हुई 'तैयार उत्पादों' में से सूत भौर जूट से बनी वस्तुक्षों के मूल्यों में कमश: 1.4 प्रतिशत थौर 15,3 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

## वयभोक्ता मूल्य

113. भोक मृह्यों में प्राणी गिरावट की प्रवृत्ति के प्रमुक्त उपभोक्ता मृहय सूचकाक (प्राधार 1960 = 100) में भी गिरावट प्राणी । वस्तुतः 1961 के बाद पहली बार सूचकांक में ऐसी उल्लेखनीय गिरावट पायी गयी। श्रीद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मृत्य सूचकांक में जहाँ 1975-  $76(^{19})$  के दौरान 10.2 प्रतिशत की गिरावट प्रायी वहाँ पिछले वर्ष की नदनुरूप श्रविश्व में 5.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। परन्तु शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के सूचकांक में श्रालोक्य भ्रविध में 4.6 प्रतिशत की न्यूनतर गिरावट श्रायी( 10 ) जब कि 1974-75 की तदनुरूप श्रविध में उसमें 6.1 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी थी।

## निवेश और अधत वेशी अधत

114. यद्यपि 1975-76 की धर्यव्यक्षस्था से मंबंधित बचत श्रीर निवेश के व्यापक श्रीकड़े भ्रमी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी धलग श्रलग श्रोकड़ों के श्राधार पर स्थूल प्रवृक्षियों का संकेष किया जा सकता है। परनु इस बान को ब्यान में रखने की भ्रावश्यकता है कि यहां प्रस्तुत किये गये बचन और निवेश के श्रनुमानित श्रांकड़े ग्रस्थायी हैं और जब परिपूर्ण श्रांकड़े उपलब्ध हो जायेंगे तम उनमें महत्वपूर्ण संशोधन हो सकता है।

115. सारणी 18 में प्रस्तुत किये गये प्रांकड़े यह दशित है कि राष्ट्रीय आय में देशी बचत का प्रमुपान 1974-75 के 13.1 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 1975-76 में 14.5 प्रतिशत हो गया । देशी बचत में हुई बृद्धि में सरकारी तथा घरेलू बोनों केशों का योगवान रहा है । सापेक्ष मूल्य स्थायिता के बातावरण में पिछले वर्ष के विपरीत 1975-76 में विसीय भ्रास्तियों के रूप में रहनेवाली बचत में उल्लेखनीय बृद्धि हुई । इसके विपरीत ऐसा प्रतीन होता है कि कुल देशी बचत में निजी संपनी क्षेत्र के प्रंग में गिरावट ग्रायी ।

## कुल निवेश

116. देशी अचत में उपर्युक्त प्रकार से उल्लेखनीय वृद्धि होने के परिणामस्त्ररूप प्रयंग्यवस्था में अचन की समग्र दर 1974-75 में स्थित राष्ट्रीय उत्पाद के 14.8 प्रतिशत में अकुकर 1975-76 में 16.0 प्रतिशन हो गयी। प्रधिक महत्त्वपूर्ण बान यह है कि विदेशी मुद्रागत साक्षमों की शुद्ध प्राप्ति में कमी होने के आवजूद अचत में वृद्धि हुई।

यह अनुमान है कि प्राप्त विदेशी मुद्रागत माधनों की माला आहाँ 1974-75 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का 1.7 प्रतिशत थी वहाँ 1975-76 में घटकर 1.5 प्रतिशत हो गयी। बास्तव में इस स्तर पर भी निवेश में विदेशी मुद्रागत माधनों का योगवान काफ़ी अधिक था। इस प्रकार देशी बचन के कारण न केवल प्राप्त विदेशी मुद्रागत माधनों में हुई कमी की पूर्ति हो सकी परन्सु प्रयंक्यवस्था में ममग्र निवेश के स्तर में भी सुधार ग्रा सका।

## बाजार ऋण

117. इस सन्दर्भ में सरकारों के बाजार ऋणों के सम्बन्ध में कुछ कहा जाए। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को बाजार ऋणों से संयुक्त रूप से प्राप्त राशि (21) 1975-76 के विनोध वर्ष में 728 करोड़ क्यये थी जब कि पिछले वर्ष उकन राशि 708 करोड़ क्यये थी। 1975-76 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने दो प्रवसरों पर बाजार ऋण जारी किये और 453 करोड़ क्ययों की शुद्ध राशि जुटाई जब कि 1974-75 में 495 करोड़ क्ययों की राशि जुटाई थी। पहला ऋण जहां नक्षी सौर परिवर्तन ऋण के रूप में जारी किया गया वहां दूसरा ऋण पूर्ण रूप से नकटी समिदानों पर आधारित था। इन ऋणों के स्रतिरिक्स साय और सम्पत्ति की स्वैच्छिक प्रकटन की योजना के सन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के बांडों में 39 करोड़ क्ययों की राशि का निवेश किया गया।

⁽¹⁹⁾ जुलाई 1975 के सूचकांक की तुलाग में जून 1976 में

^{(&}lt;sup>20</sup>) जुलाई 1975 के सूचकांक की तुलना में धर्मेल 1976 में

^{(&}lt;sup>21</sup>) ये ग्रांकड़े भारतीय रिजर्व वैंक के ग्रमिलेखों से लिये गये हैं।

सारणी 18 : वेशी सचत ग्रीर निवेश के प्रावकलनः वर्तमान मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत (अनंतिम) विनीय वर्ष (ग्रप्रैल, मार्च)

मदे					1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
1	 <del></del>	 	 <u> </u>	***************************************	2	3	4	5
1 देणी बचत					13.0	12.8	13.1	14,5
2 विवेशी मुद्रागत साधनों से प्राप्त राशि					0.8	0.8	1.7	1.5
	•				13.8	13.6	14.8	16.0

टिप्पणीः 1972-73 से 1974-75 तक के अनुपानों को भ्रणतः केन्द्रीय माख्यिकीय संगठन के राष्ट्रीय भ्राय सम्बन्धी भांकणों के प्राक्कलनों में संगोधन किये जाने तथा श्रंगतः बचन और निवेश के घटकों के सम्बन्ध में श्रधिक श्रद्धतन श्राकड़े उपलब्ध होने से संगोधित किया गया है।

राज्य सरकारों ने 1975-76 में नकदी में दो ऋण जारी किये श्रीर उनमें 274 करोड़ क्षये जुटाये जब कि 1974-75 में 213 कराड़ क्षये गुटाये थे। पहले निर्गम में 179 करोड़ क्षये श्रीर दूसरे निर्गम में 95 करोड़ क्षये जुटाये गये। राज्य सरकारो द्वारा बाजार से जुटाये गए कुल 274 करोड़ क्षयो में से उन सरकारो ने 1975-76 के दौरान केन्द्रीय सरकार को 100 करोड़ क्षये जुकाये जो 1963-64 में जुटाये गए केन्द्रीयकृत बाजार ऋणों में उनके श्रिश क्षा का बोतक थातथा 174 करोड़ क्षयों की गेप राग राज्य सरकारों ने श्रयने पास रख ली।

## विवेशी क्षेत्र

118. 1975-76 में भारतीय प्रयंख्यवस्था के विदेशी क्षेत्र के कार्यकलाप से पूर्व वर्षों के विपरीत संग्रस्ता के स्पष्ट लक्षण परिलक्षित होते
हैं। इस सगक्त स्थिति के कारण लगानार दूसरे वर्ष भी भारी माता में
क्यापार क्षेत्र में घाटा होने के बावजूद प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निश्चियो
में अभूतपूर्व दृद्ध हुई। यद्यपि विदेशी वित्तीय साधनों से प्राप्त राणि
से सहायता मिली फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह सणक्त स्थिति
प्रमुखन देशी कारणा से उत्पन्न हुई है। 1975-76 के लिये भुगतान
सन्तुलन सम्बन्धी क्यौरेवार आकड़ो के अभाव में इस समय यह निर्धारित
करना कठिन है कि 1975-76 की भुगतान सम्बन्धी स्थिति स्थाई स्वस्प
की है या वह दीर्षकालीन प्रवृत्ति का केवल एक अंश मात्र है। कोई भी
क्यिंसत स्थूल रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि भुगतान सन्तुलन
सम्बन्धी वीर्षकालीन संभावनाये बढ़ गई हैं।

#### **ध्यापार घाटा ग्रौर भुगतान की स्थिति**

119. पहले प्रस्पकालीन प्रवृत्ति को देखा जाए । 1975-76 में प्रायान धौर निर्यात दोनों में पूर्व वर्ष की घरेका त्यूनसर वृद्धि दरे पायी गई। निर्यातों में केवल 16 प्रतिमन की वृद्धि हुई जाकि 1974-75 में उनमें लगभग 32 प्रतिमत की वृद्धि हुई थी। परन्तु प्रधिकांग्र भारतीय वस्तुग्रो/पण्यों के निर्यातों से हुई प्रामवनी में 1974-75 में जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी उसे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में ध्रायी गिरावट की प्रवृत्ति के कारण बनाय नहीं रखा जा सका। ग्रायातों में हुई 11 प्रतिभात की वृद्धि की मुलना में काफी कम थी। ग्रायातों में हुई वृद्धि प्रमुख रूप से खायाक्षों तक ही सीमित थी तथा उनत वृद्धि त्रायातों की मान्ना भीर मूल्य दोनों में हुई। इसके विपरीन ग्रायात सम्बन्धी प्रदायगियों की मान्ना पैट्रोलियम महित ग्रन्य कई सस्तुग्रों के कारण काफी कम थी, इसके ग्रांशिक परिणाम के रूप में 25 GI/77—5

1975-76 के धायातों में प्रपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। इसका णुद्ध परिणाम यह हुआ कि 1975-76 में व्यापार बाटे का राणि पिछले वर्ष के दौरान विद्यमान 1189 करोड़ रुपयों के बाटे की तुलना में 1155 करोड़ रुपयों पर लगभग अपरिवर्तित रही।

120. लगातार भारी मान्ना में व्यापार घाटा होने के बावजूद सौभाग्यवश भारत की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में 1975-76 के वित्तीय वर्ष के दौरान 881 करोड़ रुपये की ग्रभूतपूर्व वृद्धि हुई (22)। भुगनान सन्तुलन सम्बन्धी स्यौरेवार घांकड़ों के प्रभाव में उक्त निधियों में हुई वृद्धि का सही स्पष्टीकरण देना कठिन है। परन्तु स्थूल संकेतों से यह विवित होता है कि यह वृद्धि प्रमुख रूप से दो कारणों से अर्थान् प्रधिक माला में सहायता प्राप्त होने तथा ग्रदृश्य लेत-देनो की ग्रामदनियों में वृद्धि होने से हुई। यद्यपि प्राप्त सहायता के सम्बन्ध में पूर्ण प्रांकड़े श्रभी उपलब्ध नहीं है फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि 1975-76 में सहायता की जो सकल राशि प्राप्त हुई वह 1974-75 की भपेक्षा लगभग 400 करोड़ रूपमें घिषक थी। इसके विपरीत ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किये गये लेन-देनों के परिणामस्वरूप 1975-76 में काफी कम मास्रा में राशि प्राप्त हुई। प्रारक्षित निधि की स्थिति में मुधार श्रा जाने के बाद भारत ने जहां ग्रगस्त 1975 में ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तेल सुविधा (1975) के भन्तर्गत 207 करोड़ रुपयों की राशि निकली वहां भारत ने क्षतिपूरक वित्तपोषण सुविधा के भ्रन्तर्गत फरवरी 1974 में निकाले गए 65 करोड़ रुपयों को पुन: खरीदा। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किये गये लेन-वेनों से प्राप्त शुद्ध राशि 1975-76 में 142 करोड़ रुपये थी जबकि 1974-75 में इस प्रकार प्राप्त शुद्ध राशि लगभग 485 करोड़ रुपये थी। ब्रतः सकल सहायता नितरणों में 1975-76 में हुई वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कम राणि निकाली जाने के कारण काफी हद तक समायोजित हो गई। इस वृष्टिकोण से देखने पर प्रारक्षित निधियों की स्थिति में जो सुधार ग्राया उसका श्रेम ग्रधिकांशतः वेशीतत्वों को वियाजा सकता है

## प्रवृश्य लेन-वेनों में मुधार

121. यद्यपि ध्रवृथ्य लेन-देनों के खाते से सम्बन्धित आंकड़ों की संकलित करना श्रभी बाकी है, फिर भी स्थूल संकेत स्पष्ट है: प्राधिकृत आपारियो द्वारा रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा की जो गुढ़ बिकी की गई उसमें प्रपार वृद्धि हुई। ऐसी बिकी की माला 1974-75 की सुलना में 1975-76 में तिगुनी थी ग्रीर वह प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किये

⁽²²⁾ यह वृद्धि मार्च के घन्त में विधामान प्रारक्षित विवेशी मुद्रा निधियों के सन्दर्भ में है भीर इसमें सोना एवं विशेष श्राहरण श्रिकार सम्मिलित नहीं हैं।

गये विवेशी मुद्रागत लेत-वेतों के शुद्ध मिश्रोष की बोतक है। इस वृद्धि के मूल में निहित प्रमुख कारण इस प्रकार प्रतीत होता है: प्रदृश्य लेत-वेतों में, विशेष रूप से तिजी क्षेत्र को विवेशों से प्राप्त राशा में बढ़ोतरी हुई। यहां इस बात का अनुमान लगना उचित ही होगा कि जब तस्करों एवं विवेशी मुद्रा के अपराधियों के विवेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू की उसके बाव गलत तरीके से विदेशी मुद्रा का बाहर जाना बन्द हो गया है जिसका प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होने लगा है। इसके अलावा गैर-रिहायशी भारतीयों तथा विवेशों में रह नेवाले भारतीय मूल के व्यक्तिययों की विदेशी मुद्रा निध्यों को भारत में प्रेषित करने के लिये प्रोत्साहित करने तथा गैर-रिहायशी भारतीयों को कितपय निविच्ट उद्योगों की शेयर पूंजी में निवेश करने के लिये प्राक्तिय करने के निमित्त भी सरकार ने कई उपाय किये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर इन उपायों का भारत के अवस्थ लेत-देनों के खाते पर सन्तोषजनक प्रभाव पड़ा है।

122. दीर्घकालीन संभावनाओं को वेखने हुए 1975-76 में भुगतान सम्बन्धी स्थिति में जो समदनता आयी वह भारत के भुगतान सन्तुलन में होने वाले उल्लेखनीय परिवर्तन का चिन्ह प्रतीत होती है। निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये अवश्य ही इन पहलुओं का गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है; परस्पु कम से कम ऐसे परिवर्तन के कतिपय संकेतों का उल्लेख किया जा सकता है। अर्थ व्यवस्था में उच्चतर निर्यात कामना का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही तेल या अधिक सामान्य रूप से उर्जा के क्षेत्र में आयान प्रतिस्थापन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से किया जा रहा है। इसी प्रकार खाद्यानों एवं उर्वरकों के आयान करने की आवश्यकता भी कम हो सकती है। इसके अवस्था आशा है कि 1975-76 में अदृश्य लेन-वेनों की आमदित्यों में जो बृद्धि अनुभव की गई वह आगानी वर्षों में भी बनी रहेगी। यदि इन बातों को संकेत माना जाए तो भारत के भुगतान सन्तुलन की स्थित में लम्बी अवधि तक मुधार होने की आगा की जा सकती है।

क्यापार की प्रवृत्तियों का व्यौरेवार विश्लेषण निम्न प्रकार है:

#### क्यापार वाटी

123. 1975-76 के राजकोषीय वर्ष के दौरान व्यापार घाटे की राशि 1155 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के 1189 करोड़ रुपयों के घाटे की तुलना में केवल सीमांत रूप से कम थी। 1973 मौर 1974 में मन्तर्राष्ट्रीय पण्य बाजार में जो तेजी माई उसमें परिवर्तन मा जाने तथा ऐसे मधिकांश विकसित वेशों में जो प्राथमिक एवं परिष्कृत वस्सुमों के मुख्य बारीदार है, मन्दी की प्रवृत्तियां बनीं रहने से नियति विकास में

उल्लेखनीय रूप से मन्त्री की स्थिति द्या गई। पूर्णतः इसके परिणामस्वरूप नियनों की घामदनियों में 533 करोड़ रुपयों की काफी कम वृद्धि हुई जबिक पिछले वर्ष उनमें 807 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। निर्यास भ्रामवनियों में 1974-75 में हुई 32 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में इस वर्ष 16 प्रतिशत की बुद्धि हुई। ग्रायातों के मामले में कक्की सामग्री ग्रौर धातुभों के न्यूनतर मूख्यों के कारण ग्रवस्य ही श्रायात बिन में काफी कमी चाई, परन्तु भारत द्वारा प्रमुख रूप से बायानिन खाद्यान्नी ग्रीर उर्वरकों के मूल्यों में केवल नाममान्न की गिरावट ग्राने से उक्त कमी कुछ सीमा तक समायोजित हो गई। प्रायातों में 498 करोड़ रुपयों की जो समग्र वृद्धि हुई वह पूर्व वर्ष हुई वृद्धि (ग्रयीन् 1565 करोड़ रुपये) के मुकाबले में एक तिहाई से भी कम थी। इस प्रकार द्यायानों की वृद्धि दर 1975-76 में केवल 11 प्रतिशत थी जबकि 1974-75 धौर 1973-74 में बह् कमणः 53 प्रतिशत भीर 58 प्रतिशत थी। नियति मूल्यों की ग्रपेक्षा ग्रामात मूल्यों की वृद्धि-दर उच्चतर बनी रही। इस कारण भारत के नियक्ति-प्रायास मूल्यांक में घौर भी गिरावट घाई. घप्रैल 1975 से फरवरी 1976 तक की भवधि के लिये जो भ्रांकड़े प्राप्त हुए हैं उनसे यह विदित हुआ है कि नियति आयात मूल्यांक में 15 प्रतिशत से भी मधिक गिरावट भाई।

#### निर्यात

124 1975-76 के बित्तीय वर्ष के वौरान नियत्तिों के मूल्य में भीर भी वृद्धि हुई भीर वह बढ़कर 3863 करोड़ रुपयों के शिखर स्तर पर पहुंच गया: इस प्रकार उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 533 करोड़ रुपयों की वृद्धि पाई गई। 1974~75 में उसमें 807 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। परन्तु 1975-76 के केवल पहले नौ महीनों (ग्रप्रैल-विसम्बर) के लिये पण्यवार प्रांकड़े उपलब्ध हैं, इस प्रवधि के दौरान नियानों का कुल मूल्य 2690 करोड रुपयेचा जबकि 1974-75 की तवनुरूप भवधि में उक्त मूल्य 2355 करोड़ रुपये था (सारणी 19)। निर्यातों के पण्यवार मूल्यों में जो परिवर्तन हुए वे पूर्णतः भ्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, विशेष रूप से कृषि उत्पादों भीर परिष्कृत वस्तुकों तथा निर्मित वस्तुधों के मूल्यों के द्योतक थे। जूट की वस्तुधों, सूती बस्त्रों, बनस्पति तेलों तथा सालियों, काजू की गिरी नथा मसालों जैसी महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुओं के मामले में यह सही था; परन्तु चीनी ग्रीर चांदी के मामक्षे में यद्यपि मूल्य भ्रपेकाकृत कम थे, फिर भी निर्यातित परिमाण उच्चतर या जिसके परिणामस्वरूप इन वस्सुम्रों के निर्यातों से होने वाली मामवनियों में 1974-75 की सदनुरूप ग्रविध की उपेक्षा काफी ग्रधिक वृद्धि हुई।

			•	- 0	
सारणा	19	:	भारत के	प्रमुख निर्यात	

(राणि करोड़ रूपयों में)

	पण्य				• मप्रैल/विसम्बर		(3)/की गुलना में (4) में वृद्धि (+)/(कमी (-)		
				1974-75	1974-75	1975-76	वास्तविक	प्रतिशत	
1				2	3	4	5	6	
. बाद्यास ग्रौर जीवित पशु	•	•		1013	669	842	+173	+ 26	
1. मछली भीर मछली से क	ी वस्तुऐं			65	47	93	+46	+ 98	
2. काजूकी गिरी .				118	93	81	-12	-13	
3. कॉफी				51	44	58	+14	+32	
4. चाय (काली) .				221	157	178	+21	+13	
5. ममाले				61	38	38		·	
6. खली -				96	66	55	-11	-17	
7. <del>ची</del> नी · ·	•		•	339	175	297	+122	+ 70	

1			2	3	4	5	6
II. शराब भीर तमाब्		,	82	66	88	+ 2 2	+-33
'भ्रपरिष्कुत तमा <b>ख्</b>	•	•	80	65	84	十19	+29
III. ईंबन को छोड़कर कच्ची ग्रीर श्रवास वस्तुएं			431	290	330	+40	+14
1. रूई (कच्ची और मवशिष्ट) .			17	14	19	+ 5	+36
2. মাজাক			18	14	10	<b>-4</b>	<b>— 4</b> 9
<ol> <li>कच्चा लोहा (लोहे के टुकड़ो सिंहत)</li> </ol>			160	93	139	+46	+ 29
<ol> <li>पशुजन्य भीर ननस्पतिजन्य भपरिष्कृत व</li> </ol>	स्तुर्ये (जि	नका					
भन्यत उल्लेख नहीं किया गया है)		•	117	8.8	62	-26	<del></del> 30
${ m IV}$ . खनिज इंधन, चिकनाई के पदार्थ झीर संबंधित	बस्तुए		20	13	25	+12	+ 92
V. पशुजन्य झौर बनस्यतिजन्य तेल झौर चरबी		•	34	33	31	—12	<b>—</b> 6
चनस्पति		•	34	33	30	- 3	<b>—</b> 9
VI. रसायन			104	76	69	7	<b>9</b>
VII. निमित बस्तुएं			1158	896	908	+12	+1
<ol> <li>चमड़ा भीर चमड़े से बनी बस्तुये</li> </ol>			145	111	133	+22	+20
<ol> <li>सूती बस्क्र@</li> </ol>		•	233	187	138	-49	<b>— 2</b> 6
3. जूट से बनी वस्तुये @ .			296	257	188	69	27
<ol> <li>मोती तथा भपरिष्कृत या परिष्कृत अहुः</li> </ol>	पूरुय भीर	मधं-					
बहुमूल्य पत्पर			95	66	79	+13	+20
<ol> <li>लोहा भौर इस्पात</li></ol>			86	58	69	+11	+19
<ol> <li>चांदी (बुलियन ईंट)</li> </ol>	•	•	78	5 <b>2</b>	134	+82	+ 158
VIII. मशीने धौर परिवहन उपकरण			212	133	189	+56	+42
<ol> <li>बिजली की मशीनों को छोड़कर इसर</li> </ol>	मशीने		91	59	82	+23	+39
<ol> <li>विजली की मंगीने, उपकरण भौर साध</li> </ol>	न .	•	56	39	47	+8	+21
<ol> <li>परिवहन उपकरण</li> </ol>		•	65	35	60	+ 25	+71
IX. विविध निर्मित वस्तुएं .		1	240	173	202	+ 29	+17
1. कपड़ें		•	136	97	124	+27	+28
2. जूसें . • •		•	20	14	1 4		
<b>कुल निर्यात</b> (दूसरे निर्यातीं महिस)			3304*	2355	2690	+335	14

@इनमें रेणा भीर धागा शामिल है। *इस राणि को बाद में संघोधित कर 3331 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके लिये पण्यवार विवरण मभी उपलब्ध नहीं है।

स्त्रोत: बाणिज्यिक सूचना भौर श्रक संकलन महानिदेशालय।

125. विशावर निर्मातों का विश्लेषण करने पर वर्ष के पहले तो महीनों (अप्रैल--विसम्बर 1975) के निये उपलब्ध श्रांकड़ों से यह विदित होता है कि इस प्रविध के दौरान कुल निर्यातों में 335 करोड़ सपयों की जो वृद्धि हुई उसमें से जापान की छोड़कर प्रत्म एशिया और प्रणांत महासागरीय देशों के प्राधिक एवं सामाजिक प्रायोग के सदस्य देशों को किए गए निर्यातों में 109 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई: इस वर्ग के प्रन्तर्गत हैरान को किये गये निर्यातों के मूल्यों में हुई वृद्धि लगभग 73 करोड़ स्वये थी। जापान को किये गये निर्यातों में भी लगभग 82 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। कुल निर्यातों में सभी एशिया और प्रशांत महासागरीय देशों के प्राधिक एवं सामाजिक भायोग के सदस्य देशों का श्रंभ 25 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत युरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों, उत्तरी धमेरिका (विशेष रूप से प्रमेरिका) तथा पूर्वी यूरोपीय देशों का भंग 1974 की तवनुक्रप श्रवधि की भपेका सीमात क्या से कम था।

#### भाषात

126. 1975-76 के राजकोषीय वर्ष के पहले नौ महीनों (म्रप्रैल—विसम्बर) के दौरान किये गये माथातों के सम्बन्ध में पण्यवार विवरण उपलब्ध हैं; इन मायानों की राणि 3900 करोड़ रुपयें थों जो पिछले वर्ष की तवनुरूप भवधि की तुलना में 810 करोड़ रुपयों या 26 प्रित्रशत की वृद्धि की चोतक थी (सारणी 20)। इस वृद्धि के प्रमुख कारण खाचाभ (गेहूं) भीर उर्वरक थे। इसके मलावा मणीनो भीर परिवहन उपकरणों तथा मपरिष्कृत पेट्रोलियम के भायानों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके विपरीन इस्पान भीर भलौह धाउँभों के मायानों का मूल्य न्यूनतर था जिसका कारण यह था कि इस्पान के मामले में मायानों के परिमाण में कटौती की गई भीर मलौह धाउँभों के मामले में मूल्य मपेक्षाफ़ुन कम था।

सारणी 20: भारत के प्रमुख ग्रायात

(राणि करोड़ स्वयों मे)

पण्य		<b>म</b> प्रैल-रि		की तुलना में (4) में वृद्धि(+)/ कभी (-)	
	1974-75	1974-75	1975-76	यास्तविक	সবিগণ
1	2	3	4	5	6
I. चाद्याच्य तथा जीवित पशु	855	542	1017	+475	+88
1. गेहू	698	415	887	+472	+114
2. काजू	37	33	30	-3	— 9
II. शराच भौर तमाच्	1	1	1	مجند	
🔟. ईंधन को छोड़करकच्ची ग्रौर ग्रखाग्र वस्तुएं.	219	155	164	<b>+</b> 9	+6
रेगों की बुँछोड़कर मच्ची रूई	27	1.9	25	$+\epsilon$	+ 32
IV. व्यक्तिज ईंधन, चिकमाई के पदार्थतथा संबंधित वस्तुएं .	1157	881	912	+31	+4
<ol> <li>भ्रपरिष्कृत तथा भंगत परिष्कृत पेट्रोलियम</li> </ol>	955	727	772	+45	+6
2. पेट्रोशियम से बनी वस्तुये	202	154	139	15	10
V. पशुजन्य और वमस्पतिजन्य तेल और वरबो	35	31	16	-15	48
VI. रसायन	712	402	627	+225	+ 56
<ol> <li>रासायनिक तत्व तथा मिश्र</li> </ol>	179	120	135	<del>/-</del> 15	+ 1.3
<ol> <li>दवाद्या भीर भी०धीय वस्तुये</li> </ol>	34	24	27	+ 3	+13
<ol> <li>निर्मित्त उर्धरक</li> </ol>	425	207	406	+199	+96
VII. निर्मित वस्तुएं	763	549	464	8 5	-15
1. लोहा भीर इस्पान	417	297	236	61	- 21
2. ग्रलौह धातुर्ये	178	135	72	63	47
VIII. मशीने ग्रौर परिवहन उपकरण	670	495	649	+154	+31
<ol> <li>बिजसी की मणीनों को छोड़कर इतर मणीनें</li> </ol>	397	301	406	+105	+35
2 विजली की मंगीने, उपकरण श्रीर साधन	150	101	146	+ 45	+ 45
<ol> <li>परिवहन उपकरण</li> </ol>	123	9.3	98	<del>+</del> 5	+ 5
IX. चिकिध मिसिस वस्तुएँ	46	31	38	<del></del> 7	+23
कुल भागात	4468*	3090	3900	+810	+26

^{*}इस राणि को बाद में संशोधित कर 4520 करोड़ रुपये कर दिया गया है। असके पण्यवार विवरण श्रभी उपलब्ध नहीं है।
स्मोतः वाणिज्यिक सूचना ग्रीर ग्रंक सकलन महानिदेणालय।

127. ग्रमेरिका और यूरोपीय साझा बाजार के मदस्य देशों मे किये गये ग्रायातों में प्राक्षोच्य ग्रवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई जबिक मौवियत समाजवादी जनतन्त्र सब भौर ईरान से किये गये ग्रायातों की मात्रा 1974 की उसी ग्रवधि की ग्रपेक्षा कम थी।

# व्यापार नीति

128. लगातार दूसरे वर्ष भी भारी माला मे व्यापार घाटा जारी रहने से उससे बचने के लिये निर्यात भामवित्यों में वृद्धि करने की भावप्यकता उत्पन्न हुई। स्थेज नहर के पुन खुल जाने से निर्यातों की भामदिनियों की असुली शीधता से हो सकेगी तथा माल भाड़े में कुछ बचन भी हो सकेगी। इसके भ्रलावा वेण की व्यापार नीति को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया गया है कि निर्यातों का विस्तार हो तथा विभिन्न कीलों में निर्यात किया गया है कि निर्यातों का विस्तार हो तथा विभिन्न कीलों में निर्यात किया गया है कि निर्यातों का विस्तार हो तथा विभिन्न कीलों में निर्यात किये जाएं। हाल ही में गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये कई उपाय किये गये हैं नाकि उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हो। इन उपायों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित व्यवस्थाये सम्मितित हैं निर्यातों के प्राप्त माले उत्यावन में वृद्धि करने के निर्मित्त प्रोत्साहन दिये गए; इंजीमियरी वस्तुमों जैसी 'विकासपरक' वस्तुमों के निर्यातों को बढ़ाने के खिये प्रोत्साहन प्रदान किया गया; सीता गुल्क वापसी की पानताम्रों के भाषार पर निर्यातकों को मनुस्चित वैंकों द्वारा भविम प्रवान किये गए;

निर्मात ऋण की णतों में रियायत की गई; झास्थगित झदायगी की भतों पर पूणीयत झौर इंजीनियरी वस्तुमों के निर्मातों की कियाविधियों को सरल बनाया गया भीर इंजीनियरी परामर्ण सेवाओं तथा पाल निर्मात प्रतिष्टानों को विदेशी मुद्रा प्रदान करने की कियाविधियों को ख्रौजिस्यपूर्ण बनाया गया। (33)

# थिकास की संभावना : 1976-77

129 1975-76 की अर्थव्यवस्था के इस सिक्षण्त मूल्यांकन से जो विन्न उभरता है, वह समग्र रूप से यह है कि अर्थव्यवस्था उचित मूल्य स्थायिता के वातावरण में अपने सामान्य विकास को पुनर्व्यक्तियात कर पाई है। यवि इतना ही विकास आगामी वर्षों में भी हुआ, तो इस कथन का भौवित्य सिद्ध होगा। इस पुष्टभूमि में 1976-77 के विकास की संभावना का चिन्न प्रस्तुत करना है। इस प्रकार करने से स्थूल रूप से अगले वर्ष में अर्थव्यवस्था में आने वाले भवसरों का सकत प्राप्त होगा।

130 इटिंग क्षेत्र समग्र विकास की भूमिक। प्रस्तुत करता है। उक्त क्षेत्र व्यापक रूप से मौसम से प्रभावित होता रहता है। इससे विकास की संभावनाओं का सुनिष्चित सृख्यांकन नहीं किया जा सकता। एक बात

⁽²³⁾ इनमे मे नियात विकास सम्बन्धी किनिषय प्रयासीं के विवरण इस रिपोर्ट के भाग II में दिये गये है।

स्पष्ट प्रतीत होती है कि 1975-76 में कृषि क्षेत्र में लगभग 8 प्रतिभत की वृद्धि जो पाई गई, वह समान रूप से अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण हुई है । यद्यपि इस क्षेत्र की उत्पादन सभावना को नये भिळार तक बढ़ाया जा रहा है फिर भी आगामी वर्ष में उतनी ही वृद्धि की आशा करना अवास्तिक नहीं होगा, किन्तु मौसमी परिस्थितियों के अनुकूल होने की संभावना से कृषि उत्पादन की अपेकाकृत सामत्य वृद्धि की आगा करना उचित प्रतीत होता है। इस परिस्थिति के कई कारण है: उर्वरंक, बिजली भौर उत्तम बीजो जैसी मूल वस्तुओं की पूर्ति में सामान्य सुक्षार पाया गया। बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यंकमो में सिचाई पर जोर दिया जाता है और 1975-76 में कृषि प्राय में वृद्धि होने के कारण निजी निवेण के बढ़ने की प्रत्याशा है।

131 धागामी वर्ष में आधिक नीति में प्रमुख रूप से ग्रीबोगिक विकास के पुनरुत्थान के प्रश्न पर जोर दिया जाएगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये उक्त नीति में तीन बातों की परिकल्पना की गई है, जो इस प्रकार हैं निवेश में प्रयोग वृद्धि, मांग की मन्दी से प्रभावित उपक्षेत्रों में पाई गई मन्दी की प्रवृत्तियों में सुधार ग्रीर पूर्ण रूप से क्षमता के उपयोग को बढाना। यह बात अवश्य है कि इन सभी बातों का प्रभाव तस्कास 1976-77 में ही ग्रीबोगिक विकास की दर में परिकक्षित नहीं होंगा। किन्तु निर्विष्ट ग्रविध में ग्रीबोगिक विकास की सभावना को ग्रिधिक माजा में बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

132 ग्रर्थरुयवस्था की वर्तमान स्थिति से यह प्रतीन होता है कि मूल्य स्थायिना मे बाधा डाले बिना प्रधिकतर निवेश कराने की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न होगी। पहले से ही काफी मात्रा में इकट्टे किये गये खाद्याक्षों के स्टाको धीर कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने की वर्तमान संभावनामी से यह प्रतीन होता है कि निर्वाह बस्तुये भवण्य ही पर्याप्त माला में उपलब्ध होंगी । केन्द्रीय गरकार 1976-77 में योजना परिष्यय मे - 31,4 प्रतिशत की बद्धि करने की घोर प्रग्रसर है। इस कारण सार्वजनिक श्रीर निजी, दोनो क्षेत्रों मे प्रधिकतर निवेण का वातावरण निर्मित हो भूका है। निवेश को बढ़ाने की सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता काफी बढ़ गई है क्योंकि कर प्रणासन को मजबून कर देने से कर से प्राप्त होने वाली राणि में बहुत ग्राधिक वृद्धि होगी भीर प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो से पहले की भ्रापेक्षा भ्रव भीर भ्रासानी से राशि निकालने की काफी मधिक गृंजाइश है। इसके म्रालाबा सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र के निवेश में तीवना लाने के लिये कई उपाय किये है जिनमें निम्नलिखित शामिल है: लाइसेंस पद्धति में सुधार किया गया, लाभांगों की घोषणा पर लगाये गए प्रतिबन्धों को ब्रारम्भ में थोड़ा सा कम किया गया श्रीर भन्ततः उक्त प्रतिबन्धो ग्रीर क्रोनस ग्रेयरो के निर्गम पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। श्रायात नीति को उदार बना दिया गया है तथा चुने हुए उद्योगो में उत्पादन को बढ़ाने के लिये की कराधान के सन्दर्भ मे प्रोत्साहनो की क्यवस्थाकी गयी है। इनके अलावा 1976-77 के केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर बिन्यास को ग्रीचित्यपूर्व बनाने सथा बचत ग्रीर निवेण के लिये दिये जाने वाले प्रोत्माहनो को बढ़ाने पर धिक जोर विया गया है । यद्यपि सरकार द्वारा दिये आन नाले प्रोत्माहन श्रौर उसके प्रति निजी क्षेत्र के धनुकल महान के बीच काफी समय लग जाता है, फिर भी यह ब्राह्मा करना उचिम है कि जैसे ही सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की आएगी निजी क्षेत्र के-निवेश में भी 1976-77 में वृद्धि होगी।

133. यद्याप पूंजीगत बाजार में मन्दी जारी रही है फिर भी उनके पुनिवकाम के सकेत उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिये गैर सरकारी मार्वजनिक सीमित कम्पनियो हारा 1975-76 (ग्रप्रैल-मार्च) में जारी की गई 93 करोड़ रुपयों की नई पूजी 1974-75 के 52 करोड़ रुपयों की तुलना में काफी ग्राधिक थी। इसके श्रलावा मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्राप्त सहायता का श्राकार भी व्यापक था। भारतीय ग्रीग्रा-िगक विकास बैंक, भारतीय ग्रीग्रांगिक ऋण ग्रीर निवंग निगम तथा भारतीय ग्रीग्रांगिक श्रींग्रांगिक श्रीं

विनरित की जाने वाली राशि सामान्य रूप से मीयादी ऋण प्रवान करने वाली संस्थाभ्रो की कुल विसीय सहायता की लगभग दो तिहाई होती है। उपर्यक्षन संस्थाभ्रो की उक्त राशि 1974-75 की तुलना में कमश. 33 प्रतिशन भीर 24 प्रतिशत अधिक थी।

134 ग्रार्थिक नीति के भ्रन्तिम दो तस्वों पर जब ध्यान देने हैं तब देशी मांग की मन्दी से प्रभावित कुल उद्योगों में पून सुधार परिलक्षित होगा। इस सन्दर्भ में बस्त्र उद्योग का स्थान उल्लेखनीय है। 1975-76 में कृषि माय में पर्याप्त वृद्धि हुई। म्रातः वस्त्रां के लिये ग्रामीण मांग महेगी। इसी प्रकार 1976-77 के बजट में ग्राय ग्रीर संपत्ति के कर की दरों में कभी करने और उत्पादन शुल्कों में हाल ही में समायोजन किये जाने के कारण टिकाऊ उपभोक्ता बस्तुओं की माग शायद पून. बढ़ जाएगी। बस्तुत: परोक्ष करों के वर्तमान विन्यास का व्यापक भ्रध्ययन करने के लिये हाल ही मे भारत सरकार द्वारा एक समिति का नियुक्त किया जाना परोक्ष करो, विभोष कर उत्पादन शुल्कों के श्रौचित्यीकरण की दिशा में एक ब्रौर कदम है। विष्य-रुपापी मन्त्री में सामान्य रूप से ही सही सुधार की श्राणा है। प्रतः निर्यातों के लिये भारतीय घौद्योगिक वस्तुग्रों की मांग में वृद्धि हो सकती है। **हा**ल ही में नियति सम्बन्धी प्रोत्साहनों के वर्तमान ढांचे को मजबूत बनाने की भी कोशिश की गई है। इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाहियों में निस्नलिखित शामिल हैं . भ्रनेक इंजीनियरी वस्तुग्रों मौर कुछ परम्परागत उत्पादों के लिये म्रिनिस्कित नकदी प्रोत्साहन दिये गये। भायातों की पालता में वृद्धि की गई, नियंति भूल्क मे कटौती की गई भीर नकदी सहायमा ग्रीर शुल्क वापसी की ग्रदायगी में तेजी लाई गई।

135. मौद्योगिक विकास की 1976-77 की संभावनाओं का खिल इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ कतिपय कोड़ क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में 197 -76 में मसाधारण रूप से हुई प्रधिक वृद्धि को दोहराना सभव नहीं होगा और दूसरी तरफ कुछ प्रत्य उद्योगों के उत्पादन में गिराबट की जो प्रवृत्ति प्राई उसमें पिरवर्तन था सकेगा। इस बाल के सकेत हैं कि ग्रीद्योगिक उत्पादन की गित में तीव्रता था गई है। उदाहरण के लिये 1976 के पहले 4 महीनों के दौरान श्रीद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1975 की लुलना में 11.5 प्रतियत प्रधिक था। यदि यह बाल समग्र प्रवृत्ति का संकेत हैं, तो 1976 में 6 से 7 प्रतियत कक की वृद्धि दर की ग्राणा की जा सकती है।

136 इस मन्दर्भ में 1976-77 में उभरने वाले माग सम्बन्धी संभाव्य दशावो घौर मुद्रागत तथा ऋण सम्बन्धी नीतियों पर उनके प्रभाव की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित करना उचित होगा। राजकोर्षाय ग्रौर मुद्रागत नीतिया का प्रमुख उद्देश्य सांग प्रबन्धन है। यह इस बान से स्यष्ट होना है कि क्या ज दर की नीतियों सहित जो नियंद्रक ऋण नीतिया 1974-75 में प्रारम्भ की गयी वे श्रव भी जारी है। इसीप्रकार राजकोषीय क्षेत्र में उच्चतर धाय कर दाताओं भीर भनिरिक्त महंगाई भन्ते के सन्दर्भ में ग्रनिवार्य जमा क्वारा अतिरिक्त आय को अवरुद्ध करने की वर्तमान योजना को एक ग्रीर वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है। इसके घलाना यह भी संकेत दिया गया है कि जुलाई 1976 के बाद जमा की गई राशि को 12 5 प्रतिशत के ज्याज के साथ निर्धारित अविधि के बाद नकदी में ब्रदा किये बिना घभिदाताओं की भविष्य निधि में जमा कर दिया जाएगा। माग प्रबन्धन के इन दबाकों के जारी रहने के बावजूद तीन मुम्पष्ट स्नोत है जिनमें माग के दबाव उभर सकते हैं। वे स्नोत इस प्रकार है निवेश भवरुद्ध जमाराणियों को लौटा दना और मैंकिंग क्यवस्था। यदि मार्वजनिक भीर निजी क्षेत्रों के निवेश में 1976-77 में प्रत्याणित वृद्धि हो सा स्थावर साधनो की पूर्ति ग्रौर मांग के सन्तुलन पर दबाब झाएगा। दूसरा कारण इस तथ्य में उभरता है कि केन्द्रीय सरकार बजट में परिकल्पित 320 करोड़ सपयों के घाटे के प्रालावा उपर्युक्त श्रवरुद्ध जमाराणियों से 480 करोड़ रुपयों का उधार भारतीय रिजर्व वैक से ले सकती है; इसके साथ ही 1974-75 में मवरद्ध जमाराणियों को जुलाई 1976 से नकदी में लौटा देना शुरू हो जाएगा मौर 1976-77 में इस प्रकार लौटाई जाने वाली कुल राणि 270 करोड़ रुपये होगी जिससे व्यय में वृद्धि हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि बैंकिंग व्यवस्था के साधनों की स्थिति संप्रति सन्तोषजनक है और जमा राशियों के बढ़ने के साथ साथ उक्त स्थिति में घौर सुधार होगा। इसके विपरीत यदि निवेग में वृद्धि हो तो ऋण की माग बढ़ जाएगी।

137. खाद्याओं जैसी मूल वस्तुयों की पूर्ति थौर सांग के बीच फिलहाल सन्तोषजनक सन्तुलन हैं भीर यह स्थिति शोजनीय हाथि वर्ग की
कठिनाई का सामना करने में समर्थ है। किन्तु मूल्य स्थायिता की लाजीकी
स्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती थौर इस सन्दर्भ में निरन्तर निगरानी
रखनी चाहिये। इसके भलावा एक ऐसे तंत्र को स्थापित करने की भी
भाषश्यकता है जो एक भीर भ्रलग भगल क्षेत्रों/वस्तुयों की पूर्ति भौर मांग
के बीच भ्रमन्तुलन के उभरने का पता लगा सके भौर उसके सकत वे सक
तथा दूसरी थार ऐसे भ्रमन्तुलनों को भ्रविलम्ब दूर करने के लिये प्रभावकारी
भवन्ध की व्यवस्था कर सके। इस सन्दर्भ में देशी वसूली भौर/या भायातो
से सबेदनशील बस्तुभों के पर्याप्त स्टाक बनाये रखने भौर वितरण तन्त्र
में विश्वमान भसंगतियों का दूर करने के लिये प्रशसकीय क्षमता भौर
सामर्थ्य को भीर बढ़ाना चाहिये। इसी प्रकार जहा लजीकी स्थित की
गुंजाक्षण भवप्य है वहां पिछले दो वर्थों से चल रहे मूलभूत मुद्रागत भौर
राजकोषीय भ्रनुशामन को सफलतापूर्वक बनाये रखने की भ्रावश्यकता है।

138. दीर्षकालीन वृष्टि से 1975-76 में बन्न भीर निवेश मे पाई वृद्धि दरों को कम से कम बनाये रखना भत्याधण्यक हैं, भने ही उन्हें बढ़ाया न जाए। सरकार की हाल ही की माधिक नीतियों को इस प्रकार पुनर्ध्यवस्थित किया गया है कि बन्त भीर निवेश की उच्चतर दरों को बनाये रखना सम्भव हो। भाषात काल भीर 20 सूत्रीय भाषिक कार्यक्रम ने एक ऐसा वातावरण निर्मित कर विया है कि मार्वजनिक क्षेत्र में समप्रतः क्षमता के उच्चतर स्तर उभर भाये है। जैसा कि इस रिपोर्ट में भन्यत उल्लेख किया गया है, निजी क्षेत्र को कई प्रकार के प्रोत्साहन दिये गये हैं लाकि वह भपने निशेश भीर उत्पादकता को बढ़ा सके। इन कार्रवाइयों के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया कुछ समय के बाद ही प्रकार में भाएगी। यदि मार्वजनिक भीर निजी क्षेत्र सुनिश्चित प्रयाम करें नो पांचवी योजना में निर्धारित राष्ट्रीय भाय की बृद्धि दरों को मूल्य स्थायिता के वानावरण में बनाये रखना संभव होना चाहिये।

139. समापन के पहले यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि 1976-77 के पूर्व की अर्थव्यवस्था में उच्चतर विकास दरों तक पहुंचने और उन्हें बनाय रखने के लिये अपेक्षित क्षमना निहित है। यह क्षमता प्रन्य बातों के साथ साथ बचत और निवेण की उच्च दरों, प्रक्षिक मान्ना में खाद्याओं की उपलब्धना और प्रारक्षित विवेणी सुद्रा निक्षियों में पन्तर्निहित लोच से उत्पन्न हुई है। प्रशासकीय क्षमता और प्रवन्ध नन्त्रों के सन्वर्भ में 1975 के बीच से अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन में जो धनुभव प्राप्त हुआ है उससे अर्थव्यवस्था को उच्चतर पूंजी संस्थन और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में काफी सफलना मिलनी चाहिये।

# बारिएज्य बैंक व्यवसाय की प्रगति

140 णाखा विस्तार करने, जमाराशियां जुटाने तथा मामाजिक और धार्मिक ध्रप्रताबाल क्षेत्रों को ऋण प्रवान करने को सम्बन्ध में पाई गई बाणिज्य बैंक व्यवसाय की विकासपरक प्रशृत्तियों को 1975-76 के दौरान भी बनाये रखा गया। वास्तव में जमा संचयन की गित में जहां पिछले वर्ष गिरावट आई थी वहां फिर तीक्रता ध्राई भौर उसकी दर बढ़कर 20.0 प्रतिशत हो गई जो 1974-75 की ध्रपेक्षा 3.4 प्रतिशत श्रीधक थी। जमाराशियों की वृद्धि का स्वरूप लगभग पिछले वर्ष की तरह ही

या मर्थात् वृद्धिशील जभाराशियों का लगभग दो तिहाई भ्रोत मीयादी जमाराशियों का या। 1975-76 के दौरान 28.0 प्रतिशत का जो ऋण विस्तार हुआ। वह 1974-75 में हुए विस्तार की तुलना में दुगुना था। परन्तु ऋण में जो कुल वृद्धि हुई उसका माधे से भी मधिक श्रण आराधान्नीं की सार्वजनिक वसूली ग्रौर वितरण के लिये दिये गये ऋण का था। इसके कारण निम्न प्रकार थे: इस वर्ष फसलों की सर्वाधिक कटाई हुई तथा बाद्याक्षों के स्टाकों के वित्तपोषण की व्यवस्था बजट में करने के बजाय उस कार्य को वाणिज्य मेंक व्यवसाय तन्त्र को भन्तरित करने का निर्णय किया गया। इसके बावजूद खाद्येतर ऋणों में हुई वृद्धि की दर भी पिछले वर्ष की भपेक्षा उच्चतर (11.2 प्रतिशत के मुकाभले में 13.7 प्रतिशत) थी। ग्रालोच्य वर्ष के दौरान वाणिज्य बैकों के लाभों में भी ग्रीर वृद्धि पाई गई। भालोच्य वर्ष के दौरान जो भन्य महत्वपूर्ण गतिविधिया पाई गई उनमें निम्नलिखित सम्मिलित थी देश मे 19 क्षेत्रीय ग्रामीण सैकों की स्थापना की गई भीर बैंक ऋष की भनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित ग्राध्ययन दल की सिफारिश को कार्यान्त्रित किया गया। बैकीं को इस प्रकार सुरुधर्वास्थत करने के लिये भी व्यवस्थाये प्रारम्भ की गई कि वे 20 सूत्रीय माधिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उचित सहायता प्रदान कर सके। मन इन गतिविधियों का ब्यौरेबार विश्लेषण किया जाए। शाखा विस्तार कार्यकम

141. वाणिज्य बैकों क योजनावद भीर सुनियोजित शाखा विस्तार की नीति पर भाजीच्य वर्ष के दौरान और गम्भीरतापूर्वक भमल किया गया। यह मुनिश्चित करने के लिये कि निरन्तर शाखा विस्तार होता रहे, सभी भनुभूचित बाणिज्य बैकों भीर सीम गैर अनुभूचित बैकों को सितम्बर 1975 में यह सूचित किया गया कि वे भागामी तीन वर्षी अर्थात् 1976 से 1978 तक के वर्षों के लिये माखा विस्तार की भपनी भावी योजनाओं को प्रम्तुत करें। वाणिज्य बैंक व्यवसाय की मुविधायें प्रवान करने के मामले में हम बात को ब्याम में रखा गया कि क्षेत्रीय भसन्तुलन को कम करने की निरन्तर आवण्यकता है तथा धैंकों से यह कहा गया कि वे भपनी भावी योजनाओं में यथासम्भव अधिकाधिक बैक राहित/कम बैंक स्विधायुक्त केन्द्रों को सम्मिलन करें भीर पूर्वी तथा पूर्वोत्तर कियों नया जन जिलों पर जहां प्रति बैंक कार्यालय जनमंत्रया 75,000 भीर अधिक है, विशेष ब्याम दें।

142. इस नीति के परिणामस्यस्य वाणिज्य बैकों के शाखा विस्तार कार्य में झालोच्य वर्ष के दौरान झौर व्यापकता झाई। 1975 के कैलेंडर वर्ष के दौरान वाणिज्य बैकों ने 2,329 कार्यालय खोले जब कि उसके पूर्व वर्ष में 1,693 कार्यालय खोले थे। इसके परिणामस्वस्य प्रति बैक कार्यालय राष्ट्रीय झौसत जनसंख्या विसम्बर 1974 के झन्त में जहां 30,000 थी वहां दिसम्बर 1975 के झन्त में घटकर 27,000 झौर जून 1978 के झन्त में झौर घटकर 26,000 हो गई। परन्तु 30 राज्यों/संघणासित क्षेत्रों में से 6 राज्यों/संघणासित क्षेत्रों में प्रति बैक 'कार्यालय जनसंख्या 50,000 से झिक (1971 की जनगणना) थी झौर मिजोरस के मामने में यह जनसंख्या 1 लाख से भी झिक थी।

143. 1975-76 (जुलाई-जून) के दौरात वाणिज्य बैंकों में 2,554 कार्यालय खोले जबकि पिछले वर्ष (जुलाई-जून) उन्होंने 1,803 कार्यालय खोले थे। प्रालोच्य वर्ष के दौरान खोले गये नये कार्यालयों में से 556 कार्यालय स्टेट बैंक भार इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा, 1,156 कार्यालय राष्ट्रीयक्कत वैंकों द्वारा, 730 कार्यालय गैर सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंको द्वारा भीर 112 कार्यालय क्षेत्रीय प्रासीण बैंकों द्वारा खोले गए।

# वैक रहित केम्ब

144 भालोच्य वर्ष के दौरान बैंकों के विस्तार कार्य में भौर मुधार हुआ। भालोच्य वर्ष के दौरान खोले गए 2,554 कार्यालयों में से 859 कार्यालय भव तक के बैंक रहित केन्द्रों में खोले गये (सारणी 21)।

इस सन्दर्भ में की गई प्रगति का यदि मूल्यांकन किया जाए तो यह उल्लेख-नीय होगा कि राष्ट्रीयकरण के बाद धर्यात् 19 जुलाई 1969 से जून 1976 के धन्त तक खोले गये कुल 13,035 कार्यालयों में से लगभग भाषे (6,061 या 46.5 प्रतिशत) कार्यालय केंक रहित केन्द्रों में खोले गये थे। इन नये कार्यालयों में कम बैंक मुक्धिगुक्त राज्यों प्रथित् धनम, बिहार, जम्मू धौर काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेवालय, नागालैंड, उड़ीसा, क्षिपुरा, उक्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का धंश 33.7 प्रतिशत धा (सारणी 22)।

# पामीण क्षेत्रों में शाबा विस्तार

14.5. जनसंख्या के वर्गों के धनुसार वाणिज्य वैकी की व्यापकता के आंकड़े सारणी 23 में विथे गये हैं। उनसे यह विवित होगा कि कुल बैक

कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में कोले गये बैंक कार्यालयों का अनुपान जहीं ज्न 1973 के अन्त, जून 1974 के अन्त और जून 1975 के अन्त में कमण: 36.2, प्रतिशत 36.4 प्रतिशत और 36.3 प्रतिशत था वहां जून 1976 के अन्त में थीड़ा सा घटकर 36.2 प्रतिशत हो गया। इस गिरावट का प्रमुख कारण यह है कि उजिन बैंक व्यवसाय की क्षमनायुक्त अधिकाश ग्रामीण केन्द्रों में बैंकों की शाखायें खोली जा चुकी थी। फिर भी बैंकों से यह कहा गया है कि वे शाखा निस्तार की अपनी भाषी योजनाओं में यथासंभव अधिकाधिक ग्रामीण केन्द्रों, विशेष रूप से बैंक रहित सामुदायिक निकास खंडों की सम्मिणित करें।

सारणी 21: 1974-75 झीर 1975-76 के दौरान वाणिक्य वैकों द्वारा कोले गए नये कार्यालय

र्बंभ समृह		वाणि	ज्य बैंकों द्वारा	बोले गये नये का	र्गालय		बैक प	गर्यालयों की सं	<b>इ</b> या
		1974-75	<del>-</del>	1975-76				<b></b>	
•	जुलाई-दिसम्बर 1974	जनवरी-जून 1975	जुलाई-जून 1974-75	जुलाई-विसम्बर 1975	जनवरी-जून 1976	जुलाई-जून 1975=76	30 जून 1975 को	21 दिसम्बर 1975 को	30 जून 1976 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. स्टेट बैंक झॉफ इंडिया ,	311 (128)	93 (49)	404 (177)	326 (169)	121 (56)	<b>447</b> (225)	3, 475	3, 801	3, 922
2 स्टेट वैंक ग्रॉफ इंडिया के सहायक वैंक .	58 (21)	30	<b>88</b> (27)	63 (15)	46 (11)	109 (26)	1,739	1,802	1,848
3. 14 राष्ट्रीयकृत भैंक .	607 (187)	244 (55)	851 (242)	859 (257)	297 (92)	1156 (349)	9,863	1,0718	11,010
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक .			_	9 (8)	103 (71)	112 (79)		9	112
<ol> <li>ग्रन्य भनुसूचित वैक .</li> </ol>	264 (55)	180 (33)	444 (88)	504 (127)	206 (45)	710 (172)	3,385	3,841	4047
6 विदेशी वैंक .	1 (-)	 (-)	1 (-)	 (-)	 (-)	(-)	131	130	140
7. सभी भ्रतुसूचित वाणिज्य बैंक	1,241 (391)	547 (143)	1,788 (534)	1,761 (576)	773 (275)	2534 (851)	18,593	20,301	2 I 0 69
<ol> <li>गैर धनुभूषित वाणिष्य धैक</li> </ol>	8 ( 6)	7 (7)	15 (13)	14 (6)	6 (2)	20 (8)	137	145	151
9. सभी बाणिज्य बैंक	1,2 <b>4</b> 9 (397)	554 (150)	1,803 (547)	1 ₄ 775 (582)	779 (277)	2,554 (859)	18,730	20,446	21,220

टिप्पणी : कोच्ठकों में दिये गये झांकड़े बैंक रहित केन्द्रों में खोले गमें कार्यालयों की संख्या को वशति हैं।

सारगा 22: जून 1974, जून 1975, विसंबर 1975 घीर जून 1976 से ग्रंत में विद्यमान बैक कार्यालयों का राज्यवार वितरण

	निभ्नलिखित	स्रवधिके स्रंत	में सैक कार्यालयों	की संख्या	1974-75 के दौरान खोले	उनमें से बैंक	19 <b>7</b> 5-76 के दौरान खोले	उनमें <b>में बै</b> क		स्त्रत <mark>प्र</mark> वधि वैक कार्याल	
राज्य/संघणासित	जून	ज्न	दिसंबर 1075	जून 1976	गगे (जुलाई	रहित केन्द्रों	गये (जुलाई	रहित केन्द्रो		क्षककालाः हिजारे	
क्षेत्र	1974	1975	1975	1976	1974 से जून 1975 तक)	म खाल गय	1975 से जून 19 <b>7</b> 6 नक)	में खोल गये	जून 1975	<b>विसंबर</b> 1975	जून 1976
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
माध्य प्रवेश	1,234	1,373	1,494	1 550	142	42	177	60	32	29	28
भ्रमम	184	214	253	263	28	10	57	17	68	58	5 6
बिहार	672	796	890	953	126	66	157	72	71	63	59
गुजरात	1,436	1,552	1,686	1,711	117	18	161	45	17	16	16
हरियाणा	390	438	491	530	48	21	92	42	23	20	19
् हिमाचल प्रदेश	159	181	198	209	22	9	28	17	19	17	16
् जम्म् ग्रौर कश्मीर	164	181	227	232	26	7	43	20	24	20	20
कर्नाटक	1,621	1,750	1,857	1,905	130	26	183	59	17	16	1.5
केरल	1,163	1,296	1,435	1,473	133	46	177	71	16	15	1.4
मध्य प्रदेश	829	914	999	1050	95	27	137	37	46	42	40
महाराष्ट्र	2,005	2,188	2,335	2,381	183	44	210	52	23	22	2 1
मणिपुर	9	10	11	13	1		3	1	107	98	83
मेघालय	18	21	26	30	3	2.	9	4	48	36	3 4
नागालैड	7	8	13	14	1	1	6	2	6.5	40	37
उ <b>ड़ी</b> सा	255	301	356	382	46	26	81	47	74	62	5 7
र्पजाब	869	961	1,062	1,107	93	34	146	51	14	13	1 3
राजस्थान	743	792	852	877	49	1 4	87	23	33	30	25
<b>ममिलनाडु</b>	1,784	1,935	2,058	2,093	152	35	161	33	21	20	20
त्रिपुर।	18	20	22	24	2	1	4	2	78	7 1	63
उत्तर प्रदेश	1,673	1,896	2,095	2,218	223	94	322	124	47	42	4
पश्चिम बंगाल	987	1,090	1,241	1,317	103	20	227	66	41	36	3
ग्रंदमान ग्रौर निक	ोबार										
द्वीपसमूह्	5	5	5	6		_	1	1	23	23	1 9
स्रमणाचल प्रदेश	6	7	9	10	1	1	3	3	67	52	4
<b>संडी</b> गढ़	44	53	57	57	9		4	I	5	5	:
दादरा श्रीर नगर		4	4	4		_			19	19	11
दिल्ली	502	563	604	619	61	<del></del>	58	2	7	7	1
गोवा, दमण श्रौर		140	149	153	7	2	14	5	6	6	•
लक्षत्रीप	4		4	4	<del></del>	,		·	8	8	
मिजीरम	1		I	2	_		1	1	332	332	16
वाडिचेरी	26	28	30	33	2	1	5	1	16	16	1
जो <b>ष्ठ</b>	16,936	18,730	20,446	21,220	1803	547	2,554	859	29	27	2

### विदेशों में कार्यासय

146 सृत्यविध्यत एवं समितित रूप में विवेशों में भारतीय बैंकों के कार्यालय खानते का प्रश्न कुछ समय से सरकार तथा दिन्नवें बैंक का ध्यान आकर्षित करना था रहा है। विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं के विस्तार का कार्यक्रम बनाते समय जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं. विदेशों मुद्रा की शामदत्ती, भन्य वेशों के साथ भारत के ख्यापार में विकास और विदेशों में संयुक्त प्रतिष्ठानों को स्थापित करने में भारतीय उद्यमियों की सहायता। धालोक्य वर्ष के वौरान भी पश्चिम एशियाई प्रदेण तथा धन्तरिष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता दी जाती रही।

147 विदेश $(^{24})$  (पाकिस्तान ग्रीर बंगला देश को छोड़कर) स्थित भारतीय बैंकों के कार्यालयों की संख्या 1973 के प्रांत में विश्वमान 54 से बढ़कर 1974 के भंग में 62 भीर 1975 के भग में भीर बढ़कर 75 हो गयी। 1975 के दौरान खोले गर्ये 13 कायलियों में में 5 कार्यालय ब्रिटेन में, 4 कार्यालय हांगकाग में, 2 कार्यालय किन्नी द्वीपसमूह मे तथा एक-एक कार्यालय बहामास ग्रीर दुवर्द में खोले गये। जिन 8 भारतीय बैंकों के कार्यालय विदेशों में स्थित थे उनमें बैंक आफ़ बड़ीदा के कार्यालयां की संख्या 34 थी; उसके बाद बैंक ब्राफ़ इंडिया का स्थान था (14 कार्यालय)। यदि देशवार देखा जाए तो भारतीय बैकों के सर्वाधिक कार्यालय ब्रिटेन (20) में थे, तदनतर फिजी द्वीपसमूह (10), केल्या भ्रीर हांगकांग (प्रत्येक में 9 कार्यालय), सिंगापूर (6) तथा मारिशस (5) का स्थान था। जनवरी-मई 1976 के वौरान विवेशो में छः भौर कार्यालय खोले गये ग्रर्थात् ब्रिटेन, भ्रमेरिका, हांगकाग, मारिशस, संयुक्त ग्ररब राष्ट्र समुदाय ग्रीर ग्रोमन में एक-एक कार्यालय खोला गया। इनके प्रलावा स्टेट बैंक भ्राफ़ इंडिया का एक कार्यालय बंगला देश में तथा बैंक आफ इडिया श्रीर बैंक श्रॉक बड़ौदा के विदेशी सहायक बैकों के 5 कार्यालय नाइजीरिया ग्रीर युगीडा में विद्यमान थे।

148. विवेश स्थित भारतीय बैंकों की कुल जमाराशियां दिसंबर 1974 के श्रंत में विद्यमान 427 करोड़ रुपयों से बढ़कर दिसंबर 1975 के श्रंत में 651 करोड़ रुपये ही गयी। जमाराशियों मे हुई श्रिष्ठिकांश वृद्धि मीयादी जमाराशियों में हुई जिनमें 157 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई। जबिक मांग जमाराशियों में 67 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई। भारतीय बैंकों के विवेशी कार्यालयों हारा प्रदान किये गये ऋण की राशि

(²⁴) सिक्किम को छोड़कर जो भारत का एक भ्रंग है।

विसंबर 1975 के श्रांत में 396 करोड़ रुपये थी जो एक वर्ष की श्रवधि में हुई 145 करोड़ रुपयों की वृद्धि की श्रोतक थी। फिर भी उनके ऋण जमा श्रनुपात में तेजी से वृद्धि हुई श्रीर वह दिसंबर 1974 के 58.9 प्रतिशत में बढ़कर विसंबर 1975 के श्रांत में 64.4 प्रतिशत हो गया।

### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर बर्गों को ऋण प्रदान करना

149. ग्रव तक के बैंक रहित/कम बैंक मुविधायुक्त के न्द्रों में श्रपनी शाकाश्रों का विस्तार करने के भनावा वाणिज्य बैंक श्रर्थ व्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त भीर 'उपेक्षित' क्षेत्रों को उदारतापूर्वक ऋण सुविधाएं प्रवान करता रहा। उक्त क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, निर्मात, सड़क और जल परिवहन चालक, स्वनियोजित व्यक्ति, व्यावसायिक व्यक्ति श्रावि मिन्मिलित हैं। विभेदक व्याज दर योजना के श्रंतर्गत समुवाय के कमजोर वर्गों को दिये जानेवाले श्रपने ऋण में वृद्धि करने के लिए भी बैंकों ने तीन उपाय किये।

#### प्राथमिकना प्राप्त क्षेत्रों को स्रप्रिम

150. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को धनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वियोगये अग्निमो की राणि जहा दिसेंबर 1974 के प्रांत में 2112 करोड़ रुपये थी बहां दिसंबर 1975 के ग्रांत में बढ़कर 2597 कराड़ रुपये हो गयी; कुल वैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्राप्त ऋष्ण का अनुपात भी एक वर्ष की अविध में 26.4 प्रतिशत से थोड़ासा बढ़कर 26.6 प्रतिणत हो गया (सारणी 24)। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रवत्त कुल ग्रमिमों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ग्राग जहाँ दिसंबर 1974 के ग्रांत में 88.7 प्रतिशत था वहां दिसंधर 1975 के ग्रांत में बदकर 89.7 प्रतिशत हो गया। इस वृद्धि का श्रेय सपूर्णतः 14 राष्ट्रीयहरूत वैंकों को था; सभी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये मग्रिमों में इन बैंकों का मंश दिसंबर 1974 में जहां 58.0 प्रतिशत था वहाँ दिसंबर 1975 में बढ़कर 59.3 प्रतिशत हो गया। प्राथमिकना प्राप्त क्षेत्रों को वैकों द्वारा प्रवत्त कुल ग्रमिमों मे प्राथमिकता प्राप्त ग्रलग मलग क्षेत्रों के मेंश में विसंबर 1974 **के** श्रंत भीर विसंबर 1975 के अंत के बीच और परिवर्तन हुए। यद्यपि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल प्रग्निमों में 'लघु उद्योगों' का ग्रंग पहले की तरह काफ़ी मधिक बना रहा, फिर भी ऐसे मग्रिमो में उनका मंग 48.2 प्रतिशत से घटकर 44.2 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत 'प्रत्यक्ष कृषि विस्त' तथा 'सङ्क ग्रीर जल परिवहन चालकों' का ग्रंश जहां दिसंबर 1974 में क्रमणः 25.5 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत था वहां दिसंबर 1975 में बहुकर क्रमणः 27 9 प्रतिगत घोर 7.4 प्रतिशत हो गया।

सारणी 23 : वाणिजय बैक कार्यालयों का केन्द्रवार वितरण निम्नलिखित प्रविध के प्रति में कार्यालयों की संख्या

केन्द्र	जून 1969	जोड़ में प्रतिशत	जृन [*] 1972	जोड़ में प्रतिसन	जून 1973	जोड़ में प्रतिशत	जून 1974	जोर में प्रतिणत	जून 1975	ओड़ में प्रतिशत	जून 1976	जोड़ में प्रतिशत
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
— ग्रामीण	1832	22 4	1814	35 3	5561	36.2	6165	36.4	6806	36.3	7687	36.2
श्र <u>धेशह</u> री	3322	40.1	4385	32 2	4723	30.8	5089	30.0	5569	29.7	6387	30.1
शहरी	1447	17.5	2323	17 1	2573	16 7	2899	17 I	3267	17.5	3739	17 6
महानगर/पत्तन शहर	1661	20.0	2100	15.4	2505	16.3	2783	16.5	3088	16.5	3407	16.1
 जोड़	8262	100.0	13622	100.0	15362	100 0	16936	100.0	18730	100.0	21220	100.0

टिप्पणी : ग्रामीण केन्द्र: 10,000 तक की अनमंख्यायुक्त स्थान।

भ्रक्षेणहरी केन्द्र : 10,000 से भ्रधिक श्रौर 1,00,000 तक की जनसंख्यायुक्त स्थान । शहरी केन्द्र : 1,00,000 से भ्रधिक श्रौर 10,00,000 तक की जनसंख्यायुक्त स्थान ।

महानगरीय केन्द्र : 10,00,000 से प्रधिक जनसंख्यायुक्त स्थान ।

^{* 1971} की जनगणना के श्रोंकड़ों के श्राधार पर पुनर्दर्गीकृत।

सारणी 24 : प्राथमिकता प्राप्त सेन्नों को श्रमुनूचित वाणिज्य वैकों का ऋण

(राणि करोड़ रुपयो मे)

		दिसम्बर 197	4 (म्रनतिम)			दिसम्बर 197	ऽ (ग्रनंतिम)	
<b>मद</b>	स्टेट श्रैक समूह	चौतह राष्ट्रीय कृत बैंक	सरकारी क्षेत्र के वैक (2+3)	मभी भ्रमुसूचित बाणिज्य बैंभ	स्टेट <b>वैं</b> क समह	भौदह राष्ट्रीय कृत बैक	सरकारी <b>क्षेत्र</b> के खैक (6+7)	सभी श्रनुमूजित त्राणिज्य श्रेक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल बैक ऋण भाषमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण	2230	4506	6736	7993	2884	5445	8329	9769
( <b>क</b> ) কূবি								
<ul><li>(i) प्रत्यक्ष कित्त</li><li>(ii) परोक्ष कित्त</li><li>.</li></ul>	156 73	323 154	479 227		228 86	430 193	658 279	
(ख) लघुउद्योग	370	540	910	1017	410	625	1035	
(ग) सड़क और जल परिवहन चालक .	15	80	9 5	121	23	131	154	191
<ul><li>(ष) फुटकर व्यापार श्रीर छोटे कारोबार .</li></ul>	32	93	125	149	37	118	155	179
( <b>ङ</b> ) व्यावसायिक भ्रौर स्वनिघोजित व्यक्तिः .	4	30	3 4	40	5	38	43	5 1
(च) शिक्षा		4	4	4		5	5	5
'क'से'च'तककाओंड़ , .	650	1224	1874	2112	789	1540	2329	2597
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को प्राप्त सभी वैक ऋणों में कैंक समूह का प्रतिशस स्रंश	30.8	58.0	88,7	7 100.0	30.4	59 3	89 7	100.0
कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के प्राप्त ऋण काप्रतिशत	t 29.1	27.2	27.8	3 26.4	27.4	28 2	28.3	26.6

# कृषि क्षेत्र की सहायता

151. इस वर्ष दूसरे नरीकों से कृषि का विक्तपोषण करने में भी वाणिज्य बैंको की सहभागिता में पृद्धि हुई। वे छोटे कृषक विकास एजेसी/सीमांत कृषक तथा कृषि श्रम एजेंसी के क्षेत्रों के पता लगायें गये सहभागियों की महायता करते रहे। इसके श्रलावा बैंकों ने जून 1970 में प्रारंभ की गयी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वित्तपोषण की योजना के श्रन्तर्गत भी कृषकों को श्रन्त्पावधि और मीयावी वित्त प्रदान किया। (विवरणों के लिए "सहकारी बैंक व्यवसाय की गतिविधियां" शीर्षक के श्रन्तर्गत अनुकछेद 305 श्रीर 306 वेखें)।

152. विक्त पोषण संबंधी उन योजनाओं में अनुसूचिन वाणिज्य बैंक सिक्तय रूप से भाग लेते रहे जिनके लिए कृषि पुनर्वित और विकास निगम से पुनर्विक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मई 1976 के अंत तक निगम ने लगभग 382.8 करोड रुपयों की कुल विक्तीय सहायतायुक्त 1,699 योजनाए वाणिज्य बैंकों के लिए मंजूर की थीं। वाणिज्य बैंकों को निगम द्वारा विनरित की गयी राशि मई 1976 के अंत तक 106.3 करोड़ रुपयें थी जबकि एक वर्ष पहले उक्त राशि 46.4 करोड़ रुपयें थी। इन विनरणों में अधिकांश भाग (79 प्रतिभत) लघु सिचाई और खेती के मणीनीकरण की योजनाओं का था।

# भ्रम्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को सहायता

153. इसके श्रलावा विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्तिर्माण और विकास बैक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता के साथ मजूर की गयी परियोजनाओं में भी वाणिज्य बैंक भाग लेने रहें। कृषि पुनिविक्त और विकास निगम के जरिए वितरित अंतरिष्ट्रीय पुनिमिर्माण और विकास बैंक/अंतरिष्ट्रीय विकास संघ की सहायता में उनका ग्रंश जहां जून 1975 के ग्रंत में 15 करोड़ रुपये था वहा 31 मई 1976 को बढ़कर 43 करोड़ रुपये हो गया। आलोक्य वर्ष के दौरान ग्रंतरिष्ट्रीय विकास संघ ने तीन और परियोजनाओं, प्रयाद समेकित कई विकास परियोजना, राष्ट्रीय बीज परियोजना और नागार्जुनसागर व्यापक क्षेत्रीय विकास परियोजना को संजूरी दी। इनके संदर्भ में 32 करोड़ रुपयों की ग्रंतरिष्ट्रीय विकास संघ की सहायता कृषि पुनिवित्त और विकास निगम के जरिए प्रदान की जानी थी।

154. राष्ट्रीय कृषि भ्रायोग की सिफारिशों के ग्रनुसरण में केन्द्रीय महकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंको द्वारा कृषक सेवा सिमितियां गठित ग्रौर विस्तेपित की जा रही हैं। जून 1976 के ग्रंत नक 17 वाणिज्य बैंकों द्वारा 12 राज्यों में ऐसी 101 सिमितियां गठिन की गयों थीं।

### कृषि ग्रविमों की वसूली

155. सरकारी क्षेत्र के बैंको के कृषि ध्रिप्रमो (प्रत्यक्ष बित्त) की कुल मांग (भ्रथित् पिछले जून के ध्रितम शुक्रवार को विद्यमान ध्रितदेय राणि भौर जुलाई 1974—-जूम 1975 के दौरान हुई चालू माग) मे तेजी से बढ़ोस्तरी हुई। साथ ही इन बैंकों द्वारा की गयी बसूली की राशि में भी काफ़ी श्रीधक बृद्धि हुई। मांग में बसूली का श्रीखल भारतीय

प्रतिशत जहा 1973-74 के दौरान 0.2 प्रतिशत श्रधिक हुआ था वहा 1974-75 के दौरान ग्रीर अधिक हुआ भीर वह 48 2 प्रतिशत (संशो धित) से बढ़कर जून 1975 के ग्रत में 50.2 प्रतिशत हो गया।

156. मध्य और पिष्वमी केंन्नों का छोड़ कर मन्य सभी केन्नों में बसूली में सुधार होने की सूचना प्राप्त हुई। जिन राज्यों में बसूलियों में उल्लेखनीय सुधार पाया गया उनमें लिपुरा, प्राध्य प्रवेण, पिष्चम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार सम्मिलन थे। पिष्चमी क्षेत्र में यद्यपि बसूलियों का समग्र भनुपात पिछले वर्ष के 39.7 प्रतिणत पर अपरि-वितित रहा, फिर भी गुजरान में बसूली की स्थित में गिरावट पायी गयी। परंतु इस क्षेत्र के अन्य घटकों द्वारा उल्लेखनीय सुधार होने की सूचना प्राप्त होने से उक्त गिरावट समायोजित हो गयी। जम्मू और काश्मीर, मेघालय और तमिलनाडु राज्यों तथा पांडिचेरी और चंडीगढ़ के संघ-शामित क्षेत्रों में भी बसूली की स्थित में गिरावट आयी।

# ग्राम ग्रमिस्वीकरण योजना

157. आलोज्य वर्ष के दौरान 'ग्राम श्रिभिस्वीकरण योजना' के श्रांतर्गत बैंक गावों का श्रिभ्स्वीकरण करने रहे। इस योजना के श्रंतर्गत बैंक श्रंपनी गाखाओं के कार्य क्षेत्र में स्थित गांवों का व्यौरेवार तकनीकी-श्राधिक सर्वेक्षण करने के पश्चात् किसी गांव को या गांवो के समूह को खुनते है, स्वीकार करने योग्य प्रस्तावों का वित्तपोषण करने के निमित्त उपयुक्त कार्यक्रम बनात है तथा मभी सक्षम तथा सक्षम होने की संभावनायुक्त कुषकों को श्रावश्यकता पर श्राधारित ऋण प्रवान करने हैं। इसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र की कृषि संबंधी अर्थ व्यवस्था का समेकित तथा सुमंगत विकास होना है भौर साथ ही दो या श्रिधिक वाणिज्य बैंको बारा एक ही केल में प्रयाम किये जान तथा वित्तीय साधन लगाये जाने की संभावना नहीं रहती।

# विभेदक स्थाज दर योजना

158. यालांच्य वर्ष के दौरान योजना धायोग द्वारा श्रीधागिक द्वार में पिछड़ भीर इस कारण वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त के लिए पास जिलों के रूप में अतिरिक्त जिले मधिसूचित किये गये। इसके परिणामस्थरूप बैकों से यह कहा गया कि वे इस जिलों, अर्थात् औरंगा-साद, बेगुसराय, गया, सुगेर मौर नवाडा (बिहार), पषुक्कोट्टै (तिमलनाषु) भौर लिलतपुर भौर रामपुर (उत्तर प्रदेश) में विभेदक ब्याज दर योजना को लागू करे। इन जिलों को मिलाकर इस योजना के अंतर्गत अब देश के 275 पिछड़े जिले और छोटे कुपक विकास एजेसी/सीमांत कुपक तथा कुषि अम एजेसी के जिले एवं संघशासित क्षेत्र आते हैं।

159. 1975 (जनवरी-दिसबर) के बौरान उक्त योजना के ग्रंतगंत ऋण प्रदान करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने श्रीर प्रगति की। श्रालोक्य वर्ष के दौरान ऋण खातों की मक्या में 1,50,146 की वृद्धि हुई भौर उक्त संख्या बढ़कर 4,64,811 हो गयी तथा बकाया ऋण की राशि में 7.5 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई श्रीर वह बढ़कर 21.0 करोड़ रुपयों हो गयी। प्रति खाने श्रीसन ऋण की राशि भी विसंबर 1974 के ग्रंत में स्थित कुछ 426 से बढ़कर विसंबर 1975 के ग्रंत में कुछ 452 हो गयी जो इस बात की ग्रोतक थी कि समाज के कमजोर वगों को दिये जानेवाले ऋण में वृद्धि करने के लिए श्रीकों ने भारी प्रयास कियेथे।

### निर्यात क्षेत्र

160. बैक ऋण प्रदान किये जाने के मामले में निर्यात क्षेत्र को प्रत्यधिक पार्थमिकता दी जाती उन्हीं। श्रालीक्य वर्ष के दौरान बैकों ने विशेष रूप में यह कहा गया कि वें निर्यात ऋण प्रदान किये जाने में संबंधित प्रपन्ता कियाबांध का जांच करे गया शीद्रा निर्णय केने के मामले में यदि कोई बाधाए हों तो उन्हें दूर करें।

### निर्यात विस संबंधी स्थायी समिति

161. रिज़र्व बैंक में स्थापित निर्याप जिल्ल संबंधी स्थायी समिति निर्यात विश्त की समस्याध्रों पर विजार विमर्ध करती रही। उसके विजार विमर्शों के धाधार पर धालोच्य वर्ष के दौरान यह सुनिध्चित करने के लिए कई उपाय किये गये कि निर्यात क्षेत्र को पर्यात माला में समय पर ऋण उपलब्ध हो। उक्त उपायों का विवरण संक्षेप में नीचे विया गया है।

# शुल्क बापसी ऋण योजनाः 1976

162 निर्यात के जिकास के उपाय के रूप में रिजर्स बैंक ने प्रतिम मजूरी और धवायगी होने तक सीमा णुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप ने प्रमाणित सीमा शुल्क वापमी की पालता के आधार पर निर्यातकों को बैंको द्वारा धाप्रिम प्रदान किये जाने के लिए एक ऋण योजना बनायी।

163. 1 फ़रवरी 1976 से अमल में आयी इस योजना के ग्रंतर्गन ऐसे भ्रप्रिम, प्रदान किये जाने की नारीख से अधिकतम 90 दिनों की प्रविध तक रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात होते है। रिजर्ब बैक उन सभी प्रन्चित वाणिज्य बैको को जो विदेशी सुद्रा के प्राधिकृत भ्यापारी हैं, सीमा गुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित उनकी शुरूक वापसी की पान्नता के चनुसार नियनिकों को दिये गये चित्रिमों के संबंध में उनके द्वारा की गयी बोषणाध्रों के ग्राधार पर मांग पर प्रतिदेव वचनपत्नों पर पुनर्वित प्रवान करेगा। सप्रति रिजर्व बैंक के अंबई, दिल्ली, कलकत्ता ग्रौर भद्राम स्थित कार्यालयो में पुनर्वित की यह सुविधा उप-लब्ध है। बैंक अलग-भ्रलग निर्यातकों को उनके निर्यात संबंधो कार्य, गुरूक बापमी की पा**क्रना तथा श्र**स्य सबधित तथ्यों पर विचार करते हुए उचित ऋण सीमाए संजूर करेगे। ऐसे प्रक्रिम तथा रिजार्थ बैक द्वारा प्रचान किया जाने बाला तदनुरूप पुनर्वित्त स्थाजमुक्त होगे। तथापि बैक प्रणामनिक क्या प्रौर उन केन्द्रों जहा रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया जाता है और उन केन्द्रो जहा नियतिकों को मग्रिम प्रदान किये जात है, के बीच निधियों के प्रेषण पर हाने वाले व्यय के लिए उचित प्रभार ले सकते है। बैंक यदा कदा सीमा महुक प्राधिकारियो द्वारा ध्रनंतिम रूप से प्रमाणित शुल्क वापसी की राणि तथा प्रदान किये जानेबाल भ्रमिमों के भीच चयनारमक आधार पर 10 प्रतिशत में भनधिक मार्जिन निर्धारित करना भावस्थक मान सकते है। इन भग्निमो को रिजर्व बैक द्वारा प्रक्रिमों के लिए न्यूमतम ब्याज वर निर्धारित करने हुए जारी किये गये निवेश से छुट प्राप्त है। इस योजना के भ्रंतर्गत प्रक्रिमों के रूप मे नियनिकों का श्रदा की गयी राशि नियति ऋष (ब्याज उपदान) योजन के ग्रनर्गत उपदान के लिए पात्र नही है।

# निर्यात ऋण योजनाम्रों का उदारीकरण

164. बिभिन्न निर्मात ऋण योजनाम्नो की मानों को भीर उदार बनाया गया। प्रारंभ में जिन निर्दिष्ट मझौले एवं भारी इंजीनियरी बस्तुमो तथा विदेशी निर्माण कार्य सबंधी ठेकों के संबंध में दैंकों द्वारा निर्याण जाने वाले ब्याज की उच्चनम सीमा निर्धारित की गयी है उनकी सूची को ब्यापक बनाकर उसमें मूलत सम्मिलत की गयी 44 मदो के स्थान पर 55 मदे सम्मिलित की गर्या। तैयार हालत में प्रस्तुत की जानेवाली परियोजनाम्नों के मामले में भ्रमण भ्रलग मामलों के गुणदोषों के ब्राधार पर अधिक से अधिक एक वर्ष की श्रवधि के लिए रियायती दर पर पोलनवानपूर्व ऋण प्रदान करना स्वीकार किया गया।

165 दूसरी बार्न यह है कि केवल परामर्श सेवामो का निर्मात करनेवाली परामर्शदाला फर्मों के नामले में बैंको को यह सूचिन किया गया कि वे परामर्श करारो पर परियोजना के निर्मित्त नियुक्त किये गये तकनीकी एवं अन्य कर्मावारियों से मंबधित व्यय तथा उक्त प्रयोजन के लिए भावश्यक कोई नामग्री खरीदगपर हाल अल ब्यय के लिए उचित पोतलदात पूर्व ऋण कुविधाए प्रयान करने के मंबध में विवार करे। प्रवध परामर्शदात कर्मों क्षारा निर्मीत के प्रयोजनों के निए उत्पादिता संगणन प्रणालियों तथा

कार्यक्रमो को उन्हें प्रदत्त पैकिंग साख प्रग्निमो की रक्षा-राणि के स्प मे मानाजा सकता है।

166 तीसरी बान यह है कि चीनो मिला को उनके द्वारा भारतीय चीनो उद्योग निर्यात निर्मात निरम लिमिटेड को निर्यात के लिए प्रवान की जाने वाली चीनो के सबध मे निगम के साथ किये गये करार संबधी वस्तावेजो को या निगम से प्राप्त वाति श्रमुवेणो को प्रस्तुत करने पर श्रधिकतम 60 विनो को श्रवधि तक पोतलवानपूर्व रियायती ऋण सुधिधामो के लिए पान बनाया गया। जिम शेष श्रवधि के तिए उच्चलम सीमा की वरे निर्विष्ट की गयी है, उसके लिए भारतीय चीनी उद्योग निर्यात निगम को पोतलवानपूर्व रियायती ऋण प्राप्त हो सकता है।

167 जौथी बात यह है कि कालीन नियंतिकों के मामले में बैंकों का यह सूचिन किया गया कि वे न केवल प्रेषण के लिए तैयार वस्तुओं पर, अपितु कज्जी सामग्री की लागत थ्रौर निर्माण व्यय नथा निर्यात की प्रतीक्षा में कालीनों के स्टाक जमा करने पर होनेवाले व्यय की पूर्ति करने के लिए भी इस शर्त पर उचित सीमा तक पैंकिंग साख अग्रिम प्रवान करने पर विचार करें कि उचित समयाविध के भीतर साख प्रश्न/निर्यात थ्रादण उनके पास रखे जाए। बैंकों का यह सूचित किया गया कि विवेणी खरीवरों से प्राप्त तार सूचनाक्षों के आधार पर जृट मिला को इस शर्त पर पैकिंग ऋण सुविधाएं प्रदान करें कि यथासमय निर्यात थ्रादेण या साख पत्र उनके पास रखें जाए।

168 इनके श्रलावा बैंको को सूचित किया गया कि वे पहले विवेस्रो मे प्रदर्शनो ग्रौर बिश्री के लिए भेजी जानेवाली वस्तुग्रो पर सामान्य रूप से वित्त प्रदान करे और निर्यात की बिक्री पूरी हो जाने पर पात-लबानपूर्व तथा पोनलदानात्तर दोनो स्थितिया मे दिये जानेवाले ऐसे म्रग्निमा पर निर्विष्ट अर्थाध तक बट्टे के रूप मे रियायती ब्याज दर की सुविधा प्रदान करे। इसके ग्रलावा पैकिंग साखा प्रश्निमा के परिचाला ं में लचीलापन लाने के उद्देश्य में रिजर्वविक ने इस गर्न को हटा दिया था कि यदि सबधित ठेके के स्थान पर दूसरे ठेके के लिए अनुसति प्रदान करनी है तो पैकिंग साख अग्रिमो द्वारा वित्तपोषित वस्सुग्रो का निर्यात उसी देश को किया जाना चाहिए। इस रियायत के परिणामस्वरूप दूसरे ठेके से सबधित निर्मात बिलो का बेचान कर लचीले ढंग से पैकिंग ऋण का समायाजन करने की ग्रनुमिं दी गयी है बशर्ले कि उन प्रग्रिमा के भ्रंतर्गत भ्रानेवाली वस्तुभो का निर्यात प्रतिस्थापित ठेके के भ्रतर्गत उजिन समय के भीतर किया आए। जिन मामलो मे उपपूर्तिकर्ता हा उन मामलो मे निर्यात प्रतिष्ठान/एजेसी भीर सबधिस उप-पूर्तिकर्ना दोनो को स्वीकृत श्राधार पर निर्दिग्ट अवधियो के मीतर पोतलदानपूर्व रियायती ऋण सुविधा का लाभ उठाने की ग्रनुमित प्राप्त है।

# भिर्मात ऋण (ब्याज उपदान) योजना, 1968

- 169 म्नालोक्य वर्ष के दौरान भारत सरकार ने निर्यात ऋण (ब्याज उपदान) योजना, 1968 में सैंग्रानिक रूप से निस्तप्रकार संशोधन करना स्वीकार किया
- (1) भारताय निर्यातको द्वारा विदेशो में प्रारंभ की गयी नैयार हालत में प्रस्तुन की जानवाली परियोजनाओं के संबंध में भ्रन्य देशों से की जानेवाली खरीदा पर विये जानेवाल अग्रिमा को रियायती ब्याज दर तथा ब्याज उपवान के लिए पात माना जाए। ऐसे भ्रग्निमा का पान-लदानोत्तर ऋण माना जाएगा।
- (2) 180 दिना से भधिक श्रवधि के लिए प्रधान किये जानवाल पातलदान पूर्व ऋण के लिए रिजर्व बैंक का अनुभोदन प्राप्त करने की जब का हटा दिया जाए।
- (3) श्रास्थिनित श्रदायनी की शर्ती पर दिये जानेवाले पोनलदानाश्चर ऋरण पर श्रीको का देश स्थाज उपरान का बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाए।

- (4) खरीदारों के ऋण पर भी ब्याज उपदान प्रवान किया जाए ताकि सहभागी वाणिज्य बैंकों का भी भ्रास्थिगत श्रदायगी की सर्ती पर पोनलदानोत्तर (विकेताग्रों के) ऋण मामलों में उपलब्ध लाभ प्राप्त हो।
- 170 इस बीच बैंक निर्धारित ब्याम देर पर ध्रमन हारा प्रदत्त निर्यात ऋण के सब्ध में वर्तमान योजना के ग्रमगत वाधिक 1 5 प्रतिणत की दर पर उपदान प्राप्त करने गरे। 1975 76 (जुलाई से जून तक) के दौरान 47 याग्य बैंकों से 8 9 करोड़ रुपयों की राणि के ब्याज उपदान के लिए प्राप्त दावों का निपटान किया गया। उक्त राशि में पानलदान पूर्व ग्रौर पोनलदानोत्तर ऋणों का ग्रम क्रमण 1 7 करोड़ रुपये ग्रौर 4 2 करोड रुपये था। योजना के प्रारम्भ से लंकर 30 जून 1976 तक दिनरित उपदान की कुन राणि 39 9 करोड रुपये थी।
- 171 भारतीय सीकांगिक विज्ञास बैंक युनाइटेड कर्माणयन केंक सौर युनाइटेड बैक आफ इंडिया का बगना दंश स्थित नित्यय विलीय संस्थाओं को भारत से किंपिय निर्दिष्ट पूर्णागन वस्तुओं का आयात करने के निमिक उनके द्वारा प्रदत्त 25 करोड रुपयों के विणेय बैंक ऋणपर वाणिज्य मक्षालय की बाजार विकास निधि में वार्षिक 1 5 प्रतिशत की दर पर तथा विदेश मक्षालय हारा नियन की गयी निधि में से वार्षिक 3 प्रतिशत की दर पर क्याज उपदान प्रदान किया जा रहा है। आलोच्य अवधि के दौरान इन तीन बैंका का विनियन किये गये कुत ब्याज उपदान की राणि 24 7 लाख रुपये (1 5 प्रतिशत की दर पर 6 4 लाख रुपये स्त्रीर 3 प्रतिशत की दर पर 18 3 लाख रुपये ) थी।
- 172 सूझन का निर्यात करनेवाला पर उस देश में विद्यमान विदेशों मुद्रा सबधी कठिनाइयों के कारण होने वाल क्याज संबंधी भार को कम करने के उद्देश्य से रिज्ञव बैंव ने 14 जुलाई 1976 का बैंका का यह सूचिन किया कि वे भारत में निर्याता की राणि प्राप्त होने की तारीख तक प्रधिकतम 90 दिनों की श्रवधि के लिए वार्षिक 11 5 प्रतिशत से श्रान्धिक दर पर क्याज ले बशर्नों कि घायनक द्वारा बिल की श्रवधियों स्थानीय मुद्रा में की गयी हो। दिसबर 1976 के अह तक यह छूट उपलब्ध होगी श्रीर बैंक श्रधिकतम 90 दिनों तक की श्रवधि के लिए 1 5 प्रतिशत की दर पर ब्याज उपवान प्रष्त करने के लिए पात होगे।

# सहायता/सहभागिता ज्यवस्थाएं सहायता सन्नीय बैकिंग

173 पिछल वर्ष की रिपार्ट में यह उल्लेख किया गया था कि महायता/महभागिता के आधार पर ऋण सीमाए प्रदान करने से संबधित
प्रध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारियों के आधार पर रिजर्ब बैंक ने
बाणिज्य बैंका को अनुदेश जारी किये हैं। अन्य बाता के साथ-पाथ वैंका
को यह मूचित किया गया था कि वे अन्य बैंका के साथ पहले ही दिये
गयं सुझाव के अनुसार समन्वयन वे लिए उचिन कियाबिध बनाने के
निमित्त बातचीत करना प्रारम करे। चूकि इस सवर्ष में कितपय बैंका
बारा की गयी कार्रवाइया अपर्याप्त पायी गयी अन रिजर्ब बैंक ने अपने
कोत्रीय कार्यालय को यह सूचिन किया कि वे अपने निरीक्षण अधिकारिया का बैंको वा विक्रीय निरीक्षण करने समय इस पत्र की जांच
करन तथा तस्सबधी अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट दें। के अनुदंश दे।

174 इसके प्रलाबा बैकी के सहायता संघीय ऋण प्रदान किये जाने के संवर्भ में विद्यमान किन्यय प्रस्वस्थ तत्वों को दूर करने के उद्देश्य से बैको से यह मुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि महमागिना प्रिप्रिमी से मिकाली जाने वाली राशि यथासभव बैको के सहायता सच द्वारा मजूर की गयी कुल ऋण सीमा में होने वाले बैका के घण के प्रनुपान में में हो। वित्तपोषक धामुषीनक कारोबार धर्यान् हुंडियों की वसूली, गारटी पत्नों के निर्गम, बिदेशी भुद्रा सबधी कारोबार आदि को ममाम रूप में विभाजित करने की व्यवस्था करना बांछमीय हागा।

# खाद्याओं की सार्वजनिक बसूली के लिए विये जाने वाले ऋण के संवर्ष में ब्रध्ययम बल

175. रिजर्ब बैंक ने महायता संबीय व्यवस्थाओं के श्रांगंत याद्यासी की सार्वजितिक बसूली करतेवाली एजेसियों तथा विभिन्न सार्वजितिक एवं निजी क्षेत्रों के उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त कियाविधियों तथा महायता मंधीय नमूना दस्तावेज बनाने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया। खाद्यासों की बसूली के वित्तपीयण की वर्तमान व्यवस्थाओं के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यह अध्ययन दल गठित किया गया; उक्त पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यह अध्ययन दल गठित किया गया; उक्त पुनरीक्षण से यह स्पष्ट हो गया था कि खाद्याओं की सार्वजितिक वसूली संबंधी कार्यकलायों के लिए निविष्ट सहायता संघ के अप्रणी के रूप में स्टेट बैंक श्रपने 36 मदस्य वैकों के बीच आवधिक रूप से उनका श्रंण आवटित करने में कतिपय परिचालनगत कठिनाइयों का अनुभव कर रहा था। श्राणा की जाती है कि प्रध्ययन दल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

176. मार्च 1970 में प्रायोगिक रूप स प्रारक्ष की गर्या सहणागिता प्रमाणपत्न योजना में ब्रालोच्य अवधि के दौरान उल्तेखनीय पगित हुई। सहभागिता प्रमाणपत्न के निर्गम में सब्बित गर्ते ब्रालोच्य वर्ष के दौरान अपित्वित्तित रहीं। इस योजना के अन्तर्गम रिजर्म बैंक द्वारा अनुमोदिन बैंकों की सख्या जून 1975 के अन में विद्यमान 37 में बढ़कर दिसंबर 1975 के अंत में 43 (9 विदेशी बैंको सहित) हो गयी तथा जारी किये गये और बकाया रहनेवाले सहभागिता प्रमाणपत्नों की राग्नि 113 5 करोड़ रुपये थी। योजना की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता था और उसे जून 1977 के अन तक और बढ़ाया गया तथा योजना की अवधि को और बढ़ाया गया तथा योजना की अवधि को में वढ़ाया गया तथा योजना की अवधि को और बढ़ाया गया तथा योजना की अवधि को मौर बढ़ाने पर विचार करने के उहेश्य से उगका पुनरीक्षण प्रारंभ किया जा रहा है।

#### मीबादी ऋण प्रदान करना : वाणिज्य अंक

177. यह स्मरण होगा कि रिजर्ष बैंक समय-समय पर वाणिज्य बैको से विशेष रूप से निर्दिष्ट की गयी उच्च प्राथमिकता प्राप्त परियोज-नामों को दिये आनेवाले मीयादी ऋणीं में बृद्धि करने के लिए भाग्रह करते हुए मार्गदर्शी सिद्धान जारी करना द्या रहा है। नवंबर 1975 के दौरान रिजर्व वैंक ने वाणिज्य वैंको को तीन वर्षों से ग्राधिक ग्रयधि के लिए कम की गयी लागत पर प्रधिक मास्ना में मीयादी ऋष्ण प्रवान करने की भावस्यकता के बारे में पुनः श्रवगत कराया । श्रर्थब्यवस्था में दीर्घकालीन निवेश को भौर पोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकन[ा] के संदर्भ में वैंको से यह अनुरोध किया गया कि वे तीन वर्षों से प्रधिक भवधि के मीयावी ऋणो पर 15 प्रतिशत में भ्रतिधिक दर पर ब्याज सी। तदमंगर बैंको को यह सूचित किया गया कि वे 1 ग्राप्रैण 1976 से मान वर्षी से अन्यून अवधि के लिए उद्योग क्षेत्र को प्रवत्न मीयादी ऋण पर 14 प्रतिशत से मनधिक दर पर ब्याज ले चूंकि ऐसे मीयादी 'ऋण के ब्याज से होनेवाली भ्राय को ब्याज कर मे छुट दी गयी है। परस्त तीन भीर सात वर्षों के बीच की श्रविधयों के मीयावी ऋणों की ब्याज दर (ऋणों के ब्याज कर को मिलाकर) 15 प्रतिशत ही रहेगी।

# ऋण स्रायोजना ग्रीर अङ्गण प्राधिकरण योजना ऋज स्रायोजना

178 स्रालोच्य वर्ष के घौरान ऋण की साग ग्रौर पूति के बीच अधिक सार्थक सबध स्थापित करने के उद्देश्य में ग्रधिक प्रभावी ऋण स्रायोजना की प्रणालियों ग्रौर उपायों के संबंध में बैंकरों के साथ विचार-विमर्श किये गर्मे। ऋण ग्रायोजना सबंधी कार्य में मुधार लान के निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गर्मे मये डाचे के ग्रन्गार प्रविश्वकों को ग्राहिए कि ये वार्षिक बजर बनाने की पुरानी प्रणाकी क स्थान पर निमाश्चा ऋण बजट बनाये। विभिन्न कोलों में होनेवाली ऋण की मांग का विवर्ण

तैयार करते समय बैंकों से कहा गया कि वे प्राप्ते उधारकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करे ताकि उक्त विवरण उनके कारोबार संबंधी भागया का ठीक-ठीक प्रतिपादन कर मकें। रिजर्व बैंक उस पर अनुवर्ती कारेंबाई करेगा और उत्पादन में संभावित तथा वास्तविक वृद्धि के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के भीच ऋण का वितरण करने के लिए कार्रवाइयां करेगा। इस उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी मूलभून मांक्यिकीय विवरण प्रणाली को और व्यापक बनाने हुए अब ऋण के क्षेत्रीय वितरण की मासिक सूचना प्रणाली प्रारंभ की है।

### ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई के अध्ययन दल की रिपोर्ट

179. ऋण प्राधिकरण योजना के कार्य को प्रभावित करनेवाली महत्वपूर्ण गिनिविधि यह थी कि बैंक ऋण की प्रनुवर्ती कार्रवाई पर मार्गवर्णी सिद्धांन बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 1974 में गिठम अध्ययन दल ने भगस्त 1975 में अपनी प्रतिम रिकोर्ट प्रस्तुत की। दल की प्रमुख मिफारियों ऋण प्रदान करने के वृष्टिकोण, स्टाक और विलो के मानकों, सूचना प्रणाली, ऋण पद्धति, ऋण की प्रमुखर्ती कार्रवाई और पर्यवेक्षण स्था ऋणकर्ता कपनियां के विलीय विज्याम से संबंधित थी।

180. ऋण प्रदान करने के दुष्टिकोण के सबध में दल ने यह स्पष्ट किया है कि ऋणदासा के रूप में बैंक का प्रधान कार्य यह है कि वह ऋणकर्ता की उत्पादन संबधी अपेक्षामों के संदर्भ में वर्तमान भ्रास्तियों के भ्रपेक्षित स्तर को अनाये रखने के लिए उसके विचीय साधनों की प्रतुर्पत करे। इस परिप्रेक्ष्य में दल ने कार्यकारी पूंजी की खाई (घल्पावधि र्वेक ऋष्णों को छोड़कर चालू देयताश्री की तुलना में विद्यामान चालू ब्रास्तियों का ब्रातिरिक्त श्रंश) की पूर्ति करने के निमित्त ग्रधिकतम स्वीकृत बैक ऋणों का हिसाम लगाने के लिए तीन प्रणालिया सुप्तायी है। प्रत्येक क्रमिक प्रणाली से चालू ग्रास्तियों को दीर्घकालीन निधिया ग्रर्थात् ऋणकर्ता की ग्रपनी निधियों ग्रीर मीयावी ऋणो से प्राप्त होनेवाली सहायना में वृद्धि होती है। ऋणकर्नाध्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए दल ने बह सिफारिण की है कि सभी ऋणकर्ताओं को एक वर्ष के भीतर ऋण प्रदान करने की पहली प्रणाली के धंतर्गन लाकर प्रारंभिक कार्रवाई की जाए और बाद में तत्काल विद्यमान स्थिति के संबंध में रिज़र्व बैक द्वारा किये जानेश्राले मृत्यांकन के श्राधार पर दो चरणों में दूसरी और तीसरी प्रणालियों को अपनाया जाए। रिजर्ब बैंक ने संप्रति ऋण प्रदान करने की पहली प्रणाली ग्रपनायी है जिसके ग्रन्तर्गत ऋण कर्ताभी को दीर्घकालीन मिधियों से कार्यकारी पूंजी की खाई के 25 प्रतिशत का श्रभिदान करना पड़ता है। ऋगकर्ता को पहली प्रणाली के ग्रंतर्गत लाने का ताल्पर्य यह है कि नगी प्रणाली के भ्रांतर्गत ऋणकर्सा जिस ग्रल्पाविध वित्त के लिए पाक्ष होगा उसकी तुलना में बैंक ऋणों के भतिरिक्त श्रग का बैंक हिसाब लगायेंगे भौर ऐसी भ्रतिरिक्त राशि को मीयादी ऋण में प्रिरिवर्तित करेंगे; ऐसे ऋण के परिणोधन की धर्वाध ऋणकर्ता के नकवी निधि उत्पादन करने की क्षमता भादि पर निर्भर करेगी। इसके भलावा, जिस ऋणकर्ता ने पहले से ही अतिरिक्त ऋण लिये हो उसे कतिपय शतों पर ब्रितिरिक्त ऋण मुविधाएं भी प्रवान की जा सकली है।

181 प्रध्ययन दल की रिपोर्ट के प्रनुसार कार्यकारी पूजीगत अपेकाधों का मूल्यांकन करने के निमित्त निभीष स्प में स्टाको और बिला के सदर्भ में चाल ग्रास्तियों के स्तरों के ग्रीचित्य का निर्धारण करने के लिए अपनायें जाने वाल बैका के दृष्टिकोण में पर्याप्त समानता नहीं है; ग्रतः दल ने 15 प्रमुख उद्योगों के सबंध में स्टाको एवं बिलो के मानक सुक्षाये है। इस मानकों का इस उद्देण्य में निरंतर पुनरीक्षण किया जाना नाहिए कि याँव किसी मानक में बदली हुई परिस्थिति के अनुसार कोई सशोधन करना न्यायोधिन हों तो उत्तमें उचित सशोधन किया जाना चाहिए।

182. दल ने बैंक ऋण प्रधान करने की प्रणाली में परिवर्तन करने का भी मुझान विया है; किसी वर्ष के लिए नकदी ऋण खाने में पूरी ऋण सीमा उपलब्ध कराने के बदले उसे ऐसी 12 मामिक ऋण किश्ता में विभाजित कर देना चाहिए जो ऋण के उस न्यूनतम स्नर की धोनक हो जिसको वर्षभर के दौरान ऋणकर्ता प्रयोग में लाने की भ्राणा करना हो तथा उसे मांग नकदी ऋण खाते के रूप में भी परिवर्तित कर देना चाहिए जा ऋणकर्ता की घटने-बढ़नेवाली श्रपेक्षामों की पूर्ति करे। समेकित प्रणाली के एक भ्रंग के रूप में दल ने यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण का उचित ढंग से भ्रंतिम उपयोग किया है, उसकी भ्रनुवर्ती कार्रवाई और पर्यवेक्षण के लिए व्यापक सुझान विये है।

183. रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई प्रध्ययन वल की प्रखुख सिफारिशे वाणिण्य बैंको को अगस्त 1975 में सूचित की गयी तथा प्रध्ययन दल की सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित करने के लिए बैंको के संगठन-विन्याम को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने समय भानेवाली समस्याभ्रों की सतत समीक्षा करने के निमित्त रिज़र्व बैंक लेथा कितप्य प्रमुख बैंको के प्रतिनिधिया से युक्त एक निदेश मिनित रिज़र्व बैंक में गठित की गयी। इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया कि बैंक अपने परिचालन-प्रधिकारियों तथा उपभोकताओं के बीच एक दूसरे की समस्याभ्रों तथा विचारों को समझने के लिए बैचारिक तालमेल स्थापित करने के निमित्त बैंकरों और ऋणकतिभ्रों की विचार गोष्टियां भायोजित करे। इसके भ्रनावा दल की सिफारिशों का गहराई से भ्रध्ययन करने के निमित्त दल की रिपोर्ट पर कई विचार-गोष्टियां भायोजित की गयीं।

#### ऋण प्राधिकरण योजना

184. वस वर्ष पहले प्रारम की गयी ऋण प्राधिकरण योजना रिजर्व वैंक की ऋण नीति को कार्याग्वित करने में महत्वपूर्ण धूमिका अदा करती रही। इस प्रकार प्रालोक्य वर्ष के वौरान जा ऋण सीमाणं प्राधिकृत की गयीं वे स्यूल रूप में ऋण मीति के निम्नितिश्वित प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप थी: निवेण को बनाये रखने, उत्पादन को बढ़ाने, खाद्याक्षों की वसूली का विस्पायण करने, प्रत्यावस्त्रक वस्तुओं के प्रधिक प्रच्छे वितरण में सुविधा पहुनाने और नियति विकास की सहायता करने के निम्निष्पर्यात ऋण उपलब्ध कराना। योजना के प्रंतर्गत प्राप्त प्रम्तावों की जान करने समय रिजर्व बैंक ने स्टाकों के मानवण्डों और ऋण प्रवान करने के नये वृष्टिकोण के संबंध में ऋण की अनुवर्ती कार्रवाद्वि से संबंधित अध्ययन वल द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान मे रखा। अध्ययन वल की सिफारिशों के प्रनुसार बैंको से व्यापक प्राकड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना के प्रंतर्गत निर्विष्ट विवर्णयों के कित्यय प्रपन्नों में भी रिज्ञवं वैंक ने संशोधन किये।

185. ऋण प्राधिकरण योजना को प्रधावित करनेवाली महन्वपूर्ण गिनिविधि यह थी कि निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताधों के लिए पूर्व प्राधिकरण की न्यूनतम सीमा को नवबर 1975 में 1 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 2 कराड़ रुपयों कर दिया गया। योजना के परिचालन में और लजीलापन लाने के उद्देश्य से बैकों को यह सूचित किया गया कि वे रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण लिये बिना भारतीय श्रीद्योगिक विकास बैंक/कृषि पुनिवन द्यीर विकास निगम के साथ सहायता सघीय आधार पर मजुर किये गये मीयादी ऋणों के ध्रपने ग्रंग के श्राधार पर श्रतिरम किस/पूरक ऋण प्रदान कर सकते हैं बगर्ते कि उक्त सम्थाओं द्वारा पबके वायद किये जाने तथा उनमें बैकों का ग्रंग निर्धारित किये जाने के वाद ही प्रक फण प्रदान कि भाग। अखिल भारतीय यिलीय सरभाया द्वारा वायश की गर्म विकास किये जाने के वाद ही प्रक फण प्रदान कि भाग। अखिल भारतीय यिलीय सरभाया द्वारा वायश की गर्म विकास के प्राधार पर भी ऐसे ऋण प्रदान किये जा सकते हैं। बैंकों को यह स्पष्ट किया गया कि जिन अहणकर्ताओं को पूरी वैक्तिय प्रणाली में 3 कराड़ स्पया से कम राश्च की ऋण सीमाए प्राप्त विकास प्रणाली में 3 कराड़ स्पया से कम राश्च की ऋण सीमाए प्राप्त विकास प्रणाली में 3 कराड़ स्पया से कम राश्च की ऋण सीमाए प्राप्त

हो उनके सदर्भ में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो द्वारा गारंटीकृत श्रांग्रमों के लिए पूर्व प्राधिकरण में उपलब्ध छूटे केवल कार्यकारी पूंजीगत श्रांक्षाओं तक सीमित है और ये पूजीगत व्यय से संबंधित श्रतरिम वित्त या पूरक वित्त प्रवान किये जाने के लिए नहीं है।

186. प्रध्ययन वस की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद अर्थ-व्यवस्था में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कतिपय उद्योगों प्रथित् कर्ताई मिलों, जूट मिलों श्रीर उर्दरक यूनिटों के संदर्भ में दल द्वारा निर्धारित स्टाक मंबधी मानकों को उदार बनाया गया। यह भी निश्चय किया गया कि ऋणों और स्टाकों पर प्रतिरिक्त माजिन लागू करने के लिए नवम्बर 1973 में बैकों को जो सूचना दी गयी थी उसे भी वापस ले लिया जाए, क्यांकि ऋणकर्ताक्रों के बीच अनुशासन लाने के निमित्त बैंकों द्वारा विभिन्न उपाय प्रारम किये जा चुके थे।

187 जपर उहिलखिन निजी क्षेत्र के प्रितिष्टानों के लिए बैंक के पूर्व प्राधिकरण की त्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रायों से बढ़ाकर 2 करोड़ रायें कर दन के कारण योजना के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों की मल्या जून, 1975 के अन में विद्यामान 1786 से घटकर ज्न 1976 के अन में 851 हो गयी, जिनमें वार्वजनिक क्षेत्र के 151 प्रतिष्टान भी सिम्मिलित हैं। परन्तु प्राप्त आवेदनपत्नों की संख्या जसी अवधि में 1058 से बढ़कर 1181 हो गयी और गंबधित राणि 1022 करोड़ रुपयों से बढ़कर 2646 करोड़ रुपये हो गयी। 1975-76 के दौरान प्राप्त कुल आवेदनपत्नों में से 216 आवेदनपत्न मार्वजनिक क्षेत्र के थे और तत्संबधी गिश 1781 करोड़ रुपये थी। प्राधिकृत मामलों की कुल संख्या और सर्वधित राणि 1781 करोड़ रुपये थी। प्राधिकृत मामलों की कुल संख्या और मर्वधित राणि में 1975-76 के दौरान बढ़ांनरी पायी गयी। प्राधिकृत मामलों की संख्या 1974-75 के 528 से बढ़कर 1975-76 में 716 हो गयी तथा राणि 428 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1962 करोड़ रुपये हो गयी (इस ऋण के अधिकाश भाग का उपयोग खाद्याओं की वसूली के कार्यों के लिए किया गया)।

188. ऋण प्राधिकरण याजना के भ्रतर्गत श्रानेशाले मामलो के सवर्भ में श्रमल मे रहने बाली कुल ऋण सीमाओं की राशि जून 1976 के भ्रत में 8476 करोड़ रुपये थी जो जून 1975 के भ्रंत में प्राप्त ऋण सीमाओं की तुलना में 17 प्रतिशत की बृद्धि की ग्रांतक थी। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्टानो के संदर्भ में प्रमल में रहने बाली ऋण सीमाओं की राशि 4440 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 68 प्रतिशत अधिक थी। जन 1976 के ध्रंन में फुल सीमाफ्रो के उद्देण्यवार वितरण का जो स्वरूप था वह लगभग ग्रपरिवर्तित रहा श्रर्थात् कार्यकारी पुंजीगत प्रयोजना के लिए लगभग 90 प्रतिणत, मीयादी विस के लिए 7 प्रतिशत ग्रौर श्रास्थगित ग्रवायगी के ग्राधार पर मशीनों की बिक्षी के लिए 3 प्रतिशत बिर्तारत था। यदि उद्योगधार देखा जाए तो जृत 1976 के श्रंत में विद्यमान कुल ऋण सीमाध्रो में ध्यापारक्षेत्र का श्रंण लगभग 33 प्रतिणत (इसमें से खाद्याओं की बसूसी के कार्य-कलापों का श्रंग 28 प्रतिशत था), इंजीनियरी उद्योग का श्रंश लगभग 21 प्रतिशत (इसमे से परिवहन उपकरणों का ग्रंश 4 प्रतिशत था) भीर वस्त्र उद्योग का श्रम लगभग 7 प्रतिशत था। सार्वजनिक क्षेत्र के सदर्भ में विद्यमान ऋण सीमाक्रो में व्यापार क्षेत्र का ग्रश 30 प्रतिशत, इजीनियरी उद्योग का ऋण 6 प्रतिशत (इसमें से परिवहन उपकरण का श्रंग 1 प्रतिणत था) श्रौर बिभली प्रतिष्ठानो का श्रंग 3 प्रति-सन्धा।

#### कसिपय उद्योगों को स्रप्रिम

189. कितपय उद्योगों द्वारा अनुभव की गयी विशेष समस्यात्रा की ध्यान में रखने हुए बाणिज्य बैंकों को श्रपेक्षाकृत उदार णहीं पर उनकी ऋण संबंधी आवण्यकताओं की पृति करने की अनुमति वी गयी।

#### ज़ट उद्योग

190. यह स्मरण होंगा कि पिछले जर्प जून 1975 के ब्रम तक की किस्थार्या ब्रविध के लिए 9 सप्ताहों के उत्पादन के बराबर के नियत्तों के लिए अपेक्षित तैयार वस्तुओं के अधिकतम स्टाको के आधार पर अलग-प्रमाग जूट मिलो को अहुण प्रदान करने की प्रमाम वैको को थी गया थी। देशी और विदेशी मागो में बराबर विद्यमान मदी तथा जूट उचाग की अनिश्चिता के कारण निर्यातों के लिए उत्पादित जूट वस्तुओं के संबंध में थी गयी छूट की अवधि को अगली सुजना तक बढ़ा दिया गया तथा देशी बित्रियों के लिए अपेक्षित तैयार वस्तुओं के स्टाकों के लिए निविष्ट मानवण्डो को भी अगली सुजना तक 6 सप्ताहों की बित्री की माला तक कम कर दिया गया। बैकों को यह भी सुजित किया गया कि जिन मामला में ऊपर उल्लिखिन अनिरक्त स्टाको वा बित्त-पायण करने के लिए उपलब्ध कराये गये ऋण में की गयी बृद्धि स्टाको पर वी गयी वर्तमान ऋण सीमाओं के 10 प्रतिशत नहीं होगा।

### वस्तु उद्योग

191 पिछले वर्ष बैकी को राष्ट्रीय अस्त्र निगम द्वारा प्रपने अधिकार में ली गयी मिलो का जून 1975 के ग्रंत नक की उनकी उत्पादन योजना के अनुसार रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त विये बिना उचिन माला तक नदर्थ ऋण मीमाएं प्रदान करने की अनुमित प्रदान की गयी थी। राष्ट्रीय यस्त्र निगम द्वारा अधिकार में ली गयी धलग-प्रलग मिलों के खातों को प्रतिम रूप देने में आनेवाली किठिनाइयों के सबंध मे उसके द्वारा प्रतिबेदन किये जाने पर यह रियायन कमिक रूप में मिनंबर 1976 के भ्रंत तक बढा दी गयी।

192 हथकरथा उद्योग में विद्यामान मंदी की स्थित के परिणाम-स्वरूप सूती रेगे, विणेष रूप से हैंक के रेगे भारी माला में मचित हो जाने के कारण नवंबर 1975 में बैंको को यह सूचित किया गया कि वे सूती कताई मिलो के लिए लागू वर्तमान समग्र मानकों के भीतर कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार यदि कच्ची कई के संबंध में अधिकतम ऋण सीमा का कोई श्रग्न अप्रयुक्त रहे तो तैयार वस्तुओं पर वी जाने वाली ऋण मीमा को अधिकतम उपलब्ध 21 महीनों की सीमा के अतिरिक्त विद्यमान माला के बराबर की सीमा तक मार्च 1976 के अंत तक की श्रस्थायी श्रविधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी वृद्धि को अधिकतम तीन सप्ताहों की श्रविधि तक ही सीमित किया जाए। दूसरे णड़शे में तैयार वस्तुओं के स्टाकों श्रीर बिलो का स्तर किसी भी हालत में तीन महीनो से श्रविक नही होना चाहिए। इस छूट की श्रविध को बाद में ऋमिक रूप से जुलाई 1976 तक बढ़ा दिया गया।

### उर्वरक उद्योग

193. सैयार उर्थरकों के स्टाकों के मंचित होने से उत्पन्न समस्याग्री को देखते हुए कच्ची सामग्री श्रीर पैकिंग मामग्री के स्टाक के स्तर से संबंधित वर्तमान मानकों की मार्च 1976 के श्रंत तक की श्रवधि के लिए श्रम्थायी रूप से 2 महीनों के उपभाग की मान्ना से बढ़ाकर 3 महीनों की उपभोग-मान्ना श्रीर तैयार वस्तुश्रों तथा बिलों के स्तर को 2 महीनों से बढ़ाकर चार महीने कर विया गया। इस श्रवधि के बाद में ऋमिक रूप से श्रक्तूबर 1976 के श्रंत तक बढ़ा विया गया।

### चीनी उद्योग

194. 1975-76 के दौरान चीनी के उत्पादन की संभावनाम्रो का पुनरीक्षण करने के बाद रिपार्व बैंक ने नवस्वर 1975 में बैंकों को सूचित किया कि वे अलग-म्रलग चीनी मिलों को पेराई के पिछले दो मौसमी (1973-74 भीर 1974-75 के मौसम) के लिए मंजूर की गयी नियमित सीमाम्रों के भीनर विद्यमान प्रधिकतम बकाया राणि (इनमें नियमित सीमाम्रों के भीनर विद्यमान प्रधिकतम बकाया राणि (इनमें नियमित सीमाम्रों के भीनर किये गये म्राहरण, यदि कोई हो, तथा म्रस्थायी माम्रा पर मंजूर की गयी ऋण सीमाएं मम्मिलन नहीं हैं) की मान्ना तक उनके गुण-दोषों के भ्राधार पर ऋण प्राधिकरण योजना के भ्रातर्गत पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना भ्रष्टण सीमाएं मंजूर कर सकते है।

इपके भ्रालाबा बैंकों को पुन: यह मुनिविधन करने के लिए कहा गया कि गर्घ के उत्पादकों का गन्ने के संबंध में देय गणि की तत्काल प्रवासगी की जानी है।

#### भ्रन्य उद्योग

195. कागज उद्योग ग्रीर मोटरों के पुत्री के उद्योग हारा प्रमुभव की गयी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वर्षमान मानकों को 6 महीनों की श्रम्थायी प्रविध (प्रधांत् सितम्बर 1976 के प्रतानक) के लिए सशाधित किया गया। कागज उद्योग के मामले में तैयार वस्तुष्रों ग्रीर बिलों के लिए क्रमणः 12 महीनों की बिकी लागत ग्रीर बिकी का मंयुक्त मानक निर्धारित कर कुछ लचीलापन लाया गया। इसके पहले नैयार वस्तुष्रों के लिए एक महीने की बिकी लागत (नियत्नित बिकी) नथा रे महीने की बिकी (मुक्त बिकी के लिए ग्रोधित वस्तुए) ग्रीर बिलों के लिए रे महीने की बिकी का मानक निर्धारित था। मोटरों के पुर्जी के श्रमिटों के मामले में तैयार वस्तुग्रों ग्रीर बिलों के लिए विद्यमान संयुक्त मानकों को 2 महीनों की बिकी लागत का बदलकर कमणः 3 महीनों की बिकी लागत ग्रीर बिकी का मानक निर्धारित किया गया।

#### कमञ्जोर स्त्रौद्योगिक प्रतिष्ठान

196. रिजर्व वैंक द्वारा बंबई में अप्रैल 1976 में कमजोर श्रीशोगिक प्रतिष्ठानो से संबंधित विभिन्न समस्यान्नो पर विशेष रूप से बैको तथा वित्तीय संस्थाम्रों की दृष्टि से विचार-विमर्श करने के निमित्त एक विचार गोष्ठी ग्रायोजित की गयी। ग्रनुवर्ती उपाय के रूप में बैको को यह सुचिन किया गया कि वे कमजोर श्रीकोगिक प्रतिष्ठानो से संबंधित विभिन्न समस्यात्रों को सुलक्षाने के लिए विशिष्ट 'कक्ष' स्थापित करे। ऐसे कक्षों का तत्काल कार्य यह होगा कि वर्तमान ऋणकर्तास्रो की स्थिति का पून-रीक्षण किया जाए और पहले से ही कमजोर रहनेवाले या कमजोर होने की संभावनायुक्त युनिटों का पता लगाने की कोशिश की जाए ताकि ऐसे यूनिटों की समस्यात्रो पर प्रधिकाधिक ध्यान दिया जा सके भौर सभाव्य मुधार कार्य किये जा सकें। इस संदर्भ में टंडन समिति के सुझाव के श्रनुसार रिजर्व वैक में एक व्यापक श्रासूचना प्रणाली निर्मित करने की न्नावश्यकता पर भी जोर दिया गया। रिजार्व बैंक के भीतर भी कमजोर यनिटों से संबंधित जानकारी के समागोधन गृह के रूप में कार्य करने तथा सरकार, बैंकीं, विलीय संस्थायो श्रौर श्रन्य एजेसियो की श्रार से एक समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए एक कक्ष स्थापित किया गया ।

# चयनात्मक ऋण नियंत्रण

197 कृषि वस्तुत्रों के उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि तथा कृषि प्राधा-रित उद्योगों की भ्रावश्यकताम्रों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक ऋण नियंत्रणो को अनिवार्यंतः कई वस्तुत्रों, जिनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तुए मुंगफली ग्रीर चीनी थी, के सदर्भ में न्युनतम मार्जिन सबंधी प्रपेक्षा में कटौती कर कुछ लचीलेपम के साथ ग्रमल में लाया गया । गुजरात गौर महाराष्ट्र में मूगफली पर दिये जाने वाले ग्रिग्रिमों के लिए 75 प्रतिशत का न्युननम मार्जिन निर्धारित था । नवम्बर 1975 में इस क्षेत्रीय विभेद को हटा दिया गया भीर समग्र देश में 60 प्रतिशत का एक समान मार्जिन लागू किया गया । सार्च 1976 में इस न्यूनतम मार्जिन को ग्रौर कम कर 50 प्रतिशत कर दिया गया जबकि मूंगफली के स्टाकों से सर्वोधन गोदाम रमीदो पर विये जानेवाले घग्निमो के लिए 45 प्रतिशत का मार्जिन निर्धारित किया गया । चीनी के संदर्भ में लेकी ग्रीर मुक्त बिकी की चीनी के लिए निर्धारित अलग-अलग माजिनों के स्थान पर 15 प्रतिशत का एक समान माजिन निर्धारित किया गया । सूर्ता वस्त्रो (मानव निर्मित रेगे सहित) पर व्यापारियों को दिये जाने वाले मग्रिमों के माजिन को भी 10 प्रतिशान में कम कर 30 प्रतिशत **कर दि**या गया।

198 श्रिप्रमा के लिए उच्चनम सीभाए पहले की तरह पार्टीबार श्राधार पर निर्धारिन की जाती रही। परन्तु श्रन्पान स्तर निर्धारिन करने का प्राधार पिछले तीन वर्षों (नवस्वर-प्रक्न्बर) प्रथित् 1974-75, 1973-74 प्रीर 1972-73 में से किसी वर्ष के दौरान बकाया प्रशिमों के णिखर स्नर का 100 प्रतिशत था। व्यापारियों की प्रवन प्रशिमों से संबंधित दानों की प्रपत्ती देवता की सीमा को बढ़ाने के लिए भारतीय ऋए गाउँटी निगम निमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव की ध्यान में रखते हुए निगम की गाउँटी योजना के प्रतांत ग्राने वाले ध्राप्रमों के सबध में छूट की सीमा को रूठ 20,000 से बहुाकर रूठ 25,000 कर दिया गया। ऋए गाउँटी संगठन हारा गाउँटीकृत ध्रिप्तमों तथा ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के प्रतर्गत प्रांने याले प्रशासकर प्रांतिकाण-यूनिटों को प्रदन प्रशिमां के मामले में भी इसी प्रकार की छूट दी गयी।

199. खाद्याक्री को छोड़कर अन्य अन्यावश्यक उपभोकता वस्तुक्रों के मामले में बैकों को यह सूचिन किया गया कि वे ऐसी वस्सुक्रों के वितरण का कार्य करने वाली राज्य/केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों तथा उपभोकता सहकारी समितियों को दिये जाने बाले अग्रिमों में संबंधित स्टाकों पर 10 प्रतिशास का मार्जिन अनार्य रखे अग्रेने कि सरकारी गार्टी उपलब्ध हो। अत्यावश्यक उपभोकता वस्तुक्रों के वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवितित योजना के अनुगंत रखे हुए वनस्पति नेलों और चीनी के स्टाको पर उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्रवान किये जाने वाले यग्रिमों के संबंध में मार्जिन और ऋण के स्तर, दोनों में उपयुक्त छुटे वी गयी।

200. सभी केन्द्रों में स्थित खास्रान्त्र-प्रशिसस्करण यूनिटों को खास्रान्तों पर वियो जाने वाले प्राप्रिमो को निर्धारित ऋण स्तर से छुट दी गयी। 1 लाख या उससे कम जनसंख्यायुक्त केंद्रों में 1 जनवरी, 1970 को या उसके बाद खोली गयी बैंकों की नयी णाखाओं से ऋण सीमाधी की ग्राभ्यर्थना करने वाली नयी पार्टियों के लिए सभी राज्यों ग्रीर संघशासित क्षेत्रों में 1 लाख रूपये का ग्रांतिरिक्त ऋण-स्तर निर्धारित किया गया। सरकारी एजेंटो के रूप मे कार्य करने वाले चावल मिल मालिको को धान ग्रीर चावल पर प्रवान किये जाने वाले अधिमी को ऋण नियत्नण सबंधी निवेशों से उस सीमा तक पूरी छूट दी गयी जिस सीमा तक उत्पादको के वसूली खाते में भ्रलग से स्टाक रखें गये हो। खाद्य एवं ग्रखाद्य तिलहनो ग्रीर तेलों के बीच विभेद किया गया ग्रीर श्रखाद्य तिलहनो नथा तेला के लिए स्थनतर मार्जिन निर्धारित किये गये । रुई की कतिपय प्रतिरिक्त किस्सो को ऋण-स्वर की भ्रपेक्षा से छूट तथा न्यूनतर मार्जिन की हकदारी के लिए पान बनाया गया । सूनी वस्त्रों की बिकियों से उत्पन्न होने वाली 60 दिनो से अन्धिक अवधियुक्त विनिमय हुंप्रियों की भुनाई करने की भी अनुमति बैकों को दी गयी।

201 1975-76 की अंतिम तिसाही में रुई के बढते हुए मुख्यों की देखाने हुए तथा मिलो डारा ग्रधिकतम स्टाक रखे जाने के बारे में बस्स द्यायक्त क्षारा की गयी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए बैक ने 8 जलाई. 1976 में रुई श्रीर कपास के लिए । दये जाने वाले श्रिशमों के संबंध में चयनात्मक ऋण नियक्षणो को कठोर बना दिया है। जिन स्टाको के स्तरी के सबध में निम्न मार्जिन लाग होते हैं उन्हें काफी ग्रधिक कम कर दिया गया । इस प्रकार बम्बई ग्रौर ग्रहमदाबाद की मिलो के मामले मे 12 सप्ताही के उपभोग के स्टाक के लिए 25 प्रतिगत और इसमें प्रधिक स्टाक के लिए 50 प्रतिणत के वर्तमान मार्जिकों को बदलकर 4 मण्ताही के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत भीर उससे भ्रष्ठिक स्टाक के लिए 45 प्रतिपात पून निर्धारित किया गया । राष्ट्रीय बस्त्र निगम के प्रधिकार में रहने वाली मिला और बंबई और ब्रह्मदाबाद को छोडकर दूसरे क्षेत्रों की मिलों के मामले में इसी प्रकार के परिवर्तन किये गये है। मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों के मामले में मार्जिनों को नयी/या सम्बे रेगेबाली रुई के मामले में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत, देशी रुई की ग्रन्य किस्मो के लिए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और गोदाम रसीदो के ब्राधीन बाने वाले स्टाकों के लिए, 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

202. तिलहनो स्रौर बनस्पति तेलों की पूर्ति स्रौर मुख्य की स्थिति की समीक्षा करने पर 14 जुलाई, 1976 से रिजर्व बैक नेन्युननम मार्जिन में 10 प्रतिशास की बुद्धि की प्रार्थात मुगफली, एरण्ड के बीज ग्रीर ग्रासी के बीज के लिए दिये जाने वाले स्रियमों के मामले में 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत ग्रीर एरण्ड के तेल ग्रीर अलमी के तेल के मामले में 15 प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कर दिया है। बिनौले ग्रीर बिनौले के तेल के लिए विसे जाने वाले प्रिप्रम भी चयनात्मक ऋण नियस्रणों के भ्रधीन लाये गये । इनके लिए निर्धारिक न्यूननम मार्जिन कमण 60 प्रतिशत ग्रीर 75 प्रतिशत है। उनके लिए भी उच्चेतम ऋण स्तर ग्रीर 15 प्रतिशत की त्युनतम ब्याज दर की शर्ते लागु की गयी । जहा तक तोरिया के थीज/सरसों के बीज का सबध है, न्यूनतम मार्जिन में 10 प्रतिशत की बृद्धि हुई—–उसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार भौर पश्चिम बगाल की पंजीकृत तेल मिलों के लिए 25 प्रतिशत में अकाकर 35 प्रतिशत ग्रीर ग्रन्थ राज्यों की पजीकृत तेल मिली के लिए 40 प्रतिशत में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया । गोवाम रसीदो पर विधे जाने बाले प्रश्निमों के लिए भी उचित न्युनतम मार्शित निर्धारित किये गये । धम्तृत म्ंगफली के तेल, तोरिया के बीज के तेल/ सरमों के तेल भ्रौर बनस्पति पर दिये जाने वाले श्रिप्रमां के लिए निर्धारित वर्तमान 75 प्रतिशत के न्यूनतम माजिन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । बनम्पति तेलों पर बनस्पति उत्पादको को दिये जाने वाले श्राग्रमो से संबंधित वर्तमान मार्जिन भी श्रपरिवर्तित रहे। बिनौले के तेल के लिए निर्धारित न्युनसम मार्जिन बनस्पति उत्पादको पर लागू नही थे।

#### प्रप्रणी बैक योजना

203. दिसम्बर, 1969 में रिजार्व कैंक द्वारा आरंभ की गयी अग्रणी श्रेक योजना के छ. वर्ष पूरे हो गये हैं। अन यह निक्चय किया गया कि दो राज्यो अथित् गुजरात और महाराष्ट्र में इस योजना की कार्य-प्रणाली का गभीर अध्ययन किया जाए।

### योजना की कार्य प्रणाली से संबंधित ग्रध्ययन दल

204 इस निर्णय के अनुसार रिजर्ब बैंक ने अगस्स, 1975 में दों अध्ययन दलों का गठन किया: उनके विचारणीय विषयों में निम्नलिखित शामिल थें । जिला स्तरीय सलाहकार समितियों के गठन और कार्य-प्रणाली की जांच, वितीय सस्थाओं और राज्य सरकारों के बीच संबंध और उनका स्वरूप तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के निरूपण और कार्यान्वयन में बैंकों की सहभागिता की सीमा । उक्त अध्ययन दलों ने विसम्बर 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

205 प्रपनी मयक्त रिपोर्ट में भ्रध्ययन दल इस निकर्ष पर पहुंचे थे कि जहा प्रग्रणी बैंक कार्यक्रम का पहला चरण जिसमें बैंकिंग की संभाष्यता वाले केन्द्रो का पता लगानर ध्रौर उन केंद्रो में दैंक शाखाए खोलना शामिल है, नये कार्यालयों की संख्या श्रौर सहभागी प्रयासी के एक नये स्वरूप के उद्भव की दृष्टि से सफल रहा वहा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के निरूपण ग्रीर कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हुई । ग्रध्ययन दलो को यह ज्ञात हुआ। कि कुछ बैकों द्वारा भ्रापने जिलों मे बनाई। गयी 'ऋण योजनाश्रों' की कार्यपद्धति ग्रीर क्षेत्रीय व्यापकता मे अन्तर है। यद्यपि दलों ने इस संबंध में समान पद्धति की सिफारिण नही की है फिर भी जन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी भौर भ्राधिक दुष्टि से सक्षम योजनाए बनायी जाएं तथा मभी वित्तीय संस्थाएं उन योजनायों की सामू-हिक रूप से कार्यान्त्रित करे। उन्होंने सुझाव दिया कि बैको को प्राथ-मिकता वाले क्षेत्रों के व्यापक क्षेत्र में ऐसी योजनाएं बनाने का कार्य गुरू करना चाहिए जिन्हे तत्काल कार्यान्वित किया जा सके ग्रीर 3 से 5 कर्षों के दौरान पूरा किया जा सके । प्रध्ययन दलो ने अन्नणी बैक योजना को मधिक प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धात प्रस्तृत किये है; उक्त योजना में बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने योग्य योजनाएं बनाना ग्रोर उनको कार्यान्वित करना तथा जिला सलाहकार समितियो

का गठन भीर कार्य शामिल है। अध्ययन दलों ने समीक्षाधीन श्रम्रणी बैक योजना की समग्र प्रगति को बनाये रखने के उद्देण्य से रिजर्थ बैक में एक स्थायी समिति के गठन का सुझाब भी दिया है।

### उच्च स्तरीय समिति

्रे06. इस सिफारिश के छन्मार प्रग्नणी बैक योजना के लिए रिजर्व बैक ने एक उच्च स्तरीय समिति गठिम की । यह समिति श्रन्थ बातों के साथ-साथ प्रग्नणी बैक योजना की प्रभावणाली ढंग से चलाने के लिए नीति सबंधी मार्गदर्शी सिद्धाल जारी करेगी, योजना के कार्यान्वयन में आने वाली श्रीर राज्य सरकारों तथा रिजर्व बैक के क्षेग्नीय कार्यान्वयन में आने वाली श्रीर राज्य सरकारों तथा रिजर्व बैक के क्षेग्नीय कार्यान्वयन में प्राचन की जानेवाली विधिष्ट समस्याओं की जाच करेगी श्रीर स्वीकृत वायरों का प्रनुपालन न करने से सबंधित मामलों के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी। गुजरात श्रीर महाराष्ट्र में योजना की कार्यपद्यति के सबंध में उपर्युक्त प्रध्ययन दलों द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धातों को सभी बैकों में प्रचालित किया गया है।

207- 24, फरवरी 1976 को भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के वैंकों के मुख्य कार्यपालको की एक बैंठक आयोजिस की जिसमें बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंको की भूमिका पर विचार-विमर्ण किया गया।

# बीस सूत्रीय ग्रार्थिक कार्यक्रम की ग्रीर सरकारी क्षेत्र के बँकों का सुझाव

208 भीम सूत्रीय प्राधिक कार्यक्रम के कार्यान्त्रयन के लिए बैक जिन प्रमुख क्षेत्रों में महायता प्रवान कर सकते है उनमे निम्नलिखित शामिल है: (क) अत्यावस्यक वस्तुओं की वसूलो ग्रौर विकरण, (स्र) जिन भूमिहीन मजदूरो तथा समाज के भ्रन्य कमजोर वर्गों को भूमि श्रीर मकात बनाने के लिए जमीन प्रदान की जा रही है उनकी सहायना, (ग) बंधक मजदूरी से मुक्त लोगों के लिए सक्षम उत्पादक कार्य गरू करने मे महायना, (घ) भृमिहीन मजदूरो, छोटे किसानो ग्रौर कारीगरो से की जाने-वाली ऋण की वसूली के अधिस्थगन के फलस्वरूप ऋण क्षेत्र में उत्पन्न आर्थ को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराना ग्रीर ग्रामीण ऋणग्रस्ततः के समापन के लिए कार्यक्रम को क्रमणः कार्यान्वित करना, (इ) लघु सिचाई योजनायो भौर भूमिगत जल साधनो के ग्रधिक भच्छे उपयोग के लिए कृषि क्षेत्र को अधिक माल्ला में विसीय सहायता, (च) हथकरधा बुनकरो को वित्तीय महायता, (छ) जिन लोगां को सङ्क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परिमट प्रदान किये जाते हैं उनकी सहायता, (अ) छात्रावामो में छात्रों के लिए अत्यावश्यक वस्तुम्रों तथा नियंद्रित मुल्यो पर पुस्तको ग्रौर लेखन सामग्री की पूर्ति करने के लिए बनाये गये कार्येकम में सहायता, ग्रौर (झ) उधामियों के लिए रोजगार ग्रौर प्रशिक्षण के श्रवसरों को, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लिए, बढ़ाने के निमित्त योजनाएं।

209 बैंको से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोटों के धनुसार बैंकों ने कार्यक्रम के सहस्व को समझ लिया है और समाज के विभिन्न कमजोर बगों को विलीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाए प्रस्तुत करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं। रिजवं बैंक ने भी समय-समय पर बैंकों को धावश्यक मार्गपर्थी सिद्धांत जारी किये हैं। उनमें से धवतन मार्गपर्थी सिद्धांत समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनायी गयी आवास योजनाओं के लिए विलीय सहायता प्रदान करने के संबंध में हैं। इसके प्रलावा पूर्व 1976 में रिजवं बैंक ने बीम सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के कार्यात्वयन में बैंकों की भूमिका पर एक विवार गोष्ठी आयोजित की थी। विचार गोष्ठी के दौरान बैंकों हारा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बनायी गयी विभिन्न योजनाओं पर विचार किया गया। बैंकों ने भी अपने कर्मचारियों को वैकिंग के इस नवीन क्षेत्र की शिक्षा देने के लिए कार्यभालाएं/शिवर/विचार गोष्टिया आयोजित की।

210. जहां प्रत्येक बैंक, को इस कार्यक्रम के प्रधीन पाये गये जोगों को सहायला प्रदान करने के लिए प्रावण्यक पहल करनी होगी वहीं प्रप्रणी बैंकों से यह आणा की जाती है कि वे अपनी स्थित के बल पर इस दिणा में अन्य बैंकों को मार्ग दिखाये। अतः 2 जून 1976 का भारत सरकार ने इन बैंकों का निवेश दिया कि वे बीस सून्नीय आर्थिक कार्य-कम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनी योजनाओं को पुनर्व्यवस्थित करें। इस मंबंध में बैंकों से बहा गया है कि वे समय-समय पर अपने संगठन तंत्र, ऋण मंजूर करने की शक्तियों के प्रत्यायोजन, ऋण सम्बन्धी कियाविध और ऋण की शर्तों की समीक्षा करें ताकि गांवों की गरीब जनता को शिद्य ऋण वितरित किया जा सके। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने द्वारा किये गये बीस सून्नीय आर्थिक कार्य-कम के कार्यान्वयन-कार्य के परिमागा और गुणवना का समय-समय पर मृत्यांकन करें।

### क्षेत्रीय प्रामीण बैक

211, 26 मितंबर 1975 को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 के अधीन 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 के अधीन 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गयी वह श्रालोच्य वर्ष के दौरान वैकिंग क्षेत्र की उस्लेखनीय उपलब्धि हैं। उपर्युक्त अध्यादेण का स्थान बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ने ले लिया। यह कार्रवाई उस कार्यकारी दल की सिफारिशों के फलस्वरूप की गयी जिसे 1 जुलाई 1975 को भारत सरकार द्वारा बीस सूक्षीय ग्राधिक कार्यक्रम के अधीन उठाये गये कदमों के संदर्भ में ग्रामीण जनता को संस्थापत ऋण प्रवान करने के लिए वैकल्पिक एजेसिया बनाने की समस्या पर गहराई से ग्रध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रमुख लक्ष्य, उनके पूंजी निर्माण, संगठन, कारोबार और कार्यप्रणाली के प्रन्य पहसुद्धों पर ग्रामे विवार किया जा रहा है।

### लक्ष्य, स्वापना ग्रौर पूंजी

212. क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य विशेष कपा से ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे श्रौर सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, कारी-गरों ब्रौर छोटे उद्यमियों को ऋण तथा अन्य मुविधाएं, प्रवान करना है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण मैंक स्थानीय मीमाओं के ग्रंतर्गत जो ग्राधसूचना द्वारा निविष्ट की जाएगी, कार्य करेगा । भ्रावश्यकनानुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैक सरकार द्वारा अधिसूचिन किसी स्थान पर शास्त्राएं या एजेंसियां भी स्थापित कर सकता है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकारी क्षेत्र के किसी बैक द्वारा प्रवर्तित होता है जो कई तरह से उसे सहायना प्रदान करता है; उक्त महायता में निम्निविधित गामिल है: उसकी शेयर पूंजी में प्रशिदान करना, श्रापसी समझौते के श्रमुसार प्रबंध संबंधी और विश्लीय महायता प्रवान करना ग्रीर क्षेत्रीय ग्रामीए। बैक को प्रारम्भिक कार्यकाल में कर्म-चारियों की भर्ती और प्रशिक्षण में महायता प्रवान करना । प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पृत्री । करोड़ रुखे है धीर जत्री की गयी पुत्री 25 लाख रुपये हैं। जारी की गयी पूंजी मे भारत सरकार के ग्राभिदान का ग्रंग 50 प्रतिशत, संबंधित राज्य सरकार का ग्रंग 15 प्रतिशत भीर शेष भर्षात् 35 प्रतिशत ग्रंग प्रवर्तेक श्रेंभ का होता है।

#### प्रबन्ध तंत्र

213. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबंध नो सदस्यीय निवेशक संहल के हाथ में होता है जिसका अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निवेशक मंडल को अपना कार्य वाणिज्य मिद्रांतों भौर रिजर्व बैंक के परामर्थ से भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निवेशों के भ्रनुमार करना होता है। जहां क्षेत्रीय न्नामीण बैंकों को भावश्यकतानुसार अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने की अधिकार है वहां उनका पारिश्रमिक उस बैंक के कार्यक्षेत्र में स्थित राज्य सरकार ग्रीर स्थानीय प्राधिकरणो

के कर्मेचारियों के बेतन ढांचे के तुलनात्मक स्तर श्रौर स्थिति के भनुगार भारत सरकार द्वारा निर्धारिन किया जाता है।

#### व्यवसाय

211. प्रत्येक क्षेत्रीय प्रामीण बैंक बैंककारी विनियमन प्रधिनियम, 1949 की धारा 5 (ख) की परिभाषा के अनुमार बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत हैं धौर वह उक्त प्रधिनियम की धारा 6 (1) में निर्दिष्ट प्रत्य कारोबार भी कर सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य करना जरूरी है: (क) कृषि उद्देश्यों या कृषि कार्यों अथवा ग्रन्थ संबंधिन उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत या सामू-हिक रूप से छोटे ग्रीर सीमान्त किमानों ग्रीर कृ.व श्रीमकों तथा सहकारी समितियों प्रयात् कृषि विपणन समितियों, कृषि भ्रमिसस्करण मिनियों, सहकारी कृषि समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों या कृषक सेवा समितियों को ऋण भीर भ्रमिम प्रवान करना; (ख) भ्रपने कार्यक्षेत्र में कारीगरों, छोटे उद्यमियों भ्रीर व्यापार, वाणिज्य, उद्योग या भन्य उत्पावक कार्यों से लगे हुए कम साधनों वाले लोगो को ऋण भीर भाग्रम प्रवान करना।

# रिवर्ष मैंक की सहायता और करों में रियायतें

215. मब तक स्थापित सभी श्रेतीय ग्रामीण वैकों को भारतीय रिश्वर्व बैक मधिनियम, 1934 की दूसरी मनुसूची में शामिल कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रधिनियम, 1934 में किये गये संशोधनों द्वारा रिजर्व बैंक उक्त भिधिनियम की धारा 46(भ्र) भीर 46(भ्रा) के मधीन राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि भीर राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋणों धौर प्रक्रिमों के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण वैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही बैंककारी विनियमन प्रधिनियम, 1949 में किये गये एक संशोधन द्वारा रिजर्ब बैंक को यह मधिकार प्राप्त हो गया है कि वह क्षेत्रीय ग्रामीण वैंकों के मामले में उक्त मधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2 (म्र) में उहिलाखित वैंकिंग कंपनी की मांग झीर मीयादी देयताओं के झनुरूप चल धास्तियों को बनाये रखने के संदर्भ में निर्धारित प्रतिशत में परिवर्तन कर सके। इस प्रकार क्षेत्रीय प्रामीण वैंकों द्वारा जो स्यूनतम सांविधिक चल भास्तिया बनाये रखने की भ्रपेका है उनकी सीमा केवल 25 प्रतिशत निर्वारित की गयी है जबकि मन्य भनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में वर्तमान मपेक्षा 33 प्रतिगत है। रिश्वर्व वैंक द्वारा जारी की गमी एक मधिसुवना द्वारा 2 मन्द्रबर 1975 से एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रपनी कुल मांग घौर मीयावी वेयताघों के 3 प्रतिगत की दर पर सकदी प्रारक्षित निधि रखना जरूरी है (जैसा कि भारतीय रिजर्थ वैक प्रधिनियम,

1934 की घारा 42 की छपधारा (1) में निर्विष्ट है) जबकि घरण धनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए उक्त दर 4 प्रतिशत है। इसके प्रतिरिक्त प्राथकर प्रधिनियम, 1961 या घाय लाभ या उपलब्धि पर लागू कर से संबंधित किसी धन्य प्रधिनियम के उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को महकारी ममिति के रूप में माना जायगा। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ब्याज दर प्रधिनियम, 1974 के प्रधीन कर देने के लिए बाध्य नहीं है।

#### कार्यपञ्जति

216 राणि जमा करने/निकालने, ऋण प्रावेधन-पत्न प्रस्तुन करें, ऋण दस्तावेज निष्पादिन करने प्रादि में होने वाले कियाबिधि संबंधी विलम्ब को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रथनायी जाने वाली लेखाविधि धौर परिचालन संबंधी कार्यपद्धति ग्रादि की सलाह देगी नाकि ग्रामीण ग्राहक इन बैंकों के साथ कार्य करते हुए भ्रपनापन अनुभव करें। रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के भव्यकों और गाखा प्रबंधकों को सथाशीध्र प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का कार्य भी शुरू किया है।

### क्रोत्रीय प्रामीण बैकी का कार्य

217. 30 जून 1976 के धंत तक देश के विभिन्न राज्यों में 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा चुके हैं। इस प्रकार का पहला बैंक 2 प्रकटूबर 1975 को और उत्तमीसवां बैंक 30 प्रप्रैल 1976 को स्थापित किया गया (सारणी 25)। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इस छोटी सी भवधि में लगभग 112 कार्यालय खोले, उनकी गतिशील जमा राशियां 1.2 करोड़ रुपए हैं भीर उन्होंने 1.5 करोड़ रुपयों के भग्निम प्रवान किये हैं।

# वेक्तिंग विधान वैककारी विनियसन (कल्पनी) नियमावली 1949 में संशोधन

218. पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि बैककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949 में संशोधन के संबंध में सरकार की ग्रिक्षिसूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। इस ग्रिक्षिसूचना के जारी हो जाने के फलस्थरूप रिजर्व बैंक के संशोधनों की सूचना देते हुए सभी बैंकों को एक परिपक्ष जारी किया; उक्त संशोधन 13 दिसम्बर 1975 से धमल में ग्राये।

सारणी 25 : क्षेत्रीय प्रामीण बैकों की सूची

बैंक का नाम प्रौर उसका प्रधान कार्यालय	स्थापमा की नारीख	प्रवर्तक बैक	राज्य	ग्नधिकार क्षेत्र (जिलों की स्थानीय सीमा के ग्रधीन)	खोशी गयी णाखामो की संक्या
1	2	3	4	5	6
<ol> <li>गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण वैक, गोरखपुर</li> </ol>		स्टेट बैंक फ्रॉफ इंडिया	उसर प्रदेश उत्तर प्रदेश	मुरावाबाव गोर <b>ख</b> पुर ग्रोर देवरिया	9
<ol> <li>हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी</li> <li>जयपुर नागौर ग्रांचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर</li> </ol>		पंजाब नेमानल बैंक युनाइटेड कर्मामयल बैंक	हरियाणा राजस्थान	भिवासी जयपुर झीर नागीर	12

	1	2	3	4	5	6
5.	गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्वा .	02-10-1975	युनाष्ट्रेड वैंक भ्रॉफ़ इंडिया	पश्चिम बंगाल	माल्दा, पश्चिमी दीनाजपुर भीर मुणिदाबाद	18
6.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैक, मारा	26-12-1975	पंजाब नेशनल बैक	बिहार	भोजपुर ग्रीर रोहताम	6
	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण कैंक, भाजमगढ़	06-01-1976	युनियन भैंक झांफ इंडिया	उत्तर प्रवेश	भाजमगढ भौर गांजीपूर	7
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होणंगाबाद	20-01-1976	सेन्ट्रल बैक झाफ़ इंडिया	मध्य प्रवेश	होशंगाबाद भीर रायसेन	6
	तुगभद्रा प्रामीण वैंक, बल्लारी	25-01-1976	कनारा बैक	कर्नाटक	बस्लारी श्रीर रायचुर	7
	पूरी ग्राम्य वैंक, पिपली	25-02-1976	इंडियन क्रोबरसी प्र बैंक	उड़ीसा	पुरी	2
	जम्म् स्टरल <b>वै</b> कं, जम्म् .	12-03-1976	जम्मू एण्ड कश्मीर वैकलि०	<b>अम्म् झौर</b> काण्मीर	_ जम्म्	2
12	वपारन क्षेत्रीय ग्रामीण वैक, चपारन	21-03-1976	सेन्ट्रल बैंक झॉफ इंडिया	बिहार	पूर्वी भीर पश्चिमी चंपारन	3
1.3	बारावंकी ग्रामीण बैंक, बाराबकी	27-03-1976	बैंक प्राफ़ि इंडिया	उत्तर प्रदेण	मारामकी	1
14	गुड्गाव ग्रामीण वैंक गृक्ष्मीव .	28-03-1976	सिडिकेट बैक	हरियाणा	गुङ्गाव	8
15	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण गैंक,					
	रावबरेली .	29-03-1976	भैक ग्रॉफ बड़ौदा	उत्तर प्रवेश	रायबरेली	1
16	फर्रुवाबाव ग्रामीण बैक, फर्रुखाबाद	29-03-1976	बैक स्रॉफ़ इंडिया	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	1
17	मल्लभूम ग्रामीण वैक, बकुरा	09-04-1976	युनाइटेड बैंक झॉफ़ इंडिया	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया बंकुरा श्रीर मिदनापुर	3
18.	कोलांगीर सांचलिक ग्रामीण बैक,				- •	
	बोलांगीर	10-04-1976	स्टेट मैक भ्रॉफ़ इंडिया	<b>उड़ी</b> सा	बोलांगीर	1
19	नागार्जन ग्रामीण वैंक, खम्मम	30-04-1976	स्टेट बैंक भ्रॉफ इंडिया	माध्य प्रदेश	चम्मम भौर नलगोंडा	4

### राज्यों के विधान

219. यह स्मरण होगा कि 1971 में राज्य प्रिधिनियमों से सबधित विशेषकों के दल ने विभिन्न राज्यों द्वारा एक घावर्ण विधेयक अपनाने की सिफारिश की थी जिससे प्रधिक जल्दी और समय पर कृषि ऋण विश्तरित किये जा सकें। अब तक 10 राज्यों ध्रयात् हरियाणा, हिमाचल प्रवेश, कर्नाटक, मध्य प्रवेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, विपुरा, उत्तर प्रवेश घौर पश्चिम बगाल ने विधान बनाये हैं। प्रालोच्य वर्ष के दौरान र राज्यों ध्रयात् झांध्र प्रवेश, प्रसम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर भीर मेधालय ने प्रारूप विधेयक बना लिये है।

### निरीक्षण, विलयन और तंबीधत संगठनात्मक विषय-मिरीक्षण

220 पिछले तीन वर्षों (जुलाई-जून) के धौरान बैकी तथा बैक कार्यालयों का जो निर्शक्षण किया गया उसकी तुलनात्मक स्थिति नीचे वर्षायी गयी हैं:---

		1975-76
-		
2.1	28	31
752	506	787
614	1217	1492
2218	2362	2328
1	2	2
	2 1 752 614	24 28 752 506 614 1217 2218 2362

221 वाणिज्य बैको की विलीव स्थित निर्धारित करने के लिए रिजर्ब बैंक द्वारा समय समय पर किये जाने वाले निरीक्षण के आधार पर आलोच्य वर्ष के दौरान बैंककारी विनियमन प्रधिनियम, 1949 की धारा 35 के घधीन 30 प्रनुसूचित बैंकों प्रौर 1 गैर-प्रमुसूचित बैंक का निरीक्षण किया गया/उन्हें निरीक्षणार्थं लिया गया। इनके प्रलावा घालोच्य खबधि के दौरान चिटेन ग्रौर फिजी द्वीप समृह में स्थित भारतीय बैंको की शाखाओं का निरीक्षण पूरा किया गया।

222 1,492 केन्द्रों में 2,328 कार्यालयों का निरोक्तण किया गया। इस वर्ष के वौरान प्रलग-श्रलग बैंको की प्रणालियों प्रौर कियाविधियों की जांच करने धौर जहा-जहा प्रावश्यक हो, उनमें सुधार का सुझाय देन के निमित्त उन बैंकों का प्रध्ययन करने का कार्यक्रम जारी रहा। इस वर्ष के दौरान यो बैंकों भर्चात् युनाइटेड बैंक ग्रॉफ इंडिया घौर बैंक श्रॉफ मतुरा लिं० के संबंध में प्रध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि बैंक ग्रॉफ महाराष्ट्र घौर युनाइटेड बैंक ग्रॉफ इंडिया की प्रध्ययन रिपोटों को ग्रंतिम रूप दे दिया गया है गौर उन बैंकों को प्रेज दिया गया है गौर उन बैंकों को प्रेज दिया गया है। 1971 में जब यह कार्यक्रम णूस किया गया था तब से लेकर प्रव तक रिजर्ब बैंक ने 8 बैंकों की प्रणालियो घौर किया विधियों का प्रध्ययन पूरा कर लिया है। संबंधित बैंकों को प्रध्ययन रिपोटों भेज वी गयी है ताकि उनमें पायी गयी ब्रुटियों का सुधार घौर उनमें दिये गये सुझाबों को कार्यान्वित किया जा सके।

# बैकों का विलयन झौर परिसनापन

223 इस वर्ष स्वैच्छिक समामेलन, वेयताग्रों ग्रीर ग्रास्तियों के ग्रांत-रण ग्रीर सहभागिता व्यवस्थाश्रों के ग्रारा वैकिंग व्यवस्था को समेकित करने के प्रयत्न जागे रहें । 1975-76 के दौरान गौहाटी बैंक लि०, को पूर्वांवल बैंक लि० के साथ ममायमेलित कर विया गया । बैंककारी विनियमन ग्रिधिनियम, 1949 की धारा 44भ के ग्रिधीन समामेलम की यह योजना जुलाई 1975 में मंजूर की गयी ग्रीर 1 ग्रगस्त 1975 से ग्रमल में ग्रायी।

224 पिछली वाषिक रिपोर्ट में यह उस्लेख किया गया कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत भारत सरकार में 49 बैंकों के समामेलन की योजनाएं मंजूर की थी। इन योजनामों के प्रधीम हम्नांतरी बैंकों को 6-12 वर्षों की अविधि या भारत सरकार द्वारा रिकर्व बैंक से परामर्थ कर मंजूर की गयी उससे पहले की अविधि के पश्चान हस्तांतरक बैंकों की आस्तियों का अंतिम मूल्यांकन करना था। 20 बैंकों की आस्तियों के अंतिम मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है और 11 मन्य बैंकों की रिपोर्ट विचारधीन है।

225 प्रमोच्य वर्ष के दौरान एक बैंक प्रयांत् बेंकगांव बैंक लि० ने 29 नवस्वर 1975 को कारीबार समाप्त होने पर कंपनी प्रधिनियम, 1956 की धारा 293 के प्रतिगंत अपनी चुनी हुई प्रास्तियां भौर देयन्त्राए, यूनियन बैंक प्रांक इंडिया को ग्रंसरिस कर दीं । एक प्राथ्य बैंक

स्वर्षात् झरिया इंडस्ट्रियल बैंक (प्राइवेट) लिंक, जो कि एक गैर अनुसूचिन बैंक है, भी अपनी देयनाएं और आस्तियां युनाइटेड कर्माशयल बैंक को अतरिन करने के लिए सहमन हो गया है। चूंकि अंतरण कार्य नहीं हो सका अत झरिया इंडस्ट्रियल बैंक (प्राइवेट) लिंक को सूचिन किया गया कि वह स्वैच्छिक परिसमापन के लिए तत्काल कदम उटाए। परिस्मापन के लिए और समय की अनुमति मांगते हुए बैंक से प्राप्त अनुरोध अस्त्रीकार कर दिया गया। इसके अलावा अनुसूचित बेंक नारंग बैंक आँफ इंडिया लिंक की आस्त्रियों और वेयनाओं की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 के अंतर्गत युनाइटेड बैंक आँफ इंडिया में अनरित करने के प्रस्ताब पर बातचीन ही रही है।

226. इस वर्ष के दौरान बैंक प्रांफ बड़ौदा को तैनीताल बैंक लिं० (गैर प्रनुसूचित बैंक) ग्रीर बरेली कांधीरेशन बैंक लिं० (ग्रनुसूचित बैंक ) की शेयर पूंजी में अणदान करने नी प्रनुमति दी गयी। इसकें साथ ही भारत सरकार ने युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिं० की शेयर पूंजी में युनाइटेड वेंक ग्रांफ इंडिया की सहभागिता को अनुमोदम प्रदान कर दिया है। यूनियन बैंक ग्रांफ इंडिया पहले से ही बनारस स्टेट बैंक लिं०, की शेयर पूंजी में ग्रंशवान कर रहा है।

227. ग्रालोच्य ग्रवधि के दौरान चार गैर ग्रनुसूचित वैको को विघ-टित कर दिया गया भीर 4 गैर धनुसूचित बैंको (प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से 3 को पिछले वर्ष के बौरान ग्रौर 1 को 1965 में विषदित किया गया था) के संबंध में रिपोर्ट वर्लमान वर्ष के दौरान प्राप्त हुई । बैंककारी विनियमन ग्रिधिनियम, 1949 की धारा 44(1) के ग्रिधीन किसी भी बैंक को स्वैच्छिक परिसमापन के लिए प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया । केन्द्रीय सरकार से श्रावश्यक निवेश प्राप्त करने के बाद बैंककारी विनियमन प्रधिनियम, 1949 की धारा 45 थ के अंतर्गत प्रालोक्य वर्ष के दौरान परिसमापनाधीन पांच बैंको ग्रथित सेट्ल कलकमा बैंक लि०, कलकत्ता कर्माशयल बैंक लि०, बैंक ग्रॉफ कलकत्ता लि०, नाथ बैंक लि० भौर अंगाल बैंक लि० की बहियों और खातों का निरीक्षण प्रारंभ किया गया ग्रौर उसे पूरा किया गया । जहां पहले तीन बैंको की निरीक्षण रिपोर्टों की जांच की गयी और वे भारत सरकार को भेजी गयी वहां ग्रन्य रिपोर्ट प्रभी भी विचाराधीन है। बैंककारी विनियमन प्रधिनियम, 1949 की धारा 45 थ के ग्रंतर्गत एसोसिएटेड बैकिंग कॉर्पोरेशन ग्रॉफ़ इंडिया लि० का निरीक्षण कार्य, जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, भ्रालोक्य वर्ष के दौरान भी पूनः प्रारंभ नहीं किया जा संका, क्योंकि निरीक्षण के लिए संबंधित प्रिमिलेख ग्रंब तक उपलब्ध नहीं कराये गये है।

### बैकों का लाइसेंसीकरण

228. श्रासोच्य श्रवधि के दौरान किसी भी बैंक को भारत में बैंकिय का कारोबार करने के लिए कोई नया लाइसेंस प्रदान मही किया गया, किन्तु बेलगांव बैंक लिंक को प्रदान किया गया लाइसेंस रह कर दिया गया । क्योंकि जैंसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उक्त बैंक का कारोबार प्रपने श्रिक्तार में से लिया था । इसके फलस्वरूप बेलगांव बैंक लिंक का नाम भारतीय रिक्षवं बैंक प्रधिनियम, 1934 की दूसरी श्रमुसूची में से हटा दिया गया है । इस प्रकार जहां एक श्रोर लाइसेसिकृत बाणिज्य बैंकों की संख्या घटकर 45 हो गयी (इनमें नेशनल बैंक प्रांफ पाकिस्तान भी शामिल है जो शहू संपत्ति के प्रभिरक्षक के प्रधिकार में है) वहां दूसरी श्रोर उन बैंकों की संख्या, जिनके मामले में लाइसेंस रह कर दिये गये है, बढ़कर जूम 1976 के शंत तक 55 हो गयी । यहा यह बात उल्लेखनीय है कि सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों को लाइसेंस की शावश्यकता नहीं है ।

229. आलोच्य ग्रवधि के दौरान बैंककारी विनियमन ग्रधिनियम, 1949 की धारा 22 के प्रधीन किसी भी कार्यरत बैंक को भारत में किंग कारोबार करने के लिए लाइसेस देने से ग्रस्थीकार नहीं किया गया । इस प्रकार जिन बैंको को लाइसेंस देने में श्रम्बीकार किया गया है, उनकी संख्या जून 1976 के श्रंत में बिना किसी परिवर्तन के 283 ही रही।

### समारोधन गृह मुविधाएं

230. 1975-76 (जुलाई— जून) के दौरात 31 समाणोधन गृह स्थापित किये गये। इससे देश में स्थित समाणोधन गृहो की कुल संख्या बढ़कर 243 हो गयी। इनमें में 9 समाणाधन गृहो का प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, 199 का प्रबंध स्टंट बैंक ग्रांफ इंडिया हारा ग्रीर 35 का प्रबंध स्टंट बैंक ग्रांफ इंडिया हारा ग्रीर 35 का प्रबंध स्टंट बैंक ग्रांफ इंडिया हारा ग्रीर 35

# चेकों के कूटों का मानकीकरण

231. इस वर्ष के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्य बैको को एक परिपक्ष जारी किया गया जियमें उन्हें अपने चेका में सबधित बैका श्रीर शाखाओं से संबंधित एक समान नयी कूट संख्याए दो खानों में समाबिष्ट करने का अनुदेश विया गया है। यह देखा जाएगा कि एक समान कृट इस उद्देश्य से अपनाये जा रहे हैं कि समाहारी बैंक प्रपत्नों को अविलम्ब और अमतापूर्वक बैकवार छांट सके तथा धाने और जाने वाल गोधन श्रीर बसूली के चेकों पर कार्रवाई करने में होने वाल समय और अम को काकी माहा तक बचा सके।

# ऋण सूचना और सांख्यिकीय आंकड़े

232 इस वर्ष के बौरान रिजर्व बैक ने एक नयी कियायिधि धारंभ की जिसके श्रेतगैत उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को त्रैमासिक धाधार पर वाणिज्य बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र से मलग धलग जमाराणियों श्रीर भणिमों (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को सिमाकर) के जिलेबार श्राकड़े एकत्र करने का कार्य सौपा गया । इस प्रकार एकत्र की गयी सुचना समेकित की जाती है धौर संबंधित श्रप्रणी बैंकों श्रीर राज्य सरकारों को उपलब्ध करायी जाती है । इस नथी क्रिया-विधि द्वारा प्रत्येक जिले के लिए श्राधारभूत सूचना शीद्रा एकतित करने का प्रयत्न किया गया है ताकि जिला मलाहकार ममितियों की बैठकों में मार्थक विचार विभर्ग हो सके।

233. इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने बैंकों से प्रबंध सूचना प्रणाली पर एक संज्ञालन सिमित गठित की जो (क) बैंकों से प्रबंध सूचना प्रणाली प्रारंभ करने के लिए उचिन मार्गदर्शी सिद्धान प्रस्तुत करेगी धौर उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी; (ख) बैंकिंग लागन, पाखाओं की लाभप्रदत्ता, कारोबार, श्रायोजना भौर कार्य संबंधी बजट भ्रादि विभिन्न पक्षों पर बैंकों को विशेषज्ञता पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगी; (ग) श्रांकड़े तैयार करने के त्वरित भौर श्रीधक सक्षम तरीकों से सबंधित मामलों को निपटाएगी और (घ) बैंकों में सूचना प्रणाली पर बैंकिंग भ्रायोग की अन्य सिफारियों और उचित अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार करेगी।

234. रिजर्ब बैंक का बैंकिंग परिचालन ग्रीर विकास विधाग वाणिज्य बैंको ग्रीर श्रन्य प्रधिसूचिल विद्याय संस्थामों को उनके श्रनुरोध पर श्रलग श्रलग ऋणकर्तामों को दी गयी ऋण सुविधामों के संबंध में सूचना प्रदान कर उन्हें सहायसा प्रदान करता रहा । 1975-76 के दौरान 1,184 श्राबदन पत्नों के संदर्भ में श्राबदक बैंको ग्रीर विद्याय संस्थामों को ऋण संबंधी सूचना प्रदान की गयी जबकि पिछले वर्ष के दौरान 953 ग्राबदन-पत्नों के संदर्भ में ऋण संबंधी सूचना प्रदान की गयी ग्री।

### मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी योजना

235 इस वर्ष के दौरान 'मूलभूत मास्त्रियकीय विवरणी' शीर्षक की श्रृंबला के प्रतर्गत वैकिंग सांख्यिकी का भीषा बंड प्रकाशित किया गया जिसमें जून 1974 तक की जमाराशियों तथा प्रश्निमों के व्यापक प्रश्निक्ड प्रमुत्त किये गये। महत्वपूर्ण विषयों पर दिसंबर 1974 तक के प्रनितिम परिणाम वेते हुए प्रप्रेल 1976 में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गयी।

236 बड़े ऋण लेखों के संबंध में जिनका भ्रंण कुल बैक ऋण में एक तिहाई है, जून 1976 से एक मामिक सूचना प्रणानी प्रारंभ की गयी। यह प्रणानी बैको से त्रैमासिक भ्राधार पर प्राप्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ग्रिप्रमों से संबंधित ग्रांकड़ों महित मासिक ग्राधार पर ऋण का स्पूल क्षेत्रीय वर्गीकरण प्रस्तुत करेगी जो कुल ऋण का 90 प्रतिशत है।

# प्रमुखींबत बाणिज्य बैकों के कार्य-परिणाम

237. सरकारी क्षेत्र के 22 बैको (स्टेट बैक समूह तथा 11 राष्ट्रीय कृत बैक) ग्रीर 25 श्रन्य भारतीय धनुमूचित वाणिज्य बैक, जिनमे से प्रस्येक के पास 10 करोड़ रुपयों की ग्रीर जनसे श्रीधक जमाराशिया ते, के प्रकाशित कार्य-परिणामा से 1975 के क्षीण्डर वर्ष के दौरान उनके

लाभो (²⁵) में ग्रीर सुधार परिलक्षित होता है। 1975 में मरकारी क्षेत्र के बैकों की लाभ राग्नि में 39 प्रतिमत की उल्लेखनीय बृद्धि पायी गयी जबकि गैर सरकारी क्षेत्र के 25 भारतीय अनुसूजित वाणिज्य बैकों की लाभ राग्नि में 11 प्रतिमत की सीमान्त वृद्धि हुई। दूसरी ग्रीर 12 विदेशी बैकों की लाभ राग्नि में 1974 की 50 प्रतिमत की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष 16 प्रतिमत की गिराबट पायी गयी (सारणी 26)।

(25) कराधान भ्रौर कर्मचारियों को देय बोनस/श्रमुगृह भुगतान के लिये व्यवस्था करने के बाद विद्यमान लाभ । 1975 की लाभ राणि 1974 की लाभ राणि से सर्वेषा सुलनीय नहीं है, क्योंकि कुछ बैंकों के मामले में लाभ राणि का निर्धारण करने की त्रियाविधि में परिवर्तन किया गया है।

सारणी 26: अनुसुचित वाणिश्य बैकों के कार्य-परिणाम

(राशि करोड रुपयों में)

	स्टेट ग्रैक सम्	ह	राष्ट्रीयकृ	त बैंक	सरकारी क्षे कुल बै		भ्रन्य भारतीय बाणिज्य		विदेणी	बैंक
	1974	1975	1974	1975	1974	19 <b>7</b> 5	1974	1975	1974	1975
	l	£	3	4	5	6	7	8	4)	10
I. कुल प्राय							9 101.44 (43.8)			119.57
उसमें ^स ं										
(क) ब्याज ग्रीर बट्टा							86.94 (41.0)		82.10 (39.7)	96.7 (17.8
[. <b>दु</b> ल व्यय • •							9 98.55		98.75 (38.1)	
उसमें से										
(ख) उधारो, जमाराशियो प्रादि पर दिया गया ब्याज					562.32			73.73	45.27	49.5
(ग) कर्मचारियों को बेतन, भक्त, भविष्य, निधि श्रीर बोनस/		(33 1)	(50.8)	(27.6)	(49.9)	(29.3)	(41.4)	(43.6)	(48.2)	(9.4
<b>धनुग्र</b> ह भुगनान	145 12				363 29 (28.0)		33 96 (41.4)			23.4 (2.9
∐ कराधान स्रौर कर्मचारियो को देय भानसः/श्रमुग्रह राशि के लिए स्र्यव										
	5 22	7.45	10.38	15.25	5   15   60	22 70	2 89	3 22	6.30	5.
	(12.2)	(427)	(35.7)	(46.9)	(26.7)	(15, 5)	(109 4)	(11.4)	(50.0)	(-16.

टिप्पणी: कोष्टकों में दिये गये श्राकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई घट-बढ़ को दर्शात है। 1974 के ग्राकड़े परिशोधित हैं।

⁽a) ये आंकडे पैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे 25 भारतीय अनुसूचित बैंकों के हैं जिनमें से प्रत्येक के पास 10 करोड़ रुपयों की या उससे अधिक जमाराशियां है।

स्रोत . बैकों के लाभ-हानि लेखे।

### सरकारी क्षेत्र के बैक

238 सरकारी क्षेत्र के 22 बैको (स्टेट बैक समूह भीर 14 राष्ट्रीय-कृत बैक) के 1975 के कार्य-परिणामों का विश्लेषण करने पर यह विदित होता है कि उनके लाभों में पिछले वर्ष के मुकाबले मे प्राय में थोड़ी सी वृद्धि के बावजूर 1974 के 15.6 करोड़ रुपयों की तुलना में 1975 में 21 7 करोड़ रुपयों की बृद्धि हुई । 1975 में कुल श्राय भीर व्यय के बीच काफ़ी प्रस्तर होने के कारण लाभो मे वृद्धि हुई। 1975 के दौरान इन बैंकों की कुल ग्राय में 262 8 करोड़ रुपयो (25.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबिक 1974 में 286 7 करोड़ . रुपयो (38.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । ग्राय में हुई मधिकांण बृद्धि 'भ्याज भीर बट्टे' से हुई जिसमें 1975 के बौरान 231.8 करोड़ रुपयो (25 8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1974 के दौरान उसमें 252.3 करोड़ रुपयो (39.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 1975 में ऋष्ण की मात्रा को बढ़ाने भीर बैको द्वारा उद्यारों पर नियों जाने वाले न्याज की न्यूमनम घर को 23 जुलाई 1974 में 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिये जाने से उपर्युक्त स्रोत से प्राप्त बैंक की भाग में मुधार हुआ । 1975 में 'कमीणन, विनिमय ग्रीर दलाली' से प्राप्त ग्राय भी 1974 के मुकाबले ग्रंधिक थी। इन बैको के कुल क्याय मे भी वृद्धि पायी गयी; किल्लु 1975 के दौरान व्यय में हुई वृद्धि 1974 के मकाबले काफी कम थी। इस प्रकार 1975 में इस बैको के कुल क्याय मे 255 7 करोड़ रुपयोँ (24.9 प्रतिशत) की वृद्धि पायी गयी जबिक 1974 में 283.4 करोड़ रुपयो (38 2 प्रतिशत) की वृद्धि पायी गयी थी । बैंकों के व्यय की कृति मे योगदान करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक 'जमाराशियों और उधारो पर दिया गया ब्याज' है। 1975 में इसमें 164.7 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1974 के दौरान उसमें 187.3 करोड़ रुपयों की बृद्धि हुई थी। व्यय की एक मन्य प्रमुख सद ग्रथीत बेलन, भर्त्त, भविष्य निधि भौर बोनस/अनुप्रह भुगतान में 1971 में हुई 79.5 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले 68.9 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई।

# स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया

239. स्टेट बैंक प्रांफ़ इंडिया की कुल प्रांय में जहां 1974 में 74 7 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी वहां 1975 में 75.3 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी वहां 1975 में 75.3 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । स्टेट बैंक प्रांफ़ इंडिया के कुल व्यय में 1974 में हुई 74.2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वरूप स्टेट बैंक ग्रॉफ़ इंडिया की लाभ गणि 1975 में 6.5 करोड़ रुपयों थी जो 1.9 करोड़ रुपयों की उल्लेखनीय वृद्धि की द्योतक थी जबकि 1974 में उसमें केंबल 49 लाखा रुपयों की वृद्धि हुई थी । 1975 में हुए लाभ में से स्टेट बैंक ने 5 करोड़ रुपयों की राशि प्रारक्षित निधि में मंतरित की भीर शेयर-धारियों को लाभीण मृदा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपयों की अवबस्था की।

# स्टेंट बंक ग्रांफ इण्डिया के सहायक बैंक

240 स्टेट बैंक झांफ़ इंडिया के मान सहायक बैंको की शाय में 1974 में हुई 18.2 करोड़ रुपयों की वृद्धि की नुलना में 1975 में 17.7 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी। 1975 के दौरान उनके कुल क्यय में 1974 (18.1 करोड़ रुपये) की तुलना में थोड़ी सी वृद्धि (17.4 करोड़ रुपये) हुई । इसके परिणामस्वरूप उनकी लाभ राशि 1974 के 61 लाख रुपये से बढ़कर 1975 में 92 लाख रुपये हो गयी। 1975 की प्रपनी लाभ राणि में से इन बैंकों ने पिछले वर्ष के 49 लाख रुपयों के मुकाबले 61 लाख रुपये प्रारक्तित निश्चियों में स्नानिन किये सीर स्टेट बैंक को लाभांश प्रदा करने के लिए 1974 के 12 लाख रुपयों की तुलना में 31 लाख रुपयों की ब्यवस्था की।

### राष्ट्रीयशत वैक

241. 1975 के बौराम 14 राष्ट्रीयक्कृत बैंकों की कुल आय 852.3 करोड़ भपये थी मर्थात् उसमे 169.7 करोड़ रुपयो (24 8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1974 में उसमें 193.8 करोड़ रुपयों (39.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । 1975 के दौरान बाय में हुई प्रक्रिकांश वृद्धि 'म्याज श्रौर बहुं' से हुई जिसमें 1974 की 171.4 करोड़ रुपयों (39.9 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 159.2 करोड़ रूपयों (26.5 प्रतिभात) की वृद्धि पायी गयी । 1975 में इन बैकों के कुल व्यय की राणि बढकर 164.9 करोड़ रुपये (24.5 प्रतिशत) हो गयी जबकि 1974 में उसमें 191.2 करोड़ रुपयो (39.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । इत वैंकों की रुपय राशि की दो महत्वपूर्ण भदों ग्रर्थात, 'जमाराणियों क्रौर उधारो पर श्रदा किये गये व्याज' ग्रौर 'वेतन, भत्तो, भविष्यनिधि तथा कोनस/ब्रनुग्रह भुगतान ब्रादि' में भालोच्य वर्ष के दौरान कमशः 107.2 करोड रुपयों और 43.0 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1974 में उनमे क्रमण: 130.9 करोड़ रुपयो ग्रीर 48 7 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी । म्राय मौर व्यय की इन प्रवृत्तियों के प्रभाव स्वरूप 1975 में 14 राष्ट्रीयकृत बैको की लाभ राणि में 4 9 करोड़ रुपयो की वृद्धि पायी गयी जनकि 1974 में यह वृद्धि 2.7 करोड़ रुपये थी।

242 प्रपती लाभ राणि में से 14 राष्ट्रीयक्वत बैको ने सांविधिक प्रारक्षित निधियों से 9 2 करोड़ रुपये थ्रौर सरकार को बैकिंग कपनी (उपक्रमों का ग्रमिग्रहण और ग्रतरण) श्रधिनियम, 1970 की धारा 10(7) के मतर्गत 4.3 करोड़ रुपये ग्रंतरित किये। 1975 के दौरान भारत सरकार को ग्रतरित की गयी ग्रधिगोय राणि इन बैकों के ग्रभिग्रहण के लिए ग्रदा की गयी कुल क्षतिपूर्ति राणि का 5.0 प्रनिगत थी जबकि 1974 में यह राणि 4.5 प्रतिशत थी।

# भ्रत्य भारतीय भ्रनुसूचित वाणिज्य वंक

243. गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे 25 भारतीय प्रनुसूबित वाणिज्य बैको, जिनमें से प्रत्येक की जमाराशि 10 करोड़ रुपये या उससे मिश्विक है, के कार्य परिणामों से उनकी लाभ राणि के स्नर में थोड़ी सी बृद्धि परिलक्षित हुई । 1975 के बौरान इन बैकों की कुल माय में 37 8 करोड़ रुपयों (37.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 139 3 करोड़ रुपये हो गयी नथा व्यय में 37 5 करोड़ रुपयों (38 0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई प्रौर वह बढ़कर 136.1 करोड़ रुपये हो गया । इसके फलस्वरूप इन बैकों की लाभ राणि 3.2 करोड़ रुपये हो गयी जबिक 1974 में उक्त लाभ राणि 2.9 करोड़ रुपये थी । 1975 के बौरान 3.2 करोड़ रुपयों की लाभ राणि में से इन बैकों ने 1 2 करोड़ रुपये माविधिक प्रारक्षित निधियों में प्रौर 1.0 करोड़ रुपये प्रत्य प्रारक्षित निधियों में प्रतिरत किये।

### विवेशी बैक

244. 1975 के दौरान 12 विवेशी बैकों की झाय में 14.5 करोड़ रूपयों या 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई भौर उनके क्यय में 15.5 करोड़ रूपयों या 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वस्त्र 1975 के दौरान विवेशी बैकों की 5.3 करोड़ रूपयों की लाभ राशि में 1 0 करोड़ रूपयों (16.2 प्रतिशत) की गिरावट पायी गयी अविक 1974 में उसमें 2.1 करोड़ रूपयों (30 प्रतिशत) की मृद्धि हुई की।

### समितियाँ और कार्यकारी अल

245. उपर्युक्त समितियो झौर कार्यकारी दलो/श्रक्ययन दलो के झलावा झालोक्य वर्ष के दौरान रिजर्थ बैक/सरकार ने मिम्नलिखिन समितियो और श्रक्ययम/कार्यकारी दलो का गठन किया: ---

# वण्डल्बकप स्थाज वरों श्रौर सेवा शुस्कों के संबंध में समिति

2 16. 12 मार्च, 1976 को वाणिज्य वैको के मुख्य कार्यपालकों के साथ विचार विसर्ण कर रिखर्व बैंक ने भारतीय बैंक सब के प्र**टबक्श के**  परामर्श से दंडस्वरूप अयाज दरी भीर सेवा शुस्कों के संबंध में एक समिति का गठम किया । उस समिति ने श्रश्रैंस 1976 में श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । प्रथमी रिपोर्ट में समिति ने यह सिफारिश की है कि दण्ड-स्वरूप ब्याज दरो की प्रणाली को बैंको की ब्याज दर नीति का एक तर्कसंगत भाग तब नक मानना पड़ेगा जब नक उसे चयनात्मक रूप से ग्रीर ग्रलग-घलग संदर्भों में लाग किया जाए । दण्डस्वरूप ब्याज दरों को धामदनी में वृद्धि करने वाले उपाय के रूप में नहीं बल्कि ऋणकर्नाधीं के बीच प्रनगासन लाने वाले साधन के रूप से मानना चाहिए । बैंक द्वारा निम्नलिखित मामलों में दण्डम्बरूप न्याज वरे लगाया जाना भौचित्य-पूर्ण होगा (1) ऋणों की दोषपूर्ण चकौती, (2) नकदी ऋण लेखा मे पायी जाने वाली श्रनियमितताएं, (3) स्टाक संबंधी विवरण श्रौर भन्य विलीय श्रांकडे प्रस्तुत स करना, (4) उधार दस्तावेजो में चक, (5) निर्धारित तारीच पर मांग/मीयादी विनिधय हेडियों का ग्रणोधन/ग्रस्वीकृति ग्रीर या (६) ग्रतिरिक्त चालू ग्रास्तियां । समिति ने सिफारिश की है कि मिप्रिमों पर लागू सामान्य देरों के ऊपर । प्रतिशत से लेकर 2.5 प्रतिशत तक की दंडस्वरूप ब्याज दरे लगायी जा सकती है; किन्तु किसी भी परिस्थिति में वे रिजर्व बैक द्वारा श्रक्तिमों पर निर्धारित उच्चतम सीमाओं से 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । जहां तक ऋष लेखों पर लिये जाने वाले सेवा शुल्कों का संबंध है, समिति ने यह अनुभव किया है कि बैको द्वारा उधारकतिथी से गोवाम रक्षक के बेनन, कानुनी शुस्कों ग्रीर मुद्राक शुस्कों भावि के सबंध में किये गये वास्तविक फुटकर बाचों की बसूली किये जाने पर कोई भापत्ति नही हो सकती। ग्रन्य सेवा शुरुको के प्रश्न पर प्रभी भी समिति द्वारा जांच चल रही है तथा जब तक समिति घपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती तब तक किसी भी बैंक को रिजर्व बैक द्वारा ब्याज बरो की उच्चतम मीमा निर्धारित किये जाने के पूर्व विद्यमान क्षेत्रा शुरुको को बढ़ाना नही चाहिए । बैक ने इन सिफारियों को स्वीकार कर लिया है सीर बैकों को उचित मार्गदर्शी सिद्धात जारी कर दिये है।

### बैंकों की परिचालन क्षमता ग्रौर लाभप्रवता के संबंध में कार्यकारी उल

217. रिजर्ब बैक द्वारा भन्नैल 1976 में बैकों की परिचलन असता भीर लाभप्रदता के मंगंध में नियुक्त किये गये कार्यकारी कल से कहा गया है कि बह (i) मलग•मलग बैको के कार्य के मल्याकन के लिए व्यावहारिक ग्रौर वास्तविक कसौटी का मुझाव दे, (ii) विभिन्न बैंकिंग सेवाफ्रों की लागत के निर्धारण के लिए प्राधार निश्चित करें, (iii) प्रारंभ किये गये विभिन्न कार्यों के मामले में ग्रौसत लागत भीर भाय के भन्मान प्रवान करने के लिए एक व्यवस्थित सब्धिए की योजना बनाये धीर उसे कार्यान्वित करे, (iv) बैको के ग्राहको को प्रदान की गयी सेवाध्रो की मुख्यन नीति के सबध में मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये, (V) वैंकिंग अर्च पर नियन्नण, बैको की परिचालन क्षमता, उत्पादकता भौर लाभप्रदता में सुधार के लिए ग्रांतरिकत प्रणालियो घौर कियाविभियो की सिफारिण करेग्रीर (vi) खर्च नियक्षण, सेवा मुल्कों के भौचित्यीकरण और काखाओं की लाभप्रदता के विशंतपण के लिए उचिन तरीके निर्धारित करने के लिए मानवड प्रस्तृत करने के निभिक्त मलग-मलग बैंको द्वारा प्रारभ किये जाने वाले लागत संबंधी भाष्ययनों के स्वरूप सुशाए ।

# बैंकों की प्राहक सेवा के संबंध में कार्यकारी दल

248. बैकों की ग्राहक सेवा के संबंध में भारत सरकार द्वारा नियुक्त ग्रह्मयन दल ने बैकों के जटिल सेवा केतों पर प्रपत्नी ग्रतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । देख ने ग्राहक सेवा के लिए निम्नलिखिन क्षेत्रों को जिटल बताया है : (i) जमा लेखों, प्रेषण ग्रीर वसूर्ला, चैकों की भनाई, रसीर्दे आगी करना, क्षेत्रों के विवरण, ग्राप्टों के निर्गम ग्रीर भूनाई सहित चैकों ग्रीर हंडियों की वसूर्ला ग्रीर प्रेगण, (ii) ऋण ग्रीर

(iii) कर्मनारियों का कला । भारत सरकार ने बल की प्रमुख सिफा-रिणे स्वीकार कर ली है और बैकों को उन्हें पार्यान्वित करने के लिए कहा है । जिन अधिकाश सिफारिणों पर विशिष्ट और तत्काल कार-वाई की अवश्यकता है वे बैकों द्वारा कार्यान्वित की गयी है । जिन अस्य सिफारिशों पर सरकार/रिजर्ब बैंक की थोर से वैधानिक कारवाई/ उपाय किये जाने की आवश्यकता है उन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

# ऋण लेखों के अन्तरण से संबंधित समिति

249. बहे ऋण लेखां के लिए बैंको के बीच घस्वस्थ प्रतियोगिता की रोकने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 15 मार्च 1976 को ऋण लेखां के अन्नरण के संबंध में एक समिति का गठन किया । समिति से कहा गया कि वह बैंकों के बीच ऋण लेखों के अंतरण के विनियमन के लिए मानक निर्धारित करे ताकि इस मामले में परस्पर स्वीकार्य प्रणाली बनायी जा सके ।

250. रिक्व श्रेक को प्रस्तुन की गयी अपनी रिगोर्ट में समिति ने मुझाव दिया है कि प्राहकों की वास्नविक शिकायसों पर विचार करने के लिए प्रत्येक बैंक में एक उच्च स्नरीय समिति स्थापित की जाए। लेखों का प्रधिकार में लेने के लिए समिति ने जिस कार्य पद्धति का सुझाथ दिया है उसमें हस्नानरक और हस्तानरी श्रेंकों के श्रीच सनाह-मशिवरों की व्यवस्था है। उनत कार्यपद्धित में इस बात की सुरक्षा प्रवान करने की भी व्यवस्था है जिससे यह सुनिध्चित किया जा सके कि विचीय अनुशासन में बचने के लिए ऋणकर्ता कही लेखों का अंतरण तो नहीं करने। समिति द्वारा जिस कार्यपद्धित की सिफारिश की गयी है उसमें हस्नांतरी बैंक व्याज वर में रियायत नहीं है सकेंगा। इसकें साथ रिवर्ष श्रैक के हस्तक्षिप के कारण बैंक अनुचित कारणों से लेखों के अंतरण में क्कावट नहीं डाल सकेंगे। रिजर्ष श्रैकों को कुछ मार्गवर्शी सिद्धान जारी किये गयी है और इस मंबंध में श्रैकों को कुछ मार्गवर्शी सिद्धान जारी किये गयी है।

### गृह निर्माण विस्त के संबंध में कार्यकारी बल

251 7 मई, 1976 को रिजर्ब बैंक के गवर्नन ने यह घोषणा की कि गृह निर्माण योजनाओं के लिए बिनीय सहायता प्रदान करने के सदर्भ में बैंकिंग प्रणाली की भृमिका की जाब करने के लिए जल्बी ही एक कार्यकारी दल गठिन किया आएगा । कार्यकारी दल द्वारा इस विषय पर गहराई से प्रध्ययन करना प्रभी बाकी है धौर बीम-मूर्त्रीय प्राधिक कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के कमजोर बर्गों के लिए गृह निर्माण की योजना को महत्व दिया गया है । अत. रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को कुछ प्रस्थायी मार्गदर्शी सिद्धान जारी किये है । बैंकों की बित्तीय सहायना के लिए पात्र गृह निर्माण योजनाम् में ग्रामीण गृह निर्माण योजनाएं, अनुसूष्टिन जातियों और अनुसूष्टिन जनजातियों के लिए पात्र कार्यकाएं, अनुसूष्टिन जातियों और अनुसूष्टिन जनजातियों के लिए पात्र गृह निर्माण योजनाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अधीन परिवार नियोजन विकित्मालय और ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए ग्राहरी गृह निर्माण योजनाएं, शामिल है।

252. बैंकों को यह धूचिन किया गया है कि प्रस्थेक गृह निर्माण परियोजना की लागन के अधिकांश भाग का विन्तयोषण येक थित से इतर साधनों द्वार। किया जाना चाहिए और वैक ऋण ऐसे साधनों का केवल अनुपूरक होना चाहिए। बैंक ऋण सामान्यत प्रत्येक परियोजना की कुल लागन के 40 प्रतिणत से अधिक नहीं होना चाहिए और इन याजनाओं में लाभान्वित होने वालों को प्रदान किये जाने बाले प्रत्यक्ष ऋणों के मामले में व्यक्तिगन ऋण प्रत्येक चाल/अर की कुल लागत के 80 प्रतिणत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बैंकों को

सूचित किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जमजातियों के लिए बनायी गयी श्रांबास योजनाओं और छात्रावासों के
लिए प्रदान किये जाने बाले ऋणों की ब्याज दरे धिमेदक ब्याज दर
योजना के अन्तर्गन निर्धारित दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए । अन्य
वर्गों के लिए बनायी गयी आवास योजनाओं के मामले में ब्याज दर
अस कार्य के लिए प्रदत्त प्राथमिकता के अनुसार सामान्य होनी चाहिए।
बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त ऋणो पर न्युनतम ब्याज दर
संबंधी निर्देश लागू नहीं होगा।

### ऋण गारंटी निगम भौर जमा बीमा निगम

253. ग्रंत में भानोच्य वर्ष के दौरान भारतीय ऋण गारंटी निगम तथा जमा बीमा निगम की गतिविधिया की संक्षेप में समीक्षा की जाएगी।

# भारतीय ऋण गारंदी निगम

254 1975 के दौरान ऋण गारंटी निगम की तीन योजनाम्रों के ग्रधीन गारंटीकृत प्रप्रिमी में ग्रभूतपूर्व वृद्धि हुई । गारटी यीजनाम्रो के मधीन ग्राने वाले बैकों, राज्य विनीय निगमों ग्रीर सेवा सहकारी समितियां द्वारा छोटे ऋणकर्तात्रों को प्रदान किये गये कुल ऋणो स्रौर ब्रन्य ऋण सुविधात्रों की राणि दिसम्बर 1975 के श्रंतिम णुक्रवार को 799.6 करोड़ रुपये थी अविकि एक वर्ष पूर्व उक्त राशि 529.6 करोड़ रुपये थी । इसमें से अधिकांश रागि (796 1 करोड़ रुपये) केवल लागु ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिम राशि (²⁶) थी इस योजना के ग्रन्तर्गत प्रदन कुल ग्रग्निमो मे से केवल क्रुयकों भ्रौर काण्नकारों को प्रवस्त राशि 538.7 करोड़ क्यये थी ; इसके उपरांत परिवहन चालक (104.8 करोड़ रुपये), व्यापारी (80.5 करोड रुपये) और ब्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति (40.7 करोड़ क्पत्रे) भाने हैं । दो भ्रन्य योजनाभी ग्रयात् वित्तीय निगम गारंटी योजना और मेवा महकारी गारंटी योजना के अन्तर्गत गारंटीकृत श्रमिमों की राणि कमश $\cdot$  2.6 करोड़ रुपये  $(^{27})$  और 0.9 करोड़ रुपये (²⁸) थी । ऋष्ण गारंटी निगम को अप्रैल 1976 के स्रंत तक कूल 127 5 लाख रुपयों के दावों के 3,497 मावेदनपत्र प्राप्त हुए; इनमें से क्रुपको और काश्सकारों के ही 2,314 वाबे थे जिनकी राशि 84.8 लाख रुपये थी; इसके उपरांत 25.0 लाख रुपयों के लिए परिवहन चालकों के 212 वार्व थे । अप्रैल 1976 के अंत नक प्राप्त कुल दावों में से 88 लाख रुपयों के 2,272 दावों के बारे में ऋण संस्थाओं को प्रधिसूचित कर दिया गया: 13.0 लाख रुपयों की जुल राशि के 514 दावों को निपटा दिया गया, 4.3 लाख रुपयों के 111 दावों को ग्रस्कीकार कर दिया गया भीर 3.3 लाख रुपयों के 159 दावे किमी न किमी कारण से ऋष्ण संस्थायों ने स्वयंवापस लेलिये थे। शेष क्षाबो की निगम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी । निगम वाबों से संबंधित प्रावेदनपत्नों को निपटाने की वर्तमान कियाविधि की समीक्षा कर रहा है ताकि भविष्य मे वावों को प्रधिक जल्दी निपटाया भामके।

255. निगम ने ऋणकर्ताओं के कुछ बगों को ऋण सस्पामों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण मुबिधाओं के बारे में उन ऋण संस्थामों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुरक्षा के लिए निर्धारित शरों को और उदार बना दिया है। मनः 1 जनवरी 1976 से पाल ऋण सुविधाओं की उच्चतम सीमा को परिवहन चालकों के लिए 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपय, उर्वरकों भीर खनिज तेलों से मिस्न दूसरी बस्तुमों के व्यापारियों के लिए वाचिक बिकी से प्राप्त राशि की उच्चतम सीमा को 1 लाख रुपये में बढ़ाकर 2 लाख रुपये ग्रीर उर्वरकों उच्चतम सीमा को 1 लाख रुपये में बढ़ाकर 2 लाख रुपये ग्रीर उर्वरकों

भीर खनिज तेलों के व्यापारियों के संवर्ष में 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही दावों के सदर्भ में निगम की देवता को चूक की राशा के 75 प्रतिशत या रू० 37,500 इनमें से जो भी कम हो, से बढ़ाकर चूक की राशा का 75 प्रतिशत या रू० 30,000 इनमें से जो भी कम हो, कर दिया गया। मालोच्य वर्ष के दौरान स्थापित क्षेत्रीय मामीण बैंको को भी निगम की ऋण गारटी योजनाधों में शामिल हाने के लिए पान्न बना दिया गया। मब तक तीन क्षेत्रीय मामीण बैंको ने मावश्यक करार निणादित किये हैं।

### जमा बीमा निगम (20)

256. म(लोच्य वर्ष के दौरान पृत्तीचन वैक लि०, के साथ गौहारी। बैंक लि०, का समामेलन भीर बेलगांव बैक लि०, की देयताओं भीर आस्तियों का यूनियन बैक भाफ इंडिया को मंतरण किये जाने के फल-स्वरूप बीमाकृत बैंकों की संख्या 81 से कम होकर 79 हो गयी । इस वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक म्राधिनयम, 1976 के अस्तर्गत माध्य प्रवेम, बिहार, हरियाणा, जम्मू भीर काभमीर, कर्माटक, मध्य प्रवेम, प्रदेम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भीर पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थापित 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को बीमाकृत बैंको के स्प में पंजीकृत किया गया।

257 त्रिपुरा राज्य के एक सहकारी बैंक को मिलाकर जिसके लिए यह योजना लागू की गई, बीमाक्कत सहकारी बैंको की संख्या 513 से बढ़कर 536 हो गयी है। अब इस सोजना के अधीन आंध्र प्रवेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और काश्मीर, केरल और क्षिपुरा राज्यों तथा दिल्ली, गोवा, दमण और दीव एवं पाण्डिचेरी के संबधासित क्षेत्रों के सहकारी बैंक आने है। गेप राज्यों/संबधासित क्षेत्रों के लिए इस योजना को लागू करने के प्रण्न पर सिक्षय रूप से विचार किया जा रहा है।

258. बैंकों के जमाकर्ताओं को अधिकाधिक मुरक्षा प्रदान करने के जुड़ेस्य से जमा बीमा निगम ने बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत बैंकों में जमा की गयी राणि की बीमा रक्षा सीमा को 1 जुलाई 1976 में प्रति जमाकर्ता 10,000 रुपयों से बढ़ाकर 20.000 रुपये कर विया है। प्रति जमाकर्ता 10,000 रुपयों की पिछली सीमा 1 अप्रैल 1970 से असल में आयी थी।

### III. सहकारी वैक व्यवसाय की गतिविधियां

259. सहकारी बैंक व्यवसाय के क्षेत्र में प्रमुख त्रोर इस बात पर विया जाता रहा कि सहकारिया के विकास में विद्यमान क्षेत्रीय प्रसंतुलन को ग्रीर ऋण सबंधी वर्तमान खाई को कम कर विया जाए। प्राथमिक इवि ऋण समितियों को सक्षम/अमता की संभावनायुक्त समितियों के कप में पुनर्गठित कर और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों से कृषक सेवा समिति तथा बहे धाकारवाली बहुउदेश्यीय समिति जैसी समितियों को गठित कर उक्त दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयाम किया गया। जिल राज्यों में सहकारी गतिविधियों प्रव तक कमजोर रही है, उत राज्यों में कन्त्रीय सहकारी बैको का पुनर्निर्माण करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए उपाय करने के भनावा समुदाय के कमजोर वर्गों की श्रावश्यकतान्नों की पूर्ति करने के निमित्त सहकारी गतिविधि को पुनर्विस्थत करने पर भी विशेष जोर विया गया। श्रीस सुत्रीय श्राविक कार्यक्रम के कारण इन उद्देश्यों की शीष्ट्रतापूर्वक पूर्ति करने की तरकाल ग्रावश्यकता हो गयी है।

⁽²⁶⁾ ये आकड़े उक्त योजना में सम्मिलन 75 बैंकों में से 74 बैंकों के हैं।

⁽²⁷⁾ ये आंकड़े 18 विलिय निगमों में से 11 विलिय दिगमों के हैं।

⁽²⁸⁾ ये आंकड़े कंबल 6 वाणिज्य बैंको के हैं।

^{(29) &}quot;गैर बैकिंग कम्पनियों के वित्त" से सबस्थित खण्ड इस रियोर्ट के ग्रीकोंगिक वित्त की गणिविधिया",शीर्षक के भाग IV में दिया गया है।

# बोस सुलीय कार्यकम

260. बीम मूलीय आर्थिक कार्यंक्रम के कार्यान्वयन के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जाता रहा । चूकि श्रामीण ऋण ग्रम्तता का परिस्मापन करने के लिए किये गये उपायों के परिणामस्वरूप संभवतः साहकारों जैसे संयेस्तर स्त्रोतों से ऋण उपलब्ध न होने की संभावता थी भतः समितियों को यह अनुमित दी गयी कि वे कमजोर धर्गों के सदस्यों को उपभोग ऋण प्रदान करें । भ्रलग-भ्रलग व्यक्ति सीधे केन्द्रीय सहकारी वैकों से या भ्रपनी समितियों से सोने या चांदी के आभूषणों की जमानन पर भी ऋण प्राप्त कर सके । रिजर्ष बैंक को दीर्घंकालीन प्रवर्तन निधि से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को णेयर पंजी में भ्रधिदान करने ये निमित्त उनकी पालता के मामले में कतिपय रियायसे की गयी है । इनके कारण वे भ्रपनी स्वाधिकृत निधियों में भ्रौर उपभोग के प्रयोजनों के लिए अपने द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि कर सकेंगे।

261, इनके श्रलावा बीम सूत्रीय कार्यक्रम के श्रंतर्गंत उपभोक्ता सहकारी समितियों को नियंत्रित कपड़े श्रादि श्रत्यावय्यक वस्तुश्रों को उचित मूख्यों पर पृति करने के निमित्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता महासंघ, थोक सहकारी समितियां श्रीर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी सिनित्या जहां णहरी क्षेत्रों को सेवा प्रदान करेंगी वहां पुनर्गठित प्राथमिक छृपि ऋण समितियां, कृषक सेवा समितियां श्रीर बड़े श्राकारवाली बहु- उद्देक्तीय समितिया ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कार्य करेगी। बैंक की विश्वकालीन प्रवर्तन निश्च से उपलब्ध ६० 10,000 की. नियमित सीमा के श्रलावा श्रांतरिक्त श्रेयर पूंजीयत श्रामदान के लिए इन समितियों को पाल बनाया गया। इसके श्रलावा रिजर्व बैंक ने यह भी स्वीकार

किया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निधियों से इस प्रयोजन के निमित्त इन सिमितियों का उनकी निधियों के दैध प्रभार के प्राधार पर कित-पोषण करने प्रौर उपयुक्त उद्देग्यों के लिए ध्रिक्षिक माला में विसीय महायमा प्रदान करने पर विचार किया जाए । इस सदर्भ में शहरी उपभोक्ता स्टोगों की बढ़ती हुई कार्यकारी पूंजीगत धावण्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त बैंक ने यह स्वीकार किया कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा उनका वित्तपोषण किया जाए । इसके अलावा यह मुनिश्चित करने के लिये कि वाण्यय और सहकारी बैंकों से इस कार्य के लिए कार्यकारी पंजीगत वित्त ध्रिक्षिक माला में उपलब्ध हो, केन्द्रीय सरकार की गारंटी योजना जहां प्रज तक राष्ट्रीय भौर राज्य स्तरीय सहकारी उपभोक्ता महासंघों तथा थोक स्टोरों के लिए लागू थी वहां उसे उवार धनाकर धव बड़ी माला में क्यवित्रय करने वाली संतोषजनक ढंग से कार्यरत प्राथमिक समितियों को उसके धनर्गन लाया गया।

# सहकारी ऋण नीति

262. 1975-76 के बौरान सहकारी ऋण नीति का प्रमुख उद्देश्य पहले की तरह यही बना रहा कि मुद्रागत अनुशासन की रूपरेखा के भीतर विकास करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों की पृति की जाए । इस उद्देश्य के लिए सहकारी संस्थाओं को ऋषि, कृटीर और लघु उद्योगों का प्रमुख रूप से अनुपूरक वित्त पोषण करने के लिए अल्पावधि, मध्यावधि और वीर्षाविधि वित्त तर्क संगत मानदंडों पर प्रदान किया गया । 1974-75 में समाप्त हुए तीन वर्षों की अवधि के दौरान सहकारी ऋण गतिविधियों की प्रगति तथा 1974-75 और 1975-76 में सहकारी संस्थाओं को प्राप्त रिजर्व वैंक के ऋण का समग्र जिल सारणी 27 और 28 में विधे गये आंकड़ों से मिल सकता है।

भारणी 27 : भारतीय सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति

(राणि करोड़ रुपयों में)

संस्थाध्यो का प्रकार	सह•	नारी <b>वर्ष</b>	
	1972-73	1973-74	1974-75*
1	2	3	4
(क) राज्य सहकारी वैक			<u>.</u>
(i) सं <del>ग्र</del> ्या	26	26	26
(ii) स्वाधिकृत निर्धियां	117	129	142
(iii) जमाराणियां	406	489	546
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋण	246	236	377
(क) उनमें से म्रल्पावधि क्रुणि ऋण	155	154	212
(v) कार्यकारी पूंजी	849	942	1187
(vi) अभिरीकिये गये ऋष	1135	1162	1244
(vii) अकाया ऋष	635	706	720
(क) उनमें से प्रत्याविध कृषि ऋण	367	400	381
(viii) (viiक) में (ivक) का प्रतिशत	42	39	5 5
(भ्रा) केन्द्रीय सहकारी वैक			
(i) <del>संख्</del> या	344	341	341
(ii) स्वाधिकृत निधियां	254	281	314
(iii) जमाराणिया	647	719	802
(iv) भारतीय रिजर्व बैक/शिखर जैंक से लिए गए ऋ <b>ण</b>	398	448	533
(v) कार्यकारी पूंजी	1412	1595	1838
(vi) जारी किये गये ऋण	1246	1249	1520

1	2	3	4
(vii) बकाया ऋण	1028	1163	1344
(ग) राज्य/केन्द्रीय चूमि विकास बैंक			
<b>ृ(i) संख्</b> या	19	19	19
(ii) स्वाधिकृत निधियां]	98	118	134
(iii) वकाया डिर्सेचर	1015	1157	1254
(iv) कार्यकारी पूंजी	1202	1368	1502
(v) जारी किये गये ऋण	171	147	184
(vi) बकाया ऋण	849	914	993
(ध) प्रावमिक कृषि ऋष समितियाँ			
(i) संख्या (हजारों में)	155	154	153
(ii) मदस्य (हजारों में)	33528	34956	35851
(iii) स्थाधि <b>कृत निधियां</b>	323	353	391
(iv) जमा राशियां	84	89	97
(v) उ <b>घार</b>	858	918	1035
(vi) जारी किये गये ऋष	776	762	889
(vii) बकायाऋष	979	1055	1165

***ग्र**नंतिम

सारणी 28 : सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक द्वारा विये गये ऋण-1974-75 सौर 1975-76

(राणि करोड़ रुपया में)

			1974-75 (9	नुसाई⊸जून)			1975-76 (	गुलाईजून)	
		मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राणि	चुकायी गयी राणि	<b>ब</b> काया राशि	मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राणि	चुकायी गयी राशि	बकाया राशि
<u>I</u>	ब्रह्यावधि								
(i)	कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलाप (वैक								
	दर से 0.5 प्रतिणत कम दर पर)	489.52	811,79	751.15	212.15		899,73	965, 28	146.60
(ii)	रूई भीर कपास को छोड़कर ध फमलों का विपणन	न्य ) } 40.30	$\begin{cases} 18.13 \end{cases}$	19.58	[0.49]	37.37		0.49	<b>मृष्</b> नही
(iii)	रूई झौर कपास का विपणन ²	J	46.94	37.54	ر 10.25		21.89	31.97	0.17
(iv)	उर्वरकों की खरीव ग्रौर वितरण								
	(बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक दर पर)	8 28.20	22.45	3.65	18.80	47.05	62.92	61 81	19.91
(v)	हथकरये से अनने वाली वस्तुमों का उत्पादन भौर विषणन								
	(बैंक दर से 1.5 प्रतिणत कम दर पर)	15 69	29.43	23.37	11.09	20,03	34.25	33.94	11.40
(vi)	भ्रम्य कुटीर भीर लघु उद्योगों का								
	द <del>ित</del> पोषण⁴	2.52	1.33	0.28	1.33	4.75	2.53	1.55	2.31
(vii)	भाग की खरीव धौर विकी (बैंक	ī							
	वर पर)⁴	0. <b>6</b> 5	0 47	0.43	0.04	0.65	0,13	0,11	0,06
(viii)	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम								
	को ऋण (बैंक दर पर)	15,00	_	11,60	-	15.00	1.70	<del></del>	1.70
(ix)	भीनी के बंधक पर दिया गया ऋण	22.00	67.12	45.12	22.00	14.50	10.50	32.50	कुछ नहीं

छूट योजना के भनुसार ती गयी 1 5 प्रतिशत की छट के भ्रधीन 1973-74 से बैंक दर से 0.5 प्रतिशत कम दर पर; परन्तु धारा 17(4)(क) के भ्रधीन तैंक दर से 2 प्रतिशत कम दर जारी रही । 1975-76 से तैंक दर से 2 प्रतिशत कम दर पर; किन्तु संयोजन कार्यक्रम के भनुसार 1.5 प्रतिशत के भ्रतिरिक्त ब्याज की वसुनी हो ।

कर्म की एकाधिकार वसूली को मिलाकर।

¹⁹⁷² के पहले उर्थरकों की खरीद और वितरण के लिए रिजर्ब बैंक द्वारा बैंक वर पर विलीय सहायता दी जानी थी। परन्तु ब्यांभ दर को वाणिज्य बैंकों को ऋण संबंधी ब्याज दरों के धनुरूप धनाने के उद्देश्य से जनवरी 1972 से बढ़ाकर बैंक दर से 2 प्रतिशत घांधिक बना दिया गया। इस दर को पून 1974 को लिए बढ़ाकर बैंक दर से 3 प्रतिशत घांधिक बना दिया गया। झांकड़े 1974 और 1975 के कैलेण्डर बणों से संबंधित हैं।

[🌯] आंकड़े वित्तीय वर्षों से संबंधित हैं।

सारणी 28 : सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक द्वारा विए गए ऋण 1974-75 झौर 1975-76 (जारी)

(राणि करोड़ रुपयों में)

		1974-75	(जुलाई-जून)			1975-76	(जुलाई~-जून)	
	मजूर की गयी सीमाए	निकाली गयी रामि	चुकामी गयी राणि	बकाया राशि	मंजूर की गयी सोमाएं	निकाली गयी राशि	चुकायी गयी राणि	बकाया राशि
I मध्या <b>व</b> धि		,						
(i) कृषि उद्देश्य (बैंक वर से 1.5 प्रति-								
श्रत <b>कम दर पर</b> )⁵	9.87	4.58	8.83	15,65	11.59	7.18	7.48	15.3
ii) ग्रभावग्रस्त क्षेत्रों में ग्रल्पावधि ऋणों								
को मध्यावधि ऋणों मे परिवर्तित								
करना (बैंक दर से 1.5 प्रतिशत					_			
कम दरपर)	106.92 ⁶	55.03 ⁶	25.36	82.55 ⁶	50.48 ⁶	41.81 ⁶	45.60	78.7
ii) सहकारी चीनी कारखानो/ग्र <b>भि</b> -								
संस्करण समितियों के शेयरों की खरीद(बैंकदरपर) ⁵	0 #0							
,	0.53	0.18	0.34	1.01	3.04		0.38	0.6
] दीर्घावधि								
i) सहकारी ऋष्ण संस्थाओं की पोयर								
पूंजी में ग्रंग दान करने के लिए								
•	8.37	8.3 <b>7</b>	6.37	70.00	13.54	13.52	7.53	75.
ii) क्रुषि पुनर्विस ग्रीर विकास निगम								
को दिय गये ऋष्ण (वार्षिक 4.5	40.00							
प्रतिशत/४.75 प्रतिशत की दर पर) ⁷	40.00	40.00	5.80	88.20	60.00	60.00	9.80	138.

- ग्रांकड़े 1974 भीर 1975 के कैलेण्डर वर्षों से संबंधित है।
- ⁶ प्नड्यंवस्था ग्रौर कार्यक्रम के परिवृत्तन को भिलाकर।
- मितम्बर 1974 से ज्याज दर को अ.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया।

### प्रस्पावधि वित्त

# कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलाप

### रियायती विस

263. 1975-76 के बौरान रिजर्थ मैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलायों के वित्तियायण के लिए बैंक दर से 2 प्रतिशत कम दर पर मल्यावधि ऋष्ण मीमाए (भारतीय रिजर्ब बैंक प्रिंशित्यम की धारा 17(4) (ग) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 17 (2) (ख) /धारा 17(4) (ग) के संतर्गत) प्रदान करने की अपनी नीति जारी रखीं । जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख कियागया था, बैंकों को यह रियायती दर कंबल उसी सीमा तक उपलब्ध थी जिस सीमा तक बैंकों ने रिजर्ब बैंक से लिये जाने वाले उधारों की जमा संचयन से संयोजित करने के कार्यक्रम के अतर्गत प्रत्येक बैंक के लिए ग्रलम प्रलग निर्धारित कुल स्तर के भीतर उधार लिये हो । 1974-75 के दौरान केवल 24 केन्द्रीय सहकारी बैंक इन योजना के अधीन रिजर्ब बैंक से पूरी छूट प्राप्त नहीं कर सके।

264. 1975-76 के दौरान रिजर्ब कैंक द्वारा राज्य सहकारी बैको का कृषि सबंधी कार्यकलायों के बिस्सपोधण के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमा की राशि 1974-75 के 490 करोड़ रुपयों से बढ़कर 612 करोड़ रुपयों हो गयी । मल्पावधि ऋण सीमाध्यों में हुई 122 करोड़ रुपयों की वृद्धि का प्रमुख कारण यह हो सकता है कि 1975-76 के खरीफ धौर रशी दोनों मौसमों में उर्वरको एवं कृषि

के काम ब्रामेवाली श्रन्य ध्रायश्यक मूलभूत वस्तुक्यों की मांग में वृद्धि हुई ध्रौर प्राथमिक ऋण समितियों ने उत्तर प्रदेश में गन्ता संबों के सदस्यों को गन्ते की खेती का वित्तपोषण करने की नयीयोजना प्रारंभ की ।

265. पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिन राज्यों में रधी महत्वपूर्ण मौसम था बहां खरीफ भौर रबी मौसमो के लिए अखग अखग ऋण सीमाएं मंजूर की गयी । 152 केन्द्रीय सहकारी बैकों की ओर से 1975-76 के रबी मौसम के लिए 13 राज्य सहकारी बैकों को ओ अनुपूरक ऋण सीमाएं मंजूर की गयी उनकी कृत राशि 87.4 करोड़ रुपये थी । उत्तर प्रवेश राज्य सहकारी बैक को केवल गन्ने के खेती का वित्तपोषण करने के लिए 28 केन्द्रीय सहकारी बैकों की और में 19.2 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त ऋण सीमाएं भी मंजूर की गयी ।

# मौसमी तत्व

266. 1973 में भमल में लाये गये मौसमी तत्व के मनुणासन के भनुणासन के भनुण सीमा तक परंपरागत विपणन भविध में प्रदान किये गये भि्रमों के भि्रह्मिण भाग की बसूली कर सके । इसके परिणाम-स्वक्ष्प जून 1976 के श्रन्त में विद्यमान उनके बकाया ऋणों के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट भायों । सभी राज्य सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया कि विसी भी केन्द्रीय सहकारी बैंक को 1 भन्नैल 1976 के बाद उसके लिए मंजर की गयी ऋण सीमाओं में से राणि

निकालने की धनुमित तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि संबंधित केन्द्रीय महकारी बैंकों ने सिमितियों से 31 मार्ज, 1976 तक मांग राशियों का निर्दिष्ट प्रतिशत, सामान्यत. 40 प्रतिशत वसूल न कर लिया हो और यह राशि राज्य सहकारी बैंक को धंतरित न कर दी गयी हो। इस उद्देशय के लिए 1 जुलाई, 1975 में 31 मार्ज, 1976 तक की गयी सभी वसूलियों को तथा अल्पाबधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में यदि परिवर्तित कर दिया गया हो तो उन परिवर्तनों को भी यसूली के रूप में स्वीकार किया गया। जहा कही बड़ी माझा में अनुपूरक ऋण सीमाएं मंजूर की गयी, 1 जुलाई, 1976 के बाद अल्पाबधि मीमाछों में से निकाली गयी राशियों को इस प्रकार न्यूनतम वसूली कार्य दारा विनियमित कर देने की आवण्यकता थी।

### फसलों का विपणन

267. 1975-76 के दौरान बैंक ने फसलों के विषणन के लिए बैंक दर से 3 प्रनिशत प्रधिक दर पर प्रस्पावधि ऋण सीमाएं भी मंजूर की । परन्तु इन सीमाग्नों की मंजूरी पर बैंक के चयनारमक ऋण नियंत्रण उपायों के प्रधीन निर्विष्ट णतें लागू की गयी । 1975-76 के दौरान इस प्रकार सज़र की गयी कुल राशि 37.4 करोड़ रुपये थी जबकि 1974-75 में उक्त राशि 40.3 करोड़ रुपये थी । विषणन सीमाग्नों में रिजर्व बैंक के निदेशों के प्रंतर्गत माने वाली रुई मीर कपास के लिये विशेष मीमाग्नों के रूप में दिये गये 1.9 करोड़ रुपये, इन निदेशों के प्रन्तर्गत न प्राने वाली रूई के लिए दिये गये 15.4 करोड़ रुपये ग्रीर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक समिति को महाराष्ट्र सरकार की एकाधिकार बसूली प्रणाली के ग्रंतर्गत रूई ग्रीर कपास के विषणन के विलाप के लिए दिये गये १ विश्व के विषणन के विलाप के लिए दिये गये शिक कि विषण के विलाप के लिए दिये गये निर्मालत थे।

# उर्वरकों का वितरण

268. उर्वरको की खरीद, संग्रहण भीर वितरण के लिए अब कभी वाणिज्य बैक राज्य सहकारी बैकों की पूरी अपेक्षाभों की पृति करने से असमर्थ ये तब रिजर्य बैंक बैंक-दर से 3 प्रतिशत उज्वतर दर पर अस्ताविध ऋण सीमाएं प्रदान करता रहा।

# मौद्योगिक समितियों श्रीर यूनिटों को विसीय सहायता

269. रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को सहकारिता क्षेत्र से बाहर रहने वाल धौद्योगिक यूनिटो धौर बौद्योगिक सहकारी समितियों (धुन-कर सिर्मितियों को छोड़कर) का वित्तपोधण करने के लिए नैक दर पर बित्तीय महायमा प्रदान करता रहा । भालोध्य वर्ष के दौरान 22 जिला केन्द्रीय धौर 13 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की घोर से 4 राज्य सहकारी बैंकों को लगभग 475.5 लाख रुपयों की ऋण सीमाए मंजूर की गयी।

### ग्रवांछित आहरण

270. राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्रल्पाविध कृषि ऋण सीमाधों में से किये जाने वाले प्रवाछित श्राहरणों को 1975-76 के दौरान निरुत्साहिस किया जाना रहा । प्रस्थेक राज्य सहकारी बैंक ग्रन्थ बैंकों के पास जो माग कमा राणि रख सकते हैं उसके लिये उचित उच्चतम सीमाए निर्धारित की गयी भौर जहां इन उच्चतम सीमाभों से ग्रिक राणि रखी गयी वहां रिजर्व बैंक द्वारा दण्डस्वरूप क्याज दरे ली गयीं।

# चयनात्मक ऋण नियंत्रण

271 राज्य भौर केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा कतिपय चुने हुए प्राथिमिक (गहरी) सहकारी बैंकों द्वारा स्ट्री भौर कपास की जमानत पर विए जाने वाले अग्रिमों पर 1974-75 के बौरान लागू किये गये प्रतिबंध मालोच्य वर्ष के दौरान जारी रहे । पिछले वर्ष उक्त प्रतिबंधों के भ्रन्तर्गत लाग्ये गये गुनरान स्थित 14 भौर कर्नाटक स्थित 8 शहरी सहकारी

बैको के प्रलावा गुजरात स्थित 4 प्रीर बैको को उनके घंनर्गन लाया गया ।

#### ऋण प्राधिकरण योजना

### भोक पुंजी

### कार्यकारी पुंजी

273. यह सुनिभिन्नत करने के लिए कि कृष्येतर क्षेत्र को अधिवेक-वर्ण होग से कार्यकारी पंजीगत भग्निम प्रदान न किये जाएं, सभी राज्य ग्रीर केन्द्रीय सहकारी वैंकों को यह सूचित किया गया कि वे किसी एक पार्टी को क्रमणः 100 लाख रुपयो श्रीर 50 लाख रुपयों से श्रीधक द्यग्रिमप्रदान करने से पहले रिजर्वविक का पूर्वप्राधिकरण प्राप्त कर ले। परन्तु तबस्बर 1975 में प्रधिक कामकात्र के समय के प्रारंभ मे रिजर्ब बैंक द्वारा घोषित की गयी सामान्य ऋण नियंत्रण नीति के सदर्भ में उक्त राशिको बढाकर कमण: 200 लाख रुपये ग्रीर 100 लाख रुपये कर दिया गया । ऐसे ऋषों के लिए न्यनतम मर्जिनों श्रीर ब्याज दर के संदर्भ में विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित किये गये । श्रास्रोच्य वर्ष के दौरान 9 राज्य घौर 25 फेन्द्रीय सहकारी बैंकों ने 81 महकारी विप-णन, भ्रभिसंस्करण समितियों तथा उपभोक्ता स्टोरों/समितियों की भ्रोर से 202.4 करोड़ रुपयों की राशि के लिए पूर्व प्राधिकरण की श्रभ्यर्थना की । परन्तु 9 राज्य श्रीर 25 केन्द्रीय सहकारी बकों को 77 सहकारी विषणन, भ्रभिमस्करण भौर उपभोक्ता स्टोरो/ममिनियो की श्रोर से 174.3 करोड़ रुपयों की राशि के लिए प्राधिकरण प्रदान किये गये।

274. राज्य ष्ट्रीर केन्द्रीय सहकारी बैंकीं द्वारा सहकारी चीनी कारखानो को प्रदान किये जाने वाले ऋणों की प्रग्निम श्रदायगियों को केवल गन्ने के उत्पादकों तक भारत मरकार द्वारा निर्धारित माल म्यमतम वरों पर कारखानों द्वारा खरीवे जाने वाले उनके गन्ने के सवर्भ में सीमित करना था । विशेष रूप से महाराष्ट्र मे स्थित कारखानों में गन्ना खरीयने के लिए होने वाली भस्वस्थ प्रतियोगिना को दूर करने तथा कमजोर कारखानों के क्षेत्र से होने वाले गन्ने के दिशान्तरण को कम करने के उद्देश्य से उक्त प्रतिबंध लाग किया गया । सहकारी कीनी कारखानों को चीनी के स्टाकों की जमानत पर भ्रत्याथिध श्रप्रिम प्रवान करने के लिए न्युनतम माजिन को मुक्त बिकी चीनी के सदर्भ में बंधक भीर दिव्हबंधक रखी गयी चीनी के लिए कमण: 25 प्रतिशत ग्रीर 40 प्रतिशत से तथा लेबी चीती के सदर्भ में बंधक ग्रीर एप्टिबधक रखी गयी चीनी के लिए कमण 15 प्रतिशत ग्रीर 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत का एक समान न्यूनतम माजिन कर विया गया । इस उद्देश्य के लिये लेवी चीनी के स्टाकों के लिए लेवी मुख्य पर तथा मुक्त बिकी की चीनी के लिए भरकार द्वारा निर्धारित मूल्य दर या बाजार मृत्य में से जो भी कम हो, उस मृत्य पर मृत्याकन करना था।

# उपमोक्ता स्टोरों का वित्तपोषण

275. बीस सूबीय प्राधिक कार्यश्रम के प्रतगंत ग्रामीरा क्षेत्रों में प्रत्या-वश्यक वस्तुओं भीर नियंत्रित कपड़े के यितरण में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को मौपी गयी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ते उपभोक्ता सहकारी समिनियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित उस योजना के कार्यक्षेत्र को घ्यापक बनाया जिसके ध्रतगंत राज्य सरकारों की उपभोक्ता सहकारी सस्थान्नों की घेयर पूजी को सजबृत बनाने के निमित्त निधियां उपलब्ध करायी गयी थी जिनसे कि वे बैक ऋण पर निर्दिष्ट किये गये मार्जिन की ब्यवस्था कर सकें।

276 केन्द्रीय मरकार ने राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया कि वे उपभोक्ता महकारी संस्थाओं को ऋण सुविधाए प्रदान करने वाले बैकों को गारण्टी प्रदान करें।

277. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित संगोधित योजना को ध्यान में रखते हुए बैंक ने सहकारी समितियों के पंत्रीयकों को यह सूचित किया कि वे राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को इस बाम की ग्रन्मित वें कि योजना के ग्रन्मित ग्राने वाली उपभोक्ता महकारी सम्याग्री का वस्तुग्रीं की जमानत पर 10 प्रतिशत के कम माजित पर इस गर्म पर ऋण सुविधाये दी प्राएं कि राज्य सरकार मूल ऋण की चुकौती ग्रौर ब्याज की ग्रदायगी की पूरी गारटी दे।

278 सितम्बर, 1975 में राज्य गहकारिता मिल्लयों के सम्मेलन में यह सिकारिया की गयी कि जिन गहरी सहकारी बैंकों के पास अति-रिक्त वित्तीय साधन हो वे उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को वित्तपोषण करें। भारत सरकार के परामणें से रिजर्ब बैंक द्वारा इस सदर्भ में की जाने वाली व्यवस्थायों को प्रतिम रूप दिया गया। यद्यपि उपभोक्ता महकारी सम्थाए गहरी बैंकों के सदस्य नही बन सकती, किर भी गहरी बैंकों को यह अनुमति दी गयी हैं कि वे सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा राज्य महकारी समिति प्रधिनयम के सबधित उपबन्धों के प्रतिगंत प्रवस्थ अनुमित में गैर सदस्यों के रूप में उनका वित्तपोषण करें।

# लाबु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना

279. लघु उद्योगों की ऋण गारंटी योजना नवस्बर, 1974 के भन तक केवल 9 राज्य महकारी बैकों, 4 श्रोद्योगिक महकारी बैकों, 59 केन्द्रीय महकारी बैकों और 40 प्राथमिक (शहरी) महकारी बैकों द्वारा ग्वीकार की गयी। भारतीय ऋण गारंटी निगम द्वारा गठित (फरवरी, 1975) कार्यकारी दल ने यह सुझाया था कि मभी पान्न बैकों [25 राज्य गहकारी बैक, 5 श्रोद्योगिक महकारी बैक, 343 केन्द्रीय महकारी बैक श्रीर 134 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैक, 343 को योजना में मम्मिलित होने के लिए ऋण गारटी मंगठन प्रोत्माहित करें । तदनुमार रिजर्व बैक ने केन्द्रीय महकारी बैकों के साथ सीधे तथा महकारी मिनित्यों के पंजीयकों के जिरये उनसे यथा शीघ योजना में सम्मिलित होने का अनुरोध करने के निमित्त कार्रवाई प्रारम की । 30 जून, 1976 तक 9 राज्य महकारी बैक, 68 केन्द्रीय सहकारी बैक, 4 श्रीद्योगिक महकारी बैक श्रीर 57 प्राथमिक शहरी सहकारी बैक श्रावण्यक करार निष्पादिक कर योजना में सम्मिलित हुए।

### नारियल रेशा समितियाँ

280. 1975-76 के विक्तीय वर्ष के दौरात 23 प्राथमिक नारियल रेमा मिनियों का विक्तिपोषण करने के लिए 45 9 लाख रुपयों, 4 केन्द्रीय नारियल रेणा विपणन समितियों के लिए 84 लाख रुपयों भीर 8 निर्माण मिनियों के विक्तिपोषण के लिए 27 लाख रुपयों से युक्त कुल 156 9 लाख रुपयों की ऋण सीमाएं रिजर्व बैंक ब्रारा मंजूर की गयी ।

# रेशम उत्पादकों का वित्तपोवण

281 कर्नाटक में रेशम के उत्पादन के विकास के लिए सघन कार्यक्रम का विक्तपोषण करने के निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित सस्थागत व्यवस्थात्रों में उक्त राज्य के पांच जिलों में 125 से 150 तक की रेणम उत्पादकों की समितियों के गठन/पुनर्गठन की व्यवस्था सम्मि-लित है ताकि वे प्रपने रेणम उत्पादक मदस्यों तथा अत्य कृषक सदस्यो को सभी प्रकार की ऋण सुविधाए (ग्रायीन प्रत्पार्वाध, मध्यावधि भौर दीवविधि) तथा तकर्नाकी सहायसा प्रदान कर सके । परन्तु राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि इस कार्यत्रम के वित्तपोषण के लिए केवल 125 समितिया गटित की जाए । उनमें से 64 समितिया पंजीकृत की गयी थी । रेणम उत्पादकों की 33 मर्मितिया वाणिज्य बैंकों को श्रीर 12 समितियां सहकारी बैंकों को उन्हें ऋण सुविधाएं प्रदान किये जाने के लिए ग्राबंटिन की गयी । कृषि पुर्नावत्त ग्रौर विकास निगम ने भी वाणिज्य बैकों के जरिए कार्यक्रम का विस्तपोषण करनेके लिए मार्गदर्शी सिद्धात बनाये थे । रिजर्ववैंक ने रेशम उत्पादकों की समितियों का वित्तपोषण करने के लिए मैसूर जिला सहकारी बैंक की ग्रोर से कर्नाटक राज्य सहकारी बैक समिति को 17.0 लाख रुपयों की मध्यावधि ऋण सीमा मंजूर की।

#### मध्यावधि वित्त

282 1975-76 के बौरान यह निण्चय किया गया कि 'कटों की खरीद' को राजस्थान के उन मुख्क श्रीर श्रधं मुख्क श्रंचलों में, जहां श्रुवि सबधी कार्यकलापों के लिए बैलों के स्थान पर ऊंटों को प्रयोग में लाया जाता है, स्थित फेन्द्रीय विसीय एशिस्था से मध्यावधि वित्त प्राप्त करने निमित्त धनुमोदिन कृषि उद्देश्य के रूप में माना जाए। यह भी निण्वय किया गया कि महकारी समितिथों के श्रुवकेनर सबस्यों को पणु पालन के लिए दिए जाने वाल मध्यावधि ऋण भारतीय रिजर्थ वैक से पुनविल प्राप्त करने के लिए पात होंगे। अब तक यह मुलिधा केवल श्रुवक सदस्यों को दियें गये ऋणों के मदर्भ में उपलब्ध थी। इसके भ्रवावा बकरी पालन, दुधाक पणु पालन तथा मुर्गी पालन के लिए दिये जाने वाले मध्यावधि ऋणों की जमानन में संवंधित गर्नों को भी उदार बनाया गया।

283 1976 के फैलेण्डर वर्ष के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्ष-कालीन प्रवर्तन) निधि में से मध्याविध कृषि प्रियम प्रवान करने के लिए 20 करोड़ रुपयों का प्रस्थायी आवंटन किया गया ! 1975 के दौरान कृल केवल 11.6 करोड़ रुपयों की मध्याविध ऋण मीमाए मंजूर की गयी । परन्तु राज्य सहकारी बैको द्वारा केवल 7.2 करोड़ रुपया की राशि निकाली गयी, ऋण मीमाआ के उपयोग में कभी आने के कारण निम्न प्रकार थे (क) बैको द्वारा ऋण कार्यक्रम का अधिक अनुमान लगाया गया और (ख) अनिदेय राशिया भारी माला मं थी । विभिन्न राज्य महकारी बैकों को वर्ष 1976 के लिए मंजूर की गयी मध्याविध ऋण मीमाओं की कुल राशि 30 जून, 1976 तक 9.0 कराड़ रुपये थी।

284 1975-76 के सहकारी वर्ष के बौरान 2 राज्य सहकारी बैका को सहकारी चीनी कारखानों श्रीर श्रन्य भ्रभिसस्करण यूनिटों में शियर खरीबने के लिए कुल 3.0 करोड़ रुपयों के मध्यावधि ऋण मजूर किये गये।

### हथकरचा विस

285. रिजर्ब बैंक राज्य सहकारी बैंकों को हथकरमा (सूती, रेशमी हौर ऊनी) बुनकर मिनियों झौर बिजली-चालित करमा बुनकर मिनियों के उत्पादन और विपणन सबंधी कार्यकलायों का विन-पोषण करने के लिए बैंक दर से वाधिक 1.5 प्रतिशत कम रियायती दर पर इस गर्त पर विनीय सहायता प्रदान करना रहा कि हथकरथा बुनकर समितियों से ली जाने वाला व्याज दर 1 5 प्रतिशत पर गृती प्रत्य वर से जाने क

न हो जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर (भारत मरकार द्वारा वियो जाने वाले 3 प्रतिशत के ब्याज उपदान के कारण) निर्धारित की जाए।

286. हथकरघा उद्योग की समस्याग्नो का घष्ट्ययन करने के लिए गठित उच्चस्तरीय श्रध्ययन कल (1974) की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया कि नयी हथकरथा बुनकर सिमित्यों को प्रतिक्रक्या दी जाने वाली श्रष्टण सीमाध्रों को खर्च में हुई बढ़ोतरी के कारण बढ़ाया जाए। इसके परिणामस्वरूप संप्रति उक्त सीमाएं सूती हथकरथे के सन्दर्भ में रु० 1,000 ग्रौर उनी हथकरघे तथा रेणम के सन्दर्भ में रु० 2,000 है। नये बिजली चालित करघा बुनकरों/पुनः त्रियाणील की जाने वाली निष्त्रिय सिमितियों के विल-पोषण की प्रतिकरघा माला को भी बढ़ाकर रु० 5,000 कर दिया गया। पहले से ही कार्यरत सिमितियों की सीमाध्रों का मूल्यांकन ध्रनुमानित उत्पादन के 25 प्रतिशत या प्रतिकरघा निर्धारित राणि से जो भी कम हो उसके ग्रनुसार किया जाता रहा।

# सहकारी बुनकर मिलों के शेयरों के लिए ऋण

287. हथकरघा उद्योग की समस्याभों का भ्रध्ययन करने के लिए गठित उच्चस्तरीय भ्रध्ययन दल ने यह भी निफारिंग की कि रिजर्व बेंक बुनकरों को मध्यावधि विस की सुविधाएं प्रदान करे ताकि वे सहकारी बुनकर मिलो की भ्रेयर पूंजी मे भ्रभिवान कर सकें। तदनुसार बैंक ने श्रलग-भ्रलग बुनकरो-हथकरघा भीर विजली चालित करधा बुनकरो तथा प्राथमिक बुनकर ममितियों की भुकौती की क्षमता की दृष्टि से प्रस्तावों की तकनीकी भ्रौर श्राधिक संभाव्यता का पना लगाने के लिये भ्रध्ययन कार्य किया। इन भ्रष्ट्ययनों के श्राधार पर शैंक ने केवल भ्रलग-भ्रलग बिजली चालित करघों के स्वामियों/बिजली चालित बुनकर समितियों को जनवरी, 1975 में यह सुविधा प्रदान की।

# बोर्चकालीन प्रवर्तन निधि से ऋण

288. बैंक राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार की सहकारी ऋण संस्थाक्यो की शेयर पंजी में ग्राभिदान करने के लिए ऋण प्रदान करता रहा। छोटे कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त कृषक श्रीर कृषि श्रम एजेंसी/जनजातीय क्षेत्रों में ग्रीर उन क्षेत्रों में जहां वाणिज्य बैंकों ने प्राथमिक कृषि ऋण समितिया का वित्त-पोषण किया हो, कार्यरत संस्थाक्रो के संदर्भ में तथा पुनर्निर्माणाश्चीन रहने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मामले में उक्त प्रयोजन के लिए निर्विष्ट मानकों में की गयी विशेष रियायतों को जारी रखा गया। श्रासोच्य वर्ष के दौरान जनआतीय क्षेद्रों में स्थित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संदर्भ में कतिपय प्रतिरिक्त रियायते दी गयी। उन क्षेत्रों में स्थित छोटे श्राकारवाली उन प्राथमिक कृषि ऋण सिमितियों पर शेयर पृजीगत धाभितान के लिए विचार किया गया चाह उनके ऋण कारोबार का मूल्य केवस ६० 30,000 हो धौर उनके ऋणकर्ता सबस्य 100 हों, किन्तु शर्त यह थी कि पूर्णकालिक वैनिनिक सिचवो की नियुक्ति जैसी ग्रन्थ म्नावस्थक शर्तो का पालन किया गया हो। सामान्यतः गेयर पुंजीयत भ्रभिदान के लिए पात बनने के निमित्त समिति को चाहिए था कि उसके ऋण कारोबार का मूल्य कम से कम रु० 50,000 हो और उसके ऋष्णकर्ता सदस्य कम से कम 150 हों। जहां प्राथमिक कृषि ऋण समितिया **ग्रत्याव**श्यक उपभोक्ता वस्तुमो की पूर्ति करने का कार्य प्रारम्भ कर रही थी वहां रु० 10,000 की नियमित सीमा से भ्रधिक श्रतिरिक्त शेयर पंजीगत ग्रभिदान भी मंजूर किया गया ताकि समितियां उक्त कारोबार प्रारम्भ कर सके।

289. 7 राज्य सहकारी बैंको 95, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, 2 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 55 प्राथमिक भूमि बिकास बैंकों, 19 शहरी सहकारी बैंकों, 4,176 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 65 कृषक मेवा समितियों ग्रीर

20 बड़े आकार बाली बहुज्हेण्यीय सिमितियों की शेयर पूंजी में भ्रभिदान करने के लिए राज्य सरकारों को कुल 13.5 करोड़ रुपयों के ऋण प्रवान किये गये भीर इस संदर्भ में 31 मार्च, 1976 को 76.1 करोड़ रुपये बकाया थे।

290 रिजर्व बैंक ने कृषि पुनिबक्त भीर विकास निगम के लिए भी निधि में से 1974-75 के दौरान 40 करोड़ रुपयों का दीर्घाविधि ऋण और 1975-76 के दौरान 60 करोड़ रुपये का एक भौर दीर्घाविधि ऋण मजूर किया। भालोच्य वर्ष के दौरान चुकायी गयी भौर निकाली गयी राणियाँ कमण: 9 8 करोड़ रुपये भौर 60 करोड़ रुपये थी। 30 जून, 1976 को विद्यमान बकाया राणि 138.4 करोड़ रुपये थी।

# भूमि विकास बैक

291. 1975-76 के वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के कुल ऋण कार्यक्रम की राशि 229.5 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी जिसमें से 26.6 करोड़ रुपये बैकों द्वारा ग्रपने ही वित्तीय साधनों से प्रदान किये जाएंगे भीर ग्रीप भ्रांश की व्यवस्था डिकेंचर जारी कर दी जाएगी। कृषि पुनर्वित्त भ्रौर विकास निगम की पुनर्वित्त योज-नाम्रों के भन्तर्गत बैंक 119.8 करोड़ रुपयो के लिए विशेष विकास डिबेंचर, 79.7 करोड़ रूपयों के लिए सामान्य डिबेचर धौर 3.4 करोड़ रुपयों के लिए ग्रामीण डिबेचर जारी करने वाले थे। उक्त 3.4 करोड़ रुपये ग्रामीण डिबेचरो के श्रमाथा सावधि जमाराणियों की असुनी से भी प्राप्त हो सकते थे। कुल 79 7 करोड़ रुपयो के प्रनुसोदित सामान्य डिबेंचर निर्गम कार्यक्रम की तुलना में बैको ने वास्तव मे केवल 75.5 करोड़ रुपयो के डिबेचर जारी किये। कुल ग्रिभवानी में से 12.6 करोड़ रुपयों का प्रभिदान केन्द्रीय सरकार प्रीर राज्य-सरकारों द्वारा, 35.4 करोड़ रुपयों का श्रभिवान जीवन बीमा निगम श्रौर वाणिज्य बैकों जैसे संस्थागत निवेशको द्वारा और 19.2 करोड़ रुपयों का भाभवान भूमि विकास बैकों द्वारा किया गया सथा 8.2 करोड़ रुपयों की राशि उनके अपने प्रयास से जुटायी गयी।

292. 1976-77 के लिए केन्द्रीय भूमि विकास बैंको के कुल ऋण कार्यक्रम की राणि 284. 4 करोड़ रुपये निर्धारित थी। 121.2 करोड़ रुपयों की राणि युक्त सामान्य ऋगा कार्यक्रम की परिकल्पना की गयी थी। इसमें से 33.2 करोड़ रुपयों की वित्तीय व्यवस्था बैंक झपने झांतरिक वित्तीय माधनों से करेंगे भौर भेष अंग की व्यवस्था सामान्य डिबेंचर जारी कर की जाएगी। यह मान निया गया कि केन्द्रीय भूमि विकास बैंक 6 करोड़ रुपयों तक की राणि अपने प्रयाम से जुटायेंगे, झतः यह आशा की गयी कि शेष 82 करोड़ क्ययों की राणि का श्रभवान श्रन्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा (पारस्परिक महायसा-ऋण-शोधन निधि— 40 करोड़ रुपये, जीवन बीमा निगम—15 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सरकार श्रीर राज्य सरकारे-—12 करोड़ रुपये तथा वाणिज्य बैंक——15 करोड़ रुपये)।

293. केन्द्रीय भूमि विकास बैको द्वारा प्राथमिक समितियों/शाखाग्रों को प्रवक्त श्राग्रमों को वसूली संबंधी संशोधित मानकों के श्रनुसार विनियम्तित करने में प्रनुभय की गयी किठनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त ग्रीर विकास निगम ने डिबेंचर-मानकों की स्थायी समिति (गवर्नर द्वारा गठित) की सिफारिको पर विचार करने के बाद 1 जनकरी, 1974 श्रीर 1 सितम्बर, 1975 के बीच उनकी ऋण पालसा के श्रातिरक्त प्रवान किये गये ऋणों के संबंध में दूसरी ग्रीर परवर्ती किश्तों के श्रपने वायदे पूरे करने की श्रामुमति दी सगतें कि दूसरी ग्रीर परवर्ती किश्तों का वितरण कार्य 30 जून 1976 के पहले पूरा किया जाए। 1 जनवरी 1974 के पहले लघु सिचाई कार्यों के लिए प्रवक्त ऋणों के मामले में विजली-चालित परपसेट की लागर ग्रीर उसके लगाये जान के लिए दी जानेवाली दूसरी श्रीर परवर्ती किश्तों को 30

जून 1976 तक विमरित करने की ग्रनुमति दी गयी अवार्ते कि मूल मंजूरी संयुक्त प्रयोजन के लिए श्रर्थात् कुए तथा बिजली चालित पपसेट के निमित्त हो भीर वैंक इस बात से पूर्णतः श्राप्तवस्त हो कि बिजली की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण पंपसेट का ऋण नहीं लिया आ सका।

294 जहाँ प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसल न हुई हो वहाँ प्राप्निमों के विनियमन के मामले में राहत के रूप में रिजर्व बैंक नधा हुषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कनिषय रियायते प्रवान की।

295. श्रालोच्य वर्ष के दौरान श्रन्य महत्यपूर्ण नीति संबंधि गतिविधियों सिम्नप्रकार थीं:

- (!) केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा ब्रामीण डिबेंचर जारी करते की जो योजना पहले 1957 में प्रारम्भ की गयी थी, उस संपूर्ण योजना का पुनरीक्षण बैंक के कृषि ऋण मंडल द्वारा 7, ध्रगस्त 1975 को हुई बैठक में किया गया और यह निश्चय किया गया कि ग्रामीण डिबेंचर का निर्गम कार्य भविष्य में प्रादेशात्मक होने के बजाय स्वैच्छिक हो। नयी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण डिबेंचर राज्य सरकारों की गारंटी के बिना, परस्तु उच्चतर ब्याज-दर पर धौर रिजर्ब बैंक के श्रभिदान के बिना, जारी किये जायेंगे।
- (ii) ऋण णोधन निधियों के निवेश के संबंध में रिजर्व बैक द्वारा निविष्ट किये गये स्वरूप के धनुमार केन्द्रीय भूमि विकास बैकों को चाहिए कि वे धपनी ऋण गांधन निधियों के कम से कम 20 प्रतिशत का निवेश सरकारी और न्यासी प्रतिभृतियों में करें जिनमें न्यासी प्रतिभृतियों में किया जानेवाला 10 प्रतिशत का न्यूनतम निवेश भी सम्मिलित है। बैकों को भारतीय यूनिट-द्रस्ट के यूनिटों में धपनी ऋण गोधन निधियों का निवेश करने की धनुमति इस गर्त पर वी गयी है कि यूनिटों में किये जाने वाले निवेश की माला ऋण गोधन निधि के कुल निवेशों के 5 प्रतिशत से ध्रिष्ठ न हो।
- (iii) पिछली निर्मार्ट में सहकारी भूमि विकास बैंकों से संबंधित समिति की रिपोर्ट में निहिन प्रमुख सिफारियों का उल्लेख किया गया था। इन सिफारियों को बैंक के छूथि ऋण मंडल की 7 ग्रगस्त, 1975 को हुई बैंठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकारों को यह सुचित किया गया है कि वे समिति की सामान्य और विणिष्ट सिफारियों पर कार्रवाई प्रारम्भ करें। इसके मलावा बैंक के प्रनुरोध पर भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भूमि विकास बैंकों की परिचालनगत और विलिय क्षमना में सुधार लाने के निमित्त इन सिफारियों को यथा-गीन्न कार्यान्वित करने की श्रावण्यकता पर जोर देते हुए एक पन्न भी संबोधित किया था।
- (iv) सामान्य भौर विशेष डिबेंचरां के निर्गम के लिए एकसमान श्रिथाविधियां बनाने के निमित्त बैंक के कार्यपालक निदेशक की भव्यक्षता में डिबेंचर-मानकों पर एक स्थायी समिति भी गठित की गयी।

### प्राथमिक स्तर पर पुनर्गठन

2)6. भालोच्य वर्ष के दौरान भाषार स्तर पर महकारी ऋण विन्यास के पुतर्गठन की गति में तीवता लाने के प्रयास जारी रहे। सक्षम प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के निर्माण के लिए श्रिधिकांश राज्य सरकारों ने योजनाएं बनायी थी।

297. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन ग्रीर श्रक्षम मिनित्यों को पुनर्गठित मिमितियों के साथ या जनजातीय क्षेत्रों में गठिन कृषक सेवा मिनित्यों या बड़े श्राकारवाली बहुउद्देश्यीय मिनित्यों के साथ समामेलन करने में ग्रानेवाली कियालिशि संबंधी भीर ग्रन्य ममस्यान्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए 4 मई 1976 को कृतिपय राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयकों ग्रीर भारत सरकार नथा वाणिक्य बैंकों के ग्रीन

निधियों की एक बैठक झायोजित की गयी। इस बैठक में किये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को यह मुनिष्चित करने के लिए कहा गया कि सामान्यनः प्रत्यक पुनराठित प्राथमिक कृषि ऋण समिति के झन्तं-गंत 2,000 हेस्टेयर का सकल फ़सल क्षेत्र हो और उस समिति का कार्यक्षेत्र 10 किलोमीटर परिधि में हो। ऐसी वर्तमान समितियों के लिए जिनका पुनर्गिटत समिति के साथ समामेलन किया जा सकता है या उन समितियों के लिए जिनका परिसमापन किया जा सकता है, कित्पय मान-दण्ड निर्धारित किये गये। परन्तु प्रक्षम समितियों का श्रविलम्ब समामेलन करने की प्रक्रिया पर श्रमल करने की ग्राक्ति पंजीयक को प्रदान करने की मिन्ति राज्य सहकारी समिनियों के प्रधिनियमों को संशोधित करने की प्रावस्थकरा थी।

# ग्रस्पावधि ग्रौर मध्यावधि ऋण विग्यास का समस्पीकरण

298. कृषि ऋण मंडल ने अपनी सातवी बैठक में महकारी ऋण की गितविधियों के संदर्भ में अल्पाविध और दीर्घाविध ऋण विन्यासों का समाकलन करने के प्रकृत पर विचार किया और उसका यह विचार था कि छोटे राज्यों में सभी स्तरों पर ऐसा समाकलन किया जा सकता है; किन्तु अन्य राज्यों में कम से कम प्राथमिक स्तर पर समक्रगीकरण लाने पर विचार किया जा सकता है। जहां तक चयनात्मक आधार पर प्रायमिक स्तर पर समाकलन करने के प्रश्त का संबंध था, राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही। परन्तु गर्यार द्वारा सितम्बर, 1975 में उप गर्वार की अध्यक्षता में गठित सहकारी ऋण संस्थाओं के समाकलन से संबंधित समिति द्वारा उक्त वोनों विन्यासों के समाकलन के प्रश्न के सभी पहलुकों पर विचार किया जाएगा। आसा की जाती है कि यह सितित शीध ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

### कमजोर वर्गी का विस्तरोवण

299. 1975-76 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को यह सुनिध्वित करने के लिए कहा गया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋण समितिया का विये जाने वाले धिप्रिमो का 20 प्रतिशत से धन्यून धंश छोटे/ध्राधिक दृष्टि से कमजोर कुषकों का वित्तपोषण करने के लिए प्रधान किया जाना है। निर्वाध धंश (ऋण सीमा का सामान्यतः 60 से 70 प्रतिशत धंश) के धिनिधिक ऋण सीमाओं से ली जाने वाली राणि ऐसे कुषका का वित्तपोषण करने के लिए सिनितियों को जारी किये जाने वाले प्रथिमों के अनुरूप होनी चाहिए।

### ऋण राहत स्रोर उपभोग ऋण

300. बीस सूत्रीय धार्षिक कार्यक्रम के धनुसरण में कई राज्य सरकारों ने छोटे क्रुपकों, सीमान्त क्रुपकों, कृषि श्रमिकों धौर प्रामीण कारीगरो द्वारा निजी साहुकारों में लिए गये ऋषों के श्रिधस्थगन, ग्रोधन था उनकी माल्रा को कम करने के लिए विधान पारित किये हैं। यह ग्राणा है कि इन उपायों से संस्थेनर स्रोतों से उपलब्ध ऋष्ण ममाप्त हो जायेगे। भारत सरकार द्वारा ग्रामीग् ऋण्यस्तता का परिसमापन करने ग्रौर इस संवर्भ में नमूमा विधान बनाने के निमित्त नियुक्त किये गये अन्तर मंत्रालयीन दल ने यह ग्रामुमान लगाया था कि ऋण राहुस उपायों के परिणामस्तरूप उत्पन्न जिस ऋण खाई की पूर्ति करनी होगी उसकी राशि तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये होगी।

301. ऋष्ण राहत के ज्यायों से प्रभावित ऋषकति आं संस्थागत ऋषा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोग के प्रयोजनों के लिए सहकारी बैंको द्वारा विसीय सहायता प्रवान किये जाने से संबंधित बैंक की नीति में हाल ही में संशोद्यन किया गया। प्रवनुसार चिकित्सा सहायता, शिक्षा, प्रन्तयेष्टि विवाह (बहुक को छोड़कर) मादि विशिष्ट

प्रयोजनों के लिए प्राथमिक ऋण समितियों के कमजार वर्गों के कृपक सदस्यों को उत्पादन ऋण सिह्न उपभोग ऋण प्रदान करने की अनुमित दी गयी। परन्तु ऐसे ऋण की मात्रा कुल अस्पावधि अप्रिमों के 10 प्रतिमान या प्रति सदस्य रु० 250 में से जो भी कम ही उस राणि तक सीमित की गयी। अलग अलग व्यक्तियों को मोने या चादी के आभूषणों की जमानन पर उपभोग तथा दूसरे उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संबंध में बैंक ने अपनी नीति का पुनरीक्षण किया और उन्हें प्रति ऋणकर्ता रु० 1,000 से अनधिक राणि के ऐसे ऋण प्रदान करने की अनुमित प्रदान की। परन्तु अलग अलग व्यक्तियों को प्रदत्त गभी प्रकार के ऋणों और अप्रिमों की सकल राणि वैक की कुल मांग और मीयादी देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

302. राज्य सरकारों के ग्रामीण ऋण र.हत-उपायों के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने एक विशेषक समिति गठित की जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य श्री बी० शिवरामन ये ग्रीर भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण के प्रभारी कार्यपालक निदेणक उसके एक सदस्य थे। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विभिन्न राज्य सरकारों ग्रारा पारित ऋण राहत विधान के परिणामस्वरूप समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध ऋण के सस्थेतर स्रोत लगभग खत्म हो चुके थे; ग्रतः उसने यह मुझाया है कि इस ऋणकर्ता वर्ग की उपभोग ऋण सबग्नी अपेक्षाओं की पूर्ति वित्तीय एनेन्सियों द्वारा की जाए। सिमिति की श्रय्य सिकारियों निम्न प्रकार है:

- (i) उपभोग ऋण प्रवान करने के लिए ग्रास्थिक उपयुक्त संस्थागत एजेन्सी प्राथमिक ऋषि ऋण समिति, ऋषक सेवा समिति ग्रीर जनजातीय क्षेत्रों में बड़े श्राकारवाली बहुउद्देश्यीय समिति हैं जिनमें से प्रत्येक के पास पूर्णकालिक वैतिनक सचिव या प्रवस्थ निदेशक हो।
- (ii) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन, सिखवों की नियुक्ति और ऋण बसूली प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य शीद्य किया जाना चाहिए और व्यापक सदस्यना को ध्रमल में लाया जाना चाहिए, नाकि गांव के स्तर पर सहकारी संस्थाए इस प्रयोजन के लिए प्रभावी एजेन्सियों के रूप में उपयोगी हो।
- (iii) केन्द्रीय महकारी बैंक उपभोग ऋण जारी करने के उद्देश्य के लिए पुनर्गंटिन समिनियों/बड़े धाकारवाली बहुउद्देश्यीय समितियों का बित्तपोषण करेगे। जिन क्षेत्रों से ऋषक मेना समिनियों या पुनर्गंटित समितियों का वित्तपाषण याणिज्य बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जाना हो वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसी समितियों के जरिए भी उपभोग ऋण प्रवान करेगे।
- (iv) पुनर्गठित समितियों, कृषक सेवा समितियों या बड़े झाकार-वाली बहुउद्देश्यीय समितियों के भ्रन्तगैन न भाने वाले क्षेत्रों मे राज्य सरकारों को चाहिए कि वे भ्रलग श्रम्प व्यक्तियों को भ्रपने राजस्य या भ्रन्य प्रणामनिक विभागों के जरिए सीधे प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करे।
- (४) परिचालन के प्रथम वर्ष के लिए लगभग 170 करोड़ रुपयों के अनुमानित उपभोग ऋण की अपेक्षाओं में से प्राथमिक क्विय ऋण समितिया 170 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करेंगी जबकि राज्य सरकारे 100 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करेंगी।
- 303. समिति की सिफारिशो को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार, रिजर्व बैंक ग्रौर राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाये जा रहे है।

# छोटे क्षुषक विकास एजेन्सी/सोमांत कृषक ग्रौर कृषि श्रम एजेन्सी योजनाएं

304. नयम्बर, 1975 के भन्न तक इस योजना के भन्तर्गत उपलब्ध साभों के लिए पात्र के रूप में लगभग 12.5 लाख छोटे भीर मीमांग कृषक और कृषि/भूमिरहित श्रमिकों का पता लगाया गया। इनमें से 6.1 लाख व्यक्ति सहकारी सस्थाओं के मदस्य बने। जुलाई, 1975 से नवम्बर 1975 तक की श्रविध के बौरान इन सदस्यों को लगभग 19 3 करोड़ रुपयों के धल्पावधि ऋण सहकारी संस्थाओं के जरिए विनिन्ति किये गये जबिक 1 श्रवैल, 1975 से 1 नवम्बर, 1975 तक की श्रविध के दौरान 2 0 करोड़ रुपये वाणिज्य बैकों के जरिए विनित्ति किये गये। इनके भृतिरिक्त परियोजनाओं के श्रारम्भ से लेकर श्रव तक उन्हें लगभग 8.4 करोड़ रुपयों के मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी बैकों द्वारा प्रदान किये गये हैं। इसी श्रविध से वाणिज्य बैको द्वारा मंजूर किये गये मध्यावधि ऋणों की राणि 4.3 करोड़ रुपये थी।

### ऋण समितियों के लिए वाणिक्य बैकों का वित्त

305 वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का विस-पोषण किये जाने की जो योजना 1970 में प्रारम्भ की गयी वह दिसम्बर, 1975 के भन्न में निम्नलिखित 11 राज्यों में भ्रमल में थी: भांध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू भीर कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीमा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बगाल और भ्रमम। यह निश्चय किया गया है कि इस योजना को राजस्थान में भी भ्रमल में लाया जाए।

306. दिसम्बर, 1976 के धन्स तक अपनी 462 माखाओं के जिएए सोजना में भाग लेनेवाले 11 राज्यों में स्थित 22 वाणिज्य बैकों ने 3266 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को धपने प्रधिकार में ले लिया था। यदि समग्र रूप से देखा जाए तो परिचालनगत क्षमता और शाखा स्तर पर क्षेत्रीय कर्मनारियों के सर्वाधिक उपयोग के लिए परिकरियत प्रति शाखा 10 समितियों के मुकाबले में प्रति गाखा समितियों की श्रीसत संख्या 7 थी। वाणिज्य बैकों ने 1,813 समितियों को 1975 के खरीफ भौसन में 12.6 करोड़ रूपयों और 31 दिसम्बर, 1975 तक 1975-76 के एवी मौसम में 2.4 करोड़ रूपयों के प्रस्पायिध ऋण प्रदान किये थे। इसके भ्रालावा बैकों ने दिसम्बर, 1975 तक 259 समिनियों को कुल 70.9 लाख रूपयों के मध्याविध ऋण भी वितरित किये थे।

### कमजोर सहकारी बैकों का पुनर्निर्माण

307. घालोच्य वर्ष के दौरान कमजोर सहकारी बैंकों के पुनर्निर्माण की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के धन्तर्गत भारत सरकार ने 11 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 50.2 लाख कपयों की सहायता मंजूर की 1 30 जून, 1976 तक भारत सरकार ने राज्य सरकारों को संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों की धोर से सहायता के उनके धंग के रूप में 22.2 लाख रुपये प्रदान किये। द्विस्तरीय ऋण विन्यास वाले क्षेत्र में कार्यरत मणिपुर, ब्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों को भी योजना के धन्तर्गत सहायता के लिए स्वीकृत किया गया और उन्हें धालोच्य वर्ष के बौरान 9 2 लाख रुपयों की राजि प्रदान की गयी।

308. प्राथमिक सहकारी बैकों, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों भीर राज्य भूमि विकास बैंकों की शास्त्राम्नों के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम मालोच्य वर्ष भ्रथीत् 1975-76 के दौरान जारी रहा । 30 जून, 1974 तक की उनकी वित्तीय स्थितियों के माधार पर 46 प्राथमिक सहकारी वैंक, 130 प्राथमिक भूमि विकास बैंक ग्रीर केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों की 124 शास्त्राएं पुनर्निर्माण कार्यक्रम के मन्तर्गत थी।

# क्षेत्रीय ससंतुलमों को दूर करना

309. केन्द्रीय सरकार 1975-76 के दौरान श्रेणी 'ग' के राज्यों (सहकारिना की दृष्टि से कमजोर राज्य) में स्थित केन्द्रीय सहकारी पिकों को ग्रामिवेय राशियों की पूर्ति के लिए भ्रोपेक्षित उनके विक्षीय साधनों में विद्यमान घाटे को दूर करने के निमिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना रहा। ग्रामोच्य वर्ष के दौरान 5 राज्यों में स्थित 23 केन्द्रीय

राभ्य यहरारी बैहा प्रीर एक राज्य यहकारी प्रैर को इस पोधना ये अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 175 लाख रुपयो की राणि प्रशास की गयी। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भी समानातर सहायता प्रदान की गयी।

#### अध्ययम दल

#### श्रतिदेय राशियों के संबंध में

310 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट से उल्लिखित किया गया था, अतिदेय राणियों से संबंधित अध्ययन दल की विभिन्न सिफारिणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और राज्य सहकारी बैकों को सूचित किया गया। प्रधिकाण राज्यों ने समान्यत इन सिफारिणों को स्वीकार कर लिया है।

### राजस्थान के संबंध में

311 पिछली रिपोर्ट में राजस्थान की कृषि ऋण संस्थाओं से सबक्षित अध्ययन दल और उसके प्रमुख निष्कार्षों का उल्लेख किया गया था। उसकी विभिन्न सिफारियों का कार्यान्वयन राज्य सरकार, राज्य/केन्द्रीय गहकारी बैंको और वाणिज्य बैंको के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनवरी, 1976 में बैंक के कार्यपालक निदेणक द्वारा किया गया। राज्य सरकार ने विभिन्न रिफारियों पर कार्यवार्ड णुरू की थी। राज्य सहकारी बैंक ने अपने से संवधित सिफारियों को कृष्ठ सणीवतों के साथ स्वीकार किया।

#### मध्य प्रदेश के संबंध में

312 मध्य प्रदेश में विश्वमान कृषि ऋण संबंधी सम्थागत व्यवस्थाश्रा पर गठित अध्ययन दल ने 24, प्रप्रैल 1976 को अपनी रिपोर्ट को श्रन्तिम रूप दिया।

### सिक्किम में क्रुवि ऋण के संबंध में

313 26 अप्रैल, 1975 का सिक्किम भारतीय गगतज्ञ का 22वा राज्य बना। उसके फनस्थका भारत सरकार के कृषि एव विचाई मतालय ने अगस्त, 1975 में उस राज्य की कृषि ऋण स्थिति और संस्थाओं का अध्ययन करने और विभिन्न सब धन पहलुओं पर सिफारिशे प्रस्तृत करने के लिए बैक के कृषि ऋणिवभाग के प्रभारी कार्यशालक निद्याल की अध्यक्षता में एक बल गठित किया। इस अध्ययन दल से यह भी कहा गया कि 1968 से सिक्किम में कार्यरत स्टेट बैक छोफ सि सक्तम को अवीय प्रामीण बैक के रूप.से परिवर्तित करने की सभावना पर विचार किया जाए। दल के अध्यक्ष ने फरवरी, 1976 के अस्त में भारत सरकार को दल की सर्वसम्मत रिपोर्ट पेण की।

311 इस दल का सर्वप्रथम लक्ष्य मृलभृत स्पर पर ऐसी सस्थाओं का गठन करना था जो पूरे गिक्किम में बैंकिंग और ऋण मृविधान्ना की व्यवस्था कर सके। इस दत न प्रे मिक्किम राज्य में लगभग 20,000 सदस्या से युक्त 35 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की याजना बनायी है। दल ने यह अनुभव किया कि पाच माल में कम में कम । करोड़ रुपये के ऋण नाराबार का विकास सभी यृतिट मिलकर कर सकेंगे। दल द्वारा परिकल्पित महकारी सस्थान्नों का स्वरूप अहुउद्शेषीय होगा। दल ने यह सिफारिश भी की कि उक्त 35 यूनिटों में से 4 ऐसे यूनिटों को जिनकी सभाव्य क्षमता अपेक्षाकुल प्रधिक है, स्वयपूर्ण कृषव सेवा समितियों के रूप में विकलित करना चाहिए। उक्त 4 यूनिटा में से एक एक यूनिट प्रत्येक जिले में हो।

315 राज्य-स्तरीय बैकिंग संस्था, उसकी भूमिका ग्रीर उसके स्थल्य के सबध में दल ने एक ऐसे राज्य संस्कारी बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की जो थाड़ा बहुन प्रगतिशील हों। यह राज्य सहकारी बैंक हण के प्रत्य भोगा में विद्यमान राज्य सहकारी बैंका के विपरीत कृषि 25 GI/77 -9

के लिए सभी प्रकार के ऋण महकारी संस्थाध्रों के माध्यम में और ब्यापार शाणिक्य तथा उद्योग के लिये सीचे ही प्रदान करेगा। इसके अलावा उक्त राज्य सहकारी बैंक सरकारी कारोबार का लेल-देन भी करेगा। दल ने यह भी सिफारिण की कि यह भी अधिक उचिन होगा यवि स्टेट बैंक ध्रॉफ सिक्किम को प्रस्तावित सिक्किम राज्य सहकारी बैंक में प्रस्तरित कर दिया आए।

316 ग्रध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की थी कि स्टेट बैक ग्रांफ सिकिस को मिकिस राज्य सहकारी बैक में अन्तरित करने के लिए विधान तैयार करने ग्रोर साथ ही अयापक सहकारी सिमित ग्रधितियम तथा प्रस्तावित राज्य सहकारी बैक की उपविधिया बनाने के लिए एक छोटी सी मिमित गठित की जाए। इस सिमित की सिफारिणों के कार्यान्ययन पर कुछ समय तक राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार ग्रीर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ गठित की गर्छ एक राज्यस्तरीय सिमित निरन्तर निगरानी रखेगी।

317 इस ग्राध्ययन वल की रिपोर्ट पर कृषि ऋण मंडल ने 20 ग्राप्रैल, 1976 को अपनी नौती बैठक में विचार किया। इस वल की निफारिणों की राज्य स्वरीय बैकिंग व्यवस्था की विकारिण को छोडकर कृषि ऋण मंडल ने स्वीकार कर लिया। इस मडल ने उक्त प्रश्न का ग्राध्ययन करने का कार्य एक छोटी सी समिनि को सौपा था।

# राज्य स्रौर केन्द्रीय सहकारी बैको के कर्मचारी-स्वरूप के संबंध में

318 कृषि ऋण विभाग ने पश्चिम बगाल राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारी स्थरूप और आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज्य एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारी स्वरूप का ग्रध्ययन किया। इन ग्रध्ययनों की रिपोर्ट बैंका तथा मबंधिन राज्य सरकारों को भेजी गई। इन रिपोर्टों में थर्नमान कर्मचारी स्वरूप की कमिया का उल्लेख किया गया है श्रीर विभिन्न स्तरों पर ग्रपेक्षित कर्मचारी स्वरूप, भर्ती ग्रीर प्रणिक्षण ग्रादि विभिन्न सुधारान्मक कार्यश्रद्धा की सिफारिश की गयी है।

### सहकारी बेकिंग विधान

319. इस वर्ष के दौरान बैककारी विनियमन प्रधिनियम 1949 की धारा 22 के अधीन एक केन्द्रीय महकारी बैंक और चौबीस प्रायमिक सहकारी बैंकों को भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए लाइनेंस दिये गये। लाइनेंस प्राप्त राज्य, केन्द्रीय प्रौर प्राथमिक (णहरी) सहकारी बैंकों की कुल संख्या इस वर्ष के धन्त में 99 थी, जब कि पिछले वर्ष उक्त सख्या 73 थी। 7 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए लाइनेंस प्रस्वीकार किये गये क्योंकि वे बहुत प्रधिक मुक्तिधायुक्त केन्द्रों में संगठित थे। इस कारण वे सक्षम यूनिट नहीं हा सकते थे।

320. वेश में सहकारी बैंकों के कार्यालयों की संख्या जहाँ 30 सितम्बर, 1973 को 6102 थी वहाँ 30 जून, 1975 की बंद्रकर 7091 द्वीर 30 जून, 1976 को धीर बहुकर 7288 (राज्य सहकारी बैंकों के 293 कार्यालय, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 5376 कार्यालय, धीर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के 1406 कार्यालय तथा प्राथमिक (वेतनभोगियों के) 213 कार्यालय, हो गयी।

321. इस वर्ष के दौरान नये कार्यालय खालने के लिए राज्य सहकारी बैका ग्रीर प्राथमिक सहकारी बैको को 73 लाइसेस दिये गये जब कि पिछले वर्ष 59 लाइसेस विये गये थे।

322 30 जून 1976 का बैककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत 1531 सहकारी बैंक (28 राज्य, 370 केन्द्रीय और 1133 प्राथमिक सहकारी बैंक) विद्यमान थे, जब कि इस वर्ष के आरम्भ में विद्यमान सहकारी बैंको की संख्या 1494 थी। 323. 10 केन्द्रीय सहकारी बैंक बैंककारी विनियमन ग्रिधिनियम 1919 की धारा 11 (1) का अनुपालन नहीं कर रहे थे। इनमें में 7 केन्द्रीय सहकारी बैंक असम में थे और उस राज्य सरकार ने उन्हें असम सहकारी शिखर बैंक सीमत में विलियत करने का निश्चय किया है। शेष तीन केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्निर्माण कार्यक्रम जारी था। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11 (1) का अनुपालन करने से चूक गर्बे 23 प्राथमिक सहकारी बैंकों में से 3 बैंकों का समापन किया गया है और 3 बैंकों के लिए लाइमेंस अस्वीकार कर दिया गया है।

324. इस वर्ष के दौरान 802 सहकारी बैंकों (23 राज्य, 225 केन्द्रीय श्रीर 527 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, 14 राज्य भूमि विकास बैंक तथा 13 शिखर बुनकर निपणन समितियाँ) का निरीक्षण किया गया। इनमें से 108 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैकों का निरी-क्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 (1) के प्रधीन रिजर्व बैंक की श्रोर से राज्य सहकारी बैंक के श्रधिकारियों ने किया। इस वर्ष के बौरान 23 राज्य सहकारी बैंको, 292 केन्द्रीय गहकारी बैंकों, 623 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, 10 राज्य भूमिविकास **दैंकों ग्रौ**र 9 शिखर बुनकर/विषणन समितियों के निरीक्षणो की रिपोर्टें जारी की गयी। कई प्राथमिक सहकारी बैंकों ने अपने जिले या राज्य से भी बाहर रहनेवाले स्थानो पर गाखाएं खोलन के लिए लाइसेंस मौगते हुए धार्वेदन किया था। ऐसे मामलों में बैंकों से यह ध्रपेक्षा की गयी कि वें (i) निवेशक मण्डल में ऐसी शास्त्राद्यों के प्रतिनिधित्व के निमित्त उपनियमों में ब्रावण्यक व्यवस्था करें, (ii) निदेशकों के लिए निर्धारित योग्यता गोयरों को दूर करें, (iii) नियमित ऋणकर्नाध्रों को सामान्य सदस्यो के रूप में लेने की प्रणाली की समाप्त करें, धौर (iv) मदस्य के शोयरो को उसके ऋण के साथ निर्धारित धनुपात में जोड़ने की अथवस्था करें।

#### ग्रशोध्य ऋण

325. विभागीय लेखा परीक्षक प्राथमिक कृषि ऋण समिनियो और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संदिग्ध श्रीर झणोध्य ऋणो तथा अन्य श्रास्तियों का जो मूल्यांकन करने हैं, उससे मंबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में श्रपेक्षित संशोधनों पर विचार करने के लिए रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग में सबस्वर, 1975 में सहकारी समितियों के कितप्य पंजीयकों की एक बैठक बुलायी गयी। उक्त बैठक के निष्कर्षों और रिजर्व बैंक के कितप्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बाद में किये गये तदर्थ अध्ययनों के श्राधार पर मार्गदर्शी सिद्धान्तों को संशोधित किया गया है और उन्हें सहकारी समितियों के पंजीयकों को भेजा जा रहा है।

### जमा बीमा योजना

326. इस वर्ष के दौरान जमा बीमा योजना को 1 नवस्कर, 1975 से लिपुरा राज्य के महकारी बैंकों के लिए लागू किया गया। उकत योजना को लिपुरा में लागू करने से उन राज्यों थ्रौर संघशामित क्षेत्रों की मंख्या जहां यह योजना लागू है, जून 1976 के अन्त में कमण: 6 और 3 हो गयी है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों ने रिजार्व बैंक को अन्य बातों के माथ-साथ अधिलंघन समापन, ममामेलन, पुनर्निर्माण आदि की णिक्नयौं प्रदान करने हुए अपने सहकारी मिमित अधिनियमों में आवण्यक संशोधन पारित किये थे। इन राज्यों के सहकारी बैंकों पर जमा बीमा योजना को लागू करने की कार्रवाइयां की जा रही है। जमा बीमा योजना को व्यापक बनाने के लिए थोप राज्यों में महकारी सिमित अधिनियमों में संशोधन करने के प्रण्य पर संबंधिन राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

327. 30 जून, 1976 को 537 पंजीकृत एवं बीमाकृत महकारी बैंक विद्यमान थे जिनमें नौ राज्य सहकारी बैंक, 111 केन्द्रीय सहकारी बैंक, 375 णहरी बैंक श्रौर 47 वेतनभोगियों की गर्मिनियाँ सिम्मिलित थीं।

#### श्रम्य वार्ते

# म्रलग-म्रलग राज्यों में सहकारी गतिबिधि

328. रिजर्व बैंक का कृषि ऋषा विभाग अलग-झलग राज्यों में सहकार अभियान के समक्ष उपस्थित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और आवश्यक सृक्षारात्मक कार्रवाद्यों का गृक्षाव देने के लिये राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठकें बूलाता रहा। 1975-76 के दौरान असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थात, त्रिपुरा पश्चिम बगाल, मेघालय, अभणाचल प्रदेश, दिल्ली और मिजोराम राज्यों सघ गासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्ग किये गये।

### क्षेत्रीय ग्रामीण भैंक

329 भाग II में केवीय ग्रामीण बैंको की स्थापना का उल्लेख किया जा चुका है। ग्रंब तक 19 केवीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये हैं। इन बैंको के कार्य के सम्बन्ध में मार्गवर्णन प्रवान करने के लिये भारत सरकार ने एक संचालन समित गठित की है। इसके ग्रंथिक श्री बींव णिवरामन हैं और रिजर्थ बैंक के कार्यपालक निदेशक एक सदस्य है। रिजर्थ बैंक का कृषि ऋण विभाग संचालन समिति ग्रीर भारत सरकार को निम्नलिखित में संबंधित ग्राकड़े उपलब्ध कराने के लिये विशेष ग्राध्यम कर रहा है: (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिये उपयुक्त क्षेत्र, (ii) विशेष रूप से कमजोर वर्गों की ऋण संभाव्यता के सन्दर्भ में ऐसे बैंको की ग्राधिक स्थिति ग्रीर (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के की स्थापना गठित करने की संभाव्यता व सन्दर्भ में ऐसे बैंको की ग्राधिक स्थित ग्रीर (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया जा मके। इस समिति ने ग्रंब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिये 39 केव्यों का पत्रा लगाया है।

# सहकारी सांख्यिकी के संबंध में समिति

330 भारत सरकार ने भारतीय सहकारी प्रभियान सम्बन्धी सांडिय-कीय विवरण जुटान और उन पर कार्रवाई करने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की। सहकारी सांडियकी सम्बन्धी समिति की चौथी बैठक 29 जुलाई 1975 को इति ऋण विभाग में हुई। उक्त बैठक में सांडियकीय विवरणों के लिए निर्धारित वर्तमान प्रोफार्मा सार्णियों में परिवर्तन/संशोधन करने, नई प्रोफार्मा सार्णियां सम्मिलित करने, समय पर प्रकाशन प्रम्तुत करने आदि से सम्बन्धित सुझावों पर विचार किया गया।

### कृषि पुर्नीवल ग्रौर विकास निगम

331. कृषि पुनर्विन निगम अधिनियम के संशोधन समद हारा पारित किये जाने पर 15 नवस्बर 1975 से श्रमल में लाये गये। 'कृषि पुनर्विन निगम' का नाम बदलकार 'कृषि पुनर्विन श्रौर विकास निगम' कर दिया गया। इस परिवर्तन के कारण निगम हारा पहले से श्रदा की जा रही प्रवर्तक श्रौर विकासारमक भूमिकाश्रों का श्रौपनारिक श्राधार दिया गया।

### कार्यकलाप

332 1975-76 (जुलाई-जून) के दौरान निगम ने 171.2 करोड़ क्ययों का पुनिवित्त वितरित किया जबिक 1974-75 के दौरान 106.4 करोड़ क्ययों का पुनिवित्त वितरित किया गया था। निगम की स्थापना में लेकर जून 1976 के भरा तक वितरित पुनिवित्त की राशि 594.2 करोड़ क्यये थी। इसमें से भ्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ भी परियोजनामों के लिए जिनरित राणि 320.8 करोड़ रुपये या लगभग 54 प्रतिभत थी।

सितरण में हुई यह बृद्धि मुक्ष्य रूप से कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गत (अन्तर्राष्ट्रीय विकास सथ की परियोजनाथ्रा और अन्य परियोजनाथ्रों के अन्तर्गत) प्रदत्त बहुत अधिक उधार तथा दूसरे नाना प्रकार के प्रयोजनों के लिए विवरित की गई राशि में हुई समग्र बृद्धि के कारण हुई। इस वर्ष के वौरान अन्तर्गाट्टीय विकास सथ की सहायना प्राप्त परियोजनाथ्रों के अन्तर्गत विवरित राणि 132. 4 करोड़ कार्ये थी जबिक उक्त राणि 1974-75 में 61 9 करोड़ कार्य थी।

3.3. 1975-76 के दौरान निगम ने 296.9 करोड़ रुपयों के वायदा से युक्त 909 योजनाओं को मंजूरी वी अब कि पिछले वर्ष 201. य करोड़ रुपयां के वायदों से युक्त 623 योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। पिछले वर्ष निगम का कारोबार केवल लघु सिंचाई न रहकर विभिन्न प्रकार का हो गया था। यह प्रयुक्ति इस वर्ष भी जारी रही। इस सन्दर्भ में खेती के मणीनीकरण भी योजनाओं के लिये निगम द्वारा मंजूर किये गये पुनर्वित्त का प्रधिकाण भाग प्राप्त हुआ। डेरी थिकाम, मस्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरी पालन, बागान और बागबानी नथा भड़ारण और बाजार याखीं की भी कई योजनाएं थी। लघु मिचाई को छोड़कर अन्य उद्देण्यों के लिये 130 करोड़ रुपयों के वायदों से युक्त 499 याजनाथां को सजूरी दी गई जब कि पिछले वर्ष 56 करोड़ रुपयों के वायदों से युक्त 320 याजनाओं की मंजूरी दी गई थी। जून 1976 के अन्त में निगम के 2905 योजनाओं को मंजूरी दी है जिनके सन्दर्भ में पुनर्वित्त की राणि 1147 करोड़ रुपये थी।

334 1975-76 के दौरान पुनिवित्त की प्रधिकाश राणि (26.0 करोड़ रुपये) उत्तर प्रदेश को मिली, उसके बाद महाराष्ट्र (22.5 करोड़ रुपये), कर्नाटक तथा मध्यप्रदेश (प्रत्येक की राणि 19 कराड रुपये) का स्थान था। क्षेत्रवार दखने पर विनरित पुनिवित्त का 30.2 प्रतिशय दिक्षणी क्षेत्र के ान्दर्भ में पाया गया। उसके बाद मध्य क्षेत्र (21 6 प्रतिशत), उत्तरी क्षेत्र (21.0 प्रतिशत), पण्चिमी क्षेत्र (20.2 प्रतिशत) भ्रीर पूर्वी तथा पूर्वोत्तरी क्षेत्रों (7.0 प्रतिशत) का स्थान था।

# क्षेत्रीय भ्रसंतुलन

335. निगम ने समीक्षा के प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पण्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रवेश, जम्मू श्रीर कश्मीर, श्रमम तथा पूर्वात्तरी क्षेत्रों के दूसरे राज्यों को विशेष ध्यान की अपेक्षा करने वाले प्रपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया । विशेष प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ग्रीर बिहार राज्यो को इस वर्ष निगम के कूल पुनर्वित्त का 34.1 प्रतिशत प्राप्त हो सका। पश्चिम बगाल में भ्रन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की सोजनाओं के भीतर ग्रीर बाहर भारी राशि प्रदान करने का निश्चय किया गया। उडीसा मे 39 करोड रुपयों के निगम के वायका के कारण प्रगति और तीव होने की श्राशा है। विश्व बैंक द्वारा संप्रति बनाई जा रही 'पूर्वी खाद्याध परियोजना' से पण्चिम बंगाल, उड़ीसा, श्रमम श्रीर बिहार में भूमिगन जल स्त्रोंनो के उपयोग, सम्बन् अनेत्र विकास ग्रौर अनुसन्धान तथा व्यापकता जैसे क्षेत्रों में भारी निवेग किए जाने की परिकल्पना की गई है। जून 1976 के घन्त तक कम विकसित क्षेत्रों में 493 करोड़ रुपया के निगम के वायदों से यक्त 1083 योजनाम्मी को मजुरी दी गई थी। इनमें से वित्ताय सम्थामी ने 186.6 करोड़ ध्पयो की राशि निकाली है।

.336. क्र्रांष पुनिवित्त और विकास निगम अधिनियस को सिक्किम में भी लागू कर दिया गया है और उस राज्य सरकार का निगम से उपलब्ध पुनिवित्त स्विधाओं की सृजना दी गई है।

# छोडे कुषक विकास एजेंसी/सीमांत कुषक श्रीर कृषि श्रम एजेसी योजनाएं

337- जून 1976 के घन्न तक छोटे कृपक विकास/सीमान क्रयक धीर कृषि श्रम एजेशियों के धन्तर्गन मंजुर की गई योजनाधी की सन्या 158 थी जिनके सन्दर्भ में निगम के वायद की सांध 50 करोड़ रुपये थी। निगम ने इन योजनाम्मों के भ्रन्तर्गत प्रव तक 20 करोड़ रुपये विस्तिन्त किये हैं। किन्तु निगम ने इन योजनाम्मों के भ्रन्तर्गत 100 प्रतिमास पुर्नीयत प्रदान करने की भ्रपनी नीति का पुनरीक्षरा किया। भ्रपने विसीय साधनों की स्थिति भ्रौर भ्रन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखने हुए निगम ने इन योजनाम्मों के भ्रन्तर्गत 1 भ्रप्रैल, 1976 से केवल 90 प्रतिमत पुनर्वित भ्रदान करने का निण्चय किया है।

# एजेंसी द्वारा पूर्नीवत का वितरण

33% जब एजेमीबार देखते हैं, 1975-76 में निगम से उपलब्ध पुनिवित्त का स्रिधिकाण साग सूमि विकास बैंकों को मिलता रहा। उन बैंकों को प्राप्त राशि 99 1 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष वाणिज्य बैंकों को 70.8 करोड़ रुपये (कुल पुनिवित्त का 41.3 प्रतिशत) मिले। वाणिज्य बैंकों का पुनिवित्त कार्यक्रम से जो प्रक्रिकाधिक योगदान पाया गया है यह कृषि विकास के लिये प्रधिकत्तर मीथादी ऋण प्रदान करने के उनके प्रयासों तथा प्रधिक पुनिवित्त सुविधाधों की व्यवस्था करने के लिए निगम द्वारा किये गये प्रयासों का परिणाम है।

# ग्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/ग्रस्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भ्रौर विकास बैक की परियोजनाएं

339. इस वर्ष के दौरान विश्व बैंक समृह ने कृषि विकास के लिए श्रौर तीन परियोजनाओं अर्थान् समेकित कपास विकास परियोजना, श्राध्न प्रवेश सिचाई स्नौर सधन क्षेत्र विकास की मिश्र परियोजना स्नौर राष्ट्रीय वीज परियोजना को मंजूरी दी। समेकित कपास विकास परियोजना में कपास की उत्तम किस्मा के उत्पादन श्रीर उत्तम श्राधार बीजो के उत्पादन, प्रभिसंस्करण ग्रीर ग्रनुसन्धान सहित समेकित विकास की परिकल्पना की गई है। निगम में चुने गये क्षेत्रों में उत्तम किस्मों का कपास पैदा करने के लिए वाणिज्य/सहकारी बैको द्वारा कृषकों को ग्रन्पार्वाध ऋण प्रदान करने के निमित्त एक सौरामी ऋण निधि गठित की जाएगी। विशय बैक समृह ने ग्रंथ तक 25 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनके ग्रन्तर्गत कृषि नित्रेणों के लिए निगम द्वारा निधियां प्रदान की जा रही है। इन परियोजनाश्रां में 11 कृषि ऋण परियोजनाएं, 4 सघन क्षेत्र विकास परियोजनाएं, 3 डेरी विकास परियोजनाएं, 1 सेब प्रभिसंस्करण धौर विषणन परियाभना, । समेकित कपास विकास परियोजना और क्रिया पुनर्वित ग्रौर विकास निगम को दिये जाने वाले सामान्य ऋण की परि-योजना सम्मिलित है। 4 परियोजनाम्रों भर्यात् तराई बीज परियोजना, राष्ट्रीय बीज परियोजना, चम्बल संघन क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान) श्रीर ग्रांध्र प्रदेश सिचाई श्रीर सधन क्षेत्र विकास मिश्र परियोजना का वित्तपोषण प्रन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण ग्रीर विकास बैंक कर रहा है तथा णेप परियोजनात्रा की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा की जा रही है।

340. पिछने वर्ष की रिपोर्ट में कृषि पुनिश्रम और विकास निगम को प्रमार्गप्ट्रीय सब द्वारा खबु सिलाई प्रौर प्रस्य प्रमुमोदिस विभिन्न उद्देश्यों के निवेशों के खिये 750 लाख डालर ऋण मंजूर किये जाने का अल्लेख किया गया था। मंजूर की गई इस राशि में से मिगम के वायदों की राशि 264 करोड़ रुपये थी। जून 1976 के प्रंत तक विहासत राशि 24 करोड़ रुपयों की प्रत्याणित माना की तुसना मं 47 करोड़ रुपयें थी प्रौर निगम को जून 1976 के अन्त तक पूरे कार्यभ्रम को समाप्त करने की प्राणा है। निगम ने हैंक्टरों के लिये 35.7 करोड़ रुपयों का विलयोपण किया। इसके अलावा गुजरात धीर महाराष्ट्र कृषि ऋण परि-योजनाथों को भी कार्यान्तित किया गया है।

### महत्वपूर्ण मीति संबंधी निर्णय

341 निगम ने यह निश्चप किया कि गदम्ग बैंक विभिन्न राज्य बिजनी बार्डी को कुछो के विद्युतीकरण के लिये मीधे वित्त प्रदान करें। इस वित्त की माल्ला निगम द्वारा श्रनुमोदित लध सिचाई योजनाम्नों के अन्तर्गंत राज्य विजली बोर्डो हारा विद्युतीकृत पम्पसेटो की संख्या के अनुस्प होगी। इस प्रक्रिया में प्रामीण विजली निगम सीमित और प्रत्य एजेंसियों की योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ग्रामिल नहीं है। पहले निगम विनीय सस्थाओं को उनके हारा कृषकों को दिये गये ऐसे ऋणों के सम्बन्ध में जिनसे कि वे विद्युतीकरण के निये राज्य विजली बोर्डी में भ्रापनी जमा राशिया को रख सके, पुनविन्न उपलब्ध करना था। उपर्युक्त निर्णय में उक्त प्रक्रियों में प्रिवर्ग कर दिया गया है।

3.4.2. निगम ने राज्य भूमि विकास बैंका को मजूर की गई लधु मिचाई योजनाओं के लिये जारी किये जाने वाले विशेष विकास डिवेच्चरों में राज्य सरकारों के प्रणदान का प्रोत्माहन के रूप में कम कर 10 प्रतिणत कर देन का निज्जय किया है, जबकि दूसरे प्रकार की याजनाओं के लिये निर्धारित धणदान का प्रतिणत 25 था। छूपि विकास में लघु सिचाई कार्यक्रमा के महत्व को देखने हुए अगस्त 1967 में उपलब्ध हम रियायत का पाचवी पचवर्षीय याजना अवधि के अन्त तक अवधि 1978-79 तक बहा दिया गया है।

313. राघन क्षेत्र विकास के मन्दर्भ में परिकल्पिन एक समस्या ऐसे किसाना के विल्पापण के सन्दर्भ में श्री जिनका भूमि पर कोई वैध प्रधिकार नहीं था या जो सरक्षित काष्ट्रतकार थे या भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किये हुए थे। यदि पूरी सुविधा प्राप्त करनी है तो सघन क्षेत्र कार्यक्रम के भन्तर्गत पूरे क्षेत्र का विकास करने की भावण्यकता है और किसी भाग को छोड़ना नहीं चाहिये। अतः भारत सरकार पथा कृषि पुनविक्त और विकास निगम ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रपाल किसाना को विकास के लिये विन्त प्रवान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निगम ने विस्तृत सार्गवर्शी सिद्धान्त जारी किये है।

# कृषि पुनर्विस निगम प्रधिनियम में संशोधन

344 कृषि पुनर्वित निगम अधिनियम, 1963 में जो विभिन्न मणा-धन किये गये उन्हें ससद में जुलाई——अगस्त 1975 में पारित किया गया और वे सणोधन 15 नवस्त्रर, 1975 में अमल में आये। महत्वपूर्ण सणोधन निम्नप्रकार हैं: योग्य सस्था की परिभाषा को व्यापक बनाना, प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढाकर 100 करोड़ रुपये कर देना, उपहार, अनुवान और दान प्राप्त करने की अनुमति देना, बांड खरीदने और बेचने में सम्बन्धित वर्तमान उपबन्धों को संशोधित करना, भारत के भीतर और बाहर पूंजीगत वस्तुये खरीदने के लिये की जाने वाली आस्थितित अमानत में छूट देना। एक संशोधन के अनुमार निगम क येंकारी पूंजीगत निधियों पर भी पुन्यित की व्यवस्था कर सकता है। निगम ने संकित कई विकास परियोजना और रेशम उत्पादन योजनाओं जैसी चुनी हुई संमेकित विकास योजनाओं की कार्यकारी पूंजीगत निधियों के लिये भी पुनर्वित्र प्रदान करने का

#### प्रशिक्षण

3.45 प्रणिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुशा पर रूपि पुनर्वित्त ग्रीर विकास निगम को परामणं देने के लिये निगम के ग्रध्यक्ष की ग्रध्यक्षता में भारत सरकार, राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी स्था, भूमि विकास बैंक महासंघ ग्रीर वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एक समित गठित की गई है। उका नियम की ऋण परियोजना के एक श्रण के रूप में भूमि विकास बैंका श्रीर श्रत्य एजेमियों के लिये कृषि बींकम महाविद्यालय, पूणे में चार सप्ताह के प्रशिक्षण वार्यक्रम चलाये जा रहे है। ग्रब तक 10 कृषि परियोजना पाठ्यक्रम चलाये जा खुके है ग्रीर उनमें 305 कर्मचारियों ने भाग लिया है।

346 निगम ने राज्य भूमि त्रिकास बैंकों के प्रतिनिधियों की गहायता से भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण की श्रावण्यकताओं के सम्बन्ध में एक श्रष्ट्ययन पूरा किया।

#### कार्यशासा

317 राजस्थान, मध्य प्रवेण और कर्नाटक राज्यों में कार्यान्विन की जाने वाली डेरी विकास परियोजनाओं की क्रियाविधियों और परिचालन कार्यों पर उन परियोजनाओं में भाग लेने बाले बैंकों के अधिकारियों और दूसरी के लिये जयपुर, भोपाल और यंगलूर में अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये। विसम्बर 1975 के पहले स्पताह में एक परिचय कार्यणाला जयपुर में चनाई गई। इसका उद्देण्य अधिकारिया को कृषि विकास कार्यक्रमों के जिल्पोषण में निगम को भूगिका से अवगन करानाथा।

# म्रल्पाविध म्रौर यीर्घाविध सहकारी ऋण संस्थाम्रो के समेकन की संभावना का म्रध्ययन करने के लिए समिति

318 श्रलाविधि और दीर्गायधी सहकारी ऋण मस्वाश्रों का समिकित करने की सभावना का श्रध्ययन करने के लिये रिजर्व बैंक ने उपगवर्नर की श्रध्यक्षना में एक समिति गठिन की। इस समिति का सिव्यालय कृषि पुनविक्त और विकास निगम स है और समिति का कार्य आर्ग है।

# भूमि विकास बैंकों के डिबेंचरों के लिए मानदण्ड

3.49 भूमि विकास बैंका के विचीय कार्य को प्रवित्ति करन प्रीर सभी भूमि विकास बैंको के डिबेचर जारी करने के लिये रिजर्थ बैंक द्वारा एक स्थाई समिति गठित की गई है। यह समिति सभी भूमि विकास के बैंको के डिबेचर जारी किये जाने की प्रोक्षाप्रा प्रीर ऐसी प्रभक्षायों को कार्यान्वित करने के लिये प्रत्यिक सक्षम प्रणालियों का भी प्रध्ययन करेगी। इस समिति के विचार-विमर्ण के प्राधार पर भूमि विकास बैंकी के ऋण कार्यक्रम को विनियमित करने के लिये प्रतिवेय राणियों के सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों में कतिपय रियायने राज्य भूमि विकास बैंकी को थी गई है, जिसमें कि 1975-76 के दौरान उन्हें स्वीकुश ऋणा की प्रवित्तित किश्ती के लिये लागू किया जा गके।

### IV औद्योगिक वित्त की गतिविधियां

350. औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में 1975-76 के दौरान मीयादी ऋण देनेवाली सम्बाक्षा द्वारा मजूर की गई प्रौर वितरित की गई विश्लीय सहायता में ग्रीर वृद्धि पाई गई। 1975-76 के वित्तीय वर्ष के दौरान मजूर की गई कुल सहायता की राणि जहा 1974-75 के 498 8 करोड़ रूप ग्रामें बढ़कर 589 9 करोड़ रूपए हा गई बहा उनके द्वारा विलिय की गई महायता की राणि 1974-75 के 363 3 करोड़ रूपयों से बढ़कर 1975-76 में 400 6 करोड़ रूपयें हो गई (सारणी 29)। मंजूर की गई प्रौर वितरित की गई कुल सहायता में हुई प्रश्लिकाण वृद्धि भारतीय प्रौदांगिक विकास बैक (भार प्रौर विवर्ताय विकास बैक (भार प्रौर गई।

351 श्रामें के पृष्टों में भार श्रीरु विश्वेक, राज्य विसीय निममो तथा भारतीय यानिट ट्रस्ट जैसी सस्थाओं क्षारा दिये गये ऋणों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। इस श्रद्ध्याय के श्रन्त में गैर बैंकिंग कम्मानियों के बित्त के सम्बन्ध में चर्चा की गई है।

# भारतीय श्रोद्योगिक विकास बंक

352 णिखर विभीय सरा। के रूप में भा० ग्री० वि० वैक की सूमिका को व्यापक बनाने तथा देण में नियत सभी विनीय सरवाश्रों के बीच श्रधिक सफल समन्वयन लाने के उद्देश्य में 16 फरवरी 1976, में भा० ग्री० वि० कैक की भारतीय रिजर्व बैक से श्रमस्बद्ध कर विया गया तथा उसे भारत सरकार द्वारा स्वाधिकृत स्वायत्त निगम बना दिया गया।

353 छोट श्रीर नयं उद्यमिया का नया दण व श्रिअभावत कम विकसित क्षेत्रा में स्थित उद्यमा को महायता परान करन के निमित्त बनाये गये कार्यक्रमा, देणी टक्कीलोजी का प्रयत्म करन वाली तथा अधिर राजपार की अमत,युक्त परियोजनात्रा, विदेणी मुद्रा श्रीजित करन वाली या उसकी बचत करने वाली परियोजनाश्चा तथा अधिक विकास के निमित्त राष्ट्रीय कार्यक्रमा में पार्थिमकता प्राप्त दूसरी मारो परियोजनाश्चा पर भार श्रीर विर बैंक निकट भवित्य में जीर देगा।

151 इन प्राथिमकता प्राप्त क्षत्रा का फ्राब्यस्य गहायता उपलब्ध करान के निमल भाव श्रीव बिव वैक के महल न श्रमम्बध्द क्षिये जाने परहुई श्रामी पहला बैठक में बैक के कायकलापों का भाग माला में विकर्त्वाकरण ि ।। इन परिवर्तना नया शक्ति के प्रत्यावनेन के साथ भाव श्रीव विव वैव व कोनीय तथा शाखा कार्यालया की छाटे नथा छोटे मझौले ग्रीनटा को श्राक्षाश्रा की पूनि करन के लिये पूरी शक्ति होगी।

455 भा० श्रो० वि० वैक के प्रधान कार्यालय में सगठन विन्यास को भी पुनव्यवस्थित किया गया है। इस सन्वर्भ में भा० श्री० वि० वैक की विपानिविध्यों में सब्धित नरीसहम समिति तथा मीयादी निर्यात विनयापण में सम्बन्धित कुमार सभिति को सिफारिणा में भा० श्री० वि० वैक का काफी लाम पहुंचा है। बैक के प्रमुख कायी तथा परिचालना को क्षा अनग सक्या श्रियति देशा विस्त स्कन्ध श्रीर श्रन्तरीष्ट्रीय विस्त स्कन्ध को सोपा स्वार्थी है।

350 सा० प्रां० वि० बैंक तथा उसके संगठन ।वन्यास के पुनर्गठन व बाद भा० प्रो० वि० बैंक न विश्वित्र नये कार्य प्रारम्भ किय है। राज्य प्रोद्योगिक विकास निगमा को भा० प्रो० वि० बैंक के सार्थक्षत्र क प्रन्तान लाया गया नाकि इन एजिंगिया के माध्यम से विश्वय रूप से पिछंडे हुए क्षत्रा में परियोजनाध्या को स्थापित करने के लिये प्रान्याहित कर सन्तृतित के के किया जाये। इस उद्देश्य में कि नवनीशान नथा नये उद्यमकर्ता अपने से प्रविश्व किया जाये। इस उद्देश्य में कि नवनीशान नथा नये उद्यमकर्ता अपने से प्रविश्व के स्थापित कर सके भा० प्रौ० वि० बैंक प्रत्यक्ष रूप में महायना प्राप्त परियोजनाध्या के मम्बन्ध में इस प्रकार का एक योजना प्रारम्भ करने के बिनार कर रहा है। जा राज्य स्तरीय एजेंसिया ।कराया खरीद के प्रायार पर मंगीना की पृति करता है उन्ह रियायनी दरा पर विनीय मुविधाय प्रकार करने

की एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। पुनीबन तथा हुई। पुनर्भ्नाई याजनाध्रा के धन्तर्भन सडक परिवहन चालको को दी आनेवासी सहायता का भी उदार बनागा जा रहा है।

### विदेशी ऋण सहायता

357 राज्य विलीय निगमा को ऋण प्रदान करने कि लिये प्रत्नर्राष्ट्रीय विलाग मध म जून 197 । में 250 लाख अमिरिकी डालरों की जा पहली अहणिरिंग्न प्रदान को गई थी उसका मार्च 1976 नक पूर्ण रूप में उपयोग विया गया। इस बाय म प्रोत्मारित हाकर विश्व बैंक न 400 लाख प्रमेरिकी इंग्लरों का एक श्रीर ऋण प्रदान करना स्वीक्षर किया है तथा इस मन्दर्भ में बातचीन पूरों हो चुकी है। इस प्रकार भाव श्रीव विव बैंक अब छोट तथा महीले आतार वालो प्रियागनाश्री की विदेणा मुद्रा सम्बन्धी आंक्षांश्रा को पूर्व राज्य विसीय निगमा की एजिसयों के माध्यम में बहतर कम में कर सक्या।

15९ गैर सरकारी सेव की उर्वरक-परियाजनामा का उनके माधु-निकीषरण सन्तुलन-उपकरणा के क्रय मादि के लिये महायता प्रदान करने के निमित्त मन्तर्राष्ट्रीय यिकास सच ने दिसम्बर 1975 में साथ म्री० वि० वैक को 240 लाख डालरा का एक मौर ऋण भी प्रदान किया है। सार्वजनिक तथा सथुक्त केन्ना की मसौल श्राकार को पारयोजनामा (श्रयीत जिनकी अचन श्रास्त्रिया 20 करोड रुपयो नक को है) की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी भाभाग्री की पूर्ति करने के निमित्त एक और ऋण प्राप्त करने के लिये भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सथ के साथ वातनाम हो रही है।

### विकासपरक कार्यकलाप

45.9 सांव श्रीव विव र्थन के पुनगाटन श्रिन्यास का एक दूसरा महत्व-पूर्ण पहलू यह है कि (पछड़े क्षेत्रा में श्रीचारिक विकास की महायता करन ने निमित्त क्षेत्रीय विकास स्वन्य का निर्माण किया गया, चारो क्षेत्रीय कार्यालयों में इस क्षत्रीय विकास के नक्ष स्थापित किये गये हैं। इस विकास रक्ष्य ने श्राध्य प्रदेश गृजरात हिमाचन प्रदेश जस्म् श्रीर काश्मीर, उद्योग, राजस्थान श्रीर उत्तर प्रदेश में परामर्ण मगटन गटित करने का काय प्रारम्भ किया है।

सारणी 29 . 1974-75 स्रीर 1975-76 (स्रप्रैय-मार्ख) के बीरान मीबाबी ऋण प्रवान करने वाली विसीय संस्थास्रो द्वारा मंजूर को गयी स्रोर बितरित की गयी महायता

								(राजि	शांकराड कः	ायाम)
	मज्र की गई सहायता									<u> </u>
	—- रुपया ऋण		विदणी मुद्राऋण		 हामीदारी और प्रत्यक्ष श्रमिवान   +			- —— —— —— সাত্ত		
					,— ——— सामान्य श्लीर		 डिये <b>भ</b> र			
		1975-	- 7 5	1975-76	197 <b>1-</b> 75	1975-76	1974-75	1975-7	76 1974-7	 5 1975 <b>-</b> 76
- भारनीय <b>ग्रौद्या</b> गिक विकास			_		_					
र्बेक		153 76 (IIU 11)			6 00	7 25	3 00		223 83° (62 55)	261.01* (110.41)
भारतीय घोषागिक विच		,							( = / )	1110.41)
निगम .	22 22	42 91	3 52	1 45	3.50	3 61	~~~	1 00	29 1	52 50
भारतीय श्रीद्यागिक ऋण श्रीर निषेण निगम .	16-00	20 13	11 29\$	45 20 <b>\$</b>	s 17	6 05	1 50	6 57	(2.86	7 n 55
भारतीय श्रीद्यागित पुन निर्माण निगम ^{सभ}	7 59	7 17		_					7.50	5.27
राज्य विनीय निगम ^{ास न}	132 61	142 87	8 63	1, 34	0 55	0 2)	_		111 79	15 50
राज्य प्रोक्सासिय विन						_			111 77	111 30
निगम ^भ	21 31	28 00	<u> </u>		12 16	9 00			33 50	17.00
जाउ.	(6 1 59 (6 1 55)	19 + 27 (110 - 11)	5 , 11	62 19	77 95	26 20	1 50	7 47	195 51	589 83 (110 11)
भारतीय पुनिट दृश्य					3 18	2 0 1	_{1 7 4}	 5 75	<u> </u>	7 79
जीवन बीमा निर्गम 🚟 🖰	21 22	30 53			5 57	5 79	17 01		43 80	63 97

# सारणी 29 (जारी)

	जिनरिन की गई सहायता										
	रुपया ऋण <del> </del> -		विवेणी मुद्रा ऋण		हामीदारी ग्रौर प्रत्यक्ष भ्रभिदान				जोड़		
				•	सामान्य भौर	म्रिधमान <b>गे</b> यर	<u>डिबें</u> चर	- <del></del> -	•		
	1974-75	1975-76	1974-75	1975-76	1974-75	1975-76	1974-75	1975-	-76 197 <del>4</del> 75	1975-76	
—————————————————————————————————————							· - <del></del>		-		
<b>बै</b> क	163,85	* 169.49* (59,48)			1 72	5.24	0,99	0.21	166,56* (35,09)	(74 97 (59.48)	
भारतीय श्रौद्योगिक वित्त निगम	32.50	30.18	3.48	2,47	0.83	1.99	0.14	_	36 95	34.64	
भारतीय श्रीकोगिक ऋण स्रौर निवेश निगम .	13.71	16.31	29.09\$	J9, 95 <b>\$</b>	1.82	3.54	0.77	1.32	15 39	61.12	
भारतीय भौधोगिक पुन- र्निर्माण निगम**	8 05	4.73				_	_	_	8.05	4.73	
राज्य वित्तीय निगम*** राज्य श्रीबोगिक वित्त निगम	77 40  ***19.85	93.90 $21.84$	2.02	4.59	0.21 6.87	0 28 4.56	_	0.03	79 63 26 72	98.80 $26.40$	
जोड़	315.36 (35.09)	336.45 (59.48)	34.59	17.01	11.45	15.61	1.90	1.59	363.30 (35.09)	<b>4</b> 00.66 (59.48)	
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	<del></del>		<del></del>		1,69	2.71	5.87	2.20	7.58	4.91	
जीवन बीमा निगम***.	43.79	22.82		_	4.63	4.52	5 69	0.15	54.11	27.49	

^{*}इसमें प्रत्यक्ष ऋष (विभिन्न विदेशी ऋषों महित), बैंकों को प्रदान किया गया पुनर्वित्त तथा पुनर्भुनाई शामिल है। राज्य वित्तीय निगमों को प्रदान किये गये पुनर्वित्त को कोष्ठकों में भ्रमण से वर्शाया गया है भ्रौर उसे कुहरे संगणन से बचने के लिये इसमें शामिल नही किया गया है क्योंकि राज्य वित्तीय निगमों के ऋणों में उसे जोड़ विया गया है। परन्तु इसकी स्थापना से लेकर श्रोकड़ों में राज्य वित्तीय निगमों को प्रदत्त पुनर्वित्त सम्मिलत है।

# ***ग्रांकड़े श्रमंतिम है।

- 🕂 इसमें गारिटयों के कारण यदि कोई वितरण किये गये हो तो उन्हें सम्मिलित किया गया है।
- 🕂 🕂 इसमे पक्के श्राबटन तथा ग्रधिकार शेयर सम्मिलित हैं।

\$1974-75 के विदेशी मुद्रा के भांकड़े 31 विसम्बर 1971 को निखमान विवेशी मुद्रा की केन्द्रीय दरो पर दिये गये हैं।

360. भालोज्य अविधि के बौरान अण्डमान और निकोबार बीपसमूहों की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाणित की गई। इस प्रकार सारे 18 प्रधिसूचित पिछड़े राज्यों/संखणासित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है तथा उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाणित हो चुकी है। यह भी निश्चय किया गया है कि सिक्किम की औद्योगिक संभाव्यता का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जाये; उक्त राज्य सर्व्यार के अधिकारियों के साथ शीष्ट्रा ही प्रारम्भिक विवार-विमणे होने वाले हैं।

361. जून, 1975 में महाराष्ट्र में अन्तर संस्थागन दल की गठन हान के बाद अब देश के 17 राज्यों में अन्तर संस्थागन दल कार्य कर रहे हैं। अधिकांश अन्तर संस्थागन दल विभिन्न राज्य स्तरीय सगठनों के प्रयासा को समित्वित करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के निमित्त एक प्रभावी तन्त्र का निर्माण करने में सफल हुए है।

362. संयुक्त सस्थागत ग्रध्ययन यलों ने कुल मिलाकर लगमग 2800 करोड़ रुपयों के कुल निवेशयुक्त 483 परियोजनाओं का पता लगाया था। इतमें दिसम्बर, 1975 के प्रन्त नक लगभग 285 कराड़ रूपयों के निवेशयुक्त 78 परियोजनाएं या तो कार्योन्विन की जा चुकी है या कार्यान्वित की जा रही है। संयुक्त संस्थागत प्रध्ययन दलां तथा राज्य अन्तर संस्थागत दलों द्वारा सिफारिण की गई सुस्पष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य स्तरीय एजें सियों/राज्य सरकारों के कार्य पर भा० श्री० वि० बैंक बराबर ध्यान रखाना रहा तथा हमारे कार्यान्यों को इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में श्रागे कार्रवाई करने के लिये सूचित किया गया है।

### भा० ग्रौ० वि० वैक के कार्यकलाय

363. भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंगूर की गई तथा विकस्ति की गई राणि की बृद्धि को देखने पर 1975-76 के दौरान भा० औ० वि० बैंक का कार्य काफी सन्तोषजनक पाया गया। 1975-76 के दौरान कुल प्रभावी मंगूरियों की राणि 170 7 करोड़ रुपये थी अब कि उक्त राणि 1974-75 में 339 6 करोड़ रुपये थी (सारणी 30)। मंगूर किये गये

^{**}इसमें मंजूर की गई गारटियों की राणि शामिल है।

सारणी 30 : 1974-75 ग्रीर 1975-76 (जुलाई-जून) के दौरान तथा ग्रयनी स्थापना से लेकर ग्रव तक भा० ग्री० वि० वैंक द्वारा मंजूर को गयी सहायता की राशि तथा सहायता प्राप्त संस्थाग्री द्वारा प्रयुक्त राशि

(राशि करोड़ रुपया में)

—		मजूर की गई महायना प्रयुक्त सहायना प्रयुक्त सहायना								
		1974-75		1975-70		नुपाई 1964 से जून 1976 मन		1974-75	1975 76 जुलाई 1961 से जून 1976 सक	
	-	_ स <b>०</b>	गमि		राधि	 ·	— गर्मा गर्मि	 राशि	— - राणि	राशि
_	1	2	З	4	5	6	7	8	9	10
- I	- भ्रीसोगिक सस्थात्रो को विये गर्ये प्रत्यक्ष ऋण (निर्यानी									
	के लिये दिये गये ऋणी को									
	को छोडवर) .	51	69 6	97	105.6	110	530 1	40 3	48 7	260,3
	,	(51)	(67 1)	(96)	(101.3)	(376)	(136.9)	10 0		, _
2	<b>प्रौद्यो</b> गिक सस्थाओं के	,	, ,	` • ′	, ,	, ,	, ,			
	शेयरो ग्रौर डिक्वचरो की									
	हाभीदार तथा उनमे प्रत्यक्ष									
	म्रभिदान .	39	11 2	53	12 2	286	98 0	2 3	6.8	10 <b>2</b>
		(99)	(11 2)	(52)	(12,1)	(265)	(76 9)			
3	श्रीद्योगिक ऋणो का पुन-									
	विस .	6453	107 9	9255	180 7	25842	537 1	52 4	102 5	349. <b>7</b>
		(5777)	(964)	(8932)	(174 1)	(23917)	(482 4)			
4	हुडियो की पुनर्भुनाई	1062	114 4	951	120 8	2819	196 5	91 7	91.7	404 A
	,	(1062)	(114 4)	(951)	(120 8)	(2819)	(496 5)			
5.	वित्तीय सम्याम्रो के शेयरो									
	तथा आ डो में भ्रमिवान	10	6 6	21	16 1	24	71 7	7 3	14,2	68.9
		(10)	(е ь)	(21)	(16.4)	(24)	(717)			
कुल	परियोजना सहायता (1 से									
_	उतक) .	7615	309.6	10377	435.7	30381	1733.6	194,1	263.8	1124.0
	•	(6939)	(295.6)	(10052)	(427.9)	(27431)	(1564.8)			
e	— निर्यातो के लिये दिये			- ' - '	_ `	, ,				
Ü	गए प्रश्यक्ष ऋण	8	15 9	17	30 4	77	105 4	4 5	13 7	54 0
	13 21 441 16 1	(7)	(15 6)	(16)	(29 8)	(73)	(93.8)	7 /	.,,	04 0
7	निर्यात ऋणो का पुनर्विस	28	17 9	15	5 3	103	54 6	9 4	8 6	43,2
,	1940 954 10 3040	(26)	(15 9)	(15)	(53)	(96)	(47.9)	σ,	0 0	47, 2
8	विदेशी खरीदारों के ऋण	2	5 0	3	8 6	5	13.6	_	0 3	0.3
•		(2)	(4.5)	(3)	(77)	(5)	(12.2)			***
9	विभिन्न विदेशी ऋण	3	8.0			6	25.5	3.1	5.2	8.3
		(3)	(8 0)			( b)	(20.5)			
_	_									
1 से	9 तक का जोड़	7656	356.4	10412	480.0	30572	1932.7	211.7	291.6	1229.7
		(6977)	(339.6)	(10086)	(470.7)	(27611)	(1739.2)			
10	— ऋणो तथा भ्रास्थगित									
	ग्रदायगियों के लिये गारंटिया					19	64.6			
			-		_	(15)	(26.7)			19.5*
11	निर्यात गारंटिया	1	0 4	4	2,4	8	4 7		2.9	
		(1)	(0 4)							

टिप्पणिया (1) श्रांकडे युल मजूरियों से सर्वाधन है, प्रभावी मंत्र्रियों के ग्रांकडे कोठकों में दर्शाये गये हैं।

⁽८) मव 4 के सन्दर्भ में श्रापेदनपत्नो की संख्या खरी**दार-उपयोगकर्नाश्रो से संबंधित है तथा मद 5 के सन्दर्भ मे वित्तीय संस्था**श्रो की शख्या में सर्वाधन है।

^{*}निष्पादित गार्रीटयो ।

यार्थदनपता का राष्ट्राः ।) । / के । ), से प्रवस्य ।। -१० ना म । प्रेम्पर सनामना को राणि ।। , । राप रुपयो के मुक्ताक्षके ()75-70 में १९) ( क्लाइ क्ष्मय थी जा तमभग ४ प्रतिशत यृद्धि का धानक था। श्रीद्यागिक ऋणा व प्रतिवस के श्रन्तगत मित्र का गए राणि से ५। पतिणित का बंदात्रा हुई थीर पहें करा १ ) ८ ४-७० म ५७७) प्रावन्ते (त्र) र संदर्भ म १७ । संगर्न सा से सेही श्रीताच्य वर्ष भे प्रकार । ३ - ग्रायदनात्वा व सन्दर्भ म । ७ । वरार रुपये हो गई। मजुर किस गय पूर्नीवेल में में मन्य की दृष्टि से तराभग 64 प्रतिशत प्रणातथा प्रावदनपत्ना की सख्या की दृष्टि से लगभग ५१ प्रतिप्रात भ्राण तथ उद्योगो एव छाट सङ्क पश्चिष्टत चातको र सन्दर्भ म था। मार्भ्यी० थि० बैक द्वारा प्रुडियो को पूनमुनाई के जिया ५०। खरीदवार उपथागवर्ताम्रा ४ सम्बन्ध में मंजर को गई 120 ५ करोड़ कपया की राशि 1974-75 के दौरान 1062 खरोददार उपयोगक निधा के सम्बन्ध में मजर की गई। 114 4 करोड़ क्षयों की राणि की तुलनामें प्रतिमत अधिक थां । निर्यात विसे योजनीयां के ब्रन्तशत दी गई मजुरियां की 42 8 कराज रुपयों की राशि 1974 75 ने 44 0 कराज रुपयों की तूरना में सोमोन रूप से कम थी जब कि वितरणा को राणि 1974-75 में 17 5 क्यार अपया से बढ़कर 1975 76 में 27 5 क्यार अपरे हो गई। मा श्री० यि० पैत्र को स्थापना में लपर जून 1776 के श्रीत तक को कृत प्रभावी मज़रियों को राणि 13-4 तराड रूपया की गार्गटया को छोडकर 1739 2 करोड स्पय थी जब कि प्रेयुक्त सहायता की कुल राणि 12=9 7 क्रांट क्पयेथी।

364 माठ श्री० वि० बैन हारा परियाजनाश्चा ने लिये मशर की गर्ड प्रत्यक्ष महायता की राणि 1975 76 के दौरान 108 परियोजनाश्चा के मन्दर्भ मे 116 1 करोड रुपय थी जो 1971-75 मे 66 परियोजनाश्चा के मन्दर्भ मे 116 1 करोड रुपय थी जो 1971-75 मे 66 परियोजनाश्चा के मन्दर्भ में मजर किय गये 78 3 करोड रुपयों की मुलना में उन्तंखनीय रूप में अधिक थी। मजर को गर्ड गरीयता का ९७ प्रतिणत श्रण नर्ड परियाजनाश्चा क रूप में नर्ड क्षमता स्वापित रुपत या वसमान युनिया रे विम्तार/दिशानरण के लिय दिया गयो था। गहायता का लगभग 61 प्रतिणत श्रण मावजनिक सयुक्त या सहसारों थान की परियाजनाश्चा के मन्दर्भ में था। यदि उद्योगवार देखा जीप तो महायता हा 15 प्रतिशत श्रण 5 श्रयश्चा पाथमियता प्राप्त उद्योगों श्रयात उवरक गीमर कागण कोना श्रीर वस्त्र के उद्योगों को दिया गया था। रूपके श्रवाया महायता प्राप्त 108 परियोजनाश्चा में भे 8 परियोजनाय तकनीणयन उद्योगिया द्वारा प्रवित्त था तथा २8 परियोजनाय पिछड क्षेत्रों की थी। 55 9 करोड रुपयों की प्रत्यक्ष परियोजना महायता निर्विट पिछक जिला में स्थिन युनियों के लिये रियायती शर्ती एर मजूर की गर्छ।

### पिछड़ क्षेत्रो को सहायता

365 निर्देष्ट पिछर जिलां/क्षत्रा में स्थित यूनिटा का मा० श्रौ० वि० बैंक में प्राप्त सहायता की राणि में भी 1975-76 वे दौरान उत्तरखनीय बृद्धि पाई गई। आतोच्य वर्ष के दौरान रियायती शर्तों पर प्रत्यक्ष सहायता तथा श्रौचोगिक ऋणा के पुनिबन्त क रूप में दो गई सहायता ना बृद राणि 1195 निराह रूपय थी जब कि उन्तराणि 1974-75 में 59 7 बरोड रूपय थीं इस प्रकार रियायता जिली पर मजर का गई बुल सहायता नी राणि बद्धर जन 1976 के भ्रना तर 257 9 करोड रुपय हो गई।

#### शेवरो और बांडो मे श्रामवान

366 म्रालाच्य वर्ष के दौरान भारतीय भौश्विववैन न भारतीय मौद्योगिक ऋण भौर निवंश निगम के दिवलों के विशेष निगम में 1 7 वराइ रूपया का अभियान विया। इसके साथ भारतीय भौद्योगित ऋण भौर निज्ञण निगम के रिश्वाम के उत्तर जून 1771 के अन्त कर उसे प्राप्त मां आंश विश्व वैके का कुन क्षाया की राणि 1, 7 कराइ रूपय हा गई। उक्त निगम द्वारा पहन नियं गय ऋणां की विस्ता के स्प में

नगर गर । र गण स्था व या। भा यो वि दे हैं हारा ग्रांचित । भित्तरा ना राण का 197 ते प्रांचे गरे पे उपांचे स्पर्य र गर्दे। साथ हा भा अर्थ कि देने । पालाच्य वेग के दोरान राण विक्तिय निर्मा की अपर पत्री में ३ ५ रराक स्पया ना प्रमिदान निया। इसके प्रताया राज्य वित्तीय निर्मा । जारा गरिवर्ष दे राग ग्रांचित ३ १ क्षेत्र स्पर्य को ज्यरा का (विश्वा पृज्ञान अ्थरा मांचि) । ए फरवरी 1976 का माठ गांवि वैन न अपन अधिकार में वित्रा। भारतीय यनित हरते वी प्राराम्भक यूनित प्रती में भारतीय रिजर्व बैक द्वारा धारिन ३ ० वराड स्पर्या के अपना को मी नाठ ग्रीव विठ वैक ने 16 फरवरी 1976 को प्रपत्त प्रतिकार में ने निया।

#### भा० भी० वि० बैंक की ब्याज बरो का विश्यास

167 प्रालाभ्य वर्ष के दौरान मु० प्रौ० वि० वै। के व्याज दूर विल्याम में मशोधन किया गया। 1 दिनस्वर 1075 में प्रमृत में प्रायी गर्गाधिम प्राज दर प्रानबस्ध में दी गई है।

### सार्वजनिक विन्नीय सस्था विधि (संशोधन) ग्रिधिनियम 1975

३(९ 16 परवर्ग 1976 से सावजितक विलीय समा विद्वि (गणी-धा) प्रशिनियम 1975 के प्रमन में प्रान के साथ ही भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा राज्य किलीय निगमा की पृत्तों से प्रारंग भारतीय निगमी का बैंक को अन्तरित रूप दिया गया है। ग्रब तक राज्य किलीय निगमा का पर्यवक्षण जहां रिजर्ब बैंक करणा रहा बला भारु श्रीर विश्व के करेगा। कर्द्वीय बैंक्ग प्राधिवरण के रूप में राज्य विलीय निगमा के उपारों धादि के सब्ध में रिजर्ब बैंक द्वारा जा किलीय कार्य किया जाता रहा उसे रिजर्ब बैंक श्रांग भी भारु श्रीरु वि बैंक के परामण में करना रहेगा। इस निगमा के महला में नामित अपने निकेशकों के होए। तथा इन निगमा द्वारा प्रस्तुत को जानवाली विभिन्न माथिधिक विवरणियों के श्रीधार पर रिजर्ब बैंक उनना श्रमति तथा उनके कार्यक्लाणों के स्थाप में भी जान-कारी पाल करना रहेगा।

### राज्य विलीय निगमो के कार्यकलाप

उठ। तिमाननार स्रौद्धारित निवेश निगम सिंहत । ८ राज्य विजीय निगमा के प्रायमनाथा से 1975 76 (स्प्रीन—माच) के दौरान स्रौर प्रगति पायी गयी। माच 1976 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान इन निगमा द्वारा मगुर किय गये कुल ऋणों की राणि 152 । करोड रुपये थी का पिछन वर्ष के 137 6 करोड रुपया की नुलना में उच्चतर थी। 1975 76 व विकीय व्या के दौरान 99 5 करोड रुपया के जा वितरण क्ये गये व भी पिछन वर्ष (79 9 करोड रुपय) की नुलना में बाकी स्रिधिक थे। विवास ऋणा नी राणि माच 1976 के स्रन्त में 363 8 करोड रुपये थी जा एक वर्ष पहले के स्वरं की नुलना में 81 । करोड रुपयों को एक वर्ष पहले के स्वरं की नुलना में 81 । करोड रुपयों को बृद्धि स्वानक थी। विनीय सहायता रा स्रिप्तकाण भाग नघु उद्याग की कि स्वानक थी। विनीय नहायता रा स्रिप्तकाण भाग नघु उद्याग की का प्रदान किया जाता रहा तथा इस प्रकार में नर की गया 102 5 करोड रुपयों को सहायता मजर को गयी बुन ऋण राणि (738 5 बरोड रुपय) रा 51 5 प्रतिणत थी।

# लघु उद्योगो का विस्पोषरण ऋण गारटो योजना का उदारीकरण

370 भारत सरनार की ग्रांर से भारतीय रिजय बैंक द्वारा लघु उद्यागा के तिए चलाया जान बाना ऋण गरिन्टा योचा के लायक्षेत्र को ग्रालाच्य क्या व धैरान राष्ट्रा यापत बनाया गया। 10 मितस्वर 1075 से लघु उद्याग यिन्टा की परिभाषा का सणाधित किया गया तथा ऋण गरिन्टी गाचा के प्याजन र किए रिश्वा योग सणीना में निज्ञण का गर्या राण्य का सीमा का 75 चित्र रिप्ता योग सर्वाचर 10 ताक्ष रुपय कर दिया गया। उस याजना का स्विधाया का 1 प्रभेल 1976 से उने सहायक सीद्यागिक यून्टा के तिए सो ताम हिया गया

जिन्होंने मणीनों प्रौर सयतों में 15 लाख कायों तक तिवेश किये थे तथा जा (क) पुनौ, घटका, उप पुनौ, ग्रीजारां या मध्यवर्णी यस्तुओं के निर्माण नार्य स लगे है, या (ख) ग्रम्य वस्तुओं के उत्पादन के निर्मित्त हुसरे यूनिटो को सेवाए प्रदान करने हैं भीर अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत तथा कुल सेवाएं यथास्थिति प्रदान करते हैं, या प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं। परन्तु ऐसा प्रतिष्ठान किसी श्रस्य प्रतिष्ठान का सहायक या उसके द्वारा स्वाधिकृत या नियन्नित नही होगा। परन्तु जिस सहायक प्रौद्योगिक यूनिट के संयन्नों ग्रीर मशीनों मे 10 लाख कायों में श्रिक श्रीर 15 लाख कपयों तक निवेश किये गये हों उन्हें उखित सरकारी प्राधिकारियों से सहायक यूनिट के रूप में ग्रपनी हैसियन के संबंध में प्रमाणपन्न प्राप्त करना होगा।

### पात्र संस्थाएं

371 इस योजना के अन्तर्गत मुशिक्षाण प्राप्त करने के लिए पाल ऋण सस्थाओं की संख्या जून 1975 के अन्त में स्थित 609 में बद्कर जून 1976 के अन्त में 628 हो गयी जिसका प्रमुख कारण यह था कि लाइमें गीकृत न हुए 17 प्राथमिक (णहरी) सहकारी बैंको को अनुमोदित सूची में सिमिलित किया गया। योजना में गहभागी होनेवाली सस्थाओं की कुल संख्या 217 से बद्धकर श्राप्ताच्य श्रवधि के दौरान 233 हो गयी। सरकार ने श्रव गाजना के खड़ 2(ग) के अन्तर्गत निर्दिष्ट ऋण मस्थाओं की सूची में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंका का सिम्मिलित करने की श्रनुमित प्रदान की है।

#### ऋण गारंटी योजना की प्रगति

372 बकाया गारंटियो की जो राणि जून 1971 के ग्रन्त मे 1497 करोड़ रुपये थी यह जून 1975 के अन्त में बढ़कर 1726 करोड़ रुपये भौर जून 1976 के भ्रन्त में भौर बढ़कर 1950 करोड़ रुपये हो गयी जो लघु उद्योग क्षेत्र को प्राप्त संस्थागत ऋण की राणि में हुई क्षमिक वृद्धि की ग्रोनक थी। जून 1975 के प्रन्त मे विद्यमान बकाया गारंटियो की राशि का उद्योगवार विक्लेषण करने में यह विदिन होता है कि खाद्यानो के निर्माता उद्योगो को सर्वाधिक गारटियो (12.7 प्रतिशत) दी गयी , उसके बाद वस्त्र उद्योग (10.9 प्रतिगत), श्रातु उत्पाद उद्योग (१०.८ प्रतिशत), रासायनिक उत्पाद उद्योग (८.४ प्रतिशत), बिजली की मशीनों तथा उपकरणों के उन्नोगों (6.8 प्रतिशत), बिजली की मणीनों को छोड़कर भन्य मणीना के निर्माण के उन्नोगो (6.5 प्रति-शान) तथा मूल घातु उद्योगों (5.3 प्रतिशत) का स्थान था। इस योजना के प्रारम्भ से लेकर जून 1976 के घन्त तक 1201 यूनिटों के संदर्भ मे 170.1 लाख रायों के दावों की श्रदायगी की गयी है; इनमें से जुलाई 1975 में जुन 1976 तक की श्रवधि के दौरान की गयी श्रदाय-गियों की राशि 280 यृनिटो के संदर्भ में 42.2 लाख रुपये थी। दाबो के रूप में श्रदा किये गये कुल 170.1 लाखा रुपयों में से 34.3 लाखा रुपयों की राणि वसूल कर ली गयी है, इस प्रकार ग्रदा किये गये वाबों की शुद्ध राशि जून 1976 के श्रन्त में 135.9 लाख रुपये रह गयी। इम्हण न चुकाने वाले यूनिटो की सख्या मई 1976 के ग्रन्त मे 12264 थी नथा उनसे संबन्धिन राणि 57.8 करोड़ रुपये थी ; कुल बकाया गार्रिटयों की राशि में उनका श्रण 3 0 प्रतिशत था। मई 1975 के ग्रंस में कुल बकाया गारन्टियों की राणि में 8,749 यूमिटों के संदर्भ में विद्यमान 39.9 करोड़ रुपयो की गार्गटयो का अस 2.3 प्रतिशत था। जुलाई 1975 से जून 1976 तक की प्रवधि के दौरान 1.9 करोड़ रुपयों की राणि गारटी गुल्को के रूप में प्राप्त हुई तथा केन्द्रीय सरकार को द्यंतरित कर दी गर्या। 🐣

### द्मनुसूचित वाणिज्य बैकों द्वारा प्रथल सहायता

373. सिनम्बर 1975 के बाद से अनुसूचिन वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के आकड़ों में ऐसे लघु उद्याग यूनिट सम्मिलिन हैं जिनकी 25 G1/77—10

निवेश राणि मंयंत्रों ग्रीर मशीनों में 10 लाख रुपयों तक थी। 1975-78 (अप्रैल--मार्च) की पहली तीन निमाहियों के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैको द्वारा लाखु उद्योगो को प्रधान किये गये ऋणों की राणि में 107 3 करोड रुपत्रों की बढ़ोतरी हुई श्रीर वह बढ़कर 1147.4 करोड़ स्पये हो गयी। ग्रालोच्य ग्रवधि के दौरान लघु उद्योगो के बकाया ऋष में जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की तदनुरूप भवधि में हुई वृद्धि (113.5 करोड़ रुपये) की तुलना में थोड़ी सी कम थी। ग्रनः सकल बैक ऋष में (खाद्याक्रों की वसूली के लिए वियोगये ऋणों को छोड़कर) लघु उद्योगो का भंग दिसम्बर 1974 के भ्रंत में यिद्यमान 13.2 प्रतिशत से सीमान्त रूप से घटकर दिसम्बर 1975 के प्रत में 13.0 प्रतिगत हो गया। परन्तु ग्रालोच्य भवधि के दौरान महायता प्राप्त यूनिटों की मंख्या (36252) 1974-75 की तबनुरूप ग्रनिध के दौरान निग्रमान संख्या (19512) से काफी श्रधिक थी। लघु उद्योगों को विये गये बैंक ऋणों की वृद्धि दर में जो गिरावट श्रायी उसका श्रांशिक कारण मोटर गाड़ियों तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुम्रों म्नादि के उद्योगों की मांग में मायी कभी का प्रभाव हो सकता है।

374 प्रित यूनिट मंजूर की गयी ऋण सीमा की श्रीमत राणि विसम्बर 1974 के रू० 68,000 से भीर घटकर दिसम्बर 1975 में 61,000 हो गयी है भी छोटे यूनिटों का वित्तपोषण किये जाने की बैंकों की प्रमृत्ति का मंकेत करती है।

375. दिसम्बर 1975 में समाप्त हुए वर्ष की श्रवधि में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेण जैसे किनप्य पिछड़े राज्यों में लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के श्रंण में वृद्धि हुई है।

376. लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋण की जो कुल यकाया राशि दिसम्बर 1975 के प्रन्त में विध्यमान थी (1147.4 करोड़ रुपये) उगमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का फुल प्रंग 90.2 प्रतियत (1034.6 करोड़ रुपये) था। स्टेट बैंक समूह ने इस क्षेत्र को कुल 410.2 करोड़ रुपयो की राशि के ऋण प्रदान किये जो मार्ख 1975 के स्तर की तुलना में 38.6 प्रतियत की वृद्धि के द्योतक थे, इसके विपरीत 1974 की तदनुरूप प्रविध में उनमें 31.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये गये ऋणों में मार्च—दिसम्बर 1975 के दौरान 63.7 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी जबकि मार्च—दिसम्बर 1974 के दौरान उनमें 71.4 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी जबकि मार्च—दिसम्बर 1974 के दौरान उनमें

377. दिसम्बर 1975 में समाप्त हुए नौ महीनों की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा लघु उद्यागों को प्रवान किये गये मीयादी ऋणों (किक्ती ऋणों मिहिन) की राशि में 20.3 करोड़ रुपयों की दृद्धि हुई और वह बक्रेकर 239.2 करोड़ रुपये हो गयी। 50724 यूनिटों के संदर्भ में बकाया ऋणों की राणि मार्च 1975 के अंत में स्थिन 178.1 करोड़ रुपयों से बक्रकर दिसम्बर 1975 के अत्त में 57396 यूनिटों के संदर्भ में 192.4 करोड़ रुपयों हो गयी। लघु उद्योगों को प्रवत्त कुल बैंक ऋण में मीयावी ऋणों (बकाया) का अनुपान दिसम्बर 1974 के प्रमेन अस्थित 17.2 प्रनिणन ने घटकर दिसम्बर 1975 में 16.8 प्रतिणत हो गया।

378. कारीगरों तथा धन्य योग्यना प्राप्त उद्यमियों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की कुल राणि विसम्बर 1975 के धंत में 24745 यूनिटों के मंदर्भ में 60.2 करोड़ कपये थी जो नौ महीनों की घरिष्ठ में हुई 11.5 करोड़ रुपयों की वृद्धि की द्योतक थी; यह वृद्धि पिछले वर्षे की तवनुरूप अवधि में हुई 8.2 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबने में मंत्रोधजनक थी। बकाया ऋणों की राणि 12.5 करोड़ रुपयें थी; इसमें से 48 प्रतिशत अंश स्टेट वैंक आँफ इंडिया समृह का था।

क्याज वर विश्यास—मा० ग्रौ० वि० वेंक की सहायता

विसम्बर 1975 के पहले विद्यमान वरें 1 विसम्बर 1975 से प्रकारी संशोधित वरें

	ब्रौद्योगिक संस्थाकी की प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों के लिए दी गयी सहायता को छोड़कर)	वार्षिक %	बार्षिक %
	(क) नियमित दर	10.25	11.00
	(ख) निर्विष्ट पिछड़े जिलों में स्थित सूनिटों को	8.50	9,50
2.	पुनर्बित्त		
	(क) नियमित दर	8 . 50—वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली स्याज वर की उच्चतम सीमा 12 प्रतिशत	9.00-—विसीयसंस्थाधों द्वाराली जाने वाली क्याज वर की उच्चतम सीमा 12.50 प्रतिशत
	(ख) ऋण गारन्टी योजना नथा तकनीमन उद्यमी योजनाश्रोके श्रंतर्गेत श्रानेवाले लघु उद्योगयूनिटों के लिए विशेष दर	7.00—वित्तीय संस्थाभ्रो द्वारा ली जानेवाली ब्याज दर की उच्चतम सोमा 10.50 प्रतिशत	7.50 — वित्तीय संस्थाधों द्वाराली जानेवाली ज्याज दर <b>की</b> उच्चतम सीमा 11.00 ध्रतिशत
	<ul><li>(ग) निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों के लिए विशेष दर</li></ul>	5. 50—वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जानेत्राली ब्याज दर की उच्चतम सीमा 9.00 प्रतिशत	6.00 <b>—विक्तीय संस्थाधों द्वा</b> रा ली जानेवाली ज्याज दर की उच्चतम सीमा 9.50 अतिशत
	ग्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण के घन्तर्ग (विवेशी मुद्रा ऋण)	π	
	(क) ऋण गारस्टी योजना तथा तकनीमन उद्यमी योजनाम्रो के अंतर्गत मानेमाले लब् उद्योगो तथा निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों को	8.00—वित्तीय संस्थानो द्वारा ली जानेवाली ब्याज दर की उच्चतम सीमा 10.50 प्रतिशत	8.50वित्तीय संस्थामों द्वारा ली जानेवाली ज्याज की दर उच्चतम सीमा 11.00 प्रतिशत
	<b>(क</b> ) ग्रन्थ मामले .	<ol> <li>25—िनतीय संस्थाभी द्वारा ली जानेवाली स्थाज वर की जच्चतम सीमा 11.00 प्रतिगत</li> </ol>	9.00—नितीय संस्थाध्रो द्वारा ली जानेवाली अयाज दर की उञ्चलम सीमा 11.50 प्रतिशत
2	3. निर्यात ऋण		
	(क) मध्याविधि निर्यात ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त	6.50—बगर्ते कि बैंक 8.00 प्रतिगत मे भ्रनधिक दर पर ब्याज लें।	कोई परिवर्तन नहीं
	(खा) सहभागिता निर्यात वित्त योजना     (ग) खरीदधार ऋण योजमा }	ऋण के भा०ग्रौ०वि० बैंक के झंश पर ऐसी दर रहती है कि सहभागी बैंक की दर को हिसाब में लेने पर निर्यातक से संपूर्ण ऋण पर ली जाने वाली झौसत अ्याजवर	कोई परिवर्तन नहीं
	<ol> <li>हंडी पुतर्मुनाई योजना हुंडियों/वचनपत्नों की झनतीत भवधि</li> <li>(क) 6-36 सहीने</li> </ol>	सामान्यतः 7.50 प्रतिशत हो ।  9.00—वैक बारा ली जानेवाली ग्राधिकतम भूताई	10.00वैंक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भूनाई
	(1) 0 00 000	का १० वट <del>विकास के</del> ।	प्रकार के का कार्य का नामाना भागमध्य मुनाइ

दर 10.75 प्रतिशत है।

दर 10.25 प्रतिशत है।

379. दिसम्बर 1975 के भीत तक छोट सङ्क भीर जल परिवहन भारतको के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाधों की राणि 93837 यूनिटों के संवर्भ में 238.5 करोड़ रुपये थी। 191.2 करोड़ रुपयों की बकाया राशि मार्च 1975 के स्तर की कुलना में 57.7 करोड़ रुपयो की वृद्धि की बोतक थी ; यह वृद्धि 1974 की तदनुरूप अवधि में पायी गयी वृद्धि (19.7 करोड़ रुपये) की तुलना में तिगनी थी।

(सा) 36 महीनों से प्रधिक और 84 महीनों तक

380 श्रीकोगिक बस्तियों की स्थापना के लिए 17 धनुसूचित वाणिज्य बकों द्वारा मंजूर की गयी ऋण सीमान्नों की राणि दिसम्बर 1975 के श्रंत तक 57 यूनिटों के संवर्भ में 18.6 करोड़ रुपये थी। इस संवर्भ में बकाया राशि मार्च 1975 के ग्रंत में विद्यमान 9.5 करोड़ रुपयो के मुकाबले में 12.4 करोड़ रुपये थी।

8.50-- बैंक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई 9.50--- वैंक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई

दर 11.75 प्रतिशत है।

दर 11.25 प्रतिशत है।

### मारतीय यूनिट दूस्ट

381 जैसा कि य्निटों की बिक्री तथापुन क्रय से विदित होता है, 1975-76 में दौरान यूनिट ट्रस्ट के कार्यकलायों में स्पष्टत सुधार हुमा। 1975-76 में कुल बिकिया की राणि 29 0 करोड़ रुपये थी जब कि उक्त राणि पिछले वर्ष के दौरान 17 2 करोड़ रुपये थी। श्रालोच्य ग्रविध के दौरान पुन ऋय की राशि 11 0 करो**ड रु**पये थी जो पिछने वर्ष की तुलना में केवल ग्राधी थी। निम्नलिखित तथ्यो के कारण 1975-76 के दौरान उक्त सुधार हुआ है। पहला तच्य यह है कि सरकार ने जनवरी 1975 में यूनिटो में किये जानेवाले निवेशों के लिए भ्रलग से आय और सपत्ति कर सबन्धी रियायतें (30) प्रदान की, इस कारण यूनिटो की भावर्षकता में काफी युद्धि हुई । दूसरा तथ्य यह है कि लाभांण को 1973-74 के 8 5 प्रतियान से बढ़ाकर 1974-76 में 8 6 प्रतियात कर दिया गया, यद्यपि यह वृद्धि केवल सीमान्त ही थी, फिर भी इससे ट्रम्ट मे निवेणका का विश्वास भौर मजबूत हो सका। तीमरा तथ्य यह है कि भ्रालोच्य वर्ष के दौरान देश की भ्रार्थिक स्थिति मे स्पष्ट सुधार भाषा ग्रीर नाभाण संबधी नियन्नणों में 1975 में रियायते की गयी, इस कारण भी निवेश के बातावरण पर अनुकूल प्रभाव पढ़ा। इसके अलावा, अनवरी 1976 में ट्रस्ट एक नयी योजना मर्थात् यूनिट योजना 1976 में भ्रमल में लाया जिसके धन्तर्गत पूंजी बिकास के प्रमुख उद्देश्य से नये प्रकार के यूनिट प्रस्तुत किय गये भौर इस योजना के कारण प्रतिरिक्त बच्चन जमा की जा सकी। ट्रस्ट ने यूनिट योजना 1964 के प्रनार्गत दिये जानेवाले लाभांग की दर को 1974-75 के 8 60 प्रतिगत से बढ़ाकर 1975-76 में 8 75 प्रतिगत कर दिया।

382 जून 1976 के धत तक बेचे गये तथा सकाया रहने वाले पूर्तिटो की राशि 6 3 लाख से प्रधिक प्रावेदन पत्नों के प्रतर्गत 166 9 करोड रुपये थी। सारणी 31 मे 30 जून 1976 तक य्तिटो की योजना-नार बिकी, पुन ऋष और बकाया राशि दशियों गयी है।

³⁰ यूनिटो से होने वाली रु० 2,000 तक की आय तथा यूनिटो मे किये जाने वाले रु० 25,000 तक के निवेश को कमश आय कर तथा सपित कर से छूट वी गयी। ये छ्टे सप्रति कुछ निर्दिष्ट आस्तियो के साथ यूनिटो के सबन्ध मे रु० 3,000 की आय को आयकर--मे तथा 1.5 लाख रुपयो तक के निवेशो को संपत्ति कर से जो छूट प्राप्त है उसके अनिरिक्त हैं।

सारणी 31 : यूनिटों की विकी पुन ऋर ग्रीर बकाया राशि : योजनाबार विश्लेषण

(राशि करोड़ रुपयो मे)

योजना					मिक्री'			रुन ऋष		20 🕶 1076
					1974-75	1975-76	197	4-75	1975-76	30 जून 1976 कामनाया
युनिट योजना 1964				•	16 74	20 77	20	36	10 95	157 6
युनिट योजना 19 <b>7</b> 1		•			0 49	0 79	ō	01	0 02	1 75
यूनिट योजना 1976	•	•	•		سيهم	7 47				7 47
	•			*	17 23	29 03	20	37	10 97	166 87

यूनिट योजनाः 1976

383 ट्रस्ट 1 जनवरी 1976 को यूनिट योजना 1976 ध्रमण मे लाया, जिसके अनर्गत 'पूजीगत यूनिट' सामास्य जनता को बेचे जाने लगे। युनिट योजना 1964 मीर यूनिट योजना 1971 का लक्ष्य यह है कि यूनिट धारियो को निर्यामत तथा कमिक रूप से भाग प्राप्त हो, किन्तु नयी योजना का लक्ष्य प्रमुख रूप से पूजी विस्तार है। मच्छे विकास की मभावनान्ना से युक्त कंपनियों के ईक्षिश्रटी शेयरों में इस योजना की निधियों का निवेश कर इस लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी । ट्रस्ट यह ग्राशा करता है कि ग्रमाधारण तथा ग्रप्रत्याशित स्थितियों को छोडकर पूंजीयत यूनिटो में यूनिटधारियों के निवेशों की राशि लगभग 5 वर्षों में बुगुनी हो जाएगी। इस योजना मे प्रत्येक यूनिट का धकित मूल्य क्र 100 है और यूनिट न के गुणजों से बेचे जाते हैं। पूंजीगत यूनिट योजना की लोकप्रियताको उनकी बिकी की राणि से श्रांका जा सकता है। थोड़ी सी प्रविध (जनवरी से 21 प्रप्रेल 1976 तक) के दौरान ऐसे यूनिटो की जिली की राणि 7 5 करोड़ रुपये हो गयी। 22 अप्रेल 1976 से बिक्ती को भ्रस्थायी रूप में स्थगित कर दिया गया है ताकि ट्रस्ट योजना की निधियों का विकास की दिशा में ग्राभिमुख शेयरों में निवेश कर सके।

#### <del>Callor</del>

384 न्याम की निवेशयोग्य निधियों में 8 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और जून 1976 के अन्त में वे बढ़कर 184 5 करोड़ रूपये हो गयी। इनमें से सामान्य शेयरों का भ्रंग 91 5 करोड़ रुपये (49 6 प्रतिशत) था, अधिमान शेयरों का श्रंश 16.2 करोड़ रुपये (8 8 प्रतिशत) भीर डिबेचरों का ग्रंग 55 8 करोड़ रुपयें (30 2 प्रतिशत) था। 21 0 करोड़ रुपयों (11 4 प्रतिशत) का शेष ग्रंग हामीदारी के वायदों से सम्बन्धित ग्रग्निम जमाराशियों, पूरक किल, भ्रन्य जमाराशियों, माग ग्रौर भ्रन्य सूचना पर देय राशि ग्रादि के रूप में था।

### रिजर्व बैंक से मसंबद्धता

385 ट्रस्ट जहां श्रम निक रिजर्व बैंक की सहयोगी सस्या के रूप में या बहा श्रम सार्वजिनिक वित्तीय सस्या विधि (समोधन) ग्रिधिनियम, 1975 के अनुसरण में 16 फरवरी 1976 से भारतीय ग्रीग्रीगिक विकास बैंक की सहयोगी संस्था बन गया है। इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा धारिन ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूजी (2 5 करोड़ रुपये) भारतीय ग्रीग्रीगिक विकास बैंक का ग्रांदिन कर दी गयी है।

### गैर बैकिंग कम्पनियां

### गैर बैंकिंग कम्पनियों पर श्रध्ययन दल

386 पिछले वर्ष की रिपोर्ट मे गैर वैंकिंग कपिया से सम्बन्धिन सध्ययन दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुन किये जाने का उल्लेख किया गया था। अध्ययन दल की प्रमुख निफारिण गैर वैंकिंग कंगनियो, वित्तीय कपिनयों और इनामी चिट श्रीर या परम्परागन चिट कानिया से मबन्धिन है। इन सिफारिणों को रिजर्व वैंक तथा भारत सरकार द्वारा मिद्धान्तन स्वीकार कर लिया गया है।

387. गैर बैकिंग कपनियों के सबन्ध में ब्राध्ययन दल ने यह पाया कि ऐसी कपनियों द्वारा जमाराशिया स्वीकार किये जाने पर पूर्णत रोक न लगायी जाए परन्तु इस प्रकार के उपाय किये जाएं कि मुद्रानीलि से ध्येक्षित परिणाम मिल सके तथा जमाकर्ताओं के हितों को मुरक्षित रखने की धावश्यकता के धनुरूप उत्पादक प्रक्रिया में कोई बाधा न पड़े। माथ ही भंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि इन जमाराशियों की और वृद्धि को रोक विया जाए तथा उन्हें कमशः लौटा विया जाए ताकि वे उद्योग तथा ब्यापार के लिए वित्त के प्रमुख कोत बनकर न रहे। उक्त मिफारिणों को प्रभावकारी बनाने के खिए 'कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली, 1975' में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर कम्पनी कार्य विभाग विचार कर रहा है।

388. गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के मामले में ब्रध्ययन दल ने उनके बहुत प्रधिक सख्या के जमाकतियों तथा उन कम्पनियों में पाये जाने वाले दुराचारों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकलापों को प्रभाव कारी हुंग से विनियमित करने की सिफारिश की। प्रध्ययन दल ने यह सुद्धाय दिया कि इन कपनियों पर सामान्य रूप से उसी प्रकार के नियंत्रण लागू किये जाने चाहिए जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के झन्तर्गत बैकों पर लागू हैं। चूंकि ऋणवाता कंपनियों के कार्यकलाप बैको के कार्यकलापों के समान ही होते हैं ग्रतः ग्रध्ययन दल ने यह सिफारिश की कि उनके द्वारा स्वीकार्य जमाराणियों के लिए यह उज्जतम सीमा निर्धारित की जाए कि वे गुद्ध स्वाधिकृत निश्चियों के 10 गुने से प्रधिक न हो। दल का यह विचार था कि उक्त सीमातक निधियां उपलब्ध होने से उनको लाभदायक कामकाज करने का उचित भवसर प्राप्त होगा तथा बे सक्षम युनिट बन सकेगे। किराया खरीद वित्तीय कम्पनियों को जहां अब उच्चलम मीमा सम्बन्धी नियंत्रए। से छूट प्राप्त है, वहा उन पर भी ऋणवाता कम्पनियो की तरह स्वीकार्य जमाराशियों के लिए उच्चतम सीमा (उनकी गुढ़ स्वाधिकृत निधियों के 10 गूने से अनिधिक) निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है ; परन्तु गृहनिर्माण वित्त कम्पनियों को उच्चतम सीमा सम्बन्धी नियत्नणों से छूट वी जाती रहेगी। चूंकि निबेश कम्पनियों के संबन्ध मे इस प्रकार की विशेष कार्यवाई करना उचित नहीं होगा, प्रत: सुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 40 प्रतिशत की वर्तमान समन्त्रित सीभा को दो चरणों में घटाकर 25 प्रतिशत बना देने का प्रस्ताय है। क्ल ने केवल भपने सदस्यों के साथ लेन देन करने वाली 'निधियों' द्वारा स्वीकार्य जमाराशियों के लिए किसी भी प्रकार की उच्चतम सीमा की सिफारिश नहीं की है। कम्पनियों द्वारा स्वीकार्य जमाराशियों की माला के सबन्ध में नियंत्रण लगाये जाने के अलावा नयी विजीय कम्पनियां प्रारम्भ करने के लिए तथा निधियों से इतर अन्य वर्तमान कम्पनियों के संबन्ध में ग्रध्ययन दल ने न्यूननम पूंजीगत स्रोक्षास्रों की सिफारिश की है। उनके द्वारा की गयी कनिषय भ्रन्य सिफारिशें प्रारक्षित निधि का निर्माण करने, चल श्रस्तियों को बनाये रखने, निदेशकों तथा उन फर्मी भीर कम्पनियों को जिनमें उनका हित हो, ऋण और श्रप्तिम प्रवान किये जाने पर रोक लगाने तथा बैंककारी विनियमन प्रधिनियम, 1949 की कतिपय धाराम्रों के समान उपबन्धों को मधिनियमित करने से संबन्धिन हैं। वित्तीय कम्पनियों के जमाराणि स्वीकरण संबन्धी कार्यों तथा उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण को मजबून बनाने के उद्देश्य से श्रध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गयी सिफारिशो के महत्वपूर्ण स्वरूप को देखते हुए यह निज्ञ्चय किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रधिनियम, 1934 के प्रध्याय III-माके स्थान पर एक ग्रलग व्यापक विधान को श्रधिनियमित किया आए। इस विधान का प्रारूप सैयार किया जा रहा है धीर इस कीच दल की ऐसी मिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं जिन्हें अधिनियम के उक्त भ्रध्याय III-मा के वर्तमान उपजन्धो के मंतर्गत रिजर्व बैक को मौपी गयी शक्तियो का प्रयोग करते हुए संपति ग्रमल में रहने वाले निवेशों में उभित संशोधन कर कार्यान्वित किया जा सकता है। निवेशों में किये जाने वाले सशोधनों को ध्रांतिम रूप दिया जा चुका है परन्तु प्रधिसूचना जारी करना संप्रति स्थगित किया गया है क्योंकि यह निश्चय किया गया है कि गैर बैकिंग कम्पनियों पर लागू होने वाली श्रष्टययन दल की सिफारिशों को कार्यन्त्रिय करने के लिए भारत गरकार द्वारा कम्पनी (जभाराधियों का स्वीकरण) नियमावली, 1975 में किये जाने वाले इसी प्रकार के संशोधनों के साथ ही उन्हें ग्रमल में लाया जाए।

389 इनामी चिट, लाभ । अचल योजनाए ध्रावि— चलाने वाली कम्पनियों के संबन्ध में अध्ययन दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसी योजनाओं से प्रमुख रूप से प्रवर्तक लाभान्वित होने है तथा उनसे कोई सामाजिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । ऐसी योजनाएं सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हैं नथा राजकोषीय एवं मुद्रागन नीतियों के परिणामों पर प्रतिकृत प्रभाव डालती हैं । अतः यह मुझाया गया है कि अधिक ब्यापक सार्वजनिक हिन की दृष्टि में ऐसी योजनाओं के चलाये जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगायी जानी चाहिए और यदि इस उद्देश्य के लिए वर्तमान अधिनियमों के उपबन्धों को अपर्याप्त माना जाए तो उधिन वैधानिक कार्यवाद्यां की जानी चाहिए । इस संदर्भ में रिकर्ष बैंक द्वारा बनाया गया प्रारूप विधान सरकार के विचाराधीन है ।

390 परम्परागत चिट निधि का कारोबार चलाने वाली कम्पनियों के मामले में उनके द्वारा चिट के सवस्यों से प्राप्त प्रभिवानों को रिजर्व बैक द्वारा जारी किये गये निदेणा के प्रयोजन के लिए 'जमा राशियों' की परिभाषा के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जब कि ऐसी योजनाम्नों से भिन्न रीति से स्वीकार की जाते वाली जमाराणिया उक्त निवेशों के क्षेत्र के भ्रन्तर्गत श्राती है। परन्तु किनपय राज्यों/सघशामित क्षेत्रो में चिट निधि संबन्धी कारोबार को अधिनियमों के अन्तर्गत विनियमित किया गया है। येश के ग्रन्थ भागों में विनियामक उपायों के ग्रभाव में तथा इन उपबन्धों के विभेदात्मक स्वरूप को देखते हुए यह ग्रसंभव नहीं है कि बेईमान प्रवर्तक या चिट कम्पनियां ऐसे राज्यों मे चिट का कारोबार चलाकर स्थिति का भ्रनुचित लाभ उठाये, महां जहा इस प्रकार का कोई विधान नहीं है या जहां उपवन्ध कम कठोर है। यहां इस बात का उल्लेख किया आए कि गैर बैकिंग वित्तीय विचौिलयों के कार्यकलायों को विनि-यमित करने के निमित्त बैंकिंग श्रायोग द्वारा की गयी लिफारिशों के संदर्भ में अन्य बातों के साथ केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया था कि परम्परा-गन जिट निधियों के कार्यकलायों को विनियमित करने के लिए एक ऐसा अव्दर्श विधान बनाया आए जिसे वे सभी राज्य भपना सर्क जहां इस प्रकार का विधान ग्रमल में नही है। उक्त निर्णय के परिणामस्बरूप रिजर्व बैंक ने एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया जिसे केन्द्रीय विधान के रूप में ग्रधिनियमित किया जा सकता है तथा उसे प्राध्ययन दल के पास उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया। ग्रध्ययन दल की सिफारिशों के संदर्भ में समोधित उक्त विधेयक पर भारत सरकार विचार कर रही

### ग्रनिगमित निकायों द्वारा जमाराशियों का स्वीकरण

391. गैर बैकिंग वित्तीय बिचौिलयों के नियत्नण की वर्नमान योजना को पुनर्व्यवस्थित करने के संबन्ध में बैंकिंग धायोग द्वारा की गयी सिफा-रिशो पर विचार करते समय भरकार ने सैद्धान्तिक रूप से यह निश्चय किया कि सभी प्रनियमित निकायों द्वारा जमाराशियों के स्थीकरण को रोकने के लिए सांविधिक एक्तिया प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक ग्राधिनयम, 1934 में जिन धावण्यक संशोधनों के मुझाव विये थे वे सरकार के यिचाराधीन है।

### गैर बैंकिंग कस्पनियों को जारी की गयी निदेशाबली में संशोधन

392 गैर बैंकिंग विसीय कस्मिनियों की जारी की गयी निदेशावली में 29 नवस्थर 1975 की और मंशोधन किये गये तथा ऐसी कम्पिनियों की निदेणकों द्वारा गारन्टीकृत ऋणों के रूप में रहने वाली जमाराणियां शेयर आरियों से प्राप्त जमाराणियों आदि को शुद्ध स्वाधिकृत निश्चियो के 15 प्रतिणत तक घटाने के लिए छ महीनों की भौर (भ्रथीत् जून 1976 के अंत तक) अविध दी गयी। कम्पनियों द्वारा किये गये इस भाषाय के प्रतिवेदनों के बाद उक्त भ्रविध बढायी गयी कि ऐसी बकाया जमाराणियां काफी भ्रधिक है भीर वर्तमान स्थित में वे निर्धारित सीमा में ग्रधिक माहा में रहनेवाली जमाराणियों को 31 दिसम्बर 1975 तक समाप्त करने में बहुत ही कठिनाई भ्रमुभव कर रही हैं।

393 इसी प्रकार गैर बैंकिंग विसेतर कम्पिनयों के मामले में भी कम्पनी प्रधिनियम, 1956 की धारा 58-ग्र के धन्तर्गत बनायी गयी कम्पनी (जमार।शियों के स्वीकरण), नियमावली 1975 में संशोधन कर मारन मरकार के कम्पनी कार्य विभाग ने धविध बढ़ायी। इन कम्पनियों के लिए सितम्बर 1976 के प्रन तक अविध और बढ़ा वी गयी है। इसके प्रलावा रिजर्व बैंक द्वारा की गयी किनप्य सिफारिशों के संदर्भ में 18 सितम्बर 1975 को नियमावली में संशोधन किये गये; संशोधित नियमावली म्थुल रूप से बैनी ही है जैसी कि वित्तेनर कंपनियों को जारी की गयी निदेशावली जून 1975 में उसे बापम लेने के पहले विद्यमान थी। यह स्मरण होगा कि इन.मी विट/लकी हा/ बचन योजना आदि चलाने वाली कम्पनियों को उपयुक्त प्रकार की जमाराशियों को कम की गयी 15 प्रतिशत की उच्चतम मीमा के भीतर लाने के लिए दिसम्बर 1976 तक प्रविध दी जा चुकी है।

### गैर बैंकिंग कम्यनियों के पास जमाराशियाँ: 1972-73

394 31 मार्च 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए गैर वैकिंग कंपनियों के पास रहने वाली जमाराशियों का जो सर्वेक्षण किया गया उसके अंतर्गस सूचना देने वाली कंपनियों की संख्या में इस वर्ष 314 की कमी आयी और वह घटकर 2,841 हो गयी। सूचना देने वाली कंपनियों की संख्या में कमी आतों के बावजूद जभाराशियों तथा छूट प्राप्त ऋणों की कुल राशि में 56 करोड़ रुपयों की वहोतरी हुई और वह मार्च 1972 के अन में स्थित 691.8 करोड़ रुपयों से बहकर मार्च 1973 के अंत में 747.8 करोड़ रुपयों हो इसमें जमाराशियों तथा छूट प्राप्त ऋणों का अया अमणः 373.7 करोड़ रुपयों भी बहकर मार्च 1973 के अंत में 747.8 करोड़ रुपये हा गयी। इसमें जमाराशियों तथा छूट प्राप्त ऋणों का अया अमणः 373.7 करोड़ रुपयें और 374.1 करोड़ रुपये था। सूचना देने वाली कित्तीय कंपनियों की संख्या में जहां 42 की कमी आयी और बहु घटकर 879 हा गयी, बहु। सूचना देनेवाली वितेतर कंपनियों की संख्या में उहां 42 की कमी आयी। जमाराशियों और छूट प्राप्त ऋणों की कुल 747.8 करोड़ रुपयों की राशि में वहां प्रदेश रूपयों की राशि में वहां पर कंपनियों का आग 517.4 करोड़ रुपयों भी प्राप्त भाग (230.4 करोड़ रुपयें) वित्तीय कपनियां का था।

395 1971-72 की तरह 1972-73 में भी यह देखा गया कि प्रधिकांश बकाया जभाराशिया तथा छूट प्राप्त ऋण छोटी सक्या की बड़ी गैर वैकिंग कपनियों के पास थे। मार्ज 1973 के मत तक सूचना देने वाली कुल 2,841 कंपितयों में से कुल 25 लाख कपयों तक की जमाराशिया भीर छूट प्राप्त ऋण धारित करने वाली 464 कंपिनमां (16.3 प्रतिशत) का मंग 83.8 प्रतिशत था। विक्तीय कपनियों के मामले में

यह विभेषता धौर भी स्पष्ट थी। उनके संदर्भ में सूत्रना देने वाली कंप-नियों की 8.5 प्रतिमत कंपनियों के पास 78 8 प्रतिमत जमाराणियां थीं श्रीर समग्र रूप से कुल जमाराणियों श्रीर छूट प्राप्त ऋणों का 90 6 प्रतिमत था।

396. सूचना देने वाली अधिकांण कंपनियां प्रमुख रूप में तीन राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तीमलनाबु और पश्चिम बंगाल में स्थित थी। मार्च 1973 के अंत तक सूचना देने वाली कुल कम्पनियों ने इन तीन राज्यों का कुल अंग 63.9 प्रतिणत और कुल बकाया जमाराणियों तथा छूट प्राप्त अर्थों में उनका अग 71.8 प्रतिणत था।

### V. विवेशी सुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां

397 ब्रालोक्य वर्ष के दौरान विदेशो मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में पायी गयी महत्वपूर्ण गितिविधियां इस प्रकार थी—पौड स्टिलिंग से भारतीय रूपये को असंबद्ध किया गया, ब्रास्थिति अवायगी की भारों पर किये जाने वाले निर्मातों के लिये कियाविधियों को सरल बनाया गया, गैर रिहायशी भारतीयों श्रीर विदेश में रहनेवाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशों मुद्रा (गैर रिहायशी) खाने खोलने एवं बनाये रखने की अनुमति प्रवान कर एक नयी मुविधा की व्यवस्था की गयी, और उन्हें भारत में विशिष्ट उद्योगों की येयर पूंजी में निवंश करने के लिये प्रोप्याहित किया गया।

### पाँड स्टालिंग से भारतीय उपये को असंबद्ध करना

398. भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैक के परामर्ण से उस व्यवस्था का पूनरीक्षण किया जिसके प्रधीन भारतीय रूपया पौड स्टर्लिंग में संबद्ध था , साथ ही पीड़ के मुल्य के परिवर्तन के गाथ-साथ स्वयमेश परिवर्तित हो जाने वाली प्रमुख श्रनर्राष्ट्रीय मुद्राध्यों या विशेष भ्राहरण अधिकार की तुलना मे भारतीय रुपये के मृह्य का भी पुनरीक्षण किया गया। तत्काल दानि के लिये स्टर्लिंग के कय-विकय की रिजर्व बैंक की जो दरे 4 जुलाई 1972 में कमश. पीड 5.3333 भीर पीड 5.3050 प्रति २० 100 थी उन्हें रिजर्व बैंक ने 2 जुलाई 1975 में बदलकर कमश पौड़ 5.3907 भीर पौड़ 5.3619 निर्धारित किया। फिर भी, ब्रतर्राष्ट्रीय मुद्रागत स्थिति के परिप्रेक्ष्य मे ब्रीर इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि जब तक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राए मुक्त रहती है, तब तक किसी एक प्रारक्षित सुद्रा के साथ सबद्ध करने की प्रपेक्षा एक बह-सुद्रा-माधार कही अधिक उपयुक्त तथा सर्वापजनक सिद्ध होगा, यह निरुचय किया गया कि 25 सितम्बर 1975 से रुपये का स्टलिंग से प्रसबद्ध कर विया जाय ग्रौर भविष्य में भारत के व्यापार से प्रमुख रूप से सबन्ध रखनेवाली चुनी हुई प्रमुख अतर्राष्ट्रीय सुद्रामां के सदर्भ में रुपये के मूल्य का निर्धारण किया जाय। पीड स्टर्लिंग अब भी मध्यवर्ती सुद्रा के रूप मे जारी है। तबनुसार, रिआर्व बैंक न समय समय पर सल्काल वाति के लिये पौड स्टलिंग के कथ-विकय की अपनी दश का संशाधित किया। उसके विवरण निम्न प्रकार है:

तारीख				ऋय दर	विकय दर	— मध्य दर
25-9-1975				पौड 5.4769 प्रति হ০ 100 (प्रति 1 पौड হ০ 18.2583 के श्रतुरूप)	पांड 5. 1471 प्रति रु० 100 (प्रति 1 पांड रु० 18. 3584 के प्रतुरूप)	प्रति । पीड रु० 18.3084
5-12-1975	•	•	•	पीड 5.5315 प्रति ६० 100 (प्रति 1 पीड ६० 18.0784 के धनुरूप)	पीड 5.5010 प्रति क॰ 100 (प्रति 1 पीड क० 18.1784 के भनुका)	সবি 1 পীর হ০ 18.1284
8-3-1976	•		•	पौड 5.6497 प्रति বং 100 (प्रति 1 पौड হং 17.70 के प्रतुरूप)	पोड 5.6180 সশি ক <b>ে</b> 100 (সলি 1 पौड क <b>ে 17</b> .80 के श्रनु <b>क्</b> प)	সলি 1 पाँड হ০ 17.75

11-3-1976	•	,	पींड 5.8140 प्रति <b>व</b> ० 100 (प्रति 1 पींड रु० 17.20 के मनुरूप)	पाँड 5.7803 प्रति ६० 100 (प्रति 1 पाँड ६० 17.30 के ध्रमुक्प)	সুবি 1 पौँ४ হ০ 17,25
3-4-1976	•		पौड 5.9347 प्रति क० 100 (प्रति 1 पौंड क० 16.85 के श्रनुक्प)	पौड 5.8997 प्रति घ० 100 (प्रति 1 पौड रु० 16.95 के अनुरूप)	प्रति 1 पीड कः 16.90
23-4-1976			पौड़ 6.0790 प्रति रु० 100 (प्रति 1 पौंड रु० 16.45 के प्रतुरूप)	पौड 6.0423 प्रति ग॰ 100 (प्रति 1 पौंड र॰ 16.55 के मनुरूप)	प्रति । पौंड रू० 16.50
29-5-1976		•	पौच 6.2696 प्रति रु० 100 (प्रति 1 पौच रु० 15.95 के मनुरूप)	पौड 6.2305 प्रति ह० 100 (प्रति 1 पौंड ह० 16.05 के मनुस्प)	সুনি 1 <b>দীচ</b> হ০ 16,00

इन सभी श्रवसरों पर, स्टलिंग का नायदा कय करते समय तत्काल क्रय दर में प्रत्येक तिमाही या उसके श्रंण के लिये प्रति रु० 100 पोड 0.0125 का जो मार्जिन जोड़ जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया और न ही नायदा क्रय टेकों की श्रवधि को एक या प्रधिक बार बड़ाने पर प्रत्येक निमाही या उसके श्रंण के लिये प्रति रु० 100 पौड़ 0.0125 का जो शुरूक श्रदा करना पड़ता है उसमें कोई परिवर्तन किया गया । इसी प्रकार श्रास्थित ग्रदायगी की शर्तों के श्रधीन किये जानेवाले निर्यानों के संवर्ध में निर्यातकों को वीर्षकालीन वायदा विनियम मुरक्षा प्रदान करने की योजना के श्रधीन 10 वर्षों कक की श्रवधित रिखर्ष में किए स्टिलिंग का जो वायदा क्य किया जाना है उससे संबंधित रिखर्ष में के देशे को हिमाब लगाने के लिए स्टिलिंग की तत्काल क्रय दर में जोड़े जानेवाले मार्जिन में भी कोई परिवर्तन नही हुशा । उक्त मार्जिन निम्न प्रकार था ।

नायदा ठेके की भवधि	बैंक की तरकाल कय दर पर प्रतिशत मार्जिन
<ol> <li>18 महीने और अधिक किन्तु 5 वर्षी</li> </ol>	·
से घनधिक	1.25
2 5 वर्षों से भ्रधिक किन्तु 7 वर्षों से	
भनधिक	1.75
3. 7 वर्षों से ग्रधिक किन्तु 10 वर्षों से	
मनधिक	2.50

### म्रास्थिगत प्रधायणी के प्रधीन किये जानेवाले निर्यात

399. 1 जुलाई 1975 से रिजर्व बैंक ने धारुयगित धवायगी के ग्रधीन किये जानेवाले निर्यातों से संबंधित कियाविधियों को सरल बनाया। पहले की कियाविधि के अनुसार, आस्थागित भवागगी की शर्नी पर पूजीगल माल तथा इंजीनियरी माल का निर्यात करनेवालो को दो चरणो में रिजर्क बैंक का पूर्व मनुमोदन प्राप्त करना पड़ता था प्रथित एक बार विदेशी बोलियों या निविवाधी में भाग लेने या भास्थिगित मधायगी की शर्ती पर निर्यातों के लिये बातचीन प्रारभ करने के पहले सैद्धांतिक रूप में धनुमोदन प्राप्त करना पढ़ता था, भौर तूसरी बार भाईर प्राप्त होने की स्थिति में ठेके की गतों को ग्रांतिम रूप देने के पहले रिजर्व बैंक का ग्रांतिम ग्रनुमोदन प्राप्त करना पड़ता था । इसके ग्रलाका, यदि भारतीय मौद्योगिक विकास बैक का वित्त भौर निर्यात ऋष्ण तथा गारटी निगम की सुरक्षा भपेक्षित हो तो ऐसे मामलों में नियतिकों को एक साथ किन्तु ग्रलग ग्रलग गाबेदन-पत्न भा. भी. वि. बैक तथा नि. ऋ. गा. निगम को भेजना पड़ना था। इस भ्रमुविधाजनक भौर मधिक समय लेनेवाली क्रिया विधि को सरल बनाया गया है ग्रीर निर्यानको को कितपय शनौ पर विदेश में प्रस्ताव पेश करने/बातचीन करने/ठेका निष्पादित करने ग्रीर/या निविदार्भों को प्रस्पुत करने तथा बाद में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने की सामान्य मनुमति प्रवान कर उक्त कियाविधि को उदार बनाया गया है। उक्त भर्तों में सर्वाधिक महरूबपूर्ण भर्ते निम्न-प्रकार है (1) ठेके का मूल्य 50 लाख रुपयों से मधिक न हो, (2) निर्दिष्ट प्रकार के माल के लिए ऋण की ग्रविध पांच वर्षों से ग्रधिक न हो, (3) भा श्रौ वि वैंक का जिल श्रीवश्यक न हो श्रौर (4) श्रविम राणि तथा पूर्ण भुगतान की राणि कुल करार मूल्य का कम से कम 15 प्रतिशत हो ग्रौर भाषात पूर्ति एजेमी कभीशन तथा भाड़े के रूप में जो विदेशी मुद्रा बाहर जाती है वह भी उसमें शामिल हो । किन्तु करार में हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर इन मामलों में विवेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग की कार्योत्तर स्वीकृति के लिए रिजर्व बैंक को तथा प्रावश्यक बीमा रक्षा के लिये निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम को प्रावेदनपत्न भेजना बाहिए । जिन मामलों में सामान्य प्रनुमित प्रवान की जाती है उनकी कियाविधि को प्रनुमोदन प्रदान करने के लिए भा. घी. वि. बैंक को केंद्र बिन्दु बनाकर काफी सुसंगत बनामा गया है। भा. घी. वि. बैंक को समन्वित प्रपत्ना में प्रस्तुत किये गये ऐसे प्रावेदनपत्नों पर ग्रंथ एक कार्यकारी वल कार्यक्र कर रहा है। उक्त बल में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय घीषोगिक विकास बैंक लथा निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम सम्मिलित हैं। कार्यकारी दल के साथ जो विचार विमर्श किये जाते हैं उनमें प्रावश्यक संदर्भों में निर्यातको को भी उनके बैंकरों के साथ सम्बद्ध किया जाता है भीर प्रस्ताव या बोली के लिए एकमुश्त स्वीकृति प्रवान की जाती है।

### विदेशी मुद्रा (गैर-रिहायशी) खाते

400 विदेश से होनेवाले निजी प्रेषणों को प्रोत्साहित करने के लिये 1 नवंबर 1975 से एक नयी सुविधा धमल में घायी। इस योजना के ब्रधीन गैर-रिहायणी भारतीयों ग्रीर विवेश में रहनेवाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की विवेश से प्राप्त होनेवाली प्रारंभिक राशि के साथ या भारत में विदेशी मुद्रा के लेन-देन करने के लिये प्राधिकत बैंकों के पास इपयो में रखे हुए वर्तमान गैर-रिहायशी (विदेशी) स्त्राते को परिवर्तित कर, निर्दिष्ट विवेशी मुद्राभ्रों (फिलहाल भमेरीकी डालर तथा पीड स्टर्लिंग) में विदेशी मुद्रा (गैर-रिहासणी) खाते श्रोलने भौर बनाये रखने की मनुमति दी गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत गैर-रिहायशी खाताधारियों के विनिमय सबधी खतरे को पूर्णन समाप्त कर दिया गया है। उक्त खानो को 91 दिनों या भिधिक किन्तु 61 महीनो से भनिधिक भविधियों की मियादी जमा-राशियो के रूप में रखा जाएगा। उनपर देय व्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रधिसूचित की अयिंगी । ये स्याअ दरें भवधि के धनुसार भ्रलग ग्रस्रग होती हैं । संप्रति क्याज दरें 91 विनो किन्तु 6 महीनां से भनधिक भवधि की जमाराशियों पर 5क्के प्रतिशत वार्षिक है भीर 6। महीनों की जमा राशियो पर 10 प्रतिशत वार्षिक है। इन जमाराशियों पर प्रजित होनेवाले व्याज भारतीय भाय कर में मुक्त है । भारतीय रिजार्व बैंक को लिखेना जमार बिणा कोच्या जि सहित निर्विष्ट विदेशी मुद्राम्मों मे स्वतंत्रता-पूर्वक प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। रुपयों में या निर्दिष्ट विदेशी मुद्राभ्रों में गैर-रिह्।यशी (विदेशी) स्नाते में रखी जानेवाली जमाराशियों को सपत्ति कर से छूट प्राप्त है। फिर भी, उक्त राशियों को न तो सम्पदा कर से छूट प्राप्त है और न ही ऐसे खातों से किये आनेवाले उपहारों को उपहार-कर से छूट प्राप्त है।

### शेयर पूंजी में निवेश

401. प्रक्तूबर 1975 से गैर-रिहायणी भारतीयों छौर विदेशों में रहनेवाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को यह मनुमित दी गयी थी कि वे स्वीकृत उद्योगों (भायात व्यापार नियंत्रण की दिनांक 8 फ़रवरी 1974 की सार्वजनिक सूचना सं० 23-प्राईटीसी (पीएन)-74 के प्रनुबंध में दिये गये उद्योगों को छोड़कर) की भेयर पूंजी में निवेण करें, किन्सु उक्त निवेण नयी कंपनियों द्वारा जारी की गई नयी भेयर पूंजी का प्रक्षिक से ध्रधिक 20 प्रतिभात हो। ऐसे निवेणों को उन पर प्राप्त होनेवाली

धाय के साथ प्रत्यावर्तित करने की पूरी धनुमति दी आयेगी, किन्तु उनपर उपयुक्त कर लागृ होगे, साथ ही शर्त यह होगी कि इस प्रकार का निवेश विदेशों गे प्राप्त राशियों धथवा गैर-रिहायशी (विदेशों) खालों से रहने वाली निधियों से किये जाए। उक्त निवेश सरकार द्वारा मवधित कंपनी के लिए स्वीकृत विदेशों शेयर निवेशों के धनिरिक्त होगे।

### परामर्शवाता/विजाहम इंजीनियरिंग सेवाधों का निर्यात

402. भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 1975 में भारतीय परामर्ण-दाना/डिजाइन इंजीनियरिंग सेवाघों के निर्यात से संबंधित धपनी वर्तमाम कियाविधि को उदार बना विया है। भारतीय परामर्गदाना/डिजाइन इंजीनियरिंग फर्मों को धब यह अनुमति प्रदान की गयी है कि यदि पिछले वर्ष विदेशों मुद्रा में अजित उनकी धामदनी पांच लाख रुपयों से कम न रही हो नो वे निबंध याला परिमट की मुबिधा प्राप्त कर सकती है। विदेशों में याला करने या विदेशों में किये जानेवाले प्रारंभिक खर्बों/ बायदों की पूर्ति के लिये प्राप्त भायदेनपत्रों पर भव धिक उदारनापूर्वक प्रत्येक मामले के मुणवाषों के भाषार पर विचार किया जाता है।

### एशियाई समाशोधन यूनियन

403 एशियाई समाशोधन युनियन की स्थापना 9 दिसंबर 1974 को की गई थी और इसका उद्देश्य यह था कि एशियाई धौर प्रशांत महासागरीय भाषिक भीर सामाजिक भायोग के सदस्य देशों के भीतर बहुपक्षीय बाधार पर किये जानेवाले चालू भंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों से संबंधित भवायगियों में सुविधा हो । उक्त यूनियन ने 1 नवंबर 1975 से समागोधन कार्य प्रारंभ किया । छः देशों भ्रथति बंगला देश, भारत, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान भौर श्रीलंका के केद्रीय बैंक इसके वर्तमान सवस्य है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भौर उनसे उत्पन्न वस्तुत्रों के लिए की जानेवाली श्रवायिगयो, भ्रंतर सरकारी भीर गैर चालू लेन-देनों जैसे कतिपय लेन-देनों को छोड़कर भारत भौर एशियाई समाशोधन यूनियन के सदस्यों के बीच होनेवाले सारे लेन-देन उक्त यूनियन के समाशोधन तंत्र के माध्यम से किये जाएंगे। ए शियाई समाशोधन यूनियन के द्वारा लेन-देन करने के लिये विदेशी मुद्रा के उनतीस प्राधिकृत व्यापारियों को निर्धारित किया गया है। समाशोधन केलिये योग्य प्रपत्नो को या तो सदस्य देशो की मुद्रा में या एशियाई समाशोधन यूनियन के सामान्य यूनिट प्रथीत् एशियाई मुद्रा युनिट मे जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा समय समय पर मूल्यांकित विशेष झाहरण धधिकार के एक यूपिट के समान है, बर्गीक्वत किया जाएगा। भारतीय रिजर्व मैंक नामित प्राधिकांत व्यापारियों से तीन, छः या नौ महीनों तक (इस भवधि को कुल मिलाकर 12 महीनो तक बढ़ाया जा सकता है) दाति किये जाने के लिए एशियाई मुद्रा युनिटों का हाजिर भीर वायदा कय करेगा तथा उक्त व्यापारियों को इन यूनिटों का हाजिर विकय करेगा । यह ऋय-विक्रय एशियाई समाशोधन यूनियन द्वारा समय समय पर घोषित रुपये और एशियाई मुद्रा यूनिट के बीच की विनिमय दर के प्राधार पर किया आएमा ।

### इयूरा मार्क ग्रीर जापानी येन का बायवा कय

404. इयूण मार्क धौर जापानी येन का हाजिर कय तथा एक महीने, दो महीने धौर तीन महीने का बायदा क्रय करने के अलावा, रिजर्थ बैंक ने 1 सितम्बर 1975 से छः महीने की समाप्ति पर बायदा दाति के लिये इयूण मार्क धौर जापानी येन खरीदना प्रारंभ कर दिया है। छ. महीने की बायदा दानि के लिये इयूण मार्क धौर जापानी येन की रिजर्थ बैंक की क्रय दरें पिछले कार्य दिन के ध्रत में इयूण मार्क धौर जापानी येन की रिजर्थ कें के की क्रय दरें धौर की बायदा दाति के लिये लेंदन बाजार में स्थित क्रय दरों धौर क्रय के दिन छः महीने की बायदा दाति के लिये

स्टिलग की रिजर्क बैक की श्रय दर के बीच की प्रति-दरे होगी। फिलहाल उक्त क्रय केवल बस्बई स्थित बैक के कार्यालय में किया जायेगा। यह भी निम्नय किया गया कि यदि अलग अलग प्राधिकृत व्यापारी द्वारा रिजर्व बैक को स्यूण मार्क और जापानी येन की वायदा दानि के प्रस्ताय 800,000 इ्यूण मार्क या 10 करोड़ जापानी येन या अधिक राणि के लिए पेण किये जाएँ तो उनके साथ 27 अगस्त 1975 में और अगली सूचना तक उन मुनिश्चित निर्यात आदेशों की प्रमाणित प्रतिविषयाँ संलग्न की जानी चाहिएं जिनके आधार पर प्राधिकृत व्यापारी ने अपने याहक/प्राह्कों से स्यूण भार्क या जापानी येन चरीदा हो।

### निर्मंध विदेशी मुद्रा परमिट

405. योग्य निर्यात प्रतिष्ठानो ग्रीर ग्रन्य निर्यात यूनिटो को निर्बंध विदेशी मुद्रा परमिट जारी करने की कियाविधि को और उसके ग्रधीन राशि प्राप्त करने की सुविधा को जुलाई 1975 में व्यवस्थित कर मलग बनाया गया है ताकि योग्य निर्यात यनिट मी झता से सुविधाओं का लाभ उटा सके । निर्मंध परिमट की प्रश्नावली को भी उचित रूप से संशोधित किया गया है। मंगोधित कियाविधि के मधीन निर्बंध विदेशी मुद्रा परमिट से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के नाम पर्रामट पर नही लिखे जाने। निर्यात युनिटों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी इच्छा से किसी भी कर्मनारी को या निर्यात विकास से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध प्रपने परामर्णदानाध्रो को प्रति-नियुक्त करें । निर्यातकों की वास्तविक ग्रावश्यकनाश्रों की समुचिन पूर्ति के लियें निर्वेध परमिट के ग्रधीन प्रदान की जानेवाली विदेशी मुद्रा की बढ़ा दिया गया है । निर्यात विकास के उद्देश्य से निर्वंध या श्रन्थ परिमटों पर बिदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति विदेश में होनेवाले भूमिगत यात्रा-स्यय ग्रीर ग्राकस्मिक **बचों की पूर्ति के** लिए दैनिक दरों के 20 प्रति-शत तक श्रतिरिक्त मुद्रा प्राप्त करने के पात्र हैं। निर्वंध परिमट के मुख्य के 10 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा मनोरंजन व्यय के लिए प्राप्त की जा सकती है बगर्से कि प्रध्यक्ष या निवेशक के नेतृत्व में जानेवाला वल प्रति याद्वा 100 पीष्ठ से प्रधिक खर्च न करे श्रीर श्रन्य बरिष्ठ कार्यपालक ग्रधिकारियों के नेतृत्व मे जानेवाला वार्ता दल 50 पौंड से ग्रधिक खर्च न करें। जो संस्थाएँ एक लाख कपयों से ग्रिक्षिक किन्तु पंद्रह लाख कपयों से भ्रमधिक मृत्य के परम्परेतर माल ग्रौर पांच लाख रुपयो से ग्रधिक किन्तु 75 लाख भ्पयों से श्रनधिक मूल्य के परम्परागत माल का निर्यात करती हैं उन्हें भी नियात विकास के प्राधार पर वर्ष में दो बार यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा प्रवान की जाती है । वाणिज्य मत्रालय में 'निर्यान प्रनिष्ठानों' के रूप में पंजीकृत निर्यातक पहले की तरह निर्वंध विदेशी मुद्रा परमिट प्राप्त करने के योग्य रहेगे, चाहे उनका पिछला निर्यात कार्य कुछ भी क्यों न हो । साथ ही निबंध परिमट के योग्य बनने के लिये ग्रन्य निर्यातकों के संबंध में निर्यातों की राशि की वार्षिक न्युननम बसूली के संबंध में विश्वमान मानवंडों में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थान उक्त मानदंड परम्परेतर माल के लिए पन्त्रह लाख रुपये ग्रीर परम्परागत माल के लिए पचहसर लाख नपये होगे।

406. भारत से बाहर रहते वाले व्यक्तियो, भारत में रहते वाले विदेशी नागरिकों, विदेश में निगमित कपनियों भीर ऐसी कंपनियों जिनमें गैर-रिहायणी हित 40 प्रतिशत में प्रधिक है और साथ ही ऐसी कंपनियों की शाखाओं को भी यह अनुमति प्रदान की गयी है कि वे निम्तलिखित मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ के लिए किसी भी व्यक्ति या कपनी को भ्रापते व्यापार चिन्हों का उपयोग करने दे : अर्थात् (i) नेपाल और भूतान को छोड़कर अन्य देशों को सम्पूर्ण रूप से निर्यात किये जाने वाले भाल और (ii) किसिय जीवन रक्षक और आवश्यक दवाइयो और पौधों के सरक्षण के लिए उपयोग में आनेवाली कीटनागक दवाइयो तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के संबंध में व्यापार चिन्हों को उपयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त सद (i) और मद (ii) के लिए जिनमें 17 प्रकार की

---वही---

के बराबर के कोई भी

दबाइयां श्रीर पौधे के संरक्षण के लिये उपयोग में श्रानेवामी 25 प्रकार की कीटनाशक दवाइया तथा अन्य रासायनिक पदार्थ शासिल है, रिजर्व वैंक ने कमश. श्रप्रैल 1975 तथा मार्च 1976 में गामान्य श्रनुमति दी है ।

#### मारत-मारिशस ऋण करार 1975

407 भारत सरकार ने 9 जनवरी, 1970 को मारिणम सरकार के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये । इसके अनुसार सुचिबद्ध, भारतीय वस्तुक्रों के अन्य क्रौर क्रायात तथा मारिशम में स्वीकृत परि-योजनाश्रों के लिए मारिशस सरकार को पाँच करोड़ भारतीय रुपयो तक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

### राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना

408. भारत स्थित बैंकों में जिन लोगों के राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना विशोष खाते रहते हैं उन्हें चाहे उन खातो की जमाराणिया कुछ भी क्यो न हों, अब (23 जून 1976 से) यह अनुमति प्रवान की गयी है कि वे भारत में किये जाने वाले निवेशो ग्रौर भारत को/भारत से की जानेवाली याला के किरायें के भुगतान को छोड़कर स्थानीय वितरणों में उक्त राणि का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करें। इन खातो की जमाराणियों से रु० 50,000 से प्रधिक राणि निकाले जाने पर प्रय तक जो प्रसियन्ध लागू रहा है उसे ग्रब हटा दिया गया है । ग्रब उनकी जमाराशियों का उपयोग (i) सावधि जमा खाते खोलने, (ii) भारत सरकार की प्रतिभृतियो या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटो में निवेश करने और (iii) रिजर्व बैंक की पूर्व प्रनुमति से भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए स्वतंक्रतापूर्वक किया जा सकता है। किन्सु उक्त निवेशों की विकी से या उनकी प्रविध समाप्त होने पर प्राप्त होनेवाली राशियों को फिर से राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजनः विशेष खाते में जमा कर देनः होगा । भारत को या भारत से भी की जाने वाली यात्रा के लिये इन खानों से किराये का भुगतान करने के लिए रिजर्व बैंक खांताधारियो या उनके श्राश्रितो का श्रावेदन किये जाने पर प्राधिकृत करेगा बणर्ते कि यात्रा एग्नर इंडिया या इंडियन एग्नर लाइंस सेवाधों द्वारा की जाये।

#### ग्रन्य गतिविधियां

409 इस क्षेत्र की अन्य गतिविधियों में निम्नलिखिन शामिल है: (1) 23 अप्रैल, 1976 से क्षियंद्रम और माने (हुलूसे), मालबीय द्वीप समह के बीच की हवाई याजा के लिए 'पी' फार्म पर भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट दी गयी है। मालदीव की याम्रा को विदेश यात्रा योजना 1970 के भ्रधीन यात्रा करने के जहेंग्यो के लिए विदेश यावा के रूप में नहीं माना आयेगा। (2) भारत ध्रौर चेकोस्लोवाकिया के वीच 4 दिसम्बर, 1974 को व्यापार ग्रौर भगतान संबंधी जो करार किया गया उससे इन दोनो देशों के बीच होनेवाले भुगतान गोधन से सबधित बैंकिंग व्यवस्थान्त्रों में 11 फरवरी, 1976 से कतिपय पश्चिनीन किये गये है । आगे से स्वर्ण खंड को संबंधित करारों में जोड़ने की श्रनुमति नहीं दी जायेगी श्रीर न ही भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई मे रहनेवाले चेकास्लोवाकिया श्रोबचोडनी बैंका, ए० एस० प्राहा (सी० एस० ग्रो०बी०) के केंद्रीय खाते की जमाराणि को स्वर्णखंड के ग्रांतर्गत लाया जाएगा । विशेष श्राहरण ग्रधिकार भौर रुपये के बीच की दरो के द्याधार पर करारो (इनमें एक वर्ष से द्रधिक भुगतान शामिल है) के साथ-साथ मी० एस० ग्रां० बी० के केद्रीय खाते की जमाराणि की भी सरक्षण प्रवान किया जायेगा । (3) विदेशी मुद्रा में होनेवाली घट-बढ़ को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने यह निष्चय किया है कि हवाई प्रद्वो और गोदी मे कार्यरन स्वयंपूर्ण सूद्रा परिवर्तको द्वारा भारत से बाहर जाने वाले विभिन्न श्रीणियो के यात्रियो का बेर्च जानेवाले विदेशी मुद्रा नोटों तथा मिक्कों के लिए क्पयों की सीमाएं निर्धारित की जाएं । उक्त सीमाए निम्न प्रकार है:

- (क) डेक याक्रियो सथा बंगला प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये 60 देश, भृतान, नेपाल, पाकिस्तान या श्री लंका जाने याले यास्त्रियो को मुद्रा नीट या सिक्के । छोड़कर ध्रन्य सभी यावी
- (ख) ग्रंनर्राष्ट्रीय पारपहा किसी ब्रन्य देश को जाने हुए याद्री पाकिस्तान जाने वाले
- (ग) पाकिस्तान जाने वाले यात्री प्रति व्यक्ति रुपये 30 के बराबर के पाकिस्तानी मुद्रानोट तथा सिमके।
- (घ) श्री लका जाने वाले यात्री प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये 30 फ़ारसी खाड़ी पत्तन या सिगापूर सुद्रा नोट **ग्रौ**र सि<del>क्</del>के। जाने वाले यात्री
- तथा बर्मा, पूर्व ग्रफीका, सलेशिया, के बरावर के कोई भी विदेणी
- (इ) बंगला देश जाने वाली यात्री प्रति व्यक्ति भारतीय रूपये 20 के बराबर के कोई भी विदेशी मुद्रा नोट और सिक्के।
- (4) कियाविधियों को सरल नथा सुमगत बनाने के लिए भारतीय रिजार्थ बैक 1 जून, 1976 से गैर-रिहायशी बैक खालो में विदेशी मुद्रा प्रेषित करने/जमा करने के लिए सभी परिमट बैंक के दो प्रधिकारियों के हस्ताक्षरों के साथ जारी करेगा चाहे उनका मुख्य कुछ भी क्यों न हो। जिन बैंकों को ग्रब सक परमिट के हस्ताक्षरों को सत्यापित करने की भावस्यकता थी ने भविष्य मे ऐसा नहीं करेंगे, श्रीर (5) वि वैग्य बैंक लि०, साऊय इंडियन बैंक लि० भ्रौर कैथोलिक सीरियन बैंक लि० की प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिये भारत में विदेशी मुद्रा के लेन-देन करने के लिये लाइसेंस प्रदान किये गये है।

सारणी 32 : जुलाई 1975 से जुन 1976 तक की प्रविध के सांख्यिकीय ग्रांकड़े

I विदेशों में ग्रध्ययन/प्रशिक्षण के लिये जारी किये गर्य विदेशी मुद्रा परमिट

	तकनीकी प	ाठ्यक्र <b>म</b>	गैर-तकनीकी पाठ्यकम		
देग	विद्याधियो/ प्रशिक्षणा- थियो की संख्या	प्रदान की गयी विवेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)	विद्याधियों/ प्रशिक्षणा- धियो की संक्या	प्रदान की गयी विदेशी मृद्रा की राशि (हजार रुपयों में)	
	499	8106	520	2201	
कसाधा	922	24298	648	12673	
भ्रन्य देण	179	1785	118	420	
সৌ <b>ত্ত</b>	1600	34189	1286	15294	

II भ्रष्ट्ययन/प्रशिक्षण से इतर उद्देश्यों के लिये जारी किये गये यात्रा परमिट

उद्देश्य	उन व्यक्तियो की संख्या जिनको परमिट जारी किये गये है	प्रदान की गई विदेशी सुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)
1. कारोबार	15596	151034
2. डाक्टरी चिकित्सा	380	7077
<ol><li>अध्ययन दौरे</li></ol>	636	5392
4 सम्मेलनो में भाग लेना	1476	4634
5. विविध	13429	23848
जोड़	31517	191985

### III 'पी' फार्म झावेदन पत्न*

उद्देक्य	उन व्यक्तियों की संख्या जिसके साथेदनपक अनुमोदित किये गये !
। परिवार के प्रमुख में मिलना	16938
2 रिफ्नेदारों में मिलना	18009
₃ नियति विकास	1167
<ul> <li>विदेशों में नौकरी</li> </ul>	37023
5 विदेशों में स्थामी निवास के लिए उत्प्रवाम	12412
<ul><li>विद्यार्थी/प्रणिक्षणार्थी</li></ul>	2697
7 বিশিষ	19128
भो <b>ड़</b>	107394

^{*}दन मामलों में कोई विवेशी मुद्रा प्रदान नहीं की जाती।

### VI. रिकर्व बैक द्वारा आयोजित सर्वेक्षण ग्रीर विचार गोळियां सर्वेक्षण

- 410 भारत मरकार के राष्ट्रीय तम्ता सर्वेक्षण संगठन श्रीर राज्य सरकारों के सांक्रियकीय केन्द्रों के सहस्रोग से रिजर्थ बैक द्वारा चलाये जानेवाले श्रीखल भारतीय ऋण श्रीर निषेश सर्वक्षण 1971-72 के कार्य में श्रालोच्य वर्ष के दौरान काफी प्रगति की गयी।
- 411 इस बर्ग सर्वेक्षण पर ध्यान देने के लिए बंक द्वारा नियुक्त की गयी सजावन समिति की दो बैठकें हुई और उक्त समिति ने कस संबंध में सैयार किये गये विभिन्न आधारभूत प्रपतों पर बिजार किया । पूर्ति के संबर्भ में भ% हारी केन्न में जायागि गयी विभिन्न व्यष् सर्वेक्षणों की जांच-पहताल पूरी हुई और उनके सारणीकरण में बाफी प्रगति हुई। 1961-62 में लेकर 1971-72 तक की अवधि के दौरान सहकारी आदोलन की प्रगति पर राज्यवार आधारभूत प्रगत्न तैयार किये जा रहे हैं। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उहिलकित 'वाणिज्य बैको द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विभागेवण' के सर्वेक्षण से सब्धित आवादों का सारणीकरण गमान्त हो गया और निपोर्ट का प्रावप तैयार किया गया। माग के संदर्भ में '30 जुन, 1971 को प्रामीण परिवारों को धारितयों पर एक पबंध तैयार किया गया है और बह अब छप रहा है। '30 जुन, 1971 को प्रामीण परिवारों की देशनाओं। पर एक प्रवध तैयार किया गया है और वह अब छप रहा है। '30 जुन, 1971 को प्रामीण परिवारों की देशनाओं। पर एक प्रवध तैयार वियत के रहा है।
- 112 प्रश्चित भरतीय ऋण घौर निवेश सर्वेक्षण 1971-72 की पहली ध्रनुस्ची पर कार्रवाई समाप्त हो गयी है श्रीर 30 जून 1971 का विद्यमान ग्रामीण परिवारो की ग्रास्तिया श्रीर देयताओं के श्राकड़ों की प्रमुक्त करनेवाला खाड़ 11 तथा ऐसी ही जानकारी प्रस्तुत करनेवाली राज्यवार माक्यिकीय पुस्तिवासे भी प्रवाणित की जाती है।
- 413 व्यक्षिक विभाग के ग्रामीण सर्वेक्षण प्रभाग ने श्रगस्त 1975 में 'छाटे कृषको (1967—69)' के सातर्व धनुवर्ती सर्वेक्षण की रिरार्ट ग्रीर नवकर 1975 में जुनी हुई छाटे कृपक विकास एजेंसियों के कार्यकलाप 1972-73 की रिपोर्ट प्रकाणित की । इन रिपोर्टी का उल्लेख पिछली व्यक्षि रिपोर्ट में किया गया था । सीमांत कृपक ग्रीर कृषि श्रम एजेंसियों के कार्यकलाप, 1973 की रिपोर्ट को ग्रानम रूप विद्या गया है भीर वह रिपोर्ट श्रम छप रही है । इस प्रभाग में (राज्य श्रीर नेल्ट्रीय) सरवारी वैकों के श्रीमों का वैमासिक गर्वेक्षण चलाया जाता रहा है श्रीर 1974 में वैमासिक सर्वेक्षणों पर श्राधारित सहकारी बैंक श्रीपमा की समीक्षा प्रकाणित की गर्यां । 'कृषकों की क्षम समावना (1969-70)' के क्षेत्रीय ग्राध्यन पर वार्यवाई की जा रही है ।
- (31) भारतीय रिजर्ब गैक वृत्रेटिन, दिसंबर 1975

- 4:4 स्थापार पसाग न 1970-71 से लेकर 1972-73 तम की प्रविध के सिए भारतीय उद्योग में विदेशी सहभागिता का सर्वेक्षण जलाया। विश्वरणियों का लगभग तीन चौथाई अर्थ प्राप्त हुआ है और श्रीकटा पर कार्रवार्ड की जा रही है।
- 415 ष्राधिक विभाग का अवर्गाद्रांप विस्तिप्रभाग विद्या निवेण के सर्वक्षण के लिए विदेणी कपनियों की णाखाओं और भारतीय संयुक्त पूजी कपनियों से लैमासिक रिपोर्ट आसिल्लन करता रहा । इस सर्वेक्षण के परिणाम 'भारत के प्रतर्राष्ट्रीय निवेण की स्थित 1968 ~ 72' णीर्पक के एक लेख में प्रकाणित किये गये उसे अंगर 1972-73 के लिए इसी प्रकार का एक लेख प्रकाशित किया गया उसे । इस 10000 में कम या समान राणि की जो विदेशी मुद्रा भारत में प्राप्त हाती है उसके लिए उद्देण्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है । ऐसी अवर्गीकृत प्राप्त का सर्वेक्षण जनवरी-सार्च 1976 की तिमाही के लिए णुरू किया गया । अभैत जून 1975 की तिमाही के सर्वेक्षण के आकड़ो पर कार्याई की जा रही है । जूलाई—सिनंबर 1974 के सर्वेक्षण की विवर्गणयों पर आधारित रिपोर्ट का अतिम रूप दिया जा रहा है ।

#### विचार गोष्टियां

416. कृषि पुनर्वित्त श्रौर विकास निगम ने कृषि बैकिंग महाविद्यालय, पूना में 'कृषि के लिए विकास बैकिंग' पर एक विजार गांग्डी चलायी । उक्त गोंग्डी में भूमि विकास बैंकों के मुख्य कार्गपालक श्रधिनारिया श्रौर बाणिज्य बैंकों के कृषि वित्त विकास के श्रध्यक्षा ने भाग लिया । इस वर्ष के दौरान राजस्थान श्रौर नागानैंड के जिलास्तरीय श्रधिकारियों के लिए परियोजना निर्माण श्रौर योजनाश्रों के कार्यान्वयन के लिए निर्देशक सिद्धांती पर भी विजार गोंग्डियों का श्रायोजन किया गया ।

### VII. मिक्षा ग्रीर प्रशिक्षण

417 श्रालोक्य वर्ष के दौरान रिजर्व कैंक की विभिन्न प्रशिक्षण सम्थाओं में रिजर्व कैंक, याणिज्य जैकों, सहकारी संस्थाओं तथा सरकारी विभागों के विभिन्न स्तरों ग्रथांत् श्रवर, पर्यवेक्षी श्रीर प्रवर स्तरों के श्रनेक कार्यपालक श्रीधकारियों को सामान्य श्रीर गहन प्रणिक्षण प्रवान किया जाता रहा । इस संदर्भ में जो प्रगति हुई उसकी सक्षेप में समीक्षा प्रस्तुत की आती है ।

### बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, यस्वर्ष

118. बैकर प्रणिक्षण महानिधालय द्वारा श्रायोजित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमो को इस प्रकार बनाया गया कि प्रवर्तक संस्थान्नों/की विशिष्ट श्रावश्यकताश्रो की पूर्ति की जा सके । इस उद्देश्य को ध्यान मे रुखते हुए पहले की तरह जहां ऋण विश्लेषण के नियमित पाठ्यकमो पर जोर दिया जाना रहा वहां महाविद्यालय में विकास वैकिस, मार्ग विक्ष्पेषण, निरीक्षण प्रसिमस्य प्रणिक्षण/उच्चयर निरीक्षण सबधी प्रणिक्षण, कार्मिक प्रबन्ध तथा सगठन स्रोर पद्वतिया जैसे विभिन्त विणेय विषयो पर कार्य-कम भी चलाये गर्ये । इनक अलावा परियोजना मृत्याकन ग्रीर पाथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ध्रमुवर्ती बित्त, बैकरा ने लिए सौस्पिकीय शास्त्र, कार्यकारी पुत्री के लिए ऋण तथा सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण के क्षेत्रों में भी पाच नये पाठाकम धारम किये गये । बैकर प्रशिक्षण महा-विद्यालय बैक के अपने अधिकारियों के लिए केन्सीय बैंकिंग/उच्चतर केन्द्रीय बैकिस तथा प्रशिक्षक पाठ्यकमो में प्रशिक्षण प्रदान किये भाने की। प्राव-श्यकतार्थों पर बराबर ध्यःन देना रहा । स्रालोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय के कार्यकलायों की एक प्रमुख विणेयता यह थी कि उसने बैकों के महाविद्यालयों के प्रणिक्षार्थियों के निए टडन प्रध्ययन दल की रिपोर्ट पर एक विचार गोर्च्छा तथा ऋण प्रवशन सबधी वार्यकम बलाने मे

^( 32) भारतोय रिप्तर्य वैंक वुलेटिन, जलाई 1975

⁽³³⁾ भारकीय रिजर्थ बैंक बुलेटिन, मई 1976

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान को सहयोग प्रदान किया । बैंकर प्रिणिकण महाविद्यालय ने इस उद्देश्य से भी प्रतेक कार्यत्रम चलार्य कि बेकिंग परिचालन प्रौर विकास विभाग के प्रवर प्रधिकारियों को टंडन प्रध्ययन दल की सिफारियों के प्रौधित्य से परिचित्त कराया जाए तथा उनके वियान्वयन सबंधी समस्यात्रों पर वे विचार विमर्श कर नर्के ।

419. कुल मिलाकर रिजर्व बैंक, वाणिज्य और विकास बैंकों तथा सरकारी विभागों के 1949 अधिकारियों ने आलोक्य वर्ष को विशेशन प्रशिक्षण प्राप्त किया, इस प्रकार महाविद्यालय की स्थापना से लेकर श्रव तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या बदकर 10367 हो गयी।

### कृषि बैकिंग महाविद्यालय, पूना

420. कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की प्रमुख विशेषना यह थी कि सहकारी बैंकिंग के स्थान पर कृषि बैंकिंग/किल के व्यापक क्षेत्र पर जोर विया
जाता रहा । स्वाभाविक रूप से इसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय ने
ग्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/विषय बैंक द्वारा कृषि पुनर्विक्त ग्रौर विकास निगम की
सामान्य ऋण प्रवान किये जाने के संवर्भ में कृषि परियोजना संबंधी
कई विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। प्रारंभ में कृषि संबंधी विकास बैंकिंग
पर ग्रगस्त 1975 में एक विचार गोष्ठी ग्रायोजित की गयी ग्रौर उसके
बाद कृषि परियोजना पाठ्यक्रम चलाये गये जिनमें एक सघन पाठ्यक्रम
भी सम्मिलित था। विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में स्थित बैंकों के लिये ग्रालोक्य
वर्ष के दौरान महाविद्यालय द्वारा ग्रायोजित किये जाने वात्र स्थानको
के पाठ्यक्रमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । उक्त पाठ्यक्रमों में
फमल कृण प्रणाली, जमाराशि संचयन, बैंककारी विनियमन ग्रंधिनियम ग्रौर
लघु सिचाई के लिए ऋण भावि विषय सम्मितित थे। वाणिज्य ग्रौर सहकारी/
भूमि विकास बैंकों ग्रादि के लाभ के लिए भी महाविद्यालय पाठ्यक्रम
कलाना गहा।

421. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दाले समिति की जिन सिफारिशो का उल्लेख किया गया था उनके धनुसरण में महाविद्यालय में प्राप्त मुजिधाओं को व्यापक बनाने की कार्रवाहर्य प्रारम की जा चुकी हैं। इस दिशा में पहले कदम के रूप में महाविद्यालय के सकाय में वृद्धि की गयी हैं।

422 महाविद्यालय की स्थापना में लेकर ध्रव तक उसमें सहकारी, भूमि विकास और वाणिज्य बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कुल 5,291 कर्मचारियों को प्रणिक्षण प्रवान किया गया है। जिनमें घालोच्य वर्ष के दौरान प्रशिक्षिम 1,527 कर्मचारी सम्मिलित है।

### स्टाकः प्रशिक्षण महाविद्यालय, महात

423 महाविद्यालय पहले की तरह मैंक के अपने प्रधिकारियों के लिए, स्टाफ अधिकारी विकास कार्येक्रम, गतिशीलता पाठ्यक्रम, निरीक्षण अधिकारी कार्येक्रम नथा ऋण प्रबन्धन कार्येक्रम चलाता रहा । ग्रेड क/ख में नये अधिकारियों की भी किये जाने के कारण महाविद्यालय ने उनके लाभार्थ प्रवेश पाठ्यक्रम के कई मल्ल चलाये । उनके प्रशिक्षण को अधिक सोहेश्य और आवश्यकता-आधारित बनाने के प्रयास में ऐसे सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों के 2-वर्षीय प्रशिक्षण की संपूर्ण योजना को इस प्रकार संशोधित किया गया कि स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय में संस्थायत प्रशिक्षण और व्याव-हारिक पर्यवेदिश कार्य पर अधिकारियों गये नये कार्यक्रम निम्न प्रकार थे: विदेशी मृद्रा कार्येक्रम जिसका उद्देश्य स्टाफ अधिकारियों को इस विद्या से विशेष रूप से प्रवयत कराना था तथा भी करण की अनुवर्ती कार्रवाई पर विद्यार गोप्टियाँ, जिनका छद्देश्य ग्रेड क और ख के स्टाफ अधिकारियों बैंक ऋण के नये वृद्दिकोण से परिचित कराना था।

424 प्रालीच्य वर्ष के वौरान गट्टन्वपूर्ण गनिविध यह यी कि स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए उसके कार्यकलायों के संबंध में निवेंगन देने तथा प्रावक्षक मार्गदर्शन प्रदान करने के निमित्त एक मलाह्कार समिनि का गठन किया गया । स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय की भूमिका सथा कार्यकलायों में हाल ही में किये गये विद्यानरण तथा उसके पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों/विषय यस्तुग्नों का मनन पुनरीक्षण करने के लिए ऐसी समिनि की प्रावक्षकता धनुभव की गयी । प्रशिक्षण के प्रभारी उप गवर्नर समिति के प्रध्यक्ष है नथा वैकिय परिचालन घौर विकास विभाग भीर कृषि ऋण विभाग के मुख्य प्रधिकारी, प्राधिक विभाग के परामशैवाता (प्रशासन), प्रबन्धक (प्रशिक्षण) तथा प्रबन्धक, महास, उसके सवस्य हैं तथा स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सदस्य-मनिष है ।

425. इस महाविद्यालय में भ्रव तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कुल संक्या 5193 है।

### क्षेत्रीय प्रशिक्षण केम्ब्र

426. बम्बर्ड, फलकत्ता, मद्राम श्रीर नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में लिपिक ग्रेंड I श्रीर लिपिक ग्रेंड II के लिए पाठ्य-कम श्रामेजिल किये जाते रहे। इन पाठ्यकमों की विषयवस्तुओं का सालधानी से पुनरीक्षण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ग्रंब श्रीर सुगठिल किया गया है तथा उनकी प्रशिक्षण श्रविध को लिपिक ग्रेंड I के संवर्भ में 10 सप्ताहों से घटाकर 8 सप्ताह श्रीर लिपिक ग्रेंड II के संवर्भ में 5 सप्ताहों से घटाकर 4 सप्ताह कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में दिये जाने धाले प्रशिक्षण को श्रीक प्रयोजनमूलक बनाने के निमित्त प्रायोगिक रूप में विश्वेष्ठित विभागों के लिपिक वर्ग के लिए श्रीर मामान्य विभागों के लिपिक वर्ग के लिए भायखाला केन्द्र में एक एक पाठ्यकम जलाया गया। इसमे प्राप्त मामुभव के श्राक्षार पर सभी केन्द्रों में इन पाठ्यकमों को शृक्ष करने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में श्रव तक प्रशिक्षण प्राप्त लिपिक वर्ग की कृत संख्या 11603 है।

### कर्नेचारी वर्ग की प्रतिनिय्दित

427. प्रक्रिल भारतीय/राज्यस्वरीय संघों, प्रबंध संस्थानों तथा इसी प्रकार के कुछ श्रन्य संस्थाओं द्वारा आयोजिन प्रबंध विकास आदि से संबंधित अस्पकालीन पाठ्यकां के लिए रिजर्व बैंक अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता रहा । इसके अलावा वाणिगटन स्थित आधिक विकास संस्थान, बैंक आफ इंग्लैंड, बैंकोक स्थित एशियाई आधिक विकास संस्थान, बैंक आफ इंग्लैंड, बैंकोक स्थित एशियाई आधिक विकास और आयोजना संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यकां में भाग लेने के लिए भी अधिकारियों को विदेश भेजा गया । बैंक के अधिकारियों ने ब्रिटेंस, पश्चिम अमैती, रोम आदि में स्थित ब्रींका आर विकास संस्थाओं द्वारा प्रदान की ग्री अध्ययन सुविधामां का भी लाभ उठाया । रिजर्व बैंक विदेशी वैंकिंग/केन्द्रीय वैंकिंग संस्थाओं के अधिकारियों/वरिष्ठ कार्यपालकों को अध्ययन प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करता रहा । यहां व अफगानिस्ताल बैंक द्वारा प्रेषित उत्त 10 अधिकारियों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है जिनके प्रशिक्षण की स्वस्था को लेको योजना की नकनीकी सहकारिता योजना के अंतर्गन की गयी है ।

### राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान

428. 1975-76 में राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने विशेष रूप में प्रामीण विकास पर जोर देने तथा ऋण प्रबंधन में प्रनुशासन लाने के संवर्भ में कई नये कार्बक्रम चलाये। 1975-76 में प्रारंभ की गयी प्रीर समाप्त की गयी कतिपय प्रमुखंधान परियोजनाएं निम्नलिखिल विषयों से संबंधित थीं: (i) षरेलू धवन और विन्तीय ग्रास्थिया, (ii) बंचल मुद्रा की मांग, स्टाकों के ग्रनुमानन और किसी क्षेत्र की

धर्मव्यवस्था के लिए ऋण योजना तैयार करने जैसे कितपय महत्वपूर्ण एवं भिन्न भिन्न विलीय क्षेत्रों में बैका के कार्यकलापा का प्रभाव, (iii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए जिल्ल, (iv) मधन क्षेत्र के छोटे क्षणकों के लिए ऋण समधी कार्यकलापों का संगठन, (v) देश के पूर्वीत्तर क्षेत्र में बैक सेवाए । संस्थान द्वारा चलाये गये सर्वेक्षणों में से एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किसी ग्रमुक नगर में बैका द्वारा प्रवान की जान नाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता से समधित था।

429. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान को सौपी गयी एक घन्य महत्व-पूर्ण परियोजना क्षेन्नीय ग्रामीण बैंकों के लिए क्रुपक नेवा समितियां गठित करने ने निमित्त ध्रग्रणी बलों के ब्यक्तियों की भर्ती करने भीर उनको प्रशिक्षण देने से संबंधित हैं। वैश के उत्तरी ग्रीर पूर्वी भागा में इस कार्यत्रम के लिए सदस्या का जयन करने के निमित्त एक एक शिविर का ग्रायोजन कर इस विशा में पहल की गयी।

430 भालाच्य वर्ष के दौरान 50 प्रशिक्षण मार्थक्रम सम्मेलन, विचार-गोध्व्या और नार्यशालाए चलायी गयी जिनसे 1,000 से श्रीयंक कार्यपालक प्रशिकारियों ने भाग लिया । राष्ट्रीय बैंक प्रवध सस्थान ने सुचाग्रस्त क्षेत्रों के नार्यक्रमों के ऋण प्रायीजना प्रशिकारियों के लिए भी कृषि वित्त निगम की सहभागिता के साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । प्रामीण विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय बैंक प्रवध संस्थान सयुक्त राष्ट्र संघ के एशियाई विकास सस्थान के सह-योग से कार्य कर रहा है। 1975 में कृषि विकास बैंका के श्रध्यक्षों का एक सम्मेलन धौर प्रवर्ग कार्यपालक ग्रीयकारियों के लिए एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया ।

### भारतीय रिजर्व बैक में हिंबी की प्रगति

431 घालीक्य वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वैंक ने और कई उपाय किये । इन उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं. (i) हिन्दी भाषी क्षेत्रा नथा महाराष्ट्र, गुजरात और पजाब राज्यों में स्थित बैंक के कार्यालयों में वर्षी पहनने वाले श्रेणी IV के कर्मवारियों द्वारा दिभाषिक बिल्ला का पयोग करना प्रयात बिल्ला पर हिन्दी तथा प्रग्नेजी दोनों में बैंक का नाम प्रदर्शित हो । (ii) उपर्युक्त कार्यालयों में बैंक की स्टाफ कारों पर विद्यमान नामपट्टों का दिभाषी-करण, (iii) उपर्युक्त कार्यालयों के प्रत्येक विभाग के लिए हिन्दी में टेलीफोन निर्देशिका वरीदना नथा (IV) प्रधिकारियों एव कर्मजारियों को, यदि वे चाहे तो कतियय शर्ती / परिसीमाम्रों के प्रन्तगंत मिक्तिरियों को, यदि वे चाहे तो कतियय शर्ती / परिसीमाम्रों के प्रन्तगंत मिक्तिरिक विचार विमर्शी और बातवीनों के लिए हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति देना। बैंक के कार्यालया/प्रशिक्षण सस्थायों में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किये गए जिससे कि कर्मचारी वर्ग हिन्दी के प्रपने कान को बनाए रख सके तथा उसमें वृद्धि कर सके।

432. राजभाषा प्रधिनियम, 1963 के उपबन्धों के प्रमुखरण में हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा महाराष्ट्र, गुजरान और पजाब राज्यों में शाखाएँ खोलने के लिए बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा हिन्दी और अग्रेजी वोना में लाइसेन्स जारी किये जाते रहे। विदेशी मुद्रा नियत्रण विभाग ने कुछ और परिमिट फार्म हिन्दी और अग्रेजी दोनों में मुद्रित किए।

4.3. बैक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैक तथा उसकी सहयोगी सस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में की गयी प्रगति का पुनरीक्षण करती रही। पिछले वर्ष किए गए निर्णय के अनुसार हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में बैक द्वारा समय समय पर जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के निए आयोज्य वर्ष के दौरान कामपुर सथा नई दिल्ली स्थित बैंक के कार्यान्यों में स्थानीय राजभाषा कार्यान्वयन समितिया स्थापित की गयी।

434 पिछले वर्षों की सरह इस वर्ष भी बैंक ने प्राप्ती वार्षिक रिपोर्ट तथा सहयोगी सस्थाम्रो की बार्षिक रिपोर्ट तथा मुद्रा भीर वित की रिपोर्ट (सिक्षप्त संस्करण) हिन्दी से प्रकाशित की। भारतोर रिजर्व बैंक का स्नेमासिक पृष्ट पत्न 'विदाउट रिजर्व' पहले की तरह हिन्दी खड़ो के साथ प्रकाशित किए जाते रह। दी प्रकाशित प्रयात भारतीय रिजर्व बैंक (मोट वापसी) नियमावती, 1975 तथा उसका सिक्षप्त मारांग जनता के लामार्थ हिन्दी मे प्रकाशित किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण सुविधा योजना 1975 का हिन्दी पाठ तैयार किया गया भीर भारतीय रिजर्व बैंक कुनेटिन मे प्रकाशित किया गया (अ)। पिछले वर्ष बैंकिंग शब्दावली हिन्दी मे तैयार करने का जो कार्य प्रारम्भ किया गया प्रगति कर रहा है।

135 हिन्दी प्रध्ययन महस तथा मान्यताप्राप्त हिन्दी पराजारं उनीणं करन के लिए बैंक के कर्मचारियों को मानदेव प्रदा करने की याजना जारी रही। केन्द्रीय हिन्दी निवेशालय, शिक्षा मन्नालय द्वारा चलाये जानवाल प्रधाचार पाठ्यकमों की सुविधा का भी किनप्य कर्मचारियों ने लाभ उठाया। बैंक के प्रधिकारिया के लिए 1974 में शुरु की गयी प्रनिवार्य हिन्दी शिक्षण योजना प्रालोक्य वर्ष के दौरान साल और केन्द्रों में चलायी गयी। हिन्दी टकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बैंक के टंककों को उपलब्ध नकदी प्रीत्साहन योजना को बैंक के प्राशुलिपिको तथा वैयक्तिक सहायकों के लिए भी लागू किया गया।

436 मैंक ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रयाग म 6 विसम्प्रद म 8 विसम्पर 1975 तक प्रायोजित सम्मेलन में भाग लिया। बैंक ने इस सम्मेलन में भें को में हिन्दी जीवंक की प्रवर्शनी की व्यवस्था की प्रौर उसने रिजर्व बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का जिल्ल प्रस्तुत किया गया। नई दिल्ली में 14 मई से 16 मई 1976 नक प्रविल्य भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली और हिन्दी विद्यापीठ, देवगढ़ (बिहार) के सयुक्त तत्वावधान में प्रायोजित दितीय राजभाषा सम्मेतन के प्रवसर पर भी बैंक ने इसी प्रकार की प्रदर्शनी का प्रायोजन किया।

### तरकारों क्षेत्र के बैकों में हिन्दी की प्रगति

437 घालोक्य वर्ष के दौरान यह सुनिष्ठित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गये कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैको मे राजभाषा प्रधिनियम 1963 के उपबन्धों का धनुपालन हो। राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग स्कध) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में किये ग्ये प्रमुख निर्णयों भी सूचना सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको को उनके मार्गवर्यंत और प्रनुपालन के लिए दी जाती रही। बैंको द्वारा प्रस्तुन की गयी विभिन्न रिपोटों प्रयान् (क) क्षेमासिक प्रगित रिपोटों, (ख) मूल्याकन रिपोटों, (ग) समदीय समिति के लिए प्रपेक्षित रिपोटों, (ध) बैंकिंग परिचालन भीर विकास बिभाग द्वारा जारी किये गये विभिन्न परिपत्नों पर की गयी प्रमुवर्ती कार्रवाही की रिपोटों, (इ) राजस्व और बैंकिंग विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णयों की धनुवर्ती कार्रवाह की रिपोटों के भाधार पर उनके द्वारा की गयी प्रगित से भारत सरकार को प्रवगत कराया जाता है।

438 सरकारी क्षेत्र के बैको बारा की गयी प्रगति का अध्ययन करने तथा उन बैको को हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में विये गये अनुवेशा के कार्यान्ययन में आनेवाली समस्याओं, यदि कोई हो—पर विचार विमर्श करने के निमित्त बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ने 29 प्रगस्त, 1975 को बैंका के वरिष्ठ कार्यपालक प्रधिकारियों की एक अनौपचारिक बैठक बुलायी। जिन बैका के प्रधान कार्यालय बस्बई में है उन्हे तथा बैंक आँक महाराष्ट्र को बैठक में भाग लेने के लिए आमित्रत किया गया। भाग नेनेवाले बैंकों ने यह इस्छा व्यक्त की कि बार-बाए ऐसी बैठक अभीजित की जानी पाहिएं ताकि राजभाषा कार्यक्ष को कार्यान्वित करने

⁽³⁴⁾ विसम्बर 1975 मण

के लिए सरकार द्वारा जारी किये जाने बाल धनुदेशों पर विचार-विमर्श किया जा सके तथा समस्याद्यों को मुलकाने के लिए नरकाल निर्णय किये जा सके:

439. इस उद्देष्य में तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सरकारी क्षेत्र के बैको द्वारा किमे जाने वाले प्रयासों को समन्वित करने के निमित्त यह निर्णय किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैक के बैकिंग परिचालन श्रीर विकास विभाग से एक राजभाषा कार्यान्वयन समित्ति गठित की जाए, जिससे निम्नलिखित सदस्य होगे।

ा मुख्य प्रधिकारी, बैकिंग परिचालन ग्रीर विकास विभाग,	भारतीय
रिज्ञवं यैक, ब्रम्बई	घध्यक्ष
ւ স্বল্লক (সলিঞ্ল্ল), সলান্ত্র দ্বাহিক বিদাণ,	
भारतीय रिजर्व वींक, वस्त्रई	सवस्य
14 प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैक का एक एक प्रतिनिधि	सदस्य
) स्टेट बैक ग्रांफ इंडिया का प्रतिनिधि (बहु स्टेट बैक ग्रांफ इंडिया के मान सहायक बैको का	सदस्य

भी प्रतिनिधित्य करेगा)

1 महायक प्रवक्षक, हिन्दी प्रभाग, भारतीय रिजर्व वैक,

बस्बई . . . . . . . . स्वस्य संचिक

18

440. वैशिंग परिचालन भीर विकास विभाग का हिन्दी कक्ष उक्त समिति के सिवशालय के रूप में कार्य करेगा। यह समिति सरकारी क्षेत्र के 22 बैकों में कार्यरत सभी राजमाणा कार्यान्त्रयन समितियों के लिए केस्त्रीय समन्यय समिति के रूप में भी कार्य करेगी।

#### VIII लंबो ग्रीर अभ्य विवय

441 30 जून 1976 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समायाजन करने के बाद श्रीक की भाग 516.00 करोड़ इपये थी जबकि पिछले वर्ष की भाग 448.01 करोड़ इपये थी। विभिन्न स्नातों से प्राप्त ग्राय का विवरण निम्न प्रकार है:

	(राशि करोड़ रुपयों में)		
	चर्ष		
	1975-76	1974-75	
1	2	3	
(i) राज्य सरकारा की विये गये अर्थीपाय अधिमापर ब्याज (ii) राज्य सरकारा (उपर्यक्त मद (i) में उल्लिखिन अर्थीपाय अगिमो पर प्राप्त ब्याज का छाडकर) श्रीर क्षाणिज्य तथा सहनारी कैका का विये गये ऋणों	11.80	13.01	
भौर प्रग्रिमो पर ब्याज (iii) रुपया प्रतिभृतिया पर ब्याज भौर	98.81	65.54	
रपया खजाना बिलो पर बट्टा (iv) विवणी प्रतिभृतियो, निवेशो भौर	306.61	290.35	
खजाना बिलो पर ब्याज भीर बट्टा (v) बिनिसय से भ्राप्त कमिणन भीर लाभ	80.26	59.81	
या उपलब्धि	1 ≟, 7 ↔	4.13	
(vi) भ्रन्य भाष	13.30	18,98	
	523.54	451.82	

1	2	3
घटाइए- पिजबं बैक के पास भनुसूचित बैको ढारा रखी व्ई श्रांतरिकत श्रीसत दैनिक जेमा राशियो पर		
उन वैंको को दिया गया व्याज	7.54	3,81
	516.00	448.01
घटाइएनिधियों में किये गये धन्तरण, जैसा कि नीचे विये गये धनुज्छेद		
2 में दर्णावा गया है	221 00	220 00
	295,00	228.01

442. राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय श्रीदांगिक ऋण (दीर्घ-कालीन प्रवर्तन) निधि में जो भगवान किये गये उनकी राशि जहा 1974-75 के दौरान अमण: 50 करोड़ रुपये, 45 करोड़ रुपये श्रीर 125 करोड़ रुपये थी बहा 1975-76 के दौरान 68 करीड़ रुपये 5 करोड़ रुपये निधा 150 करोड़ रुपये थी।

443 इस वर्ष के दौरान 105,00 करोड़ रुपयों का कुल बयय होने के बाद 295.00 करोड़ रुपयों की जो आय शेष भी (पिछले वर्ष 78.01 करोड़ रुपयों का क्यय हुआ था तथा 228.01 करोड़ रुपयों की आय शेष थी) उसमें से केन्द्रीय सरकार को भदा करने के लिए रखी गयी लाभ राणि 190 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष अया की गयी राशि 150 करोड़ रुपये थी।

444, पिछले वर्ष की 448.01 करोड़ रुपयों की झाय की तुला में इस वर्ष आय बहुकर 516.00 करोड़ रुपये हो गयी। इसी प्रकार उसमें 67.99 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे: (i) राज्य सरकारों और वाणिज्य तथा सहकारी वैकों को विये गये ऋणों तथा प्रश्निमी पर अजित उक्चतर ब्याज; (ii) आलोक्य वर्ष के दौरान प्रारक्षित विदेशी मुक्षा निधियों से हुई वृद्धि के कारण अजित उक्चतर ब्याज; और (iii) खाजाना बिलों पर अजित उक्चतर बहु। व्यय में 26.99 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे: (i) भारतीय स्टेट बैक द्वारा जो सरकारी कारोबार चलाया जामा है उसकी लागत को सुनिधिचल करने के लिए गठित समिति की मिकारियों के झाधार पर, 1970—75 की प्रविधि के दौरान सरकारी लेनदेनों पर भारतीय स्टेट बैक तथा उसके सहायक वैकों को प्रदत्त बकाया कमीशन; (ii) नोट कार्मों की निर्माण लागन में हुई वृद्धि; और (iii) संधित उपदान सम्बन्धी देयता के कारण उपदान तथा सेवानिवृत्ति निधि के श्रीवान में वृद्धि।

#### लेखा परीक्षक

445 बैंक के लेखों की परीक्षा मैसमें सी० मी० चोक्सी एण्ड कंपनी, बम्बई, मैसमें लबलॉक एण्ड ल्यूज, कलकत्ता, मैसमें रचुनाच राय एण्ड कंपनी, नयी विल्ली सथा मैसमें एम० के० विजेकर एण्ड कंपनी, महास द्वारा की गयी, जिन्हें भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक प्रधित्तियम, 1934 (1934 का 2) की घारा 50 द्वारा प्रवन्त शिक्स्यों का प्रयोग करने दुए जारी की गयी दिनाक 15 मई 1976 की ब्रिक्स्यना स० एफ० 1 (12)/76/लेखा । और II द्वारा नियुचन किया था। सरकार के द्वारा मैसमें विलास एण्ड कानी के स्थान पर कमणः मैसमें सी० सी० भोक्सी एण्ड कंपनी तथा मैसमें लवलॉक एण्ड ल्यूज की नियुक्त की गयी। मैसमें रचुनाथ राय एण्ड कंपनी और मेससे विजेकर एण्ड कंपनी की सरकार ने पूर्वः नियुक्त किया है। इस वर्ष बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षको द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्वास

सथा नवी दिल्ली के कार्यालयों के प्रालावा बैंक के भाषाल तथा भुवनंश्वर के कार्यालयों की लेखा बहियों की भी परीक्षा की गयी। बस्वई, कलकत्ता, मद्राम तथा नयी दिल्ली के कार्यालयों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षका का पारिश्रमिक बिना किसी परिवर्तन के प्रति कार्यालय कु 15,000 रहा । भोषाल तथा भुवनंश्वर कार्यालया के लिए उक्त पारिश्रमिक प्रति कार्यालय क० 10,000 था।

### केम्बीय बोर्ड

446. श्री एन० सी० सेनगुप्ता ने 19 श्रगरत 1975 को कारोबार बद होने के समय से बैक के गर्बनर का पद भार छोड़ दिया तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक श्रिधितियम, 1934 की धारा 8(1)(घ) के श्रधीन प श्रम्तुबर 1975 से बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ना निदेणक नामित किया गया।

447 श्री के० झार० पुरी को 19 भगस्त 1975 को काराबार बद हाने के समय से एक वर्ष की श्रविध के लिये भैक के गर्वार के रूप मे नियुक्त किया गया। इस सबर्भ में दिनाक 18 भगस्त 1975 की भारत सरकार की प्रिक्षित्वना स० एक० 7/11/75 बी० श्रो० 1 देखिए। उन्होंने 20 झगस्त 1975 के पूर्वाह्म से बैक के गर्थनंग का पर भाग सभाला। उनकी पदावधि भौग दो कर्षों के लिये बढा दी गयी है।

448 बैक के उप गर्वनर के रूप में श्री बी० बी० बारी की पदाबधि 16 नवम्बर 1975 को समाप्त हुई, केन्द्रीय सरकार ने उनकी पदाबधि को नवम्बर 1975 के अस तक बढ़ा दिया था। श्री बारी ने 30 नवम्बर 1975 को कारोबार बंद होने के समय से बैंक के उप गर्वनर का पद भार छाड़ दिया। श्री एस० एस० शिरासकर ने 17 दिसम्बर 1976 का अपनी पदावधि समाप्त होने पर बैंक के उप गर्वनर का पदभार छोड़ दिया। बैंक के उप गर्वनरों के रूप में सर्वश्री बारी तथा शिरासकर द्वारा अपने कार्यकाल में भी गयी अमृस्य सेवाआ की सराहना करने हुए बोर्ड उनके प्रति अपना आभार स्यक्त करना है।

419 बैंक के कार्यकारी निर्देणक डा० के० एस० कुष्णस्वामी तथा श्री पी० ग्रार० नागिया को भारत सरकार ने बैंग के उप गर्वनरों के रूप में 29 दिसम्बर 1975 से 28 दिसम्बर 1980 तक पाच वर्षों की प्रविधि के लिए नियुक्त किया ।

450 डा० डी० पी० सिह तथा श्री अभवार हैदरी का 13 नवस्वर 1975 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 12 की उप- धारा (5) के साथ पढ़ी जाने वाली उप धारा (4) तथा धारा 8 की उपधारा (1) के खड (ग) के अधीन रिक्व बैंक क मेडीय बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया। श्री अकबर हैदरी की भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप धारा (7) के साथ पढ़ी जाने वाली उप धारा (1) के खड (ग) के अधीन केबीय गरकार द्वारा 22 अप्रैल 1976 से चार वधों की अवधि के लिये पुनर्गित किया गया।

451 आलाक्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठके हुई, उनमें से दो बैठके बस्बई में तथा एक-एक बैठक मद्रास, पणत्री (गोवा), कलकला, गौहाटी तथा नयी दिल्ली में हुई, केद्रीय बोर्ड की समिति की बाबन बैठके हुई जिनमें से दो बैठके नयी दिल्ली में हुई।

452. श्री जें० सी० लूबर, विशेष वार्य अधिकारी का 21 दिसम्बर 1975 स बैंक के गार्यकारी निवेशक के रूप में नियुक्त ति ।। गया।

### स्थानीय बोर्ड

453 आलोच्य वर्ष के दौरान स्थानीय बोर्ड के स्वरूप या उसके सदस्यों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

#### प्रेस सम्पर्क

154 प्रेम सपर्क प्रनुषाग बैक प्रीर उसकी सहयागी सस्याघो के कार्यकलापो के बारे में जनता का अवगत करानं की अपनी भूमिका का निर्वाह करना रहा । यह अनुभाग पाक्षिक न्यूज लेटर प्रकाशित करना रहा तार्वि बैक के कमंचारी वर्ग को बैक के विभागा/कार्यालयो तथा सहयोगी सम्थाधों के सहत्वपूर्ण कार्यों तथा भावरिक मामला पर भ्रज्ञतन सूचना प्रदान करने के प्रमावा आर्थिक, विसीय सथा बैकिंग क्षेत्रों की वर्तमान गतिविधिया से भ्रवगत कराया जा सके । आलोच्य वर्ष के दौरान इस अनुभाग ने "भारतीय राष्ट्रिकता बाले गैर-रिहायणी व्यक्तियों को भारत में धन प्रेषित करने की मुविधाए" और "विदेशों में रहने वाले भारतीया पर लागू होने बाले विदेशी मुद्रा विनियम नामक वो सूचनाप्रव पुस्तिकाए प्रवाणिक की।

### बैंक के भवन

455 झालांच्य वर्ष के दौरान भैक की विभिन्न निर्माण परियोजनामों के कार्यक्रम पर प्रितिकृत प्रभाव पद्दा, क्योंकि 1973 में सरकार द्वारा परिचानतेतर भवतों के निर्माण पर लगाये गये प्रतिवक्ष को प्रारंभ में 1975-76 के विक्षीय वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, किन्तु बाद में उस जनवरी 1976 में हटा दिया गया । फिर भी बैक ने भुवनेश्वर, गोहाटी और क्रिवेश्चम में कार्यालय भवन निर्माण की परियोजनामों और भुवनेश्वर, हैवराबाव तथा चडीगढ़ की प्रावस निर्माण परियोजनामों को कार्याल्य करने के लिए छूट प्राप्त कर ली थी, क्योंकि इन परियोजनामों के प्रत्योजनामों के प्रत्योजनामों के प्रत्योजनामों के प्रत्योजनामों के प्रत्योजनामों के क्रांचाय परियोजनामों के क्रांचाय परियोजनामों के क्रांचाय परियोजनामों के कार्य में सीमेट की कभी के कारण जो गरंयवरोम मा या यह सीमेट (सरकाण और उपयोग का विनियमन) आवैश 1974 के ध्राधीन सरकार द्वारा मीमेट के उपयोग पर पहले लगाये गये प्रतिकाध को हटा विये जाने के फलस्वरूप दूर हो गया । निर्माणाधीन नयी परियोजनामों की वर्तमान स्थित किम्तलिखित अनुच्छेदों में दर्शाई गयी है।

### नये कार्यालय भवन

456 झालांच्य वर्ष के दौरान बस्बई स्थित टकसाल के प्रहात में बैंक के बहुमिजले कार्यालय भवन के निर्माण कार्य में सतायजनक प्रगति हुई धौर पहली मिजल तक का निर्माण कार्य सपन्त हो गया। हैदराबाद स्थित बैंक के कार्यालय भवन का प्रबन्तित सीमेंट कार्जीट कार्य प्राय पूरा हो चुका है धौर भवन निर्माण सबधी ध्रांतम कार्य में ध्रब प्रगति हो रही है। भुवनेण्वर, गोहाटी धौर त्रिवेन्त्रम में बैंक के कार्यालय भवनों के सबर्भ में निवित्त निर्माण कार्य के ठेके दे दिये गये हैं धौर उनका निर्माण कार्य आरी है।

#### ग्राबास भवन

457 प्रालोक्य प्रविध के दौरान बम्बई में बैंक के प्रधिकारियों के लिये 152 क्यार्टर तथा कलकता और महास में कलकों प्रौर प्रधीन कर्मचारियों के लिये 283 क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन्हें मिलाकर, रिजर्व बैंक द्वारा प्रपने कर्मचारियों का प्रदान किये गये क्वार्टरों की कुल मख्या 3,890 से बद्धकर 4325 हो गयी है। इनक प्रतिक्ति क्लां और प्रधीन कर्मचारियों के लिये 326 क्वार्टर प्रधीन कांडस्थाककम पुत्र, मद्राम मं 140 लया प्रांमबॉर्न रोड, बंगल्य में 186 क्वार्टरों मा निर्माण कार्य प्रपने प्रतिम चरण में है। हैदराबाद और मुधनेक्वर में 305 स्टाफ क्वार्टरा के लिये सिविल निर्माण कार्य है और उनके कार्य में प्रगति हा रही है।

### कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि की खरीब

158. कोचीन में कार्यालय भवन श्रौर स्टाफ क्वार्टरों के लिये तथा पटना में श्रनिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के लिये भूमि ले ली गयी है।

#### मालिक-कर्मचारी संबंध

459. श्रालोक्य वर्ष के दौरान बैंक में मालिक-कर्मकारी संबंधो पर प्रस्थक्ष प्रभाव बालने वाली दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई । पहली घटना धी 25 जून 1975 को भारत भरकार द्वारा राष्ट्रीय श्रापानकाल की घोषणा तथा दूसरी थी 19 मार्च 1976 को भारत मरकार द्वारा की गयी वह घोषणा जिसके द्वारा रिजर्व बैंक की सेवा को भारतीय रक्षा श्रीर श्रांतरिक मुरका कानुन, 1971 के शक्षीन श्रांतिवार्य सेवा बोधित कर दिया गया।

460. राष्ट्रीय प्रापानकाल की घोषणा के तत्काल बाद, रिजर्व बैंक ते सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के प्रन्य संगठकों के समान ही बैंक में कार्यक्षमता तथा प्रमुणासन को बढ़ाने के लिये प्रनेक कदम उठाये । समय निष्ठा, उपस्थित, कर्तव्यनिष्ठा, खर्च में मितव्ययिता, समयोपिं कार्य में कमी जैसे कतिएय विषयो पर निष्ये ध्यान दिया गया । जुलाई 1975 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बस्बई में सभी विभागों के श्रध्यक्षों से मिले । उसके बाद वैंक के सभी कर्मचारी वर्गों के कार्यों को विनियमित करने के लिये कई प्रमुदेश जारी किये गये । बाद में, गवर्नर ने प्रप्रेल 1976 में बस्बई में प्रबंधकों का एक सम्मेखन बुलाया जिसमें बैंक के सभी कार्यालयों के प्रबंधकों तथा स्थित सभी विभागों के प्रध्यकों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में अब तक हुई प्रगति के साथ-साथ क्षमता तथा प्रमुणासन को नढाने के लिये प्रपेक्षित दूसरे कदमो पर विचार-विमार्ण किये गये।

461. रिजर्व बैंक ने बैंक के भृतपूर्व वरिष्ठ कार्यपालक, श्रीकारी श्री बी० ए० राव की श्रध्यक्षता में बैंक में ग्राहक सेवा, निर्यंक श्रीर प्रतिक्षंध्र कर पद्धितयों श्रावि के संबंध्र मे श्रध्ययन करने तथा उनमे सुधार करने के लिए श्रावश्यक सिफारिशे प्रस्तुत करने के निमित्त एक उच्च स्तरीय समिति की भी नियुक्ति की । उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को यथानंभव शीधातिशीध्र कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रबंधकों के सम्भेलन में विचार-विमर्श किये गये । श्रापातकालीन स्थिति के कारण बैंक द्वारा किये गये उपायो श्रीर रिजर्व बैंक की सेवा को श्रस्यावश्यक सेवा घोषित कर विये जाने के संवर्भ में, बैंक में क्षमता तथा श्रनुशासन का एक सुधरा हुआ बातावरण निर्मित हुआ।

462. रिजर्व बैंक में बेहतर क्षमता तथा अनुशासन का वातावरण निर्मित करने के लिये बैंक द्वारा उठायें गयें उक्त कदमों के साथ-साथ बैंक ने कर्मचारी मंगठमों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनायें रखने के संदर्भ में ग्रापने प्रथतन जारी रखें । उक्त संगठनों के द्वारा उठाये गये विभिन्न जिच्यों पर निम्नप्रकार केंद्रीय कार्यालयीन स्तर पर विचार-विमर्ण हुए:

**प्र**गस्त 1975--

- (1) बैंक के क्लर्क श्रेणी के कर्मचारियों का प्रति-निधित्व करने वाले प्रतिक्रल भारतीय रिक्कर्व बैंक कर्मचारी संघ के साथ।
- (2) बैक के प्रधीन कर्मनारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीखल भारतीय रिजर्व बैक कामगार महासंध के साथ।

जनवरी 1976--

श्रिश्चिल मारतीय रिज़र्ल वैंक स्टाफ ग्रिशिकारी संघ के साथ।

भाग्रेल 1976-- भारतीय रिजर्ष बैंक ग्रक्षिकारी संघ के साथ।

463. शाखा-स्तर पर कार्यालयों के प्रबंधकों/प्रभारी प्रधिकारियों ने प्रपने केन्द्रों के स्थानीय कर्मचारी संध/कामगार यूनियन के यूनिटों के प्रतिनिधियों के माथ समझौता बैठकों/विचार-विमर्गों का प्रायोजन किया।

464. पिछले वर्ष की तरह 1975-76 के दौरान भी रिजर्ब बैंक कर्मचारी खेल-कूष क्लब, स्टाफ केंट्रिन, सिभिन्न स्टाफ क्लाटरों में स्थित कल्याण संगठन जैसे विभिन्न कल्याण कार्यों के लिए संरक्षण/विक्तीय सहायता प्रदान करता रहा।

465. बैंक का समासिक गृह एत्र बैंक के कर्मजारियों को धपती साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा दूसरी प्रतिभाधों को धिक्यिक प्रदान करने तथा सामाजिक धौर घरेलू क्षेत्रों के कार्यकलापों को प्रचारित करने के लिए लोकप्रिय मंच प्रवान कर रहा है। पिछने वर्षों की तरह बैंक द्वारा प्रारंभ की गयी कर्मजारी सुझाब योजना के प्रधीन विभिन्न कर्मचारियों से सुझाब प्राप्त हुए।

### कर्मचारी सावात ऋण योजना

466. 1961 में इस योजना का प्रारंभ होने से लेकर भव तक मजूर किये गये 'समिति' भौर 'ब्यक्तिगत ऋण' की कुल राशि कमशः य० 6,21,92,993.00 श्रोर ६० 3,94,28,068.00 है। कुल 3,885 कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

467. भालोच्य वर्ष के दौरान निम्नप्रकार गृह-निर्माण ऋण मंजूर किये गये:

	ममितियों की संख्या	रा <b>गि</b> ६०
(म्र) नई सहकारी गृह-निर्माण समितियां पहले ही गठित सहकारी	4	20,61,061.00
गृह-निर्माण समितियों को म्रतिरिक्त ऋण	4	31,73,133.00
	कर्मचारियों की संख्या	52,34,194.00 राशि स्रु
(म्रा) म्रलग-म्रलग कर्मचारियो को प्रदत्त ऋण उन कर्मचारियों को प्रदत्त स्रतिरिक्त ऋण जिन्होने	218	64,66,502,00
पहले ही ऋण प्राप्त किये थे	54	17,17,426.00
		81,83,928.00

### बैंक की सेवामों में मनुसूचित जातियों ग्रौर मनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

468. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस संबंध में किये गये विशेष उपायों का उल्लेख किया गया था, जैसे पालना और योग्यला संबंधों मूल मानदंशों में छूट दी गयी, वैंक की सेवाओं में भारिकत पतों के संबंध में मिशक ज्यापक प्रचार किया गया और जहां भावश्यक हो नहां केवल मनुसूचित ज्ञानियों भीर जनगानियों से विषेष भर्ता की गयी; इन उपायों के गाय-साथ समय-समय पर जारी कियें गये प्रशासकीय अनुवेशों का परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न संवर्गों में अनुसूचिन ज्ञानियों के प्रतिनिधित्य में वृद्धि हुई है और इसके साथ ही उसमें जो-जों कमी रह गयी थी वह काफी सीमा तक दूर कर दी गयी है। प्रायोच्य वर्ष में भी उक्त विशेष उपाय जारी रहे और इसके परिणामस्वरूप बैंक की सेवाग्नों में अनुसूचिन ज्ञातियों/जनजानियों के प्रतिनिधित्य में और वृद्धि हुई। 1 जनवरी 1975 को अनुसूचिन ज्ञानियों/जनजानियों के कम्मेंचारी श्रेणी IV में 1,043 श्रेणी III में, 1,412 तथा श्रेणी II और I में 48 थे और उक्त सक्या बढकर 1 जनवरी, 1976 को कमणः 1,217; 1,750 और 53 हो गयी है। इसके अनावा श्रेणी III के संवर्गों में अनुसूचिन ज्ञानियों/जनजानियों की भर्ती में जो कभी रह गयी थी उसे कमणः 69 प्रतिणत और 18 प्रतिणत की सीमा तक दूर किया जा सका। साथ ही उनके लिए निर्धारित वर्षमान कोटे को भी पूरा किया गया।

- 469. पिछले यर्षां की सरह ही, रिजर्व बैंक प्रधिकारियों के संबर्ग मे अनुसूजित जातियों और अनुसूजित जनजातियों के प्रतिनिधित्व मे वृद्धि करने के लिए उत्सुक है। तदनुमार:
- (1) भारतीय रिजर्व बैंक सर्विभेज बोर्ड को यह सूचित किया गया कि वह प्रशासन की क्षमता को बनाए रखने के सम्बन्ध में प्रपेक्षित मानवड़ों मे श्रावश्यक संदर्भों में छूट वेकर स्टाफ श्रिष्ठकारी ग्रेड 'क' (सीधी भर्ती) के रूप में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/श्रनुसूचित जनजातियों के उम्मीददारों की सिफारिश करे। श्रतएद श्रासोच्य वर्ष में बोर्ड श्रपने चयन को श्रीतम रूप देकर श्रनुसूचित जातियों श्रीर अनुसूचित जनजातियों के लिए

- न्नारक्षित 37 पदों के स्थान गर स्टाफ श्रधिकारी ग्रेड 'क' (सीधी भर्ती) के रूप में नियुक्ति के लिए 34 उम्मीदयारों की लिफारिण कर सका।
- (2) सितंभ्बर 1975 में स्टाफ श्रिषकारी ग्रेड 'क' के संबर्ग में पदोन्नति के लिए अनुसूबिल जातियों/अनुसूबित जनजातियों के कमचारी श्रर्हता परीक्षा में बैठे थे; उन्हें भी कतिपय छूटें प्रदान की गई जिसके फलस्बरूप परीक्षा में बैठे व्यक्तियों में से 31.4 प्रतिणत व्यक्ति सफल घोषित किये गये जबकि पिछली परीक्षा में केवल 17.8 प्रतिणत व्यक्ति सफल हुए थे।
- 470. धनुसूचित जातियों/धनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को बील दिये गये मानवंड के धाधार पर चयन करने की उक्त नीति स्टाफ धिकारी ग्रेड 'ख' के संवर्ग के लिए भी लागू कर दी गयी है।
- 471. धालोक्य वर्ष के दौरान, बैक ने यह निश्चय किया कि श्रेणी []] धौर [V के कर्मचारियों के लिये बनी हुई बैंक की कॉलोनियो में धावास गृहो का विनरण करने में 10 प्रतिशत धावास गृह धनुसूचित जातियों और धनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिये धारक्षित किये जाएं।
- 472. केंद्रीय कार्यालय में गठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष के एक अधिकारी ने इस वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भर्ती के लिये रखे गये रोस्टरों तथा इन समुदायों के कर्मचारियों को प्रवान की जाने वाली अन्य कई रियायतों के संबंध में केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के कार्याल्यन की जांच करने के लिए बैक के कुछ और कार्यालयां अथीत् कलकता, गोहाटी, नागपुर, पटना, कानपुर, अहमबाबाद और जयपुर कार्यालयां का दौरा किया।

### मारतीय रिजर्भ वैक

### 30 जून 1976 तक का तुलन-पता

### इस् विभाग

		वेयता <b>एँ</b>					भ्रास्ति	न्यां	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
		<b>ক</b> ০	पै o 	₹0	पै०	- /	<b>म</b> ०	<b>t</b> o	το — — —	नै०
बैंकिंग विभाग रखें हुए नोट	में	24,67,21,3	72.00			सोनेकासिक्का धीर बुलियन : (क) भारत में र <b>बा</b> कुश्रा	182,52,50,	617.44		
भंजलन में नोट		7150,33,90,1	23,50			ँ (ख) भारत के बाहर रखा हुआ विवेणी प्रतिभतियां	546,73,97,			
जारी किये गये कुल नोट				7175,0	1,11,495.50	जोड़ रुपये का शिक्षका भारत भरकार की रुपया प्रतिभनियाँ वेशी विनिमय बिल ध्रौर दूसरे वाणिज्य पत्र			729, 26, 47, 85 15, 30, 04, 38 6430, 44, 59, 25	8.73
कुल देवसाएँ				7175,0	1,11,495 50	कुल ग्रास्तियाँ			7175,01,11,49	5.50

### वैकिम विकास

दयनार्ष			<b>भा</b> स्तियाँ		•
	Fo	Ŷ o		म्	4.
च्याना प्रजी	5 00,00 000	0.0	भाट	24 67,21,372	0.0
प्रारक्षित निधि	150,00 00,000	00	रुपये का सिक्का	4,01,936	00
লড্রীয় কুমি ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्गन) निधि	400,00,000.	0.0	छोटा सिक्का	2,41,96	4.15
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि राष्ट्रीय प्रौद्धागित ऋण (दीर्घकालीन धवर्तन) निधि	145,00 00 000 510,00,00,000		म्बरीदे श्रीर नुनाए गए बिल (क्) देशी	138,07,60,341	b <b>7</b>
जमा राशियाँ:			(ख) विदेणी		
(क) सरकारी			(ग) सरकारी खजाना बिल	275,57,89,223	34
( । )  केन्द्रीय सरकार	63,12 38 550 3	20	विदेशो मे रखा हम्रा <b>ब</b> काया *	1196,05,88,818	9 9 2
( 2) राज्य सरकारे	138,78,49 015	79	निन्ने श ^{**}	565,41 66,699	8 8 6
(स्त्र) बैंक			ऋण श्रीर भगिम —		
<ul> <li>(1) अनुसूचित वाणिज्य बैक</li> <li>(2) अनुसूचित राज्य सहसारी बैक</li> <li>(3) रीर प्रनृस्चित राज्य सहसारी बैक</li> <li>(1) प्रन्य वैक</li> <li>(ग) श्रम्य देव</li> <li>तेय बिल</li> <li>प्र य देयविल</li> <li>प्र य देयविल</li> </ul>	755 54 09 48 1 60 98,94 643 1,69,82,005 4,18,42,239 2130,62,82,282 79,91,90,107 549 59,08 322	19 95 38 95	(1) मेन्दीय सरकार मी (2) राज्य सरवारों जाति ऋण ग्रीर ग्रग्नि निर्मा निरमा निर्मा निरम निर्मा निरम निर्मा न	75,70,25,217 138,40,00,000 941,98,48,790 156,18 63,494 69,61 55 000	7 55 3 33
			राज्य सहकारी बैको को ऋण भीर भ्रतिम राष्ट्रीय श्रीधोगिक ऋण (दोर्धकास्थीन प्रवर्तन) निज्ञि से ऋण, श्रियम भीर निवेश (क) विकास भैको को ऋण भीर श्रव्यम (ख) विकास बैक द्वारा जारी किये गठे थाडो/डिकेचरा मे निवेश	78,74,60,96 388,17,55.61	
			भन्य भ्रस्तियां £	927 30 98 77	9 02
कुल वेयतार	5027,45,95 951	114	<del>प</del> ल ग्रास्तियाँ	5027 45 95,95	1 04

श्रमत कवना भेयरा पर श्रावरिमन देयता र० 8 00 000 00 (पौण्ड 50,000 के स्ट्रिंग निवेशों को र० 100--6 2500पोण्ड भी दरपर बंदला गया। । भनकदी सावधि जमा और श्रम्पकालीन प्रतिभृतियाँ शामिल है। **(1) रण्टीय हुए क्रिण (दार्थकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय श्रीदोगिक क्रिण (दार्थनलान प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय श्रीदोगिक क्रिण (दार्थनलान प्रवर्तन) निधि में स्वर्तन के 100-2500 00 श्रमेरिकी हुलिर कीर 660 000 00 उप्श मार्व में समान राशि। शामिल है। (एराष्ट्रीय हुलि क्रिण (दार्थकालीन प्रवर्तन) निधि से पद्रत ऋण श्रीर श्रम्भ शामिल वहीं है परन्तु राध्य सम्वरा से दिये गये श्रम्भ गरी शावरहायट शामिल है। (एराष्ट्रीय किर्म किर्म के श्रीवर्तियम की शारा 17(1) (ग) के श्रधीन श्रममुचित वाणाय्य वैशे या मियाची किलो पर शिश्म दिये गर र० 10,30,00 000 शामिल है। ‡शादीय क्रिण ऋण (दीधवालीन प्यत्ने) निधि श्रीर राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थियोकरण) निधि से प्रदत्त ऋण श्रीर श्रीयम शामिल नहीं है। £क्षिपप श्रमुचित वाणाय्य वैका वा विशेष व्यवस्थाया वे श्रीन श्रीदम शि गर्थ कुरू 478 12 00 000 की राशि शामिल है। \$वनमें श्राक्रियकान नेश शामिल है।

इक्ल्य० जे० एफ० बाज,

के० धार० पुरः। गवर्नर

भृष्य लखावार तारीख 30 जुलाई, 1976 भ्रारक केव हजारी उप-गवर्नर श्रारक क्षेत्र शिक्षाति उप-गवर्नर केव एमक क्रुएणस्थामी, उप-गवर्नर पीव भ्रारक नांगिया, उप-गवर्नर

30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष	र्थका साथ–हानि लेखा
प्राय	ъо <b>ф</b> о
व्याज, बद्दा. विनिमय णुल्क, कमीशन आदि ^क	294,99,72,239 32
	294,99,72,239 32
<b>च्</b> यम	
स्थापना	35, 19, 37, 921 61
निवेशको और स्थानीय बोर्डों के सवस्थों की फीस और व्यय	81,484 98
लेखा परीक्षको की फीस	80,000 00
किराया, कर, बीमा, बिजली द्यादि	1,58,81,750.46
विधि प्रभार	1,03,769.71
<b>धाक और नार खर्च</b>	19,48,335.00
कोष-प्रेषण**	46,78,237.46
लेखन सामग्री धादि	54,31 080 33
प्रति—भृतिछपाई (चेक, नोट फार्म, ग्रादि)	14,38,45,495 76
बैक संपत्ति का सृष्य ह्रास ग्रीर सरम्मते	1,31,96,766 72
गजेंसी प्रभार ^{प्र≄क}	43,01,12,622.71
कर्मचारी उपदान ग्रौर ग्रधिवापिकी निधियों में ग्रंशदान ****	7,08,15,842.51
विविध व्यय	1,82,15,270 04
उपलब्ध ण्ड सेव राणि	190,00,00,136.95
जोच	294,99,72 239.33
केन्द्रीय सरकार को देय अधिणेय	190,00,00,136.95
प्रारि	नत निधि लेखा
	रु० पैं∉
30 जून, 1976 को शेष	150,00,00,000.00
लाभ-हानि लेखे से प्रतरित किया गया	<del>मुं</del> छ नही

जोड

डय्ल्य. जे. एफ. वाजं, मुख्य लेखाफार नारीम ३० जुलाई, 1976 के० भ्रार ० पुरी, गवर्नर भ्रार, कें. हकारी उप-गवर्नर श्रार के. शेपाब्रि, उप-गवर्नर के एस कृष्णस्वामी, उप-गवर्नर पी ग्रार. नोगिया, उप-गवर्नर

150,00,00,000.00

^{*}भारतीय रिजर्व क्षेत्र प्रधिनियम की धारा 17 के प्रतुसार नियमित या श्रावण्यक व्यवस्थाएँ और धारा 46क, 46**ख और** 46ग के श्रंतर्गत निधियो े में 221 करोड़ रुपयो का श्रंतरण करने के बाद।

^{**}पिछले वर्षों में किये गये भृगतान के लिए वसूल किये गये रु० 1,07,58,076. र्26 के समायोजन के बाद ।

^{***}पिछले वर्षों के २० 11,59,68,700 00 शासिल है।

^{****}पिछले वर्षो की प्रोदभृत उपदान वेयता के लिए विनियोजित १० 6,42,15,842 51 गामिल है।

### लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में,

हम भारतीय रिजर्ब बैंक के प्रधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इमके द्वारा 30 जन, 1976 तक के रिजर्ब बैंक के तुलनपत्र तथा लेखों पर केंद्रीय सरकार को प्रपत्ती रिपोर्ट प्रस्तुत करने हैं।

हमने केंद्रीय कार्यालय और कलकत्ता, बम्बई (फोर्ट), मद्राम, नई दिल्ली, भुवनेष्वर और भोपाल के कार्यालयों के लेखों और उनसे संबंधित प्रमाणपत्नों और वाजचरों से और साथ ही, दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के प्रबन्धको द्वारा पेश की गयी प्रमाणित उन विवर्गणयों में जिन्हों उक्त तुलनपत्न में समाविष्ट किया गया है, उपर्युक्त तुलनपत्न की जाँच कर ली है भौर हम यह सुचिन करते है कि हमने केंद्रीय बोई से जो जो स्पष्टीकरण और जानकारी माँगी है, वह सारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और वह संवोषजनक है। हमारी राय में यह तुलनपत्न पूर्ण और मही तुलनपत्न है। इसमें भारतीय रिजर्थ वैंक प्रधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों हारा निर्धारित विवरण दिये गये है और इसमें उक्त मिश्रीनयम भौर विनियमों के अनुसार आस्तियों का मृल्य-निर्धारण किया गया है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, यह तुलनपत्न हमें दिये गये स्पर्टीकरशों और वैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है, ताकि इममे वैंक के कार्यों की सक्बी और सही स्थित का पता लग सके।

तारी**ख** 16 श्रगस्त, 1976

मेमर्म सी. सी. चोक्सी एण्ड कंपनी मेमर्स लवलॉक एण्ड स्युज मेमर्स रधुनाथ राग्र एण्ड कंपनी मेमर्ग एम. के. यांडेकर एण्ड कंपनी

लेखा परीक्षक

### भारतीय रिजर्व वैंक के तुलन पत्र की विवरणी

विवरण		निम्नांकित तारीख को समाप्त हुमा वर्ष										
		जून 30, 197	1				<del></del>					
		₹०	गै०	₹०	पै०	<b>ঘ</b> ০	पै०	₹०	<b>पै</b> ०			
इसू विभाग												
यताएं												
• • •		37, 17, 59, 1				15,49	,78,757.00					
संचलन में नोट		6472,72,04,1	91.50			6584,7	6,76,595.50					
जारी किये गये कुल नोट .			6509,89	,63,352.50	6600,26,55,352.50							
कुल वेयताएं .		·· <u>···</u>		6509,89	,63,352.50		<del></del>	6600,2	6,55,352.50			
आस्तियां								·	<del></del>			
सोने का सिक्का और बुलियन												
(क) भारत में रखा हुआ।		182,53,04,7	31,42			182,5	2,58,101.88					
(ख) भारत के बाहर रखा हुन्ना							• •					
विदेशी प्रतिभूतियों .		166,73,97,2	34.21			121,7	3,97,234.21					
रुपये का मिक्का .		7,50,63,78	<b>7</b> ,68			5, 5	9,96,917.65					
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ		6153,11,97,5	99.19			6290,4	0,03,098.76					
वेणी विनिमय बिल झौर दूसरे												
बाणिज्य पत्र	•											
कुल झास्तियां.		6509,89,63,352.50										

### भारतीय रिकर्व बैंक के तुलन-पत्र की विवरणी---(जारी)

थिवरण		निम्नांकित तारीख को समाप्त हुन्ना वर्ष	
	जून 30, 1974	जून 30, 1975	<del></del>
वैकिंग विभाग			, —, —, , , , , , , , , , , , , , , , ,
<b>धेयता</b> एं	रू० पै०	क्0 पैं। दे पैं०	रु० पै
मुकतापूजी	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00	
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (बीर्चकालीन प्रव-			
र्तुन) नि <b>धि</b>	284,00,00,000.00	334,00,00,000.00	
राष्ट्रीय क्रिषि ऋण (स्थिरीकरण) निश्चि	95,00,00,000.00	140,00,00,000.00	
राष्ट्रीय ग्रीधोगिक ऋण (दीर्घकालीन			
प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000.00	390,00,00,000.00	
(क) सरकारी:			
केन्द्रीय सरकार	61,57,98,480.17	77,69,36,995.84	
राज्य सरकारे	26,36,81,522 93	8,44,73,019.23	
(खा) बैंक:			
(ख) बकः श्रनुसूचित वाणिज्य बैकः .	553,50,77,103.97	603,50,24,866.97	
श्रमुम्बित राज्य सहकारी <b>वै</b> क	26, 26, 10, 122.81	42,99,13,458.16	
गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी <b>बैं</b> क .	1,48,06,487.84	1,45,98,463.70	
ग्रन्य वैंक	1,09,04,310.40	1,74,10,401,96	
(ग) ध्रन्य	512,57,15,516.12	982,43,69,501.90	
देय बिल	125,52,38,985.22	97,97,68,768.31	
भ्रम्य वेयताएँ	483,81,97,868.98	750,66,31,290.04	
कुल देयताएं	2	591,20,30,398.44	3585,91,26,766.11
	ह <b>ं पै</b> ० <b>र</b>	० पै० रु० पै०	<b>र</b> ० <b>पै</b> ०
नोट	37,17,59,161.00	15,59,78,757.00	
रुपये का सिक्का	3,49,127.00	5,01,112.00	
छोटा सिक्का	2,51,761.34	2,79,617.24	
खरीदे ग्रीर भुनाय गर्य बिल	,, · • -		
(क) देशी .	274 37.78 289 83	126,12,80,388.35	
` <u>'</u>			
	128,67,52,866.15	332,15,67,737.92	
	596,33,23,105.29 ¹ 217,37,84,159.20 ² क <b>ज</b>	410,95,25,397.68 ¹	-
	217,37,84,159.40 ⁻⁴ 1 ⁻⁴¹	677, 15, 14, 553. ७६ ² का	l
ऋण ग्रीर प्रग्निमः			
• •	••	• •	
(ii) राज्य सरकार को ं .	177,82,73,164.18 ³	359,90,72,000.00	
(iii) अनुसूचित वाणिष्य वैकों को .	420,99,85,000.004	385,26,87,000,00	
(iv) राज्य सहकारी <b>बै</b> कों को	166,52,34,128.00	286,74,36,215.00 ⁶	
(v) दूमरोको	38,16,95,000.00	59,88,45,001.00	

11,13,13,970.00

52,87,68,118.00

178,69,55,519.00

153,45,05,650.407

#### विवरण निन्नाकित नारीख को समाप्त हुआ वर्ष जून 30, 1974 जून 30, 1975 पै० ůο ₹0 प्रे राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रय-र्तन) निधि से ऋण, प्रग्रिम भ्रौर निवेश (क) ऋण ग्रौर ग्रग्रिम (j) राज्य सरकारा को 67,87,33,623.72 69,70,59,860.92 (ii) राज्य सहकारी बैको को 15,65,67,755.33 13,33,72,365.66 (iii) केन्द्रीय भूमि बंधक वैंको को . . (iv) कृषि पूनवित्त निगम को 54,00,00,000 00 88,20,00,000 00 (खा) केन्द्रीय भूमि बन्ध्रक वैको के डिबे-

भारतीय रिजर्व वैक के तुलन-पत्र की विवरणी—(जारी)

## कूल ग्रास्तिया

चरों में निवेश

ऋण ग्रौर प्रप्रिम .

भ्रीर निवेश

भ्रत्य भ्रास्नियाँ

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि में राज्य सहकारी बैकीं की

राष्ट्रीय श्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, श्रीप्रम

(क) विकास वैक को ऋण और अग्रिम .

(ख) विकास बैंक द्वारा जारी कियेगये बाडों/डिबेंचरों में निवेश

2591,20,30,398.44

3585,91,26,766,11

10,65, 15, 520,00

82,54,99,826.00

264,64,55,619.00

402,75,05,791.688

- 30 जून 1974---भंगतः चुकतः गेयरों पर आकस्मिक देयता रु० 9,48,388.69 (पीड 50,000 के स्टलिंग नित्रेको को क् 100 = 5.2721 पीड की दर पर बदला गया)
- 30 जून 1975—प्रांगतः चुकता ग्रोयरों पर प्राकस्मिक देयता रु० 9,39,999.81 (पीड 50,000 के स्टर्लिंग निवेशों को ग० 100 ⇒ 5.31915 पीड की दर पर अवला गया)
- े. नक्दी, सार्वाध जमा भौर ग्रस्पकालीन प्रतिभृतियां णामिल है।
- 2. (क) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि ग्रीर राष्ट्रीय श्रीद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है।
  - (ख) बिदेशों में रखे हुए रु० 5,39,54,792.90 (50,000 पोड, 6,247,475 अमेरिकी डालर और 1,110,375 ड्यूग मार्क के समान राणि) गामिल है।
  - (ग) विदेशों में रखे हुए ६० 5,57,42,281.96 (50,000 पीड, 6,005,000.00 भ्रमेरिकी डालर भ्रीर 9,22,650.00 अ्यूण मार्क के समान रामि) गामिल है।
- 3. राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्निम गामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी स्रोवरड़ाफ्ट गामिल है।
- 4. भारतीय रिजाव बैंक श्रधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको को मीयादी विलो पर श्रीप्रम दिये गये रु० 156,63,73,000 णामिल है।
- 5 भारतीय रिजर्ब बैक श्रीर्धानयम की धारा 17 (4) (ग) के प्रधीन भनुसूचित वाणिज्य धैको का मीयाधी श्रितो पर प्राप्रम दिये गये হ৹ 208,37,00,000 णामिल है।
- 6. राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्घकालीन प्रवर्तन) तिधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदल ऋण श्रोर भग्निम शामिल नहीं है।
- 7. कतिपय अनुसूचित वाणिज्य बैको को विदेशों में उनके द्वारा किये गये निवेशों के संदर्भ में विशेष व्यवस्थान्ना के श्रधीन दी गयी रु० 50,00,00,000 की राणि शामिल हैं।
- 8. कतिपय श्रनुसूचित वाणिज्य बैंको को विदेणा में उनके द्वारा किये गये निवेशों के संदर्भ में विशेष व्यवस्थाछों के ग्रधीन अग्निम दी गयी रू० 188,20,00,000 की राशि सामिल है।

### 30 जून 1974 ग्रीर 1975 को समाप्त हुए बर्ची का लाभ-हानि लेखा

								1974	1975
								<b>ক</b> ও 🗘 ও	हु० पै०
- म्राय								195,47,95,113 00	228,00,56,335 37
प्राज, बट्टा, विनिमय, णुल्क, कमीणन, म्रा	द							195,47,95,113.00	228,00,56,335.37
यय									
थापना								28,53,25,931,78	34,65,01,633 4
नेदेणको श्रीर स्थानीय बोर्डो के सदस् •	याकी प	ीम							
गैर ष्यय	•	•	٠					66,346 31	1,05 246.1
खापरीक्षकों की फीस .		•	•	•	•	•	•	80,000 00	80,000 00
तराया, कर, बीमा, बि <b>ज</b> ली, भादि		•	•			•		1,16,05,263,44	1,21,19,577 2
र्वाध प्रभार	•	•	•		٠			1,68,540 71	87,719.8
ाकभ्रोरतारखर्च				•	•	•		14,04,042 18	16,32,353.1
ोषप्रेषण .				•	•	•		81,33,581 59	94 38,912.0
खन सामग्री श्रादि								10,22,877 04	57,20,982 7.
तिभृति छपार्ड (चैक, नोट फार्म, श्रादि)		*						5, 19, 42, 441.13	5,82,42,271 8
क संपत्ति का मृल्य-ह्नास ग्रौर सरम्मने						•		1,10,81,345 19	1,30,46,628.8
जेसी प्रभार ,								11,19,19,385.81	31,24,70,222.4
र्भचारी ग्रौर श्रधियापिकी निधियो मे 🦻	ाणदान						•	50,00,000.00	40,00,000.0
वविध व्यय								1,40,45,191 20	1,62,79,950 3
प्रम∗ध गुद्ध शेष राशि .					٠			145,00,00,163 32	150,00,00,834.3
गेड़								195,47,95,113.00	228,00,56,335.3
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष		·	<del> </del>					145,00,00,163 32	150 00,00,834 3
प्रारक्षित निधि लेखाः									
								150,00,00,000 00	150,00,00,000.0
ताभ-हानि लेखे से ग्रन्तरित किया गया								कुछ नहा	<del>দু</del> ত নস্তা
मोध्		•				• .		150,00,00,000.00	150,00,00,000.0

ोभारकीय रिजार्व बैंक श्रीधनियम की धारा 17 की ग्रन्सार निथमिन या ग्रावण्यक व्यवस्थाल करन के बाद।

# (Department of Reserve and Banking) (Banking Wing)

New Delhi, the 14th October, 1976

S.O. 1489.—Annual Report on the Working of the Reserve Bank of India and Irend and Progress of Banking in India for the year July 1, 1975—June 30, 1976

In accoldance with sub-section (2) of section 53 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following report on the Working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1976 —

### 1 PERFORMANCE OF THE ECONOMY 1975-76 INTRODUCTION AN OVERALL ASSESSMENT

If the year 1974-75 is remembered as a year in which an element of normalcy was restored to an economy, which had to pass through the traumatic experience of unusually high lates of inflation for the previous two years, the year 1975-76 could be characterised as a year in which it has been possible to put the economy back on its normal growth path Such resumption of normal growth in 1975 76 is reflected not merely in the attainment of an estimated growth of around 5.5 per cent although undoubtedly it is the focal point. In fact, recent data on industrial production have revealed an actual rate of growth in 1975-76 which is higher than that envisaged earlier and hence the overall rate of growth of the economy may turn out to be somewhat higher than 5.5 per cent Besides the overall growth rate, there are three features of growth in 1975-76 which lend support to the main theme of resumption of normal growth by the economy after an interval of unprecedented rates of inflation these are stability, a significant rise in the rates of domestic saving and investment and a move towards an eventual emergence of a viable external payments position

- 2 Containment of prices remains an outstanding achieve ment of 1975-76 Not only were prices contained but there also took place in 1975 76 and actual decline in prices by 60 per cent 1 In a world in which high lates of inflation have become almost universal, this is no mean achievement Se preliminary estimates indicate that the rates of condly. domestic saving and aggregate investment lose sharply from 13.1 per cent and 14.8 per cent of net national product in 1974-75 to 14.5 per cent and 16.0 per cent, in 1975-76. In point of fact these are the highest rates of saving and investment achieved since the beginning of the Fourth Plan. Thirdly, on the external front, notwithstanding the persistence of a sizeable trade deficit for the second year in succession the overall payments situation showed a remarkable improvement There took place an unprecedented increase in the country's foleign exchange reserves, thanks largely to the improvement in the invisibles accounts. In point of fact, there are indicators which appear to suggest that the long term balance of payments prospects have improved Taken together, these features suggest that the year 1975-76 has bequeathed an economy which can provide a strong base for sustaining growth in the remaining years of the Fifth Plan
- 3 Any assessment of the performance of the economy in 1975-76 would be incomplete without a reference to another rather unique experience in the management of the economy. The declaration of internal emergency and the in ception of the New Economic Programme in mid 1975 have, by toning up economic administration, generally and by ensuring effective implementation of specific time-bound program mes, contributed in no small measure to the growth of the economy
- 4 At the outset, it may be recalled that the economy was jolted from its normal growth path since 1971-72, primarily because of the serious set-back to the agricultural sector during two consecutive years 1971-72 and 1972-73 Consequently, inflation assumed serious proportions and there was also a dramatic deterioration in India's terms of trade. In subsequent years therefore, the task of stemming these mounting pressures of inflation domestically and of adjusting to the payments problems externally became far more urgent and hence attainment of the targeted rates of growth had of necessity, to be relegated to a secondary position. The net result

- of such disruption in the growth process was that during the Fourth Plan period the average annual growth rate of only 3 3 per cent could be achieved. Even in 1974 75, the first year of the Fifth Plan, the actual growth achieved was nominal at 0.2 per cent. In contrast, the growth estimated during 1975 76 would be somewhat higher than 5.5 per cent. at least in the second. Year of the Fifth Plan therefore, it has been possible not only to reach but also to exceed the targeted rate of growth. It is in this sense of the resumption of normal growth in an environment of price stability, that the year 1975 76 may be said to mark a turning point.
- 5 Considered sectorally, growth in 1975.76 was rather uneven, with the agricultural sector witnessing as much as 8 per cent and the industrial sector about 5.7 per cent² growth The relatively high rate of agricultural growth may give rise to doubt whether the 'fortuitous' element which tradi tionally affects agriculture has exaggerated the overall growth in 1975-76 Although admittedly climatic factors continue to dominate the trond of agricultural growth—in 1975-76 weather conditions were quite favourable—there are indicators that the investment-induced growth component as contra-distinguished from the fortuitous component, was quite significant in 1975-76 This is, for instance, reflected in a substantial increase in agricultural inputs like fertilisers, power and water More appropriately, it could be argued that the relatively lower industrial growth has tended to dampen overall growth This is because although the 'core' sector industries like coal, electricity, iron and steel, cement, nitrogenous fertilisers etc increased their production at rates above 10 per cent industries like textiles, consumer durables, tea, etc., recorded an actual decline in production Although input bottlenecks, especially in the sphere of energy and raw materials no longer hampered industrial growth slackness in demand emanat ing from both domestic and external factors began to affect some sub-sectors, even as in some sub-sectors problems of modernisation both of capital equipment and management began to assume greater importance
- 6 Analysing the place stability in concrete terms, it is clear that whether one compares the level of prices on a point-topoint basis of on the basis of monthly averages, the general trend was one of decline For intance, between end-June 1975 and end-Tune 1976, wholesale pinces recorded a decline of 3 0 per cent in contrast to phenomenal rises of 21.5 per cent and 27 8 per cent witnessed during the years 1972 73 and 1973-74 and a nominal lise of 0.7 per cent in 1974-75 A similar picture emerges if one takes into account the monthly average levels, during 1975-76 (July-June) prices recorded a decline of 60 per cent, in shaip contrast to an actual lise of 168 per cent in 1974-75. The dramatic change in the place situation is evident from the fact that the price level in mid March 1976. Suppose back to the level prevailing two years. slipped back to the level prevailing two years ago This turn-around in the price situation was no doubt basically due to an improvement in the supply demand balance, particularly in respect of agricultural commodities production of foodproduction of foodgrains set a new record of 116 million tonnes and that of oilseeds also reached a new peak Such enlargement of sup plies alone, however does not provide an adequate explana tion of the easiness in prices A fuller explanation has to be sought in the fact that the supply situation was buttressed by the continuation of monetary and fiscal policies aimed at de mand management on the one hand and by administrative measures designed to curb hoarding and use of unaccounted money, on the other
- 7 Taking fiscal policy first, the policies of the Centre and the States were geared in 1975-76 towards maintaining price stability, while promoting growth Ffforts initiated during the previous year to mobilise resources were further reinforced While total disbursements of the Centre and the States rose by 210 per cent or at about the same rate as in 1974-75 total receipts increased by 239 per cent as against a rise of 199 per cent in the previous year. The acceleration of receipts was the cumulative result of the additional tax efforts made by the Centre, and the States, better tax administration and the success of the Scheme of Voluntary Disclosure of Income and Wealth Consequently the combined budgetary deficit was substantially lower at Rs 468 crores (revised estimates) than the level of Rs 752 crores in 1974-75. In fact subsequent data show that the combined deficit for 1975-76
  - 1 Based on monthly averages July 1975-June 1976
  - 2 For the calendar year 1975 the growth rate was only 3 9 per cent

actually turned out to be much lower at Rs. 351 crores. Treating the Centre separately, the budgetary deficit turned out to be only Rs. 367 crores or lower than the revised estimate of Rs. 490 crores. The deficit in 1975-76 was sizeably smaller than that in 1974-75. Thus it was possible to contain the magnitude of budgetary deficit within safer limits.

- 8. In the sphere of monetary and credit policy, the situation warranted the adoption of a somewhat different approach. No doubt the basic anti-inflationary stance of credit policy remained unchanged, with the continuation of the existing structure of interest rates fairly restrictive Reserve Bank accommodation and implementation of credit guidelines designed to discourage speculative holding of inventories. On the other hand, the anticipated enlargement of supplies, both agricultural and industrial, called for introduction of some degree of flexibility. The approach to credit policy in 1975-76 was therefore motivated by the main objective of facilitating a higher rate of growth in the economy, without impairing greatly the basic apparatus of monetary restraint. The various measures introduced during the year, like financing by commercial banks of food procurement on an enormously larger scale, selective liberalisation of margin requirements and of inventory norms and prescription of a ceiling on lending rates—all these bear ample testimony to the degree of flexibility which it has been possible to impart to credit policy, without endangering price stability.
- 9. The impact of such a flexible approach is reflected in the trends in credit during the year 1975-76 (July-June): scheduled commercial banks' credit expanded by Rs, 2509 crores (28.0 per cent) which was more than double the expansion of Rs, 1097 crores (14.0 per cent) in the corresponding period of last year. This clearly shows that credit policy was far from rigid and that an element of resilience was built into it. Although both food and non-food sectors shated the increase, the rise in food credit at Rs. 1390 crores was substantially larger than that (Rs. 272 crores) during last year; it accounted for as much as 55 7 per cent of the incremental expansion as against only 24.8 per cent last year. The credit-deposit ratio on June 25, 1976 stood at 76.1 per cent, as against 71.4 per cent a year ago. Excluding food credit, the credit-deposit ratio at 61.6 per cent was lower than 65.1 per cent, a year ago.
- 10. In judging the magnitude of bank credit expansion in 1975-76, it is more important to underline that banks' own resources expanded at a much faster rate. Aggregate deposits of scheduled commercial banks expanded by Rs. 2512 crores or by 20.0 per cent, as compared with an expansion of Rs. 1788 crores or of 16.6 per cent in 1974-75: the increase in absolute terms in 1975-76 was the largest recorded so far. Although both demand and time deposits recorded increases, the increase was pronounced in the latter category: time deposits in 1975-76 rose by Rs. 1698 crores (23.3 per cent) as compared with an increase of Rs. 1179 crores (19.3 per cent) during the previous year. Maintenance of high nominal rates of interest in 1975-76 has meant that real rates of interest have risen the wake of a decline in prices. The unresponse to this factor.
- 11. The impact of this relatively larger expansion in bank credit is reflected in money supply with the public, which expanded during 1975-76 (July-June) by Rs. 1375 crores or by 11.3 per cent. The order of expansion was significantly higher than a 6.4 per cent expansion witnessed in 1974-75. It may be recalled that the rate of money supply expansion was restrained in 1974-75 within a narrow range, due to special factors like the support derived from the IMF drawals, as discussed in the last year's Annual Report. It may not therefore be appropriate to compare the 1975-76 expansion with that in 1974-75. If compared with the average annual rate of expansion of 15 per cent during the three-year period 1971-72 to 1973-74, the rate of expansion in 1975-76 was considerably lower. More importantly, there was a qualitative difference in the character of money supply expansion in 1975-76 came about in the wake of an increase of 5.5 per cent in real national income, during the previous years, with the sofe exception of 1973-74, expansion took place when

- national income was practically stagnant. An even more important qualitative difference lies in the factors responsible for expansion. Net foreign exchange assets of the banking sector and bank credit to commercial sector were the two predominant factors responsible for money supply expansion in 1975-76. Net foreign exchange assets of the banking sector recorded an unprecedented rise of Rs. 969 crores: to the extent that such assets could be regarded as a built-in stabiliser, this factor can be taken as a redceming feature of a much higher rate of money supply expansion. That is to say, if the situation warrants, reserves could be drawn down with a view to augmenting supplies. Secondly, the magnitude of bank credit expansion was much larger in 1975-76 but this could be explained largely in terms of food credit. Significantly, in view of the larger accretion of deposits, banks were able to finance ciedit expansion to a considerable extent from their own resources rather than by borrowings from the Reserve Bank. Consequently, the potential inflationary impact of this factor was moderated somewhat.
- 12 This qualitative difference in the character of money supply expansion, coupled with the enlargement of supplies referred to earlier, perhaps explains why despite a monetary expansion of 11.3 per cent, prices behaved the way they did in 1975-76.
- 13. The external sector of the economy presented in 1975-76, in refreshing contrast to the earliers years, distinct signs of strength. This strength manifested itself in an unprecedented rise of Rs. 881 crores¹ in the country's foreign exchange reserves, notwithstanding the persistence of a sizeable trade deficit for the second year in succession. Exports rose by only 16 per cent in 1975-76 in contrast to a rise of 32 per cent in the previous year. Although import growth at 11 per cent was also sizeably lower than the 53 per cent growth witnessed in 1974-75, the trade deficit at Rs. 1155 crores remained practically unchanged at the previous year level of Rs. 1189 crores. I hough detailed balance of payments data are not available, it seems that the rise in reserves was primarily attributable to larger inflow of aid and an increase in inflow of aid in 1975-76 was to a significant extent, offset by lower drawals from the IMH, it becomes clear that invisibles have been the predominant element in the emerging strength of reserves, Such improvement may have been in large part due to plugging of foreign exchange leakages.
- 14. Another important landmark in the external sector was the delinking of the rupees from September 25, 1975, from the pounds sterling; the external value of the rupee since then is being determined in terms of a basket of currencies of countries which are India's major trading partners. The effect of this change has been to "tabilise the value of the Indian rupee vis-a-vis, currencies other than sterling and to increase the purchasing power of the rupee in terms of sterling. This has contributed to some extent to the stabilisation of prices, by preventing an increase in the prices of imported commodities and services.
- 15. At the end, it may be in order to indicate the all-pervasive impact of the internal emergency and the 20-point Feonomic Programme on the economy. This impact is reflected in industrial harmony in the industrial sector, in the reduction both of speculative hoarding and of the use of unaccounted money in the sphere of prices, in the raising of efficiency in administration in general and in public sector undertakings and in tax administration in particular, and finally, on the external front, in strengthening of the reserves position consequent on auti-smuggling operations.
- 16. In the following pages a detailed discussion of sectoral growth, fiscal and monetary policies, trends in prices and in saving and investment and the external sector is presented. In the last section, on the basis of such indicators as are available, an attempt is made to assess the prospects for growth in 1976-77.

^{1.} The figure refers to the gross reserves of the country, whereas the figure mentioned earlier relates to the net foreign exchange assets of the banking sector.

#### National Income, Agricultural and Industrial Growth

#### National Income

17. The latest estimates of the Central Statistical Organization place the rise in national income (at 1960-61 prices) in 1974-75 at 0.2 per cent as against the earlier estimate of 20 per cent. This is in sharp contrast to the substantial increase in national income at 50 per cent in 1973-74. The explanation for only a nominal rise in national income in 1974-75 fies in the lact that there took place a decline of 43 per cent in the net domestic product of the agricultural sector.

18 In contrast to this marginal increase, the rise in national income in 1975-76 (at 1960-61 prices) is estimated at 5.5 per cent. Thus at least during the second year of the Fifth Plan, it has been possible to achieve the targeted rate of growth. In point of fact, after 1969-70, this was the first year when growth reached the level of 5.5 per cent.

#### Agricultural Production

19. The impressive increase in national income in 1975-76 is largely attributable to the agricultural sector which witnessed a growth rate of as much as 8 per cent. The relatively high rate of agricultural growth may give rise to doubt whether the exceptionally good weather has exaggerated the overall growth in 1975-76. There are indicators, however, that the investment-induced growth component, as reflected for instance, in the use of fertilisers and water, as contra distinguished from the fortuitous component was quite significant in 1975-76. The consumption of fertilisers is tikely to have shown a rise over the level of the previous two years, largely as a cumulative impact of the improvement in the supplies of fertilisers, reduction in their prices and better availability of power and irrigation supplies: basically favourable weather conditions facilitated larger use of fertilisers. Notwithstanding these favourable factors, however, the cosumption of nitrogenous fertilisers at around 22 lakh tonnes is likely to remain well below the Annual Plan target of 25 lakh tonnes. Furthermore, there was considerable improvement in the supply of other inputs like quality seeds and pesticides. This is clear from the data presented in Table 1.

TABLE: 1-PROGRESS OF AGRICULTURAL PROGRAMMES

Programme	Unit	1971-72	1072 72	1077 74	1071.76	1975	·76+	1976-77 ⊣
riogramme	Oun	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	Target	Likely Achieve- ments	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gross Area Covered High Yield Varieties	Million hectares	18 2	22.1	25.9	27.1	30.0	31,0	33.0
Plant Protection	11	58.0	52 0	63.0	64.0	_	70.0	
Soil Conservation a	,,	1 5	2.1	1,6	0 6	0 8	1.0	0 7
Consumption of Fertilisers and Pesticides								
Nitrogenous (N) (Nutrients)	Million tonnes	1.8	1.8	1.8	1.8	2.50	2 15	2.65
Phosphatic (PgO _b )	11	0.5	0.6	0.7	0.5	0.70	0,47	0.60
Potassic (K _a O)	11	0.3	0.4	0.4	0.3	0.40	0.28	0.35
Pesticides	'000 tonnes	N.A.	N.A.	N.A	0.47	0.56	0.53	0 60
Gross Area Irrigated	Million hectares	38.5	41.0	43 1	43.8	_	45.4	47 4
Gross irrigated area as percent to cropped area		23.5	'n.A.	NA.	25,9	_	26 5	27.3
Institutional Finance for Agricult- tural Development								
Medium/Long-term Loans (Direct* & Indirect£)								
(a) Loans issued (end June)	Rs. crores	276.18	415 35	193 87	477.36\$		581.09	
(b) Loans outstanding (end June)	**	1231 05	1558.72	1737.93	2041.78\$		2541.81	

⁺ Annual Plan, 1976-77.

N.A. -Not available.

Source: (1) Ministry of Agriculture, Government of India. (2) The Pertiliser Association of India.

a Additional during the year,

^{*} Of primary agricultural credit societies, fand development banks and scheduled commercial banks.

[£] Of scheduled commercial banks and Rural Electrification Corporation Ltd.

Provisional.

20. The performance in respect of foodgrains production was particularly noteworthy; the total production of foodgrains is expected to establish an all-time record of 116 million tonnes, as against the target of 114 million tonnes fixed for the year, thus surpassing by 7 per cent the earlier record of 108. 4 million tonnes reached in 1970-71. Data relating to the output of selected commodities in recent years are set out in Table 2. Rainfall and weather conditions for the 1975-76 kharif crops were very favourable resulting in production of kharif foodgrains of 70-71 million tonnes—a level which exceeded the previous peak level of 69 million tonnes reached in 1970-71. The production of rice is estimated at 48 million

tonnes far exceeding the previous record of 44 million tonnes reached in the 1973-74 season. Rabi sowings were undertaken under favourable climatic conditions, with winter rains, though delayed, proving beneficial. Consequently, rabi foodgrains production is also likely to establish a record of 45 million tonnes. Wheat production is placed around 28 million tonnes exceeding the earlier record level of 26.4 million tonnes attained in 1971-72 and is higher than the production of previous year by 3.8 million tonnes.

⁴According to later official estimates production is likely to touch 118 million tonnes.

TABLE 2: -AGRICULTURAL PRODUCTION—SELECTED COMMODITIES

							Unit	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
	1						2	3	4	5	6	7
Fotal Foodgrains							Million tonnes	105.2	97.0	104.7	101.1	116.0*
Kharif Foodgra	ins						11	63.0	58.6	67.9	60.3 ′	70.0-71. <b>0</b> 1
Rahi Foodgrain	s.						<b>&gt;1</b>	42.2	38.4	36.8	40.8	45.0*
Cereals					, .		11	94.1	87.1	94.7	90.7	
Rice							13	43.1	39.2	44.1	40.3	48.0*
Wheat							**	26.4	24.7	21.8	24.2	28.0*
Pulses			• •				1)	11.1	9.9	10.0	10.4	_
Non-Feodgrains												
Cotton		• •	• •	• •		• •	Million bales of 170 Kgs, each	7.0	5.7	6.3	7.1	6.7@
Jute and Mesta		1.1	• •		• •	• •	Million bales of 180 Kgs, each	6.8	6.1	7.7	5,8	5.8
Oilsæds							Million tonnes	8.7	6.9	8.8	8.4	10.6†
Groundnut							>>	6.2	4.1	5.9	5.1	7.0
Sugarcane (In terms of Gu	 r)	• •			• •	••	"	11.6	12.8	14.4	14.3	_

^{*} Press Reports.

21. The picture in respect of non foodgrains crops is, however, not equally encouraging, except in the case of oilseeds. According to trade estimates, production of five major oilseeds is estimated at 10.6 million tonnes in 1975-76, as compared with the target of 10 million tonnes fixed under the Annual Plan for 1975-76. The output of groundnuts has been estimated at 7.0 million tonnes which shows an increase of 36.8 per cant over the level in the previous year. The area under cotton according to All-India Third Estimates, was lower at 72.8 akh hectures in 1975-76, as against the corresponding estimate of 73.1 lakh hectares in 1974-75. No official estimates of piduction are available so far. In December 1975, the Cotton Advisory Board estimated the output at round 6.9 million bales but in June 1976 it scaled down its earlier estimate to 6.7 million bales. The output of raw jute and mesta, was stagnant at the last year's level: production is estimated at 58.29 akh bales in 1975-76 as compared with 58.33 lakh bales in 1975-75. In fact the output in 1975-76 would be the lowest since 969-70. The area under sugar-cane at 2.7 million hectares in 1975-76 would be somewhat higher than the level of 2.6 million hectares in 1974-75, but sugar production is estimated to decline to 43-44 lakh tonnes from the level of 48 lah tonnes in 1974-75.

### Procurement, Procurement Policy and Public Distribution

22. The 20-point Economic Programme has laid special emphsis on speeding up procurement and streamlining the distriction mechanism of essential commodities with a view to cotalning prices. The Government procurement policy for foodgains which was formulated in this overall framework was, a addition, guided by the twin objectives of building up large enough buffer stocks and protecting the interest of products through support prices.

- 23. There were no major changes in the procurement policy in respect of *kharif* foodgrains during the 1975-76 (November-October) marketing season. The procurement price of the standard variety of paddy was maintained at last year's level of Rs. 74 per quintal; and so also was the case in respect of prices of other coarse cereals.
- 24. The overall procurement performance and the trend in market arrivals in 1975-76 as also the trend in off-take from the public distribution system, taken together reflect the emergence of a relatively comfortable food situation generally—an aspect which was brought into sharp focus by the fact that some procurement had to be undertaken as part of price support operations.
- 25. In regard to procurement of rice during the 1975-76 season, the Agricultural Prices Commission (APC) had recommended a target of 5.3 million tonnes but the Government fixed a target of 4.6 million tonnes. Actually, the procurement target has been overfulfilled, with the procurement reaching already 6.0 million tonnes. For coarse grains, no procurement target was fixed although the APC had suggested a figure of 1.3 million tonnes: so far a quantity of 0.3 million tonnes has been procured as part of price support operations.
- 26. The procurement price of rice, however, was raised from Rs. 115.78-125 to Rs. 117-127 per quintal for the 1975-76 season, taking into account the hulling/milling ratios, escalation in statutory charges and other incidental expenses. Despite this rise, the issue prices of all varieties of rice as well as coarse grains as fixed on January 1, 1975 have been maintained unchanged in view of the over-riding objective of containing inflationary forces.

27. In respect or wheat the procurement price for the 1975-76 marketing season (April-March) was retained at the previous year's level of Rs. 105 per quintal. It may be recalled

25 GV77-13

⁽ā As given by the Cotton Advisory Board.

[†] Trade Estimates.

that the procurement price of wheat had been raised from the level of Rs 71 to Rs 74 per quintal (indigenous red variety) in 1973-74 to Rs 105 in 1974 75. Further, with a view to maximising procurement, an incentive bonus scheme for supply of wheat to the Central Government was introduced, under which bonus linked to procurement performance was to be paid to the State Governments on a graded scale. The average rate of bonus worked out to Rs 474 per quintal and the amount so realised is expected to be utilised by the State Governments for investment on developmental works primarily for the benefit of farmers. The State Governments, at their discretion, could also utilise the bonus for making available to farmers certain inputs at concessional rates. However no cash was to be paid to the farmers. The issue price of wheat stocks released from the Central pool for public distribution was maintained at Rs 125 per quintal.

- 28 Wheat procurement during the 1975-76 season out of the 1974-75 crop totalled 4.1 million tonnes, as against 2.0 million tonnes during 1974-75
- 29 For the 1976-77 season (April-March) also no change has been made in the procurement policy for wheat, both the procurement price of Rs 105 per quintal and the bonus scheme being maintained. The procurement target has been fixed at 52 million tonnes, but actual procurement has already crossed the targeted level by 12 million tonnes 5
- 30 The trend in market arrivals of both rice and wheat also reflects the improved supply position. In the current marketing season (1975-76), market arrivals of rice in selected markets have been substantially higher than those in the previous season. In the case of wheat total mailet arrivals of wheat during the 1975-76 wheat marketing season (April-March) in 317 selected markets amounted to 22.8 lakh tonnes as against 17.3 lakh tonnes during the previous season showing an increase of 31.8 per cent. During the 1976-77 wheat marketing season also the trend in market arrivals has further accelerated with total arrivals aggregating 15.8 lakh tonnes as against 10.3 lakh tonnes during the corresponding period last season.
- 31 Notwithstanding the bumper crop of foodgrains, the Government decided to maintain imports in 1975-76 at a high level so as to build up sizeable buffer stocks which is a prerequisite for sustaining price stability Imports of foodgrains aggregated 7.4 million tonnes during the year 1975.76 (July June), as against 5.8 million tonnes during the corresponding period of 1974-75
- 32 Another remarkable indicator of the easiness in supply was the decline in the off-take from the public distribution system. During 1975 76 (July-May) the monthly average off take of foodgrains from the public distribution system declined to 78 lakh tonnes from the average of 9.2 lakh tonnes in the corresponding period last year. Off-take during November 1975—May 1976 was 47 6 lakh tonnes as against 65.9 lakh tonnes during the corresponding period last year. This decline in off-take is a clear indication of the shift in demand away from the public distribution system to the open market. In urban areas. Off take in non-urban areas particularly rural areas also may have declined due to replenishment of stocks of foodgrains with small farmers consequent upon increased production.
- 33 Relatively larger imports higher procurement of fool grains and a reduction in off-take from the public distribution system—all these resulted in the swelling of stocks of food grains with the Government which stood at 14 4 million tonnes at the end of May 1976 as compared with 44 million tonnes at the end of May 1975 Such swelling of stocks lends support to the Government's objective of building up buffer stocks of about 15 million tonnes by the end of July 1976

### Industrial Production

34 The performance of the industrial sector in the calendar year 1975 presented a rather mixed picture. While the 'core' in-

dustries like coal, electricity, steel, fertilisers, cement and nonterrous metals witnessed a growth of the order of above 10
per cent in certain sub-sectors like cotton textiles and yarn
and some consumer durables, production actually recorded a
decline the net result was that the rate of growth for the industrial sector as a whole vas slightly less than 4 per cent. Although the overall rate was significantly higher than the growth
of only 2.2 per cent achieved in 1974, what needs to be underlined is that but for the decline in production in certain subsectors the overall rate of growth would have been substantially higher. A disquicting feature of the industrial scene was
that some sub-sectors continued to be affected by slackness in
demand originating from domestic and/or external factors,
at the same time as some sub-sectors threw up problems of
modernisation of both capital equipment and management. No
doubt a number of policy measures have been already initiated
with a view to correcting these trends but the impact of such
measures, which would in part be dependent upon the res
ronse of the private sector, may be felt on the everall growth
only after a time lag.

- 35 The monthly average level of the General Index of industrial production in 1975 (with 1970 as bare year) recorded a rise of 39 per cent as compared to only 22 per cent in 1974. The rate of growth in the second half of 1975 was much higher at 56 per cent as compared with 23 per cent in the first half. Basically there was a considerable improvement in the supply of power and of certain strategic inputs like coal steel and cement, besides the various steps taken by Government in the wake of the emergency and the New Economic Programme aided acceleration of industrial growth in the second half of 1975. The industrial licensing policy was liberalised so as to ensure fuller utilization of the existing capacity and to promote investment in priority sectors. Various facilities have been accorded to non-resident Indians for establishing industrial undertakings. Similarly, export and import policies for 1975-76 have been reoriented with a view to ensuring adequate and timely availability of critical raw materials and inputs to export-oriented industrial relations which was reflected in a marked decline in the mandays lost during the period July-December 1975.

  at 45 million, as against 99 million in the corresponding period of 1974.
- 36 Particularly impressive was the performance of the public sector enterprises, the weighted average rate of growth for the public sector as a whole, excluding National Textle Corporation (NTC) mills, was as high as 15 per cent in the period April-December 1975, as compared with the production during the corresponding period of 1974
- 37 On the other hand, industries such as cotton textles and yarn industries manufacturing consumer durables such a jeeps and cars, air conditioners radio receivers electric fais, dry cells etc recorded sizeable declines. A variety of factors have been responsible for sluggishness in demand for these industrial products consumer resistance to high prices may have been responsible for sluggish demand for superior varieties of textiles whereas weaknesses in the arrangements of distribution was the dominant factor in the case of controlled clith. In the case of consumer durables, resistance to unusually high prices may have been one of the factors. While a fall in the export demand for both cotton and jute manufactures was an important element in the case of these industries, adjistment of trade inventories may have been another element a these and some other industries. In order to stimulate demaid for some of these industries the Government introduced towards the end of 1975 some measures such as the relaxation of the strictions on construction activity the modification in the distribution policy of controlled doth and the reduction in excise duty in the case of a number of consumer duables.
- 38 A broad idea of the differential rates of growth o some sub-sectors of industries could be formulated on the biss of the data presented in Table 3 Despite the overall setoral growth of 3 9 per cent in 1975 the toal weightage of indistries showing a rise in output declined to 41 per cent in 197 from 48 per cent in 1974. This may be explained by a decline from 16 per cent in 1974 to 7 per cent in 1975 in the shre of consumer goods industries recording increases in production. On the other hand, the total weightage of industries showing a decline went up from 19 per cent to 26 per cent.

⁵ Upto end-June 1976

⁶ Upto June 11 1976

TABLE 3 :- CLASSIFICATION OF SELECTED INDUSTRIES BY THEIR GROWTH RATES

In terms of weights in the production index

Range of Growth Rates†	All Groups		Basic Industries		Capital Goods Industries		Intermediate Goods Industries		Consumar Goods Industries	
	 1974	1975( <u>u</u> )	1974	1975 <u>@</u>	1974	1975æ	1974	1975@	1974	1975@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Increase										
1. Moderate: Less than 5 per cent	 21.78	7.04	4.93	0.57	0.35	0.35	8.06	3.08	8.44	3.04
2. Marked: 5 per cent and above	 26,38	34.14	15.58	21.94	1.12	5.18	1.78	2.80	7.90	4.22
Of which:										
10 per cent and above	 7.10	32,76	0.09	21.72	1.12	4.11	0.23	2.71	5.66	4.22
3. Weight (1+2)	 48.16	41.18	20.51	22.51	1.47	5,53	9,84	5.88	16.34	7.26
B. Decline										
4. Moderate: Less than 5 per cent	 4.41	12.00	1,97	0.61	1.09		0.09	6.61	1.26	4.78
5. Marked: 5 per cent and above	 14.62	13.72	1,31	0.67	6.25	3.28	2.95	0.39	4,11	9,38
Of which:										
10 per cent and above	 5.35	7.53	1.31	0.67	2.21	3,18	0.24	0.33	1.59	3.35
6. Weight (4+5)	 19,03	25.72	3.28	1.28	7.34	3.28	3.04	7.00	5.37	14.16
C. Constant		0.29							-	0.29
Total weight $(A+B)$	 67.19	67.19	23.79	23.79	8.81	8.81	12.88	12.88	21.71	21.71

Note: Table is based on actual production of individual industries as index numbers of production in respect of individual industries are not available for 1975.

### @ Provisional

- 39. It is not possible to analyse precisely the trends in production of basic, capital goods, intermediate goods and consumer goods industries because the data regarding index numbers of industrial production in respect of different groups, as also individual industries, are not yet available. However, on the basis of actual production figures—and not adjusted for weight—a broad picture could be sketched. Under the 'Basic industries' group, all the major industries such as cement, finished steel, introgenous fertilisers, phosphatic fertilisers, electricity and coal recorded significant increases ranging between 10.7 per cent and 37.5 per cent (Table 4). Chemical industries such as sulphuric acid, caustic soda ash also registered, but only marginal increases. On the other hand, production of steel castings, aluminium-sheets and circles, brassheets and circles and coppersheets and circles, registered declines.
- 40. In the 'Capital Goods Industries' group, production of railway wagons, power transformers, machine tools, diesel engines, paper and pulp machinery and railway locomotics registered marked increases ranging from 9.1 per cent in the case of railway wagons to as high as 95.7 per cent in the case of paper and pulp machinery. The major industry to suffer a setback in production in this category was motor vehicles (16.7 per cent).
- 41. Under the Intermediate Goods Industries' group, cotton spinning industry was the major one to record a decline in output (1.6 per cent). Production in other industries such as jute manufactures, petroleum refinery products, automobile tyres and tubes and storage batteries, however, rose.

42. Under the 'Consumer Goods Industries' group, the important industries to suller a setback in production were radio receivers, bicycles, cigarettes, cotton weaving, matches and hurricane lanterns. Cotton weaving declined under the mill sector by 5.5 per cent. On the other hand, vanaspati, soaps, footwear (leather) and glass and glassware-sheet glass recorded a rise in production. Increases were in the range of 26.3 per cent in the case of soaps and 68.1 per cent in the case of glass and glassware-sheet glass.

#### Prospects of Industrial Growth

43. In more recent years, input bottlenecks, especially naw materials and energy, had hampered industrial growth. While these have been largely overcome, thanks to the bumper agricultural crop and to the improvement of the energy capability of the country, a new constraint which is emerging, at least in certain sub-sectors, is the inadequate growth of the market for industrial products. In fact, a number of measures have already been initiated to stimulate demand or revive industrial activity generally. To begin with, the Plan Outlay for 1976-77 has been stepped up by as much as 31.4 per cent. Since public sector investment generally sets the tone for private investment, it is reasonable to assume that such larger public investment would have a multiplier effect on total investment in the economy. Other measures taken to boost private sector investment include: reform of licensing procedures, easing of restrictions on declaration of dividend and of issue of bonus shares, selective reduction in excise duties and re-

[†] Growth rates represent percentage increases in output over the respective preceding year.

TABLE 4 :—TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIES—GROUP-WISE

						Per ce variat	
Group/Industry	Weight	Accounting Unit		Production	n	1974 over	1975 over
			1973	1974	1975( <u>ā</u>	1973	1974
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Basic Industries							
1. Cement	1,17	'000 Tonnes	15006	14265	16185	<b>-4.9</b>	- <u>+</u> 13.5
2. Caustic Soda	0.32	**	418	428	442	+2.4	+3.3
3. Finished Steel	3.13	**	4828	4952	5641	+2.6	+13.5
4. Aluminium Sheets and Circles	0.36	**	54	45	38	16.7	—15. <del>6</del>
5. Nitrogenous Fertilisers ('N'	0.07		4000	4404			aa- 4
Content)	0.87	**	1083	1101	1410	+1.7	+28.1
6. Phosphatic Fertilisers (P ₈ O ₅ )	0.52	* 11 ******	338	293	403	—13.3	+37.5
7. Electricity	9.23	Lakh KWH	638559	682120	755168	+6.8	+10.7
8. Coal (including lignite)	6.04	Million tonnes	80.4	86.9	98.7	+8.1	+13.6
9. Pig Iron	0.76	'000 Tonnes	7341.3	7253.8	8343.3	-1,2	+15.0
II. Capital Goods Industries							
1. Railway Wagons	1.07	'000 Nos.	12	11	12	8.3	<b>+9</b> .
2. Motor Vehicles (Automobiles)	2.97	"	92	84	70	8.7	—16.
3. Power Transformers	1.48	'000 KVA	11809	9002	11161	-23.8	+24.0
4. Paper and Pulp Machinery	0.08	Rs. lakhs	450	900	1761	+100.0	+95.7
5. Diesel Engines£	0.73	Nos.	136025	115057	138918	15.4	+20.7
6. Railway Locomotives	1,09	Nos.	89	85	128	4.5	+50.0
III. Intermediate Goods Industries							
1. Dry Cells	0.33	Million Nos.	603	635	543	+5.3	14.
2. Tyres—Automobiles —	1.00	'000 Nos.	4414	4736	4884	+7.3	+3.
3. Cotton Spinning	6.24	'00000 Kgs.	9953	10069	9906	+1.2	-1.6
4. Jute Manufactures	2.71	'000 Tonnes	1037	947	1114	8.7	+17.0
5. Petroleum Refinery Products	1,62	,,	19123	19397	20182	+1.4	+4.0
IV. Consumer Goods Industries						•	
1. Radio Receivers	0,97	'000 Nos.	1656	2095	1542	+26.5	<b>—26</b> .
2 Bicycles	0.36	,,,	2541	2511	2209	-1.2	—12,
- Cigarettes	2.21	Million Nos.	64450	60541	60064	-6.1	—12.V —0.
4. Vanaspati	0.68	'000 Quintals	4664	3541	4583	24.1	
5. Soap	0,61	'000 Tonnes	214	213	269	0.5	+26.
6. Matches	0.26	Million Sticks	215951	215555	186317	-0.3	
7. Electric Fans	0.24	'000 Nos.	2261	2336	2091		—13.
8. Glass and Glassware (Sheet	J.27	200 1100	<u> </u>	2330	2091	+3.3	—10.
Glass)	0.11	Lakh Sq. Mts.	141	94	158	33.3	+68.
9. Sugar	2 70		3685	4133	4646	+12.2	+12.
10. Tea	0.50	205	468	490	481	+12.2	<del></del> 1.
11. Cotton weaving—Mill Sector			4148	4316	4079	+4.7 +4.1	
12. Paper and Paper boards (Ex-	2.07		.170	7010	7013	74.1	5,
cluding Newsprint)	2.17	'000 Tonnes	748	804	813	+7.5	+1.

[@] Provisional.

[£] Relating to both vehicular and stationary type.

reduction in the incidence of personal income and wealth tax, investment allowances and a growth-oriented import policy. Thus an appropriate climate for larger private sector investment has been created. In addition, there are at least two more reasons why the industries affected by slackness of demand may witness a revival of demand. A sizeable increase in agricultural incomes in 1975-76 would mean that the rural demand for some goods like textiles would pick-up. Secondly, export demand for Indian industrial products is also likely to rise, in view of the fact that the developed countries may stage a moderate recovery from the recession. In fact there are already indications that the pace of industrial growth has picked up in the first four months of 1976; the index for industrial production during January-April 1976 shows an increase of 11.5 per cent, over the level during the corresponding period of 1975. On the other hand, it should be recognised that it may not be possible to repeat, in 1976, the much faster rate of growth witnessed in 1975 by some industries in the 'core' sector. In any case as a broad judgement, it seems reasonable to expect industrial growth of about 6 to 7 per cent in 1976.

#### **Fiscal Policy**

44. As in the previous year demand management set the tone for fiscal policy. Both the Centre and States geared their policies in 1975-76 towards maintaining price stability while promoting economic growth. Efforts initiated in 1974-75 to mobilise resources and to contain the magnitude of budgetary deflicit were further reinforced by the success of the Voluntary Disclosure of income and Wealth Scheme and vigorous tightening up of tax administration. As a cumulative result of these factors it was possible to increase investment expenditure and to reduce the combined budgetary deficit of the Centre and the States.

#### **Budgetary Deficit: Centre and States**

45. The total disbursements of the Centre and States together, but not including Union Territories, rose in 1975-76

nevised estimates) by 21.0 per cent or almost at the same raet as in the preceding year. The increase in non-developmental outlay in 1975-76 was higher at 26.6 per cent than the rise of 19.3 per cent in the case of developmental outlay. The reasons for higher expenditures under the Centre and States are indicated separately in subsequent paragraphs. The combined total receipts increased by 23.9 per cent in 1975-76 as against a rise of 19.9 per cent in the preceding year. The increase in the rate of growth of receipts during 1975-76 was the cumulative result of the additional tax efforts, made by the Centre and States during 1974-75 and 1975-76 and of the success of the Scheme for Voluntary Disclosure of Income and Wealth. Consequently, the combined budgetary deficit of the Centre and States was substantially lower at Rs. 468 crores (revised estimates) than the level of Rs. 752 crores in 1974-75 (Table 5). In fact, subsequent data show that the combined deficit for 1975-76 actually amounted to a much lower level of Rs. 351 crores.8

- 7. Budgetary Deficit (—)/Surplus (+) is as measured
  - (Λ) for the Centre: (i) not increase/decrease in outstanding treasury bills and (ii) withdrawal from/ addition to cash balances; and
  - (B) for States: State budget figures of (i) net increase/decrease in RBI credit in the form of ways and means advances and overdrafts (repayable within 7 working days with effect from May 1, 1972. (ii) decline in/addition to cash balances, (iii) net sales/purchases of securities held by States in their cash balance investment account and (iv) incashment of/investment in securities held in revenue reserve funds.
- 8. According to the information available in the Reserve Bank of India records, the combined deficit for 1975-76 amounts to Rs. 351 crores, comprising budgetary deficit of Rs. 367 crores on the Centre's account (i.e. net increase in outstanding treasury bills and reduction in cash balances) and a surplus of Rs. 16 crores on account of States (i.e. variations in cash balances, holdings of treasury bills and ways and means advances from the Reserve Bank).

TABLE 5:—COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS

(Amounts in Rupees Crores)

		1974-75 (Accounts)	1975- (Budget Est		1975 (Revised E		1976-77 (Budget Estimates) $\bar{q}$		
Items		Amount	Amount	Per cent increase(+)/ decrease(—) over the previous year	Amount	Per cent increase(+)/ decrease(—) over the previous year	Amount	Per cent increase(+)/ decrease(-) over the previous year	
1		2	3	4	5	6	7	8	
I. Total Receipts (A+B) A. Revenue Receipts  Of which:		11/1/	17007 12 <b>57</b> 3	⊢9.7 +8.2	19206‡ 14007	+23.9 +20.6	206 <b>2</b> 4 14889		
Tax Receipts		. 9206	9934	+7.9	10787	+17.2	11730	+8.7	
B. Capital Receipts II. Total Disbursements .  Of which:		. 3887 16255	4434 17243	+14.1 +6.1	5199‡ 19674	+33.8 +21.0	5735 20965		
A. Developmental Outlay  (a+b)  (a) Revenue  (b) Capital		. 7846 . 5340 2506	5870	+5.4 +9.9 —4.3	9362 6251 3111	+19 3 +17.1 +24.1	9882 6903 2979	+10.4	
		(2134)				)++ (+31.1)		+ + -4.2 (+6.5)++	

	 · · <del></del>	<del></del>			** ~ -	<del></del>		
1		2	3	4	5	6	7	8
B. Non-Developmental						<u> </u>		· ·-·
Outlay $(a+b)$	 	5279	6000	+13.7	6681	+26.6	7030	+5.2
(a) Revenue	 	5045	5729	+13.6	6198	+22.9	6729	+8.6
(b) Capital	 	234	271	+15.8	483†	+106.4	301	37.7
III. Overall Surplus (+) / Deficit (—) (I—II)	 * 1	<b>—752</b>	236		468		-341	

Notes: 1. Data do not cover Union Territories.

- 2. Figures are adjusted for inter-Governmental transfers on the basis of data available in the State Government Budgets. These adjustments do not affect the combined overall position.
- 3. Figures given here are not comparable with those given in the Annual Reports for the years prior to 1973-74 due to changes in budgetary classification adopted in 1974-75.
- 4. Figures are provisional.
- a Includes affects of budget proposals but excludes the effect of post-budget tax concessions announced on May 12, 1976.
- ‡ Includes Rs. 40 crores of bonds issued under Voluntary Disclosure Scheme of Income and Wealth in 1975.
- ++ Exclude increase in value of inventorics of fertilisers and foodgrains (received as gift from abroad) in 1974-75 and 1975-76 from the Central Government account. From March 1976, transactions in respect of fertilisers have been transferred to the Food Corporation of India.
- † Includes payment of Rs. 226.6 crores to the International Monetary Fund under its 'maintenance of value' provision. Source: Budgets of the Central and State Governments.
- 46. Taking the Central Government separately, the budget for 1975-76 anticipated an overall budgetary deficit of Rs. 247 crores. Revised estimates for the year pushed up the budgetary deficit to Rs. 490 crores. Subsequent information, however, indicates that the overall budgetary deficit has in fact been only of the order of Rs. 367 crores or Rs. 123 crores lower than that shown in the revised estimates.
- 47. As the details of receipts and expenditure corresponding to the budgetary deficit of Rs. 367 crores usually becomes available, at the time of the next budget the following review is based on the revised estimates for 1975-76.

#### Central Government's Expenditure: 1975-76

48. According to the Economic and Functional Classification of the Central Government budget for 1976-77 issued by the Department of Economic Affairs, the total expenditure of the Central Government for 1975-76 (revised estimates) recorded at Rs. 12091 clores, a sharp rise of Rs. 2306 crores or 23.6 per cent over that of 1974-75 (accounts) (Table 6). The main factor responsible for the significant increase in the total expenditure in 1975-76 was the substantial rise by 37.6 per cent in the Plan provision in the budget to Rs. 4080 crores from Rs. 2966 crores in 1974-75; both Central Plan expenditure and Central assistance to the Plans of States and Union Territories were larger over the year.

TABLE 6:—DEVELOPMENTAL AND NON-DEVELOPMENTAL EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(Amounts in Runees Crores)

						(Amou	nts in Rup	ees Crores)	
		1974-75 (Accounts)		1975-76 (Budget Estimates)		1975-76 (Revised Estimates)		1976-77 (Budget Estimates)	
Items	Amount	Per cent variations over the previous year	Amount	Per cent variations over the previous year	Amount	Per cent variations over the previous year	Amount	Per cent variations over the previous year	
1		3	4	5	6	7	8 -	9	
Total Expenditure (A+B)	9785	20.3	10577 (100.0)	8.1	12091**	23.6	12604 (100,0)	4.2	
A. Developmental Expenditure									
(i+ii)	. 4975 (50.8)	32.5	5353 (50.6)	7.6	6356 (52.6)	27.8	6595 (52.3)	3.8	
(i) Social Services	. 592 (6,0)	—1 5	705 (6,7)	19.1	733 (6.1)	23,8	815 (6.5)	11.2	
(ii) Economic Services*	4383 (44.8)	39.0	4648 (43. <b>9</b> )	6.0	5623 (46.5)	28.3	5780 (45,8)	2.8	
B. Non-developmental Expenditure (i+ii)	. 4810	9.9	5224 (49,4)	8.6	5735 (47.4)	19.2	6009 (47.7)	4.8	
an a self-self-self-self-self-self-self-self-	. 2618	6.8	2810 (26.6)	7.3	3314*** (27.4)	* 26,6	3201 (25,4)	-3.4	
(ii) Unallocable	(22.4)	13.9	2414 (22.8)	10.1	2421 (20.0)	10.4	2808 (22.3)	16.0	

Note:

- Figures in brackets are percentages to total expenditure.
- * Include block grants and loans to States and Union Territories.
- ** Includes Rs. 226 6 crores paid to the IMF under the 'maintenance of value' provision of its Articles of Agreement.

Source: Economic and Functional Classification of the Central Government Budget, 1976-77, issued by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

### Budgetary Resources and Savings Capital Formation

- 49. Expenditure on capital formation during 1975-76 at Rs. 4602 crores showed a rise over the year by 25.2 per cent, as compared to a 38 per cent rise in 1974-75. Capital formation expenditure on industry, agriculture and transport and communication increased, respectively, by 50 0 per cent, 14.6 per cent and 11.8 per cent over the levels in 1974-75. Capital formation thus accounted for 38.1 per cent of the Central Government's total expenditure in 1975-76—up by one-half percentage point over the proportion of 37.6 per cent in percentage point over the proportion of 37.6 per cent in 1974-75.
- 50 Of the total expenditure of Rs. 12091 crores by the Central Government, final outlays on consumption expenditure (i.e. expenditure directly incurred on wages and salaties and goods and services for current use) and on gross direct capital

formation (i.e. investment in buildings, public works, machinery and equipment and other assets and acquisition of inventorics) increased in 1975-76 by Rs. 576 crores or 14.1 per cent over that of 1974-75, to Rs. 4670 crores. The rise of 18 per cent in consumption expenditure accounted for almost 90 per cent of the growth in the final outlays. Nearly one half of the increase in consumption expenditure was on account of wages and salaries which rose by Rs. 214 crores or 13.2 per cent.

51. The rate of growth at 4.9 per cent in gross direct capital formation was much slower but this largely reflected only a decline in inventories of foodgrains and fertilisers, Excluding inventories, direct gross fixed capital formation recorded a growth of 17.1 per cent. Further, financial assistance to the rest of the economy for capital formation which is outside the final outlays, increased by 35.4 per cent to Rs. 3315 crores in 1975-76 (Table 7).

TABLE 7:-EXPENDITURE ON CAPITAL FORMATION BY GOVERNMENT OF INDIA

(Amounts in Rupces Crores)

	Items					1974-75 (Accounts)	1975-76 (Budget Estimates)	1975-76 (Revised Estimates)	1976-77 (Budget Estimates)
	1				_	2	3	4	5
ī.	Gross Direct Fixed Capital Formation			 		823	887	964	1092
II.	Increase in Inventories			 		405 (372)	131 (140)	323 (313)	32@, (—)
III.	Net Direct Capital Formation (Gross Direct Expenditure on Renewals and Replacements					1084	, 862	1132	952
1 <b>V</b> .	Financial Assistance for Capital Formation	(a+b-	⊦c)	 		2449	2913	3315	3781
	(a) States and Union Territorics	٠.		 		1188	1223	1386	1520
	(b) Non-departmental Commercial Underta	kings		 		1115	1555	1783	2108
	1. Financial Concerns			 		156	135	214	178
	2. Others					959	1420	1569	1930
	(c) Local authorities and other parties					146	135	146	153
	Total (I+1I+IV)			 		3677	3931	4602	4905

- Notes: 1. In this table expenditure on capital formation is shown on a gross basis.
  - Figures within brackets indicate changes in inventories of fertilisers and foodgrains.
  - With effect from March 1, 1976 the responsibility for purchase, handling and distribution of imported nitrogenous fertilisers was transferred to the Food Corporation of India.

Economic and Functional classification of the Central Government Budget issued by the Department of Economic Some : Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

52. Both savings of the Government administration and departmental commercial undertakings were higher by 6.3 per cent and 3.2 per cent, respectively, in 1975-76 (revised estimates) (Table 8). At the same time, current losses of the departmental undertakings were reduced from Rs. 80 crores in 1974-75 to Rs 34 crores in 1975-76. Gross savings of the Central Government thus rose over the year by 11.3 per cent to Rs. 1021 crores. Net savings (i.e. gross savings minus expenditure on renewals and replacements) did a shade better: they rose by 12 per cent to Rs. 866 croics in 1975-76.

#### Approach to Fiscal Policy . 1976-77

53. Before proceeding to a discussion of the Centre's budget for 1976-77, it is necessary to underline some significant changes in the basic approach to fiscal policy, which the budget reflects. The main thrust of the fiscal policy in 1976-77 is towards stimulation of saving and investment with a view to accelerating overall growth. This is for instance, reflected inter alia in the rationalisation of the direct tax structure.

54. In the public sector, the annual Plan Outlay for 1976-77 has been raised by 31.4 per cent from the original plan estimates of the preceding year. Completion of ongoing projects has been accorded priority in investment outlays. For encouraging larger investment and higher utilisation of capacity in the private sector, investment allowances have been introduced for selected industries and concessions in excise duties are granted to certain industrial products for

TABLE 8:—SAVINGS OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(Amounts in Rupees Crores)

Items					1974-75 (Accounts)	1975-76 (Budget		1976-77 (Budget Estimates)	Percentage varia- tion of column	
		Tems (Acco		(Accounts)		4 over 2			5 over 4	
	1				2	3	4	5	6	7
1.	Revenue Receipts of the Government Admi	nistrat	tion					-		<del></del>
	(i+ii)				6158	6687	7239	7595@	17.6	4.9
	(i) Tax Revenue	٠.			5076	5414	5850	6243	15.2	6.7
	(ii) Non-tax Revenue		1.7	٠	1082	1273	1389	1352	28.4	-2.7
2.	Current Expenditure				5317	5887	6345	6910	19.3	8.9
3.	Savings of the Government Administration (	l2)			841	800	894	685	6 3	-23.4
4.	Administration Savings as percentage of Rev	enue F	Receipts							
	(3 as % of 1)				13.7	12.0	12.3	9.0		
5.	- E	of De	partme	ntal						
	Commercial Undertakings (i+ii)	• •	• •		76	244	127	376	67.1	196,1
	(i) Depreciation Provision	••	• •		156	162	161	188	3.2	16.8
	(ii) Retained profits	••	• •	٠.	80	82	34	188		
6.	Gross Savings of the Central Government (3	+5)			917	1044	1021	1061	11.3	3.9
7.	Expenditure on Renewals and Replacements				144	156	155	172	7.6	11 0
8.	Net Savings (6-7)	٠.			773	888	866	889	12.0	2.7
9.	Net Direct Investments*				712	722	819	952	15,0	16,2
10.	Excess (+) or Shortfall () of Net Savings o	ver Ne	t Direc	t						
	Investments* (8—9)				61	166	47	63		

a Exclude the effects of post-budget tax concessions announced on May 12, 1976.

Source: Economic and Functional Classification of the Central Government.Budget 1976-77, issued by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

which demand has been slack. Further, incentive to both investment and productive effort is provided by the reduction in the rates of income and wealth taxes all down the line starting from the maximum rates. The rates of these direct taxes were lowered in the context of the success of the Scheme

9. The Finance Minister also had a detailed review made during 1975-76 of the entire excise duty structure, and in particular of the feasibility of adopting some form of value added tax. Since the issues thrown up by the review were seen to be highly complex and have far reaching effects, it was indicated in the Budget Speech that the existing structure of indirect tax system would be reviewed by a Committee he proposed to appoint. Accordingly, the Government of India appointed on July 20, 1976 a seven-member Committee (a) to review the existing structure of indirect taxes-central, state and local-in all its aspects; and (b) to examine the role of indirect tuxation in promoting economic use of scarce resources; the impact of excise duties on prices and costs, and the cumulative effect of such duties, their incidence on various expenditure groups, the scope of widening the tax base and increasing the elasticity of the system; the feasibility of adopting some form of value-added tax; and whether and how far it would be advisable to assist any particular industry or sectors of an industry by grant of concessions in indirect taxes; as well as the structure and levels of import duties from the view point of import trade control, protection of indigenous industry and pricing of indigenous products.

for Voluntary Disclosure of Income and Wealth so as to rationalise the tax structure and promote better tax compliance. At the same time, with a view to containing demand, the Government extended by one year, with certain modifications, the measure of impounding of additional dearness allowances of employees and the Compulsory Deposit Scheme for income-tax payers.

### New Fconomic Programme

55. Another facet, as it were, of the fiscal policy in 1975-76, was that it sought to achieve accelerated growth with greater social justice in the context of the 20-point Economic Programme ushered in in the middle of 1975 Anticipated expenditure on the New Economic Programme in 1975-76 was Rs 1970 crores, comprising Rs, 1851 crores on account of States and Union Territories and Rs. 119 crores in the Central sector. The outlay for 1976-77 has been raised to Rs. 2338 crores, consisting of Rs. 2174 crores on account of States and Union Territories and Rs. 164 crores in the Central sector. The bulk of the outlay on the Programme is under the States' sector, because the majority of the items included therein fall within the responsibility of the States. To enable the States to meet these responsibilities, the Centre has stepped up its assistance to the States, especially in the field of major and medium irrigation and power projects.

Excludes increases in inventories of fertilisers and foodgrains.

Centre's Budget 1976-77

- 56. The Central Budget estimates for 1976-77 provide for larger resources amounting to Rs. 4759 crores for the Plan, a rise of 16.6 per cent over the budgetary allocation for Plan expenditure of Rs. 4080 crores in 1975-76 (revised estimates). In spite of this rise in the allocation for the Plan Outlay, the total expenditure of the Central Government is estimated to increase by only 4.2 per cent to Rs. 12604 crores in 1976-77 as compared to a rise of 23.6 per cent in 1975-76. This has been rendered possible mainly by the following factors. First, the 'maintenance of value' payments of Rs. 227 crores to the International Monetary Fund in 1975-76 represented the entire adjustment to the Fund's holdings of rupees: such payments would have to be no doubt made during 1976-77 also, but the value of such adjustment may reasonable be expected to be of a minor magnitude. The 1976-77 budget, therefore, makes a nominal provision (Rs. 1 erore) on this account. Secondly, as the financing of imported food and fertilisers is now the responsibility of the Food Corporation of India, no provision has been deemed necessary in the 1976-77 budget for financing inventories of fertilisers and food; in 1975-76 the expenditure on this account amounted to Rs. 313 crores. Thirdly, in the context of price stability, additional expenditure on wages and salaries at Rs. 33 crores is lower than the substantial amount of Rs. 214 crores in 1975-76.
- 57. The Central Government's direct demand for goods and services for consumption and capital formation at Rs 4650 crores constitutes 36.9 per cent of its total expenditure in 1976-77, as against 38.6 per cent during 1975-76. The rate of growth of its consumption expenditure is expected to drop sharply to 4.2 per cent in 1976-77 from that of 18 per cent in 1975-76, with consumption expenditure rising very modestly over the year from Rs. 3383 crores to Rs 3526 crores.
- 58. After allowing for the transfer of transactions in fertilisers to the Food Corporation of India, the Central Government's direct gross capital formation is estimated to grow from Rs. 974 erores in 1975-76 to Rs. 1124 crores in 1976-77, with the rate of growth rising from 13.8 per cent to 15.4 per cent. At 1960-61 prices in the direct gross fixed capital formation shows an increase of 14.2 per cent in 1975-76, close on the heels of a decline by 10.2 per cent in 1974-75 in 1976-77 such capital formation would show a rise of 13.3 per cent. Thus, on this basis, although the direct gross fixed capital formation is expected to grow at a rate somewhat lower than in 1975-76, with the emphasis, mentioned earlier, on investment outlays on on-going projects the anticipated capital formation is likely to result in a larger addition to output.
- 59 Financial assistance to the rest of the economy for capital formation is estimated to rise by 14.1 per cent, over Rs. 3315 crores in 1975-76 to Rs. 3781 crores in 1976-77 (see Table 7): aggregate gross capital formation out of the Central Government's budgetary resources would took Rs. 4905 crores during 1976-77, recording an increase of 6.6 per cent over the provision of Rs. 4602 crores in 1975-76, and would represent about 39 per cent of its total expenditure as against 38.1 per cent in 1975-76.
- 60. In the context of a rise of only 4.2 per cent in 1976-77, as against 23.6 per cent in 1975-76, in the Central Government's total expenditure, its developmental expenditure is budgeted to rise by 3.8 per cent from Rs. 6356 crores; in the preceding year the rise amounted to 27 8 per cent. The trend of the capital formation expenditure for developmental purposes is expected to be better than that of the total developmental expenditure; capital formation expenditure for developmental purposes is estimated to rise by 6.5 per cent from Rs. 4561 crores to Rs. 4858 crores in 1976-77; during the previous year it increased by 25.4 per cent.
- 10. Direct gross fixed capital formation figures have been deflated by using a modified wholesale price index. The wholesale price index was adjusted to reflect only the changes in prices of petroleum products, chemicals and manufactured goods, machinery and transport equipment. Thus the index used for deflation excludes food articles, liquor and tobacco, and industrial raw materials.

- 61. It may be recalled that a significant contribution to the savings of the Government administration in 1975-76 was made by the profits of Rs. 135 crores (revised estimates) from sugar exports. Mainly because the budget estimates tor 1976-77 do not include any credit on this account, savings of administration budgeted for 1976-77 show a decline over the year by 23.4 per cent to Rs. 685 crores, though the Government's current expenditure is also expected to rise by 8.9 per cent. Despite the near trebling to Rs. 376 crores of the depreciation provision and retained profits of departmental commercial undertakings following the smart turnround anticipated in their operating results, net savings of the Central Government are, therefore, expected to rise only by 2.7 per cent or Rs. 23 crores to Rs. 889 crores, as against the rise of 12 per cent to Rs. 866 crores in 1975-76. According to the budget estimates, the Central Government's net savings would fall short of its net direct investment by Rs. 63 crores or 6.6 per cent, as against the surplus of net savings over net direct investment (excluding inventories of fertilivers and food) amounting to Rs. 47 crores in 1975-76.
- 62. Consisting of direct net investment of Rs 952 crores, ret capital transfers of Rs. 305 crores to the rest of the economy and net acquisition of financial assets of Rs. 2812 crores, the Central Government's total capital expenditure is budgeted to amount to Rs. 4069 crores during 1976-77. The net savings of the Central Government are anticipated to be at Rs. 889 crores, external assistance receipts are estimated at Rs. 1090 crores and the net increase of Rs. 1770 crores is budgeted in its domestic financial liabilities consisting of market borrowings, special borrowing of Rs. 480 crores from the Reserve Bank against likely addition during the year to compulsory deposits, small savings and other liabilities but excluding treasury bills, the budgetary deficit is therefore expected to amount to Rs. 320 crores.

Budgetary Operations: State Governments—1975-76

- 63. As in the case of the Central Government, only revised estimates are at present available in respect of finances of the State Governments for 1975-76. These indicate a perceptible improvement as compared with the 1974-75 position (Accounts); this is reflected in a budgetary surplus of Rs. 22 crores in 1975-76, in contrast to a deficit of Rs. 31 crores in 1974-75. The emergence of the surplus was a result of aggregate receipts rising by 18.8 per cent to Rs. 10221 crores while aggregate disbursements increased at a slightly lower rate of 18.1 per cent to Rs. 10199 crores (Table 9).
- 64. Aggregate tax recelpts of State Governments consisting of taxes directly levied and collected by them and of taxes shared by them with the Centre went up by 19.6 per cent to Rs. 4916 crores in 1975-76 from Rs. 4109 crores in 1974-75. The increase, over the year, of Rs. 807 crores—Rs. 540 crores in respect of State's own taxes and Rs. 267 crores in respect of shared taxes—largely reflected the additional measures adopted during the year for mobilisation of resources, both at the time of presentation of the budgets and subsequently, by the States and the Centre. Receipts relating to incomes disclosed under the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Scheme are estimated to have been responsible for half of the rise in the States' receipts from shared taxes. States' own additional taxation during 1975-76 also helped receipts from taxes levied and collected by them to rise by 18.7 per cent over the year: those efforts came on top of the substantial additional tax effort in 1974-75, when such revenues had increased by as much as one-fourth. States' non-tax revenues increased from Rs. 1300 crores in 1974-75 to Rs. 1511 crores in 1975-76 or by 16.2 per cent.
- 65. States' capital receipts excluding loans from the Centre aggregated Rs. 1279 crores in 1975-76 recording a rise of Rs. 183 crores over the preceding year The States were allowed to raise by way of open market borrowings an additional Rs. 100 crores in 1975-76 to repay to the Centre their share of centralised market borrowings, of 1963-64 referred to later: this was a special factor contributing to the rise in capital receipts during the year.

^{11.} This does not take into account the effects of the post-budget tax concessions, announced on May 12, 1976, which would involve a revenue loss of Rs. 9.9 crores in a full year and Rs. 8.8 crores in 1976-77.

TABLE 9 :—OVERALL BUDGETARY POSITION OF STATE GOVERNMENTS

(Amounts in Rupees Crores)

	1974-75		<u>-</u>	1055 50	<del></del> -	ounts in Rup	.———
	(Accounts)	(1975-76	(B.F.)	1975-76	(R.F.)	1976-77( 	
- Items	Amount	Amount	Per cent variations over the previous year (Col. 3 over (Col 2.)	Amount	Per cent variations over the previous year (Col. 5 over Col. 2.)	Amount	Per cent variations over the previous year (Col. 7 over Col. 5.)
1		3	4	5	6	7	8
I. Aggregate Receipts (A+B)	8602	9087	+5.6	10221	+18 8	10740	-( 5.1
		(9266)	(+7.7)́			(10889)	( [-6 5)
A. Revenue Receipts (i+ii)	6431	6819	+6.0	7620	+18.5	8257	-1-8.4
		(6998)	(   8 8)			(8399)	(-10,2)
(i) Tax Receipts $(a+b)$	4109	4325	<b>∔5.3</b>	4916	⊣ 19.6	5343	+87
		<b>(4</b> 498)	(+9.5)			(5466)	+(11.2)
(a) States' Taxes	2881	3001	+4.2	3421	+ 18.7	3740	<b>⊢9.3</b>
		(3133)	(+8.7)			(3831)	(+12.0)
(b) Share in Central Taxes	1228	1324	-+-78	1495	121.6	1603	-172
		(1365)	(+11,2)			(1635)	(+9.4)
(ii) Non-Tax Receipts $(c+d)$	2322	2494	+7.4	2704	F-16.5	2914	-178
		(2500)	(+7.7)			(2933)	(+8.5)
(c) States' Non-Tax Receipts	1300	1406	+8.2	1511	-+-16 1	1656	+ 9.6
		(1412)	(+8.6)			(1675)	(+10.9)
(d) Grants from the Centre	1022	1088	+6.5	1193	<b>⊢16.7</b>	1258	+5 4
B. Capital Receipts (i+ii)	2171	2268	+ 4 5	2601	<b>⊢19.8</b>	2483	-4 5
						(2490)	(-4.3)
(i) States' Capital Receipts	1096	1125	<b>⊢2.6</b>	1279	+16.7	1201	-6.1
			·		•	(1208)	(- 5 6)
Of which:							,
(a) Market Borrowings (Gross)	306£	291	4,9	275	-10.1	306	F11 3
(b) Recovery of Loans and							•
Advances	288	348	+20.8	395	+37.2	360	-8.9
(ii) Loans from the Centre (Gross)	1075	1143	-1-6.3	1322	+23.0	1282	_3.0
II. Aggregate Disbursements	8633	9255	+7.2	10199	-}-18.1	10910	<u>-7.0</u>
Of which:			•		·		,
(a) Developmental Outlay* (i+il)	5944	6213	-1-4.5	6934	+16.7	7466	<del> -</del> 7. <b>7</b>
(i) Social and Community Services	2649	2797	_{l-} 5.6	3008	- -13.6	3206	+6.6
Of which:							1
Expenditure on Natural Cala-							
mities	115	99	—14.7	122	+ 5.2	53	56 . 6
(ii) Economic Services	3295	3416	+3.7	3926	+19.2	4260	<b>⊬8.5</b>
(b) Non-developmental Outlay*	1946	2289 -	-1-17.6	2344	-j-20.5	2642 ±	
(c) Repayment of Loans to the Centre	505	642	<b>-</b> 1-27.1	759	-50 3	562	- 26 0
(d) Discharge of Internal Debt	124	32		36	•	138	
Of which:							
Market Loans	91	1		5		105	
III. Overall Surplus (+) or Deficit(-)(I-	·II)31	168		-J 22		<b>— 170</b>	
		(- -11)				(21)	

Notes: 1. Figures are provisonal.

^{2.} Figures in brackets for 1975-76 (B.E.) include estimated yield from budget proposals by the States (Rs. 83 crores), their share in Centre's net additional taxation (Rs. 41 crores) and revision in Central Sales Tax rate (Rs. 55 crores).

^{3.} Figures in brackets for 1976-77 (B.E.) include estimated yield from budget proposals by the States (Rs. 117 crores) and their share in Centre's additional taxation (Rs. 32 crores).

Comprises States' expenditure on revenue and capital accounts and loans and advances extended by States.

⁺ Includes in respect of Rajasthan, the entire liability on account of additional dearness allowance granted to State employees which could not be allocated between developmental and non-developmental expenditure because the required details are not available.

[£] The figure for Manipur included here is drawn from RBI records.

66. There was a sizeable increase during 1975-76 in the net transfer of resources from the Centre to the States consisting of Centre's grants-in-aid and loans to them. The increase over the year amounted to Rs. 164 crores or 10.3 per cent, as compared with that of Rs. 36 crores or 2.3 per cent in 1974-75. Grants accounted for the entire improvement in both the years. Grants rose in 1975-76 by Rs. 171 crores to Rs. 1193 croies and by Rs. 85 crores to Rs. 1022 crores in the preceding year. On the other hand, the Centre's loans to the States, net of repayments, declined during 1975-76 by Rs. 7 crores. In fact gross loans to the States were higher by Rs. 247 croies to Rs. 1322 crores: but States' repayments increased by Rs. 254 crores to Rs. 759 crores during the year Rs. 100 crores of which represented repayment on account of centralised market borrowings of 1963-64. The net resources transferred from the Centre to States grants and net loans) as a proportion of their aggregate receipts excluding loan repayments to the Centre declined from 19.7 per cent in 1974-75 to 18.6 per cent in 1975-76.

67. Aggregate disbursements at Rs. 10199 crores of State Governments were higher by Rs. 1566 crores in 1975-76 or by four-times the increase in the previous year. States' total developmental expenditure including loans to third parties for developmental purposes increased by 16.7 per cent to Rs. 6934 crores. Developmental outlays constituted 74.7 per cent of States' total expenditures in 1975-76, roughly three-times their non-developmental expenditure and were financed to the extent of 77.3 per cent, as compared to 76.7 per cent in 1974-75 by their own resources other than the net transfers from the Centre after meeting the non-developmental expenditure.

Budgetary Operations: State Governments-1976-77

68. Turning to budget estimates for 1976-77, they appear to show a deterioration in the overall budgetary position of State Governments as compared to the revised estimates of 1975-76 . a surplus of Rs. 22 crores in 1975-76 would give way to a deficit of very nearly the same magnitude (Rs. 21 crores). In keeping with the high priority accorded to the implementation of the 20-point Economic Programme, the overall Plan Outlay in 1976-77 is proposed to be stepped up by Rs. 917 crores or by 33.8 per cent to Rs. 3628 crores¹² as compared to the original Plan Outlay in previous year. The increases are concentrated in agriculture, irrigation and power, the 'core' sectors of the economy. This impressive step-up would be matched by further efforts at raising resources: this is reflected in the States' budgets which embody proposals for mobilising additional revenues of the order of Rs. 117 crores. 18

69. Despite the rise anticipated in States' revenues, their aggregate receipts are budgeted to increase by Rs. 668 crores or by 6.5 per cent to Rs. 10889 crores, marking a deceleration in their growth to nearly a third of that recorded in 1975-76. The deceleration is largely attributable to a decline in tax revenues shared with the Centre and grants from the Centre: the growth in shared tax revenues would drop from 21.7 per cent in 1975-76 to 9.4 per cent in 1976-77. In 1975-76, these revenues were materially boosted by receipts under the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Scheme. Further, the Centre's grants to the States would rise by only 5.4 per cent or less than one-third of the increase of 16.7 per cent in the preceding year. States' capital receipts other than loans from the Centre are expected to decline by Rs. 71 crores, compared to the rise of Rs. 183 crores in 1975-76, though market borrowings would inc-

rease over the year. Net transfer of resources from the Centre to the States (Centre's grants and net loans) would be higher by Rs. 222 crores in 1976-77 as compared to Rs. 164 crores in the previous year. The net transfer from the Centre would thus amount to 19.2 per cent of the States' aggregate receipts excluding repayments of Central loans in 1976-77 as compared to 18.6 per cent in 1975-76.

70. Aggregate disbursements of the States are budgeted to increase over the year by Rs. 711 crores or by 7.0 per cent in 1976-77, as against the rise of Rs. 1566 crores or 18.1 per cent in the preceding year. Developmental outlays are budgeted to rise by Rs. 532 crores or by 7.7 per cent to Rs. 7466 crores, though the expenditure on natural calamities is estimated to decline from Rs. 122 crores in 1975-76 to Rs. 53 crores in 1976-77. Non-developmental expenditure which increased by as much as 20.5 per cent to Rs. 2344 crores in 1975-76 is budgeted to increase by Rs. 298 crores or by 12.7 per cent. In the context of the price stability anticipated in 1976-77, expenditure on additional dearness allowance would not arise as in the preceding year (Table 10).

71. Finally, in the search for additional revenues, the States have not exploited the potential in the agricultural sector. The contribution of the agricultural sector, which had considerably benefited from the massive public investment over the years, continues to be negligible. At the same time there has been considerable escalation in the costs of irrigation and power projects. Considerations of equity suggest that beneficiaries of irrigation and power facilities need to make their contribution to their costs and indirectly to finance developmental outlays.

#### Monetary and Credit Policy

72. Monetary policy continued to operate in the overall framework of restraint: this is for instance, reflected in the continuation of the existing structure of interest rates, the generally restrictive Reserve Bank accommodation and the greater degree of discipline in the deployment of credit by commercial banks. At the same time, the anticipated enlargement of supplies, both agricultural and industrial, warranted introduction of some degree of flexibility in the credit policy. The approach to credit policy formulation in 1975-76 was therefore motivated by the objective of facilitating a higher rate of growth in the economy, while at the same time maintaining the overall apparatus of monetary restraint largely intact. The various measures discussed in the following paragraphs bear ample testimony to the degree of flexibility, which it has been possible to impart to credit policy, without endangering price stability. Financing by commercial banks, with the support of the Reserve Bank, of food procurement/stocking on an enormously larger scale, selective liberalisation of margin requirements and of inventory norms and prescription of a ceiling on lending rates all these are instances in point.

#### Credit Policy: Slack Season 1975

73. The restrictive credit policy of the busy season 1974-75 was continued without any significant change during the 1975 slack season. Broadly, stress was laid on the banks' financing credit expansion from their own resources, keeping recourse to the Reserve Bank to the minimum. Thus, all the special discretionary refinance limits granted (other than for public food procurement) were to be withdrawn by the end of the season: even in respect of the basic refinance limit of 1 per cent of demand and time liabilities; it was reiterated that resort to this facility should be restricted to unavoidable and temporary operational needs. An indication was also given that, in respect of refinance for food procurement credit, banks may not expect the same level of support in the next busy season. Further, banks were asked to plan their operations in such a way that for the year 1975-76 (May-April) as a whole, their credit expansion would be limited to around 63-64 per cent of accretion to deposits.

^{12.} Source: Annual Plan 1976-77.

^{13.} Exclusive of the resources raised by State Flectricity Boards and State Road Transport Corporations.

^{11.} The collections from land revenues and agricultural income-tax together constituted only 6.2 per cent of tax receipts of State Governments in 1975-76. Further, land revenue and agricultural income-tax accounted for only 3 per cent of developmental outlay and loans to third parties for developmental purposes in 1975-76

TABLE 10 :- DEVELOPMENTAL AND NON-DEVELOPMENTAL EXPENDITURE OF THE STATE GOVERNMENTS

(A no rat in Rupees Crores)

	1974-75	(Accounts)	1975-76 (Rovisod F. timales)		1976-77 (Budget Estimates)		
Items	Amount	Percentage variations over the previous year	Amount	Percentage variations over the previous year	Amount	Percentage variations over the previous year	
1		3	4	5	6	7	
Total Expenditure (A-  B)  (A) Developmental Expenditure	7890	+9 6	9278	17.6	10103	+3.9	
(i+li)	5944	+12.9	6934	+16 7	7466	<b> -7.7</b>	
(i) Social and Community Services	<b>2</b> 649		3008	+13 6	3206	+0.6	
(h) Economic Services	3295		3926	+19 2	1260	+8.5	
(B) Non-Developmental Εχρεπαίτατε (ι   ii) .	1946	+06	2344	+20.5	2642 a	+12.7	
(t) Goneral Services	1885	<b>⊸0</b> 7	2283	+21.1	2569 a	+12.5	
(ii) Others .	61	+74 3	61	<b>-</b>	73	+19.7	

u Includes, in respect of Rajasthan, the entire liability on account of additional dearness allowance granted to State employees which could not be allocated between developmental and non-developmental expenditures because the required details were not available.

#### Trends in Credit: Slack Season 1975

74. Against the background of this enunciation of policy, the actual trends in credit may be briefly reviewed. During the slack season, deposits rose by Rs. 1142 crores (9,5 per cent) as compared with Rs. 912 crores (8.8 per cent) in the preceding slack season (Table 11). Despite larger accretion to deposits, banks could reduce their borrowings from the Reserve Bank by only Rs. 38 crores as compared with Rs. 270 crores in the 1974 slack season: this was so because there took place a sizeable expansion in bank credit. Gross bank credit (including bills rediscounted) recorded an expansion of Rs. 543 crores—the highest level of expansion in any slack season. There was an increase in public food procurement credit of Rs. 173 crores, in contrast to a decline of Rs. 169 crores in the 1974 slack season. The increase in advances to sectors other than food procurement was also higher at Rs. 450 crores as compared with Rs. 298 crores in the preceding slack season. Consequently, the credit-deposit ratio at the end of the season at 70.6 per cent was higher than the level of 68.9 per cent at the end of the preceding slack season. I he incremental credit-deposit ratio worked out to 55 per cent.

### Credit Policy: Busy Season 1975-76

75. The credit policy for the busy season 1975.76 aimed at imparting some measure of flexibility in the credit discipline to sustain growth and stimulate investment, without at the same time impairing the basic objective of preventing a rectudescence of inflationary pressures. Selective credit controls were operated with some degree of flexibility—taking into account the anticipated increase in the output of agricultural commodities and the needs of the agro-based industries.

76. It was emphasised that the credit expansion during the busy season would have to be met mainly through banks' own resources and that the Reserve Bank support, except in respect of food procurement credit would be minimal and essentially of a temporary nature. In the deployment of their own resources, banks were advised to give primary attention to the priority areas indicated. To stimulate investment, banks were advised to provide larger term loans for periods beyond three years at a rate of interest not exceeding 15 per cent including an element of one per cent on account of interest tax. Subsequently, in view of the relief from interest tax which was granted in respect of medium-term loans, banks were advised to charge, effective

from April I, 1976, a rate of interest not exceeding 14 per cent on term loans granted for periods of not less than seven years.

#### Discretionary Accommodation

77. To ensure that banks' recourse to the Reserve Bank is kept to the minimum both in terms of amount and duration of utilisation, relinance/rediscount facilities were made even more discretionary than in the past. Banks were allowed a basic refinance limit equal to one per cent of demand and time liabilities (as on the last Friday of September 1975). Such refinance as well as refinance for food procurement credit, attracted a fixed rate of interest of 10 per cent. Such refinance limits aggregated Rs. 139 crores. Further, in the case of food procurement credit, a change was introduced in the formula for refinance: banks could claim 50 per cent of the increase in public food procurement credit between Rs. 450 crores and Rs. 600 crores, as against the range of Rs. 300 and Rs. 450 crores earlier and full refinance for increase over an outstanding level of Rs. 600 crores as against the level of Rs. 450 crores carlier. If food procurement credit were to exceed the level of Rs. 900 crores, the nature and size of the Reserve Bank support was to be reviewed.

78. All refinance, other than the two categories specified above, were to be provided strictly at the discretion of the Reserve Bank in respect of cost as well as availability. The rate of interest on such accommodation was to range from 11.5 per cent to 18 per cent. The operation of refinance facilities on the basis of the net liquidity ratio system was discontinued; the discretionary refinance was to be hence-forward provided taking into account banks' general compliance with policy objectives, their credit-deposit ratio, export performance, sectoral priorities in deployment of credit, availability of resources from IDBI, ARDC and money market and any other special considerations that may be relevant in specific cases. A part of such refinance was to be directly linked to the export credit performance of banks and was to be made available at 11.5 per cent. Export refinance limits aggregating Rs. 73 crores were sanctioned to banks initially up to end-April 1976 but later were permitted to continue upto the end of the 1976 slack season. It was also decided to discontinue except tinder special circumstances, all special discretionary accommodation provided so far in favour of linancing petroleum companies and public sector undertakings.

79. Banks were also allowed, as before, a basic bill rediscount limit equal to 10 per cent of total bills purchased and discounted with them (as on last Friday of September 1975) at the Bank Rute. Additional bill rediscount limits were available to banks at the discretion of the Reserve Bank, at rates ranging from 10 per cent to 15 per cent. The basic limits aggregating Rs. 155 crores sanctioned initially till April 30, 1976 are being continued up to end-October 1976. The Bank further sanctioned additional limits of Rs. 135 crores till end-April 1976, which were temporarily extended till end-June 1976. The extent of this accommodation which was availed of during the 1975-76 buy season aggregated Rs. 181 crores, compared to Rs. 191 crores in 1974-75 and Rs. 279 crores in 1973-74.

80. Another source of refinance relates to the Duty Draw Back Credit Scheme. 1976¹⁵ introduced with effect from February 1, 1976. In terms of the Scheme, banks would grant advances to exporters against their duty draw back entitlements as provisionally certified by Customs Authorities, pending final sanction and payment and such advances would be refinanced by the Reserve Bank.

# Other Changes

81. Other changes introduced with a view to providing some flexibility in the application of credit restraint incasures, may be said to form part of the process of progressive implementation of the recommendations of the Study Group on Follow-up of Bank Credit. Firstly, the minimum limit in respect of prior credit authorisation, under the Credit Authorisation Scheme was raised from the existing level of Rs. 1 crore to Rs. 2 crores for undertakings in the private sector. Secondly, the additional margins on book debts and inventories imposed in November 1973 were withdrawn. Thirdly, the system of levying of commitment charge of 1 per cent per annum on the unutilised portion of cash credit limits was withdrawn.

82. A continuous watch was kept over the developments in various sectors of economy and appropriate liberalisations were made in selective credit controls, in respect of groundnuts, foodgrains and free sale sugar. Inventory norms in respect of bank advances were also liberalised torindustries such as jute, paper, automobile ancillaries and cotton spinning mills in the light of the specific problems faced by them.

# Celling on Interest Rate

83. Before taking up a review of the trends in credit during the busy season, a major reform introduced during the season, affecting interest rate structure needs to be highlighted. While the Reserve Bank had stipulated the minimum rate of interest to be charged by commercial banks on their advances, no ceiling rate had been so far prescribed, except in cases of certain categories of export credit. As a result, banks had been charging very high rates in some cases: this is, for instance, borne out by the fact that about 15 per cent of total bank credit was extended at rates over 16 per cent. The incidence of such high rates, in many cases, fell on small borrowers also. The situation therefore called for a structural change, in order to bring about a proper alignment of interest rates. The maximum lending rate by scheduled commercial banks was therefore prescribed at 16.5 per cent (inclusive of the tax on interest income), effective from March 15, 1976. For banks with demand and time habilities between Rs. 25 crores and Rs. 50 crores, the ceiling was fixed at 17.5 per cent. Banks with demand and time liabilities of less than Rs. 25 crores were exempted from the ceiling, However, penal rates on

irregular accounts and advances against commodities subject, to selective credit controls, were kept out of the purview of the ceiling on rate of interest.

#### Trends in Credit: Busy Season 1975-76

84. During the 1975-76 busy season, gloss cledit tincluding bills rediscounted) rose by Rs. 1802 croies of 19.2 per cent as against Rs. 994 croies of 12.7 per cent in the previous busy season (See Table 11). The larger credit expansion in the 1975-76 busy season, which took place on top of the record expansion in the 1975 slack season referred to earlier, was mainly due to the much higher increase in public food procurement credit—an increase of Rs. 870 crores as compared with Rs. 316 crores in the 1974-75 busy season. Excluding food procurement credit, gloss credit rose by Rs. 932 crores (10.8 per cent) as compared with reference of Rs. 678 crores (8.9 per cent) recorded in the 1974-75 season, Deposit growth was also higher at 9.2 per cent as compared with 7.0 per cent in the last busy season. As in the 1974-75 busy season, the bulk of deposit growth was under the category of time deposits. Reflecting the larger credit expansion, the credit-deposit ratio at the end of the 1975-76 busy season at 76.9 per cent was significantly higher than 72.1 per cent, a year before.

85. Reserve Bank accommodation (in terms of both refinance and rediscount) registered an increase of Rs. 671 crores during the busy season, whereas in the previous busy season, the increase was only Rs. 242 crores. The large increase was entirely accounted for by refinance for food procurement credit (Rs. 509 crores). The peak of total recourse to the Reserve Bank reached during the busy season was Rs. 1063 crores: of this, refinance for public food procurement was Rs. 787 crores. The peak in 1975-76 was thus much higher than the peak of Rs. 656 crores reached in the 1974-75 season. At the end of the 1975-76 season, the outstanding amount of accommodation stood at Rs. 966 crores, as against Rs. 413 crores a year before.

# Overall Assessment: 1975-76

86. Taking the year July 1975 to June 1976 as a whole, expansion in bank credit was more than double the increase recorded in the previous year. Bank credit showed an increase of Rs. 2509 crores as against Rs. 1097 crotes in the comparable period of the previous year. Including bills rediscounted, the increase was Rs. 2521 crores as compared with Rs. 955 crores during last year. Excluding food procurement credit, the increase in gross credit was 1131 crores while the increase in the comparable period of the previous year was relatively much less at Rs 683 crores. The growth in aggregate deposits was higher at 20.0 per cent as against 16.6 per cent and as in the previous year, the bulk of the increase was accounted for by time deposit Resort to the Reserve Bank (both rediscount and refinance together) recorded an increase of Rs. 498 crores, whereas in the comparable period of 1974-75 there was a decline of Rs. 289 crores. The credit-deposit ratio was higher at 76.1 per cent on June 25, 1976 than the ratio of 71.4 per cent a year before.

# Sectoral Deployment of Credit: Busy Season 1975-76

87. An analysis of the sectoral deployment of credit in the 1975-76 busy season reveals that food procurement credit accounted for 49.4 per cent of the increase in gross bank credit, as against 31.2 per cent in the 1974-75 busy season (Tables 12 and 13). Excluding food procurement credit, almost the entire increase was accounted for by the private sector. Of the non-food credit, priority sector advances formed 37.6 per cent (28.7 per cent in the 1974-75 busy season). I xport credit which had recorded a marginal decline in the 1974-75 season formed as much as 24.1 per cent of the increase in non-food credit.

^{15.} The details of the Scheme are provided in Part II of this Report,

# TABLE 11 :-- SEASONAL VARIATIONS IN SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' DATA

(Annuts in Runess Croros)

		Slack	Busy	Slack	Bu∖y	Slack	Busy	Slack	Busy
Items		Season 197 <b>2</b>	Season 1972-73	Season 1973	Season 1973-74	Season 1974	Season 1974-75	Season 1975	Season 1975-76
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Aggregate Deposits		+705	+811	+899	-677	+912	-784	+1142	+ 1218
		(+9.7)	(+10.2)	(+10.3)	(+7.0)	(+88)	(+7.0)	(  -9 5)	(+9.2)
(a) Demand Deposits .	•	<b>-262</b>	+335	+252	+407	+298	+316	+434	+- 395
		(+8 3)	(+98)	(+6.7)	(+10 2)	( +-6 8)	(+6.7)	(+8.7)	(+7.3)
(b) Time Deposits		+443 (+10.8)	+ 476 (+10 5)	+647 ( ⊦12.9)	+270 (+4 8)	+614 (+10.3)	+468 ( ⊦7.1)	+708 (+10-1)	+823 (+10 7)
2. Bank Credit	1	+67 (+1-3)	+897 (+17 1)	+346 (+5 6)	+1111 (+17.1)	+129 (  -1 7)	+935 (+12 1)	+6 <b>2</b> 3	+1758 ( ⊢18 9)
2. Pitt. Padic ounted with P.BI		~ -10	+19	+ 1,5	<b>⊹244</b>	<b>—171</b>			
3. Bills Rediscounted with RBI	,						<b>⊹59</b>	⊸80	+44
4. Gross Bank Credit (2+3)		.+57 (	+916 (+17.4)	+361 (+5.8)	+1355 (+20 7)	42 ( -0 5)	+994 (+12 7)	+543 (+61)	+1802 (+19.2)
5. Public Food Procurement Credit		-1	<b>⊦</b> 6	58	<b></b> 188	—169	-316	- - 173	+870
6. Non-Food Bank Credit (25)		<b>-68</b>	+891	+404	+923	+298	+619	+450	+888
•		(+(4)	(+179)	(+6.9)	(十14.7)	(+4 1)	(  -8 <b>3</b> )	( +5 6)	(+10.4)
7. Non-Food Gross Bank Credit		+58	+910	+419	+1167	+127	+678	+ 370	- <b>+932</b>
(45)		(+1.2)	(+18 3)	(+71)	( +18 5)	(-17)	( ⊦8 9)	(+4 5)	( +10 8)
8. Investments		+619	+4	- -282	_{[~} 157	+472	+165	+405	+394
(a) Government Securities .		+519	-89	+187	+73	+349	+118	+225	+345
(h) Other Approved Securities	• 1	<b>⊣-100</b>	+ 93	+95	+84	+123	+47	<b>⊦180</b>	+-49
9. Cash and Balances with RBI		+57	+60	+ 444	213	-  117	- ~79	j- 63	<b>-17</b>
(a) Cash in hand		<b>+2</b> 7	+20	+25	J- <b>4</b>	+25	+ 31	<b>→11</b>	+7
(b) Balance with RBI .		+30	+ 40	+ 419	-217	+92	<b>11</b> 0	+ 74	+118
10. Money at Call and Short Notice		+13	+ 72	<b>⊸</b> 41	-26	+61	+25	-9	+114
11. Borrowings from RBI		→16	+17	<b>⊦56</b>	+253	-270	+183	-38	+627
12. Crodit Deposits Ratio .		66.2	70 3	67 3	73.7	68.9	72 J	70-6	76 9
13. Credit excluding I ood Credit	Deposit		0	,			, <u>-</u> .		_
Ratio		62 6	67.0	64 9	69 6	66 6	67 4	65 0	65.6
14. Investment Deposit Ratio .	•	36-3	33 0	32 9	32 2	33.8	33 0	33.2	33,1

TABLE 12: --SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK OPEDIT (INCLUDING BILLS REDISCOUNTED WITH RESERVE BANK OF INDIA)

(Amounts in Rupees Crores)

	Variations during									
Items	BUSY	SEASON 197	4-75	BUSY SEASON 1975-76						
_	Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total				
1	2	3	4	5	6	7				
Public Food Procurement Credit	+306 (68-6)		+306 (31.2)	+864 (101 3)	_	+864 (49.4)				
2. Priority Sector (including export credit granted to										
this Sector)	+8 (1-8)	+186 (34-7)	+194 (19.7)	+1	-[-33 <b>2</b> (37,θ)	+333 (19.0)				
(a) Small-scale Industries	[-1] (θ-2)	+77 (14,4)	+78 (7,9)	<b>– 2</b>	+124 (13.8)	- -122 (7,0)				
(b) Agriculture	+7 (1.6)	+76 (14,2)	+83 (8 4)	-	+98 (10 9)	+98 (5,6)				
(c) Other Priority Sectors		+33 (6.1)	+33 $(3,4)$	+3 (0.4)	+110	+113 (6,4)				
3. All Other Sectors* .	+132	+ 350	+- 48 <b>2</b>	<b>—12</b>	+564	+552				
(including exports credit granted to these Sectors).  4. Non-Food Credit (2+3)	(29,6) +140	(65, 3) +536	(49 1) +676	—11	(63 0) +896	(31,6) +885				
5. Of item 4—Export Credit	(31 <b>. 4</b> ) +9	(100,0) <b>—22</b>	(68.8) —13	+6	$\begin{array}{c} (100 \ 0) \\ +207 \end{array}$	( <i>50 6</i> ) + <b>2</b> 13				
6. Total Gross Credit (1+4)	(2.0) <b>+446</b> (100.0)	+ <b>536</b> (100,0)	+982	$(0.7) + 853$ $(100 \ 0)$	(23,1) + 896 $(100,0)$	(12 2) + <b>1749</b> (100,0)				

Notes: 1. Figures in brackets are proportions to gross bank credit.

^{2.} Figures for 1975-76 are based on data collected from banks which account for 92 1 per cent of total bank credit, *Includes large and medium industries and wholesale trade.

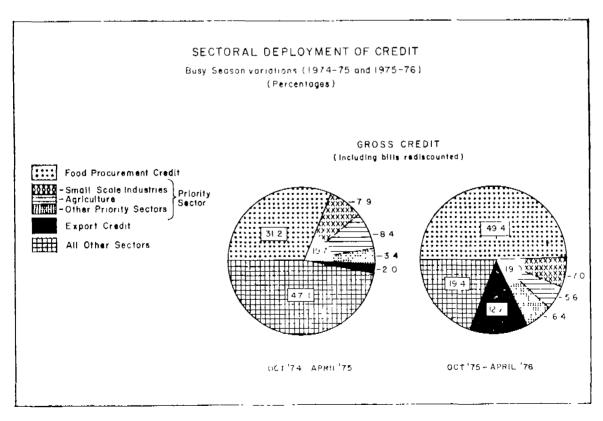


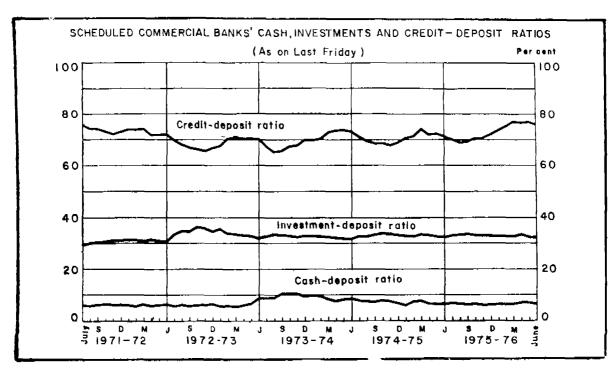
TABLE 13: --SECTORAL DEPLOYMENT OF OUTSTANDING GROSS BANK CREDIT (INCLUDING BILLS REDIS-COUNTED WITH RESERVE BANK OF INDIA)

(Analits in Rupees Crores)

The second	As on A	pril 25, 1975		As on 4	pril 30, 1976	
Ttems -	Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
	2	3	4	5	6	7
1. Public Food Procurement Credn	564 1 (37,5)	-	564,1 (6,4)	1572.8 (54-5)		1572 × (/‡, 3)
2. Priority Sectors (including Export Credit granted to this Sector)	149 8 (8 9)	2000.3 (28.2)	2150 1 (24,5)	142.6 (f.9)	2630 1 (32, 5)	277 <b>2.7</b> (25-3)
(a) Small Scale Industries	7 7 (0.5)	1035.2 (14.6)	1042.9	8,6 (0,3)	1179,6 (14,3)	1133 2 (10 8)
(b) Agriculture	136.4 (#.1)	648.6 (9.1)	785,0 (A,9)	125 1 (£, 3)	91 a 6 (71, 3)	1041.7 (9-5)
(c) Other Priority Sectors	5.7 (0.3)	316.5 (4.5)	322.2 (3.7)	8.9 (0.3)	533-9 (7,5)	542,8 (£ 9)
3. All Other Sectors† (Including Export Credit granted						
to these Sectors)	970.5 (57,6)	5101.8 (71.8)	6072,3 (69,1)	1170 5 (47,6)	5459 6 ( <i>67 5</i> )	6621 . 1 (60 . 4)
4. Non-Food Credit (2+3)	11 <b>2</b> 0.3 (66-5)	7102.1 (100-0)	8222,4 (93,6)	1313.1 (45-5)	8080.7 (107.0)	9393.8 (85.7)
5. Of item 4Export Credit	90.1 (5 f)	659.3 (9.3)	749.4 (8.5)	72.4 (2-5)	903.6 (11.2)	981 0 (8.9)
6. Gross Bauk Credit (1+4)	1684.4 (100-0)	7102.1 (100.0)	<b>8786.5</b> (100.0)	2885.9 (100.0)	8080.7 (100.0)	10966.6 (100.0)

Notes: (1) Figures for 1976 are based on data collected from banks which account for 98 0 per cent of total Bank Credit.

[†] Includes large and medium industries and wholesale trade.



⁽²⁾ Figures in brackets are proportions to gross Bank Credit.

TABLE 14 .--TRENDS IN MONEY SUPPLY AND MONETARY RESOURCES (ANNUAL)

(Amounts in Rupecs Crores)

	Outstandi	ngs at the en	d of June	Varia	itions
Items	1974	1975	1976£	1974-75	1975-76
1	2	3	4	5	6
A. Money Supply with the Public (1+2)	11450	12187	13562	- <del>-</del> -737	+13 <b>7</b> 5
				(+6.4)	( ⊢11.3)
1. Currency with the Public	6603	6707	7297	- <b></b> 104	+590
				(-1.6)	(+8.8)
2. Deposit Money@	4847	5480	6265	-⊢633	+785
				( <del> </del> -13 1)	(+14.3)
B. Factors Affecting Money Supply Variations $(1+2+3+4+5)$					
<ol> <li>Net Bank Credit to Government (a+b)</li></ol>	9102	10506	10779	+1404	-⊢273
(a) Reserve Bank's Net Credit to Government	6570	7515	7256	+945	—259
(b) Other Banks' Credit to Government	2532	2991	3524	1.459	+533
<ol> <li>Bank Credit to Commercial Sector (a+b)*.</li> </ol>	10014	11277	13874	<b>+1263</b>	+2597
(a) Reserve Bank's Credit to Commercial Sector	652	625	740	—27	+115
(b) Other Banks' Credit to Commercial Sector	9362	10652	13134	+1290	<b>⊣-2482</b>
3. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector .	672	310	1279	-362	+969
4. Government's Net Currency Liabilities to the Public	521	554	550	[-33	-4
5. Non-Monetary Liabilities of Banking Sector $(a+b+c)$ .	8859	10460	12921	- -1601	<b>→ 2461</b>
(a) Time Deposits with Banks	6459	7682	9411	<b>⊢1223</b>	- 1729
				(+18.9)	(+22.5)
(b) Net Non-Monetary Liabilities of RBI	1474	1957	2451	+483	+494
(c) Residual	926	821	1059	105	+238
C. Aggregate Monetary Resources [A+B 5(a)]	17909	19869	22972	+1960	+3103
				$(+10\ 9)$	(+15.6)

Note: Figures within brackets relate to percentage variations.

# Credit Policy Slack Season 1976

88. The credit policy for the 1976 slack season, announced at the end of the busy season 1975-76, did not show any significant departure from the policy of restraint pursued so far. The emphasis was on relating availability of bank credit to actual increases in real output, and to assist increase in production without generating any serious pressure on prices. The general features of accommodation from the Reserve Bank remained unchanged except that the food refinance formula was revised. Under the new formula, banks are expected to finance from their own resources public food procurement credit upto an outstanding level of Rs. 800 crores: they are entitled to refinance on the basis of two-thirds of the incremental food procurement credit over the level of Rs. 800 crores. Reserve Bank would, as before, continue to provide selective and necessary support to banks to enable them to meet adequately the genuine requirements of public food procurement, exports and essential needs of production.

# Trends in Credit: 1976 Slack Season

89. The 1976 slack season (upto July 16, 1976) witnessed a further expansion in public food procurement credit. Public food procurement credit rose by Rs. 647 crores as against Rs. 187 crores in the corresponding period of 1975; outstanding food procurement credit touched an unprecedented level of Rs. 2283 crores on July 9. In the slack season 1976 (upto July 16) non-food bank credit recorded an increase of Rs. 132 crores (as against an increase of Rs. 16 crores in the slack season 1975), gross credit rose by Rs. 800 crores as compared with an increase of Rs. 154 crores in the 1975 slack season. This scale of assistance by the commercial banks for food procurement effort, was facilitated by the support provided by the Reserve Bank. Borrowings from the Reserve Bank surpassed the earlier peak of Rs. 187 crores on March 19, 1976 and reached a level of Rs. 1104 crores on July 9; of this, refinance for public food procurement amounted to Rs. 976 crores. Total recourse to the Reserve Bank, on July 16, 1976 stood Rs. 1075 crores, as compared with the peak of Rs. 1063 crores in the 1975-76 busy season. Aggregate deposits expanded by Rs. 942 crores as compared with Rs. 715 crores 25 GI/77—15

in the last slack season: the major part of the increase was under the category of the time deposits. The credit-deposit ratio stood at 77.2 per cent, as compared with 69.7 per cent a year ago. Excluding food procurement credit, the ratio was lower at 62.4 per cent then that of 63.7 per cent a year before.

90. During the slack season, in view of the rise in prices, the situation in respect of sensitive commodities was kept under constant review; selective credit controls on cotton and oilseeds were tightened.

# Trends in Moncy Supply

91. The impact of this selective liberalisation in credit policy was reflected in the trends in money supply: money supply with the public during the year 1975-76 (July-June) showed an expansion of Rs. 1375 crores or 11.3 per cent (Table 14). The order of expansion was substantially higher than that of Rs. 737 crores or 6.4 per cent registered in 1974-75 but it should be noted that it was considerably lower than the average annual rate of expansion of 15 per cent witnessed during the three-year period 1971-72 to 1973-74. More importantly, there is a qualitative difference in the character of money supply expansion during 1975-76 and in earlier years: while expansion during 1975-76 and in earlier years: while expansion during 1975-76 and income, during the earlier years, with the exception of 1973-74, expansion took place when national income was practically stagnant. An even more important qualitative difference lies in the factors responsible for expansion—an aspect which is discussed later.

92. The growth in reserve money or high powered money¹⁶ in 1975-76 was also significantly higher at Rs. 681 crores, as compared with a much lower expansion of Rs. 82 crores in 1974-75. Of this, currency with the public accounted for Rs. 590 crores while the share of bank reserves was only Rs. 110 crores. In the preceding year the rise in currency was much smaller at Rs. 104 crores and bank reserves had registered an actual decline of Rs. 39 crores (Table 15).

^{*} Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for Commercial purposes.

m Inclusive of Other Deposits with the RBI.

[£] Provisional

^{16.} High powered money comprises currency with the public bank reserves and other Deposits with the RBI.

TABLE 15: -- MONETARY RATIOS

Year (July-June)	Bank Reserves£	Cur- rency	Other Deposits with RBI	Bank Money	Reserve Money (2+3+4)	Money Supply (3+4-+5)	Time Deposits	Aggregate Monetary Resources (7+8)	Cur- rency to Money Supply	Currency to Monetary Resources
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Outstanding as on last Friday								<u> </u>	Average	Ratio
(Rs. Crores)									(Por ce	nt)
1971-72	560	4979	66	<b>347</b> 8	5604	8523	4476	12999	58.4	38.3
1972-73	873	5829	41	4092	6743	9962	5491	15454	58.5	37.7
1973-74	933	6603	47	4800	7584	11450	6459	17909	57.7	36.9
1974-75	894	6707	65	5415	7666	12187	7682	19869	55.0	33.8
1975-76*	1004	7297	46	6219	8347	13562	9411	22972	53.8	31.8
Increase over previous									Margir	nal Ratios
year (Rs. Crores)									_	(Per cent)
1971-72	148	388	34	639	569	1061	816	1877	36.6	20.7
1972-73 .	313	850	-25	614	1139	1439	1015	2455	59.1	34.6
1973-74	60	774	7	708	841	1488	968	2455	52.0	31.5
1974-75 .	<b>—39</b>	104	18	615	82	737	1223	1960	14.1	5.3
1975-76*	110	590	19	804	681	1375	1729	3103	42,9	19.0
Percentage variations over the year										
1971-72	35,9	8.5	106.3	22.5	• 11.3	14.2	22.3	16.9		
1972-73	55.9	17.1	39.4	17.7	20.3	16.9	22.7	18.9		
1973-74	6.9	13,3	17.5	17.3	12.5	14.9	17.6	15.9		
1974-75	-4.2	1.6	38.3	12.8	1.1	6.4	18.9	10.9		
1975-76*	12.3	8,8	29.2	14.8	8.9	11.3	22.5	15.6		

^{*} Provisional.

93. Reverting to trends in money supply, of the two components, expansion in deposit money amounting to Rs. 785 crores or 14.3 per cent was considerably larger than that of Rs. 633 crores or 13.1 per cent during the previous year. So also, currency with the public recorded an increase of Rs. 590 crores or 8.8 per cent, which was more than five times the expansion of Rs. 104 crores or 1.6 per cent in 1974-75. Larger Reserve Bank refinance for food procurment as well as a phenomenal rise in foreign assets of the Reserve Bank appear to have induced a higher currency growth during the year.

94. The behaviour of broad money or aggregate monetary resources¹⁷ was also characterised by an accelerated pace of expansion. The rise in aggregate monetary resources at Rs. 3103 crores or 15.6 per cent was larger by Rs. 1143 crores than the expansion in 1974-75: such larger expansion was a combined result of a sharp rise in money supply referred to earlier and a faster growth in time deposits (see Table 14).

95. An explanation for the larger expansion in money supply in 1975-76 has to be sought in the trends in factors affecting money supply. An analysis of these factors indicate that not foreign exchange assets of the banking sector and bank credit to commercial sector were the two predominant causative factors. Net foreign exchange assets of the banking sector recorded an unprecedented increase of Rs. 969 crores; these assets had actually declined by Rs, 362 crores in 1974-75. To the extent that foreign exchange assets could be regarded as a built-in stabiliser of money stock, this factor can be taken as a redeeming feature of a much higher rate of

monetary expansion witnessed in 1975-76. A more significant contributory factor was bank credit to commercial sector. Bank credit expanded by Rs. 2597 crores, i.e. a level higher by Rs. 1334 crores than the risc witnessed in 1974-75. Of the total expansion, as much as 96 per cent was accounted for by the commercial and co-operative banks and the rest by the Reserve Bank. Here again, qualitatively a larger expansion could be explained in terms of food credit which accounted for 56 per cent in 1975-76, as against only 21 per cent in 1974-75, of total bank credit expansion. Significantly, in the wake of larger accretion of deposits, 18 banks were in a position to support credit expansion to a considerable extent from their own resources rather than by borrowings from the Reserve Bank. Consequently, the potential inflationary impact of this factor was moderated somewhat.

96. The extent of the impact of net bank credit to Government on money supply was relatively lower in 1975-76: net bank credit to Government rose by Rs. 273 crores as compared with Rs. 1404 crores in the preceding year. What is more important, as a result of larger revenue and foreign aid realisations in relation to Government disbursements, Reserve Bank's net credit to Government showed an actual decline of Rs. 259 crores in contrast to a marked rise of Rs. 945 crores in 1974-75.

[£] Consist of cash with banks and their deposits with RBI

^{17.} Broad money or aggregate monetary resources comprise money supply with public and time deposits held by banks.

^{18.} With an inclease of Rs. 2533 crores during the year, total deposits with banks showed 97 per cent increase from Rs. 7954 crores as at the end of June 1972 to Rs. 15630 crores by end June 1976. Of this increase of Rs. 7676 crores time deposits accounted for Rs. 4935 crores and demand deposits Rs. 2741 crores.

97. Among the non-monetary liabilities which exert a contractionary influence, time deposits with banks showed a record increase of Rs. 1729 croites or 22.5 per cent as computed with Rs. 1223 crores or 18.9 per cent during the previous year: these deposits thus acted as the largest depressant on money supply.

Seasonal Trends Slack Season: 1975

98. The trends as they emerged in the two traditional seasons viz, slack season and busy season, may now briefly be discussed. The slack season of 1975 witnessed an increase of Rs 286 crores in money supply with the public, in contrast to a fall of Rs, 150 crores registered in the previous slack season. This perhaps indicates the resumption of a tren of contraseasonal expansion, in evidence since 1969, with the sole exception of 1974. The increase is attributable to deposit money which rose by Rs, 415 crores, while currency showed a decline of Rs, 129 crores. The expansion stemmed mainly from bank credit to commercial sector and net bank credit to the Government, both of which recorded increases of Rs, 627 crores and Rs, 362 crores, respectively. A small rise of Rs, 68 crores in net foreign exchange assets also aided the expansion in money supply (Table 16).

Busy Season: 1975

99. Monetary expansion during the busy season of 1975-76 amounted to Rs. 924 crores and was Rs. 92 crores larger than the increase in previous busy season. Of this increase, the share of currency was Rs. 527 crotes and that of deposit money Rs. 397 crores, In terms of factors affecting money supply, rise in bank credit to the commercial sector at Rs. 1926 croies was higher by Rs. 746 crores, than the level of increase in the 1974-75 busy season. Net foreign exchange assets of the banking sector recorded a sizeable increase of Rs. 367 crores in contrast to a decline of Rs. 118 crores in the 1974-75 busy season. Although net bank credit to Government also contributed to the monetary expansion, the expansion in this factor (Rs. 207 crores) was less than onethird of that in the plevious busy season. The cumulative impact of all these factors was offset to a large extent by a rise in non-monetary liabilities of the banking sector by Rs. 1579 crores (See Table 16).

TABLE 16:—TRENDS IN MONEY SUPPLY AND MONETARY RESOURCES (SEASONAL)

(Amounts in Rupees Crores)

Varia	Items						Variation	is during	
Items						Slack S	Season	Busy S	eason
						1974	1975	1974-75	1975-76
1						2	3	4	5
A. Money Supply with the Public (I+2)					,	150	+286	+832	+924
1. Currency with the Public						433	—129	+477	+527
2. Deposit Money@						+283	+415	J-355	+397
B. Factors affecting Money Supply variations $(1+2+3)$	+4-	-5)							
1. Net Bank credit to Government (a+b) .						+ <b>527</b>	362	+694	+207
(a) Reserve Bank's Net Credit to Government						- <b>-</b> 168	+129	<b>+578</b>	141
(b) Other Banks' credit to Government .						+359	+234	- <b>⊢116</b>	+347
2. Bank credit to Commercial Sector (a+b)*						+251	<b>+627</b>	+1180	+1926
(a) Reserve Bank's credit to commercial sector						76	20	+134	+-85
(b) Other Banks' credit to commercial sector .						+328	+647	+1046	+1841
3. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector		•				—162	+68	—118	+367
4. Government's Net Currency Liabilities to the Public	٠				1	<b>+8</b>	+12	+20	+4
5. Non-monetary Liablities of Banking Sector (a $+b+c$ )						<b>+774</b>	+783	-]-944	+1579
(a) Time Deposits with banks						+647	+740	4-482	+823
(b) Net Non-monetary Liabilities of R B ! .						+64	-J- <b>299</b>	+433	+106
(c) Residual						<b>+ 63</b>	—256	+29	-⊦649
C. Aggregate Monetary Resources [A+B 5(a)] .					•	+498	+1026	+1313	<b>+1748</b>

Note: Figures within brackets relate to percentage variations.

- * Includes advances made to Public Sector enterprises and State Governments for commercial purposes.
- inclusive of 'Other Deposits' with R B I.

The Price Situation

# General Trends and Factors Responsible

100. The most remarkable achievement of the Indian economy in 1975-76 was in the sphere of prices. At a period when high lates of inflation continued to affect most countries of the world, or at any rate are not showing signs of abatement, India has been able to not only contain, but actually bring India has been able to not only contain, but actually bring down the prices from the heights to which they had risen during the two years 1972-73 and 1973-74 of inflationary bout. The General Index of Wholesale Prices (base year 1961-62-100) which had reached an all-time high of 330.7 on September 21, 1974 began to decline steadily thereafter, to reach 311.0 by end of June 1975 and dipped further to a low of 282.3 on March 20, 1976. At this point of time, therefore the nice level may be said to have actually bided therefore, the price level may be said to have actually slided back to the level prevailing two years earlier; for instance, the index had stood at the level of 282.1 on March 2, 1974.

101. Between September 1974 and mid-March 1976, the general level of wholesale prices recorded a decline of as much as 14.6 per cent. This phase of consistent decline was, however, interrupted on March 20, 1976, since when prices began sirming up, with the index rising to 301.8 at end-June 1976 or by 6.9 per cent. Notwithstanding this rise, the general trend of prices during the year 1975-76 (July-June), as a whole, reveals a net decline, whether one compares the level of prices on a point-to-point basis or on the basis of monthly averages. For instance, between the end of June 1975 and end of June 1976, wholesale prices recorded a decline of 3.0 per cent: this trend was in contrast to the phenomenal rises of 21.5 per cent and 27.8 per cent witnessed during the years 1972-73 and 1973-74, respectively and a nominal rise of 0.7 per cent in 1974-75. A better picture would emerge, if one takes into account the monthly average levels: during 1975-76 (July-June) prices recorded a decline of 6.0 per cent, in sharp contrast to an actual rise of 16.8 per cent in 1974-75.

102. The abiding trend in 1975-76 is therefore one of decline—a decline which cannot be regarded purely as a seasonal phenomenon brought about by the bumper crop of 1975-76, although it was undoubtedly assisted by it. The declining trend reflects the impact, apart from the good crop, of continued monetary and fiscal discipline and of the administrative measures taken to curb speculative hoarding. The experience of 1975-76 has brought into sharp focus the importance of another aspect of price behavior namely, that in the context of the Indian economy, the supply-demand balances provide: but only a partial explanation of the fluctuations in prices: price administration is perhaps as important as the supplydemand balances because of the fact that there is sufficient scope for introducing distortions by speculative operations. These operations have been largely eliminated by the declaration of internal emergency in June 1975 and by a whole range of the measures which included the crackdown on economic offenders, black marketeers and smugglers and the curbing of the use of unaccounted money.

103. On the whole, there is sufficient evidence to argue that the year 1975-76 would bequeath a degree of price stability, of course, given a good agricultural season 1976-77. At least two reasons could be put forward in support of the argument: it has been possible to build sizeable buffer stocks of foodgrains, as also to accumulate substantial foreign exchange reserves, which could be drawn down to combat domestic inflationary forces if they show sings of re-cmerging.

# Decline in Prices June 1975 to March 20, 1976

104 Reverting to the trend in prices during the year 1975-76, the trend can be more meaningfully analysed into two distinct phases: the first phase between end-June 1975 upto March 20, 1976 when prices recorded a decline and the second phase from the third week of March 1976 till end-June 1976 when prices actually rose. During the first phase, wholesale prices recorded a decline of 9.2 per cent. The bumper crop of 1975-76, as well sizeable imports of foodgrains in two successive years may be said to have set the tone for the trend. The influence of these factors was reinforced by the various anti-inflationary measures, referred to earlier.

Rise in Prices: March 20 to end-June 1976

105. The second phase witnessed a arise in prices of 6.9 per cent. The bulk of the rise however seems to have occurred in

the month of June 1976: for instance, between June 5 and June 26, the rise in wholesale prices was of the order of 3.3 per cent. It may be recalled that prices had actually shown a nominal decline in June 1975. One explanation for the substantial rise in prices in June 1976 seems to lie in the fact that with the delayed monsoon in most parts of the country, price expectations changed and hence the speculative element perhaps gained some ground. This explanation is particularly true in the case of specific commodities, such as raw cotton and groundnut, where the supply-demand balance had not deteriorated to any great extent.

106. Parenthetically, it may be added here that a wellspread public distribution system can provide an effective countervailing force to such situations.

107. Taking this phase as a whole, however, a part of the rise could be attributed to the approach of the slack season, a more meaningful explanation has to be sought in the specific commodities/articles, which witnessed significant rises in prices. The two main groups which were responsible for this tise were 'Food Articles' (8.9 per cent) and 'Industrial Raw Materials' (23.6 per cent). It may be added that these very groups were mainly responsible for keeping down the general level of prices throughout the financial year 1975-76. In the Food Articles group the pressure on prices was largely reflected in commodities of relatively lower importance such as fruits and vegetables, fish, eggs and meat and sugar and allied products. The prices of foodgrains however recorded only a marginal rise of 0.9 per cent, the rise being more pronounced in the case of jowar and bajra. Edible oil prices too recorded a rise of 16.1 per cent. The prices of pulses however, declined significantly. In the Industrial Raw Materials group, the main pressure emerged from raw cotton, 'Industrial Raw the prices of which rose by as much as 42 per cent. Although there was an imbalance between supply and demand in the case of cotton, the extent of the rise does not seem to have been warranted by this imbalance alone. Similarly, prices of oilseeds also recorded a rise of about 31 per cent during this phase

# Group wise Trends: 1975-76

108. A more detailed analysis of the price trends during 1975-76 as a whole may now be attempted. The decline in prices of 3.0 per cent during 1975-76 (July-June) was brought about by the following groups: 'Food Articles' (10.2 per cent), 'Chemicals' (10.4 per cent) and 'Machinery and Transport Equipment' (1.6 per cent); together these groups account for about 50 per cent of the total weightage in the general index. In contrast, the groups 'Lautor and Tobacco' (1.7 per cent), 'Industrial Raw Materials' (5.6 per cent) and 'Manufactures' (3.1 per cent) firmed up, the rise in the group 'Fuel, Power, Light and Lubricants' was substantial at 13.1 per cent (Table 17).

109. The index for the group 'Food Articles' declined to 331.0 at end-June 1976, from a peak of 368.7 at end-June 1975, or by 10.2 per cent as against increases of 3.2 per cent and 26.0 per cent recorded in 1974-75 and 1973-74, respectively. The decline in the prices of foodgrains was 24.0 per cent, as against increases of 4.6 per cent and 36.6 per cent in 1974-75 and 1973-74. Interestingly enough, among 'Foodgrains' both cereals and pulses recorded sharp declines of 22.1 per cent and 31.1 per cent, respectively, as against an increase of 6.9 per cent in the case of cercals and a fall of 3.4 per cent in the case of pulses during the previous year. Again, among cereals, all cereals, major as well as coarse, witnessed declines—a unique phenomenon noticed during the year. Rice and wheat prices declined substantially by 23.6 per cent and 9.4 per cent, respectively. The prices of both lower and bajra dipped heavily by 12.9 per cent and 44.7 per cent, respectively. Sizeable imports and the decision to build up a substantial buffer stock of foodgrains had a favourable impact on foodgrains prices. Edible oils prices witnessed a sharper decline of 24.0 per cent, as compared to a decline of 15.9 per cent last year. Among edible oils, groundnut oil prices declined steeply by 32.7 per cent followed by vanaspati (31.8 per cent).

110. The index for the group 'Industrial Raw Materials' recorded an increase of 5.6 per cent in contrast to the decline of 16.5 per cent in 1974-75. It may be seen from Table 17 that the prices of this group however declined by 14.5 per cent till mid-March 1976 (July-March) : the decline was mainly accounted for by 'oilseeds' (30.3 per cent). This declining trend in raw material prices was reversed subsequently and an uptrend in prices set in thereafter. The index of

FABLE 17:--TRENDS IN INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES (Base: 1961-62=100)

(Percentage Variations)

							(Percentage	e Variations)
Group	o, Sub-Group/Commodity	Weights*	End-June 1975 over End-June 1974	End-June 1976 over End-June 1975	Match 22, 1975 over Fnd-June 1974	End-June 1975 over March 22, 1975	March 20, 1976 over End-June 1975	End-June 1976 over March 20, 1976
		2	3	4	5	6	7	8
All Com	modities	1000	j-0.7	——————————————————————————————————————		—— +0.9	<u>9.2</u>	-  6.9
	Food Articles	413	$+\tilde{3}.2$	-10.2	10 2	+3 0	—17.6	+8.9
	I oodgrams	(35.8)	<b>⊹4.6</b>	-24.0	+5.1	-0.5	-24.7	+0.9
	(a) Cereals	(29.3)	+6.9	22.1	+7.2	-0.3	- 25.4	+4.4
	(1) Rice	(16-2)	10.4	23.6	+1.0	-193	27.8	<b>45.8</b>
	(II) Wheat	(7.8)	-2.3	-9.4	-  11.9	12.7	- 5 7	-3.9
	(III) Jowar	(2.2)	-1.9	12 9	+2.9	-1.0	28 3	-  21.5
	(Iv) Bajra	(1.1)	-, 33.6	~- 44 7	-+46.6	-8.9	<b>—53,3</b>	-] 18.5
	(b) Pulses	(6.5)	-3.4	—-31 J	-2.1	-1.3	21.7	12.0
	Fruits and Vegetables .	(5.7)	13.0	+11.3	18,9	- <del>-</del> 7 3	14.6	+30.4
	Milk and Milk Products .	(14.7)	-167	-6.4	1-3.0	+3.6	10.7	14.7
	Edible Oils	(13.0)	15 9	-24.0	-12.7	-3 6	-33 7	+16.1
	Fish, Eggs and Meat	(4.9)	<b>⊢5.0</b>	- <u>+21-6</u>	-1.2	+6.3	- -12 3	+8.3
	Sugar and Allied Products .	(15.7)	4-16.3	-( 4.8	+4.4	. 411.4	14.4	+22.5
	Sugar	(8.9)	-6.2	+5 2	4-10.3	3 7	$+1 \ 2$	+3.9
il.	Liquor and Tobacco	25	1-4.2	+1 7	11.4	2.8	- <b>0.8</b>	+0.9
111.	Fuel, Power, Light and Lubricants	61	+-5.7	13 1	, 5 1	-}- <b>0.6</b>	+12.4	-[-0.6
IV.	Industrial Raw Materials	121	<b>—16.5</b>	+5 6	- 14.0	3.9	14.5	- <b>-23</b> 6
	Fibres	(34.0)	-13.6	- <b>⊦29</b> .5	-12 5	1 2	+3.7	+24.9
	(i) Cotton raw	(18.5)	24 8	<b>-48.2</b>	22.3	3 3	-, 4.3	+42.0
	(fi) Jute raw	(9.6)	<b>⊰ 26.</b> 7	<b>⊢7</b> 5	- <u>-</u> -16.6	-⊢8.7	+15.6	—-7. <b>1</b>
	Oilsecds , ,	(43.3)	20 3	8.3	<b>—15.1</b>	-6 1	<b>— 30 3</b>	4 30.9
	(1) Groundnuts	(20.8)	_S 8	21 3	-6.4	2 4	-42.5	+36.7
X'	Chemicals	7				0.2		<b>—5</b> 6
	Machinery and Transport Equipme					-11		-1.4
	Manufactures	294				-0.3	+0.9	<b>+22</b>
	(a) Intermediate Products .	(19.5)	•	÷9 6		0.7	+4.0	+5 4
	(b) Finished Products	(80.5)	÷5.1	- -1.2		0.6	_0.1	1.2
	Textiles	(38,6)				· -1.3	-0.6	1.6
								-  1 8
	(i) Cotton Manufactures .	(26.8)	•		·	+0.6		
	(ii) Jule Manufactures	(8.1)		-		<del>-7.0</del>	$\frac{-2.3}{+2.4}$	-13.3 +0.3
	Metal Products	(13.0) (9.2)	·	$+2 8 \\ +3 7$	∤-13,1 1-12,6	+0.1 -1.3	-	+0.5 $+5.3$
		(9.2) $(1.8)$		+3 / - ·21 0		-1.3 + 0.4		•
	Fertilisers	(1.0)	F.J. 1	0 انت -	-o	+0.4		

^{* 1} iguies in brackets refer to the percentage distribution of the weightage assigned to the respective main groups Source: Office of the Economic Adviser, Ministry of Industrial Development, Government of India.

'industrial Raw Materials' rose by 23.6 per cent between March 20 and end-June 1976. Such rise was conspicuous in the case of raw cotton (by 42 per cent) and oilseeds' (by 31 p. cent). The unprecedented increase in the prices of raw cotton was attributed to the persistent mill demand, especially for the new crop and the absence of selling pressure, even at higher prices. Further, the Cotton Advisory Board scaled down in June 1976, the cotton crop estimates by 2.5 lakh bales to 66.5 lakh bales. In respect of 'oilseeds', speculative hoarding as well as restrictions on the inter-State movement of oilseeds, particularly of groundnuts and groundnut oil, imposed by some States were responsible for the rice. Measures have since been taken for bringing down the prices of these commodities. Thus during the entire year 1975-76 (July-June) raw cotton prices went up by 48.2 per cent and those of oilseeds declined only by 8.3 per cent. Raw Jute prices, however showed raise of 7.5 per cent due to lower output of raw jute and mesta.

111. The group 'Chemicals' witnessed a declined of 10.4 per cent in 1975-76 as against rises of 14.9 per cent and 36.9 per cent recorded during the years 1974-75 and 1973-74.

respectively. Prices of fertilisers which were successively reduced by the Government contributed largely for this decline. On the other hand, the hike in the prices announced by the Government in the case of kerosene oil, furnace oil and petroleum, pushed up the index of the group 'Fuel, Power, Light and Lubricants' by 13.1 per cent.

112. The group 'Manufactures' recorded a marginal increase of 3.1 per cent. Both the sub-groups viz., 'Intermediate Products' and 'Finished Products' were responsible for the rise: the former showed a use of 9.6 per cent as against a decline of 12.1 per cent, witnessed last year, while the later rose marginally by 1.2 per cent, as compared with an increase of 5.1 per cent recorded last year. Among 'Finished Products' prices of both cotton and lute manufactures firmed up by 1.4 per cent and 15.3 per cent, respectively.

# Consumer Prices

113 In consonance with the declining trend in wholesale prices, the Consumer Price Index (base 1960 = 100) witnessed a decline. In fact, such a remarkable decline was noticed in

the index for the first time since 1961. The Consumer Price Index for Industrial Workers declined by 10.2 per cent during the year 1975-76¹⁸ as against a rise of 5.5 per cent recorded during the comparable period of last year. The Index for Urban non-Manual Fmployces, however, registered a relatively lower decline of 4.6 per cent,²⁰ in contrast to an increase of 6.1 per cent witnessed during the corresponding period of 1974-75.

# Saving and Investment

# Domestic Saving

114. Although comprehensive data regarding saving and investment in the economy in 1975-76 are not yet available, on the basis of fragmentary data, it is possible to indicate the broad trends. It is necessary to sound a note of caution that the estimates of saving and investment presented here, are tentative and may undergo significant revision when fuller data become available.

115. The data presented in Table 18 show that the ratio of domestic saving to national income rose sharply from 13.1 per cent in 1974-75 to 14.5 per cent in 1975-76. Both the public sector as well as the household sector have contributed to the growth in domestic saving. In an environment of relative price stability, unlike in the previous year, saving in the form of financial assets rose significantly in 1975-76. On the other hand, the share of the private corporate sector in total domestic saving appears to have declined.

#### Aggregate Investment

116. Such a significant rise in domestic saving resulted in raising the overall rate of investment in the economy from 14.8 per cent of net national product in 1974-75, to 16.0 per cent in 1975-76. What is more, the increase in investment came about, notwithstanding a decline in the net inflow of foreign resources, the size of inflow has been estimated to have declined from the record ratio of 1.7 per cent of net national product in 1974-75 to 1.5 per cent in 1975-76. Of course, even at this level the contribution of foreign resources to investment was significant. Domestic saving was thus able not only to make up for the decline in inflow but also to increase the level of overall investment in the economy.

# Market Borrowings.

117. At this stage a word about Governments' market borrowings. The combined net receipts of the Central and State Governments from market borrowing²¹ ammounted to Rs. 728 crores in the financial year 1975-76 as against

TABLE 18 :—ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND INVESTMENT : PER CENT OF NET NATIONAL PRODUCT AT CURRENT PRICES

# (PROVISIONAL)

Financial Year (April-March)

Items	1972– 73	1973- 74	1974- 75	1975– 76
1	2	3	4	5
<ol> <li>Domestic Saving</li> <li>Inflow of Foreign</li> </ol>	13.0	12.8	13.1	14.5
Resources 3. Aggregate Investment	0.8	0.8	1.7	1.5
(Net) (1+2)	13.8	13.6	14.8	16.0

- 19. June, 1976 over July, 1975 index.
- 20. April, 1976 over July, 1975 index.

Note: The ratios for 1972-73 to 1974-75 have been revised partly on account of the revision of CSO's estimates of national income and partly owing to the availability of more recent figures of components of savings and

Rs. 708 crores in the previous year. During 1975-76 the Centre entered the market on two occasions and raised a net amount of Rs. 453 crores as against Rs. 495 crores in 1974-75. While the first floatation was a cash-cum-conversion offer, the second floatation was wholly based on cash subscriptions. In addition to these loan floatations, a sum of Rs. 39 crores was invested in Central Government bonds under the Scheme of Voluntary Disclosure of Income and Wealth, State Governments raised Rs. 274 crores in 1975-76 on a cash basis in two floatations, as against Rs. 213 crores in 1974-75: in the first floatation Rs. 179 crores and in the second, Rs. 95 crores. Out of the total amount of Rs. 274 crores they raised from the market, the States repaid Rs. 100 crores to the Central Government during 1975-76, representing their share of centualised market borrowings raised in 1963-64, and retained the balance of Rs. 174 crores.

# External Sector

118. The performance of the external sector of the Indian economy in 1975-76 shows, in refreshing contrast to the earlier years, distinct signs of strength: this strength is teflected in an unprecedented rise in foreign exchange reserves, notwithstanding a sizeable trade deficit for the second year in succession. Although the inflow of external resources has assisted, the emergence of this strength seems to be primarily attributable to domestic factors. In the absence of detailed balance of payments data for 1975-76 it is difficult to assess, at this stage, whether the trend in the payments position of 1975-76 is in the nature of a once-for-all phenomenon or whether it forms part of a long-run trend. All that one can infer as a board judgement is that the long-term balance of payments prospects have improved.

#### Trade Deficit and Payments Position

119. Taking the short-term trend first both imports and exports in 1975-76 showed much lower rates of growth than in the previous year; exports rose by only 16 per cent in contrast to a growth of as much as 32 per cent in 1974-75. Obviously, the spectacular rise that took place in 1974-75 in export earnings of a number of Indian goods/commodities could not be sustained owing to the declining trend in international prices. Import growth at 11 per cent was sizeably lower than a 53 per cent growth witnessed in 1974-75. The rise in imports was mainly confined to food-grains and was attributable to a rise in both volume and price. On the other hand, import payments on account of several other items including petroleum were much lower, which in part explains the substantially lower growth in imports in 1975-76. The net result was that the size of the trade deficit remained in 1975-76 practically unchanged at Rs. 1155 crores, as compared with the deficit of Rs. 1189 crores during the previous year.

120. Fortunately, notwithstanding the persistence of a sizeable trade deficit, India's foreign exchange reserves recorded, over the financial year 1975-76, a phenomenal rise of Rs 881 crores²². In the absence of detailed balance of payments data, it is difficult to provide a precise explanation of the rise in reserves. However, broad indicators suggest that the rise was attributable primarily to two factors, namely, larger inflow of aid and increase in invisible earnings. Although fuller data regarding inflow of aid are not yet available, it seems that goes aid disbursements in 1975-76 were higher by about Rs. 400 crores, than the level in 1974-75. On the other hand, transactions with the IMF resulted in a much lower level or inflow in 1975-76. While India made a drawing in August 1975 of Rs, 207 crores from the IMF Oil Facility (1975), following the improvement in the reserve position, India repurchased the drawing from the Compensatory Financing Facility, made in February 1974, of Rs, 65 crores. Thus the net inflow in 1975-76 from transactions with the IMF was of the order of Rs. 142 crores, whereas in 1974-75 such net inflow aggregated as much as Rs. 485 crores. In a sense therefore the increase in gross aid disbursements in 1975-76 was, to a large extent, offset by lower drawals from the IMF. Viewed from this perspective, the improvement in the reserves position could be ascribed largely to domestic factors.

- 21. These figures are drawn from Reserve Bank of India records.
- 22 The increase is with reference to the foreign exchange reserves, excluding Gold and SDRs at end March, levels.

#### Improvement in Invisibles

121. Although data regarding invisibles account are yet to be compiled, the broad indications are clear : there was a jump in net sales of foreign exchange to the Roserve Bank by authorised dealers. The size of such sales which represent the net surplus of foreign exchange transactions put through the authorised dealers was in 1975-76 over three times that in 1974-75. In the absence of detailed accounts, it is difficult to state if the rise in invisibles is a transient situation or likely to be of a permanent nature. It is only reasonable to infer that following the strong Governmental action against smugglers and foreign exchange offenders, there has taken place a plugging of foreign exchange leakages, the impact of which has begun to reflect itself. Moreover, the Government has also initiated a number of measures towards encouraging remittances of funds by non-resident Indians and persons of Indian origin abroad and also attracting non-resident Indians to invest in equity capital in certain specified industries. Taken together, these measures seems to have had a salutary impact on India's invisibles account.

122. Turning to the long-term prospect, the strengthening of the payments position in 1975-76 appears to be symptomatic of a significant change which might take place in India's balance of payments. Admittedly, these aspects need to be studied in depth to arrive at definitive conclusions but at least some indicators of such change may be mentioned Higher export capability is being built up in the economy, at the same time as import substitution in the sphere of oil, or more generally energy, is taking place at a faster pace. Similarly, the need for imports of foodgrains and fertilisers might tend to diminish. Further, the growth in invisible earnings experienced in 1975-76 may hopefully continue in the coming years. If these indicators are any guide, in the long run, one can hope for an improvement in India's balance of payments position.

A detailed discussion on the trends in trade follows:

#### Trade Deficit

123. The trade deficit during the fiscal year 1975-76 worked out to Rs. 1155 crores, a level which was only marginally lower than the deficit of Rs. 1189 crores, in the preceding

year. There was a marked slackening in export growth in the wake of the reversal of the international commodity boom witnessed in 1973 and 1974 and the persistence of recessionary trends in most developed countries which are major buyers of primary and processed goods. This was fully reflected in a much smaller magnitude of rise in export earnings of Rs. 533 crores as compared with a rise of Rs. 807 crores in the preceding year: the rise in export earnings was 16 per cent as compared with 32 per cent in 1974-75. In the case of imports, lower prices of raw materials and metals, not doubt, sizeably reduced the import bill; but this was more than offset by a substantial increase in import prices of foodgrains and fertilisers. The overall rise in imports at Rs. 498 crores was less than one-third of that in the preceding year (viz., Rs. 1565 crores). The rate of growth in imports in 1975-76 was thus only 11 per cent as compared with 53 per cent and 58 per cent rises in 1974-75 and 1973-74, respectively. The persistence of a higher rate of increase in import prices in relation to export prices, resulted in a further deterioration of India's terms of trade: reported data for the period April 1975 to February 1976 showed that the terms of trade worsened by over 15 per cent.

#### **Exports**

124, Exports during the financial year 1975-76 rose further to a record level of Rs. 3863 crores registering a rise of Rs. 533 crores over the preceding year as compared to a rise of Rs. 807 crores witnessed in 1974-75. Commodity-wise details however, are available only for the first nine months of 1975-76 (April-December) during which period exports aggregated Rs. 2690 crores as compared with Rs. 2355 crores in the corresponding period of 1974-75 (Table 19) The changes in the commodity composition of exports reflected fully the impact of international prices—particularly of agricultural produce and processed goods as well as manufactured articles. This was true of major export items such as jute goods, cotton textiles, vegetable oils and oilcakes, cashew kernel and spices. In the case of sugar and silver, however, although precies were relatively lower, the quantity exported was higher with the result, export earnings from these items were much larger than in the corresponding period in 1974-75.

TABLE 19:—INDIA'S PRINCIPAL EXPORTS

(Amounts in Rupees Crores)

												•	•
Commodities		-				<u>-</u> ,			1974-75	APRIL-DECEMBER		Incresase (+)/of Decrease (-) (4) over (3)	
										197475	1975 – 76	Actual	Per cent
1				-					2	3	4	5	6
I. Food and Live Animals .				·					1013	669	842	+.173	-  <b>26</b>
<ol> <li>Fish and fish preparations</li> </ol>									65	47	93	+46	+98
2. Cashew kornels									118	93	81	-12	-13
3. Coffee									51	44	58	+14	+32
4. Tea (Black)				Ċ				-	221	157	178	-1-21	+13
5. Spices								Ċ	61	38	38	-	,
6. Oileakes				-					96	66	55	-11	-17
7. Sugar	•				ì				339	175	297	+122	+70
II. Beverages and Tobacco Tobacco unmanufactured									<b>82</b> 80	<b>66</b> 65	<b>88</b> 84	+ <b>22</b> +19	$^{+33}_{+29}$
li. Crude Materials, Inedible except	Fuels								431	290	330	+40	+14
									17	14	19	5	+36
2. Mica									18	14	10	4	-29
3. Iron ore (including concent	trates)							_	160	93	139	146	+49
<ol> <li>Crude, animal and vegetab</li> </ol>			n.e.s.						117	88	62	-26	-30
V. Mineral Fuels, Lubricants and R	elated	Mate	rials						20	13	25	12	+92
V. Animal and Vegetable Oils and l Vegetable oils	Fats		:			:	:		<b>34</b> 34	<b>33</b> 33	<b>31</b> 30	- 2 - 3	- 6 - 9
T. Chemicals									104	76	69	<b>— 7</b>	_ 9

				_								
1								2	3	4	5	6
VII. Manufactured Goods	,	,						1158	896	908		- 1
<ol> <li>Leather and Leather manufacture</li> </ol>	res							145	111	133	- <del>-22</del>	<b>∃</b> 20
2. Cotton textiles@								233	187	138	-49	-26
<ol> <li>Jute manufactures@</li> </ol>								296	257	188	-69	-27
<ol> <li>Pearls and precious and semi-pre</li> </ol>	ecious	ston	es, un	work	ed or	worke	ed .	95	66	79	<b>-</b> 13	+20
5. Iron and Steel								86	58	69	+11	+19
<ol><li>Silver (bullion bar) , .</li></ol>								78	52	134	+82	+158
VIII. Machinery and Transport Equipment								212	133	189	+56	<b>→ 42</b>
1. Machinery other than electric	•							91	59	82	+23	- -39
2. Electrical machinery, apparatus	and ar	plia	nces					56	39	47	+ 8	+21
<ol><li>Transport equipment</li></ol>								65	35	60	+25	+71
IX. Miscellaneous Manufactured Articles								240	173	202	+29	+17
1. Clothing								136	97	124	+27	¹ 28
2. Footwear	•							20	14	14	·	_
Total Exports (Including others)		, 						3304*	2355	2690	+335	-14

[@]Includes yarn and thread,

125. Direction-wise, the data available for the first nine months of the year (April-December 1975) showed that, of the rise in total exports during this period of Rs. 335 crores, exports to the Economic and Social Commission for Asia and pacific (ESCAP) countries excluding Japan rose by Rs. 109 crores: within this group, the rise in exports to Iran was of the order of nearly Rs. 73 crores. Exports to Japan also rose by nearly Rs. 82 crores. The share of all ESCAP countries rose from 25 per cent to 29 per cent of the total. On the other hand, the shares of ECM countries, North America (particularly the U.S.A.) and the Fast European countries were marginally lower than is the corresponding period in 1974.

# Imports

126. Imports during the first nine months (Aprial-December) of fiscal year 1975-76 for which commodity details are available, amounted to Rs. 3900 crores recording an increase of Rs. 810 crores or 26 per cent over the corresponding period of the previous year (Table 20). The two major items which contributed to the increase were foodgrains (wheat) and fertilisers. Besides, imports of machinery and transport equipment as well as petroleum crude were noticeably higher. On the other hand, the value of imports of steel and non-ferrous metals was lower, on account of reduction in the volume of imports in the case of steel and on account of lower prices in case of non-ferrous metals.

TABLE 20 :- INDIA'S PRINCIPAL IMPORTS

(Amounts in Rupees Crores)

Commodities	1974–75			Increase(-  )/l of (4) ove	
		1974–75	1975–76	Actual	Per cent
1	2	3	4	5	6
I. Food and Live Animals	 855	542	1017	+475	-  88
1. Wheat	698	415	887	+472	+114
2. Cashewnuts	37	33	30	3	_ 9
II. Beverages and Tobacco	1	1	1	_	
III. Crude Materials, Inedible except Fucis	219	155	164	-1 9	+ 6
Colton raw, other than linters	27	19	25	+ 0	+32
1V. Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials	1157	881	912	<b>⊣-31</b>	+ 4
1. Petroleum, crude and partly refined	955	727	772	+45	6
2. Petroleum products	202	154	139	15	-10
V. Animal and Vegetable Olis and Fats	35	31	16	- 15	-48
VI. Chemicals	712	402	627	+225	+56
1. Chemical elements and compounds	179	120	135	15	+13
2. Medicinal and pharmaceutical products	34	24	27	j- 3	<b>-</b> 13
3. Fertiliser manufactures	425	207	406	1 199	-96
VII. Manufactured Goods	763	549	464	- 85	-15
1. Iron and Steel	417	297	236	61	21
2. Non-ferrous metals	178	135	72	63	-47
VIII. Machinery and Transport Equipment	670	495	649	- -154	+31
1. Machinery other than electrical	397	301	406	105	+35
<ol><li>Electrical machinery, apparatus and appliances</li></ol>	150	101	146	<b>+45</b>	-⊦ 45
3. Transport equipment	123	93	98	+ 5	-  5
IX. Miscellaneous Manufactured Articles	46	31	38	+ 7	- - <b>23</b>
Total Imports	4468*	3090	3900	+810	+26

^{*}Subsequently revised to Rs. 4520 crores for which commodity-wise details are not yet available.

Source: D.G.C.I. & S.

^{*}Subsequently revised to Rs. 3331 crores for which commodity-wise details are not yet available.

*Source: D.G.C.I. & S.

127. Imports from the USA and LCM countries rose considerably during the period, while those from the USSR and from were lower than in the same period in 1974

#### Trade Policy

128. The need for stepping up export earnings was brought in sharp relief by the persistence of a large trade deficit for the second year in succession. The re-opening of the Suez Can il might facilitate faster realisation of export proceeds as also some saving in freigh cost. Further, the country's trade policy has been greared towards intensifying export efforts both in terms of expansion and diversification. Recently a number of measures have been taken to provide incentives to the private sector with a view to achieving these objectives. These measures, inter alia include provision of incentives for stepping up production for exports, incentives for promotion of exports of 'growth' items like engineering goods, widening of the scope of the scheme of case compensatory support, grant of advances by scheduled banks to exporters against duty drawback entitlements, relaxation in the terms of export credit, streamlining procedures of export of capital and engineering goods on deferred payment terms and of release of foreign exchange to consultancy engineering services and to eligible export houses.²⁸

#### Outlook for Growth s 1976-77

129. On the whole, the picture that emerges from this brief assessment of the performance of the economy in 1975-76 is that the economy has resumed its normal growth in an environment of reasonable price stability. The validity of this theme would be established if growth of a similar order is sustained in the coming years. It is against this background that the outlook for growth in 1976-77 has to be sketched. In effect this exercise is tantamount to indicating broadly the opportunities open to the economy in the next year.

130. The agricultural sector, which in a way sets the tone for overall growth, continues to be vulnerable to weather over a wide area and it does not lend itself to a precise assessment of growth prospects. One thing seems obvious that a growth rate of the agricultural sector of around 8 per cent in 1975-76 attributable to uniformly favourable wheather conditions. Accordingly even though the production potential in the sector is being raised to new heights, it would not be unrealistic to expect growth of a similar order in the coming year. However, with the likelihood of weather conditions being favourable it seems reasonable to expect a relatively moderate growth in agricultural production; the factors taken into account in this context are, among others, the general improvement in the supply of inputs like fertilisers, power and quality seeds, the emphasis on irrigation in the 20-point Fconomic programme and an anticipated rise in private investment in view of the rise in agricultural incomes in 1975-76.

131. A major preoccuption of economic policy in the coming year would be the question of revival of industrial growth. Three planks of policy have been visualised for attaining this objective namely, a sizeable step-up in investment, correction of recessionary trends in sub-sectors affected by slackness of demand, and promoting fuller capacity utilisation. Admittedly, the impact of all these measures may not be reflected immediately in the rate of industrial growth in 1976-77 itself, but what is important is to ensure greater expansion of the potential for industrial growth over a period.

132. The present state of the economy appears to provide suitable conditions for the absorption of higher doses of investment, without impairing price stability. The sizeable stocks of foodgrains already built-up and the existing potential for increasing the production of textiles, seem to guarantee adequate availability of wage-goods. The climate for ensuring larger investment in both the public and private sectors has already been created with the Central Government taking the lead to step-up the Plan Outlay in 1976-77 by as much as 31.4 per cent. The ability of the public sector to step up investment has greatly improved both because of the tightening of the tax administration which might boost tax receipts and also because

of the considerable scope for drawing on foreign exchange reserves more freely than in the past. In addition, the Government has taken recently a number of measures to boost private sector investment which include the reform of licensing, initially easing of restrictions on the declaration of dividends and finally removing the restriction altogether and on the issue of bonus shares, the liberalisation of import policy and provision of tax incentives for increasing production in selected industries. Further, the Central budget for 1976-77 has laid greater emphasis on rationalising the direct tax structure and increasing incentives for savings and investment. Although, there is a time-lag between stimulation by the Government and response to it by the private sector, it is teasonable to expect that private sector investment will tend to pick-up in 1976-77, even as public investment is stepped-up.

133. Although the capital market continues to remain sluggish, it is showing signs of revival: for instance, new capital issues by non-Government public limited companies in 1975-76 (April-March) at Rs. 93 crores were substantially larger than the level of Rs. 52 crores in 1974-75. Further, the size of the support from term-lending institutions was also larger: both sanctions and disbursements of IDBI, ICICI and IRCI, which generally account for about two-thirds of the total financial assistance by term-lending institutions, were higher in 1975-76 by 33 per cent and 24 per cent respectively, as compared with the levels in 1974-75.

134. Reverting to the last two planks of policy, some industries affected by slackness of domestic demand might stage a recovery, the textile industry being a case in point. Thanks to a sizeable increase in agricultural incomes in 1975-76, the rural demand for textiles may rise. Similarly, the reduction in rates of tax on income and wealth in the 1976-77 budget and the adjustments made recently in exciso duties might perhaps resuscitate the demand for consumer durables. The appointment recently, by the Government of India, of a Committee to conduct a comprehensive examination of the existing structure of indirect taxes is a further move towards rationalisation of indirect taxes, particularly excise duties. Lastly, since there is expected to be a recovery, at any rate moderate from the world recession, export demand for Indian industrial products might tend to pick-up. Recently, an attempt has also been made to strengthen the existing framework of export incentives: measures taken in this context include additional cash incentives to many engineering goods and to some traditional products, increased import entitlements, reduction in export duty, faster payment of cash assistance and duty drawback.

135. The picture of industrial growth prospects for 1976-77 is thus clear. On the one hand it may not be possible to repeat the unusually high rates of increase in production achieved in 1975-76 by some 'core' sector industries: on the other, the declining trend in production witnessed by some other industries might be reversed. Already there are indications that the pace of industrial growth has picked up: for instance, the index of industrial production during the first four months of 1976 was higher by as much as 11.5 per cent, than the corresponding figure of 1975. If this is any indication of the overall trend one could expect to achieve a growth rate of 6 to 7 per cent in 1976.

136. At this stage, it may be appropriate to draw attention to the potential demand pressures which are likely to emerge in 1976-77 and their implications for monetary and credit policies. Of course, the objective of demand management continues to dominate both fiscal and monetary policies. This is reflected in the fact that the restrictionary credit policies, including interest rate policies, initiated in 1974-75 are being continued. Similarly, in the fiscal sphere the existing scheme of impounding of additional incomes through compulsory deposits both in relation to income-tax payers in higher brackets and to additional D.A. have been extended for another year. Further, it has been indicated that the amounts deposited after fully 1976 would be credited alongwith interest of 12.5 per cent to the Provident Fund of the subscribers rather than paid in cash, after the stipulated period. Notwithstanding the continuation of these demand management measures, there are three clearly identifiable sources which may generate demand pressures: these are, investment, de-impounding of deposits and the banking system. If investment, both public and private, records a jump in 1976-77 as anticipated, the supply-demand balance in terms of real resuorces would be

^{23.} Details of some of these export promotion measures are indicated in Part  $\Pi$  of this Report.

under pressure. The second factor arises from the fact that the Centre is expected to borrow from the RBI, besides the projected budget deficit of Rs. 320 crores, a sum of Rs. 480 crores against the impounded deposits referred to above. At the same time, cash repayments of deposits impounded in 1974-75 will commence from July 1976 and the total amount of such repayments in 1976-77 would add up to the tune of Rs. 270 crores. This process of repayment would add to the expenditure stream. Thirdly, the resources position of the banking system, which is at present comfortable, may improve further with the acceleration of deposit growth. On the other side, given the rise in investment, there may take place a rise in the demand for credit.

137. No doubt the present supply-demand balance in respect of basic commodities like foodgrains is comfortable in the sense of being able to tide over the contingency of a bad agricultural year. However, the vulnerability of price stability should not be overlooked and there is, need for continuous vigilance. Moreover, there is also a need for establishing a system which would, on the one hand, detect and monitor signs of emergence of imbalances of supply and demand in isolated pockets/sectors/commodities and on the other, ensure effective management for correcting such imbalances without delay. In this context, administrative skills and capability for the purpose of maintaining adequate stocks of sensitive commodities from domestic procurement and/or imports and eliminating imperfections in the distribution mechanism have to be further developed. Similarly, while there would be certainly room for flexibility, the basic monetary and fiscal discipline, which has been in operation since the last two years needs to be effectively maintained.

138. Finally, from a longer term point of view, what is important is that the rates of saving and investment achieved in 1975-76, need to be at least maintained, if not improved upon. The recent economic policies of the Government have been reoriented in such a manner that sustaining higher rates of saving and investment becomes possible. The emergency and the 20-point economic Programme have created an environment in which the public sector's performance, on the whole, has risen to greater levels of efficiency. A wide range of incentives, referred to in the Report have also been provided to the private sector to enable it to raise investment and to improve productivity. The response of the private sector to these measures may manifest itself after a time-lag. Given the concerted efforts by both the public and private sectors, it should be possible to sustain growth rates of national income stipulated in the Fifth Plan in an environment of price stability.

139. Before concluding it must be recognised that the economy on the eve of 1976-77 has inherited a degree of capability for attaining and sustaining higher rates of growth. This capability stems from inter alia, high rates of saving and investment, the availability of foodgrains buffer, as well as from the cushion implicit in the level of foreign exchange reserves. The experience gained in the management of the economy since mid-1975, both in terms of administrative skills and in terms of instruments of management, should stand in good stead for moving the economy to higher levels of capital accumulation and growh.

# II. PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING

140. The progressive trends in commercial banking—in respect of branch expansion, deposit mobilisation and extension of credit to sectors of social and economic priority—were sustained during 1975-76. In fact, the pace of deposit accretion, which had slowed down in the previous year, picked up again to reach a rate of 20.0 per cent which was 3.4 percentage points higher than in 1974-75. The composition of the deposit growth was more or less similar to the previous year, with around two-thirds of the incremental deposits being accounted for by time deposits. Credit expansion during 1975-76 at 28.0 per cent was double the rate of expansion in 1974-75. More than half of the total increase in credit was, however, on account of public sector food procurement and distribution which followed from the record harvest of the year, as also the policy decision to transfer from the budget to the commercial banking system the task of financing the maIntenance of food stocks. Even so, the rate of expansion in non-food credit was also higher than in the previous year (13.7 per cent as against 11.2 per cent). The year allow

witnessed further rise in commercial banks' profits. The other important developments during the year included, the setting up of 19 Regional Rural Banks in the country and the implementation of the recommendations of the Study Group for Follow-up of Bank Credit. Airangements were also initiated to gear banks to extend appropriate support to the implementation of the 20-point Economic Programme. These developments may now be taken up for detailed discussion.

# Branch Expansion Programme

141. The policy of planned and systematic branch expansion by commercial banks was intensified during the period under review. In order to ensure continuity in the matter of branch expansion, all scheduled commercial banks and three non-scheduled banks were advised in September 1975 to submit their perspective plans for branch expansion for the next three years viz.. 1976 to 1978. The continuing need to minimise regional disparities in the provision of commercial banking facilities was kept in view and banks were asked to include as many unbanked underbanked centres as possible in their perspective plans and pay particular attention to the Eastern and North Fastern Regions as also to districts where the population per bank office was 75,000 and above.

142. In response to this policy, branch expansion by commercial banks witnessed further intensification during the period under review. During the calendar year 1975, commercial banks opened 2,329 offices, as compared to 1,693 in the previous year. Following this, the national average population per bank office, which was 30,000 at the end of December 1974, declined to 27,000 at the end of December 1975, and further to 26,000 at the end of June 1976. In 6 out of the 30 States|Union Territories, the population per bank office, however, continued to be above 50,000 (1971 census) and in the case of Mizoram it exceeded 1 lukh.

143. Taking the year 1975-76 (July-June), as a whole, commercial banks opened 2,554 offices as against 1,803 offices opened in the previous year (July-June). Of the new offices opened during the year, 556 were opened by the State Bank of India and its subsidiaries, 1,156 by the nationalised banks, 730 by private sector Indian banks and 112 by Regional Rural Banks.

# Unbanked Centres

144. The expansion achieved during the year also marked further progress in the geographic spread of banking. Out of the 2,554 offices opened during the year under review, 859 were opened at the hitherto unbanked centres (Table 21). Assessing the progress in this regard, it may be noted that of the 13,035 offices opened since nationalisation, i.e., from July 19, 1969 to the end of June 1976, nearly half (6,061 or 46.5 per cent) were in unbanked centres. The under-banked States of Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Maghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura, Uttar Pradesh, and West Bengal accounted for 33.7 per cent of these new offices (Table 22).

# Rural Branch Expansion

145. Data regarding the spread of commercial bank offices according to population groups are set out in Table 23. It will be observed that the proportion of bank offices in rural areas to total, which was 36.2 per cent at the end of June 1973, 36.4 per cent at the end of June 1974 and 36.3 per cent at the end of June 1975, slightly declined to 36.2 per cent at the end of June 1976. This decline is attributable mainly to the fact that a large number of rural centres with teasonable banking potential were already covered by the banks' branches. However, the banks have been asked to include in their plans for future bank expansion, as many rural centres as possible, particularly unbanked community development blocks.

# Offices Abroad

146. The question of opening offices of the Indian banks in foreign countries in a planned and co-ordinated manner has been engaging the attention of the Government and the Reserve Bank for same time. The carning of foreign exchange, furtherance of India's trade with other countries and and tanks tance to Indian entrepreneurs in the setting up of joint ventures abroad, are some of the main considerations taken into account in framing the branch expansion programme of Indian banks abroad. During the year, priority continued to be

assigned to the West Asian region and international financial centres.

147. The number of Indian banks' offices abroad²⁴ (excluding Pakistan and Bangladesh) increased from 54 at the end of 1973 to 62 at the end of 1974 and further to 75 at the end of 1975. Out of the 13 offices opened during 1975, 5 were in the U. k., 4 in Hong Kong 2 in Fiji Islands and one each in Bahamas and Dubai. Among the 8 Indian banks having their offices abroad, Bank of Baroda alone accounted for

24F voluding Sikkim, which forms a part of India.

34 offices, followed by Bank of India (14 offices). Countrywise, the largest concentration of Indian banks' offices was in the U.K. (20), followed by Fiji Islands (10), Kenya and Hong Kong (9 each), Singapore (6) and Mauritius (5), During January-May 1976, six more offices were opened abroad, one each in the U.K., U.S.A., Hong Kong, Mauritius, UAE and Oman. Besides these offices, the State Bank of India had one office in Bangladesh and the foreign subsidiaries of Bank of India and Bank of Baroda had a total of 5 offices in Nigeria and Uganda.

TABLE 21 :-- NEW OFFICES OPENED BY COMMERCIAL BANKS DURING

1974-75 AND 1975-76

Paul Creus	New (	Offices open	ed by Comm	ercial Ban	ks		Bank	offices as or	n
Bank Group		1974–75			1975–76				
	July- Dec. 1974	Jan June 1975	July- June 1974–75	July- Dec. 1975	Jan June 1976	July- June 1975–76	30th June 1975	31st Dec. 1975	30th June 1976
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. State Bank of India	311 (128)	93 (49)	404 (177)	326 (169)	121 (56)	447 (225)	3475	3801	3922
2. Subsidiaries of State Bank of India	58 (21)	30 (6)	88 (27)	63 (15)	46 (11)	109 (26)	1739	1802	1848
3. 14 Nationalised Banks	607 (187)	244 (55)	851 (242)	859 (257)	297 (92)	1156 (349)	9863	10718	11010
4. Regional Rural Banks	• • •	·	••	9 (8)	103 (71)	112 (79)	• •	9	112
5. Other Scheduled Banks .	264 (55)	180 (33)	444 (88)	504 (127)	206 (45)	710 (172)	3385	3841	4047
6. Foreign Banks	1 ()	( <del></del> )	1 (—)	( <del>-</del> )	( <del></del> )	(—)	131	130	130
7. All Scheduled Commercial Banks	1241 (391)	547 (143)	1788 (534)	1761 (576)	773 (275)	2534 (851)	18593	20301	21069
8. Non-Scheduled Commercial Banks	8 (6)	7 (7)	[5 (13)	14 (6)	6 (2)	20 (8)	137	145	151
9. All Commercial Banks	(3) (397)	554 (150)	1803 (547)	1775 (582)	779 (277)	2554 (859)	18730	20446	21220

Note: - Figures in brackets relate to unbanked centres.

TABLE 22 :-- STATE-WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THE END OF JUNE 1974, JUNE 1975 DECEMBER 1975

AND JUNE 1976

State/Union Territory							during which of 1974–75 un-	Opened during 197576	which un-	Population per bank office (in thousands) as at the end of						
-				June 1974	June 1975	Decem- ber 1975	- June 1976	(July 1974 to June 1975)	centres	(July 1975 to June 1976)	banked centres	June 1975	December 1975	June 1976		
		1	 			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Andhra P	radesi	h .			•	1234	1373	1494	1550	142	42	177	60	32	29	28
Assam			•			184	214	253	263	28	10	57	17	68	58	56
Bihar			,	•	٠	672	796	890	953	126	66	157	72	71	63	59
Gujarat						1436	1552	1666	1711	117	18	161	45	17	16	16
Haryana						390	438	491	530	48	21	92	42	23	20	19

(contd.)

TABLE 22 :--- STATE-WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THL LND OF JUNE 1974, JUNF 1975, DI CLMBER 1975

AND JUNF 1976 -- (Concld)

State/Union Territory	اه د N	offices a	s at the e	nd of	Opened Of during which 1974-75 un-		Opened Of during which 1975–76 un-		Population per bank office (in thousands) as at the end of		
	June 1974	June 1975	Decem- bor 1975	June 1976	(July 1974 to June 1975)	banked centres	(July 1975 to lune (1976)	banked centres	June 1975	Decem- bet 1975	June 1976
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Himachal Pradesh	. 159	181	198	209	22	9	28	17	19	17	16
Jammu & Kashmir	164	181	227	232	26	7	43	20	24	20	20
K arnataka	1621	1750	1857	1905	130	26	183	59	17	16	15
Kerala .	. 1163	1296	1435	1473	133	46	177	71	16	15	14
Madhya Pradesh	829	914	999	1050	95	27	137	37	46	42	40
Maharashtra	2005	2188	2335	2381	183	44	210	52	23	22	21
Manipur .	9	10	11	13	1		3	1	107	98	83
Meghalaya .	18	21	26	30	3	2	9	4	48	36	34
Nagaland	7	8	13	14	1	1	6	2	65	40	37
Orissa	255	301	356	382	46	26	81	47	74	62	57
Punjab .	869	961	1062	1107	93	34	146	51	14	13	12
Rajasthan	743	792	852	877	49	14	87	23	33	30	29
Tamil Nadu	1784	1935	2058	2093	152	35	161	33	21	20	20
Tripura	18	20	22	24	2	l	4	2	78	71	65
Uttar Pradesh	1673	1896	2095	2218	223	94	322	124	47	42	40
West Bengal	987	1090	1241	1317	103	20	227	66	41	36	34
Andaman & Nicobar Island	. 5	5	5	6			1	1	23	23	19
Arunachal Pradesh	6	7	9	10	1	1	3	3	67	52	47
Chandigarh	. 44	53	57	57	9		4	1	5	5	5
Dadia and Nagar Haveli	4	4	4	4					19	19	19
Delhi	502	563	604	619	61		58	2	7	7	6
Goa, Daman and Diu	133	140	149	153	7	2	14	5	6	6	6
Lakshadweep	4	4	4	4					8	8	8
Mizoram	1	1	1	2			1	1	332	332	166
Pondicherry	26	28	30	33	2	1	5	1	16	16	14
Total .	16,936	18,730	20,446	21,220	1,803	547	2,554	859	29	27	26

TABLE 23 —CENTRE-WISE DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANK OFFICES

					Number	of offices	as at the	end of				
Centre	June 1969	% to Total	June* 1972	°, to Fotal	June 1973	% to Total	June 1974	% to Total	June 1975	% to Total	June 1976	% to Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Rural	. 1832	22.4	4814	35 3	5561	36 2	6165	36 4	6806	36 3	7687	36 2
2 Semi-Urban	3322	40 1	4385	32 2	4723	30 8	5089	30 O	5569	<b>29</b> 7	6387	30.1
3 Urban	1447	17 <b>5</b>	2323	17 l	2573	16 7	2899	17 1	3267	17 5	3739	17.6
4. Mctropolitan/Port												
Towns	1661	20 0	2100	15 4	2505	16 3	2783	16 5	3088	16 5	3407	16 1
Total .	. 8262	100 0	13622	100.0	15362	100 0	16936	100 0	18730	100 0	21220	100 0

Note :- Rural Centres Places with population upto 10,000.

Semi-Urban Centres Places with population over 10,000 and upto 1,00,000 Urban Centres Places with population over 1,00,000 and upto 10,00,000 Metropolitan Centres Places with population over 10,00,000

^{*}Re-classified on the basis of 1971 census population figures

148. The aggregate deposits of the Indian banks' offices abroad increased from Rs. 427 crores at the end of December 1974 to Rs. 651 crores at the end of December 1975. The bulk of the deposit expansion was on account of time deposits, which rose by Rs. 157 crores, while demand deposits registered a rise of Rs. 67 crores. Credit extended by foreign offices of the Indian banks, at Rs. 396 crores at end-December 1975, expanded over the year by Rs. 145 crores. However, their credit-deposit ratio increased sharply from 58.9 per cent in December 1974 to 64.4 per cent at the end of December 1975.

# Lending to Priority Sectors and Weaker Sections of the Society

149 Besides expanding their branch network in hitherto unbanked/underbanked centres, the commercial banks continued to extend liberal credit facilities to the priority and 'neglected' sectors of the economy which include: agriculture, small-scale industries, exports, 10ad and water transport operators, self-employed persons, professionals, etc. Banks also took vigorous measures to step-up their lending to the weaker sections of the population under the Scheme of Differential Rates of Interest.

#### Advances to Priority Sectors

150. Scheduled commercial banks' advances to the priority sectors rose from Rs. 2112 crores at the end of December 1974 to Rs. 2597 crores at the end of December 1975; the proportion of priority sector advances to total bank credit also registered a smal rise over the year from 26.4 per cent to 26.6 per cent (Table 24). The share of public sector banks in the total priority sector advances improved further from 88.7 per cent at the end of December 1974 to 89.7 per cent at the end of December 1975. This improvement was entirely attributable to 14 nationalised banks whose share in all banks' advances to priority sectors improved from 58.0 per cent in December 1974 to 59.3 per cent in December 1975. The shares of individual priority sectors in total priority sector advances underwent further changes between end-December 1974 and end December 1975. Though 'small-scale industries' continued to account for a large proportion of total priority sector advances, their share in such advances further dropped from 48.2 per cent to 44.2 per cent. On the other hand, the shares of 'direct agricultural finance' and 'road and water transport operators' improved from 25.5 per cent and 5.7 per cent in December 1974 to 27.9 per cent and 7.4 per cent, respectively, in December 1975.

TABLE 24 . -SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' ADVANCES TO PRIORITY SECTORS

(Amounts in Rupees Crores)

[tem	D	ecember 197	74 (Provisio	nal)	December 1975 (Provisional)				
item	State Bank Group	Fourteen Nationa- lised Banks	Public Sector Banks (2+3)	All Schedu- led Commer- cial Banks	State Bank Group	Fourteen Nationa- lised Banks	Public Sector Banks (6 +7)	All Schedu- led Commer cial Banks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Total Bank Credit II. Advances to Priority Sectors	2230	4506	6736	7993	2884	5445	8329	9769	
(1) Direct Finance	156	323	479	539	228	430	658	725	
(ii) Indirect Finance	73	154	227	242	86	193	279	299	
<ul><li>(b) Small-Scale Industries</li><li>(c) Road and Water Transport</li></ul>	370	540	910	1017	410	625	1035	1147	
Operators	15	80	95	121	23	131	154	191	
<ul><li>(d) Retail Trade and Small Business .</li><li>(e) Professional and Self-employed</li></ul>	32	93	125	149	37	811	155	179	
Persons	4	30	34	40	5	38	43	51	
(f) Education		4	4	4	1	5	5	5	
Total of (a) to (f)	650	1224	1874	2112	789	1540	2329	2597	
Percentage share of the bank group in all banks' advances to Priority Sectors	30.8	58.0	88 7	100.0	30 4	59 3	89.7	100,00	
Percentage of advances to priority sectors in total bank credit.	29.1	27.2	27.8	26.4	27.4	28.2	28.3	26.6	

# Assistance to the Agricultural Sector

151. Commercial banks' participation in financing agriculture in other ways also increased during the year. They continued to assist the identified participants in SFDA/MFAL areas. Besides, banks also provided short-term and term finance to agriculturists under the Scheme of Financing Primary Agricultural Credit Societies introduced in June 1970 (for details please see paragraphs 305 and 306 under the head 'developments in Co-operative Banking').

152. Scheduled commercial banks continued to actively participate in financing schemes for which refinance facilities are available from Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC). As at the end of May 1976, the Corporation had sanctioned 1,699 schemes to commercial banks

mvolving total financial assistance to the extent of Rs. 382.8 crores. The Corporation's disbursements to the commercial banks amounted to Rs. 106.3 crores till the end of May 1976, as against Rs. 46.4 crores a year ago. Minor irrigation and farm mechanisation schemes claimed a major share of there disbursements (79 per cent).

# IDA Assistance

153. Further, commercial banks continued to participate in projects sanctioned with assistance from IBRD/IDA for financing programmes in various States. Their share in the IBRD/IDA disbutsement routed through the ARDC increased from Rs. 15 crores at the end of June 1975 to Rs. 43 crores on May 31, 1976. During the year, International Development Association (IDA) sanctioned three more projects viz., the Integrated Cotton Development Project, National

Seed Project and Nagarjunasagar Command Area Development Project, involving  $1D\Lambda$  assistance of Rs. 32 crores to be routed through the ARDC.

154. In pursuance of the recommendations of the National Commission on Agriculture, Farmers' Service Societies are being organised and financed by central co-operative banks and commercial banks. As at the end of June 1976, 101 such societies had been set up in 12 States by 17 commercial banks.

# Recovery of Agricultural Advances

- 155. The total demand for agricultural advances (durect finance) of the public sector banks (i.e. overdue amount as on the last Friday of previous June plus current demand during July 1974—June 1975) increased sharply. At the same time, the amount of recovery by these banks also increased substantially. The All-India percentage of recovery to demand, which had increased by 0.2 percentage point during 1973-74, showed further improvement during 1974-75. rising from 48.2 per cent (revised) to 50.2 per cent as at the end of June 1975.
- 156. All the regions, excepting the Central and Western regions, reported improvement in the recoveries. States, which showed remarkable improvement in recoveries included Tripura, Andhra Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Punjab and Bihar. In the Western region, though the overall proportion of recoveries remained unchanged over the year at 39.7 per cent, Gujarat showed a deterioration in recoveries position, which was, however, offset by a significant improvement reported by other, constituents of this region. The recovery position deteriorated also in the case of Jammu & Kashmir, Meghalaya, Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry and Chandigarh.

#### Village Adoption Scheme

157. During the year, banks continued to adopt villages under the 'Village Adoption Scheme'. Under this Scheme banks after conducting a detailed techno-economic survey of the villages in the area of operation of their branches, select a village or a cluster of villages, formulate suitable programmes of financing of bankable proposals and extend need-based credit to all the viable or protentialy viable farmers. This leads to integrated and harmonious development of the agricultural economy of that area and at the same time avoids the possibility of overlapping of efforts and resources in the same area by two or more commercial banks.

# Scheme of Differential Rates of Interest

- 158. During the year under review, additional district were notified by the planning Commission as industrially backward and hence eligible for concessional finance from the financial institutions. Consequently banks were asked to extend the Scheme of Differential Interest Rates to these district viz.. Aurangabad, Begusarai, Gaya, Monghyr and Nawadh (all from Binar), pudukkottai (Tamil Nadu) and Lalitpur and Ram pur (Uttar Pradesh), Including these districts, the Scheme now covers 275 backward and SFDA/MFAL districts and Union Territories in the country.
- 159. Public sector banks made further progress in lending under the Scheme during 1975 (January-December). Over the year, the number of borrowal accounts increased by 1,50,146 to 4.64,811 and the amount of loans outstanding rose by Rs. 7.5 crores to Rs. 21.0 crores. The average amount of loan per account, also increased from Rs. 426 at the end of December 1974 to Rs. 452 at the end of December 1975, indicating the vigorous efforts made by the banks to step up their lending to the weaker section of the society.

# Export Sector

160. The export sector continued to receive high priority in the provision of bank credit. During the year under review, banks were specifically asked to look into their procedure for providing export credit and take steps to remove the bottlenecks, if any, in the way of speedy decisions.

# Standing Committee on Export Finance

161. The Standing Committee on Export Finance, set up in the Reserve Bank, continued to discuss the problems of export finance. In the light of its deliberations, several measures were introduced during the year to ensure the availability of adequate and timely credit to the export sector. These are briefly described below.

#### Duty Drawback Credit Scheme, 1976

- 162. As an export promotion measure, a credit scheme was drawn up by the Reserve Rank for grant of advances by banks to exporters against their duty drawback entitlements as provisionally certified by Customs Authorities, pending final sanction and payment.
- 163. Under the Scheme, which came into force from February 1, 1976, such advances are eligible for refinance from the Reserve Bank upto a maximum period of 90 days from the date of advance. The Reserve Bank will give refinance to all scheduled banks, which are authorised dealers in foreign exchange, against their promissory notes repayable on demand on the basis of their declarations in respect of advances made by them to exporters against their duty drawback entitlements as provisionally cerified by Customs Authorities. At present, such refinance facility is available at the Reserve Bank offices in Bombay, Delhi, Calcutta and Madras. The banks will sanction suitable limits to individual exporters for advances taking into account their export performance, eligibility for the drawback and other relevant factors. The advances and the corresponding refinance by the Reserve Bank will be interest-free. Banks may, however, charge a reasonable amount towards administrative expenses or costs relating to transmission of funds between the centres where refinance is obtained from the Reserve Bank and the centres where advances are made to exporters. Banks may sometimes consider it necessary to stipulate on a selective basis a margin not exceeding 10 per cent between the amount of duty drawback provisionaly certified by Customs Authorities and the advances to be granted. The advances will be exempt from the Reserve Bank's directive stipulating minimum lending rates. The amounts paid to exporters by way of advances under this Scheme are not eligible for subsidies under the Export Credit (Interest Subsidy) Scheme.

# Liberalisation of Export Credit Schemes

- 164. The terms of various export credit schemes were liberalised further. To begin with the list of specified medium and heavy engineering goods and overseas construction contracts, in respect of which ceiling on the rate of interest to be charged by banks is stipulated, was enlarged to cover 55 items as against 44 items included originally. In the case of turn key projects, it was agreed to extend the concessionary pre-shipment credit up to a maximum period of one year, depending upon the merits of individual cases.
- 165. Secondly, in the case of consultancy firms exporting consultancy services only, banks were advised to consider granting suitable pre-shipment credit facilities against consultancy agreements for meeting the expenses of the technical and other staff employed for the project and purchase of any materials required for the purpose. Computer systems and programmes produced for export purposes by the management consultancy firms are also to be considered as cover for packing credit advances granted to them.
- 166. Thirdly, sugar mills were made eligible for concessional pre-shipment credit facilities up to a maximum period of 60 days, in respect of sugar to be supplied by them for export to Indian Sugar Industries Export Corporation Ltd., (ISIEC) on production of the contracts entered into with the ISIEC or despatch instructions received from ISIEC. The ISIFC will be eligible for concessional pre-shipment credit for the remaining period for which ceiling rates are stipulated.
- 167. Fourthly, in the case of carpet exporters, banks were advised to consider granting packing credit advances to a reasonable extent not only against finished goods ready for despatch, but also to cover cost of raw materials and manufacturing expenses and for stocking of carpets, in anticipation of exports, subject to the condition that letters of credit/export order are lodged within a reasonable time. Banks were

advised to extend packing credit facilities to jute mills on the basis of cable advices from foreign buyers, subject to the lodgement of export orders or letters of credit in due course

168 Fifthly, banks were advised to provide finance against goods for exhibition and sale abroad in the normal course in the first instance and after the export sale was completed, allow the benefit of the concessional rate of interest on such advances by way of a rebate covering both the pre-shipment and post shipment stages up to stipulated periods. Further, with a view to imparting flexibility in operation of packing credit advances, the Reserve Bank waived the stipulation that the goods financed by a packing credit advance should be exported to the same country, if substitution of contract is to be permitted. Consequent upon the relaxation, packing credits are allowed to be adjusted flexibly by negotiating export bills are allowed to be adjusted flexibly by negotiating export bills relating to another contract, provided the goods covered by the advance are exported under the substituted contract within a reasonable time. In cases where sub-suppliers are involved, both the export house/agency and the concerned sub-supplier are permitted to take advantage of the concessionary preshipment credit, on an agreed basis, within the stipulated periods.

#### Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968

- 169. During the year, the Government of India agreed, in principle, to amend the Export Credit (Interest Subsidy) Scheme. 1968, on the following lines: (i) Advances in respect of third-country purchases relating to turn key projects undertaken abroad by Indian exporters, may be considered as eligible for concessional rate of interest and interest subsidy. Such advances will be treated as post-shipment credit.
- (ii) The requirement that the Reserve Bank's approval should be obtained for extending pre-shipment credits beyond 180 days, may be waived,
- (iii) Interest subsidy payable to banks on post-shipment credit on deferred payment terms may be increased to 4 per cent.
- (iv) Interest subsidy may be provided also on buyers' credits so as to give the participating commercial banks the same return as in the case of post-shipment (sellers') credit on deferred payment terms.
- 170. In the meantime, the banks continued to receive subsidy under the existing scheme at the rate of 1.5 per cent per annum in respect of export credits granted by them at the stipulated rate of interest. During 1975-76 (Inly to June), claims for interest subsidy amounting to Rs. 8 9 crores received from 47 eligible banks were settled. Out of the above, pre-shipment credit accounted for Rs. 4.7 crores and post-shipment credit for Rs. 4.2 crores. Total amount of subsidy disbursed since the inception of the scheme up to June 30, 1976 comes to Rs. 39.9 crores.
- 171. Interest subsidy at the rate of 1.5 per cent per annum from the Market Development Fund of the Commerce Ministry and at the rate of 3 per cent per annum from the funds allotted by the Ministry of External Affairs, is also being paid to the Industrial Development Bank of India United Commercial Bank and United Bank of India on a special bank credit of Rs. 25 crores extended by them to certain financial institutions in Bangladesh for import of specified capital goods from India. The total interest subsidy disbursed to the three banks during the period under review amounted to Rs. 24.7 lakhs (Rs. 6.4 Jakhs at 1.5 per cent and Rs. 18.3 lakhs at 3 per cent).
- 172 With a view to reducing the interest burden on exponters to Sudan, on account of foreign exchange difficulties in that country, the Reserve Bank advised the banks on July 14, 1976 to charge interest at a rate not exceeding the ceiling rate of 11.5 per cent per annum upto the date of receipt of proceeds in India, subject to the maximum period of 90 days, provided the bill was paid by the importer in the local currency. This relaxation will be available till the end of December 1976 and banks will be eligible for interest subsidy of 1.5 per cent upto the maximum period of 90 days.

# Consortium/Participation Arrangements Consortium Banking

- 173. In the last year's Annual Report a reference was made to the instructions issued by the Reserve Bank to the commercial banks on the basis of recommendations made by the Study Group on Extension of Credit Limits on consortium/participation basis. Among other things, the banks were advised to initiate a oldogue with other banks with a view to evolving an appropriate procedure for co-ordination on the lines already suggested to them. As the action taken by some of the banks in this regard was found inadequate, the Reserve Bank advised its regional offices that they should instruct their inspecting officers to examine this aspect in the course of financial inspections of banks and report their assessment.
- 174. Further, with a view to eliminating certain unhealthy features in the working of consortium lending, banks were advised to ensure that drawings in the participation advances were, as far as possible, proportionate to the respective shares of the banks in the aggregate credit limit granted by the consortium. Financing banks were further advised that it was desirable to arrive at an arrangement for equitably sharing ancillary business of the borrower, such as, collection of bills, issue of letters of guarantee, foreign exchange business, etc.

#### Working Group for Public Food Procurement Credit

175. The Reserve Bank constituted a Working Group for evolving procedures and model consortia documents for meeting the credit needs of public food procurement agencies and also of various public and private sector borrowers under consortium arrangements. The Working Group was constituted following a review of the existing arrangements for financing of food procurement, which revealed that the State Bank as leader of the consortium for public food procurement operations was experiencing certain operational problems in periodically allocating shares among its 36 member banks. The Working Group is expected to submit its report shortly.

# Participation Certificates Scheme

176. The Participation Certificates Scheme, which was introduced on an experimental basis in March 1970, made notable progress during the period under review. The terms and conditions governing the issue of participation certificates remained unchanged during the year. The number of banks approved by the Reserve Bank under the Scheme increased from 37 at the end of June 1975 to 43 (including 9 foreign banks) and the amount of participation certificates issued and outstanding as at the end of December 1975 stood at Rs. 113.5 crores. The Scheme, which has been extended from time to time, was further extended till the end of June 1977 and a review of the Scheme is being undertaken with a view to considering its further extension.

# Term Lending: Commercial Banks

177. It will be recalled that the Reserve Bank has been issuing guidelines from time to time to the commercial banks, urging them to increase their term-lending for projects of high priority indicated specifically. During November 1975, the Reserve Bank again impressed on the commercial banks the need to provide larger term loans for periods beyond three years at a reduced cost. In the context of the need to provide further stimulation to long-term investment in the economy, banks were triged to charge a rate of interest not more than 15 per cent on term loans for periods beyond three years. Subsequently, banks were advised to charge, with effect from April 1, 1976, a rate of interest not exceeding 14 per cent on term loans granted to industry for a period of not less than seven years in view of the exemption given from interest tax for interest income on such term loans. The rate on term loans between three and seven years will, however. continue to be 15 per cent (inclusive of interest tax on advances).

# Credit Planning and Credit Authorisation Scheme Credit Planning

178. During the year under review, the Reserve Bank held discussions with the bankers about the methods and measures

of more effective credit planning with a view to bringing about a more meaningful co-relation between the demand for and supply of credit. In terms of the new framework evolved by the Reserve Bank to improve the credit planning exercise, banks are now required to prepare a quarterly credit budget, instead of the earlier practice of preparing an annual budget. While preparing projections of demand for credit from various sectors, banks have been asked to hold discussions with their borrowers so that these projections reflect their business intentions accurately. The Reserve Bank would follow this up and devise measures to monitor the flow of credit among sectors with reference to the projected and actual increase in output. For this purpose, the Reserve Bank has since introduced a monthly reporting system on sectoral flow of credit as a further dimension to its Basic Statistical Returns System.

# Report of Study Group on Follow-up of Credit

179. A major development having an impact on the working of the Credit Authorisation Scheme (CAS) was the submission of the final report in August 1975 by the Study Group which was set up by the Reserve Bank in July 1974 to frame guidelines for follow-up of bank credit. The main recommendations of the Group relate to the approach to lending, norms for inventory and receivables, information system, style of credit, follow-up and supervision of credit and financial structure of borrowing companies.

180. As regards the approach to lending, the Group has visualised that the main function of a bank as a lender is to supplement the borrower's resources in carrying a reasonable level of current assets in relation to his production requirements. In the light of this, the Group has suggested three methods for working out the maximum permissible bank borrowings to meet the working capital gap (excess of current assets over current habilities other than short-term bank successive method increases the borrowers' own borrowings). long-term funds—comprising support of term borrowings-to the current To avoid hardship to the borrowers, the Group has recommended that a beginning may be made by placing all borrowers on the first method of lending within a year and then moving to the second and third methods in stages in the light of the Reserve Bank's assessment of the situation then prevailing. The Reserve Bank has accepted for the time being the first method of lending under which borrowers have to contribute 25 per cent of the working capital gap from long-term funds. Placing the borrower on the first method means that banks would work out the excess of bank borrowings over the short-term finance to which the borrower would be eligible under the new formula borrower would be eligible under the new formula and convert such excess amount into a term loan, the period of amortisation of which would depend on the borrower's cash generating capacity, etc. Further, additional credit faci-lities to a borrower already having excess borrowings could also be provided, subject to certain conditions.

181. According to the Study Group's report, there is no sufficient uniformity in the approach of banks in judging the reasonability of the current assets levels for the purpose of assessing working capital requirements, especially in regard to inventories and receivables. The Group has, therefore, suggested norms for inventory and receivables in respect to 15 major industries. These norms are to be kept constantly under review, the idea being that if there is a change in the environment, justifying a modification of any norm, it should be appropriately changed.

182 The Group has also suggested a change in the style of extending bank credit; instead of making available the entire credit limit in a cash credit account for a year, it may be bifurcated into a 12-month loan representing the minimum level of borrowings which the borrower expects to use throughout the year and a demand cash credit account which will take care of his fluctuating requirements. As a part of the integrated system, the Group has made comprehensive suggestions for follow-up and supervision of credit for ensuring its proper end-use

183. The main recommendations of the Study Group, already accepted by the Reserve Bank, were conveyed to the

commercial banks in August 1975, emphasising the importance of gearing up banks' organisational set-up for early implementation of the Study Group's recommendations. A Committee of Direction, comprising representatives from the Reserve Bank and some major banks, for an on-going review of the problems arising in the course of the implementation of the Study Group's recommendations was set up in the Reserve Bank. The desirability of banks conducting banker-borrower seminars to create an understanding between the operating officials of banks and the customers for appreciating each other's problems and points of view was also stressed. Further, for an in-depth study of the recommendations of the Group, a series of seminars on the report of the Group were organised.

# Credit Authorisation Scheme

184. The Credit Authorisation Scheme (CAS) which was introduced over a decade ago, continued to play a useful tole in implementing the Bank's credit policy. Thus, the additional credit limits authorised during the year broadly conformed to the basic objectives of credit policy viz., providing adequate credit for sustaining investment, augmenting production, financing procurement of foodgrains, facilitating better distribution of essential commodities and assisting export promotion. While scrutinising the proposals received under the Scheme, the Reserve Bank kept in view the recommendations made by the Study Group on Follow-up of Credit with regard to inventory norms and the new approach to lending. In the light of the Study Group's recommendations, the Bank also modified certain proformae of statements prescribed under the Scheme with a view to obtaining comprehensive data from the banks.

185. A major development affecting the CAS was the stepping up in November 1975 of the minimum limit for prior authorisation from Rs. 1 crore to Rs. 2 crores for borrowers in the private sector. To impart further flexibility in the operation of the Scheme, banks were advised that they could grant without Reserve Bank's prior authorisation, interim finance/bridge loans against their own share of the term loans sanctioned on a consortium basis with IDBI/ARDC, provided such bridge loans are released only after these institutions have made a firm commitment and banks' share therein has been determined. Such loans could also be given against the committed financial assistance from the all-India financial institutions. It was clarified to banks that the exemptions from prior authorisation available for advances supported by Central and State Government guarantees in respect of borrowers enjoying credit limits below Rs. 3 crores from the entire banking system were confined to working capital requirements only and not for the provision of interim finance or bridge loans relating to capital expenditure.

186. Having regard to changes in the economy since the submission of the Study Group report, the inventory norms stipulated by the Group in respect of certain industries viz., spinning mills, jute mills and fertiliser units were liberalised. It was also decided to withdraw the advice given to banks in November 1973 to impose additional margins on books debts and inventories, as several measures had already been initiated by the banks to enforce discipline among the borrowers.

187. Due to the raising of the minimum limit of Rs. 1 crore to Rs. 2 crores for the purpose of Bank's prior authorisation for undertakings in the private sector referred to above, the number of parties covered by the Scheme decreased from 1,786 at the end of June 1975 to 851 at the end of June 1976, inclusive of public sector undertakings numbering 154. However, the number of applications received increased over the same period from 1,058 to 1,181 and the amount involved from Rs. 1022 crores to Rs. 2646 crores. Of the total number of applications received during 1975-76, 216 belonged to the public sector, involving an amount of Rs. 1781 crores. The total number of cases authorised and the corresponding amount involved showed an increase during 1975-76. The number of cases authorised increased from 528 in 1974-75 to 716 in 1975-76 and the amount from Rs. 428 crores to Rs. 1962 crores (a major portion of this credit is utilised for food procurement operations).

188. Total limits in force telating to the cases covered by CAS at Rs. 8476 crores at the end of June 1976 showed an increase of 17 per cent over the limits obtained at the end of June 1975. Of this, limits in force in respect of public sector undertakings amounted to Rs. 4440 crores or 68 per cent higher than the previous year's level. The pattern of purpose-wise distribution of the total limits in force as at the end of June 1976 remained more or less unchanged, that is about 90 per cent were for working capital purposes, 7 per cent for term finance and 3 per cent for sale of machinery on deferred payment basis. Industry-wise, of the total limits in force as at the end of June 1976, trading accounted for about 33 per cent (of which, food procurement operations claimed 28 per cent), engineering industry accounted for about 21 per cent (of which transport equipment's share was 4 per cent) and cotton textile about 7 per cent. Of the credit limits in force relating to public sector, trading accounted for about 30 per cent, engineering industry for 6 per cent (of which, transport equipment's share was 1 per cent) and electricity undertakings for 3 per cent.

# Advances to Certain Industries

189. In view of the special problems faced by certain industries, commercial banks were permitted to meet their credit requirements on relatively liberal terms.

#### Jute Industry

190. It may be recalled that last year, banks were allowed to extend credit to individual jute mills on the basis of maximum inventory of finished goods intended for exports equal to 9 weeks' production for a temporary period till end-June 1975. In view of the continued slackness in both domestic and external demand and the uncertain outlook facing the industry, the relaxation in respect of jute goods for exports was extended until further advice, and the norms for inventory of finished goods intended for domestic sales was also relaxed upto 6 weeks' cost of sales until further advice. Banks were also advised that in cases where the increase in credit made available for financing the additional inventory referred to above did not exceed 10 per cent of the existing credit limits against inventories, prior authorisation of the Reserve Bank would not be required.

# Textile Industry

191. Last year, banks were permitted to grant reasonable ad hoc limits to the mills taken over by the National Textile Corporation (NTC) in relation to their production plans upto the end of June 1975 without Reserve Bank's prior authorisation. On representations made by the NTC regarding the difficulties in finalisation of the accounts of individual mills taken over by it, this concession was extended in stages upto end-September 1976.

192. In the context of the large accumulation of cotton yarn, particularly hank yarn, reflecting the depressed condition in the handloom industry, banks were advised in November 1975 that they might consider some interchangeability within the overall exisiting norms applicable to cotton spinning mills. Thus, if a part of the maximum credit limit against raw cotton remained unutilised, the credit limit against finished goods might be enhanced to an equivalent extent over and above the present maximum permissible limit of 2½ months for a temporary period upto end-March 1976. It was also clarified that such enhancements should be restricted to a maximum of 3 weeks. In other words, the level of inventory of finished goods and receivables should not in any case be in excess of 3 months. This relaxation was subsequently extended in stages upto end-July 1976.

# Fertiliser Industry

193. In the light of the problems arising out of accumulation of finished fertiliser stocks, the existing norms on the level of holdings of inventory of raw materials and packing materials were relaxed from 2 to 3 months' consumption and that of finished goods and of receivables from 2½ to 4 months' sales, as a temporary measure till the period ended March 1976. This period was subsequently extended in stages upto end-October 1976.

#### Sugar Industry

194. After reviewing the prospects of sugar production during the 1975-76 season, the Reserve Bank advised banks in November 1975 that they might sanction credit limits, on merits to individual sugar mills to the extent of the maximum outstanding under regular limits (exclusive of drawings if any, over and above the regular limits, as also limits granted on a temporary basis) sanctioned to them for the last two crushing seasons (1973-74 and 1974-75 seasons), without obtaining prior authorisation under the Credit Authorisation Scheme. Further, banks were advise once again to ensure prompt payment of cane dues to the sugarcane growers.

#### Other Industries

195. Having regard to the difficulties faced by the paper industry and automobile ancillaries, the existing norms were modified for a temporary period of 6 months (i.e., till end-September 1976). In the case of paper industry, a measure of flexibility was imparted by prescribing a combined norm for finished goods and receivables at 1½ months cost of sales and sales respectively, instead of previous norm of one month's cost of sales for finished goods (controlled sales) and ½ month's sale (goods meant for free sales) and ½ month's sale for receivables. In the case of automobile ancillary units, the existing combined norms for finished goods and teceivables were relaxed from 2½ months' to 3½ months' cost of sales and sales, respectively.

# Sick Industrial Undertakings

196. A seminar on Sick Industrial Undertakings was organised by the Reserve Bank at Bombay in April 1976 to discuss the various problems relating to sick industrial undertakings, particularly from the viewpoint of banks and financial institutions. As a follow-up measure, banks were advised to set up specific 'Cells' to tackle the various problems associated with sick industrial undertakings. The immediate task to such Cells would be to undertake a quick review of the position of the existing borrowers and try to identify units which are already sick or prone to sickness, so that increased attention could be focussed on the problems of such units and feasible corrective action taken. In this connection the need for establishing a comprehensive information system in the Bank, on the lines suggested by the Tandon Committee, was also stressed. Within the Reserve Bank also, a Cell was established to function as a clearing house of information relating to sick units and to act as a co-ordinating agency on behalf of the Government, banks, financial institutions and other agencies.

# Selective Credit Controls

197. Taking into account the anticipated increase in the output of agricultural commodities and the needs of agrobased industries, the selective credit controls were operated with some flexibility essentially through a reduction in the minimum margin requirement in respect of advances against a number of commodities, the most important being ground nut and sugar. The prescribed margin for advances against groundnut in the States of Gujarat and Maharashtra was 75 per cent, In November 1975, this regional distinction was done away with and a uniform margin of 60 per cent was specified for the whole country. In March 1976, this minimum margin was further lowered to 50 per cent while the margin for advances against warehouse receipts covering stocks of groundnut was fixed at 45 per cent. In respect of sugar, in place of different margins for levy and free sale sugar, a uniform margin of 15 per cent was prescribed. The margin on advances against cotton textiles (including yarn of manmade fibres) to traders was also reduced from 40 per cent to 30 per cent.

198. The ceiling limits for advances continued to be fixed on a party-wise basis. The base for fixing the permissible level, however, related to 100 per cent of the peak level of advances outstanding in any of the three preceding years (November October) viz., 1974-75, 1973-74 and 1972-73. Taking into account the proposal of Credit Guarantee Corporation of India Ltd. to enhance the limit of its liability pertaining to claims in respect of advances granted to truders, the exemption limit in respect of advances covered by a guarantee scheme of the Corporation was raised from Rs. 20,000 to Rs. 25,000. Similar relaxations were provided in the case of

advances covered by the Credit Guarantee Organisation and those granted to processing/manufacturing units coming under Rural Industries Projects.

199 In the case of essential consumer goods other than foodgrains, banks were advised to maintain a margin of 10 per cent on stocks relating to advances to State/Central Government agencies as also to consumer co-operatives, undertaking distribution of such commodities, subject to the availability of Government guarantee. Suitable exemptions were accorded on account of both margin and level of credit to advances against vegetable oils and sugar granted to consumer co-operatives for stocks held under the Centrally-sponsored Scheme for distribution of essential consumer articles.

200. Advances against foodgrains to foodgrain processing units in all centres were exempted from the level of credit stipulation: the additional level of credit for new sceking facilities from new branches of banks opened on or after January 1, 1970 at centres with a population of 1 lakh or below was made uniform at Rs. 1 lakh for all States and Union Territories. Advances against paddy and rice to rise millers acting as Government agents were completely exempted from credit control directives to the extent that the stocks were held separately on producers' levy account. A distinction was made between edible and non-edible oilseeds and oils thereof and lower margins were stipulated for non-edible oilseeds and oils. Some additional varieties of cotton were made eligible for exemption from level of credit requirement and entitlement to lower margin. Banks were also permitted to discount bills of exchange arising out of sales of cotton textiles having usance not exceeding 60 days.

201. In view of the untrend in the prices of raw cotton in the last quarter of 1975-76, the Bank tightened selective credit controls relating to advances against cotton and kapas, effective July 8, 1976, bearing in mind the action taken by the Textile Commissioner regarding the maximum stocks that can be held by mills. Inventory levels in respect of which lower margins are applicable were substantially reduced. Thus, in the case of mills in Bomoay and Ahmedabad, as against the existing margins of 25 per cent for excess stocks of 12 weeks' consumption and 50 per cent for excess stocks, the margins were refixed at 25 per cent for excess stocks, the margins were refixed at 25 per cent for excess stocks. Similar changes were made in respect of mills under the National Textile Corporation and other mills in areas other than Bombay and Ahmedabad In the case of parties other than mills, margins were raised from 25 per cent to 45 per cent in respect of new and/or longstaple cotton, from 50 per cent to 60 per cent for other varieties of indigenous cotton, and from 40 per cent to 50 per cent for stocks covered by warehouse receipts.

202. On a review of the supply and price situation relating to oilseeds and vegetable oils, the Bank stepped up minimum margins, with effect from July 14, 1976, by 10 percentage points—from 50 per cent to 60 per cent with regard to advances against groundnut, castorseed and linseed—and by 15 percentage points—from 60 per cent to 75 per cent in respect of castor oil and linseed oil. Advances against cottonseed and cotton seed oil were also brought under selective credit controls, the relative minimum margins being 60 per cent and 75 per cent, respectively. They were also subjected to celling level of credit and minimum rate of interest of 15 per cent. As regards rapeseed/mustard seed, the increase in minimum margin was by 10 percentage points—from 25 per cent to 35 per cent for registered oil mills in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and West Bengal and from 40 per cent to 50 per cent for registered oil mills in other States. The minimum margins for advances against warehouse receipts were also fixed suitably. No changes were, however, made in the existing minimum margin of 75 per cent for advances against groundnut oil, rapeseed oil/mustard oil and vanaspati. The existing margins for advances to vanaspati manufacturers against vegetable oils also remained unchanged. The stipulation of minimum margin for cottonseed oil did not apply to vanaspati manufacturers.

# Lead Bank Scheme

203 The Lead Bank Scheme ushered in by the Reserve Bank in December 1969 completed six years of its existence. It was, therefore, decided to undertake an intensive study of the working of the Scheme in the two States of Gujarat and Maharashtra.

# Study Groups on the Working of the Scheme

204 In pursuance of this decision, the Reserve Bank constituted in August 1975 two Study Groups; their terms of reference included: the examination of the constitution and working of the district level consultative committees, nature and extent of liaison between financial institutions and the State Governments and the extent of involvement of banks in the formulation and implementation of area development programmes. The Study Groups submitted their report in December 1975.

205. In their common report, the Study Groups came to the conclusion that while the first phase of the lead bank programme, consisting of the identification of centres holding potential for bank operations and the opening of bank branches therein, had been a success both in terms of the number of new offices and in the emergence of a new pattern of collaborative effort, the progress in the formulation and implementation of area development programme was slow. The Study Groups observed that the 'credit plans' drawn by some banks for their districts varied in methodology and coverage. Though the Groups did not recommend a uniform approach in this regard, they laid emphasis on the expediapproach that the least, they laid emphasis on the expedi-tious preparation of technologically feasible and economi-cally viable schemes and their collective implementation by all financial institutions. They suggested that banks should set about the task of formulation of such schemes in the broad area of the 'priority sectors' which could be immediately implemented and completed within a span of 3 to 5 years. The Study Groups have provided certain guidelines for the more effective operation of the Lead Bank Scheme covering the formulation and implementation of bankable schemes and the constitution and functioning of the District Con-sultative Committees. The Study Groups have also suggested the constitution of a standing committee in the Reserve Bank for the purpose of keeping the overall progress of the Lead Bank Scheme under review.

# High Power Committee

206. Following this recommendation, a high power committee for the Lead Bank Scheme was constituted by the Reserve Bank. The Committee will, inter alia issue policy guidelines for the effective functioning of the Lead Bank Scheme, examine specific problems in the implementation of the Scheme and those referred by the State Governments and regional offices of the Reserve Bank and act as a reviewing authority for matters relating to non-compliance of the accepted commitments. The guidelines formulated by the Study Groups, referred to above, on the working of the Scheme in Gujarat and Maharashtra have been circulated among all the banks.

207. The Government of India convened a meeting of the Chief Fxecutives of Public Sector Banks on February 24, 1976, wherein the role of banks in the implementation of the 20-point Fconomic Programme was discussed.

# Public Sector Banks' Orientation to Twenty-Point Economic Programme

208. The principal areas in which banks can assist in the implementation of the 20-point Economic Programme are (a) procurement and distribution of essential commodities. (b) assistance to the landless labourers and other weaker sections of the community, who are being allotted land and house sites, (c) assistance to those released from bonded labour for undertaking viable productive ventures, (d) increased flow of credit to rural areas to take care of the credit gap created by the moratorium on recovery of debt from landless labourers, small farmers and artisans and progressive implementation of the programme for liquidation of rural indebtedness, (e) increased assistance to the agricultural sector for minor irrigation schemes and for better use of underground water resources, (f) assistance to handloom weavers, (g) assistance to those who are granted national permits for road transport, (h) support to programme for supply of essential commodities to students in hostels and books and stationery at controlled prices and (i) schemes for apprentices for enlarging employment and training opportunities, especially for weaker sections.

209. According to the preliminary reports received from the banks, they have recognised the importance of the Programme and have taken the necessary steps to evolve schemes for providing assistance to the various weaker sections of the community. The Reserve Bank, 551 its part, has also issued necessary guidelines to the banks from time to time, the latest one being in regard to the provision of finance for housing schemes meant for weaker sections of the society. In addition, the Reserve Bank organised in June 1976 a Seminar on the role of banks in the implementation of the 20-point Economic Programme. During the Seminar, various schemes formulated by the banks for implementing the programme were discussed. Banks on their part also organised workshop/camps/seminars to educate their own staff in the field of this innovative banking.

210. While each bank is expected to display the necessary initiative for extending assistance to the beneficiaries under the Programme, the Lead Banks by virtue of their position are expected to give a lead to others in this direction. Therefore, on June 2, 1976, the Government of India directed these banks to reorient their Schemes to achieve the objectives of the 20-point Economic Programme. In this connection, the banks were asked to review from time to time their organizational machinery, delegation of loan sanctioning powers, loan procedures and the terms and conditions of loans so as to ensure prompt disbursement of credit to rural poor. Public sector banks were also advised to make periodically quantitative and qualitative assessment of the work done by them in the implementation of the 20-point Economic Programme.

# Regional Rural Banks

211. A significant development in the field of banking duting the year was the establishment of 19 Regional Rural Banks (RRBs) under the Regional Rural Banks Ordinance, 1975, promulgated by the Government of India on September 26, 1965 and subsequently replaced by the Regional Rural Banks Act, 1976. This followed the recommendations made by the Working Group constituted by the Government of India on July 1, 1975 to study, in depth, the problem of devising alternative agencies to provide institutional credit to tural people in the context of the steps being initiated under the 20-point Economic Programme. The main objectives of RRBs, their capital structure, organization, business and other aspects of working are discussed below:

# Objective, Establishment and Capital

212. The main objective of setting up the Regional Rural Banks is to provide credit and other facilities, especially to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs in rural areas. Each RRB will operate within the local limits to be specified by a notification. If necessary, a RRB might also establish branches or agencies at any place notified by the Government. Each RRB is sponsored by a public sector bank, which provides assistance in several ways, viz., subscription to its share capital, provision of such managerial and financial assistance as may be mutually agreed upon and help in the recruitment and training of personnel during the initial period of its functioning. The authorised capital of each RRB is Rs. I crore and the issued capital is Rs, 25 lakhs. Of the issued capital, 50 per cent is subscribed by the Government of India, 15 per cent by the concerned State Government and the balance viz, 35 per cent by the sponsor bank.

# Management

213. The management of each RRB is vested in a nine member Board of Directors, headed by a Chairman who is appointed by the Government of India. In discharging its functions, the Board of Directors is required to act on business principles and in accordance with the directives issued by the Government of India, after consultations with the Reserve Bank. While a RRB is empowered to appoint officers and other employees, which it may consider necessary, their remuneration is prescribed by the Government of India in accordance with the salary structure of the employees of the State Government and local authorities of comparable level and status in the area of operation of the RRB.

#### Business

214. Every RRB is authorised to carry on and transact the business of banking as defined in Section 5(b) of the Banking Regulation Act, 1949 and may also engage in other business specified in Section 6(1) of the said Act. In particular, a RRB is required to undertake the business of (a) granting loans and advance, to small and marginal farmers and agricultural labourers, whether individually or in groups and to co-operative societies, including agricultural marketing societies, agricultural processing societies, co-operative farming societies, primary agricultural credit societies or farmers' service societies, for agricultural puposes or agricultural operations or for other related purposes and (b) granting of loans and advances to artisans, small entrepreneurs and persons of small means engaged in trade, commerce, industry or other productive activities, within its area of operation.

#### Reserve Bank Assistance and Tax Concessions

215. All the RRBs set up so far have been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934. The amendments made to the Reserve Bank of India Act, 1934 enable the Reserve Bank to grant assistance to RRBs, by way of loans and advances from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund under Sections 46A and 46B. Further, by an amendment made to the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank is empowered to vary, in respect of RRBs, the percentage governing maintenance of liquid assets in relation to demand and time liabilities of a banking company referred to in sub-section 2(A) of Section 24. Thus, the statutory liquid assets required to be maintained by the RRBs have been fixed at only 25 per cent as against the present requirement of 33 per cent in the case of other scheduled commercial banks. By a notification issued by the Reserve Bank, for a period of one year with effect from October 2, 1975, the RRBs are required to maintain a cash reserve at the rate of 3 per cent of their total demand and time liabilities (as specified in Sub-Section (1) of Section 42 of the R.B.I. Act, 1934) as against 4 per cent currently maintained by other scheduled commercial banks. Moreover, for the purpose of Income-tax Act, 1961 or any other act relating to tax on income, profits or gains, a RRB is deemed to be a co-operative society. As such, a RRB is not liable to pay tax under the Interest Tax Act, 1974.

# Operational Procedures

216. In order to minimise the procedural delays in making/withdrawing deposits, submitting loan applications, executing loan documents, etc., the Reserve Bank have constituted a Committee to suggest accounting and operational procedures, etc. to be followed by the RRBs, so that their rural clients feel at home in dealing with these banks. The Reserve Bank have also undertaken the task of providing training facilities to the Chairmen and Branch Managers of the RRBs, as early as possible.

# Performance of RRBs

217. By the end of June 30, 1976, 19 Regional Rural Banks had been established in different States of the country. The first such bank was established on October 2, 1975 and the 19th bank on April 30, 1976 (Table 25). Within the short span of their working, the RRBs have opened 112 offices, mobilised deposits amounting to Rs. 1.2 crores and extended advances of the order of Rs. 1.5 crores

# Banking Legislation

# Amendments to Banking Regulation Companies Rules, 1949

218. It was mentioned in the last Annual Report that the Government's notification regarding amendments to the Banking Regulation (Companies) Rules, 1949 was awaited. Following the issue of this notification, the Reserve Bank issued a circular to all banks advising them of the amendments, which came into force from December 13, 197.

# State Legislations

219. It may be recalled that the Expert Group on State Enactments had recommended, in 1971, the adoption of a model bill by the various States to facilitate quicker and timely disbursements of agricultural credit. So far 10 States viz., Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal have enacted the legislations. During the year, 6 more States viz., Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Manipur and Meghalaya prepared the draft bills.

# Inspections, Mergers and Related Organisational Matters Inspection

220. The comparative position in regard to inspection of banks and bank offices carried out during the last three years (July—June) is indicated below:

	197374	1974-75	<b>1975–7</b> 6
Financial Inspection	<del></del>	<del></del>	
No. of banks inspected/			
taken up for inspection .	24	28	31
No. of offices inspected .	752	506	787
Centre-wise Inspection			
No. of centres	614	1217	1492
No. of offices	2218	2362	2328
Systems Inspection			
No. of banks inspected .	1	2	2

221. In pursuance of the Reserve Bank's programme of periodical inspections of commercial banks to asses their financial position, 30 scheduled banks and 1 non-scheduled bank were inspected/taken up for inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 during the year under review. Besides these the inspection of branches of the Indian banks in the U. K. and Fiji Islands was also completed during the period.

222. Centre-wise inspections were conducted at 1,492 centres covered by 2,328 offices. The programme of study of individual banks for examining their systems and procedures and suggesting improvements, wherever necessary, was continued during the year. Studies in respect of two banks viz., United Bank of India and Bank of Madura Ltd. were completed during the year, while the study reports on Bank of Maharashtra and United Bank of India were finalised and sent to the respective banks. Since the introduction of this programme in 1971, the Reserve Bank has completed the study of systems and procedures of 8 banks. The study reports are sent to the concerned banks with a view to ensuring rectification of the defects pointed out and for implementing the suggestions made therein.

# Bank Mergers and Liquidations

223. Efforts to consolidate the banking system through the process of voluntary amalgamations, transfer of liabilities and assets and participation arrangements continued during the year. During 1975-76 Gauhati Bank Ltd. was amalgamated with Purbanchal Bank Ltd. This scheme of amalgamation under Section 44A of the Banking Regulation Act, 1949 was sanctitoned in July 1975 and came into force on August 1, 1975.

# TABLE 25 :- LIST OF REGIONAL RURAL BANKS

Nam	e of Bank and its Head Office	Date of establishment	Sponsor Bank	State	Jurisdiction (within local limits of Districts)	No. bran- ches opened	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Prathama Bank, Morada- bad	02-10-1975	Syndicate Bank	Uttar Pradesh	Moradabad		ـــــ و
2.	Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur	02-10-1975	State Bank of India	Uttar Pradesh	Gorakhpur and Deoria		10
3.	Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani	02-10-1975	Punjab National Bank	Haryana	Bhiwani		12
4.	Jaipur-Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur	02-10-1975	United Commercial Bank	Rajasthan	Jaipur and Nagaur		11
5.	Gaur Gramin Bank, Malda .	02-10-1975	United Bank of India	West Bengal	Malda, West Dinajpur an Murshidabad	d	18
6.	Bhojpur Rohtas Gramin Bank, Arrah	26-12-1975	Punjab National Bank	Bihar	Bhojpur and Rohtas		6
7.	Samyut Kshetriya Gramın Bank, Azamgarh	06-01-1976	Union Bank of India	Uttar Pradesh	Azamgarh & Ghazipur		7
8.	Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad	20-01-1976	Central Bank of India	Madhya Pradesh	Hoshangabad & Raisen		6
9.	Tungabhadra Gramin Bank, Bellary		Canara Bank	Karnataka	Bollary & Raichur	•	7
10.	Puri Gramya Bank, Pipli .	25-02-1976	Indian Overseas Bank	Orissa	Puri		2
11.	Jammu Rural Bank, Jammu .	12-03-1976	Jammu & Kashmir Bank Ltd.	Jammu & Kashmir	Jammu		2
12.	Champaran Kshetriya Gramin Bank, Champaran		Central Bank of India	Bihar	East & West Champaran		_ 3

	1	2	3	4	5	6
13.	Bara Banki Gramin Bank, Bara Banki	27-03-1976	Bank of India	Uttar Pradesh	Bara Banki	1
14.	Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon	28-03-1976	Syndicate Bank	Haryana	Gurgaon	8
15.		29-03-1976	Bank of Baroda	Uttar Pradesh	Rae Bareli	1
16.	Farrukhabad Gramin Bank, Farrukhabad	29-03-1976	Bank of India	Uttar Pradesh	Farrukhabad	I
17.	Mallabhum Gramin Bank, Bankura	09-04-1976	United Bank of India	West Bengal	Purulia, Bankura and Midnapur	3
18.	Bolangir Aanchalik Gramya Bank, Molangir	10-04-1976	State Bank of India	Orissa	Bolangir	I
19.	Nagarjuna Gramin Bank, Khammam	30-04-1976	State Bank of India	Andhra Pradesh	Khammam and Nalgonda	4

224. It was mentioned in the last Annual Report that Government of India had sanctioned schemes of amalgamation under Section 45 of the Banking Regulation Act 1949 in respect of 49 banks. Under these schemes the transferee banks were required to make a final valuation of the assets of the transferor banks after a period of 6/12 years or such earlier periods as might be sanctioned by the Government of India in consultation with the Reserve Bank. The final valuation of the assets of 20 banks has been completed and reports in respect of 11 other banks are under consideration.

225. During the year, one bank i.e., the Belgaum Bank Ltd. transferred its selected assets and liabilities to Union Bank of India under Section 293 of the Companies Act, 1956, from the close of the business on November 29, 1975. Another bank viz., Jharia Industrial Bank (Pvt.) Ltd., a non-scheduled bank, agreed to transfer its liabilities and assets to United Commercial Bank. Since the transfer did not materialise, the former bank was advised to take immediate steps to go into voluntary liquidation. The bank's request for allowing further time for going into liquidation was rejected. Besides this, the proposal for transfer of assets and liabilities of the Narang Bank of India Ltd., a scheduled bank, to United Bank of India under Section 293 of the Companies Act, 1956 is in the stage of negotiation.

226. During the year, Bank of Baroda was allowed to participate in the share capital of Naini Tal Bank Ltd. (a non-scheduled bank) and Bareilly Corporation (Bank) Ltd. (a scheduled bank). Further the Government of India approved United Bank of India's participation in the share capital of the United Industrial Bank Ltd. It may be added that Union Bank of India is already participating in the share capital of the Benares State Bank Ltd

227. During the period under review, four non-scheduled banks were dissolved and reports on 4 non-scheduled banks (3 of which were stated to have been dissolved during the last year and one in 1965) were received. No bank was issued a certificate to go into voluntary liquidation under Section 44(1) of the Banking Regulation Act, 1949. After obtaining the necessary directive from the Government of India, the inspection of books and accounts of five banks under liquidation viz., Central Calcutta Bank Ltd., Calcutta, Commercial Bank Ltd., Bank of Calcutta Ltd., Nath Bank Ltd. and Bengal Bank Ltd. under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 was taken up and completed during the vear under review. While the inspection report in respect of the first three banks were examined and forwarded to the Government of India, the other reports are still under consideration. Inspection under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 of the Associated Banking Corporation of India Ltd., referred to in the last Annual Report, could not be resumed during the year under review also, as the relevant records were still not being made available for the purpose of inspection.

# Licensing of Banks

228 During the period under review, no new licence to carry on banking business in India was granted to any bank,

while the licence granted to the Belgaum Bank Ltd. was cancelled consequent upon its business being taken over by Union Bank of India referred to earlier. Following this, the name of Belgaum Bank Ltd. was excluded second Schedule the Reserve Bank the to of India Act, 1934. Thus, the number of licensed com-mercial banks stood reduced to 45 (including National Bank of Pakistan which is under the Custodian of Enemy Property), while the number of banks in whose cases the licences have been cancelled increased to 55 as at the end of June 1976. It may be reiterated that the 22 public sector banks do not require licence.

229. During the period under review, no licence under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on banking business in India was refused to any existing bank. Thus the total number of banks to whom licences have been refused remains unchanged at 283 as at the end of June 1976.

#### Clearing House Facilities

230. During 1975-76 (July-June), 31 clearing houses were established, bringing the total number of clearing houses in the country to 243. Of this, 9 are managed by the Reserve Bank of India, 199 by the State Bank of India and 35 by the subsidiaries of the State Bank of India.

# Standardisation of Coding of Cheques

231. During the year, a circular was issued to all scheduled commercial banks instructing them to incorporate in their cheques new uniform code numbers in two boxes pertaining to the banks and branches concerned. It may be observed that uniform coding is intended to enable the collecting banks to sort out the instruments bank-wise promptly and efficiently and save considerable time and labour in processing outward/inward clearing and collection.

# Credit Information and Statistics

232. During the year, the Reserve Bank introduced a new procedure under which its Regional Offices were entrusted with the job of collecting, on a quarterly basis, district-wise data on deposits and advances (including to the priority sectors) in respect of each State/Union Territory separately from the regional offices of the commercial banks. The information so collected is consolidated and made available to the conceined dead banks and State Governments. The new procedure attempts to collect quickly the basic information for each district so as to facilitate meaningful discussions at the meetings of the District Consultative Committees.

233. During the year, the Reserve Bank set up a Steering Committee on Management Information System in Banks (a) to evolve proper guidelines for the introduction of management information system in banks and to oversee its implementation; (b) to provide expert guidance to banks on various aspects like banking costs, profitability of branches, business planning and performance budgeting; (c) to deal with matters relating to specdier and more efficient ways of data processing and (d) to consider other recomendations of the Banking Commission on information system in banks and suitable follow-up action.

234. The Department of Banking Operations and Development of the Bank continued to assist commercial banks and other notified financial institutions by furnishing to them, on request, information of credit facilities allowed to individual borrowers. During 1975-76, credit information in respect of 1,184 applications was furnished to the applicant banks and financial institutions as compared to 953 applications during the previous year.

#### Basic Statistical Returns Scheme (BSR)

- 235. The fourth volume of Banking Statistics under the series 'Basic Statistical Returns' presenting comprehensive data on deposits and advances as on June 1974 was published during the year. A brochure giving the provisional quick results upto December 1974 in respect of important items was also brought out in April 1976.
- 236. A monthly reporting system in respect of large borrowal accounts, representing about two-thirds of the total bank credit, was introduced from June 1976. Together with the data on priority sector advances, which are called from banks

on a quarterly basis, this would provide broad sectoral breakup of credit on a monthly basis covering 90 per cent of total credit.

#### Working Results of Scheduled Commercial Banks

- 237. The published working results of 22 public sector banks (the State Bank Group and the 14 nationalised banks and 25 other Indian scheduled commercial banks, each with deposits of Rs. 10 crores and above) show a further improvement in profits during the calender year 1975. The profits of public sector Banks recorded a marked increase of 46 per cent in 1975, while those of the 25 Indian scheduled commercial banks in the private sector showed a marginal increase of 11 per cent. On the other hand, the profits of 12 foreign banks registered a decline of 16 per cent in 1975, as against an increase of 50 per cent in 1974 (Table 26).
- 25. Profits after provision for taxation and for bonus/exgratia payment to staff. Profits for the year 1975 are not strictly comparable with those of 1974 in view of the change in procedure in the case of some banks in arriving at profits.

TABLE 26 :- WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Amounts in Rupees Crores)

Items	State Bank Group		Nationalised Banks		Total Public Sector Banks		Other Indian Scheduled Commercial Banks@		Foreign Banks	
-	1974	1975	1974	1975	1974	1975	1974	1975	1974	1975
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Total Earnings .	358.57 (34.9)	451.61 (25.9)	682.55 (39.7)	852.28 (24.8)	1041.12 (38.0)	1303.89 (25.2)	101,44 (43.8)	139.28 (37.3)	105.05 (38.8)	119.51 (13.8)
Of which:										
(a) Interest and . Discount .	297.69 (37.3)	370.26 (24.4)	601.58 (39.9)	760.81 (26.5)	899,27 (3 <b>9</b> .0)	1131.07 (25.8)	86.94 (41.0)	119.90 (37.9)	82.10 (39,7)	96,72 (17.8)
II. Total Expenditure	353.35 (35.3)	444.16 (25-7)	672 17 (39.7)	837.03 (24.5)	1025.52 (38.2)	1281.19 (24.9)	98,55 (42.6)	136,06 (38,0)	98.75 (38.1)	114.23 (15.7)
Of which:										
(b) Interest paid on Borrowings, Deposits, etc	173.60 (48.0)	231.08 (33.1)	388.72 (50.8)	49 <b>5</b> .95 (27-6)	562,32 (49.9)	727.03 (29.3)	51.35 (41.4)	73.73 (43.6)	45.27 (48.2)	49.51 (9.4)
(c) Salaries, Allowances, Provident Fund and Bonus/Ex-										
gratia payment to	145.12	169.97	218.17	261 20	363.29	431.17	33.96	42,86	22.82	23.48
Staff	(26.9)	(17.1)	(28.7)	(19-7)	(28.0)	(18.7)	(41.4)	(26.2)	(22.9)	(2.9)
III. Profits after provision for taxation and Bonus/Ex-										
gratia payment to Staff	5.22 (12-2)	7.45 (42.7)	(0.38 (35.7)	15.25 (46.9)	15.60 (26.7)	22.70 (45.5)	2.89 (109.4)	3.22 (11.4)	6.30 (50.0)	5.28 (16.2)

Note: Figures in brackets indicate percentage variation over the previous year; figures for 1974 are revised.

Source: Profit and Loss Accounts of banks.

a figures relate to 25 Indian Scheduled Commercial Banks in the private sector with deposits of Rs. 10 crores and over.

#### Public Sector Banks

238. An analysis of the working results of the 22 public sector banks (the State Bank Group and the 14 nationalised banks) for 1975, shows that their profits increased from Rs. 15.6 crores in 1974 to Rs. 22.7 crores in 1975 despite a smaller rise in income as compared to last year. The higher profits were due to a larger spread between total earnings and expenses in 1975. The total income of these banks rose by Rs. 262.8 crores (25.2 per cent) during 1975, as compared to an increase of Rs. 286.7 crores (38.0 per cent) in 1974. The bulk of the increase in earnings was from 'interest and discount' which rose by Rs. 231.8 crores (25.8 per cent) during 1975 as compared with the rise of Rs. 252.3 crores (39.0 per cent) in 1974. The increase in the volume of credit in 1975 as also the hike in the minimum lending rate of banks from 11 per cent to 12.5 per cent since July 23, 1974 contributed to the improvement in the banks' income from this source. Income earned from 'commission, exchange and brokerage' was also higher in 1975 than in 1974. Total expenditure of these banks also showed an increase, but the rise in expenditure was at a much lower rate during, 1975 than in 1974. Thus, the total expenses of these banks increased by Rs. 255.7 crores (24.9 per cent) in 1974. An important component contributing to the increase in banks' expenses was 'interest paid on deposits and borrowings'. It increased by Rs. 164.7 crores in 1975 as compared to a rise of Rs. 187.3 crores during 1974. Another major item of expenditure viz., 'salaries, allowances, provident fund and bonus/ex-gratia payment' recorded an increase of Rs. 67.9 crores as compared to Rs. 79.5 crores in 1974.

#### State Bank of India

239. Total earnings of the State Bank of India recorded an increase of Rs. 75.3 crores during 1975 as compared to a rise of Rs. 74.7 crores in 1974. The increase of Rs 73.4 crores in the total expenditure during 1975 was lower as compared to the increase of Rs. 74.2 crores in 1974. As a result, the profits of the State Bank of India at Rs. 6.5 crores in 1975 recorded a marked increase of Rs. 1.9 crores as compared to an increase of only Rs. 49 lakhs in 1974. Out of the profits for 1975, the bank transferred Rs. 5 crores to reserve fund and provided Rs. 1.5 crores for dividend to shareholders.

# Subsidiaries of State Bank of India

240. The seven subsidiaries of the State Bank showed an increase in their income of Rs. 17.7 crores in 1975 as compared to that of Rs. 18.2 crores in 1974. Their total expenses recorded a smaller rise (Rs. 17.4 crores) during 1975 than in 1974 (Ro. 18.1 crores). Consequently their profits rose from Rs. 61 lakhs in 1974 to Rs. 92 lakhs in 1975. Out of the profits for 1975, these banks transferred an amount of Rs. 61 lakhs to reserves as against Rs. 49 lakhs last year and made provision for payment of divided to State Bank of Rs. 31 lakhs against Rs. 12 lakhs in 1974.

# Nationalised Banks

241. The total income of the 14 nationalised banks at R2. 852.3 crorse in 1975 registered an increase of Rs. 169.7 crores (24.8 per cent) as compared to a rise of Rs. 193.8 crores (39.7 per cent) in 1974. The bulk of the increase in earnings during 1975 was from 'interest and discount' which recorded a rise of Rs. 159.2 crores (26.5 per cent) as compared to a rise of Rs. 171.4 crores (39.9 per cent) in 1974. Total expenses of these banks rose by Rs. 164.9 crores in 1975 (24.5 per cent) as compared to the rise of Rs. 191.2 crores (39.9 per cent) in 1974. The two important items of expenditure, viz., 'interest paid on deposits and borrowings' and 'salaries allowances, provident fund and bonus/ex-gratia payment etc.', increased during the year by Rs. 107.2 crores and Rs. 43.0 crores, respectively, as compared to the increase of Rs. 130.9 crores and Rs. 48.7 crores in 1974. Reflecting these trends in income and expenses, the profits of 14 nationalised banks recorded a rise of Rs. 4.9 crores in 1975, as compared to Rs 2.7 crores in 1974.

242. Out of their profits, the 14 nationalised banks transferred Rs. 9.2 crores to the statutory reserves and Rs. 4.3 crores to the Government under section 10(7) of the Banking Companies (Aquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The surplus amount transferred to Government of India during 1975 represents 5.0 per cent of the aggregate compensation paid for the acquisition of these banks as compared to 4.5 per cent in 1974.

#### Other Indian Scheduled Commercial Banks

243. The working results of 25 private sector Indian scheduled commercial banks each with deposits of Rs. 10 crores and over reveal a smaller rise in the level of their profits. During 1975, these banks' total income increased by Rs. 37.8 crores to Rs. 139.3 crores (37.3 per cent) and expenditure by Rs. 37.5 crores to Rs. 136 I crores (38.0 per cent). Consequently, these banks showed profit of Rs. 3.2 crores as compared with Rs. 2.9 crores in 1974. Out of the profits of Rs. 3.2 crores to statutory reserves and Rs. 1,0 crore to other reserves.

# Foreign Banks

244. During 1975, the income of the 12 foreign banks increased by Rs. 14.5 crores or by 13.8 per cent and their expenditure rose by Rs. 15.5 crores or by 15.7 per cent. Reflecting this, their profits at Rs. 5.3 crores recorded a decline of Rs. 1.0 crore (16.2 per cent) during 1975 as compared to a rise of Rs. 2.1 crores (50 per cent) in 1974.

# Committees and Working Groups

245. Besides the Committees and Working Groups/Study Groups referred to earlier, the Reserve Bank/the Government appointed/constituted the following committees and study/Working Groups during the year under review.

# Committee on Penal Rates and Service Charges

246. Following discussions with the Chief Executives of the commercial banks on March 12, 1976, the Reserve Bank, in consultation with the Chairman of the Indian Banks Association, constituted a Committee on Penal Rates and Service Charges. The Committee submitted its report in April 1976. In its report, the Committee has recommended that the system of penal rates has to be accepted as a justifiable part of the interest rates policy of banks as long as they are applied with selectivity and discrimination. Penal rates should be regarded not as a revenue raising measure but ans an instrument to enforce discipline among the borrowers. A bank may be justfied in charging penal rates in the following cases viz., (i) default in repayment of loans, (ii) irregularities in cash credit accounts, (iii) non-submission of stock statements and other financial data, (iv) default in borrowing convenants, (v) non-payment/non-acceptance of demand/usance bills of exchange on due date and/or (vi) excess current assets. The Committee has recommended that penal rates may vary from 1 per cent to 2.5 per cent over and above the normal rates applicable to advances, but in no circumstances the penal rate should exceed per cent over the ceiling rates prescribed by the Reserve Bank on advances. As regards service charges on borrowal accounts, the Committee has observed that there could be no objection to banks recovering from the borrowers actual out-of-pocket expenses incurred by them such as godown keeper's salary, legal charges and stamp duties. In regard to other service charges, the question is still being examined by the Committee and therefore until the Committee submits and its final report, no bank should increase the scale of such service charges prevailing before the ceiling on interest rates
was prescribed by the Reserve Bank. The Bank has accepted these recommendations and issued appropriate guidelines to the banks.

# Working Group on Operational Efficiency and Profitability of Banks

247. The Working Group on Operational Efficiency and Profitability of Banks, which was appointed by the Reserve Bank in April 1976, has been asked to (i) suggest practical and realistic criteria for the evaluation of the performance of individual

banks, (ii) determine the basis for assessment of cost of various banking services, (iii) plan and organise a systematic survey to provide estimates of average cost and income in respect of different functions undertaken, (iv) provide guidelines on the pricing policy of banks in relation to the services rendeted to the constituents, (v) recommend internal systems and procedures to control banking costs, improve operational efficiency, productivity and profitability of banks and (vi) advise the nature of cost studies which should be undertaken by individual of service charges and evolving suitable methods for profitability analysis of branches.

# Working Group on Customer Service in Banks

248. The Working Group on Customer Service in Banks, which was appointed by the Government of India, submitted its interim report on the critical service areas of banks. The Group identified the following areas as critical for customer service viz, (i) deposit accounts, remittances and collections, encashment of cheques issuance of receipts, statements of accounts, collection of cheques and bills and remittances including issue and encashment of drafts, (ii) loans and (iii) staff attitudes. The Government of India have accepted the major recommendations of the Group and advised the banks to implement them. Most of the recommendations, which call for specific and urgent action, have been implemented by the banks. Other recommendations, which require legislative action/measures on the part of the Government/Reserve Bank are being considered by the appropriate authorities.

#### Committee on Transfer of Loan Accounts

- 249. With a view to discouraging unhealthy competition among the banks for big loan accounts, the Reserve Bank constituted on March 15, 1976 a Committee on Transfer of Loan Accounts. The Committee was asked to work out norms for regulating the transfer of loan accounts among banks so as to develop a mutually acceptable system in this regard.
- 250. The Committee in its report, submitted to the Reserve Bank, has suggested the establishment of a high level committe in each bank to consider the genuine grievances of the customers. The procedure suggested by the Committee for taking over of accounts provides for consultations between the transferor and transferee banks. The procedure also provides for safeguards to ensure that the borrowers do not transfer accounts to avoid financial discipline. Under the procedure recommended by the Committee, the transferee bank will not be able to give concessions in the rate of interest. Further, with the intervention of Reserve Bank, banks would not be able to block transfer of accounts for unjustifiable reasons. The Committee's recommendations have been accepted by the Reserve Bank and certain guidelines are being issued to banks in this regard.

# Working Group on Housing Finance

- 251. On May 7, 1976, the Governor of the Reserve Bank announced that a Working Group will be constituted shortly to examine the role of the banking system in providing finance for housing schemes. However, pending an in-depth study of the subject by the proposed Working Group and in view of the importance assigned to housing for the weaker sections of the community under the 20-point Economic Programme, the Reserve Bank issued certain tentative guidelines to the commercial banks. Housing Schemes eligible for bank finance would be rural housing schemes, housing as well as hostels for scheduled castes and Scheduled tribes, slum clearance schemes, family planning clinics and rural health centres covered under public health programmes and urban housing schemes for low income group.
- 252. Banks have been advised that bulk of the cost of each housing project should be financed from sources other than bank finance and bank credit should only supplement such resources. Generally, bank credit should not exceed 40 per cent of the total cost of each project: and in the case of direct loans to the beneficiaries under the Schemes, individual loan should not exceed 80 per cent of the total cost of each

tenement/house. Further, banks have been advised that the rate of interest on loans for housing schemes and hostels intended for scheduled castes and scheduled tribes should not exceed the rate prescribed under the Differential Interest Rates Scheme. In respect of housing schemes for other categories, the rate of interest should be moderate and in keasing with the priority assigned to this activity. The Bank has clarified that the minimum lending rate directive will not apply to the aforesaid types of loans.

# Credit Guarantee Corporation and deposit Insurance Corporation

253. Finally, the activities of the Credit Guarantee Corporation of India and the Deposit Insurance Corporation during the year under review may be briefly reviewed.

# Credit Guarantee Corporation of India (CGCI)

- 254. During 1975, there was a notable increase in the coverage of advances guaranteed under the three Schemes of the Credit Guarantee Corporation. The total loans and other Credit facilities extended to small borrowers by banks, state financial corporations and service co-operative societies covered by the Guarantee Schemes as on the last Friday of December 1975 amounted to Rs. 799.6 crores, as compared to Rs. 529.6 crores a year before. Bulk of this amount (Rs. 796.1 crores, was under the Small Loans Guarantee Of the granted under alone²⁶. total advances Scheme, farmers and agriculturists alone accounted for Rs. 538.7 crores, followed by transport operators (Rs. 104.8 crores), traders (Rs. 80.5 crores) and professionals and self employed (Rs. 40.7 crores). The sum of advances guaranteed under other two schemes, viz., Financial Corporation Guarantee Scheme and Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, amounted to Rs. 2.6 27 crores and Rs. 0.928 crore, respectively. As at the end of April 1976, the Credit Guarantee Corporation had received 3,497 claim applications for a total of Rs. 127.5 lakhs, of these farmers and agriculturists alone accounted for 2,314 claims involving an amount of Rs. 84.8 lakhs, followed by transport operators for 212 claims involving Rs. 25.0 lakhs. Out of the total claims received upto the end of April 1976, 2,272 claims for Rs. 88.0 lakhs were notified to credit institutions, 514 claims for an aggregate amount of Rs. 13.0 lakhs were discharged, 111 claims of Rs. 4.3 lakhs were rejected, and 159 claims for Rs. 3.3 lakhs were withdrawn by the credit institutions themselves for one or the other reason. The remaining claims were being examined by the Corporation. The present procedure for dealing with claim applications is being reviewed by the Corporation with a view to setling the claims more speedily
- 255. The Corporation further liberalised the conditions on which the benefit of protection was made available to credit institutions in regard to the credit facilities granted by them to certain categories of borrowers. Thus, with effect from Innuary 1, 1976, the ceiling limit for the eligible credit facilities to transport operators was raised from Rs. 1 lakh to Rs. 1.5 lakhs; for traders in goods other than fertilisers or mineral oils, the ceiling limit on annual sales turnover was raised from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs and in respect of traders in fertilisers or mineral oils it was increased from Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs. Further, the Corporation's liability in respect of claims was enhanced from 75 per cent of the amount in default or Rs. 37,500 whichever is lower to 75 per cent of the amount in default or Rs. 50,000 whichever is lower. The Regional Rural Banks, set up during the year, were also made eligible to join the Corporation's Credit Guarantee Schemes: so far, three Regional Rural Banks have executed the necessary agreements.

# Deposit Insurance Corporation (DIC)

256. During the year under review, the number of insured commercial banks came down from 81 to 79 consequent upon the amalgamation of the Gauhati Bank Ltd. with the Purbhanchal Bank Ltd. and transfer of liabilities and assets

^{26.} Figures relate to 74 out of 75 banks, which have joined the Scheme.

^{27.} Figures relate to 11 out of 18 financial corporations.

^{28.} Figures relate to 6 commercial banks only.

^{29.} The Section on Finance of Non-Banking Companies' appears in Part IV (Developments in Industrial Finance) of this Report.

of the Belgaum Bank 1 to to the Union Bank of India Forther, 19 Regional Rural Banks established under the Regional Rural Banks Act, 1976 in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan. Uttar Pradesh and West Bengal were registered as insured banks during the year

257. The number of insured co-operative banks went up from 513 to 536 including one co-operative banks in the State of Tripura to which the insurance scheme was extended. The Scheme now covers co-operative banks in the States of Andh a Pridesh. Madhya Pradesh, Maharashtra, Jammu and Kashmir, Kerala and Tripura and the Union Territories of Delhi, Goa Daman and Diu and Pondicherry The question of extending the Scheme to the remaining States, Union Territories is under active consideration.

258. With a view to providing a gleater measure of protection to bank depositors the D.I.C. raised the limit of insurance cover for deposits in registered insured banks from Rs 10,000 per depositor to Rs. 20,000 with effect from July 1, 1976. The previous limit of Rs. 10,000 per depositor came into force on April 1, 1970.

# III. DEVFLOPMENTS IN CO-OPERATIVE BANKING

259. The main emphasis in the sphere of co-operative banking continued to be on the reduction of regional imbalances in co-operative development and the narrowing down of the existing credit gaps. The latter objective was sought to be

achieved by reorganising the primary agricultural credit societies into viable/potentially viable ones and by organising new societies like the Fatmers Service Societies (FSS) and Large-sized Multipurpose Societies (LAMPS), particularly in the tribal areas. Apart from undertaking measures for rehabilitating and strengthening central co-operative banks in States where the co-operative movement has so far been weak, special stress was also placed on gearing the movement to meet the needs of the weaker sections of the community. The Twenty-point Economic Programme has imparted a new sense of urgency to the attainment of these objectives.

#### Twenty-point Economic Programme

260. Special attention was being paid to the implementation of the 20-point Economic Programme. As the measures taken for the liquidation of the rural indebtedness were likely to dry up the credit line from non-institutional sources such as money-lenders, consumption loans were permitted to be given by societies to members of the weaker sections. Individuals could also get loans either directly from the central cooperative banks or from their own societies against the security of gold or silver ornaments. Certain relaxations have been made in the matter of eligibility of primary agricultural credit societies for share capital contribution from out of the Bank's Long-term Operations Fund: these would enable them to augment their owned funds and their lendings for consumption purposes.

TABLE 27 -- PROGRESS OF COOPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA

(Amounts in Rupees Crores) Co-operative year Type of institutions 1972-73 1973-74 1974-75* _ 3 (a) State Co-operative Banks (i) Number * (ii) Owned funds (iii) Deposits (a) Of which, short-term agricultural . (v) Working capital . . . (vi) Loans issued (vii) Loans outstanding . (a) Of which, short-term agricultural . (viii) Percentage of (iv a) to (vii a) (b) Central Co-operative Banks (1) Number . (ii) Owned funds . . . . (iii) Deposits . . . . . (iii) Deposits . (iv) Borrowings from the RBI/apex bank . (v) Working capital . . . (vi) Loans issued . . . (vii) Loans outstanding . . (c) State/Centre Land Development Banks (ii) Owned funds . . . (iii) Debentures outstanding (iv) Working capital . (r) Loans issued . (vi) Loans outstanding . (d) Primary Agricultural Credit Societies (t) Number (in thousands) (ii) Membership (in thousands) (iii) Owned funds . (iv) Deposits (r) Borrowings (vi) Loans issued . . . . - - - - 979 (vii) Loans outstanding

^{*}Provisional. 25 GI/77--18

TABLE 28 :-- RESERVF BANK CREDIT TO CO-OPERATIVES 1974-75 AND 1975-76

(Amounts in Rupees Crores) 1974-75 (July-June) 1975-76 (July-June) Items Limits Drawals Repay-Outstan-Limits Drawals Repay-Outsta-Sancments dings Sancments ndings tioned tioned 1 2 4 Q 3 6 5 7 8 I. Short-term (1) Seasonal agricultural operations (at 1 % below Bank Rate)1 489.52 811.79 75 L. 15 212 15 146.60 611.89 899.73 965 28 (ii) Marketing of crops other than cotton and kapas 0 49 1 18 13 19.58 Nil 0 49 40 30 37 37 (iii) Marketing of cotton and kapasa 46.94 37 54 10 25 ) 21 89 31 97 0.17 (iv) Purchase and distribution of fertilisers (at 3% above Bank Rate)8 28.20 22.45 3.6518.80 47 05 62.9261 81 19.91 (v) Production and marketing of handloom products (at  $1\frac{1}{2}$ °, below Bank Rate)4 15.69 29,43 23.3711 09 20.03 34.25 33.94 11 40 (vi) Financing other cottage and small scale industries4 . . . . 2 52 1,33 0.281.33 4.75 2.53 1 55 2.31 (vii) Purchase and sale of yarn (at Bank 0.65 Rate)4 0.470.430 04 0.65 0.13 0.11 0.06 (viii) Loans to ARDC (at Bank Rate) . 15 00 11 60 15,00 1.70 1.70 67.12 (/v) Against pledge of sugar 22 00 45,12 22.00 14 50 10.50 32.50 Nil II. Medium-term (i) Agricultural purposes (at  $1\frac{1}{4}\%$ below Bank Rate)5 9 87 4 58 8,83 15.65 7 48 15 35 11.59 7 18 (ii) Conversion of short-term loans into medium-term loans in scarcity affected areas (at 11 % below Bank Rate) 106,926 55.036 25 366 82 556 50 486 41 816 78.766 45 606 . (iii) Purchase of shares in co-operative sugar factories/processing societies (at Bank Rate) . 0.53 0.16 0.341.01 3.04 0.38 0.63 III. Long-term (1) Loans to State Governments for contribution to share capital of cooperative credit institutions4 8 37 8 37 6 37 70 00 13,54 13.52 75 70 7 53 (ii) Loans to ARDC (at  $4\frac{1}{3}\%/4\frac{3}{4}\%$ 40.00 per annum)7 40.00 5.80 88,20 60.00 60.00 138.40 9.80

261. Further, under the 20-point Economic Programme, the consumer co-operatives were assigned an important role in the public distribution system for supply of essential goods such as controlled cloth etc. at reasonable prices. While the state level consumers' federations, wholesale co-operatives and the primary consumer co-operatives will serve the urban areas, the reorganised primary agricultural credit societies, the FSS and the LAMPS would attend to the distribution work in rural areas. These societies were made eligible for additional share capital contribution in excess of the normal limit of Rs. 10,000 from the Bank's Long-Term Operations Fund. Besides, the Bank had agreed to consider the involvement of the funds of the central co-operative banks in financing

these societies for this purpose as a legitimate charge on their funds and grant larger financial accommodation for eligible purposes. To meet the growing working capital needs of urban consumer stores in this context, the Bank agreed to their being financed by the urban co-operative banks. Further, in order to ensure flow of increased volume of working capital finance from commercial and co-operative banks for this activity, the Central Government's Guarantee Scheme which was so far confined to national and state level co-operative consumers' federations and wholesale stores was liberalised to cover good working primary societies having large turnover.

^{1.} At  $\frac{1}{2}\%$  below Bank Rate from 1973-74 subject to rebate of  $1-\frac{1}{2}\%$  as per Rebate Scheme excepting under Section 17(4)(a) which continued to be at 2% below Bank Rate. At 2% Below Bank Rate from 1975-76 subject to recovery of an additional interest of  $1-\frac{1}{2}\%$  as per Linking Scheme.

^{2.} Including monopoly procurement of cotton

^{3.} Prior to 1972, pruchase and distribution of fertilisers was financed at Bank Rate by the Bank. However, from January 1972, the interest rate was raised by 2% above the Bank Rate with a view to aligning it to the lending rates of commercial banks. Again it was further raised to 3% above Bank Rate for 1974. Data relate to calendar year 1974 and 1975.

^{4.} Data relate to financial years.

^{5.} Data relate to calendar year 1974 and 1975.

^{6.} Including rephasement and reschedulement

^{7.} The interest was raised from 4-\frac{3}{2}\, o to 6\, o from September 1974.

# Co-operative Credit Policy

262. The main aim of the co-operative credit policy during the year 1975-76 continued to be to subserve the national objectives of development within the framework of monetary discipline. For this purpose, funds were provided, on rational norms, to co-operative institutions on short-term, mediumterm and long-term basis for financing agriculture and cottage and small-scale industries largely on a supplementary basis. An overall view of progress of co-operative credit movement during the three years ended 1974-75 and of the Reserve Bank credit to co-operatives in 1974-75 and 1975-76 can be had from the data in Tables 27 and 28.

#### Short-term Finance

Scasonal Agricultural Operations

#### Concessional Finance

263. The Bank continued its policy of sanctioning short-term credit limits during 1975-76 (under Section 17(2) (b) read with Section 17(4) (c) /Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act) for financing seasonal agricultural operations to state co-operative banks at 2 per cent below the Bank Rate. As mentioned in the last year's Report this concessional rate was available to banks, only to the extent of their borrowings within an aggregate level fixed separately for each bank in this regard under the scheme of linking borrowings from the Bank with efforts at deposit mobilisation. During the year 1974-75, only 24 central co-operative banks did not get full rebate from the Bank under the Scheme.

264. During the year 1975-76, credit limits sanctioned by the Bank for financing agricultural operations to state cooperative banks increased to Rs. 612 crores from Rs. 490 crores in 1974-75. The increase of Rs. 122 crores in the short-term credit limits may be attributed mainly to the increased demand for fertilisers and other inputs in both the kharil and rabi seasons of 1975-76 and the newly introduced scheme of financing sugarcane cultivation of members of cane unions in U.P. by the primary credit societies.

265. As in the previous years, separate khartf and rabl limits were sanctioned in certain States where rabl was an important season. Supplementary credit limits sanctioned to 13 state co-operative banks on behalf of 152 central co-operative banks for the rabl season 1975-76 aggregated Rs. 87.4 ctores. Additional credit limits were also sanctioned to the Uttar Pradesh State Co-operative Bank for Rs. 19.2 crores on behalf of 28 central co-operative banks exclusively for financing sugarcane cultivation.

# Seasonality

266. Under the seasonality discipline first introduced in 1973, the banks were to some extent able to recover a major part of their advances made in the convention marketing period. This resulted in a perceptible fall in the level of their loans outstanding at the end of June 1976. All the state co-operative banks were advised that none of the central co-operative banks should be permitted after April 1, 1976 to draw on the credit limits sanctioned to them, unless the concerned central co-operative banks had recovered from societies at least a stipulated percentage, generally 40 per cent, of the demand as on March 31, 1976 and passed on that amount to the state co-operative bank. For this purpose, all the recoveries from July 1, 1975 till March 31, 1976 as well as conversions of short-term into medium-term loans granted, if any, were reckoned as recoveries. Wherever large supplementary credit limits were sanctioned, the drawals on short-term limits fater July 1, 1976 were to be regulated by a similar discipline of a minimum recovery performance.

# Marketing of Crops

267. The Bank also sanctioned short-term credit limits for marketing of crops during the year 1975-76 at 3 per cent above the Bank Rate. The sanction of these limits, however, was subject to the stipulations under the selective credit control measures of the Bank. The limits so sanctioned during 1975-76 aggregated Rs. 37.4 crores as against Rs. 40.3 crores during the year 1974-75. The marketing limits comprised

Rs. 1.9 crores as special limits for cotton and kapas covered by Bank's directives, Rs. 15.4 crores for cotton not covered by these directives and Rs. 20.0 crores to the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. for financing marketing of cotton and kapas under the monopoly procurement scheme of the Maharashtra Government.

#### Distribution of Fertilisers

268. The Bank continued to provide short-term credit limits to the state co-operative banks at 3 per cent above the Bank Rate for purchase, stocking and distributing fertilisers wherever the commercial banks were not able to meet the requirements in full.

#### Accommodation to Industrial Societies and Units

269. The Bank continued to provide financial accommodation to state co-operative banks at Bank Rate for financing industrial units outside the co-operative sector and industrial cooperative societies (other than weavers'). During the year, credit limits to the tune of Rs. 475.5 lakhs were sanctioned to 4 state co-operative banks on behalf of 22 district central and 13 primary (urban) co-operative banks.

#### Unwarranted Drawals

270. Unwarranted drawals on short-term agricultural limits by state co-operative banks continued to be discouraged during the year 1975-76. Suitable ceilings were fixed for each state co-operative bank for the call deposits it may maintain with other banks, and penal rates of interest were charged by the Reserve Bank wherever these ceilings were exceeded.

#### Selective Credit Controls

271. The restraints imposed during 1974-75 on advances against the security of cotton and kapas by the state and central co-operative banks and certain selected primary (urban) co-operative banks were continued during the period under review. In addition to the 14 urban co-operative banks in Gujarat and 8 in Karnataka covered last year, the directives in this regard covered 4 more banks in Gujarat.

# Credit Authorisation Scheme

# **Block Capital**

272. The Scheme requiring the state and central co-operative banks to obtain the Bank's prior authorisation for granting advances above Rs. 25 lakhs for meeting block capital requirements of manufacturing/processing units was continued during the year 1975-76. Under the Scheme, 11 state and central co-operative banks had approached the Bank for prior authorisation, as against 5 state and 4 central co-operative banks in the preceding year, for an amount of Rs. 2628.0 lakhs on behalf of 31 manufacturing/processing units. Authorisation, however, was granted to 10 state and 7 central co-operative banks involving an amount of Rs. 1752.7 lakhs on behalf of 24 manufacturing/processing units during the year, as compared to 4 state and 2 central co-operative banks for the previous year.

# Working Capital

273. In order to ensure that working capital advances to the non-agricultural sector are not granted indiscriminately, all the state and central co-operative banks were advised to obtain the Bank's prior authorisation in respect of advances to any single party in excess of Rs. 100 lakhs and Rs. 50 lakhs, respectively. These amounts were subsequently raised to Rs. 200 lakhs and Rs. 100 lakhs, respectively in the context of the general credit control policy announced by the Bank at the beginning of the busy season in November 1975. Specific norms in relation to the minimum margins and the rate of interest had also been prescribed for such loaning. During the year, 9 state and 25 central co-operative banks had asked for prior authorisation for an amount of Rs. 202.4 crores on behalf of 81 co-operative marketing, processing societies and consumer stores/societies. Authorisations, were granted to 9 state and 25 central co-operative banks involving an amount of Rs. 174.3 crores on behalf of 77 co-operative marketing, processing and consumer stores/societies.

274. In respect of the lendings of the state and central co-operative banks to co-operative sugar factories, advance

payments were to be confined to cane growers in respect of their cane being purchased by the factories only at the minimum prices fixed by the Government of India. This restriction was imposed to eliminate unhealthy competition for purchasing cane by factories particularly in Maharashtra and to minimise diversion of cane from the area of weak factories. For sanctioning short-term advances to co-operative sugar factories against the security of stocks of sugar, the minimum margin had been reduced from 25 per cent for pledge and 40 per cent for hypothecation for free sale sugar and 15 per cent for pledge and 25 per cent for hypothecation for levy sugar to a uniform minimum margin of 15 per cent. For this purpose, the stocks of levy sugar were to be valued at the levy price and stocks of free sale sugar at the tariff value fixed by the Government or at the market value, whichever was

# Financing of Consumer Stores

275. In view of the significant tole assigned to the consumers' co-operative in the distribution of essential commodities and controlled cloth in rural areas under the 20-point Economic Programme, the Government enlarged the scope of the Centrally Sponsored Scheme for consumer co-operatives under which funds were made available to the State Governments for strengthening the share capital of the consumer co-operatives to enable them to provide the margins prescribed on bank credit.

276. The Central Government also advised the State Governments to provide guarantee to the banks extending credit facilities to the consumer co-operatives.

277. In view of the modified Centrally Sponsored Scheme, the Bank advised Registrars of Co-operative Societies to allow the state/central co-operative banks to provide credit facilities to consumer co-operatives covered under the Scheme at a reduced margin of 10 per cent on the security of goods, on the condition that the State Government would fully guarantee the repayment of principal and payment of interest on the Joans.

278. The Conference of State Ministers for Co-operation held in September 1975 recommended that the urban co-operative banks which had surplus resources might finance consumer co-operative stores. The arrangements in this regard were finalised by the Bank in consultation with the Government of India. Although consumer co-operatives cannot become members of urban banks, the latter have been allowed to finance these as non-members with the permission of the Registrar of Co-operative Societies granted under the relative provisions of the State Co-operative Societies Act,

# Credit Guarantee Scheme for Small-scale Industries

279. The Credit Guarantee Scheme for Small-scale Industries was accepted by only 9 state co-operative banks, 4 industrial co-operative banks, 59 central co-operative banks and 40 primary (urban) co-operative banks till the end of November 1974. The working group constituted by the Credit Guarantee Corporation of India (February 1975) had suggested that the Credit Guarantee Organization should induce all banks, the eligible banks (numbering 25 state co-operative banks, 5 industrial co-operative banks, 343 central co-operative banks and 134 primary (urban) co-operative banks to join the Scheme. The Bank accordingly took up the matter with the concerned central co-operative banks directly as well as through the Registrars of Co-operative Societies with a view to pursuading them to join the Scheme early. Till June 30, 1976, 9 state co-operative banks, 68 central co-operative banks, 4 industrial co-operative banks, and 57 primary (urban) co-operative banks have joined the scheme by executing the necessary agreements.

# Coir Co-operatives

280. During the financial year 1975-76 credit limits amounting to Rs. 1569 lakhs comprising Rs. 45.9 lakhs for financing 22 primary coir societies. Rs. 84 lakhs for 4 central coir marketing societies and Rs. 27 lakhs for financing 8 manufacturing societies were sanctioned by the Bank.

#### Financing of Sericulturists

281. The institutional arrangements for financing the Crash Programme for the Development of Scriculture in Karnataka envisaged by the Bank provide for formation/reorganisation of 125 to 150 senculturists' societies, in five districts in the State to provide the entire range of credit facilities (i.e. short-term, medium and long-term) and technical assistance to their sericulturists as well as other agriculturist members. The State Government had, however, decided to organise 125 societies only for financing the programme, of which 64 societies had been registered. Sericulturists' societies, numbering 33 were allotted to the commercial banks and 12 societies to the cooperative banks for providing credit facilities to them 'The Agricultural Relinance and Development Corporation had also prepared guidelines for financing the programme through the commercial banks. The Bank sanctioned a medium-term credit limit of Rs 17.0 lakhs to the Karnataka State Co-operative Bank Ltd., on behalf of the Mysore District Co-operative Bank for financing the sericulturists' societies.

#### Medium-term Finance

282. During the year 1975-76, it was decided to treat the purchase of camels as an approved agricultural purpose for medium-term finance from the central financing agencies situated in the arid and semi-arid zoneo of Rajasthan where camels were being used as a substitute for bullocks for agrecultural operatios. It was also decided that medium-term loans for animal husbandry to non-agriculturist members of co-operative societies would be eligible for refinance from Reserve Bank of India. Hitherto, this facility was available only in respect of loan to agriculturist members. Further, the condition relating o security for medium-erm loan for sheep rearing, milch cattle and poultry farming were liberalished.

283. For the calendar year 1976, a tentative allocation of Rs. 20 crores was made for making medium-term agricultural advances out of the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund. The total medium-term credit limits sanctioned during the year 1975 amounted to only Rs. 11.6 crores. However, actual drawals by the state co-operative banks were Rs, 7.2 crores, the short-fall in the utilisation of the limits being mainly due to (a) over estimation of lending programmes by the banks and (b) a high level of overdues. The medium-term credit limits sanctioned to various state co-operative banks for the year 1976 aggregated Rs. 9.0 crores as on June 30, 1976.

284. During the co-operative year 1975-76, medium-term loans aggregating Rs, 3.0 crores were sanctioned to 2 state co-operative banks for the purpose of purchase of shares in co-operative sugar factories and other processing units.

# Handloom Finance

285. The Bank continued to provide financial accommodation to state co-operative banks for financing the production and marketing activities of handloom (cotton silk and woollen) weavers' societies and the powerloom weavers' societies at a concessional rate of 1.5 per cent per annum below the Bank Rate with the stipulation that the rate of interest charged to the hadloom weavers' societies should not exceed 7.5 per cent or such other rate of interest as may be fixed by the Government of India from time to time (in view of the Interest subsidy of 3 per cent provided by the Government of India).

286. The recommendation of the High Powered Study Team (1974) on the problems of Handloom Industry that credit limits to new handloom weavers' societies on a per loom basis should be raised, in view of the cost increases, was agreed upon. Consequently, the limits stand at present at Rs. 1,000 in respect of cotton handloom and Rs. 2,000 in regard to woollen handloom and silk handloom. The scale per loom for financing the new powerloom weavers' Idormant societies to be reactivised was also raised to Rs. 5,000. The limits for societies already operating continued to be assessed at 25 per cent of the estimated production or the amount worked out on per loom basis whichever was less.

# Loans for Shares in Co-operative Spinning Mills

287. The High Powered Study Teom on the problems of Handloom Industry also recommended that the Bank should give facilities for medium-term finance to weavers in order

to enable them to contribute to the share capital of co-operative spinning mills. Accordingly, the Bank conducted studies to find out the technical and economic feasibility of the proposition from the point of view of repaying capacity of individual weavers—handloom as well as powerlooms and primary weavers' societies. The Bank extended this facility on the basis of these studies only to individual powerloom owners/powerloom weavers' societies in January 1975.

# Loans from Long-term Operations (LTO) Fund

288. The Bank continued sanctioning loans to State Governments from the National Agricultural Credit (1.10) I and for contributing to the share capital of various types of co-operative credit institutions. The special relaxations in the norms laid down by the Bank for this purpose in respect of institutions, operating in the SFDA, MFAL tribal areas and in areas where the commercial banks financed primary agricultural credit societies and in the case of central cooperative banks under rehabilitation, were continued. During the year, certain additional relaxations were made in respect of primary agricultural credit societies in the tribal areas. Small-sized agricultural credit societies in these areas were considered for share capital contribution even if they had attained a loan business of only Rs, 30,000 and had a coverage of 100 borrowing members, provided the other essential conditions like the appointment of full-time paid secretaries, were satisfied Normath, a secrety to be eligible for share capital contribution is required to have a minimum loan business of Rs. 50,000 and a coverage of at least 150 borrowing members. Where the primary agricultural credit societies were undertaking supply of consumer requisites, additional share capital contribution in excess of the normal limit of Rs. 10,000 was sanctioned to enable the societies to undertake this business.

289. Loans aggregating Rs. 13.5 croies were advanced to the State Governments for contribution to the share capital of 7 state co-operative banks, 95 central co-operative banks, 2 central land development banks, 55 primary land development banks, 19 urban co-operative banks, 4,176 primary agricultural credit societies, 65 FSS and 20 LAMPS and the outstandings on this account as on March 31, 1976 amounted to Rs. 76.1 crores.

290. The Bank also sanctioned to the Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC), a long-term loan of Rs 40 crores from the Fund during 1974-75 and another Rs, 60 crores during 1975-76. Repayments and drawals during the year were Rs. 9.8 crores and Rs. 60 crores, respectively The outstandings as on June 30, 1976 were Rs. 1384 crores.

# Land Development Banks

291. The total lending programme of the central land development banks (CLDBs) for the financial year 1975-76 was fixed at Rs 229.5 crores out of which Rs. 26.6 crores were to be provided by the banks from their own resources and the balance by issuing debentures. The banks were to issue special development debentures under ARDC+-refinanced schemes to the extent of Rs 119.8 crores, ordinary debentures for Rs. 79.7 crores and rural debentures /collection of fixed deposits for Rs. 3.4 crores. As against the total approved deposits for Rs. 3.4 crores. As against the total approved deposits actually zoated to the tune of only Rs. 79.7 crores banks actually zoated to the tune of only Rs. 75.5 crores. Of the total subscriptions, Rs. 12.6 crores were subscribed by the Central and State Governments, Rs. 25.4 crores by institutional investors like the LIC and commercial banks Rs. 19.2 crores by the fand development banks and Rs. 8.2 crores by way of self-help.

292. For 1976-77, the total lending programme of the CLDBs was placed at Rs. 284.4 erores. The ordinary lending programme was envisaged to involve Rs. 1212 erores, which was to be financed upto Rs. 332 erores by the banks from out of their internal resources and the remainder by way of floatation of ordinary debentures. Assuming that the CLDBs would raise resources to the extent of Rs. 6 erores by way of self-help, the balance of Rs. 82 erores was expected to be subscribed by the other agencies (mutual support sinking fund investment Rs. 40 erores, LIC Rs. 15 grores Central and State Governments Rs. 12 erores and Commercial Banks Rs. 15 erores).

- 293. With a view to mitigating the difficulties experienced by CIDBs in the regulation of advances to primaries/branches in accordance with the revised recovery norms, the Bank and the ARDC, after considering the recommendations made by the Standing Committee on Debenture Norms (constituted by the Governor) permitted the banks to fulfil their commitments under second and subsequent instalments, in respect of loans granted between Lanuary 1 1974 and September 1, 75 in excess of their loan eligibility, subject to the condition that disbursements of the second and subsequent instalments were completed before 30, 1976. In the case of loans for minor irrigation works given prior to January 1, 1974, the second and subsequent instalments on account of the cost of electric pumpset and its installation were allowed to be disbursed up to June 30, 1976, provided the original sanction was for a composite purpose, i.e., tor well and electric pumpset could not be availed of because of non-availability of electric connection,
- 294. As a measure of relief, the Bank and the ARDC allowed certain relaxations in the matter of regulation of advances where there was crop failure on account of natural calamities.
- 295. The other important policy developments during the year were as under:
- (i) The entire scheme for floatation of fittal debentutes by CLDBs first introduced in 1957 was reviewed by the Agricultural Credit Board of the Bank at its meeting on August 7, 1975 and it was decided that the floatation of fittal debenture might, in future, be undertaken on a voluntary basis instead of being mandatory. Under the new scheme, rural debentures would be issued without State Government guarantee but at a higher rate of interest and without any contribution thereto from the Bank.
- (ii) As per the pattern of investment of sinking funds prescribed by the Bank, CLDBs should invest not less than 20 per cent of their sinking tunds in Government and trustee securities including a minimum investment of 10 per cent in Government securities. The banks have been permitted to invest their sinking funds in the units of the Unit Trust of India on the condition that investment in the units should not exceed 5 per cent of the total investments of the sinking fund.
- (ni) In the last Report a reference was made to the important recommendations contained in the Report of the Committee on Co-operative I and Development Banks, These recommendations were placed for consideration of the Agricultural Credit Board of the Bank at its meeting held on August 7, 1975. The State Governments have been advised to initiate action on the general and specific recommendations of the Committee. Further, the Government of India at the Bank's request have also addressed the State Covernments impressing on them the need to implement the recommendations early in order to improve the operational and linancial efficiency of the land development banks.
- (iv) A Standing Committee on Debenture Norms under the Chairmanship of the Bank's Executive Director was also constituted for evolving uniform procedures for the floatation of ordinary and special debentures

# Reorganisation at the Primary Level

296. During the year, efforts were continued to quicken the pace of reorganisation of the co-operative credit structure at the base level. Most of the State Governments had drawn up plans of action to bring about viable primary agricultural credit societies.

297. A meeting of the Registrats of Co-operative Societies of some States and the representatives of the Government of India and the commercial banks was convened on May 4, 1976 to discuss the procedural and other problems relating to the reorganisation of primary agricultural credit, and amalgamation of non-viable societies with the reorganised societies or with the newly formed Parimers' Service Societies of Large Sized Multipurpose. Societies or ganised in tribal areas. Following the decisions taken at this meeting, the State Governments were advised to ensure that ordinarily

every reorganised primary agricultural credit society should cover a gross cropped area of 2,000 hectares and within a radius of 10 kms. Certain norms were also indicated for the existing societies which might be amalgamated with the reorganised society or for those that might be liquidated. The state co-operative societies' acts were, however, required to be amended with a view to empowering the Registral to carry out the process of amalgamation of non-viable societies expeditiously.

# Unification of Short-term and Long-term Structures

298. The Agricultural Credit Board which considered at its Seventh meeting the question of integration of short-term and long-term credit structures in the co-operative credit movement was of the view that in smaller States such an integration at all levels could be done but in other States the unification atteast at the primary level could be considered. The reaction of the State Governments had been favourable so far as integration at the primary level on a selective basis was concerned. The issue of integration of the two structures would, however, be considered in all its as pects by the Committee on Integration of Co-operative Credit Institutions consituted by the Governor in September 1975 with a Deputy Governor as Chairman. The Committee in expected to submit its report shortly.

#### Financing of Weaker Sections

299. During the year 1975-76, the state co-operative banks were advised to ensure that not less than 20 per cent of the central co-operative banks' advances to primary credit societies were issued for financing small/economically weak farmers. Diawals on the credit limits in excess of the free portion (generally 60 to 70 per cent of the limit) were required to be matched by corresponding advances issued to societies for financing such farmers.

#### Debt Relief and Consumption Loans

300 In pursuance of the 20-point Economic Programme, many State Governments have passed legislation for moratorium, discharge or scaling down of debts incurred by small farmers, marginal farmers, agricultural labourer, and rural artisans from private money lenders. These measures were expected to result in drying up the credit line from non-institutional sources. The Inter-Ministerial Group, which was appointed by the Government of India to prepare a plan for liquidation of rural indebtedness and a model legislation in this behalf, had estimated that the credit gap required to be filled in as a result of the debt relief measures would be of the order of Rs. 300 crores per year for a period of 3 years.

301 With a view to making alternate sources of institutional credit available to the borrowers affected by debt relief measures, the Bank's policy in regard to provision of accommodation by co-operative banks for consumption purposes was modified recently. Accordingly, loans for consumption purposes were allowed along with production credit to farmer-members of primary credit societies belonging to the weaker sections for specified purposes like medical aid, education death ceremonies, marriages (exchiding dowry) etc. The quantum of such loan was, however, limited to 10 per cent of the total short-term advances or Rs. 250 per member whichever was less. The Bank had also reviewed its policy in regard to the central co-operative banks granting direct loans to individuals against the security of gold and silver ornaments for consumption and such other purposes and they were permitted to grant such loans not exceeding Rs. 1000 per borrower. The aggregate of the loans and advances of all types against individuals should, however, not exceed 10 per cent of the bank's total time and demand liabilities.

302. Consequent upon the rural debt relief measures taken by the State Governments, the Government of India had constituted an Expert Committee with Shri B. Sivaraman, Member, Planning Commission, as Chairman and the Executive Director, Reserve Bank of India, in charge of agricultural credit as one of its members. The Committee has come to the conclusion that by and large non-institutional sources of credit for weaker sections of the community had dried up substantially in the wake of the recent debt relief

legislation passed by various States and has, therefore, suggested that the consumption credit requirements of this group of borrowers might be provided by institutional agencies. The other recommendations of the Committee are:

- (1) The institutional agency best suited for purveying consumption credit is the primary agricultural credit society, farmers service society and large-sized multi-purpose society in tribal areas, each having a full-time paid secretary or managing director.
- (ii) The re-organisation of primary credit societies, appointment of secretaries, toning up of loan recovery system should be pushed through and introduction of universal membership introduced so that the co-operatives at the village level serve as effective agencies for this purpose.
- (iii) The central co-operative banks would finance the reorganised societies/LAMPS for the purpose of issuing consumption loans. In areas where farmers' service societies or reorganised societies were financed by commercial banks or regional rural banks, the latter would provide consumption finance also through such societies.
- (iv) In areas not covered by re-organized societies, farmers' service societies or large sized multi-purpose societies the State Governments themselves should take steps to provide consumption credit to individuals directly through their revenue or other administrative departments.
- (v) Of the estimated consumption credit requirements of the order of Rs. 170 crores for the first year of operations, primary co-operatives would provide Rs. 70 crores, while the State Governments would provide Rs. 100 crores.
- 303 Steps are being taken by the Government of India, the Bank and the State Governments to implement the recommendations of the Committee.

# SFDA/MFAL Schemes

304. Till the end of November 1975 as many as 12.5 lakhs of small and marginal farmers and agricultural/landless labourers were identified as eligible for benefits under the Scheme. Of these 6.1 lakhs were enrolled as members of co-operatives, During the period July 1975 to November 1975, short-term loans to the extent of Rs. 19.3 crores were disbursed to these members through co-operatives while Rs. 2.0 crores were disbursed through commercial banks during the period April 1, 1975 to November 1, 1975. In addition, medium-term and long-term loans to the tune of Rs. 8.4 crores have been issued to them by co-operative banks since the inception of the projects. The term-loans sanctioned by commercial banks during the same period amounted to Rs 4.3 crores.

# Commercial Banks' Finance for Credit Societies

305. The Scheme of financing primary agricultural credit societies by commercial banks, introduced in 1970 was in operation in 11 States at the end of December 1975, viz., Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Jammu & Kashmir, Kamataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam. It has beer decided to introduce the Scheme in Rajasthan also.

306 As at the end of December 1975, 22 commercial banks participating in the Scheme through their 462 branches, in 11 States, had taken over 3,266 primary agricultural credit societies. The average number of societies per branch, taken as a whole, worked out to 7 as against the norm of 10 societies per branch envisaged for operational viability and optimum use of the field staff at branch level. The commercial banks had provided short-term loans to 1,813 societies to the extent of Rs 12.6 crores in kharif 1975 and Rs. 2.4 crores for rabi 1975-76 till December 31, 1975. Besides, the banks had disbursed medium-term loans aggregating Rs 70.9 lakhs to 259 societies upto December 1975.

- ___ -

# Weak Co-operative Banks: Rehabilitation of

307. During the year, under the Central Sector Scheme for rehabilitation of weak co-operative banks, the Government of India had sanctioned assistance of Rs. 50.2 lakhs to 11 central co-operative banks. Till June 30, 1976, the Government of India had released to the State Governments a sum of Rs. 22.2 lakhs as their share of the assistance on behalt of the concerned central co-operative banks. The Manipur, Tripura and Himachal Pradesh State Co-operative Banks functioning in the area served by two tier credit structure were also approved for assistance under the Scheme and an amount of Rs. 9.2 lakhs was released during the year.

308 The programme of rehabilitation of primary co-operative banks, primary land development banks and branches of state land development banks continued during the period under review i.e., 1975-76. Based on their financial positions as on June 30, 1974, 46 primary co-operative banks, 130 primary land development banks and 124 branches of central land development banks were under the rehabilitation programme.

# Removal of Regional Imbalances

309. The Central Government continued to grant assistance during 1975-76 to the central co-operative banks in group C States (co-operatively weak States) for meeting the expected deficits in their resources required to cover the overdues During the year under review, a sum of Rs. 175 lakhs was provided by the Central Government under this Scheme to 23 central and one state co-operative banks in 5 States. Matching contributions were made by the concerned State Governments.

# Study Teams

#### On Overdues

310 As mentioned in the last year's Report, the various recommendations of the Study Team on Overdues were communicated to the State Government and state co-operative banks for necessary action. Most of the States have generally accepted the recommendations.

# On Rajasthan

311. A reference was made in the previous Report to the Study Team on Agricultural Credit Institutions in Rajasthan giving the main findings of the Team. The implementation of the various recommendations was followed up with the representatives of the State Government, state/central co-operative banks and the commercial banks by the Bank's Executive Director in January 1976. The State Government had initiated action on the various recommendations. The state co-operative bank had accepted the recommendations concerning it with certain amendments.

# On Madhya Pradesh

312. The Study Team on Institutional Arrangements for Agricultural Credit in Madhya Pradesh finalised its report on April 24, 1976.

# On Agricultural Credit in Sikkim

- 313. Consequent or Sikkim becoming the twenty-second State of the Indian Union on April 26, 1975, the Government of India, in the Ministry of Agriculture and Irrigation constituted in August 1975 a Team under the Chairmanship of Executive Director of the Bank in charge of Agricultural Credit Department to study the agricultural credit situation and institutions in the State and to make recommendations on various related aspects. The Team was also advised to look into the possibility of conversion of the State Bank of Sikkim—which was functioning in Sikkim since 1968 into a Regional Rural Bank. The Chairman submitted the Team's manimous report to the Government of India in February 1976.
- 314. The primary concern of the Team was the set-up of institutions at the grassroot level which could provide banking and credit facilities throughout the territory of Sikkim. The Team has evolved a plan of kovering the entire State with 35 primary agricultural credit societies with membership of about 20,000 Taking a five year view, the Team felt that the development of a loan business of at least about Rs. 1

- crore by all the units put together was possible. The co-operatives envisaged by the Leam will be multi-purpose in character. The Team also recommended that four of the 35 units at the rate of one in each district, with a relatively larger potential, should be developed into fullfledged farmers' service societies.
- 315 As for the banking institution at the state level, its role of functions, and the manner in which it should be brought into being, the Team recommended the setting up of a state co-operative bank of a some-what unorthodox character. The state co-operative bank would, unlike its counterparts in the rest of the country, provide all types of credit for agriculture through co-operatives and directly for trade, commerce and industry, besides transacting Government business. The Team further recommended that it would be appropriate if the undertaking of the State Bank of Sikkim was transferred to the proposed Sikkim State Co-operative Bank.
- 316. The Study Team had also recommended that a small committee might be set up to draft legislation for the transfer of the undertaking of the State Bank of Sikkim to the Sikkim State Co-operative Bank and also for drafting a comprehensive Co-operative Societies Act as well as the by-laws of the proposed state co-operative bank. The implementation of its recommendations was also to be supervised continuously for some time by a state level committee constituted for the purpose by the State Government with representation of the Government of India and the Reserve Bank of India.
- 317. The Study Team's report was considered by the Agricultural Credit Board in its ninth meeting held on April 20, 1976. The recommendations of the Team were broadly accepted by the Agricultural Credit Board except the recommendation regarding the banking arrangement at the state level. The Board had referred the issue to be reviewed by a small committee.

# On Staffing Pattern of State and Central Co-operative Banks

318 The ACD conducted a study of the staffing pattern of West Bengal State Co-operative Bank and the pattern obtaining in the state and certial co-operative banks in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. The reports on these studies indicating the deficiencies in the existing staffing pattern and recommending the remedial measures covering various aspects such as the appropriate staffing pattern at different levels, recruitment and training etc. had been forwarded to the banks and to the concerned State Governments.

# Co-operative Banking Regulation

- 319. During the year, licences were granted to one central co-operative bank and twenty-four primary co-operative banks under section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 authorising them to carry on banking business in India. The total number of licensed state, central and primary (turban) co-operative banks stood at 98 as at the end of the year as against 73 in the previous year. Licences were refused to 7 primary (urban) co-operative banks as they were organised in heavily banked centres and as such were not likely to be viable units.
- 320 The number of offices of co-operative banks in the country which stood at 6,102 as on September 30, 1973 mercased to 7,001 as on June 30, 1975 and 7,288 [293 offices of state co-operative banks, 5,376 of central co-operative banks and 1,406 mimary (mban) co-operative banks and 213 primary (salary carners' type)] as on June 30, 1976.
- 321. During the year, 73 licences were issued to state co-operative banks and primary co-operative banks for opening new offices as against 59 licences granted during the previous year.
- 322. As on June 30, 1976, there were 1,531 co-operative banks (28 state 370 central and 1 133 primary co-operative banks) coming under the purview of the Banking Regulation Act, 1949 as against 1,494 co-operative banks as at the beginning of the year.
- 323 There were 10 central co-operative banks not complying with the provisions of section 11(1) of the B.R. Act. 1949. Of these, 7 central co-operative banks were in

Assam and the State Government has taken a decision to merge them with the Assam Cooperative Apex Bank Itd. The remaining 3 central co-operative banks were mider a programme of rehabilitation. Of the 23 parmary co-operative banks, which failed to comply with section 11(1) of the said B.R. Act, 3 banks have been subsequently placed under liquidation and 3 banks have been refused hierore.

324. During the year, 802 co-operative banks [23 state, 225 central, 527 primary (urban), 14 state land development banks and 13 apex weavers /marketing societies] were inspected. Of these, 108 inspections of primary (urban) co-operative banks were conducted by the officers of state co-operative banks on behalf of the Bank under section 35(1) of the Banking Regulation Act, 1949. Reports relating to inspections of 23 state co-operative banks, 292 central co-operative banks, 623 primary (urban) co-operative banks, 10 state land development banks and 9 apex weavers, marketing societies were issued during the year. Many primary co-operative banks had applied for licences to open branches at places outside their district or even State. In such cases the banks were required to (i) provide in the bylaws for representation for the branches on the board of directors, (ii) remove qualification shares for directors, (iii) do away with the practice of admitting regular borrowers as nominal members and (iv) provide for the linking of share holding by a member to his borrowings at the prescribed ratios

#### Doubtful Debts

325. A meeting of some of the Registrars of Co-operative Societies was convened in the Agricultural Credit Department of the Bank in November 1975 to consider modifications to the existing guidelines for the assessment of bad and doubtful debts and other assets of primary agricultural credit societies and central co-operative banks by the departmental auditors. On the basis of the conclusions reached at the meeting and ad hoc studies subsequently coducted by some of the Regional Offices of the Bank, the guidelines have been revised and are being issued to the Registrars of Co-operative Societies.

# Deposit Insurance Scheme

326. During the year, the Deposit Insurance Scheme was extended to co-operative banks in the State of Tripura with effect from November 1, 1975. With the introduction of the Scheme in Tripura the number of States and Union Territories where the Scheme had been extended lose to 6 and 3, respectively as at the end of June 1976. The States of West Bengal, Rajasthan and Karnataka had passed the necessary amendments to their Co-operative Societies Acts vesting in the Bank, powers, among others, in regard to supersession, winding up, amalgamation, reconstruction etc. Steps were being taken to extend Deposit Insurance Schemes to co-operative banks in these States. The question of amending the Co-operative Societies Act in the remaining States to facilitate the extension of Deposit Insurance Scheme was being pursued with the State Governments concerned.

327. As on June 30, 1976, there were 537 registered insured co-operative banks comprising 9 state co-operative banks, 111 central co-operative banks, 375 urban banks and 42 salary earners' societies.

# Other Items

# Co-operative Movement in Individual States

328. The Agricultural Credit Department of the Bank continued the practice of holding annual discussions with the representatives of the State Covernments regarding different problems facing the co-operative movement in the individual States and for suggesting suitable alleviating measures/lines of action. During the year 1975-76, discussions were held with the representatives of the States/Union Territorics of Assam, Gujarat, Haryana, Maharashtra, Manipur Nagaland, Rajasthan, Tiripura, West Bengal, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Delhi and Mizoram.

# Regional Rural Banks

329. Reference has already been made in Part II to the setting up of Regional Rural Banks. So far, 19 Regional Rural Banks were set up. A Steering Committee has been set up by the Government of India with Shri B. Sivaraman

as Chairman and the Executive I nector of the RBI as the of the members to punde the functioning of these banks. Special studies were being conducted by the Agricultural Credit Department of the Bank with a view to making available to the Steering Committee as well as the Government of India data on (i) the are is appropriate for setting up the Regional Rural Banks-(ii) the economics of such banks with reference to credit potential especially in respect of weaker sections and (iii) the scope for organising farmers. Service Societies in the areas of the Regional Rural Banks. In all, particulars in respect of 97 districts have so far been furnished to the Government of India with a view to enabling the selection of appropriate areas for setting up Regional Rural Banks. The Committee has so far identified 39 centres for setting up Regional Rural Banks.

#### Committee on Co-operative Statistics

330. A committee for reviewing the collection and processing of statistics relating to the Co-operative Movement in India, was constituted by the Government of India. The tourth meeting of the Committee on Co-operative Statistics was held in the Agricultural Credit Department, on July 29, 1975 where further suggestions for revision/modification of the existing proforma tables prescribed for the statistical statemen's, inclusion of new proforma tables, bringing out of the publication in time, etc., were considered.

# Agricultural Relinance and Development Corporation (ARDC)

331. The 'Agricultural Refinance Corporation' changed its name to 'Agricultural Refinance and Development Corporation' when the amendments to the Agricultural Refinance Corporation Act as passed by Parliament were put into effect from November 15, 1975. With this change, the promotional and developmental roles already being undertaken by the Corporation were put on a formal basis.

#### Operations

332 During the year 1975-76 (July-June) the Corporation disbursed refinance of Rs. 171.2 crores as against Rs. 106.4 crores disbursed in 1974-75. Gross disbursement of refinance of the Corporation since inception and upto the end of June 1976 amounted to Rs. 594.2 crores. Of this, disbursement under the IDA Projects was Rs. 320.8 crores or nearly 54 per cent. Increase in disbursement was mainly due to brisk lending under the farm mechanisation component (both under IDA Projects and outside) and alround increase in the disbursement for other diversified purposes. Disbursement during the year under IDA-aided Projects was Rs. 132.4 crores as against Rz. 61.9 crores in 1974-75.

333 During 1975-76, the Corporation sanctioned 909 schemes with a commitment of Rs. 296.9 crores, as against 623 schemes with a commitment of Rs. 204.4 crores sanctioned in the previous year. The trend in favour of diversification of business of the Corporation from minor irrigation to other purposes witnessed in the last year was continued, with farm mechanisation schemes accounting for a substantial portion of the refinance sanctioned by the Corporation during the year. Dairy development, fisheries, poultry and sheep breeding, plantation and horticulture, and storage and market yards also accounted for a size ble number of schemes. As many as 499 schemes with a commitment of Rs. 130 crores were sanctioned for purposes other than minor irrigation, as against 320 schemes with a commitment of Rs. 56 crores sanctioned during the previous year. At the end of June 1976, the Corporation has sanctioned 2 905 schemes involving refinance of Rs. 1147 crores.

334. During 1975-76, Uttar Pradesh availed of the largest amount of refinance (Rs. 260 crores, Maharashtra came next (Rs. 225 crores) followed by Karnataka and Madhya Pradesh (Rs. 19 crores each). Areawise, the Southern region accounted for 302 per cent of the gross disbursement of refinance, followed by the Central region (216 per cent), Northern region (21.0 per cent), Western region (20.2 per cent) and Eastern and North-Fastern regions (7.0 per cent).

### Regional Imbalances

335. For its review purposes, the Corporation had categorised the States of Ultar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihai, West Bengal, Orissa, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmi, Assam and the other States in the North-Eastern region as relatively less developed areas which require special attention. Due to special efforts, the States of Ultar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar could avail of 34.1 per cent of the total relinance from the ARDC during the year. Substantial amounts were committed in West Bengal both under IDA Schemes and outside. In Orissa, with ARDC's commitment of Rs. 39 crores, progress is expected to be faster. Fastern Foodgrains Project' now being formulated by the World Bank contemplates substantial investments in West Bengal, Orissa, Assam and Bihar in fields such as groundwater exploitation, command area development and research and extension. At the end of June 1976, 1,083 schemes involving Corporation's commitment of Rs. 493 crores had been sanctioned in the less developed areas. Of these, the financing institutions have so far drawn Rs. 186.6 crores.

336. The ARDC Act, has been extended to Sikkim also and the State Government has been advised of the refinance facilities available from the Corporation.

#### SFDA/MFAL Schemes

337. At the end of June 1976, schemes sanctioned under the aegis of SFD/MFAL Agencies totalled 158 with the Corporation's commitment of Rs. 50 crores. The Corporation has so far disbursed Rs. 20 crores under these schemes. However, the Corporation recently reviewed its policy of granting 100 per cent refinance in repart to these schemes. Taking into account its own resources position and other relevant factors, the Corporation has decided to grant only 90 per cent refinance under these schemes beginning from April 1, 1976

#### Disbursement of Refinance by Agency

338. Agency-wise, the land development banks continued to account for the major portion of the refinance availed of from the Corporation at Rs. 991 crores during 1975-76. Commercial banks availed of Rs. 70.8 crores (41.3 per cent of total during the year. This increased participation is a combined result of the deliberate attempts by commercial banks to provide larger term-credit for agricultural development and the Corporation's own efforts to provide larger refinance facilities.

## IDA/IBRD Projects

339. During the year the World Bank Group sanctioned three more projects viz., Integrated Cotton Development Project, Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project and the National Seed Project for agricultural development. The Integrated Cotton Development Project envisages an integrated development including production of improved varieties of cotton and processing, production of improved foundation seeds and research. A seasonal credit fund will be set up in ARDC for providing short-term credit to the farmers in the selected areas for growing improved variety of cotton through commercial/co-operative banks. So far, the World Bank Group has sanctioned 25 projects under which funds for ontarm investments are being routed through the ARDC. These comprise 11 agricultural credit projects, 4 command area development projects, 3 dairy development projects, 2 market vards project, an integrated cotton development project and a general line of credit to the ARDC. Four project and a general line of credit to the ARDC. Four project namely. Tanai Seeds Project, National Seed Project, Chambal Command Area Development Composite Project are being financed by the IBRD, while the remaining projects are being assisted by the IDA.

340. Mention was made in the last Report about the sanctioning of a general line of credit (\$ 75 million) to the ARDC by the IDA covering investments in minor irrigation and other approved diversified purposes. Of the sanctioned amount, the Corporation had commitments to the extent of Rs. 264 crores. Disbusements upto the end of June 1976 amounted to Rs. 47 crores as against the expected level of Rs. 24 crores, and the Corporation hopes to 25 GI/77 -19

complete the entire programme by the end of June 1977. Financing of tractors by ARDC amounted to Rs. 35.7 crores. In addition, Guitarat and Maharashtra Agricultural Credit Projects have been fully implemented.

## Important Policy Decisions

341. The Corporation took a decision to allow the memberbanks to provide funds for energisation of wells directly to the various State Flectricity Boards (SEBs), relating the quantum to the number of pumpsets energised by the SFBs under the minor irrigation schemes approved by it, thus excluding in the process, areas covered by the schemes of the Rural Electrification Corporation Ltd., and other agencies. This is in modification of the earlier procedure by which refinance was made available by the Corporation to the financing institutions in respect of loans granted by them to cultivators to enable them to keep deposits with the SFBs for energisation.

342. As an incentive, the Corporation has agreed to a reduced contribution of 10 per cent by the respective State Covernments in regard to special development debentures floated under minor irrigation schemes sanctioned to state lend development banks (SLDBs) as against 25 per cent contribution stipulated for other types of schemes. This concession which was made available from August 1967 has since been extended upto the end of the Fifth Five Year Plan period i.e., 1978-79, in view of the importance of minor irrigation programmes in agricultural development.

343. One of the problems encountered in command area development was financing farmers who were not having valid titles to lands or who were protected tenants or illegal occupants. Under the command area programme the entire area has to be developed and no portion is to be left out if full benefit is to be derived. The Government of India and the ARDC have therefore evolved a system by which such 'incligible' farmers could be provided funds for development. Detailed guidelines have been issued by the ARDC in this regard.

## Amendments to ARC Act

344. The various amendments to the ARC Act, 1963 which were passed by Parliament in July-August 1975, came into effect from November 15, 1975. The important amendments related to enlargement of the definition of an eligible institution, provision for raising the authorised share capital to Rs. 100 crores, an enabling provision for receiving gifts, grants, donations, amendment to the existing provision for purchase and sale of bonds, guaranteeing deferred payments for purchase of capital goods from inside and outside India and waiver of security for reflaance. In terms of one of the amendments, the Corporation can provide refinance against working capital funds also. The ARDC has since decided to provide refinance against working capital tunds in selected integrated schemes of development such the Integrated Cotton Development Project and sericulture schemes.

## Training

345. In order to advise the ARDC on various aspects of the training programmes, a Committee has been set up, headed by the Chairman, ARDC and comprising representatives of the Government of India, National Institute of Bank Management, National Co-operative Union of India, LDBs' I education and commercial banks. As part of the ARDC Credit Project, training programmes of tour weeks duration are being conducted at the College of Agricultural Banking, Punc, for the senior and middle level staff of IDBs and other agencies connected with project implementation. So far, 10 agricultural project courses have been conducted giving benefit to 305 participants.

346. The ARDC has also, with the help of representatives of the state land development banks, completed a study of the training requirements of the junior level LDB staff.

## Workshops

347. Short-term training programmes were conducted in Jaipur, Bhopal and Bangalore for officers of participating

banks and others on procedural and operational matters relating to dairy development projects being implemented in the States of Rajasthan, Madhya Pradesh and Karnataka. A familiarisation workshop was also conducted in Jaipur during the first week of December 1975 to acquaint the officials with the 10le of the Corporation in linancing agricultural development programmes.

## Committee for Studing Feasibility of Integration of Short-Term and Long-Term Co-operative Credit Institutions.

348. A Committee under the Chairmanship of Deputy Governor was set up by RBI to examine the feasibility of integrating the short-term and long-term co-operative credit institutions. The secretariat is in the ARDC and the work of the committee is in progress.

#### Norms for LDB Debentures

349. A Standing Committee has been set up by the RBI for the purpose of monitoring LDBs financial performance and the issuance of all LDB debentures. The Committee will also make a study of the requirements for the issuance of all LDB debentures as well as the most efficient ways of implementing such requirements. On the basis of the deliberations of this Committee, certain relaxations in the overdues criteria prescribed for regulating the lending programme of land development banks have been given to the SLDBs for covering the undisbursed instalments of committed loans during 1975-76.

## IV. DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE

- 350. In the sphere of industrial finance, the year 1975-76 witnessed a further rise in the financial assistance provided by the term-lending institutions, which was reflected in both sanctions and disbursements. Total sanctions during the financial year 1975-76 rose to Rs. 589.8 crores from Rs. 498.8 crores in 1974-75, while total disbursements rose from Rs. 363.3 crores in 1974-75 to Rs. 400.6 crores in 1975-76 (Table 29). The Industrial Development Bank of India (IDBI) and State Financial Corporations (SFCs) accounted for bulk of the increase in total assistance both in terms of sanctions and disbursements.
- 351. In the following pages, the trends in lending of institutions like the IDBI, SFCs and the UTI are discussed. At the end of this Part, finances of non-banking companies are discussed.

## Industrial Development Bank of India

- 352. In order to enlarge the role of the IDBI as the spex financial institution and to achieve more effective coordination among all financial institutions in the country, IDBI was delinked from the Reserve Bank of India with effect from February 16, 1976 and made an autonomous Corporation owned by the Government of India.
- 353. The emphasis of the IDBI in the immediate future would be on the programmes designed to extend assistance to small and new entrepreneurs and to enterprises located in relatively underdeveloped regions in the country, projects which use indigenous technology and have greater employment potential, projects which earn or save foreign exchange and all other projects accorded priority in the national programmes for economic development.
- 354. In order to expedite assistance to these priority areas, the IDBI Board at its first meeting after delinking, effected substantial decentralisation of the bank's operations. With these changes and delegation of power, regional and branch offices of IDBI will be fully empowered to meet the requirements of small and small-medium units.
- 355 The organisational structure of the IDBI at the Head Office has also been revamped. IDBI has benefited considerably in this regard from the recommendations of the Narasimham Committee on IDBI procedures and of the Kumar Committee on term export financing. The principal functions and operations of the bank have been entrusted to two separate wings—the Domestic Finance Wing and the International Finance Wing.

356. Consequent on restructuring of the IDBI and its organisational set up, IDBI is undertaking several new lines of activities. State Industrial Development Corporations (SIDCs) were brought under the purview of IDBI's activities so as to promote through these agencies balanced regional development, especially by encouraging location of projects in backward areas. With a view to enabling technicians and new entrepreneurs to secure funds for contributing minimum level of equity expected of them, IDBI is giving consideration to introduce a scheme of this type in respect of directly assisted projects. A new scheme for providing financial facilities at concessional rates to state level agencies which are supplying machinery on hire-prochase basis, is being initiated. Liberalisation of assistance to road transport operators under refinance and bills rediscounting schemes is also being effected.

#### Foreign Lines of Credit

- 357. The first line of credit of US \$ 25 million from IDA for on-lending to SFCs, which became effective in June 1973, was fully committed by March 1976. Encouraged by the performance, the World Bank has agreed to grant another line of credit for \$ 40 million and negotiations in this behalf have already been completed. Thus, IDBI would now be in a better position to meet the foreign exchange requirements of small and medium-sized projects, through the State Financial Corporations.
- 358. IDA has also granted to IDBI another line of credit in December 1975 for \$ 24 million for assisting specific private sector fertiliser projects for their modernisation, purchase of balancing equipment, etc. The negotiations are also under progress with the IDA for a separate line of credit to meet the foreign exchange requirements of medium-sized projects (i.e. those with fixed assets upto Rs. 20 crores) in the public and joint sectors.

### Promotional Activities

- 359. Another important aspect of the recognised set-up of the IDBI is the creation of a Regional Development Wing with sells in all the four regional offices to help promote industrial development of backward areas. The Development Wing has taken on hand the task of setting up consultancy organisations in Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmii, Oissa, Rajasthan and Uttar Pradesh.
- 360. During the period under review, the survey report on Andaman and Nicobar Islands was published. Thus the surveys of all the 18 notified backward States/Union Territories have been completed and the survey reports published. It has also been decided to undertake an industrial potential survey of Sikkim and preliminary discussions with the officials of the State Government are scheduled to be held shortly.
- 361. With the formation of Inter-Institutional Group (IIG) in Maharashtra in June 1975, IIGS now function in 17 States in the country. Most of the IIGs have succeeded in creating effective machinery for co-ordinating and fortifying efforts of various state level organisations.
- 362. Joint institutional study teams had identified in all 483 projects involving an aggregate investment of about Rs. 2,800 crores. Of these, as at the end of December 1975, 78 projects involving capital investment of about Rs. 285 crores have either been implemented or are under implementation. IDB1 continued to watch the performance of state level agencies/State Governments in regard to the implementation of identified projects recommended by the joint institutional study teams and the State IIGs and the offices are advised to pursue these projects.

# TABLE 29 :—ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY TERM FINANCING INSTITUTIONS DURING 1974-75 AND 1975-76 (APRIL-MARCH)

(Amounts in Rupees Crores)

						S	anctions					
T - 434 A - 4		Rupee	Loans	Foreign Lo			Underwri Direct Subs	_	+	Total		
Institutions	Institutions — 19			1974-75	1975-76	Ordinary rence Sh		Debent	ures			
						1974-75	1975-76	1974-75	1975-76	1974-75	1975-76	
1	••	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.D.B.I		214.83*	253.76*			6,00	7.25	3 00		223.83*	261.01*	
		(62.85)	(110.41)							(62.85)	(110.41)	
I.F.C.I.		22.22	42.94	3.52	4.95	3.50	3,61		1.00	29.24	52.50	
I.C.I.C.I		16.00	20.43	41.29\$	45.20\$	3.77	6.05	1.80	6.87	62.86	78.55	
I.R.C.I.**		7.59	5.27						• •	7.59	5.27	
S. FCs***		132.61	142.87	8.63	12.34	0.55	0.29			141.79	155.50	
S.I.D.Cs*** .		21.34	28.00			12.16	9.00	• •		33.50	37.00	
Total .		414.59 (62.85)	493.27 (110.41)	53.44	62.49	25.98	26.20	4.80	7.87	498.81 (62.85)	589.83 (110.41)	
U.T.I	,					3.18	2.04	3.78	5.75	6.96	7.79	
L.I.C.***	•	21.22	30.53		• •	5.57	5.79	17.01	27.65	43.80	63.97	

		•	Rupec	Loans+	Foreign loa	currency ns		Underw Direct Subs	riting and scriptions		Tot	!	
			1974-75	1974-75 1975-76 1		1975-76	Ordinary ference S		Debent	ures			
							1974-75	1975-76	1974-75	1975-76	1974-75	1975-76	
I.D.B.I.			163.85* (35.09)	169,49* (59,48)			1.72	5.24	0.99	0.24	166.56* (35.09)	174.97 (59.48)	
I.F.C.I.			32.50	30,18	3,38	2.47	0.83	1.99	0.14		36.95	34.64	
I.C.I.C.I.			13.71	16.31	29.09\$	39.95\$	1.82	3.54	0.77	1.32	45.39	61.12	
I.R,C.I.**			8.05	4.73							8.05	4.73	
S.F.Cs***			77.40	93.90	2.02	4.59	0.21	0.28		0.03	79.63	98.80	
S.I.D,Cs***		•	19.85	21.84		F4	6.87	4.56			26.72	26.40	
Total	•		315.36 (35.09)	336.45 (59.48)	34.59	47.01	11,45	15.61	1.90	1.59	363.30 (35.09)	400.66 (59.48)	
U.T.I. , L.I.C.*** .	•		43,79	22.82			1.69 4.63	2.71 4.52	5.87 5.69	2.20 0.15	7.58 54.11	4.91 27.49	

^{*} Comprising direct loans (including foreign lines of credit), refinance to banks and rediscounts. Refinance to SFCs, indicated separately within brackets, is excluded to avoid double counting since this is covered under loans of SFCs. Since incep figures, however, are inclusive of refinance to SFCs.

^{**} Including the amount of guarantees sanctioned.

^{***} Data are provisional.

⁺ Including disbursements, if any, on account of guarantees.

⁺⁺ Including firm allotments and right issues.

^{\$} Foreign currency figures for 1974-75 are covered at the Central rates of exchange prevailing on December 31, 1971.

# TABLE 30 :—ASSISTANCE SANCTIONED BY THE IDBI AND UTILISED BY THE ASSISTED CONCERNS DURING 1974-75 AND 1975-76 (JULY-JUNE) AND SINCE INCEPTION

(Amounts in Rupees Crores)

T	Assist	tance Sanctio	oned				Assistance Utilised			
Type of Assistance -	1974-	75	1975		July 1964   June 1976	(0	1974-75	1975-76	July 1964 to June 1976	
	No.	Amount	No.	Amoun	ıt No.	Ambunt	Amount	Amount	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Direct loans to industrial con- cerns (other than for exports)	51 (51)	69.6 (67.1)	97 (96)	105.6 (104.3)	410 (376)	530.1 (636.9)	40 3	48.7	260.3	
2. Underwriting of and direct subscriptions to shares and de- bentures of industrial concerns	39 (39)	11.2 (11.2)	53 (52)	12.2 (12.1)	286 (265)	98.0 (76.9)	2.3	6 8	40.2	
2. Refinance of industrial loans	6453	107.9	9255	180.7	26842	537 4	52.4	102 5	349.7	
4. Rediscounting of bills	(5777) 1062 (1062)	(96.4) 114.4 (114.4)	(8932) 951 (951)	(174.4) 120.8 (120.8)	(23947) 2819 (2819)	(482.8) 496.5 (496.5)	91,7	91.7	404,9	
Subscription to shares and bonds of financial institutions	10 (10)	6.6 (6.6)	21 (21)	16.4 (16.4)	24 (24)	71.7 (71.7)	7.3	14.2	68.9	
Total Project Assistance (1 to 5)	7615 (6939)	309 6 (295.6)	10377 (10052)	435.7 (427.9)	30381 (27431)	1733.6 (1564.8	194 1	263.8	1124.0	
6. Direct loans for exports .	8 (7)	15.9 (15.6)	17 (16)	30.4 (29.8)	77 (73)	105.4	4.5	13.7	54.0	
7. Refinance of export credits .	28 (26)	17.9 (15.9)	15 (15)	5.3 (5.3)	103 (96)	54.6 (47.9)	9.9	8.6	43,2	
8. Overseas buyers' Credit .	2 (2)	5.0 (4.5)	3 (3)	8.6 (7.7)	5 (5)	13 6 (12.2)	• •	0,3	0,3	
9. Foreign lines of credit	3 (3)	8.0 (8.0)	• •	• •	6 (6)	25.5 (20.5)	3.1	5.2	8.3	
Total (1 to 9)	7656 (6777)	356.4 (339.6)	10412 (10086)	480.0 (470.7)	30572 (27611)	1932.7 (1739.2)	211.7	291,6	1229.7	
10. Guarai tecs for loans on deferred payments					19 (15)	64.6 (26,7)		<del></del>	19.5*	
11. Export guarantees	1 (1)	0.4 (0.4)	4 (4)	2.4 (2.4)	(13) 8 (8)	(26,7) 4.7 (4.7)	• •	2.9*	4.7*	

Notes:-(1) Figures relate to gross sanctions: figures of effective sanctions are indicated within brackets.

## **IDBI's Operations**

363. The performance of the IDBI was quite impressive during 1975-76 as judged by the glowth in its sanctions and disbursements. The total effective sanctions during 1975-76 amounted to Rs. 470.7 crores as against Rs. 339.6 crores in 1974-75 (Table 30). The number of applications sanctioned increased substantially from 6,977 in 1974-75 to 10,086 in 1975-76. The assistance utilised in 1975-76 was Rs. 291.6 crores, as against Rs. 211.7 crores—showing an increase of about 38 per cent. Sanctions under refinance of industrial loans went up by 81 per cent from Rs. 96.4 crores in respect of 5,777 applications in 1974-75 to

Rs. 174.4 crores in regard to 8,932 applications in 1975-76. About 64 per cent of the refinance sanctioned in terms of value and 92 per cent in terms of number of applications was in respect of small-scale industries and small road transport operators. The amount sanctioned for rediscounting of bills by the IDBI at Rs. 120.8 crores during 1975-76 was higher by 6 per cent covering 951 purchase-users as against Rs. 114.4 crores covering 1,062 purchaser-users during 1974-75. Sanctions under export finance schemes were marginally lower at Rs. 42.8 crores as against Rs. 44.0 crores in 1974-75, whereas disbursements have gone up from Rs. 17.5 crores in 1974-75 to Rs. 27.8 crores in 1975-76. Total effective sanctions since the inception of

⁽²⁾ The number of applications in respect of item 4 relates to the number of purchaser-users and in respect of item 5 to the number of financial institutions.

^{*} Guarantees executed.

IDBI upto the end of June 1976 amounted to Rs. 1739.2 crores excluding guarantees for Rs. 31.4 crores while the utlisation of assistance aggregated Rs. 1229.7 crores.

364. The direct assistance sanctioned by the IDBI for projects during 1975-76 was markedly higher at Rs. 116.4 crores in respect of 108 projects compared to Rs. 78.3 crores for 66 projects in 1974-75. Eighty-seven per cent of the sanctioned assistance was for setting up fresh capacities by way of new projects or expansion/diversification of existing units. Around 61 per cent of the assistance was in respect of projects in the public, joint or co-operative sector. Industry-wise, 45 per cent of the assistance was in respect of 5 high priority industries viz., fertilisers, cement, paper, sugar and textiles. Further, 8 of the 108 projects assisted were promoted by technician entrepreneurs and 58 projects belonged to backward areas. The direct project assistance for Rs. 55.9 crores was sanctioned on corcessional terms to units in specified backward districts.

#### Assistance to Backward Areas

365. The IDBI assistance to units in specified backward districts/areas has also shown a significant increase in 1975-76. The total assistance both direct and refinance, of industrial loans sanctioned on concessional terms during the year amounted to Rs. 119.5 crores as compared to Rs. 59.7 crores in 1974-75, raising the total assistance sanctioned on concessional terms to Rs. 257.9 crores upto the end of June 1976.

#### Subscriptions to Shares and Bonds

366. During the year, the IDBI contributed Rs. 4.7 crores to the special issue of debentures of the ICICI. With this the total assistance of the IDBI to the ICICI since inception amounted to Rs. 32.7 crores upto the end of June 1976. With repayment of Rs. 6.4 crores being the instalment of loans taken by the ICICI earlier, the IDBI's holdings of the ICICI debentures amounted to Rs. 26.3 crores at the end of June 1976. Besides, the IDBI subscribed Rs. 3.8 crores to the share capital of SFCs during the year. Further, the shareholdings of the Reserve Bank (including special capital) in SFCs amounting to Rs. 3.1 crores were taken over by (DBI on February 16, 1976. Reserve Bank of India's shareholding of Rs. 2.5 crores in the iritial unit capital of the Unit Trust of India was also taken over by the IDBI on February 16, 1976.

## IDBI's Structure of Interest Rates

367. During the year under review the structure of the IDBI's interest rates was revised. The revised rates which came into effect from December 1, 1975 are presented in the Annexure.

## Public Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 1975

368. Pursuant to the Public Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 1975 coming into force with effect from February 16, 1976, the holdings of the Reserve Bank of India in the capital of SFCs have been transferred to the IDBI. While the supervisory functions over the SFCs hitherto exercised by the Reserve Bank would now be performed by IDBI, the 'core' functions of the Reserve Bank as a central banking authority with regard to borrowing, etc. of SFCs will continue to be exercised by the Reserve Bank in consultation with IDBI. The Reserve Bank will also keep itself informed of the progress and functioning of these Corporations through its nominees on their boards and through various statutory returns submitted by them.

## Operations of SFCs

369 The operations of 18 SFCs, including Tamil Nadu Industrial Investment Corporation (THC), showed further improvement during 1975-76 (April –March) The total loans sarctioned by these Corporations during the year ended March 1976 were higher at Rs 152.1 croics as compared to Rs. 137.6 croics during the preceding year. Disbursements during the financial year 1975-76 at Rs. 99.5 crores were substantially higher than in the previous year (Rs. 79.9 crores). The loans outstanding as at the end of

March 1976 amounted to Rs. 363.8 crores showing a risc of Rs. 84.6 crores over the level a year ago. A major proportion of figureral assistance continued to be granted to small-scale sector and such assistance sanctioned at Rs. 402.5 crores accounted for 54.5 per cent of the total amount of loans sanctioned (Rs. 738.5 crores).

### FINANCING OF SMALL-SCALE INDUSTRIES

## Liberalisation of the Credit Guarantee Scheme

370. The period under review witnessed a significant widering of the coverage of the Credit Guarantee Scheme for small-scale industries administered by the Reserve Bank of India on behalf of the Grovernment of India. With effect from September 10, 1975, the definition of a 'small-scale industrial unit' was modified by enhancing the ceiling on investment in plant and machinery from Rs. 7.5 lakhs to Rs. 10 lakhs for the purpose of the Credit Guarantee Scheme. The benefits of the Scheme were further extended with effect from April 1, 1976 to ancillary industrial units having investment in plant and machinery upto Rs. 15 lakhs and engaged in (a) the manufacture of parts, compoments, sub-assemblies, toolings or intermediates or (b) the rendering of services and supplying or rendering on proposing to supply or render 50 per cent of their production or the total services, as the case may be, to other units for production of other articles; provided that no such undertaking shall be a subsidiary of or owned or controlled by any other undertaking. An ancillary industrial unit having investment in plant and machinery exceeding Rs. 10 lakhs and upto Rs. 15 lakhs is, however, required to obtain a certificate from the appropriate Government authorities regarding its status as an ancillary unit.

## Eligible Institutions

371. The number of credit institutions eligible for facilities under the Scheme increased from 609 at the end of June 1975 to 628 at the end of June 1976 mainly due to inclusion of 17 unlicensed primary (urban) co-operative banks in the approved list. The total number of institutions participating in the Scheme had gone up from 217 to 233 during the period. The Government have since approved the inclusion of Regional Rural Banks in the list of credit institutions specified under clause 2(c) of the Scheme.

## Progress of Credit Guarantee Scheme

372. The amount of outstanding guarantees which stood at Rs. 1497 crores at the end of June 1974 increased to Rs. 1726 crores at the end of June 1975 and further to Rs. 1950 crores at the end of June 1976, reflecting a steady increase in the flow of institutional credit to the small-scale industrial sector. An industry-wise analysis of the amount of guarantees outstanding as at the end of June 1975 shows that the food manufacturing industry accounted for the largest share (12.7 per cent) followed by textiles (10.9 per cent), metal products (10.8 per cent), chemical products (8.4 per cent), electrical machinery and equipments (6.8 per cent), manufacture of machinery except electrical machinery (6.5 per cent) and basic metal industries (5.3 per cent). Since the inception of the Scheme till the end of June 1976, claims aggregating Rs. 170.1 lakhs have been paid in respect of 1,201 units; of these, the payments made during July 1975—June 1976 amounted to Rs. 42.2 lakhs in respect of 280 units. Out of the aggregate amount of Rs. 170.1 lakhs paid as claims a sum of Rs. 34.3 lakhs has since been recovered placing the net amount of claims paid at Rs. 135.9 lakhs as at the end of June 1976. The number of units in default as at the end of May 1976 was 12,264 involving Rs. 57.8 crotes which formed 3.0 per cent of the aggregate amount of outstanding guarantees as against 8,749 units involving Rs. 39.9 crotes which formed 2.3 per cent of the aggregate amount of outstanding guarantees as at the end of May 1975. During the period July 1975—June 1976 a sum of Rs. 1 9 crores was received as guarantee fees and transferred to the Central Government.

## Scheduled Commercial Banks' Assistance

- 373. Data on scheduled commercial banks' credit from September 1975 onwards cover small-scale industrial units having investment in plant and machinery up to Rs. 10 lakhs. During the first three quarters of 1975-76 (Aptil—March). the total credit extended by the scheduled commercial banks to small-scale industries showed a rise of Rs. 107.3 crores to Rs. 1147.4 crores. The increase in the outstanding credit to small-scale industries during the period under review was slightly lower than the increase (Rs. 113.5 crores) during the corresponding period of the previous year. The share of small-scale industries in the total bank credit (excluding advances for food procurement operations), therefore, declined marginally from 13.2 per cent as at the end of December 1974 to 13.0 per cent as at the end-December 1975. The increase in the number of units assisted (36,252) during the period under review was, however, significantly higher than that in the comparable period of 1974-75 (19,512). The deceleration in the rate of growth of bank advances to small-scale industries may partly be attributed to the impact of the slackness in demand in industries such as automobiles and consumer durable goods.
- 374. The average amount of credit limits sanctioned per unit has come down further from Rs. 68,000 in December 1974 to Rs. 64,000 in December 1975 indicating a trend towards financing smaller units by the banks.
- 375. Over the year ended December 1975, the chare of advances to small-scale industries in some of the backward States such as Bihar, Orissa and Uttar Pradesh had gone up.
- 376. The State Bank of India Group and the 14 nationalised banks together accounted for 90,2 per cent (Rs. 1034.6 crores) of the total outstanding bank credit (Rs. 1147.4 crores) to the small scale industries sector as at the end of December 1975. The State Bank Group extended credit

- to this sector for an aggregate amount of Rs. 410.2 crores showing a rise of Rs. 38.6 crores over March 1975 level as compared to an increase of Rs. 31.3 crores in the corresponding period of 1974. The credit extended by the 14-nationalised banks to small-scale industries showed an increase of Rs. 63.7 crores during March—December 1975 as against Rs. 71.4 crores during March—December 1974.
- 377. During the nine-month period ended December 1975, the term-loans (including instalment credits) sanctioned by banks to small-scale industries recorded a rise of Rs. 20.3 crores to Rs. 239.2 crores. The outstandings increased from Rs. 178.1 crores covering 50,724 units at the end of March 1975 to Rs. 192.4 crores spread over 57,396 units as at the end of December 1975. The proportion of term-loans (outstandings) to total bank credit extended to small-scale industries had gone down from 17.2 per cent in December 1974 to 16.8 per cent in December 1975.
- 378. The credit limits sanctioned to craftsmen and other qualified entrepreneurs as at the end of December 1975 totalled Rs. 60.2 crores covering 24,745 units showing a rise of Rs. 11.5 crores over the nine-month period, which compares favourably with a rise of Rs. 8.2 crores in the corresponding period of the previous year. Outstanding credit stood at Rs. 42.5 crores; 48 per cent of which was accounted for by State Bank of India Group.
- 379. As at the end of December 1975, the credit limits sanctioned to small road and water transport operators amounted to Rs. 238.5 crores spread over 93,837 units. The amount outstanding at Rs. 191.2 crores recorded an increase of Rs. 57.7 crores over the March 1975 level which showed a three-fold increase as compared to the increase during the corresponding period of 1974 (Rs. 19.7 crores).
- 380. Credit limits sanctioned by 17 scheduled commercial banks for setting up of irdustrial estates amounted to Rs. 18.6 crores as at the end of December 1975 covering 57 units. The balance outstanding was Rs. 12.4 crores as against Rs. 9.5 crores as at the end of March 1975.

# ANNEXURE INTEREST RATE STRUCTURE—IDBI's ASSISTANCE

	Rate prevailing before December 1, 1975	Revised rates effective from December 1, 1975
1	2	3
Direct assistance to industrial concerns     (other than for exports)	% p.a.	% p.a.
(a) Normal rate	10.25	11.00
(b) To units in the specified backward districts	8.50	9.50
2. Refinance		
(a) Normal rate	8.50— Ceiling on the rate to be charged by the financial institutions at 12 per cent	9.00— Ceiling on the rate to be charged by the financial institutions at 12.50 per cent
(b) Special rate for sall-scale industrial units covered under the CGS and technician entrepreneur schemes	7.00— Ceiling on the rate to be charged by the financial institutions at 10.50 per cent	7.50→ Ceiling on the rate to be charged by the financial institutions at 11.00 per cent
(c) Special rate for units in the specified backward districts	5.50— Ceiling on the rate to be charged by the financial institutions at 9.00 per cent	6.00— Ceiling on the rate to be charged by the financial institutions at 9.50 per cent
Under IDA line of Credit (Foreign currency		
component)		
(a) To smull-scale industries covered under CGS, technician entrepreneur schemes and units in specified backward districts.	8.00— Ceiling on the rate to be charged by the financial institutions at 10.50 per cent	8.50— Ceiling on the rate to be charged by the financial institutions at 11.00 per cent
(h) Other cases	8.25 — Ceiling on the rate to be charged by the financial institutions at 11 00 per cent	9.00— Ceiling on the rate to be charged by the fluancial institutions at 11.50 per cent

3

2

⁰′ູ່ p.a.

% p.a.

## 3. Export credit

- credits
- (a) Refinance against medium term export 6.50- Provided the bank does not charge. No change more than 8.00 per cent
- (b) Participation export finance scheme
- (c) Buyers' credit scheme

The rate on IDBI's portion of the credit is No change such that after taking into account the participating Bank's rate. average rate to the exporter on the entire credit will generally be 7.50 per cent

## 4. Bills Rediscounting Scheme

Unexpired usance of bills/promissory notes

- 9.00- The maximum discount rate by 10.00- The maximum discount rate by (a) 6→ 36 months bank is 11.75 per cent bank is 10.75 per cent
- (b) Over 36 months and upto 84 months 8.50— The maximum discount rate by 9.50— The maximum discount rate by bank is 11.25 per cent bank is 10.25 per cent

## Unit Trust of India

381. There was a distinct improvement in the operations of the Unit Trust during 1975-76 as reflected in sales and repurchases of Units. Total sales amounted to Rs. 29.0 crores in 1975-76 compared with Rs. 17.2 crores during the previous year; repurchases during the period at Rs. 11.0 crores, were only about one-half of those in the previous year. The improvement during 1975-76 can be attributed to the following factors. Firstly, the exclusive income and wealth tax concessions of granted by the Government in January 1975 in respect of investment in Units considerably improved their attractiveness. Secondly, the increase in the

30. Income from units upto Rs. 2,000 and investment in units upto Rs. 25,000 were granted exemption from income tax and wealth tax respectively. These exemptions are in addition to the existing exemption of Rs. 3,000 from income tax and of Rs. 1.5 lakhs from wealth tax available to units along with certain other specified assets.

dividend for 1974-75 to 8.6 per cent from 8.5 per cent for 1973-74, though only marginal, went a long way in strengthening further the confidence of the investors in the Trust. Thirdly, the distinct improvement in the economic situation of the country during the year and the relaxations of the dividend restrictions in 1975 had also a favourable impact on the investment climate. Further, in January 1976, the Trust introduced a new Scheme, namely, the Unit Scheme 1976, which offered a new type of unit primarily scheme towards capital browth and this Scheme was able oriented towards capital growth and this Scheme was able to mobilise additional savings. The Trust raised the rate of dividend for 1975-76 under the Unit Scheme 1964 to 8.75 per cent from 8.60 per cent for 1974-75.

382. At the end of June 1976, units sold and outstandings amounted to Rs. 166.9 crores under more than 6.3 lakhs applications. Table 31 gives the Scheme-wise sales, repurchases and outstandings till June 30, 1976.

TABLE 31-SALES, REPURCHASES AND OUTSTANDINGS OF UNITS: SCHEME-WISE ANALYSIS

(Amounts in Rupecs Crores)

Catalan e								Salo	es	Repurch		outstandings as on
Scheme								1974-75	1975-76	1974-75	1975-76	June 30, 1976
	1		 				 	2	3	4	5	6
Unit Scheme 1964	•		,	,	,	,		16.74	20.77	20.36	10 95	157 65
Unit Scheme 1971								0.49	0.79	0.01	0.02	1.75
Unit Scheme 1976	•	•	,	•			•		7.47	·		7.47
	Total							17.23	29.03	20.37	10.97	166.87

### Unit Scheme 1976

383. The Trust introduced the Unit Scheme 1976, January 1, 1976, under which 'Capital Units' were offered for sale to the general public. Unlike the Unit Scheme 1964 and the Unit Scheme 1971, which aim at regular and growing income to the unit-holders, the new Scheme is primarily oriented towards capital growth. This objective is sought to be achieved by investing the funds of the Scheme in the equity shares of companies having good growth prospects. The Trust expects that, barring extra-ordinary and unforescen situations, the unit-holders' investment in the capital units would double in about 5 years. The face value of each unit of this Scheme is Rs. 100 and the units was sold in multiples of the The company of the C are sold in multiples of five. The popularity of the Capital Unit Scheme can be gauged from the amount of their sales. During the short period (January to April 21, 1976) sales of such units amounted to Rs. 7.5 crores. Sales have been temporarily suspended with effect from April 22, 1976 with a view to enabling the Trust to invest appropriately the first of the Sales as a contract to invest appropriately the funds of the Scheme in growth oriented shares.

#### Investments

384. The investible funds of the Trust increased by 8.6 per cent to Rs. 184.5 crores as at the end of June 1976. Of these, ordinary shares accounted for Rs. 91.5 croies (49.6 per cent) preference shares for Rs. 16.2 croies (8.8 per cent) and debentures for Rs. 55.8 crores (30.2 per cert). The balance of Rs. 21.0 crores (11.4 per cent) represented advance deposits against underwriting commitments, bridging finance, other deposits, money at call and short notice,

## Delinking from Reserve Bank

385. The Trust which was hitherto an associate institution of the Reserve Bank, became an associate institu-tion of the Industrial Development Bank of India with effect from February 16, 1976 in terms of the Public Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 1975. As a result, the initial capital (Rs. 2.5 crores) of the Trust held by the Reserve Bank, as been transferred to the Industrial Development Pool of India lopment Bank of India.

## NON-BANKING COMPANIES

## Study Group on Non-Banking Companies

386. Reference was made in the last year's Report about the submission of the report by the Study Group on Non-Banking Companies. The main recommendations of the Study Group cover non-financial companies, financial companies and companies conducting prize chits and/or conventional chits. ventional chits. These recommendations have been accepted in principle by the Reserve Bank and the Government of

387. With regard to non-financial companies the Study Group observed that the acceptance of deposits companies may not be prohibited altogether but the measures should be so designed as to ensure the efficacy of monetary policy and to avoid disruption of the productive process consistent with the need to safeguard the depositors' interests. At the same time, the ultimate objective should be to discourage further growth of these deposits and to roll them back gradually so that they would cease to be a significant source of finance for industry and trade question of amending the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 suitably, to give effect to the recommendations is under the examination of the Department of Company Affairs.

388. Ir the case of non-banking financial companies, the Study Group recommended effective regulation of their activities considering the large number of depositors involved as well as the incidence of malpractices in these companies. The Study Group suggested that such companies should be subjected, by and large, to the same type of controls as banks under the Banking Regulation Act. 1949. As the operations of loan companies are analogous to those of banks, the Study Group recommended a ceiling of 10 times the net owned funds. In the opinion of the Study Group, availability of funds to that extent would give

them a reasonable chance of profitable working and enable them to become viable units. While in regard to hire-pur-chase finance comparies, which are at present exempt from ceiling restrictions, a ceiling (not exceeding 10 times their net owned lunds) as in the case of loan companies has been proposed, housing finance companies, however, will be ceiling restrictions. Since continue to be exempted from the ceiling restrictions. such special considerations will not be relevant in respect of investment companies, the existing composite ceiling of 40 per cent of the net owned funds is proposed to be reduced to 25 per cent in two stages. The Group had not recommended any ceilings on deposits with niddis which Apart from the restrictions deal only with their members. on the quantum of deposits that may be accepted by the companies, the Group has recommended minimum capital requirements for starting new financial companies and also in respect of existing companies other than nidhts. Some of the other recommendations made by it relate to the creation of reserve fund, maintenance of liquid assets, prohibition of grant of loans and advances to the directors firms and companies in which they are interested and the enactment of provisions on the lines of certain sections of the Banking Regulation Act, 1949. In view of the substantive nature of the recommendations made by it for the purpose of tightening the control over the deposit acceptance activities of financial companies as also the operational aspects relating to their working, it has been decided to enact a separate comprehensive legislation in place of Chapter IIIB of the Reserve Bank of India Act, 1934. The drafting of the legislation is in progress and in the meantime, steps are also being taken to implement such of the recommendations as could be given effect to by invoking the power vested in the Reserve Bank under the existing provisions of Chapter IIIB of the said act by suitable amendments to the directions now in force. The amendments to the directions have been finalised but the issue of the Notification has been deferred for the time being as it has been decided to bring them into force simultaneously with the corresponding amendments to be made to the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 by the Govenment of India for implementing the recommendations of the Group as may be applicable to non-financial companies.

389. As regards companies conducting prize chits, beneflts/savings schemes etc., the Group has come to the conclusion that such schemes benefit primarily the promoters and do not serve any social purpose. Such schemes are prejudicial to public interest and also adversely affect the efficacy of fiscal an monetary policy. It has, therefore, suggested that the corduct of such schemes should be totally banned in the larger interests of the public and that suitable legislative measures should be taken for the purpose, if the provisions of the existing enactments are considered inadequate. The draft legislation prepared in this regard by the Reserve Bank is under consideration of the Government.

390. In the case of companies conducting conventional chit fund business, the subscriptions received by them from the members of the chits are excluded from the scope of the term 'deposits' for the purpose of the directions issued by the Reserve Bank, while deposits accepted outside such schemes fall within the purview of the directions. Chit fund business, however, is regulated under State enactments in certain States/Union Territories. In the absence of any regulatory measures in the other parts of the country and also in view of the diversity in these provisions, it is not unlikely that unscrupulous promoters or chit companies may exploit the situation by conducting chits in such of the States as have no such legislation or in States where the provisions are less rigorous. It may be added that in the context of the recommendation of the Banking Commission for regulating the activities of non-banking financial intermediaries, the Central Government had, inter alia, decided that a model law to regulate activities of conventional chit funds may be formulated adoption by all the States which have no such legislation. Pursuant to the above decision, a Bill was drafted by the Reserve Bank to be enacted as Central legislation and was referred to the Study Group for its comments. The Bill, as suitably modified in the light of the recommendations of the Study Group, is under examination of the Government of India.

## Accepance of Deposits by Unincorporated Bodies

391 The Government, while considering certain recommendations made by the Banking Commission in regard to the retructuring of the existing scheme of control over ron banking financial intermediaries, decided in principle that statutory powers should be assumed to prohibit acceptance of deposits by all unincorporated bodies. Necessary amend mens to the Reserve Bank of India Act, 1934, proposed by the 3ark in this connection, are under examination of the Government.

### Amadments to Directions issued to Non-Banking Companies

39 The directions issued to non-banking financial companie were further amerded on November 29, 1975 extendig the time allowed to such companies by six months (i.e., up to the end of June 1976) for reducing the aggregate imount of deposits in the form of loans guaranteed by directs, deposits received from shareholders, etc. to 15 per ent of the net owned funds. This extension of time was sequel to the representations made by companies that the utstanding amount of such deposits was quite substantial ad that under the existing conditions they were firding it very difficult to liquidate, the deposits held in excess of the pescribed ceiling by December 31, 1975.

393 A similar extension of time in the case of nonbankin non-finarcial companies was allowed by the Departmet of Company Affairs, Government of India amendig the Companies (Acceptance of Deposits) Rules. 1975 mde under Section 58A of the Companies Act, 1956 These companies have been allowed further extension of time uto the end of September 1976 Besides, in the light of cerun suggestions made by the Reserve Bank, Rules here amended on September 18, 1975, the amended Rules boadly follow the pattern of the directions to nonfinancial companies as were in force prior to their with drawal i Jure 1975 It will be recalled that companies conductly prize chits/lucky draws/saving schemes etc have already een allowed time up to the end of December 1976 to bringdown the above type of deposits within the reduced coing of 15 per cent

## Deposits vi Non-banking Companies, 1972-73

394 Th total number of reporting comparies under the Survey of Deposits with Non-banking Companies for the year endedMarch 31, 1973 declined during the year by 314 to 2,84 Despite a reduction in the number of reporting compani, the total amount of deposits and exempted loans record ar increase of Rs 56 crores from Rs 6918 crores at thend of March 1972 to Rs 7478 crores at the end of March 973 Of this, deposits amounted to Rs 373 7 crores and empted loans Rs 3741 crores number of rerting financial companies declined by 42 to 879, the nume of reporting non-financial companies de clined by 272, 1962 Of the total of Rs 7478 crores of deposits a exempted loans, non-financial companies accounted for I 5174 crores and financial companies for the balance (R9 10 4 crores) 25 GI/77---20

395 As observed in 1971-72, the concentration of outstanding deposits and exempted loans with a small number of large non-banking companies was also noticed in the year 1972-73. Out of 2,841 reporting companies at the end of March 1973, 464 companies (16.3 per cent) holding deposits and exempted loans aggregating Rs 25 lakhs accounted for 83.8 per cent of the total. This feature was more pronounced in the case of financial companies where 8.5 per cent of the reporting companies accounted for 78.8 per cent of the deposits and 90.6 per cent of the deposits and exempted loans taken together.

396 The reporting companies were mainly concertrated in three States viz, Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal These three States taken together accounted for 63 9 per cent of the reporting companies and 71 8 per cent of the total outsanding deposits and exempted loans at the end of March 1973.

#### V. DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL

397 In the sphere of Exchange Control, the main developments during the year related to the delinking of the Indian fibra pound sterling, simplification of procedures for exports on deferred payments terms, introduction of a new facility to non-resident Indians and persons of Indian origin resident abroad by allowing bein to open and maintain foreign currency (non-resident) accounts and to encourage them to invest in the equity capital of specified industries in India

## Delinking of the Rupee from Pound Sterling.

398 The Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, reviewed the arrangement under which the Indian rupee was linked to the pound sterling, its value vis-a-vis the other major international currencies ur the Special Drawing Rights (SDRs) being changed every day automatically with changes in the value of the pound Effective July 2 1975 the Bank had fixed its spot rates for sterling at £53907 buying and 53619 selling both per Rs 100 in place of the rates of £5,3333 and £5,3050 respectively, which were in force since July 4, 1972 However, in the context of the international monetary situation and having regard to the fact that a multi-currency peg is likely to be much more suitable and satisfactory than a link with any single reserve currency, so long as the major international currencies are floating, it was decided that the rupee should be delinked with effect from September 25, 1975 from sterling and its value should be determined in future with reference to a selected number of major international currency units, which are India's major trading partners. The pound sterling continues as the currency of intervention Accordingly the Bank revised its rates for the purchase and sale of pound sterling for spot delivery from time to time as per details given below .

Datc				-		Buying	Selling	Middle rate
<b>25-9-1975</b> .	•	•	•	•		£5.4769 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 18.2583 per £ 1)	£5.4471 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 18.3584 per £ 1)	Rs. 18,3084 per £ 1
05-12-1975	•	•	•	•	-	£ 5.5315 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 18.0784 pci £ 1)	£5.5010 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 18.1784 per £ 1)	Rs. 18.1284 por £ 1
08-03-1976 .	•	٠	•	-	•	£5.6497 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 17.70 per £ 1)	£5.6180 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 17.80 per £ 1)	Rs. 17.75 per £ 1
11-03-1976	•	•	•	•		£ 5.8140 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 17.20 per £ 1)	£5.7803 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 17.30 per £ 1)	Rs. 17.25 per £ 1
03-04-1976	•		•		•	£ 5.9347 per Rs. 100 (corresponding to (Rs. 16.85 per £ 1)	£ 5.8997 per Rs. (00 (corresponding to Rs. 16.95 per £ 1)	Rs. 16.90 per £ 1
23-04-1976	-			•	•	£ 6.0790 per Rs. 100 (corresponding to (Rs. 16.45 per £ 1)	£ 6.0423 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 16.55 per £ 1)	Rs. 16.50 per £ 1
<b>29-05-1</b> 976 ,		-	٠			£ 6.2696 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 15.95 per £ 1)	£ 6.2305 per Rs. 100 (corresponding to Rs. 16.05 per £ 1)	R9. 16.00 per £ 1

On all these occasions, there was no change in the margin of £ 0.0125 per Rs. 100 per quarter or part thereof to be added to the spot buying rate while buying sterling forward, nor in the charge of £ 0.0125 per Rs. 100 per quarted or part thereof on one or more extensions of forward purchase contracts. Likewise the margin to be added to the spot rate for sterling for calculating the Bank's rates for forward purchases of sterling for periods upto 10 years under the scheme for providing long term forward exchange cover to exporters in respect of exports under deferred payments terms remained unchanged as indicated below:—

Per	iod of forwarded contract	Percentage margin over the Bank's
_	The state of the s	buying rate
1.	For 18 months and above but not exceeding 5-years	1.25
2.	Abovo 5 years but not exceeding 7 years	1.75
3.	Above 7 years but not exceeding 10 years	<b>2</b> ,50

## Exports under Deferred Payments

399. On July 1, 1975, the Reserve Bank simplified the procedures relating to exports on deferred payments. According to the earlier procedure, exporters of capital goods and engin-cering goods on deferred payment basis had to seek the Reserve Bank's prior approval in two stages, viz., once for approval in principle before participating in foreign bids or tenders or initiating negotiations for exports on deferred payment terms, and for a second time, for Reserve Bank's final approval before finalising the terms of the contract in the event of their securing the order. In addition, in some cases simultaneous but separate applications were required to be made by the exporter to the Industrial Development Bank of India (IDBI) and the Export Credit Guarantee Corporation (ECGC), if IDBI finance and ECGC cover were also required. This inconvenient and time-consuming procedure has been simulfied and liberalised by experimentary. cedure has been simplified and liberalised by granting general permission to exporters subject to certain conditions to make offers abroad/enter into negotiations/contracts and/or submit tenders and to obtain post-facto Exchange Control clearance subsequently. The most important of these conditions are: (1) the value of the contract should not exceed rupees fifty lakhs, (2) the credit period should not exceed five years for specified types of goods, (3) IDBI finance is not required and (4) the advances and down payment should be a minimum of 15 per cent of the total contract value and should also cover foreign exchange outgo by way of import replenishment, agency commission and freight. Within 15 days of signing the contract, applications are, however, required to be made in these cases to the Reserve Bank for post-facto exchange control clearance and to the ECGC for necessary insurance cover. The procedure legarding cases not covered by the general permission has been considerably streamlined by making the IDBI the focal point for grant of approvals. Such applications in a composite form submitted to the IDBI, are now processed by a Working Group which includes RBI IDBI and ECGC. The exporters with their bankers, are also being associated. being associated, where necessary, in the discussions of the

Working Group and package clearance granted for the offer or bid.

#### Foreign Currency (Non-resident) Accounts

400. To encourage private remittances from abroad, i new facility came into existence from November 1, 1975. Inder the Scheme, non-resident Indians and persons of Indianorigin resident abroad are permitted to open and maintain breign currency (non-resident) accounts in designated foreign urrencies (for the time being in U.S. dollars and pound strling) with the initial remittances received from abroad or by convention of existing non-resident (external) accounts maltained in rupees with banks authorised to deal in foreign echange in India. Under this arrangement, the exchange risk to the non-resident account holders has been completely elimated. The accounts would be maintained in the form of 100 per periods of 91 days or more but not exceding 61 months. The interest rates payable would be nofied by the Reserve Bank of India, For the present interst rates vary from 5.5 per cent per annum on deposits of 91 days but less than 6 months to 10 per cent per annum on deposits of 61 months. The interest accruing on thes balances is free of Indian income tax. The balance including the interest accrued are freely repatriable in the designized foreign currencies without reference to the Reserve Jank of India. Balances held in non-resident (external) acounts in rupees or in designated foreign currencies are except from wealth tax. They are, however, not exempt from eate duty, nor are the gifts made from such accounts except from gift tax.

## Investments in Equity Capital

401. Non-resident Indians and persons of Indian origin resident abroad were permitted from October 197 onwards to invest in the equity capital of permitted industes (other than those given in the annexure to the Import Trie Control Public Notice No 23-ITC(PN)-74 dated Februar 8, 1974) upto a maximum of 20 per cent of the new isied equity capital of new companies. Repatriation of such ivestments along with the income accrued thereon would be freely allowed, subject to the applicable taxes, provide such investments were made by remittances from abroa or out of funds held in non-resident (external) accounts, less investments would be in addition to any foreign equit investments permitted by the Government in the company ocerned.

## Export of Consultancy/Design Engineering Servis

402. The Reserve Bank of India has libersed in June, 1975 its existing procedure regarding export Indian consultancy/design engineering services. Indian consultancy/design engineering firms are now being alloyl to avail of blanket travel permit facility if their foreign xchange earnings in the previous year were not less in rupees five lakhs. Application for travel abroad or fomeeting initial expenses/commitments abroad are now being onsidered more liberally depending on merits of each case.

## Asian Clearing Union

403. The Asian Cleating Union (ACU) hich was established on December 9, 1974, with the old of facilitating payments for current international transions within the member countries of Economic and Soc Commission for Asia and Pacific (ESCAP) on a multilater basis, commenced

the clearing operations from November 1, 1975. The Central Banks of six countries—Bangladesh, India, Iran, Nepal, Pakistan and Sri Lanka—are its present members. Barting certain transactions such as payments for petroleum, natural gas and their products, payments between Nepal and India, inter-governmental and non-current transactions, all transactions between India and members of the ACU may be channelised through clearing mechanism of ACU. Twenty-nine authorised dealers in foreign exchange have been designated for handling transactions through ACU. The instruments digible for clearance may be denominated in the members' currency or the Asian Monetary Unit which is the common unit of account of ACU and which is equivalent to one SDR as valued by the IMF from time to time. The Reserve Bank of India will make spot and forward purchase of AMU for delivery upto three, six and nine months (extendable upto 12 months in all) from the designated authorised dealers and spot sales to them on the basis of exchange rate between the rupee and AMU announced by the ACU from time to time.

## Forward purchase of Deutsche Marks and Japanese Yen

404. With effect from September 1, 1975, in addition to the spot, one months', two months' and three months' forward purchases, the Reserve Bank commenced purchasing Deutsche Marks (DM) and Japanese Yen forward for delivery on completion of six months. The rates for the Reserve Bank's purchases of six months' forward Deutsche Marks and Japanese Yen would be the respective cross rates between the London market's buying rates for Deutsche Marks and Japanese Yen for six months' forward delivery at the close of the preceding working day and the Reserve Bank's buying rate for forward sterling for six months' delivery ruling on the day of purchase. The purchases would for the present be made only at the Bombay Office of the Bank. It was also decided that with effect from August 27, 1975 and until further notice, all offers of forward Deutsche Marks and Japanese Yen to the Reserve Bank by authorised dealers for amounts of DM 800,000 or Yen 100 million or over individually, should be accompanied by authorised dealers of the firm export orders against which the Deutsche Marks or Japanese Yen have been purchased by the authorised dealer from his customer/s.

## Blanket Foreign Exchange Permits

405. The procedure for issue of blanket exchange permits to eligible export houses and other export units and the facility for drawal of amounts thereunder have been streamlined and simplified from July, 1975 so as to enable the eligible export units to avail of the facilities expeditiously. The questionnaire for blanket permit has also been suitably amended. Under the revised procedure, the names of persons who may avail of the blanket exchange permit are not endorsed therein. The export units are free to depute any employee of their choice or their consultants directly associated with export promotions. The release of exchange under the blanket permit is suitably increased to take care of the genuine needs of exporters. Persons travelling abroad against blanket or other permits on export promotion grounds are eligible to draw additional exchange upto 20 per cent of the per diem rates for meeting the cost of surface travel and incidental expenditure abroad. Exchange upto 10 per cent of the value of the blanket permit can be availed of for entertainment expenses provided the team led by the Chainman or the Director does not spend more than £ 100 per trip and £ 50 in case the negotiating team is led by other senion executives. The concerns exporting non-traditional goods for value exceeding Rupees one lakh but less than Rupees fifteen lakhs and traditional goods for value exceeding Rupees one lakh but less than Rupees fifteen lakhs but less than Rupees seventy-five lakhs are also released exchange for two trips a year on export promotion gounds. While the exporters registered as Export House' within the Ministry of Commerce would continue to be eligible to get blanker exchange permits irrespective of their past export performance, there would be no change in the present criteria regarding the minimum annual export realisations for other exporters for being eligible for

issue of blanket permits i.e., Rupees fifteen lakhs for non-traditional goods and Rupees seventy-five lakhs for traditional goods.

## Use of Foreign Trade Marks

406. Persons resident outside India, foreign citizens resident in India, companies incorporated abroad and companies in which the non-resident interest is more than 40 per cent as well as branches of such companies have been permitted to allow the use of their trade marks by any person or company for direct or indirect consideration in cases where the trade marks are used in respect of (i) goods which are intended to be wholly exported to countries other than Nepal and Bhutan and (ii) certain life saving and essential drugs and pesticides and other chemicals used for plant protection. General permission to this effect for item (i) above and for item (ii) covering 17 types of drugs and more than 25 types of pesticides and other chemicals used for plant protection, has been given by the Reserve Bank in April, 1975 and March, 1976, respectively.

#### Indo-Mauritius Credit Agreement 1975

407. The Government of India entered into a credit agreement with Government of Mauritius on January 9, 1975 whereby a line of credit up to Indian Rupees five crores has been made available to Government of Mauritius for purchase and import of listed Indian goods and for agreed projects in Mauritius.

## National Defeuce Remittance Scheme (NDRS)

408. Holders of the NDRS (National Defence Remittance Scheme) Special Accounts with banks in India, irrespective of the size of balances, have now been (from June 23, 1976 onwards) allowed to use the amount freely for local disbursements except for investments in India and payment of The restrictions hitherpassage fare for travel to/from India. to in force on withdrawals if balances in accounts exceeding Rs. 50,000 have been withdrawn. The balances can also now be used freely for (i) opening fixed deposit accounts, (ii) investing in Indian Government securities or units of the Unit Trust of India and (iii) purchasing shares of Indian companies with the prior approval of the Reserve Bank. The sale or maturity proceeds of these investments are. however, required to be credited back to the NDRS Special Accounts. Payment of passage fare from out of the Accounts for travel to from India will be authorised by the Reserve Bank on application by the account holders or their dependants provided travel is undertaken on Air India or Indian Airlines services.

## Other Developments

409. Other developments in this area include: (1) exemption from April 23, 1976 of air travel between Trivendrum and Male (Hulule), Maldive Islands from the requirements of prior approval of the Reserve Bank of India on form 'P'. Visits to Maldives will not be treated as a visit abroad for the purpose of travel under the Foreign Travel Scheme. 1970 (2) Certain changes have been made with effect from February 11, 1976 with regard to the banking arrangement for servicing of payments between India and Czechoslovakia arising out of the Trade and Payments Agreement dated December 4, 1974 between the two countries. The gold clause will no longer be permitted to be incorporated in relative contracts, nor the balance in the Central account of the Czechoslovakia Obchodni Banka, A. S. Praha (CSOB) with Reserve Bank of India, Bombay will be covered by the The contracts (involving payment beyond one gold clause. vear) as also the balance in CSOB's central account will be protected on the basis of SDR-rupee rates. (3) In view of the fluctuations in foreign currency, Reserve Bank decided to lay down the limits in terms of runees, for the amount of foreign currency notes and coins that can be sold by full-fiedged money-changers operating at the air-ports and docks to various categories of travellers proceeding out of India, as follows:

- (a) All travellers, other than deck passengers and travellers proceeding to Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan or Sri Lanka.
- (b) Travellers proceeding to Pakistan in transit to some other country on an international passport.
- (e) Travellers proceeding to Pakistan
- (d) Travellers proceeding to Sri Lanka and deck passengers proceeding to Burma, East Africa, Malaysia, Persian Gulf Ports or Singapore.
- (e) Travellers proceeding to Bangladesh

Any foreign currency notes and coins upto the equivalent of Indian Rs. 60 per person.

-Do-

Pakistan currency notes and coins upto the equivalent of Indian Rs. 30 per person.

Any foreign currency notes and coins upto the equivalent of Indian Rs. 30 per person.

Any foreign currency notes and coms upto the equivalent of Indian Rs. 20 per person.

(4) Commencing from June 1, 1976, all permits for remittances of foreign exchange/credits to non-resident bank accounts will be issued by the Reserve Bank of India under the signatures of two officials of the Reserve Bank irrespective of value in order to simplify and streamline the pro-

cedure. The banks which were hitherto required to verify the signature on the permits would not do so in inture and (5) The Vysya Bank I td., South Indian Bank Ltd. and Catholic Syrian Bank Ltd., have been granted licences to deal in foreign exchange in India initially for a period of two years.

TABLE 32:—STATISTICAL DATA FOR THE PERIOD FROM JULY 1975 TO JUNE 1976

1. Fresh Exchange Permits issued for Study/Training Abroad

Country						Technica	1 Courses	Non-techni	cal Courses
Country						Number of Students/ Trainees	Amount of Exchange released (Rs. '000s)	Number of Students/ Trainces	Amount of Exchange released (Rs. '000s)
1	 	•			 	2	3	4	5
J.K. and Europe	<del></del>		<del></del> -	· .		499	8106	520	2201
J.S.A. and Canada		,				922	24298	648	12673
Other Countries .						179	1785	118	420
Total .						1600	34189	1286	15294

## II. Travel Permits issued for purposes other than Study/Training

	Purpose											Amount of exchange released (Rs. '000s)
	1				. •			•			2	3
1.	Business			· <del></del> -					<del></del> -		15596	151034
2.	Medical Treatment									,	380	7077
3,	Study Tours .									,	636	5392
4,	Attendance at Confe	erence	)5 .			,					1476	4634
5.	Miscellaneous .										13429	23848
	Total .										31517	191985

## III. 'P' Form Applications*

	Purpose							 . , .					No. of persons covered by approvals granted
	1				_		•	 					2
1.	Joining head of family	,				<u>.</u>				 			16958
2.	Visits to Relatives												18009
3.	Export Promotion								,				1167
4.	Employment Abroad			,									37023
5.	Emigration for Perman	nent	Settle	ment									12412
6.	Students/Trainces.								· ·				2697
7.	Miscellaneous .											•	19128
	Total .					 •			,		,		107394

^{*}No foreign exchange is released in such cases.

## VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE

#### RESERVE BANK

## Surveys

410. During the year under review, considerable progress was made in regard to the work of the All-India Debt and Investment Survey 1971-72 conducted by the Bank in collaboration with the National Sample Survey Organisation of the Government of India and Statistical Bureaux of the State Governments.

411. The Steering Committee appointed by the Bank to oversee the conduct of the Survey met twice during the year and assessed the progress of the Survey and considered various background papers prepared in this regard. On the supply side investigation, scrutiny of different mini-surveys conducted in the field of co-operative sector was completed and substantial progress was made in respect of their tabulation. State-wise background papers on the progress of co-operative movement during the period 1961-62 to 1971-72 are under preparation. Further, the tabulation of the data on the Survey of 'Financing of Primary Agricultural Credit Societies by Commercial Banks,' referred to in the last year's Annual Report was completed and a draft report was prepared. On the demand side, a Monograph on the 'Assets of Ruial Households as on June 30, 1971' has been finalised and is under print and another Monograph on the 'Liabilities of the Rural Households as on June 30, 1971' is under preparation.

412. The processing of the first schedule pertaining to the All-India Debt Investment Survey 1971-72 is completed and volume II presenting data on assets and liabilities of rural households as on June 30, 1971 and state-wise statistical pamphelts presenting similar information are also published.

413. The Division of Rural Surveys, Economic Department released to the public in August 1975, the Report of the Seventh Follow-up Survey on "The Small Farmers (1967-69)" and in November 1975, the report on the operations of selected Small Farmers' Development Agencies (SFDA), 1972-73, referred to in the last year's Annual Report The Report on the Operations of the Marginal Farmers' and Agricultural Labourers Agencies (MFAL 1), 1973, has been finalised and is under print. The Quarterly Survey of (State and Central) Co-operative Banks' Advances, continues to be conducted in the Division and a review of the co-operative bank advances during 1974 based on the quarterly surveys was published.⁸¹ The data on the field study of 'Savings Potential of Farmers' (1969-70) are being processed.

414. The Division of Trade conducted the Survey of Foreign Collaboration in Indian Industry for the period 1970-71 to 1972-73. About three-fourths of the returns have been received and data are being processed.

415. The Division of International Finance of the Economic Department continued to call for quarterly reports from branches of foreign companies and Indian Ioint Stock Companies for the Foreign Investment Survey and the results of this survey were published. In an article on 'India's International Investment Position 1968-72' and for 1972-73 a similar article was published. The Survey of unclassified receipts, covering inward receipts of foreign exchange in amounts below Rs 10,000 or equivalent for which no purpose-wise details are available, was initiated for the quarter January-March 1976, and the data for the Survey pertaining to quarter April-June 1975 are being processed while the report based on returns for July-September 1974 Survey is being finalised.

#### Seminars

416. The Agricultural Refinance and Development Corpotation conducted a seminar on 'Development Banking for Agriculture' at the College of Agricultural Banking, Pune in which Chief Executives of state land development banks and heads of agricultural finance departments of commercial banks took part. Seminars on project formulation and guidelines for implementation of schemes were also arranged for the district level officers of Rajasthan and Nagaland during the year.

#### VII. EDUCATION AND TRAINING

417. During the year under review, various categories of personnel—junior, supervisory and senior executive—from the Bank as well as from commercial banks, co-operative institutions, and Government Departments continued to receive both general and intensive training through the various training institutions of the Reserve Bank. The progress made in this field is briefly reviewed.

## Bankers' Training College, Bombay

418 Many of the training programmes organised by the Banker's Training College (BTC) were so designed as to meet the specific requirements of the sponsoring institutions. With this end in view, while continuing its accent on the usual courses in credit analysis, the College held a wide variety of specialised programmes such as on Development Banking, Demand Projections, Inspection Orientation/Inspection-Advanced, Personnel Management and Organisation and Methods etc. In addition as many as five new courses on areas of Project Appraisal and Follow-up Finance for Priority Sectors, Statistics for Bankers. Lending for Working Capital and Social Cost-Benefit Analysis, were instituted by the College. The BTC continued to pay attention to the training needs of the Bank's own officers in Central Banking/Central Banking Advanced and Faculty Courses. A special feature of the activity of the College was its collaboration with the National Institute of Bank Management in the conduct of a seminar on the Tandon Study Group Report for trainers of banks' colleges and a Programme on Management of Lending. The BTC also conducted a series of programmes to acquaint the senior officials of the Department of Banking Operations and Development (DBO & D) with the rationale of the recommendations of the Tandon Study Group and to enable them to discuss the problems in their implementation

419. In all, 1,949 officers from the Reserve Bank, commercial and development banks and the Government, received training during the year raising the total number of personnel trained to 10,367 since the inception of the College.

## College of Agricultural Banking, Pune

420. The activities of the College of Agricultural Banking (CAB) were characterised by a marked shift in emphasis from co-operative banking to a wider spectrum of agricultural banking/finance. As a corollary, the College has undertaken series of special programmes on Agricultural Projects in the context of sanctioning of a general line of credit to the Agricultural Refinance and Development Corporation by the IDA/World Bank. To begin with, a Seminar on Development Banking for Agriculture was held in August 1975, followed by the conduct of Agricultural Projects Courses, including a condensed one. There was a remarkable increase in the number of outstation courses organised by the College for banks in different regions/States during the year. The subjects covered included Crop Loan System, Deposit Mobilisation, Banking Regulation Act and Lending for Minor Irrigation. The College also continued to conduct courses for the benefit of commercial and co-operative/land development banks, etc.

421. Measures for enlarging the facilities at the campus in pursuance of the Datey Committee's recommendations, to which a reference was made in the last year's Report, are already under way. As a first step, faculty strength of the College has been augmented.

422. Since its inception, the College has so far imparted training to 5.291 personnel of co-operative, land development and commercial banks, as also the RBI including 1,527 trained during the year under review.

^{31.} R. B. I. Bulletin, December 1975.

³², R. B. J. Bulletin, July 1975.

^{44.} R. B I. Bulletin, May 1976.

## Staff Training College, Madras

- 423. The College continued to conduct the Staff Officers' Development Programme, the Mobility Courses, the Inspecting Officers' Programmes, and the Credit Management Programme for Bank's own officers With the recruitment of a fresh batch of officers in Grades A/B, the College held a number of sessions of the Induction Programmes for their benefit. In an attempt to make their training more purposive and needbased, the entire scheme of two-year training for such directly recruited officers has been revised so as to place greater emphasis on institutional training at the Staff Trining College (STC) and actual iob performance in supervisory desks The new programmes instituted during the year at the STC were: a Foreign Exchange Programme aimed at equipping the Staff Officers specifically with the knowledge of this subject and seminars on Follow-up of Bank Credit intended to expose the Officers, in Grades A and B to the new approach to bank lending.
- 424. An important development during the year was the setting up of an Advisory Committee for the STC for directing its activities and providing necessary guidance. The need for such a Committee was felt in view of the recent diversification of the STC's tole and activities and undertaking of constant review of its course objectives/contents. The Deputy Governor in-charge of Training is the Chairman of the Committee which includes Chief Officers of DBOD and ACD, Adviser (Administration) of Economic Department. Manager (Training) and Manager, Madras as members and Principal of STC as Member Secretary.
- 425. The total number of employees who have so far received training at the College is 5,193.

## Zonal Training Centres

426. The Zonal Training Centres (ZTCs) at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi continued to conduct courses for Clerks Grade I and Clerks Grade II. The contents of these courses were closely reviewed whereby they have now been made more compact and their duration reduced from 10 to 8 weeks in respect of Clerks Grade I course and from 5 to 4 weeks in the case of Clerks Grade II course. As an experiment in making the training at the ZTCs more functional, two separate courses, one for clerical staff from specialised departments and the other for clerical staff from the general side departments were held at Byculla Centre. In the light of the experience gained, it is proposed to introduce these courses at all the Centres. The total number of clerical staff who have so far received training at the ZTCs stood at 11,603.

## Deputation of Staff

427. The Bank continued to depute its officers to short-term courses on management development, etc., organised by the All India/State level Associations, Management Institutes and a few other similar institutes. Besides, officers were also sent for training abroad to participate in the programmes conducted by the Economic Development Institute, Washington, the Bank of England, the Asian Institute of Economic Development and Planning, Bangkok, etc. Study facilities offered by the banking and financial institutions in the U. K., West Germany, Rome, etc. were also availed of for the Bank's officers. The Bank continued to extend observation/training facilities to the officials/senior executives of foreign banking/central banking institutions. Particular mention may be made of 10 nominees of Da Afghanistan Bank whose training has been an anged under the Technical Co-operation Scheme (TCS) of the Colombo Plan.

## National Institute of Bank Management

428. In 1975-76, the National Institute of Bank Management (NIBM) initiated a number of new activities especially in the context of the emphasis on tural development and introducing discipline in credit management. Some of the research projects initiated and completed during the year 1975-76 pertained to subjects such as (i) household savings

- and financial assets, (ii) influence of bank activities in certain key financial variables such as savings, demand for money, estimation of inventory and formulating credit plan for the economy of a region, (iii) finance for rural electrification programme, (iv) organisation of credit operations for small farmers in a compact area and (v) the banking services in the north-eastern region of the country. One of the important surveys carried out related to the quality of customer service offered by the banks in a city.
- 429. Another important project assigned to the NIBM relates to the recruitment and training of Members of Spearhead Teams for organising Farmers' Scrvice Societies for Regional Rural Banks. A beginning was made in this direction by organising two camps, one each in the northern and eastern parts of the country, to select members for this programme.
- 430. During the year, 50 training programmes, conferences, seminars and workshops were held at which over 1,000 executives participated. NIBM also organised a training programme for credit planning officers of DPAP in collaboration with the Agricultural Finance Corporation. NIBM is collaborating with the Asian Development Institute of the United Nations, in the area of rural development. In 1975 a conference of Chairmen of Agricultural Development Banks and a course for the Senior Executives were organised.

#### Promotion of Hindi in RBI

- 431. During the year under review, the Bank took further measures to promote the use of Hindi. These include: (i) Use of bilingual badges i.e. badges with the Bank's name in both Hindi and English by the Clas IV staff wearing uniforms in the Bank's offices in Hindi speaking areas and in the States of Maharashtra. Gujarat and Punjab: (ii) Bilingualisation of the name plates on the Bank's staff cars in the above offices; (iii) Purchase of telephone directory in Hindi by each Department in the above offices and (iv) Permission for use of Hindi by the officers and employees as a medium in official discussions and conversations, if they so desire, subject to certain conditions/limitations. Hindi libraries were set up in the Bank's offices/training institutions to enable the members of the staff to develop and sustain their knowledge of Hindi.
- 432. In compliance with the provisions of the Official Languages Act, 1963, licences for opening branches in Hindispeaking areas and in the States of Maharashtra. Guiarat and Punjab continued to be issued by the Department of Banking Operations and Development in Hindl and English. The Exchange Control Department printed some more permit forms in both Hindi and English.
- 433. The Official I anguages Implementation Committee (OII) of the Bank continued to review the progress made in the use of Hindi in the Bank and its associate institutions. In pursuance of the decision taken last year, local OLI Committees were set up in the Bank's offices at Kanpur and New Delhi during the year with a view to watching the implementation of various instructions issued by the Bank from time to time regarding progressive use of Hindi.
- 434. As in the previous years, the Bank brought out Hindl versions of its Annual Report and those of associate institutions and the Report on Currency and Finance (abridged). The RBI monthly Bulletin and its quarterly house journal Without Reserve' continued to be published with separate Hindi Sections as before. Two publications viz. RBI (Note Refund) Rules, 1975 and a summary thereof were brought out in Hindi for the benefit of the public A Hindi version of RBI Remittance Facilities Schemes, 1975 was prepared and published in the RBI Bulletin. 4 The preparation of a Hindi glossary of banking terms initiated last year, is in progress.
- 435 The Hindi Adhyayan Mandal (Hindi classes) and the scheme of payment of honorarium to the Bank's employees for passing the recognised Hindi examinations were continued. The facilities of the correspondence courses in Hindi conducted by the Central Hindi Directorate, Ministry of Education were also availed of by some of the employees. The

³¹ December 1975 issue.

Compulsory Hindi Teaching Scheme for the officers of the Bank which was put into operation in 1974, was extended to seven more centres during the year, under review The cash incentive scheme applicable to the Bank's Typists for passing Hindi typewriting examination was extended to Stenographers and Personal Assistants of the Bank.

436 The Bank participated in the convention organised by Hindi Sahitya Sammelan at Prayag from December 6 to 8, 1975 At this convention the Bank arranged an exhibition entitled 'Hindi in Banks' depicting the progress made in the use of Hindi in the Reserve Bank and public sector banks. A similar exhibition was also arranged by the Bank on the occasion of the second convention on Official Language organised at New Delhi from May 14 to 16, 1976 under the joint auspices of Akhila Bhuatiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi and Hindi Vidyapith, Devghar (Bihar)

## Promotion of Hindi in Public Sector Banks

437 During the year, effective steps have been taken to ensure compliance with the provisions of the Official Languages Act, 1963 by all the public sector bank. The important decisions taken in the meetings of the Official Languages Implementation Committee of the Department of Revenue and Banking (Banking Wing) were continued to be conveyed to all the public sector banks for their guidance and compilance and the Government of India is being apprised of the progress made by the banks on the basis of the information furnished by them in their various reports, viz (a) quarterly progress reports, (b) assessment reports, (c) parliamential committee reports, (d) reports on the follow-up action on the various circulars issued by the Department of Banking Operations and Development (DBO & D) and (e) reports on the follow-up action on the decisions of the Official Languages Implementation Committee of the Department of Revenue and Banking

438 To study the progress made of the nublic sector banks and to discuss the problems, if any, in implementing the instructions regarding introduction of Hindi in the tanks, the DBO & D had convened an informal meeting in Bombay of the senior executives of the banks, on August 29, 1975. The banks with headquarters in Bombay and Bank of Maharashtra were invited to attend the meeting. The participating banks expressed their desire that such meetings should be held frequently so that instructions issued by Government for implementing the Official Language Programme could be discussed and on the spot decisions taken for solving the problems.

439 In view of the above and in order to co-ordinate the efforts of all the public sector banks for the progressive use of Hindi, decision has been taken to constitute an Official Languages Implementation Committee in the DBO & D of RBI with the following members

Chief Officer, DBO & D, Reserve Bank of India, Chairman Bombay Manager, (Training), Department of Administration and Personnel, Reserve Bank of India, Member Bombay One representative each of Member the nationalised banks Representative of State Bank of India, (He will represent 7 Subsidiary Banks of SBI also) Member Assistant Manager, Hindi Division, Reserve Bank of India, Me ther Bombay Sudars 440 The Hindi Cell of the DBO & D will work as the Secretariat for the above Committee This Committee will also act as a Central Coordinating Committee for all the Official Languages Implementation Committees functioning in 22 public sector banks

## VIII. ACCOUNTS AND OTHER MATTERS

441 During the accounting year ended June 30, 1976 the Bank's income, after making adjustment tor various provisions, amounted to Rs. 516 00 crores as compared with last years income of Rs. 448 01 crores. The details of the income from various sources are as follows.

	•	mounts in
	Ye	ar
	1975-76	1974-75
(t) Interest on Ways and Means Advances to State Governments	11 80	13 01
(ii) Interest on Loans and Advances to the State Governments (other than on Ways and Means Advances re- ferred to at item (i) above) and Com- mercial and Co-operative Banks	98-81	65 54
(iii) Interest on Rupee Securities and Discount on Rupee Treasury Bills	306 61	290 35
(1v) Interest and Discount on Foreign Securities, Investments and Treasury Bills	80 26	59 81
(v) Commission and Profit or gain by	12 76	4 13
(vi) Other meame	13 30	18 98
	523 54	451 82
Less Interest paid to the Scheduled Banks on the additional average daily balances maintained by		
them with the Reserve Bank	7 54	3 81
	516 00	448 01
Less · Transfers to Funds as stated in paragraph 442 below	221 00	220 00
· <del></del>	295 00	228 01

442 The contributions to the National Agricultural Credit (1 ong Term Operations) Fund, the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund and the Local Industrial Credit (I ong Term Operations) Fund were Rs 60 cross 5 crores and Rs 150 cross, during the year 19.5-76 as 150 cross, Rs 45 crores and Rs 125 cross, respectively, during the year 1974-75

443 Out of the balance of income amounting to Rs 295 00 croies after allowing for total expenditure of Rs 105 00 croies during the year (as against the balance of income amounting to Rs 228 01 crores and expenditure of Rs 78 01 crores in the pievious year) the surplus of profit set aside for payment to Central Government was Rs 190 crores in comparison with Rs 150 crores paid last year

444 The rise of Rs 67.99 crores in the total income from the level of Rs 448.01 crores last year to Rs 516.00 crores was largely due to (i) higher interest earned on loans and

advances to State Governments and commercial and cooperative banks; (ii) higher interest earned due to increase in foreign exchange reserves during the year; and (iii) higher discount earned on treasury bills. The rise of Rs. 26.99 crores in the expenditure was mainly due to (i) errears of commission paid to the State Bank of India and its Subsidiaries on Government turnover transactions during the period 1970—75 on the basis of the recommendations made by the Committee for determining the cost of conducting Government business by State Bank of India; (ii) an increase in the manufacturing cost of note forms; and (iii) increase in contribution to the Gratuity and Superannuation Fund on account of accrued gratuity liability.

### Auditors

445. The accounts of the Bank have been audited by Messrs C. C. Chokshi & Co., Bombay, Messrs Lovelock and Lewes, Calcutta, Messrs Raghu Nath Rai & Co., New Delhi and Messrs M. K. Dandekar & Co., Madras, who were appointed by the Government of India by notifications Nos. F. 1(12)/76/Accts, I & II both dated May 15, 1976, issued in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934). Messrs C. C. Chokshi & Co. and Messrs Lovelock and Lewes were appointed by the Government in place of Messrs Dalal & Shah and Messrs P. K. Mitra & Co., respectively, while Messrs Raghu Nath Rai & Co. and Messrs M. K. Dandekar & Co. have been reappointed by the Government. In addition to the Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi offices, books of accounts of the Bhopal and Bhubaneswar offices of the Bank were also audited by the Bank's statutory auditors this year. The remuneration of the auditors for the audit of accounts of Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi Offices remained unchanged at Rs. 15,000 per office. In the case of Bhopal and Bhubaneswar Offices the remuneration was Rs. 10,000 per office.

#### Central Board

- 446. Shri N. C. Sen Gupta relinquished charge of the office of Governor of the Bank as from the close of business on August 19, 1975, and was nominated as a Director of the Central Board of the Bank under Section 8(1)(d) of the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from October 9, 1975.
- 447. Shri K, R. Puri was appointed as the Governor of the Bank for a period of one year with effect from the close of business on August 19, 1975 vide Government of India notification No. F. 7/11/75-BO. I dated August 18, 1975 and he assumed charge of office of the Governor of the Bank with effect from the forenoon of August 20, 1975. His term has since been extended by two years.
- 448. Shri V. V. Chari, whose term of appointment as Deputy Governor of the Bank expired on November 16, 1975, was granted an extension by the Central Government till the end of November 1975. Shri Chari relinquished charge of office as Deputy Governor of the Bank from the close of business on November 30, 1975. Shri S 9. Shiralkar relinquished charge of office as Deputy Governor of the Bank on expiry of his term on position of the Bank on expiry of his term on position of the valuable services rendered by Deputy Governors Sarvashri Chari and Shiralkar during the services of the Bank
- 449. Dr. K. S. Krishnaswamy and Shri P. R. Nangia the Executive Directors of the Bank, were appointed by the Government of India as Deputy Governors of the Bank for a period of five years, commencing on December 29, 1975 and ending with December 28, 1980.
- 450. Dr. D. P. Singh and Shri Akbar Hydari were appointed as Directors of the Central Board of the Bank under sub-section (4) of Section 12 read with sub-section (5) thereof and clause (c) of sub-section (1) of Section 8 of the RBI Act, 1934 with effect from November 13, 1975. Shri Akbar Hydari was renominated by the Central Government under clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (7) of Section 8 of the RBI Act, 1934 for a period of four years from April 22, 1976.

- 451. Seven meetings of the Central Board were held during the year, two of which were held in Bombay and one each in Madras, Panaji (Goa), Calcutta, Gauhati and New Delhi. The Committee of the Central Board held fifty-two meetings, two of which were held in New Delhi.
- 452. Shri J. C. Luther, Officer on Special Duty, was appointed as Executive Director of the Bank with effect from December 24, 1975.

#### Local Boards

453. There was no change either in the composition or in the membership of the Local Boards during the year under review.

## **Press Relations**

454. The Press Relations Section continued its activities of disseminating information to the public about the working of the Bank and its affiliates. The Section also continued to issue a fortnightly newsletter to keep the staff informed about matters concerning current developments in the economic financial and banking sectors, besides providing the staff with up-to-date information on important functional as well as internal matters concerning the Bank's departments/offices and associate institutions. During the year, the Section brought out two informative brochures: "Facilities for Non-residents of Indian Nationality or Origin for Remutance of Funds to India" and "Exchange Control Regulations as Applicable to Indians Abroad."

## Bank's Premises

455. The construction programme of the Butter various projects continued to be affected during the year under review as the ban imposed butter. Government in 1973 on construction of no functional buildings was extended initially for the familiar year 1975-76 but was later withdrawn in January 1976. The Bank had, however, obtained exemption for going ahead with the construction of office building projects at Bhubaneswar, Gauhati and Trivandrum and residential projects at Bhubaneswar, Hyderabad and Chandigarh in view of the pressing need for early construction of these projects. The progress of work in respect of the Bank's building projects, which had slackened due to shortage of cement, gained momentum consequent on withdrawal of the restriction on use of cement earlier imposed by the Government under the Cement (Conservation and Regulation of Use) Order, 1974. The present position of the new projects under construction is given in the following paragraphs.

## New Office Premises

456. During the year under review, the construction work of the Bank's multi-storeyed office building in the compound of the Mint, Bombay, progressed satisfactorily and has reached the first floor. The R.C.C, frame work of the Bank's office building at Hyderabad is practically complete and finishing items of work are in progress. The contracts for civil works in respect of Bank's office buildings at Bhubaneswar, Gauhati and Trivandrum have been awarded and the constructions are in progress.

## Residential Quarters

457. The construction of 152 quarters for the Bank's officers at Bombay and 283 quarters for clerical and subordinate staff at Calcutta and Madras has been completed during the period under review. With this, the total number of quarters provided by the Bank for its staff has risen from 3,890 to 4,325. In addition, 326 quarters for clerical and subordinate staff viz., 140 at Kodambakkam, Pudur, Madras and 186 at Csborne Road, Bangalore are in final stages of completion. The contracts for the civil work in respect of 305 staff quarters at Hyderabad and Bhubaneswar have been awarded recently and are in progress.

## Purchase of Land for Office Buildings/Staff Quarters

458. Possession of the plots of land for office building and staff quarters at Cochin and for additional staff quarters at Patna has been taken.

#### Employer-Employee Relations

459. Two important events took place during the year under review having a direct impact on employer-employee relations in the Bank. The first was the declaration of national emergency by the Government of India on Tane 25, 1975 and the second was the declaration by the Government of India on March 19, 1976 making employment in the Reserve Bank an essential service under the provisions of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971

and Internal Security of India Rules, 1971

460. Soon after the declaration of national emergency, the Bank, in line with the Government Departments and other public sector organisations, took several steps to improve efficiency and discipline in the Bank. Attention was particularly given to certain matters like punctuality, attendance, devotion to duty, economy in expenditure, reduction of overtime work, etc. The Governor also that the heads of departments in Bombay in July 1975 in pursuance of which, several instructions were issued to regulate the activities of all categories of the staff of the Bank. Later, the Governor convened a Managers' Conference in Bombay in April 1976 which was attended by the Managers of all RBI offices as well as the heads of departments in Bombay. The progress made so far as well as further steps which need to be taken for improving efficiency and discipline, were discussed in the conference.

461. The Bank also appointed a High Power Committee under the Chairmanship of Shri V. A. Rao, a former senior executive of the Bank, to study and make recommendations for improvements in the customer service, avoiding wasteful and restrictive practices etc. in the Bank. The recommendations made by the Committee were discussed at the Managers' Conference with a view to implementing them as expeditiously as possible. In the context of the measures taken by the Bank in the wake of the emergency and the declaration of service in the Bank as essential, an improved climate of efficiency and discipline has been ushered in the Bank.

462. Concurrently with the above steps taken by the Bank to bring about an atmosphere of improved efficiency and discipline in the Bank, the Bank continued its efforts to maintain harmonious relations with the employee-organisations. Discussions on various issues raised by them were held at the Central Office level as and, to:

August 1975...

- (i) With the All India Reserve Bank Employees' Association representing the clerical staff of the Bank.
- (ii) With the All India Reserve Bank Workers' Federation representing the subordinate staff of the Bank.

January 1976 -

With the All India Reserve Bank Staff Officers' Association.

April 1976-

With the Reserve Bank of India Officers' Association.

463. At the branch level, the Managers/Officers-in-Charge of the offices held concultation meetings/discussions with the representatives of the units of the local Employees' Association/Workers' Union at their respective centres.

464. As in the previous year, during 1975-76 also, the Bank continued to extend pattonage/financial assistance to various welfare activities such as staff sport, clubs, staff canteens, welfare organisations in various staff quarters, etc.

465. The Bank's House Magazine, published quarterly, continues to provide a very popular forum for the staff of the Bank to give expression to the literary, cultural academic and other talents as well as to publicise the activities in the social and domestic spheres. As in the previous years, the Staff Suggestion Scheme introduced by the Bank attracted suggestions from various members of the stuff.

## Employees' Housing Loan Scheme

466. The total amount of 'society' and 'individual' forms sanctioned since the introduction of the Scheme in 1961 amounts to Rs. 6.21,92,99,300 and Rs. 3.94,28,068,00 respectively. In all, 3.885 employees have availed 'hemselves of this facility.

25 61 77-21

· 467. During the year under report Housing Loans were sanctioned as under:

		No. of Societies	Amount Rs.
Α.	New Co-operative Housing Societies	4	20,61,061 . 00
	operative Housing Societies already formed	4	31,73,133.00
			52,34,194.00
		No. of Emplo- yees	Amount Rs.
В.	Individual members of Staff Additional Loans to Employees who had already availed	218	64,66,502 00
	of loans earlier	54	17,17,426.00
			81,83,928.00

## Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Bank's Service

468. As mentioned in the last Report the special measures, such a relaxations in the basic eligibility standards and qualifying norms, wider publicity of reserved posts in the Bank's service and, where necessary, special recruitment confined to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, coupled with administrative instructions issued from time to time, have resulted in increasing the representation of Scheduled Castes in various cadres as also in clearing the back-log to a considerable extent. The above special measures were continued during this year also and as a result, the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the Bank registered a further increase. Compared to the position as on January 1, 1975, the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees has increased from 1,043 in Class IV, 1,412 in Class III and 48 in Classes II and I to 1,217, 1,750 and 53 respectively, as on January 1, 1976. Besides the back-log in the recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Class III cadies could be cleared to the extent of 69 per cent and 18 per cent, respectively, by the end of June 1976, in addition to filling the prescribed current quota.

469. As in earlier years, the Bank has been anxious to increase the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Officers' cadre. Accordingly.—

- (1) the Reserve Bank of India Services Board were advised to recommend Scheduled Castes/Scheduled Tribe candidates for recruitment as Staff Officers Grade 'A' (Direct Recruits) by relaxing the standards where necessary having regard to the maintenance of efficiency in administration. The Board could, therefore, recommend 34 Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates for appointment as Staff Officers Grade 'A' (Direct Recruits), as against 27 posts reserved in their favour, in the selection finalised by them in the year under review.
- (2) the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees who appeared for the qualifying examination for promotion to the cadre of Staff Officers Grade 'A' held in September 1975 were also given certain relaxations as a result of which 31.4 per cent of those who took the test were declared successful in the test as against only 17.8 per cent qualified in the preceding test.

470 The above policy of judging the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates by a relaxed standard has been extended to the cadre of Staff Officers Grade 'B' also.

471. During the year under review, the Bank decided to provide for 10 per cent reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in allotment of residential accommodation in the Bank's colonles meant for its Class III and IV employees.

472 An Officer in the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Cell in Central Office visited during the year some more offices of the Bank i.e., Calcutta, Gauhati, Nagpur, Patna, Kanpur, Ahmedabad and Jaipur to check the rosters maintained for recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the implementation of Central Office instructions regarding various other concessions to be extended to employees belonging to these communities.

## RESERVE BANK OF INDIA

## BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1976

#### ISSUE DEPARTMENT

	LIABILITIES			ASSETS							
	Rs.	P.	Rs. F	2.		Rs.	P.	Rs,	P.		
Notes held in the Banking Department	24,67,21,37	2.00			Gold Coin and Bullion:  (a) Held in India  (b) Held outside India .	182,52,50,61	7.44				
Notes in circulation .	7150,33,90,12	3.50			Foreign Securities	546,73,97,23					
Total Notes issued .		<del></del>	7175,01,11,495	5.50	Total Rupee Coin			729,26,47, 15,30,04,			
					Rupee Securities . Internal Bills of Exchange and other Commercial			6430,44,59	9,255.12		
					Paper				•••		
Total Liabilities .			7175,01,11,495	.50	Total Assets			7175,01,11,	495.50		

## BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES		ASSETS						
	Rs. P.	Rs.	P.					
Capital Paid-up	5,00,00,000.00	Notes	00					
Reserve Fund	150,00,00,000.00	Rupee Coin 4,01,936.	co					
National Agricultural Credit (Long-Term		Small Coin	15					
Operations) Fund	400,00,00,000.00	Bills Purchased and Discounted :						
National Agricultural Credit (Stabilisation)		(a) Internal	. 67					
Fund	145,00,00,000.00	(b) External						
National Industrial Credit (Long-Term		(c) Government Treasury Bills	34					
Operations) Fund	540,00,00,000.00	Balances Held Abroad*	.82					
•		Investments**	86					
Deposits:		Loans and Advances to :—  (i) Central Government						
(a) Government	63,12,38,550.20							
(i) Central Government (ii) State Governments	138,78,48,015.79	(ii) State Government@	.uu					
(ii) State Governments	136,76,46,013.79	(i) Scheduled Commercial Banks† . 941,98,48,796	.30					
(b) Banks		(ii) State Co-operative Banks: 156,18,63,494						
	-50 5- 50 404 40	(iii) Others	00					
(i) Scheduled Commercial Banks .	758,54,09,484.28	Loans, Advances and Investments from						
(ii) Scheduled State Co-operative	CO 00 04 C42 40	National Agricultural Credit (Long-Term						
Banks	60,98,94,643.18	Operations) Fund						
(iii) Non-Scheduled State Co-operative	1 (0.00.005.05	(a) Loans and Advances to :—	٠.					
Banks	1,69,82,005.95	(i) State Governments						
(iv) Other Banks	4,18,42,239.38	(ii) State Co-operative Banks 12,59,04,003	.33					
(c) Others	2130,62,82,282,95	(iii) Central Land Mortgage Banks (iv) Agricultural Refinance and Develop-	• •					
		ment Corporation 138,40,00,000	.00					

	LIABILITIES		ASSETS	
Bills Payable	. ,	79,91,90,407.09	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,82,07,720.00
Other Liabilities\$ .		549,59,08,322.22	tural Credit (Stabilisation) Fund  Loans and Advances to State Co-operative Banks	78,74,60,968.00
			Operations) Fund	
			the Development Bank	827,30,98,779.02
Total Liablitties		5027,45,95,951.04	Total Assets	5027,45,95,951.04

Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,00,000.00 (Sterling Investments of £ 50,000 converted @ Rs. 100=6.2500) *Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

- **(1) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.
  - (ii) Includes Rs. 8,37,91,214.71 (equivalent of £ 50,000, U.S. \$ 9,002,500.00 and D.M. 660,000.00) held abroad.
- @Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 10,30,00,000 advanced to scheduled commercial banks against unsance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

- £ Includes an amount of Rs. 478,12,00,000 advanced to certain Scheduled Commercial Banks under special arrangements.
- \$ Includes contingency accounts.

W. J. F. VAZ Chief Accountant Dated the 30th July, 1976. K. R. PURI,
R. K. HAZARI,
Peputy Governor
R. K. SESHADRI,
Deputy Governor
K. S. KRISHNASWAMY,
P. R. NANGIA,
Deputy Governor
Deputy Governor

## PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1976

INCOME												
Interest, Discount, Exchange, Commission, e	etc. †											Rs. P, 294,99,72,239,32
												294,99,72,239.32
EXPENDITURE											_	
Establishment												35,49,37,921,61
Directors' and Local Board Members' Fees a	and E	xper	isos								,	81,484.98
Auditors' Fees												80,000.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc												1,58,81,750.46
Law Charges												1,03,769,71
Postage and Telegraph Charges				,					,			19,48,335.00
Remittance of Treasure;												46,78,237.46
Stationery, etc												54,31,080.33
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	)						,					14,38,45,495.76
Depreciation and Repairs to Bank Property												1,31,96,766.72
Agency Charges†††												43,01,12,622.71
Contributions to Staff Gratuity and Superans	nuatio	on F	ands:	††††								7,08,15,842,51
Miscellaneous Expenses												1,82,15,270.04
Net available balance						•		-				190,00,00,136.95
Total												294,99,72,239.32
Surplus Payable to the Central Government .			•							<u>.</u>	•	190,00,00,136.95

#### RESERVE FUND ACCOUNT

			 										Rs. P.
By Balance on 30th June 1976 .						٠.	•						150,00,00,000.00
By transfer from Profit and Loss A	ccount			,	•		,	•		•		•	Nil
												_	150.00.00.000.00
l'otal ,		•	•	1				•	•	•	•	•	150,00,00,000.00

[†]After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act and transfer of Rs. 221 croics to Funds under Sections 46A, 46B and 46C.

K. R. PURI Governor
R. K. HAZARI Deputy Governor
R. K. SESHADRI Deputy Governor
K. S. KRISHNASWAMY Deputy Governor
P. R. NANGIA Deputy Governor

W. J. F. VAZ
Chief Accountant
Dated the 30th July, 1976

## REPORT OF THE AUDITORS

## TO THIL PRESIDENT OF INDIA,

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30th June 1976.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and of the offices at Calcutta, Bombay (Fort), Madras, New Delhi, Bhubaneswar and Bhopal and with the returns submitted and certified by the Managers of the other Offices and Branches, which Returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information from the Central Board such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank.

Messers. C. C. CHOKSHI & CO.
Messers. LOVELOCK & LEWES
Messers. RAGHU NATH RAI & CO.
Messers. M. K. DANDEKAR & CO.

Anditors

Dated the 16th August, 1976

## STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET

	For the year ended										
Particulats		June 30	1974		June 30, 1975						
ISSUE DEPARTMENT	Rs.	P.	Rs.	Р.	Rs.	P.	Rs.	Р.			
LIABILITIES Notes held in the Banking Department Notes in circulation	37,17,59,1 6472,72,04,1				15,49,78,7 6584,76,76,5						
Total Notes issued	<del></del>		6509,89,63	352.50			6600,26,55	,352.50			
Total Liabilities			6509,89,63,	352.50			6600,26,55	,352 . 50			
ASSETS											
Gold Coin and Bullion:  (a) Held in India	182,53,04,7	31.42			182,52,58,1	01.88					
(b) Held outside India	166,73,97,3 7,50,63,				121,73,97,3 5,59,96,	917.65					
Government of India Rupee Securities .	6153,11,97,5	99.19			6290,40,03,0	98,76					
Internal Bills of Exchange and other Com- mercial Paper							• •				
Total Assets			6509,89,6	3,352.50			6600,26,55	352 50			

[‡]After adjusting recovery of Rs. 1,07,58,076.26 against payment made in previous years.

^{†††}Includes Rs. 11,59,68,700.00 relating to earlier years.

^{††††}Includes Rs. 6,42,15,842.51 appropriated on account of accrued gratuity liability for past years.

1	2	3 4 5
BANKING DEPARTMENT		
LIABILITIES		
Capital Paid-up	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
Reserve Fund	150,00,00,000,000	150,00,00,000,00
National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	284,00,00,000.00	334,00,00,000 00
National Agricultural Credit (Stabilisation)		
Fund	95,00,00,000.00	140,00,00,000.00
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	265,00,00,000.00	390,00,00,000.00
Deposits		
(a) Government		
(i) Contral	61,57,98,480.17 26,36,81,522.93	77,69,36,995.84 8,44,73,019,23
• •	20,30,01,242.93	0,74,73,019,23
(b) Banks	552 50 77 102 07	(0) 50 <b>3</b> 4 97 . 07
(i) Scheduled Commercial Banks .	553,50,77,103.97	603,50,24,866 . 97 42,99,13,458 . 16
<ul><li>(ii) Scheduled State Co-op. Banks .</li><li>(iii) Non-Scheduled State Co-opera-</li></ul>	26,26,10,122 81	+4,72,1.7,430 [0
tive Banks	1,48,06,487.84	1,45,98,463.70
(iv) Other Banks	1,09,04,310.40	1,74,10,401.96
(c) Others	512,57,15,516.12	982,43,69,501.90
Bills Payable	125,52,38,985.22	97,97,68,768.31
Other Liabilities	483,81,97,868.98	750,66,31,290.04
Total Liabilities		1,20,30,398.44 3585,91,26,766.11
ASSETS		
Notes	37,17,59,161.00	15,59,78,757.00
Rupec Coin	3,49,127.00	5,01,112.00
Small Coin Bills Purchased and Discounted:	2,51,761.34	2,79,617.24
(a) Internal	27/ 27 70 200 93	126,12,80,388.35
(b) External	274,37,78,289.83	120,12,00,300.33
Government Treasury Bills	128,67,52,866,15	332,15,67,737.92
Balances held abroad	596,33,23,105.291	410,95,25,397.681
Investments	217,37,84,159.20°ab	677,45 14,553,66°ac
Loans and Advances to		
(i) Central Government	177.02 - 2.444.404	25/1 00 50 000
(li) State Governments	177,82,73,164.181	359,90,72,000,003
(iii) Scheduled Commercial Banks (iv) State Co-operative Banks	420,99,85,000,004 166,52,34,128,004	385,26,87,000.00° 286,74,36,215.00°
(v) Others	38,16,95,000.00	59,88,45,001.00
Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long-Ierm	,-0,,	
Operations) Fund :		
(a) Loans and Advances to:		
(i) State Governments	67,87,33,623.72	69,70,59,860.92
(ii) State Co-operative Banks	15,65,67,755 33	13,33,72,365.66
(iii) Central Land Mortgage Banks	1.5	
(iv) Agricultural Refinance Corpo- ration	54,00,00,000.00	88,20,00,000.00
ration	୰୳୲୰୰ୢ୲୰୰ୢ୲୰୰୰୷୰୰	00,20 <u>,000,000</u> ,0 <del>0</del> 0
Bank Debentures	11,13,13,970.00	10,65,45,520.00
Loans and Advances from National Agricul-	•	
tural Credit (Stabilisation) Fund to State	da 09 /0 110 00	06 7/ 00 04 / 00
Co-operative Banks	52,87,68,118.00	82,54,99,826.00

1	2	3	4	5
Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund:	<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(a) Loans and Advances to the Development Banks	178,69,55,519.00		264,64,55,619.00	
issued by the Development Banks .				
Other Assets	153,45,05,650.407		402,75,05,794.68*	
Total Assets		2591,20,30,398.44		3585,91,26,766.11

June 30, 1974—Contingent liability on partly paid shares Rs. 9,48,388.69 (Sterling Investments of £50,000 converted @Rs. 100 = £5,2721).

June 30, 1975—Contingent liability on partly paid shares Rs. 9,39,999.81 (Sterling Investments of £50,000 converted  $\bar{w}$ Rs. 100 = £5,31915).

- 1. Includes Cash, Fixed Deposits and Short-Term Securities.
- a. (a) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.
  - (b) Includes Rs. 5,39,54,792 90 (equivalent of £50,000, U.S. \$6,247,475 and D.M. 1,110,375) held abroad.
  - (c) Includes Rs. 5,57,42,281.96 (equivalent of £50,000, U.S £6,005,000.00 and D.M. 9,22,650 00) held abroad.
- Excluding loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund but including temporary overdrafts to State Governments.
- 4. Includes Rs. 156,63,73,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.
- 5. Includes Rs. 208,37,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.
- 6. Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Torm Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.
- Includes an amount of Rs. 50,00,00,000 advanced to certain scheduled commercial banks under special arrangements in respect
  of their investments abroad.
- Includes an amount of Rs. 188,20,00,000 advanced to certain scheduled commercial banks under special arrangements in respect of their investments abroad.

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1974 AND 1975

			_ ••							1974	1975
										Rs. P.	Rs. P
INCO	OME	— — C					•		_		
Interest, Discount, Exchange, Commission, e	tc.†									195,47,95,113.00	228,00,56,335.3
										195,47,95,113.00	228,00,56,335.3
]	EXP	ENDI	ITUI	RE						<del></del>	<del></del>
Establishment										28,53,25 934.78	34,65,01,633.4
Directors' and Local Board Members' Fees &	& Ex	pense	8							66,346.31	1,05,246.1
Auditors' Fees										80,000.00	80,000.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc										1,16,05,263.44	1,24,49,577.2
Law Charges									,	1,68,540.71	87,719.80
Postage and Telegraph Charges										14,04,042.18	16,32,353,18
Remittance of Treasure										81,33,581.59	94,38,912.02
Stationery, etc.										40,22,877.04	57,20,982,75
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	)									5,19,42,441.13	5,82,42,274.86
Depreciation and Repairs to Bank Property										1,10,81,345.49	1,30,46,628.8
Agency Charges								,		11,19,19,385.81	31,24,70,222.4
Contributions to Staff and Superannuation F										50,00,000,00	40,00,000.0
Miscellaneous Expenses										1,40,45,191.20	1,62,79,950.3
Net available balance				-						145,00,00,163.32	150,00,00,834.3
TOTAL	•									195,47,95,113 .00	228,00,56,335.3
Surplus Payable to the Central Government .						•			,	145,00,00,163.32	150,00,00,834.3
RESERV	E FU	JND	ACC	COUN	νī [—]						<del>.</del>
By Balance on 30th June										150,00,00,000 00	150,00,00,000.00
By Transfer from Profit and Loss Account										Nil	Nil
TOTAL					·	·	•			150,00,00,000.00	150,00,00,000.0

## नई विल्ली, 2 मई, 1977

का० सा० 1490.—भारतीय रिजर्व बैंक प्रधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (क) और उप धारा (1) के प्रम्यरण में, केन्द्रीय मरकार, एतव्हारा श्री एम० नर्गमहम को 2 मई, 1977 से अगले प्रावेशों तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर नियक्त करनी है।

[मं० एफ० 7(3)/77-वी० ग्रो० रू] बलदेव सिह्, सयुक्त संखिव

## New Delhi, the 2nd May, 1977

S.O. 1490.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) and sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby appoints Shi M. Narasimham as the Governor of the Reserve Bank of India with effect from 2nd May, 1977 until further orders

[No. 7/3/77-BO. 1] BALDEV SINOH, Jt. Secv.

## केन्द्रीय उल्पाब शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय

कलकत्ताः २९ विसम्बर, 1976

## केन्द्रीय उत्पाव शस्क

का॰ भा॰ 1491. — केन्द्रीय उत्पाद णुल्क नियम, 1941 नियम 15 के साथ नियम 233 के द्वारा प्राप्त कार्यक्षमाना का उपयोग करने हुए तथा इस समाहर्नालय के दिनांक 18-8-69 की ग्रांधमूचना सं० 2/69 जिसमें सम्पूर्ण मालदह जिले को "ग्रांनिरिक्त उपजाऊ क्षेत्र" सूचित किया गया है, का श्रांशिक संणोधन करने हुए नीचे दिए गए तालिका के कालम 2 मे उल्लिखित मालदह जिला के गावों के क्षेत्रों को छांड्कर प्रन्य क्षेत्रों को "ग्रांनिरक्त उपजाऊ क्षेत्र" घाषित करना हूं जहां सम्बाक् उत्पादक उपरोक्त नियम के श्रमुमार प्रपत्न उत्पाद क्षेत्र की घोषणा देने से इस गार्ने पर विचत किये जाने है कि उनके द्वारा उपयुक्त क्षेत्र 10 एरीज से घषिक न हो।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दी गई सीमा से ऋधिक क्षेत्र में तम्बाकू की खेती करती है तो सामान्य उत्पाद शुरूक का दायीदार होंगा। सारणी

जिलाकानाम	उपयुक्त भ्रम	छूट मार	दी ग ब्रा
मालदह	मपूर्णं (रतुष्ठा थाना के प्रधीन बलरामपुर, पिरजई, सुल्यानगंज, रनुष्ठा, हरिपुर, गोकुलपुर, खेलसना, ककुन्दीपुर, सत्मरा, कुतुबगज, धासीनगर, परनपुकुर, खेमपुर, महाराजपुर, कुमारगंज, रानीनगर, राजा- पुर, राधानगर, चेकनी, इलाहाबाद गजील थाना के प्रधीन श्रस्तीनगर, राजारामचक, कीयला बाद, रामनगर, कुनुबपुर श्रीर हरिचन्द्रपुरा थाना के ग्रधीन महरिया, कसीमपुर, मोसलवा) ।	40	<b>कि</b> न्नो

[ग्राधिमुचना स० 2-76/सी०मं० **V** (28)16-के० उ०/प० मं०/76]

## Collectorate of Central Excise and Customs

Calcutta, the 29th December, 1976

#### CENTRAL EXCISE

S.O. 1491.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 15 of the Central Excise Rules, 1944, read with Rule 233 of the said rules, and in partial modification of this Collectorate Notification No. 2/69 dated 18-8-69 notifying the whole of the District of Malda as "Sparse growing areas". I hereby notify the areas in the District of Malda other than the areas comprised in villages specified in Col. 2 of the table below as "Sparse growing areas" where the growers of tobacco will be exempt from furnishing declaration of their are as under the said rule provided the area cultivated by a grower does not exceed 10 areas.

If, however, a person cultivates an area in excess of the specified limit, the person cultivating the tobacco shall be subjected to normal excise control.

#### TABLE

Name of the District	Portion Covered	Exempted		
Malda .	. Whole (excluding villages Balarampur, Pirgal, Sultanganj, Ratua, Haripur, Gokulpur, Khailsana, Rukundipur, Satmara, Kutubganj, Ghasinagar, Paran-pukur, Khempur, Maharajpur, Kumargani, Raninagar, Rajapur, Radhanagar, Chekni, Ellahabad Under RATUA P.S., Alinagar, Rajaramchak, Koilabad, Ramnagar, Kutubpur. Under GAZOL P.S. and Maharia, Kassimpur, Mosaldaunder Harischandrapur P.S.)	•		

[Notification No. 2-76/C, No. V (28)16-CE/WB/76]

## कलकत्ता, 23 जनवरी, 1977

भार 1492.— केन्द्रीय उत्पाद मुस्क नियम 14 के नियम 15 भीर 16 के साथ नियम 233 हबिद द्वारा प्राप्त कार्यक्षमना का उपयोग करते हुए और इस समाहतिलय के दिनांक 18/8/69 की भिंधसूचना मंठ 2/69 (केंठ उ०) और 3/69 (केंठ उ०) का भांशिक संगोधन करते हुए नियम 15 हबिद के अनुसार मैं सूचित करता हूं कि जलपाइगुड़ी, कूचबिहार, वार्जिलय और पिष्यम दिनाजपुर जिल्मों में उत्पादको हारा तस्वाकू उगाने के लिए प्रयुक्त दम (10) एरीज भूमि को "परिमित उत्पादन केंव" समझा जाएगा जहा तस्वाकृ उत्पादको को अपने केंवफल की धोषणा न करने की छुट रहेगी।

उपरोक्त जिलों के साथ मालवह जिला के तस्वाक समाधको हारा समोधित बाधिक तस्वाक की माला 40 किलों से घधिक न होने पर वे अपनी उपज की घोषणा नियम 16 इबिद के प्रनुसार नहीं करेगे, लेकिन इस समाहतिलय के दिनाक 29 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना सठ 2/1976 (केठ उ०) में विनिधिष्ट गांबी को छोड़कर।

[भ्राधिसूचना स० 1/77/मी० न०  $\mathbf{V}(28)$  16-कें० उ०/प०ब०/76]

### Calcutta, the 23td January, 1977

S.O. 1492.—In exercise of the powers conferred on me under Rules 15 and 16 of the C. E. Rules 44 fead with rule 233 ibid and in partial modification of this Collectorate earlier Notification Nos. 2/69 (CF) and 3/69(CF) both dated 18-8-69, I hereby notify under Rule 15 ibid that the area of land not exceeding 10(Ten) Ares used by a grower for cultivation of Tobacco in the District of Jalpaiguri, Cooch Behar, Darjeeling and West Dinajpur is to be treated as "Spare growing areas" where the growers of Tobacco will be exempted where the growers of Tobacco will be exempted from furnishing declaration of their areas.

The curers of Tobacco in the said districts as well as in the district of Malda excluding these villages as specified in this Collecorate Notification No. 2/1976(CF) dated 29th December, 1976 will be exempt from furnishing declaration of the said of the constitution of the said of of their yields under rule 16 ibid provided the quantity to be cured by a curer does not exceed 40 kgs. in a year

[Notification No. 1/77/C No. V(28)16-CF/WB/76]

का० आ० 1493.— केन्द्रीय उत्पाद श्रुक नियम, 1944 के नियम 5 के प्रनुसार प्राप्त कार्य क्षमता का उपयोग करते हुए मैं इस समाहर्तालय के केन्द्रीय उत्पाद शुरूक सहायक समाप्तर्ता को धनुमनि देता हू कि ग्रपने कार्य क्षेत्र के प्रधीन वे समाहर्ना के कार्य क्षमता का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शहन नियम, 44 के नियम 115 के तृतीय शर्त क्लाज (ए) के प्रनुसार, धन्ना कम (फ्लू) संसाधित तस्त्राक के सम्बन्ध में समय बढ़ाने के लिए कर सकते है लेकिन यह बृद्धि 2 माल के बाद एक माल से ध्रश्चिक न हो ।

> [ग्रिधिमूचना म० 2/77/मी० न० **V**(16) । को०५०/प०वं०/77] ए० के० भौमिक, समाहर्ता

S.O. 1493.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the CF Rules, 1944, I hereby authorise the Assistant Collector of Central Excise of this Collectorate, to exercise, within their respective jurisdiction the powers of Collector under clause (a) of the 3rd Proviso to Rule 145 of the CE. Rules 44 to grant a further period of extension not exceeding one year beyond the period of two years in respect of flue cured tobacco.

[Notification No. 2/77/C. No.V(16)4/CE/WB/77]

A K. BHOWMIK, Collector,

## केरबीय उध्पाद शुरुक क समाहर्ला का कार्यालय

पूर्ण, 18 मार्च, 1977

## केन्द्रीय उत्पाद श्रुक्क

का० आ० 1494.---केन्द्रीय उत्पाद-गुरुक नियम s के प्रधीन मुझे प्रद<del>न</del> शक्तियो का प्रयोग हुए, मैं संलग्न सारणी के स्तभ 3 में विनिदिष्ट पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद-शहक समाहर्तालय के ध्रधिकारियों को, सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखन नियम के ब्रधीन, उनसे सर्वाधन क्षेत्राधिकार में "समाहर्सा" की गस्तियो का प्रयोग करने के लिए सणक्त बनाना हु।

_	सा	रणी		
समाहर्ताको प्रदक्ष की गयी णक्तिया का स्वस्प		जिस प्रधि- कारी को शक्तिया प्रदत्त की जाने बाली है, उस की श्रेणी	मीमाए यदि कोई हो	· ग्रभ्यक्ति
भाडागारों में अवि- निर्मित तस्वाकृ को स्टोर करने की दो वर्षों की सामास्य श्रविध में श्रीर एक वर्ष की वृद्धि करना		केन्द्रीय उत्पादणुल्क के सहायक समाहर्ना		<u>.                                    </u>
— <u>- — —</u> सि० सी० '		977/फा० सं <b>०</b>	V(4) 8-2/दी	डी/77]

મારું≎ 5/1977/46**૦ લ૦ V (**4) 8-2/લો કો/7 जे० एम० वर्मा, समाहर्ता

## Office of the Collector of Central Excise Pune, the 18th March, 1977 CENTRAL EXCISES

S. O. 1494.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I empower the officers of the Central Excise Collectorate, Pune specified in colum 3 of the sub-joined table to exercise within their respective jurisdiction the powers of "Collector" under the Rule mentioned in column 2 of the table below :--

	TA	ABLE		
Nature of powers conferred on Collector	Rule No.	Rank of officer to whom power to be delegated	Limita- tion if any	Remarks
To grant one year's extension in addition to the normal period of storage of 2 years in warehouses of unmanufactured tobacco.	145 (amended) 3rd Proviso	Asstt. Collr. of C. Ex.	Rectricted to flue- cured tobacco only,	
- <del>-</del>	[No. C.E.]		. No. V(4)8 . VERMA,	

## समाहर्ता कोन्द्रीय उत्पाद शुरुक का कार्यालय

कानपुर, 4 म**ई**, 1977

कां० आ॰ 1495 — भारत सरकार विस सम्रालय (राजस्व श्रीर बैंकिंग विभाग) की श्रीधेस्थना स० ८1/७७ केन्द्रीय उत्पाद शुरुक दिनाक ७१-७-७७ के प्रधीन निर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुरूक नियमावली, १९११ के नियम २९३-ए के प्रनुपालन में नियमालिखिन कोटि के व्यक्तियां के नाम ग्रौर पन भ्रौर धन्य वियरण जो कि उपायद्व मारिणी में है प्रकाशित किये जाते है ।

- (क) वे व्यक्ति जो किसी स्वायालय द्वारा केर्स्याय उत्पाद शल्क ग्रीर समक श्रिधिनियम, 1943 की धारा ७ के अर्धान सिद्ध दोषी ठहराये गये (कनियक-
- (स्व) वे व्यक्ति जिल्हे, श्रीधनियम की धारा 33 में निविष्ट श्रिधिकारी द्वारा अधिनियम के किभी उपायद या उसके अर्थान बनाये गर्थ किसी नियम का उल्लंख न करने वाला पाया गया है और उन पर ऐसे अधिकारी द्वारा दस रूपसे हजार या उससे अधिक के शास्ति अधिरोपित की गई है ।

## सारणी

केन्द्रीय उत्पाद णृत्क और नमक प्रक्षिनियम भीर नियमावली, 1944 के भ्रष्ठीन विभागीय कार्यवाही द्वारा 10,000 रु० या प्रक्षिक से दण्डित श्रेप राधियों के नामो को दिशन करने वाली सारिणी

क्रम सं०	नाम भौर पना	अधिनियम के उपबद्ध या, उसके घल्लगैत बनाये गये नियम जिनका उल्लंघन किया गया है ।		उत्पाव गुल्क योग्य माल या अन्य सम्पत्ति का मृह्य जिसका समय- हरण, न्यायाक्षय बारा नियम की आरा 10 के समीन किया जाता है या धारा 33 में निर्दिष्ट प्रधिकारी बारा न्यायनिर्णीत किये जाने पर जिनका स्रधिकरण किया जासा है।	अधिनियम की धारा 39 के अधीन अधिकरण के अवले जुर्माने की राणि	नियम 181 वे भ्रन्तर्गत फ विवरण
(1)	(2)	(2年)	( 2ख)	( 2ग)	(2可)	( 2 <b>F</b> )
	<del></del>		रु०	क्र	₹0	
1. मधैरटन	वेस्ट एण्ड कभ्यती, कानपुर	म्रधिनियम 9, 53, 173 जी म्रौर 226 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क म्रीघिनियम 1944	25,000.00	24,691.96	8,250.00	~-
2. स्वदेशी प	ीलीटैक्स गाजियाबाद	म्रधिनियम 9(1), 52-ए, 173-एफ म्रौर 173-जी केन्द्रीय उत्पाद मुस्क म्रधिनियम 1944	12,000.00	~~		<b>-</b>
		न्यायालय द्वारा सिद्ध वोषी ठहराये गये (भन -कुछ	•	यों का विवरण~-		

[मधिसूचना स॰ 6/77/सी॰ सं॰ 5 (30) एमपी/मिस॰/एड्ज॰/20/76]

कु० श्री० विलिपसिष्ठुजी, समाहर्ता

# Office of the Collector of Central Excise Kanpur, the 4th May, 1977

- S.O. 1495:—In pursuance of Rule 232-A of the Central Excise Rules, 1944, issued under Govt. of India, Ministry of Finance (Deptt. of Revenue & Banking) Notification No. 21/76-CE dated 21-2-76, the names and addresses and other particulars of the following categories of persons are published herewith in the table annexed below:—

  25 GI/77—22
- (a) persons who have been convicted by a Court under section 9 of the Central Excises & Salt Act, 1944; and
- (b) persons who have been found by an officer referred t in Section 33 of the Act to have contravened any of the provisions of the Act or rules made therein and on whom a penalty of ten thousand rupees or more has been imposed by such officer.

#### **TABLE**

Particulars of offenders on whom a penalty of Rs. 10,000 or more has been imposed in Departmental proceedings under Central Excises & Salt Act & Rules, 1944.

SI.	Name and Addresses	The provisions of the Act or rules made there under contravened		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	in lieu of con- fiscation if any imposed under Sec. 34 of the	any licence re- voked under rule
1	2	2(a)	2(b)	2(c)	(2d)	3
1.	M/s. Atherton West & Co. Ltd. Kanpur/Seiz/MP/Adj/ 40/76		Rs. 25,000	Rs. 24,691.96	Rs. 8250	
2.	M/s. Swadeshi Palytex Ltd., Ghaziabad. Seiz/MP/Adj/ 12/74.	Rule 9(1), 52-A, 173-F & 173G of C. Ex, Rules 1944.	Rs. 12,000	_	<b>-</b>	_

## PARTICULARS OF OFFENDERS CONVICTED BY COURT OF LAW -- NIL --

[Notification No. 6/77/C No. V (30) MP/Misc./Adj/20/76] K.S. DILIPSINHJI, Collector

## वाणिज्य मंत्रालय

## नई दिल्ली, 11 म**ई,** ₹1977

कार आर 1496 — केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंक्षण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रवत्त गावितयों का प्रयोग करने हुए यह द्योतन करने के प्रयोजन के लिए अण-वीपो (फलेशलाइट) के सबध में भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह को मान्यला देने की प्रस्थापना करती है, कि जहां क्षणवीपों पर ऐसे चिन्हन लगाए गए है, वहां यह समझ लिया जाएगा कि वे उक्त अधिनियम के प्रधीन उन पर लागू होने वाले मानक विनिर्देशों के अनुकल हैं

श्रीर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त प्रस्तावों को निर्यात (भवालिटी नियम्नण श्रीर निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की श्रपेक्षा निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है.

ग्रत, ग्रब उक्त उप-नियम के ग्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन सभी व्यक्तियों की आनकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उनसे प्रभावित होने की सभावना है।

- 2 यह सूचना वी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावा के बारे में कोई प्राक्षेप या सुझाव भेजना चाहे तो वह उन्हें इस अधिसूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'बल्डं ट्रेंड मंटर' (आठवी मिजल), 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा।
- 3 परिभाषा—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए 'क्षणदीपो' से अभिप्राय घरेलू तथा अन्य कार्यों के लिए शुष्क बैटरी से जलने वाले अजदीपों से है (जो सामान्यत टार्च के साम से भी जानी जाती है।)

[स॰ 6(1)/76-नि॰ नि॰ तथा नि॰ उ०]

#### MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th May, 1977

SO. 1496—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), proposes to recognize the Indian Standards Institution Certification Mark in relation to Flashlights for the purpose of denoting that where Flashlights are affixed with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the standard specifications applicable thereto under the said Act;

And whereas the Central Government has forwarded the aforesaid proposal to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

- 2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposal may forward the same within fortyfive days of the publication of this Notification in the Official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre' (7th Floor), 14/1B. Ezra Street, Calcutta-700,001.
- 3. Definition—For the purposes of notification, "Flashlights" shall mean dry battery operated Flashlights (also commonly known as torches) for domestic and other uses

[No. 6(1)/76--El & EP]

नई दिल्ली, 21 मई, 1977

## **ল্**ক্রিपন্ন

का० आरं० 1497 — भारत के राजपत्र भाग II काउ 3 उपखंख (ii) तारीख 5 मार्च 1977 के पुष्ठ 887 से 889 पर प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के ग्रादेश संबयः का॰ धा॰ 699, ता॰ 5 मार्च, 1977 में--

- (i) पृष्ठ उपर, धनुसूची क में. --
- (क) स्त्रमभ-2 में कम मै० 1 के सामन .

"ग्रनुसुची क" के स्थान पर "ग्रनुसूची ख" पाक्ए,

- (स्त) स्तम्भ 4 मे, कम सं० 2 के मामने "ग्रनुसुची खा" के स्थान पर "ग्रनुसूची गा" पिंकण,
- (ग) स्तम्भ 2 में, क्रम स० 3 के सामने :"ग्रनुसूची खा" के स्थान पर "ग्रनुसूची ग" पिकृष् ।

[ম০ 6(6)/76-নি০নি০ নখা নি০ ড০]

के व्याल माल मुबहमण्यम, उपनिदेशक

## New Delhi, the 21st May, 1977 CORRIGENDUM

S.O. 1497.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 699 dated the 5th March, 1977, published at pages 887—889 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 5th March, 1977.—

(i) on page 4, in sub-paragraph (3) of paragraph 2, for "and in the case of by the Government of the importing country;"

read "by the Government of the importing country; and in the case of";

- (ii) on page 6, in schedule A,-
  - (a) against Sl. No. 1 in the second column, for "Schedule A" read "Schedule B";
  - (b) against Sl. No. 2, in the fourth column, for "Schedule B" read "Schedule C";
  - (c) against Sl. No. 3, in the second column, for "Schedule B" read "Schedule C";
- (iii) on page 6, in Schedule C, in the last paragraph—for "1 to 5" read "1 to 4".

[No. 6(6)/76-EI & EP]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director

## उप-मुख्य निर्वेत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

## मादेश

हैदराबाद, 28 मार्च, 1977

का० आ० 1498.—सर्वेश्वी बोमीडाला बादमी लि०, मंगलिगिरी रोड़, गुनटूर को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के श्रन्तर्गत ग्रंत्रैल—सार्च 77 नीति रेड बुक बा० 2/खंड 1 के भाग बी की कंडिका 45 में दर्शाई गई प्रतिबन्धित मदों से भिन्न परीक्षण भौजारी तथा उपकरणों का श्रायान करने के लिए 17,000 क्षए (सत्तरह हजार क्षए मान्न) के लिए श्रायान लाइसेस संख्या पी/एल/2771443/मी/एक्स एक्स/50/डब्स्य/4.3-44/जे०-1, दिनाक 9-8-76 प्रदान किया गया था। उन्होंने श्रव उक्त लाइसेस की दोना प्रतियों सीमा शृल्क प्रयोजन प्रति था मुद्रा विनिमय नियंद्रण प्रति की श्रन्तिमिण प्रति जारी करने के लिए इस श्राधार पर आवेदन किया है कि मृल प्रतिया बिल्कुल उपयोग में लाए, बिना ही ग्रन्थानस्थ हो गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आयेदक ने आयात व्यापार नियक्षण नियम तथा कियाबिधि पुस्तक, 76-77 की कडिका 320 के साथ पढ़ी जाने वाली परिशिष्ट 8 में अपेकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ-यत बॉबिल किया है। में मन्तुष्ट हूं कि लाइसेम की मूल सीमा शुल्क एव मुद्रा विनिभय नियंत्रण दोनो प्रतियां अस्थानस्थ हो गई है।

प्रवातन तथा संशोधित भाषान (नियन्नण) भाषेण, 1955, दिनोक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) के प्रन्तर्गत प्रवत्त भिक्षकारों का भयोग कर भाषेण विया जाता है कि भ्रायात लाइसेस संख्या पी/एल/ 2771443/सी/एक्स एक्स/60/इब्ल्यू/43-44/जे•-1, दिनांक 9-8-76 की सीमा शुल्क एव मुद्रा निनिमय नियंत्रण दोनों प्रतियों को रह् करने का भाषेण दिया जाता है।

श्रायात व्यापार नियंत्रण नियम एवं कियाबिधि पुस्तक 1976-77 की किषका 320 के अनुसार उक्त लाइसेंस की सीमा सुरूक तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति दोनों की अनुलिपि प्रति जारी करने के विषय में ग्रम ग्रावेदक के मामले पर विचार किया आएगा।

[संख्या : टांब/ 1/एजे-76/आरईपी/हैदरा०]

एन० के० जगताप, उप-मुख्य नियन्नक

# Office of the Deputy Chief Controller of Imports & Exports ORDER

Hyderabad, the 28th March, 1977

S.O. 1498.—M/s. Bommidala Brothers Ltd., Mangalagiri Road, Guntur were granted import licence No. P/L/2771443/C/XX/60/W/43-44/J 1 dated 9-8-1976 for Rs. 17,000 (Rupees Seventeen thousand only) for the import "Testing Instruments & Equipment other than banned as per \( \Lambda M-77 \) policy Red Book Vol. II/para 45 of part 'B' of Section 1" under G.C.A. They have now applied for issue of duplicate copy of both Customs copy and Exchange Control copy of the above licence on the ground that the original copy has been misplaced without having been utilised at all.

The applicant has filed an affidavit on a stamped paper in support of their contention as required in para 320 read with appendix 8 to the I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure 1976-77. I am satisfied that the original copy of both Customs & Exchange Control copy of licence have been misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under clause 9(CC) of Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended upto date and order the cancellation of the both Customs & Exchange Control copy of licence No. P/L/2771443/C/XX/60/43-44/J. 1 dated 9-8-1976.

The applicant's case will now be considered for the issue of duplicate copy of both Customs & Exchange Control copy of licence referred above in accordance with para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedures, 1976-77.

[File No. Tob/1/L/AJ 76/REP/Hyd.] N. K. JAGATAP, Dy. Chief Controller

## मुक्य नियंत्रक, आयात-भिर्यात का कार्यालय,

## प्रावेश

**नई दि**ल्ली, 26 श्र**प्रै**ल, 1977

का० आ० 1499.—सर्वश्री टाटा रोबित्स फ़ेजर लि०, 11-स्टेशन रोड, वर्मा माइस, जमशेवपुर (बिहार) को स्थीडन साख के अन्तर्गत 1,75,000 रुपए के लिए सलंग्न सूची के अनुसार कच्च माल एवं सच्टकों का आयात करते के लिए आयात लाइसेंस सख्या पी/डी/2201408/आर/एस डब्स्यू/56/एच/39-40, विनाक 27-8-1975 प्रदान किया गया था।

- 2. उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा शुस्क प्रयोजन प्रति की प्रनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस प्राधार पर भावेदन किया है कि मूल सीमा शुस्क प्रयोजन प्रति सीमा शुस्क सदन, कलकत्ता में पंजीकृत कराने के परचात खो गई/प्रस्थानस्थ हो गई है। लाइसेमधारी ने ध्रागे यह भी बताया है कि लाइसेंस पर जिना उपयोग में लाई हुई धनराणि 1,75,000 इपए शेष है।
- 3 प्रपने तक के समयंत में घावेदन ने एक णपय-पत्न दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी मन्तुष्ट है कि भायात लाइसेंस संख्या पी/डी/2201408/ दिलांक 27-8-1975 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा अस्यानस्य हो गई है और अनः निदेण देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमा शुस्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एनदुद्वारा रद्द की जाती है।
- उक्त लाइसेस की सीमा गुल्क प्रयोजन प्रति की प्रनुलिपि प्रिनि प्रस्ता से जारी की जा रही है।

[संख्या मैक/टी-2(10)/ए एम-75/भारएम-4/97]

## Office of the Chief Controller of Imports & Exports ORDER

New Delhi, the 26th April, 1977

- S.O. 1499.—M/s. Tata Robins Fraser Ltd., II Station Road Burma Mines, Jamshedpur (Bihar), were granted import licence No. P/D/2201408/R/SW/56/H/39-40, dt. 27-8-1975 for import of Raw Materials & Components as per list attached to it value at Rs. 1,75,000 from Swedish Credit.
- 2. They have requested for the issue of duplicate customs purposes copy of the above said licence on the ground that the original Customs purposes copy has been lost or misplaced after having been registered with the Customs, Calcutta. It has been further reported by the licensee that the licence had an unutilised balance of Rs. 1,75,000.
- 3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs purpose copy of Import Licence No. P/D/2201408 dt. 27-8-1975 has been lost or misplaced and hence directs that a duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to he applicant. The original Customs Purposes Copy is hereby cancelled.
- 4. The Duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately.

[File No. Mach/T-2(10)/AM-75/RM-4/97]

## आदेश

का० आ० 1500.— सर्वभी लारमन एण्ड टौबो लि०, एस एण्ड टी हाऊस, बैलार्ड एस्टेट, नरोत्तम मोरारजी रोष्ट, बम्बई को मामान्य मुद्रा क्षेत्र से 3,25,000 रुपए के लिए संलग्न सूधी के मनुमार कच्च माल/ सर्घटको का भायान करने के लिए भ्रायान लाइसेंस सख्या पी/जी/1405131/सी/एक्स एक्स/53/एच/37-38, दिनांक 10-12-1974 प्रदान किया गया था।

- 2. उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की प्रनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी, बम्बई के पाम पंजीकृत करान के पण्यात् ला गई/ग्रम्थानस्य हां गई है। लाइसमें मधारी ने ग्रागे यह भी बताया है कि लाइसेंस में बिना उपयोग की हुई श्वनराणि 75,688 क्पए शेष है।
- 3. प्रपने तक के समर्थन में प्रावेदक ने एक णपथ पत्न वाखिल किया है। प्रधोहस्त(छरी सन्तुष्ट है कि प्रायान लाइसेम संख्या थी/छी/1405131, विनाक 10-12-1974 की सूल सीमा शुक्क प्रयोजन प्रति खा गई/प्रस्थानस्य हो गई है भीर मतः निदेश देना है कि आवेदक की उक्त

लाइसेंस की मीमा गुस्क प्रयोजन प्रति की ब्रनुलिपि प्रति जारी की जाती चाहिए । मुल सीमा शुस्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रह की जाती है ।

उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की ध्रनुलिपि प्रति
 ग्रव श्रलग से जारी की जाती है।

[सख्या मैक/एल-1 ( 7 ) /ए एम-7 4/ग्रार एम-4/98]

एन० ए० कोहली, उप-मुक्य नियंत्रक कृते मुख्य नियंत्रक

#### ORDER

- S.O. 1500.—M/s. Larsen & Toubio Limited, L&T House, Ballard Estate, Naiottam Morarjee Road, Bombay were granted import Licence No. P/D/1405131/C/XX/53/H/37-38 dt, 10-12-1974 for import of Raw Materials/Components as per list attached to it valued at Rs. 3,25,000 from G.C.A.
- 2. They have requested for the issued of duplicate Customs Purposes copy of he above said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost or misplaced after having been registered with the Customs, Bombay. It has been further reported by the licensee that the licence had an unutilised balance of Rs. 75,688.
- 3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purpose Copy of Import Licence No. P/D/1405131, dated 10-12-1974 has been lost or misplaced and hence directs that a duplicate Customs Purposes copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy is hereby cancelled.
- 4. The Duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately.

[File No. Mach/L-1(7)/AM-74/RM4/98] N. A. KOHLY, Dy. Chief Controller for Chief Controller

## उद्योग मंत्रासच (ग्रौधोगिक विकास विमाग) आदेश

नई दिल्ली, 10 मई, 1977

कार आर 1501.— आई० डी० आर० ए० 6/4/77 केन्द्रीय सरकार, विकास परिषय (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 के नियम 2,5,7 और 8 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) प्रिधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रवस्त मिन्सिनों का प्रयोग करते हुए, श्री एग० एस० सचरेव, सलाहकार (पेट्रो-रसायनिक) को श्री एन० सी० कृष्णामृति के स्थान पर, और श्री एस० के० लूथा सहायक विकास प्रधिकारी को श्री ए० के० दास के स्थान पर, 18 जुलाई, 1977 तक की अवधि के लिए, जिसमें वह दिन भी सम्मिलत है, कार्बनिक रसायम उद्योगों की विकास परिषय के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त श्री एस० के लूथा को उक्त परिषय के सचित्र के कृष्यों का पालन करने के लिए भी नियुक्त करती है, और निदेश देती है कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (श्रीद्योगिक विकास विभाग) के श्रावेश सं० का० आ० 2280-आई० डी० आर० ए०/6/3/75, तारीख 14 जुलाई 1975 में निम्नलिखन संगोधन किए जाएंगे, प्रथान:—

उक्त प्रावेश मे, पैरा 1 में,---

(i) कम सं० 26 और उसमे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्न-लिखित कम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, ग्रयोत:---

"26. श्री एस० एस० सचदेव, सलाहकार (पेट्रो-रसायनिक), रसा-यन भौर उर्वरक महालय, नई दिल्ली।":

- (ii) अभ मंख्या 27 ग्रीर उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखिन कम मंख्या ग्रीर प्रविष्टि रखी जाएगी, श्रथिन् —
  - "27 श्री एम० के० लूधा, विकास श्रधिकारी, तकनीकी विकास महा निवेणालय, नई दिल्ली ।"
- (iii) पैरा 2 मे, "श्री ए० के० दाम, विकास ग्रिधिकारी" मध्दो के स्थान पर "श्री एम० के० लुधा, विकास ग्रिधिकारी" शब्द रखे आएगे।"

[सं० 8/3/74-सी० डी० एन०]

प्रैम नारायण, भ्रवर मचिव

#### MINISTRY OF INDUSTRY

## (Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th May, 1977

8.0. 1501.—IDRA/6/4/77—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 5, 7 and 8 of the Development Counsil (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints for a period upto and inclusive of the 18th July, 1977, Shri S. S. Sachdeva, Adviser (Petro-Chemicals) vice Shri N.C. Krishnamoorthy

and Shri S. K. Luthra, Development Officer vice Shri A. K. Das as members of the Development Council for Organic Chemical Industries, also appointsaid Shri S. K. Luthra to carry out the functions of the Secretary to the said Council and directs that the following amendments shall be made to the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 2280-IDRA/3/75, dated the 14th July, 1975, namely:—

In the said Order, in paragraph 1,-

- (i) for setlal No. 26 and the entry relating thereto the following serial No. and entry shall be substituted, namely:—
  - "26. Shri S. S. Sachdeva, Adviser (Petro-Chemicals), Ministry of Chemicals & Fertilizers, New Delhi.";
- (ii) for serial No. 27 and the entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be substituted, namely:—
  - "27. Shri S. K. Luthra,
    Development Officer,
    Directorate General of Technical Development,
    New Delhi."
- (iii) In paragraph 2, for the words "Shri A. K. Das, Development Officer", the words "Shri S. K. Luthra, Development Officer" shall be substituted.

[No. 8/3/74-CDN] PREM NARAIN, Under Secy.

## नागरिक पृत्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

### मारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1977-04-28

का० आ०1502 — मारन के राजपन्न भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) धिनीक 1976-12-18 में प्रकाणित नागरिक पूर्ति तथा महकारिता मंत्रालय (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या 4733 दिनांक 1976-11-25 के प्रागे भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ड्रमों के चूड़ीदार उक्काों से सम्बन्धित मानक चिह्न की अतिरिक्त डिजाइन तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक तथा शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची में दिए ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है।

भारतीय मानक लंस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमो नथा विसियमो के निमित मानक चिह्न की यह अतिरिक्त डिजाइन 1977-02-10 से लागू होगी ।

## अनुसूची

कम मानक चिह्न क संख्या डिजाइन	ी      उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की शीर्षक ग्रौर पदनाम	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
FLANGE (S. 17)		IS : 1784—1961 ष्ट्रमों के चुड़ीदार क्षेम्फनों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' णब्द होने हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई गैली और नुपात में सैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उसे मोनोग्राम के बांई घोर शब्द 'फ्लैंज' ग्रीर मोनोग्राम के बांई ग्रोर भारतीय मानक की पदमंख्या दी गई है।

## MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

## INDIAN STANDARD INSTITUTION

Now Delhi, the 1977-04-28

S.O. 1502.—In continuation of the Ministry of Civil Supplies and Co-operation (Indian Standards Institution) notification number S.O.4733 dated 1976-11-25 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1976-12-18, the Indian Standards Institution, hereby, notifies the additional design of the standard mark for screwed closures for drums, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard, is given in the following schedule.

This additional design of the standard mark, for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1977-02-10:

- 07	Ъ	$\mathbf{F}\Gamma$	<b>`</b>	
- 21	-11	ĿĿ	<i>,</i> U.	

Sl. Design of the	Product/Class of Product	No. and title of the Relevant	Verbal description of the design of the
No. Standard Mark		Indian Standard	Standard Mark
FLANGE [5] 15-1764	Screwed closures for drums	IS: 1784—1961 Specification for screwed closures for drums.	The monogram of the Indian Standards Institution consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the words 'FLANGE' being superscribed on the left-hand side and the number of the Indian standard being superscribed on the right-hand side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9]

कां आ 1503. — भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुनार भारतीय मानक संस्था द्वारा ग्रिअस्चित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन और णाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानकों के शीर्षक सिहत नीचे अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन जिहून) प्रधिनियम 1952 और उसके प्रधीन बने नियमों के निमित ये मानक जिनह 1977-04-01 से लागू होगी।

## अनसुची

क्रम मानकचिह्नकी संख्या डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पद- मंक्या भीर शीर्षक	मानक की विजाइन का शाब्दिक विवरण
	फाइबर मोर्ड के पनालीदार स <del>म</del> ्से	IS:2771-1965 फाइबर बोर्ड के पनालीदार बक्सों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते है, स्तम्भ (2) में दिखाई गैली भीर भ्रनुपात में तैयार किया गया है और जैमा बिजाइन मे दिखाया गया है उस मोनोग्राम के उत्पर की भ्रोर भारतीय मानक की पदसंख्या तथा मोनोग्राम के नीचे की भ्रोर शब्द 'केबल बक्स' दिए गए हैं।

[सक्या सी एम जी/13: 9]

S.O. 1503.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1977-04-01:

## SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	15.77.71 15.00 15.00 ONLY	Cortugated fibreboard boxes	1S: 2771—1965 Specification for corrugated fibreboard boxes.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the words 'BOX ONLY' being subscribed under the bottom side of the monogram.

as indicated in the design.

का॰ आ॰ 1504---समयसमय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के भनु-सार भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रशिमूचिम किया आता है कि गंस्था ने एक मानक चिह्न निर्धारित किया है जिसकी दिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानक के शीर्षक महित नीचे धनुसूची में वी गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्नु) प्रधितियम, 1952 और उसके प्रधीन बने नियमों के निमित यह मानक चिह्नु 1977-03-01 से लागू होगी।

## धनुसूची

कम स <b>ख्</b> या	मानक <b>चिक्र</b> की डिजाइन	इत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्मस्बन्धी भारतीय मानक की पद- संख्या स्नौर शीर्षक	मानक की डिजाइन का णाब्दिक विवरण
1	2	3	4	5
1. <b>I</b>	S: 5424		IS: 5424-1969 बिजली कार्यों के लिए रबड़ की चकतियों की विशिष्ट	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली श्रौर श्रनुपान में तैयार किया गया है श्रौर जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उसा मोनोग्राम के ऊपर की श्रोर भारतीय मानक की पदसंख्य दी गई है।

[सक्या सी एम जी/13.9]

S.O. 1504.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard(s) is/are given in the Schedule hereto ann exed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1977-03-01:

#### **SCHEDULE**

SI. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. I	S : 5424	Rubber mats for electrical purposes.	IS: 5424—1969 Specification for rubber mats for electrical purposes.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the mono- gram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9]

का बारा अधिसूचित किया जाता है कि फाइबर बोर्ड के पनालीदार बक्सों की प्रति इकाई प्रमाणन चिह्न लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए अयौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और यह फीम 1977-04-01 से लागू होगी।

## यनुसूची

कम उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी सख्या	तत्सम्बन्धी मानक की संख्या श्रौर शीर्षक	इकाई	प्रति ६काई मुहर लगाने की फीस
1 फाइबर बोडं के पनालीदार अक्से	IS: 2771 – 1965 फाइबर थोर्ड के पनालीबार अक्सो की विभिष्टि	ा । ∩ कि० ग्रा०	5 पैसे

[सब्या सी एम डी/13:10]

S.O. 1505.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for corrugated fibreboard boxes details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fees shall come into force with effect from 1977-04-01:

## **SCHEDULE**

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Co	orrugated fibreboard boxes	IS: 2771—1965 Specification for corrugated fibreboard boxes.	10 kg.	5 Paise

[No. CMD/13:10]

का॰ बा॰ 1506.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के श्रनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा ग्रिक्षिसूचित किया जाता है कि बिजली कार्यों के लिए रखड़ की चकतियों की प्रति दकाई मुहर लगाने की फीस धनुसूची में दिए गए ब्योरों के श्रनुसार निर्धारित की गई हैं और यह फीस 1977-03-01 से लागू होंगी ।

## **भनुस्**ची

क्रम उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी संख्या	तत्सम्बन्धी मानक की संख्या ग्रौर शीर्षक	इकार्द	प्रति इकाई मृहर लगाने की फीस
1. बिजली कार्यों के लिए रबड़ की चकतियां	IS: 5424-1969 बिजली कार्यों के लिए रबड़ की चकतियों की विशिष्टि	एक मध	रु० 2.00

[संख्या सी एम डी/13:10] ए० बी० राव, उपमहानिदेशक

S.O. .—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for rubber mats for electrical purposes details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1977-03-01:

#### **SCHEDULE**

Sl. Product/Class of Product No.		No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. R	tubber mats for electrical purposes	IS: 5424—1969 Specification for rubber mats for electrical purposes.	One Piece	Rs. 2.00	

[No. CMD/13:10] A. B. RAO, Director General

## पेट्रोलियम मंत्रालय

मई विल्ली, 21 मप्रील, 1977

का० आ० 1506.—भारत सरकार के प्रधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां
सलग्न धनुषूची में प्रविधित किया गया है और पेट्रोलियम पाईप लाइन
(प्रयोक्ता के भूमि प्रधिप्रहण प्रधिकार) प्रधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के
उपखण्ड (1) के प्रन्तर्गत प्रकाणिन किया गया है, गुजरात राज्य के कूलोल
तेल क्षेत्र में उक्त परिभिष्ट भूमि में बेधन स्थल सं० जी० जी० एस०
सोमासन से सी० टी० एफ० कलोल तक पट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग
के प्रधिकार प्राप्त किए गए है।

तेल एवं प्राकृतिक गैम श्रायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप-खण्ड (1) की धारा (1) में निर्विष्ट कार्य दिनांक 5-8-1974 से समाप्त कर दिया गया है।

हात: श्रव पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोक्ता के भूमि

अधिग्रहण मधिकार) नियम, 1963 के अन्तेंगत सक्षम प्राधिकारी एनद्-द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की निथि मधिसूचिन करते हैं।

#### भनसंची

जी०जी०एस० सोमासन से सी०टी०एफ० कलील तक पाईप लाइन कार्य की समाप्ति

—- मं <b>ज्ञा</b> लय का नाम	गोब	का०श्रा० भारत के राजनक्र सं० में प्रकाशन की तिथि		कार्य समाप्ति की निधि
 पट्रोलियम	मये <b>ज</b>	5259	13-12-1975	5-8-1974

[स॰ 12020/4/77-प्रोडक्शन -1]

## MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 21st April, 1977

S.O. 1507. Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. No. G.G.S. Sobhasan to C.T.F. Kalol in Kalol oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 5-8-1974.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

## **SCHEDULE**

Termination of Operation of Pipeline from D.S. G.G.S. Sobhasan to C.T.F. Kalol.

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publica- tion in the Gazette of India	Date of termi- nation of ope- ration
PETROLEUM	SAIJ	5259	13-12-1975	5-8-1974

[No. 12020/4/77-Prod-I]

का०आ० 1508.---भारत सरकार के प्रधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न प्रनुसूची में प्रविभित्त किया गया है और पेट्रोलियम पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि प्रधिग्रहण प्रधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के धन्तंगत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल लेल क्षेत्र में उक्त परिणिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० जी०जी०एस० सोभासन से सी० टी० एक कलोल तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के प्रधिकार प्राप्त किए गए है।

नेल एव प्राकृतिक गैस श्रायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य विनांक 5-8-1974 से समाप्त कर दिया गया है।

श्रतः श्रव पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोक्ता के भूमि श्रिधि-ग्रह्ण ग्रिधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एत्तवृतारा ग्रव उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि श्रिधिमुचित करते हैं।

## अनुसूची

जी बजी बएस व सोभासन से सी बटी बएफ व कलोल तक पाइप लाइन बार्य की समाप्ति

र्म <b>क्षाल</b> य का नाम	गांव		भारत के राजपन्न में प्रकाशन की तिथि	कार्य ममाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम	 पीयज	5259	13-12-1974	5-8-1974

[मं॰ 12020/4/77-प्रोडम्शन—[I]

S.O. 1508.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. No. G.G.S. Sobhasan to C.T.F. Kalol in Kalol oil field in Gujarat State.

And, whereas, the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of subsection (1) of section 7 of the said Act on 5-8-1974.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

#### **SCHEDULE**

Termination of Operation of Pipeline from D.S. G.G.S. Sobhasan to C.T.F. Kalol.

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	termi- nation of ope-
PETROLEUM I	PIEJ	5259	13-12-1975	5-8-1974

[No. 12020/4/77-Prod.-II]

का अग । 1509. — भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसाकि यहां मंलग्न अनुसूची में प्रदर्णिन किया गया है और पैट्रोलियम पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गन प्रकाणिन किया गया है, गुजरान राज्य के कलोल नेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल भं अनिव-38 से मानंद-18 तक पैट्रोलियम के लिए भृमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए है।

तेल एवं प्राकृतिक गैम भायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्विष्ट कार्य विनाक 10-12-74 से समाप्त कर विया गया है।

भ्रतः भ्रव पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोक्ता के भूमि भ्रधिग्रहण भ्रधिकार) नियम, 1963 के श्रन्तर्गत मक्षम प्राधिकारी एनव्-क्वारा भ्रव उनत तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि भ्रधिसूचित करने हैं।

अनुसूची

मानंद-38 से सानंद-18 तक पाइप लाइन कार्य की समाध्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का <i>०</i> ग्रा सं०	भारत के राजपन्न में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की निधि
पट्टोलियम	<b>खा</b> मप्र सन्तवड	2612	17-7-76	10-12-74
			<del></del>	

[मं॰ 12020/4/77-प्रोडक्शन-III]

S.O. 1509.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. No. Sanand-38 to Sanand-18 in Kalol oil field in Gujarat State.

And, whereas, the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 10-12-74.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963 the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. Sanand-38 to Sanand-18.

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termi- nation of ope- ration
PETROLEUM	Khatraj & Sanawad	2612	17-7-76	10-12-74

[No. 12020/4/77-Prod,-III]

का० अ(० 1510.—भारत सरकार के अधिमूचना के द्वारा जैमाकि यहां संलग्न अनुसूची में प्रवेशित किया गया है और पैट्रोलियम पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिप्रहण अधिकार) अधितियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गम प्रकाणित किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी तेल क्षेत्र में उक्त परिणिष्ट भूमि में बेधन स्थल म० मानंब-39 से जी० जी० एम०/एम० आई० पी० तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस भायोग ने उपर्युक्त नियम के आएड 7 के उप-खण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 13-9-74 में समाप्त कर दिया गया है।

ग्रतः ग्रब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोक्ता के भूमि ग्रिधिग्रहण ग्रिधिकार) नियम, 1963 के ग्रतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्-द्वारा अब उक्त निथि को कार्य समाध्यि की निथि ग्रिधिमुचिन करने है r

अनुसूची

मानंद-39 से जीव जीव एस/एमव्याईव्यीव तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

महालय का नाम	गीव	का०ग्रा० स०	भारत के राज- पत्न में प्रकाणन की तिथि	कार्य समाध्यि की विधि
पेट्रोलियम	<u>श्</u> रोल	2613	17-7-76	1 3-9-7 4

S.O. 1510—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. No. Sanand-39 to G.G.S. at S.I.P. in Kadı oil field in Gujarat State.

And, whereas, the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 13-9-74.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

## **SCHEDULE**

Termination of operation of Pipeline from D.S. Sanand-39 to G.G.S. at S.I.P.

Name of Ministry	Village	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termina- tion of opera- tion
PETROLEUM	Thol	2613	17-7-76	13-9-74

[No. 12020/4/77-Prod.-I

कार आर 1511.—भारत सरकार के प्रधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न प्रमुख्नी में प्रविश्त किया गया है ग्रीन पैट्रोनियम पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि ग्रक्षिग्रहण ग्रिधिकार) ग्रिधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के ग्रन्नर्गत प्रकाशिन किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सर सानव 1 ग्रीर 33 से जीर जीरण्म/एसर आईर पीर तक पैट्रोनियम के लिए भूमि उपयोग के ग्रिधिकार प्राप्त किए गए है।

नेल एव प्राकृतिक गैंस प्रायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप-खण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य विनाक 23-12-74 से समाध्त कर दिया गया है।

ग्रतः, ग्राब, पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोकता के भूमि ग्रक्षिग्रहण ग्रक्षिकार) नियम, 1963 के भन्तर्गत सक्षम प्राक्षिकारी एनव्-द्वारा उक्त निधि को कार्य समाप्ति की निधि ग्रिधिसूचित करने हैं।

## अनुसूची

मानंद 1 और 33 से जी ० जी ० एस ० / एस ० आई० पी ० तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मञ्जालय का नाम	गांव	কা <b>ং</b> সাং শ্	भारत के राज- पत्न में प्रकाशन की निधि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम	थोल	2611	17-7-76	23-12-74

S.O. 1511—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. No. Sanand 1 & 33 to GGS-SIP in Kadi Oil field in Gujarat State

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 23-12 74

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S Sanand 1 & 33 to GGS-SIP

Name of Ministry	Village	S O No	Date of publication in the Gazette of India	Date of termina- tion of opera- tion
Petroleum	Thol	2614	of India 17 7-76	23-12-74

[No 12020/4/77-Prod V]

कां ग्रां 1512 — भारत सरकार के ग्रधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहा सलग्न भ्रनुसूची मे प्रदर्णित किया गया है ग्रौर पट्रोलियम पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि ग्रधिग्रहण ग्रिप्तकार) ग्रधितियम 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के भ्रन्तर्गत प्रकाणित किया गया है, गुजरात राज्य के बड़ी तेल क्षेत्र मे उक्त परिणिष्ट भूमि मे वेधन स्थल से जक्तमन पाइट में जीं जीं एस०-दक्षिण कड़ी तक पैट्रालियम के लिए भूमि उपयोग के ग्रिकार प्राप्त किए गए है।

नेल एव प्राकृतिक गैस ब्रायोग न उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप-खण्ड (1) की धारा (1) मे निर्दिष्ट कार्य दिनांक 26-9-1974 से समाप्त कर दिया गया है।

श्रम श्रम पैट्रोलियम पारप लाइन के नियम 4 (प्रयोक्ता के भूमि श्रिधिग्रहण ग्रिधिकार) नियम, 1963 के श्रन्तर्गत मक्षम प्राधिकारी एनद्-द्वारा उक्त निथि, मो कार्य समाप्ति की निथि श्रश्रिमृचित करने हैं।

ग्रनुसूची

जनमन पःइन्ट से जी ० जी ० एम ०-दक्षिण कडी तक पाइप नाइन कार्य की समाप्ति

मस्रालय वा नाम	गाव	का०ग्रा० <i>स</i> ०	भारत के राज- पत्न में प्रकाशन की निधि	कार्य समाप्ति की निधि
पैट्रोलियम	व डी	5257	13-12-70	2(+9-71

[40 12020/4/77 माउसार **V**[]

S.O. 1512.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d 5 No Junction Point to GGS South Kadi in Kadi oil field in Gujarat State.

And whereas the oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 26-9-1974.

Now therefore under Rule 4 of the Petioleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

## **SCHEDULE**

Termination of operation of Pipeline from DS Junction Point to GGS South Kadi

Name of Ministry	Vil age	S O.No	Date of publica- tion in the Gazette of India	Date of termina- tion of opera- tion
Petroleum	Kadı	5257	13-12-75	26-9-74

[No 12020/4/77-Prod VI]

का० आ० 1513.—भारत सरकार क अधिसूचना क द्वारा जैमा कि यहां सलग्न अनुसूची में प्रविधित किया गया है और पैट्रोलियम पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खप्ट ७ के उपखड़ (1) के अन्तर्गत प्रकाणित किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी तन क्षेत्र में उक्त परिणिष्ट भूमि में बेधन स्थल स० जी० जी० एम० साभासन सं सी० टी० एफ० कलोल तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग क अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तल एव प्राकृतिक गैस आयाग ने उपर्युक्त नियम के आपण्ड 7 के उपराज (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनीक 26-9-1974 में ममाप्त कर दिया गया है।

ग्रम श्रव पैट्रोनियम पाइप लाइन ने नियम ±(प्रयाक्ता के भूमि प्रधिग्रहण प्रधिकार) नियम, 1963 ने श्रन्सर्गन सक्षम प्राधिकारी एतद्-द्वारा उक्त निथि को कार्य समाप्ति की निथि प्रधिस्थित करने है।

भ्रनुसूची

जीं जी । एस । सोमासन संसी । टी । एफ । कलोल नक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

महालय का नाम	गात्र	का० ग्रा० स०	भारत के राजपक्ष म प्रकाशन की{ तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम ————	श्राष्ट्रन्द्रा	5259	13-12 75	26-9-74

[12020/4/77-प्रोडक्णन **VII**] के० बी० देश पाण्डे.

गुजरात क लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 1513.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. No. G.G.S. Sobhasan to C.T.F. Kalol in Kadi Oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) cisection 7 of the said Act on 26-7-1774.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

**SCHEDULE** 

Termination of operation of Pipeline from D.S. G.G.S. Sobhasan to C.T.F. Kalol.

Name of Ministry	Village	S.O.No.	Date of publica- tion in the Gazette of India	Date of termina- tion of opera- tion	
Petroleum	Adundra	5259	13-12-75	26-9-74	

[No. 12020/4/77-Prod. VII]

K, V. DESHPANDE,

Competent Authority Under the Act for Gujarat

का० आ० 1514.—यतः पैट्रांलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के भ्राधिकार अर्जन) श्राधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के भ्रधीन भारत सरकार के पेट्रोंलियम और रसायन मजालय (पेट्रोलियम विभाम) की भ्रधिसूचना का० श्रा० म० 2289 तारीख 24-5-76 हारा केन्द्रीय संरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न श्रनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के श्राधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए श्राजित करने का अपना श्राणय घाषित कर दिया था,

ग्रीर यत. सक्षम प्राधिकारी के उक्त प्रधिनियम की धारा ७ की उपधारा (1) के श्रधीन सरकार को रिपोर्ट द दी है,

श्रीर आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करने के पत्रचात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिद्दिष्ट भूमियो म उपयान का अधिकार अजिन करने का विनिष्णय किया है,

श्रव, अतः उक्त भिधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) द्वारा प्रदक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वाधित करती है कि इस प्रधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार पाइप लाइन श्रिष्ठाने के प्रयोजन के लिये एनद्द्वारा श्रीजन किया जाना है,

न्नीर, श्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त गक्तिया का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निवेण देती है कि उक्त भूमियों से उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में विहिन होने के बजाय तेल ग्रीर प्राकृतिक गैस न्नायोंग में, गर्मी सयला से युक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाणन की इस तारीख को निहित होगा।

## ग्रनुमुची

कें० ई० एक्स०-।। से कें०-92 से जी०जी०एस०-। तक पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का श्रर्जन करना

राज्य : गुजरात : जिला : गोधीनगर : ताल्का . गार्धानगर

गाव	ब्लाक नं०	हेरिटयर	एधारई	सैटियर
जमियातपुरा	53	()	()4	20
-	46	0	10	35
	44	0	0.8	25
	48	0	18	4.5
	49	0	0.1	0.0
	34	0	09	0.0
	3.3	O	0.1	0.0
	15	υ	25	0.5
	कार्ट-			7.5
	टैक	()	0.0	5.3
	16	U	06	
	कार्ट-			
	<b>टै</b> क	0	00	68
मर्या	. सर्वेक्षण			
	मं०			
	666	0	02	6.2
	665	U	13	20

[सं०12016/3/76-एल० एण्ड एल० प्रोडक्शन]

S.O. 1514.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 2289 dated 24-5-1976 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laving pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by subsection (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by subsection (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

#### **SCHEDULE**

Acquisition of R.O.U. for laying Pipeline from KEX-11 to K-92 to GGS-1.

State: Gujarat District: Gandhinagar Taluka: Gandhinagar

Village	Block No.	Hec-	Aic	Cen-
			tiore	
Jamiyatpına	53	0	04	
	46	0	10	35
	44	0	08	25
	48	0	18	45
	49	0	01	00
	34	0	09	00
	33	0	01	00
	15	0	25	05
	Cart-track	0	00	75
	16	0	06	53
	Cart-track	0	00	68
Sertha	Survey No.			
	666	0	02	62
	665	0	13	20

[No. 12016/3/76-L & L/P1od.]

का० आरं 1515.—यन. केन्द्रीय मरकार की यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह प्रावस्यक है कि गुजरात राज्य मे केथोडिक प्रोटेक्शन स्टेशन से एनोडे बेंड तक पेट्रोलियम के परिश्रहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम श्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

श्रीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइना की बिछान के प्रयोजन के निये एतद्पाबद श्रनुसूची मे विणिप्त भूमि मे उपयोग का श्रीक्षकार श्रीजत करना श्रावक्ष्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस साक्तियों का प्रयाग करने हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आस्य एनव्द्वारा घोषिन किया है:

अक्षतें कि उक्त भूमि में हिन्यस्त काई व्यक्ति. उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये श्रीक्षेप समक्ष श्रीधकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैम श्रायोग, निर्माण श्रीर देखभाल प्रभाग, सकरपुरा रोड, बदोवरा-9 को इस श्रीधमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

श्रीर ऐसा श्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्ट यह भी क्थन करेगा कि क्या यह चोहता है कि उसकी मुनत्राई व्यक्तिश. हा या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

#### अनुसूची

केथोडिक प्रोटेक्शन स्टेशन से एनोड बेउ श्रार० झा० यू० तक बायर बेड के लिये भिस के उपयोग के श्रश्चिकार का श्रर्जन

राज्य : गुजरात जिला : बराद। श्रीर ब्रोच नालुका . कर्जन श्रीर बाच : गाव ब्लाक नंऽ हेक्ट्रेयर एग्रारई संदियर मानपुर जिला बरोदा तालुका क जन गाय 132 () 0.0 U3 नाबीपूर जिला ब्रोच मालुका ब्रोच गाव सर्वेक्षण स० 2.17/10.10.0

[स॰ 12016/3/76-एल एण्ड एल०/प्राडक्शन-I]

S.O. 1515.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Cathodic Protection Station to Annode bed in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### **SCHEDULE**

Acquisition of R.O.U. for wire bed from cathodic protection station to Anode Bed R.O.U.

State : Gujarat District : Baroda & Broach Taluka : Karjan & Broach

Block No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare
132	0	00	93
Survey	No.		Broach 00
	District : Bate 132 r District :	District: Batoda Talul 132 0 r District: Broach Survey No.	District: Batoda Taluka: Karj 132 0 00 r District: Broach Taluca: Survey No.

[No. 12016/3/76-L & L/Prod. I]

का॰ प्रति 1516 — यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हांता है कि लोक-हित से यह प्रावश्यक है कि गुजरान राज्य से कूप ने० 206 (ए० एन० के॰ आरे॰) में जी॰ जी॰ एस॰-VI तक पैट्रालियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

श्रीर यन यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एनव्पाबक अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का श्राधकार अजित करना श्रावण्यक है।

श्रत, श्रव पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के श्रधिकार का श्रेत्रन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गक्तिया का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का श्रधिकार अजिन करने का अपना श्राणय एसद्वारा घोषित किया है:

क्षणने कि उपने भृषि में हिन्धद्ध काई अक्रीकन, उस भूभि के तीचे धादपलाइन बिछाने के लिये आक्षप समक्ष अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बदीबरा-9 को इस अधिसूचना की मारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

भौर ऐसा स्राक्षेप करने वाला हर ध्यमित विनिदिष्ट. यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहना है कि उसकी सुनवाई ध्यक्तिण: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### श्रम् सूची

कूप ने॰ 206 (ए० एन॰ के॰ फ्रो॰) से जी॰ जी॰ एस॰-VI तक भूमि के प्रधिकार का अर्जन

जिला :	क्षोच तास्तु	का श्रंट	हरे <b>ने एवर</b>
सर्वेक्षण स०		ग्रारई से	न्टियर
. 287 286	0	0 <b>7</b> 10	20 80
	सर्वेक्षण स॰ . 287	सर्वेक्षण स॰	. 287 0 07

[म० 12016/3/76-एन० एड एल०/प्रोडक्णन-**II**]

S.O. 1516.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 206 (Ank-0) to G. G. S.VI in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of Uses in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Acquisition of right of user in land from well No. 206 (ANK-0) to GGS-VI.

District: Broach State: Gujarat Taluka : Ankleshvar Village Survey No. Hcc-Are Centare tiare 287 0 07 20 Adol 286 0 10 80

[No. 12016/3/76- L & L/Prod. II]

कार ध्यार 1517.—यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन होता है कि सोकहिन में यह ध्रावण्यक है कि गुजरान राज्य में कूप नर 203 (एर एनर केर V) से जीर जीर एसर-८ तक पट्टालियम के परिबहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस श्रायाग द्वारा बिछाई जानी बाहिये।

श्रीर यन यह प्रमीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एलद्पाबढ़ श्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का श्रधिकार प्रजित करना श्रीवर्ष्यक है।

श्चन, श्रव पेट्रालियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के श्रिधिकार का श्चर्यन) श्रविनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा उ की उपधारा (1) द्वारा पदल णिक्त्या का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का श्रविकार श्रवित करने का श्रपना श्राणय एनदद्वारा घोषित किया है: वणतें कि उनन भूमि में हिनकद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन किछाने के लिये आक्षेप समक्ष अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयाग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, सकरपुरा रोड वदादरा-9 का इस अधिस्वना की नारीख से 21 दिना के भीसर कर सकेगा।

ग्रीर ऐसा आक्षेप करने बाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह वाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिण: हो या किसी विधि व्यवसाधी की मार्फत।

## ग्रनुसची

कूप न० 203 (ए० एन० के०-V) से जी० जी० एस-6 तक भृमि के उपयोग को अधिकार का अर्जन

राज्य : गु	<b>ग</b> राम	সিলা	· श्रीच	नालुका	ग्रंब	हत्त्रेष्टवर
गांव		सर्वेक्षण २०	हेक्टेयर ग	— - प्रारई	 से	
घ्रडोल		374		0	02	40
		299/2		0	0.8	2.1
		289/1		0	0.7	80
		289/2		0	0.3	60
		290		O	0.3	60
		288/5-1		0	0.9	24
		286		0	0.3	00

[स॰ 12016/3/76-एल एड एल॰/प्रोडक्शन-[II] टी॰ पी॰ मृत्रमनियम, अबर सचिव

S.O. 1517.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 203 (Ank-V) to GGS-6 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission:

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-6;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of right of user in land from well No. 203 (ANK-V) to GGS-6.

ch Taluka : Ankleshvar			State : Gujarat District : Broa		
Cen- tiare	Arca	Heç- tare	Survey No.	Village	
40	02		374	Adol —	
24	09	0	299/2		
80	07	0	289/l		
60	03	0	289/2		
60	03	0	290		
24	09	0	288/A-1		
00	03	0	286		
	03	0	286		

[No. 12016/3/76-L & L/Prod. III]

Γ. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याम मंत्रालय

## (स्वारध्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 धप्रैल, 1977

कां० ग्रा० 1518—खाद्य अपिमश्रण निवारण द्रिशिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 3 की उपधारा (2) के खोड (इ) के श्रन्सरण में व्रिपुरा सरकार ने ट्रा० पी० मजूमदार, स्वास्थ्य मेथा निदेशक, विपुरा सरकार, श्रगरतला को घा० जी० रामन, जिन्होंने पद स्थाग दिया है, के स्थान पर केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किया है,

भन , श्रम, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रक्रियों का प्रयोग करने हुए, निदेश देती है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संवालय (स्वास्थ्य विभाग) की प्रधिसूचना सं० का० ग्रा० 276 (श्रमा०), नारीख 1 श्रप्रैल, 1976 में निस्नलिखिन और संशोधन किया जाएगा, श्रप्रान्-—

जक्त श्रिधमूजना में, "धारा 3 की उपधारा (2) कें खड़ (इ) कें अधीन नामनिर्देणित सबस्य" शीर्षक के नीचें, कम में 19 के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर "डा० पी० मजूमबार, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, त्रिपुरा सरकार, अगरनला 1" प्रविष्टि रखी जायेगी।

[सक्या पी० 15016/1/76-डी० एण्ड एम० एम० (भाग 2)]

जीं० पजापकेशन, ग्रवर सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

#### (Department of Health)

New Delhi, the 30th April, 1977

S.O. 1518.—Whereas in pursuance of clause (c) of subsection (2) of section 3 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Government of Tripura have nominated Dr. P. Majumdar, Director of Health Services, Government of Tripura, Agartala, as a member of the Central Committee for Food Standards vice Dr. G. Raman, who resigned;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that the following further Amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), No. S.O. 276(E), dated the 1st April, 1976, namely:—

In the said notification, under the heading "Members nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 3", against Sl. No. (19), for the entry, the entry "Dr. P. Majumdar, Director of Health Services, Government of Tripura, Agastala" shall be substituted.

[No. P. 15016/1/76-D&MS(Pt. II)]

G. P. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 1977

का० ग्रा० 1519 — केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मद्रास) नियमावली, 1975 के नियम 1 के उप नियम (3) के ग्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मद्राम में निम्नलिखित और क्षेत्रों को बिनिर्विष्ट करनी है जिनमें उक्त नियम 1 सर्घ, 1977 में लाग होगे, ग्रथनि —

#### जार्ज टाउन घोवधालय

उत्तर मे बेमिन बिज बस श्रष्टुं से चलकर बेमिन बिज रोड के साथ-साथ पूर्व की त्रोर श्रोल्ड जेल रोड, इन्नाहिम जी साहिब स्ट्रीट से होते हुए बहा तक चले जहां इसका संगम समुद्र तट के साथ होता है। फिर वहां से समृद्र तट के साथ-साथ समृद्र के साथ क्यम नदी के विलय के संगम तक चले। फिर वहां में साउध श्रीच रोड के उत्तर तक चले, फिर कूयम नदी के साथ-साथ पण्जिम की ध्रीर बिक्यम नहर के साथ इसके सगम तक चले। फिर वहां में उत्तर की घ्रीर नहर के किनारे के साथ-साथ उस स्थान तक की जहां से पहले चले थे।

> [म० एग० 11012/6/77-के० म० स्वा० यो०] वी० रामचन्द्रन, ध्रवर म<mark>चिव</mark>

#### New Delhi, the 2nd May, 1977

S.O. 1519.—In pursuance of sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Madras) Rules, 1975 the Central Government hereby specifies the following further areas in Madras to which the said Rules shall extend, with affect from the 4th May 1977, namely:—

#### GEORGE TOWN DISPENSARY

On the North starting from Basin Bridge Bus Terminus proceed East along Basin Bridge Road, Old Jall Road, Ibrahimji Sahib Street upto its junction with the sea coast. Proceed South along the sea coast upto the junction of confluence of the Cooum River with the Sea. Proceed upto South Beach Road North, then West along the Cooum river upto its junction with Buckingham Canal. Proceed North along the canal bank upto the starting point.

[No. S. 11012/6/77-CGHS(P)]

V. RAMACHANDRAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 मई, 1977

का० ग्रा॰ 1520 — इस मंत्रालय की 30 नवम्बर 1976 की अधिमूचना संख्या थी॰ 17020/49/76-एम॰ ई॰ (पी॰ जी॰) के पैरा 3 का द्रांणिक संशोधन करते हुए जीच खायोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करन की श्रन्तिम लारीख एतद्द्वारा बढाकर 15 प्रप्रैल, 1977 लक कर दिया गया है।

[संख्या बी॰ 17020/49/76-एम॰ ई (पी॰ जी॰)] का॰ रा॰ फुल्णमृति, संयुक्त संचित

New Delhi, the 4th May, 1977

S.O. 1520.—In partial modification of para 3 of this Ministry's Notification No. V. 17020/49/76-M.E. (PG), dated the 30th November, 1976, the last date for submission of Report of the Commission of Enquiry is hereby extended upto 15th April, 1977.

[No. V. 17020/49/76-M.E. (PG)] C. R. KRISHNAMURTHI, Jt, Secy.

## मॉबहन ऑर परिवहन मंत्रालय

#### (परिवहम पक्ष)

नई दिल्ली, 30 श्रप्रैल, 1977

कां आ 1521.—नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैराग्राफ 44 के साथ पठिन नाविक भविष्य निधि प्रधिनियम 1966 (1966 का 1) की धारा 4 की उपधारा (3) के प्रमुप्तरण में और भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मवालय (परिवहन पक्ष) की प्रधिसूचना संक्या सा० आ० 854, दिनांक 28-2-1977 के प्रतिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एमबुद्धारा निर्देश देती है कि भविष्य निधि ग्रंशदान, क्याज और अन्य प्राप्तियां, जो कि प्रावश्यक व्यय घटाने के बाद हुई, में से संभवन को निम्मलिखिन नमुने के श्रनुमार लगाया जाए, श्रथांतु:—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजिन और निर्गन लोक ऋष अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड 2 में यथापरिभाषित गर-कारी जमानते—-

25% में कम नहीं।

(2) किसी राज्य सरकार द्वारा मृजित और निर्णत लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 19) की धारा 2 के खंड 2 में यथापरि-भाषित सरकारी जमानते—

25° र्से कम नहीं

(3) कोई प्रत्य परकास्य जमानने अथवा बन्द पत्न, जिसका सूलधन और उस पर ब्याज को बिना गर्न केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्यद्वारा पूरी नरह गारंटी शदा हो

25 % से कम नही

(4) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्न (बूसरा और नीसरा निर्गमन) अथया डाकधर सावधिक जमा—

30% अधिक नहीं

(5) भारत सरकार, वित्त सल्लालय (श्रष्टं विभाग) की अधिसूचना सं० एफ० 16(1)-पी० डी० 75, विनांक 30-6-1975 द्वारा श्रुर की गई विणेष जमा योजना

20 % से अधिक नहीं

2. उक्त नमृना एक ग्राप्तैल, 1977 में 30 जून, 1977 नक लागू रहेगा। इस ग्रविध के दौरान पूरी होने वाली डाकघर साविधक जमा योजना का पुनर्निवेश को 50% डाकघर साविधक अचन ग्रीर 50 विशेष बचत में लगाया जाएगा। इस गर्त के ग्राधीन को भविष्य निश्चि संचयन की ग्रन्य परिपक्षता को पैराग्राफ (1) में उल्लिखिन नमूने के भनुसार की जाती रही।

[मं॰ एम॰ डब्स्यू॰ एम॰ (20)/77] श्रीमती बी॰ निर्मल, अवर सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

## (Transport Wing)

New Delhi, the 30th April, 1977

S.O. 1521—In pursuance of sub-section (3) of Section 4 of the Seamen's Provident Fund Act 1966 (4 of 1966), read with paragraph 44 of the Seamen's Provident Fund Scheme 1966, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 854 dated 28-2-1977 the Central Government hereby directs that accumulations out of provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely:—

- (i) Government securities as defined in Not less than Clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government.
- (ii) Government securities as defined in Clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government.

(iii) Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.

Not less than 25%

- (iv) 7-year National Saving Certificate (Se- Not exceeding cond issue and Third Issue) or Post 30%

  Office Time Deposits.
- (v) Special Deposit Scheme introduced by Not exceeding the notification of the Govt, of India in the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) No.F.16 (1)-PD/75 dated 30-6-1975.
- 2. The above pattern will be in force from the 1st April, 1977 to 30th June, 1977. Reinvestment of Post Office Time Deposits maturing during this period shall be made 50% in Post Office Time Deposits and 50% in special Deposits. Subject to this, reinvestment of all other maturities of Provident Fund accumulations shall continue to be made in accordance with the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[No. MWS(20)/77] SMT. B. NIRMAL, Under Secy,

### निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1977

का॰ आ॰ 1522.—दिल्ली नगर कला ध्रायोग प्रधिनियम, 1973 की धारा 5 के साथ पठिन धारा 4 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के निर्माण और घ्राधास मंत्रालय के विनाक 27 ध्रप्रैल, 1974 की ग्रिधसूचना मं॰ सा॰ का॰ नि॰ 190(ध्र) द्वारा स्थापित दिल्ली नगर कला ध्रायोग में केन्द्रीय मरकार श्री भगवान सहाय को ध्रशकालिक ग्रध्यक्ष के रूप में तथा श्री ए० पी० कनिबन्दे और श्री ई० ध्रलकानी को ग्रशकालिक सदस्यों के रूप में एनब्द्वारा पुनं नियुक्त करती है।

[सं० के--।8013/2/77-नं वि०**IV**-क] श्रार० गोपालस्वामि, संयुक्त संचिव

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 29th April, 1977

S.O. 1522.—In exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5, of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby reappoints Shri Bhagwan Sahay as part-time Chairman and Shri A. P. Kanvinde and Shri E. Alkazi as part-time members of the Delhi Urban Art Commission, established by the notification of the Government of India in the Ministry of Work, and Housing number G.S.R. 190(E) dated the 27th April, 1974, with effect from the 1st May, 1977.

[No. K-18013/2/77-UD. IV-A] R. GOPALASWAMY, Jt. Secy.

## नई विस्ली, 5 मई, 1977

का० आ० 1523.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (भ्रप्राधिकृत म्रियमंगियों की बेदखली) श्रीधनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के निर्माण और श्रावास मंत्रालय की श्रीधमुजना सख्या 1699 नारीख 10 जुलाई, 1972 को श्रीधकाल्य करते हुए नीजे मारिणी में विनिर्दिष्ट श्राधकारियों को, जो सरकार के राजपित्तन श्रीधकारी है, उक्त श्रीधनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा श्रीधकारी नियुक्त करती है और ऐसे श्रीधकारी उक्त सारिणी के स्तम्भ (2) में की नत्सबंधी श्रीविष्ट में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के

सरकारी स्थानो की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन संपद्मा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौपे गए कर्नव्यों का पालन करेंगे। सारणी

र्थाधकारी का पदाभिधान

मरकारी स्थानं। के प्रवर्गसीर भ्रधिकारिता संबंधी स्थानीय सीमाएं

(1)

(2)

- कार्यपालक इंजीनियर, पांडिचेरी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग. पाडिचेरी सरकार
  - गैसे परिसर जो पाइेचेरी सघ राज्य क्षेत्र के भीतर पांडिनेरी क्षेत्र की स्थानीय सीमाग्रों में भ्रौर जो क्रमश प्रणामनिक नियंत्रण के ग्रधीन है।
- 2 कार्यपालक इंजीनियर, कराइकल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग. पाडिचेरी सरकार
- लेंसे परिसर जो पडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर कराइकल क्षेत्र की स्थानीय मीमाध्रो के भीतर है भीर उसके प्रणासनिक नियंत्रण के प्रधीन है।
- इजीनियर. 3 महायक माहे भीर यमण क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पाडिचेरी सरकार
- ऐसे परिसर जो पाहिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर माहे धौर यमण क्षेत्र की स्थानीय मीमाध्रो के भीतर स्थित हैं ग्रौर उसके प्रशासनिक नियन्नण के अधीन
- 1 उप कलक्टर/महायक कलक्टर उप कलक्टर (राजस्व)
- ऐसे परिसर जो पांजिनोरी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित है भ्रोर कमणः उनकी श्रधि-कारिता के भीतर है किन्तु उनसे भिन्न जो पाडिचेरी सरकार के लोक निर्माण विभाग के कार्य-पालक इजिनियरो और सहायक इंजीनियरों के प्रणासनिक नियं-त्रण मे है।

[स॰ 21012/1/70 नीवि-3] स्राई० चौधरी, सम्पदा निवेशक

#### MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 5th May, 1977

S.O. 1523.- In exercise of the powers conferred by section 3 of the public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 1699 dated the 10th July, 1972, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in Column 1 of the Table below, being Gazetted Officers of Government to be estate officers for the purposes of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act, within the limits of their jurisdiction in respect of the cate gories of public premises specified in the corresponding entry in column (2) the said. Table,

#### TABI F

Designation of the officer

Categories of public Premises and local limits of jurisdiction

(2)

(1)

- 1. Executive Engineers. Pondicherry Region, Public Works Department, Government of Pondicherry.
- Premises which are situated within the territorial limits of Pondicherry region of the Union Territory of Pondicherry and are under their administrative respective control.
- 2. Executive Engincer, Karaikal Region, Public Works Department, Govt. of Pondicherry.
- Premises which are situated within the territorial limits of Karaikal region of the Union Territory of Pondicherry and are under his administrative control.
- and Yanam Regions, Public Works Depti. Government of Pondicherry.
- 3. Asstt. Engineers, Mahe Premises which are situated within the Territorial limits of Mahe and Yanam regions of the Union Territory of Pondicherry and are under their respective administrative control
- 4. Sub-Collectors/Assistant Collectors and Deputy Collectors (Revenue).
- Premises which are situated within the territorial limits of the Union Territory of Pondicherry and within respective "jurisdic their than those other tions administrative under the control of the Executive Engineers and Assistant Engineers of the Public Works Department, Pondicherry.

[No. 21012(1)/70-Pol. IIII.

I. CHAUDHURI, Director of Estates.

## श्रन मंत्रालय

#### भादेण

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1977

कारु आरारु 1524.—विन्तीय सरवार की राय है कि इससे उपावदा भ्रमुखी में विनिदिष्ट विषया के अप में शान्ध्र वैक लिमिटेड, पंनामाल्ल्क, कृष्णा जिला के प्रथन्धतल से सम्बद्ध नियानका श्रीर उनके कमेकारी के बीच एक प्रोट्याधिक विवाद विद्यमान है

भ्रौर केन्द्रीय सरकार ∋क्त तिबाद ता न्यायनिर्णयन के लिए निर्णे-शित करना बाछनीय समझ ी है

भ्रत, भव, ग्रीयोगिक विवाद अधिनियम । १५४७ (१९४७ व.। १४) की धारा 7 क और धारा 10 ती उपधारा (1) वे खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त णक्तियो का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार एक स्रीद्यागिक श्रिधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन श्रीधकारी श्री के० पी० नारायण राव हागे, जिनका मुख्यातय टेंदराबाद में टागा और उक्त विवाद को उक्स स्रौद्योगिक प्रधिकरण का न्यायनिर्णयस के लिए निद्योगित करती P۱

## अनुसूची

क्या आन्ध्र बैक लिमिटेष्ट के प्रबन्ध तैस की पेनामाल्लुरु शास्त्रा के श्री पी० पेल्लया, चपरासी को 9-7-1976 से सेवा से पहच्युन करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, सो कर्मकार किस अनुताय का हकदार है ?

[र्स**ः** एल=12012/175/76=डी॰ **II**=ए०]

## MINISTRY OF LABOUR

#### ORDER

New Delhi, the 18th March, 1977

S.O. 1524.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Andhra Bank Ltd., Penamallulu, Krishna Distt. and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, The Presiding Officer of which shall be Shri K. P. Naryana Rao with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

#### **SCHEDULE**

Whether the action of the management of Andhra Bank Ltd., in dismissing Shri P. Yellayya, Peon at Penamaluru from service with effect from 9-7-76 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-12012/175/76-D.If. A]

#### ग्रादेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1977

का बार 1525 --- इससे उपाबक अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में रिजर्ज बैंक आफ इंडिया, सागपुर के सम्बन्ध नियोजकों धीर उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद केन्द्रीय मरकार शोधोगिक प्रक्षिकरण, जबलपुर के समक्ष लिखत है।

श्रीर श्रीसकों से, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय रिजर्ष बैंक कर्मचारी संघ, नागपुर करता है, उक्त विवाद से सम्बन्धित कार्यवाहियों को उक्त केन्द्रीय सरकार श्रीद्योगिक श्रधिकरण, जबलपुर से श्रीद्योगिक श्रधिकरण, नागपुर को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुमा है, जिस पर रिजर्व बैंक ग्राफ इडिया, के प्रबन्धकों श्रीर रिजर्व बैंक वर्कर्स यूनियन, नागपुर को कोई श्रापनि नहीं है;

भत, श्रव, केन्द्रीय सरकार श्रीद्योगिक विवाद अधिमियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 खंकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदेश शिक्षियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्रीद्योगिक प्रधिकरण, जवलपुर से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेली है धौर उन्हें उक्त श्रधिनियम की धारा 7 क के श्रधीन गठित श्रीद्योगिक श्रधिकरण, जिसके पीठा भीन श्रधिकारी श्री बीठ केठ एवमेलकर है तथा जिनका मुख्यालय नागपुर में है, को श्रन्तरित करती है श्रीर यह निदेण देती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार श्रीद्योगिक श्रधिकरण, नागपुर श्रीर श्रागे कार्यवाहिया उसी प्रशम से श्रारम्भ करेगा जिस पर वो उसे श्रन्तरित की जाएं श्रीर विधि के शनु-मार उनका निपटान करेगा।

### धनसूची

विवाद सख्या	आदेश संख्या	विवाद के पक्षकार
एल <b>०मी० (ग्रार) (</b> 30)/75	एस—- 12012/7/75 शी 2ए, नारीचा 30-4-1975	रिजर्व बैक भ्राफ डिंडिया का प्रवन्धतस्त्र श्रीर उनके कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व रिजर्व बैक वर्कसं यूनियन, नागपुर श्रीर रिजर्व बैक कर्मचारी संघ, नाग- पुर करने हैं।

#### विवादग्रस्त मामले

"क्या रिजर्थ वैक श्राफ इंडिया, नागपुर के प्रबन्धतंत्र द्वारा इलेक्ट्रिणियन-एव-केयरटेकर के रिक्त स्थान को भरने के लिए रिक्ति को श्रिधिसूचिन किए बिना श्रीर श्रेणी 4 के कर्मचारिया से श्रावेदनपत्र आमंत्रित किए बिनाश्री डी० डी० पेटे को उक्त पत्र के लिए चुनना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उपचार का उपाय क्या है।"

[स॰ एस-12012/**7/**75-डी-2ए]

राम प्रसाद महला, ध्रवर सचिव

#### ORDER

New Delhi, the 21st March, 1977

**S.O.** 1525.—Whereas the industrial dispute existing between the employers in relation to the Reserve Bank of India, Nagpur and their workmen in respect of matters specified in the Schedule hereto annexed in pending before the Central Govt. Industrial Tribunal, Jabalpur.

And whereas a proposal has been received from the workmen represented by the Rashtriya Reserve Bank Karamchari Sangh, Nagpur for transfer of the proceedings in the dispute from the said Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur to an Industrial Tribunal at Nagpur, to which the management of the Reserve Bank of India and the Reserve Bank Workers Union, Nagpur have no objection;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute from the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur and transfers the same to the Industrial Tribunal presided over by Shri W. K. Abmelkar with headquarters at Nagpur constituted under Section 7A of the said Act and directs that the said Central Government Industrial Tribunal, Nagpur shall proceed with the same proceedings from the Stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

## **SCHEDULE**

Dispute No.	Order No.	Parties to the dispute
LC(R)(30)-75	L-12012/7/75-D.H.A. dated 30-4-1975	Management of the Reserve Bank of India and their workmen represented by Re- serve Bank Workers Union, Nagpur and Reserve Bank Karam- chari Sangh Nagpur

#### MATTERS IN DISPUTE

"Whether the management of the Reserve Bank of India, Nagpur is Justified in selecting Shi D. D. Pete as Electrician-cum-Caretaker without notifying the vacancy and inviting applications from amongst Class IV Staff for filling the said post? If not, what will temedial measure?"

> [No. L-12012/7/75-D. Π. A] R. P. NARULA, Under Secy.

#### New Delhi, the 12th May, 1977

S.O. 1526.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 10-5-77.

## CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

#### Reference No. 18 of 1975

#### PARTIES:

Employers in relation to the management of the State Bank of India.

#### AND

#### Their Workmen

#### APPEARANCE:

On behalf of Employers, Shri C. L. Ganguly, Advocate, with Shri S. K. Dutt, Advocate and Sri A. K. Mitra, Addl. Law Officer.

On behalf of Workmen, Shii K. B. Deb Krori, Advocate.

STATE: Assam INDUSTRY: Banking

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, vide their Order No. L-12012/67/74-LR. III, dated 26th February, 1975, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of the State Bank of India and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads as:

- "Whether the action of the State Bank of India, Imphal in terminating the services of Shri Sushanta Deb with effect from the 10th July, 1971 is justified and if not to what relief is the workman entitled to?"
- 2. The workman, Shri Sushanta Deb was an employee of the State Bank of India at their branch in Imphal as a Godown keeper. His first appointment was on a temporary basis from 17-8-1970 to 30-9-1970 in which capacity he continued in service till 18-1-1971. On 19-1-1971 he was however appointed on a six months probation in the same post vide Ext. M1 memorandum of appointment. While so, on 10-7-1971 his service was terminated vide Ext. W-4 order dated 10-7-1971. It reads:
  - "It has been decided by the Regional Manager's office, Shillong to terminate your services with immediate effect.
  - Your services are accordingly terminated as from the close of business today and you will be paid one month's salary and allowance in lieu of notice."
- 3. The management has relied upon the Bank Award made under Chairmanship of S. Panchapagesa Sastry in 1953, the para 522 (Section IV) of which the relevant portion reads.
  - "The services of a probationer may be terminated by one month's notice or on payment of one month's pay and allowances in lieu of notice."

This clause is superimposed with a condition that in cases not involving disciplinary action for misconduct and subject to clause (6) of para 522, the management's right to terminate the services of the employee can be asserted. Any way the direction in para 522 referred to above had not been deviated from in the subsequent settlements. Parties agree that the action of the management to terminate the services of the workman concerned in this reference is vested in this paragraph.

- 4. The case of the management is that Shri S. Deb was on probation from 19-1-1971 for a period of 6 months and that his services were terminated with effect from 10-7-1971, which was before the expiry of the period of 6 months. So, according to them the management was entitled to terminate his services under the Bank Award and the termination in this case was only a termination simplicitar without any penal action attached to it.
- 5. The workman on the other hand contended that he entered the services of the Bank on 17-8-1970 and he continued in service as such until 10-7-1971 when his services were illegally terminated. The flist question that arises for determination, therefore, is whether the workman was a probationer from 17-8-1970 or from 19-1-1971. The first appointment as per Ext. W-1 order shows that he was appointed on a termporary basis upto 30th September 1970, though he was allowed to continue in that capacity till 18-1-1971. But his appointment under the terms and conditions setforth in Ext. M-1 shows that he was to be on probation for a period of six months from 19-1-1971. Even in the written statement of the workman (paragraph 1) he had admitted that first appointment was on a temporary basis. In his application (Ext. W-6) dated 16-7-71 addressed to the Regional Manager he stated: "I am a new recruit hardly spent six months' probationary period...." In Ext. M-1 dated 19-1-71 he was given directions us to the terms of his new employment. Six months' probationary period was specifically mentioned in it, which was to commence on 19-1-1971. In Ext. M-2 of the same date the workman made a declaration that he was to be made permanent later and that his probationary service was liable to be terminated at any time without stating any reason. Ext. W-3, Ext. W-4 and Ext. W-5 were his declarations to show that his period or probation would have commenced only with effect from 19-1-1971. Ext. W-2 appointment order also indicated that he was appointed as a temporary Godown keeper with effect from 17-8-1970. In his evidence when examined before the Tribunal on 18-2-1977 as WW-1 he stated as follows:
  - "I was apointed as temporary Godown keeper in August 1970. On 19th January 1971 I was appointed probationary Godown keeper."

It was clear from the evidence and all the records kept and maintained in this case that the workman entered the services of the Bank as a Probationer only with effect from 19-1-1971 and his prior service ending with 18-1-1971 was only on a temporary basis without any right to get continuity of service as a permanent incumbent.

- 6. The next question is whether the management is entitled to terminate his services under the provisions of para 522 of the Bank Award referred to above in the circumstances of the case. In case of such termination of services if such order of termination gives rise to an industrial dispute the form of the order is not decissive and therefore the Tribunal which adjudicates the dispute should examine the substance of the matter and decide whether the termination is in fact discharge simplicitar or dismissal though the language of the order is one of simple termination of service. If it is satisfied that the order is punitive or mala fide or is made to victimise the workman or amounts to unfair labour practice, it is competent to set it aside. The test is whether the act of the employer is bona fide. If it is not, and is colourable exercise of the power under the contract of service, or standing orders, the Tribunal can discard it and in a proper case direct reinstatement.
- 7. The instant case is one in which the management had lost faith and confidence in the concerned workman. Long before the workman entered the services of the Bank he was employed under the Sterling General Insurance Co. Limited, Imphal. One Sri Roy was the Secretary of that Insurance Company. Shri P. K. Mitter, who gave the temporary

appointment to Shri Deb as per Ext. W-2 order of appointment on 17-8-70 was the Agent of the State Bank branch at Imphal. There was evidence that Roy, Deb and Mitter colluded to raise fake loans from the State Bank branch at Imphal in the names of fictitious persons. In that tegard there was an enquiry which was conducted by MW-1 who was the Agent of the State Bank at Shillong during the relevant period. Ext M-14 is the report of MW-1 who completed the enquiry. Page 4 of Ext. M-14 deals with the collusion of Shri Deb in the loan transactions. Deb as WW1 admitted his handwriting in the originals of Ext. M-8, M-9 and M-9(a), Ext. M-10, M-10(a) and Ext. M11 and Ext. W-6. These were some demand promissory notes, cheques and application for loans by third pairtes. The workman's connection with the borrowers of the loans was made out even in his Ext. M-11 letter addressed to MW. 1 who conducted the enquiry Shri Mitter was chargesheeted for his alleged partisan complicity in the loan transactions. Ext. M-13 was the chargesheet levelled against him. He was also suspended from colluded to raise fake loans from the State Bank branch sheet levelled against him. He was also suspended from service. One Nibohal Handloom Wallah who got the loan service. One Nibohal Handloom Wallah who got the loan from the bank was found to be a fictitious person. One Maniput Medical Stores were alleged to have received loans, but those loans were never received by them. Their names appeared in the Schedule attached to Ext. M-14 enquiry report. It was in the names of such persons that Shi Deb wrote cheques and promissory notes. His complicity in the loan transactions was amply brought out in the evidence during the enquiry which was conducted by MW-1. It was therefore material for the management to have entertained the view that Shri Deb, who was then an employee of the Bank, acted against the interest of the bank and that it would be suicidal for them to keep him in service. Fxt. M-14 report was dated 23-3-71. Thereafter on 6-7-187t. a report of Deb's complicity in the loan transactions was made to the Regional Manager. Ext. M-15 was that report. On the basis of the recommendations of the Staff Superintenmade to the Regional Manager. Ext. M-15 was that report. On the basis of the recommendations of the Staff Superintendent and Asstt. General Manager, the termination of the service of Deb was decided upon by the Regional Manager vide his order Ext. M-15(d) dated 6-7-1971. It was accordingly that Ext. W-4 order of termination was passed. It was passed the approval of the Regional Manager.

8. The leading case on the point is one reported in Chartered Bank v. Chartered Bank Employees Union, AIR 1960 Supreme Court, 919. It laid down the employer's powers as to the discharge simplicitor and the limitations thereon. The Chief Cashier of the Bank in that case reported acts of disobedience of the Cashier under him and declined to stand surity for him any further in terms of the system in force, which was necessary for holding the post of Cashier Instead of holding enquity and dismiss the cashier by way of punishment for misconduct, the Bank decided to terminate his services. The Supreme Court held even in such a case discharge was permissible if it did not happen to be a colourable exercise of power. The Supreme Court could not the Bank in the circumstances to have acted in colourful exercise of the power as good reasons were found to exist exercise of the power as good reasons were found to exist for it to act. The Supreme Court stated:

"In Buckingham and Carnatic Co. I td. v. Workers of the Company, 1952 Lab. A.C., 490(LATI), the Labour Appellate Tribunal had occasion to consider this matter relating discharge by notice in lieu thereof by payment of wages for a certain period without assigning any reason. It was of opinion that even in a case of this kind the requirement of bonafides is essential and if the termination of service is a colourable exercise of the power or as a result of victimisation or unfair labour practice the industrial tribunal would have the jurisdiction to intervene and set aside such termination. Further the details of services in the delicities of the power of the pow it held that where the termination of service is capricious, arbitrary or unnecessarily harsh on the part of the employer judged by normal standard of reasonable man that may be cogent evidence of victimisation or unfair labour practice. We are of opinion that this correctly lays down the scope of the power of the Tribunal to interfere where service is terminated simplicitar under the provisions of contract, or of standing orders or of some Award like the Bank Award."

9 These rules have been affirmed in Mumgam Mills Itd. v Industrial Tribunal, 1965 Supreme Court, 1496 and in L. Michael v Johnson Pumps Ltd., AIR 1975, Supreme Court,

661. In the case of Workman v Motipur Sugar Factory, AIR 1965 Supreme Court, 1803 it was observed that the employer can justify the dismissal or discharge orders in court, when challenged by leading evidence to support its case even when enquiry held was defective or no enquiry whatsoever was held. The case of discharge and dismissal on the one hand and case of 'no enquiry' or 'defective enquiry' on the other hand, according to the Supreme Court, stood on the same footing. The question of malafides or acting in colourable exercise of power, cannot arise unless allegations set up are unfounded and imaginary and the act is motivated by some ulterior purpose.

10. Nothing of the sort happened in the case on hand. It was not in respect of a misconduct alleged against the workman during the course of his employment that the management lost faith and confidence in the workman. it was in respect of his antecedent conduct long before he joined the Bank service that the bank was compelled to take action against the workman. It was proved without any take action against the workman. It was proved without any shadow of doubt that the workman was directly involved in some loan transactions against the interest of the State Bank of India while he was the employee of the aforesaid Insurance Company. The enquiry of MW-1 tevealed that the workman got himself involved in those transactions and the enquiry officer was convinced that the allegations against the workman was such that his continuance in the employment of the Bank was not in the best interest of the Bank. The Assistant Zonal Manager and the Zonal Manager nad also came to the same conclusion. The complicity of the workman was more or less admitted by him in his Ext. M11 petition addressed to the Enquiry Officer. Having found all the circumstances against the workman it is apparent that the management exercised their right of termination of his the management exercised their right of termination of his services in accordance with law under para 522 of the Bank Award. In case of misconduct, it is open for the employer either to hold enquiry and dismiss the employee by way of punishment or discharge him and pay all legitimate charges. The employer has a choice to adopt either of the cases, provided action is bona fide. The question of mala fides or acting in colourable exercise of power as already pointed out by me, cannot arise unless allegations set up are unfounded and imaginary, and the action is motivated by some ulterior nursose. ulterior purpose.

11. There is nothing in the evidence or in other circum-11. There is nothing in the evidence or in other circumstances of the case that the management had any other motive in terminating the services of the workman. The workman was also not able to allege and prove any case of victimisation or of unfair labour practice. The workman's case was not even taken up by any Union of the establishment for reddressing his alleged grievances. I find that there is no case of mala fide conduct on the part of the Bank in the instant termination. So the termination of the workman's services has to be upheld. I do so.

12. The principles set out in State Bank of India v N. Sundra Money, 1976 (32) Indian Factories and Labour Re-Sundra Money, 1976 (32) Indian Factories and Labour Reports, 197 regarding retranchment compensation cannot be applied to this case since the period of the workman's service did not enure for the period of one year as required by Sec. 25F of the Industrial Disputes Acl, 1947. It cannot therefore be said that the termination is bad on account of the management's failure to comply with the provisions of Sec. 25F of the above Act. I find accordingly that the workman is not entitled to any retrenchment compensation. workman is not entitled to any retrenchment compensation.

13. In the result, I find the termination of service of Sii Sushanta Deb with effect from 10-7-1971 is justified and that he is not entitled to any other relief. The award is made as above.

Dated, Calcutta, E. K. MOIDU, Presiding Officer

The 2nd May, 1977. [F. No. L-12012/67/74-LR. III/D. II. A.]

#### New Delhi, the 13th May, 1977

S.O. .—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Bank of India, Gauhati and their workmen, which was received by the Central Government on the 11-5-1977.

## CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

#### REFERENCE NO. 9 OF 1976

#### PARTIES:

Employers in relation to the Central Bank of India,

#### AND

#### Their Workmen

## APPEARANCE:

On behalf of Employers—Shri S. Sarkar, Laboui Consultant, On behalf of Workmen—Sii P. K. Goswami, Advocate. STATE: Assam INDUSTRY: Banking.

#### **AWARD**

The Government of India, Ministry of Laboui, vide their Order No. L-12012/175/75-DII(A), dated 231d February, 1976, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the Central Bank of India and their workman, to this Tribunal, for adjudication The reference tends:

- "Whether the dismissal from service of Shri Janardan Sarma, Head Cashier, Shillong Branch of the Central Bank of India by the Assistant Zonal Manager of the said Bank, Gauhati is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"
- 2. The Bank and the concerned workman filed written statements raising various contentions.
- 3. This is a case where a domestic enquiry was conducted by the Bank against the workman in respect of his gross negligence resulting in heavy financial loss to the Bank So. as usual the validity of the domestic enquiry was in question and a preliminary enquiry was held hearing both sides. I passed the order dated 1-3-1977 upholding the validity of domestic enquiry. A copy of the order is attached to this award.
- 4 In view of the substainability of the domestic enquity, the next question that arises for consideration in this reference is as to whether the management has brought home the guilt of the workman under para 19(5)(i) of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966 and if so what, if any, is the quantum of punishment to be awarded to the workman taking into consideration all the circumstances of the case.
- 5 Reference had already been made in my previous order that the enquiry officer came to the conclusion that the workman was grossly negligent in the discharge of his duties and responsibilities on the foot of the evidence of two witnesses examined by him during the domestic enquiry. Their evidence established that the workman concerned had been handling the cash primarily in the Cash Section and that the entire responsibility for the loss of the cash rested with him. That evidence is consistent with the Manual of Instructions issued by the Bank in Volume VII. These instructions provide for dual control over Strong Room and Cash Safe. It reads:
  - "Both the strong room door and the cash safe should have double locking system it eas can be opened only by the use of two keys, one each of the two keys of cash safe and of the two keys of the strong-room shall be kept by the Cashier. The second set shall kept by the Agent or In-charge or Accountant. This arrangement of dual control is devised to ensure safety and as a matter of abundant caution".

#### Then it adds.

"Nevertheless, the primary responsibility for all cash and other valuables held in the safe and also for other articles of value which may be kept in cabinets or loose in the strong room will be that of the Cashier"

- 6. In the Bipartite settlement Itself the duties of a Head Cashier are enumerated. This being a A category Bank the duties specified are in Appendix B of the settlement. It states, "that their duties involve holding the bank's cash, keys, and other valuables in safe custody jointly with an officer and being accountable for them and being responsible for the running of the Cash Department."
- 7 The special responsibility entrusted with the Head Cashier cannot be ignored even if there has been joint responsibility of the Head Cashier with the Agent or the Accountant for handling the keys of the Sting room and Cash Safe. In this regard reference has been made to a passage occurring in the Manual of Instruction. That passage reads.

"Cash should be carefully checked at the close of every day by the Agent or the Accountant or by a Senior Official not connected with the Cash Department and the daily Cash Balance Book of Memo Book should bear the signature in full of the checking officer to certify the correctness of the same."

This rule of the Manual does not in any manner reduce the responsibility of the Head Cashier in the matter of handling cash on hand. It is the Head Cashier who has to take out eash from the Cash safe for day to day use and he will be in touch with the entire quantity of the cash in the safe. In another place of the Manual it is observed, "Bundles of notes when being taken out of the Safes for use, as also when being placed back in the Safe having not been utilised for the day's transactions, should be checked. Their correctness as to the amount, should not be taken for granted on the presumption that the bundles appear to be in tact. Without such checking, it is possible that any clever pilfering of notes from the bundles will be undetected for a long time." The underline is that of mine. This is really what happened in the instant case. When the Head Cashier takes out and puts back the bundles of notes he has a primary duty to see that those Bundles are intact. The surprise check by the Internal Auditor on 25-8-1971 revealed that out of one thousand Government currency notes of the denomination of Rs. 100 bound in a bundle of 10 packets of Rs. 100 each, only 183 pieces were genuine and the balance of 817 were replaced by pieces of plain white paper accurately and suitably cut out to the size of Government currency notes of the same denomination. On account of the malpiactice and fraud practised the Bank sustained a loss of Rs. 81,700. If the Head Cashier primarily had bestowed some care—and caution as to the bundles of notes kept in the Cash Safe the Bank would not have sustained the loss.

- 8 Having established the huge loss of the Bank's cash out of the Cash Safe by the evidence adduced and other encumstances brought out in the case the irresistable conclusion is that the Head Cashier is primarily responsible for the loss.
- 9 The charge under para 19 5(j) of the Settlement is proved against the Head cashier beyond a reasonable doubt and he is found to be guilty of the charge of gross misconduct due to his gross negligence. I have gone through the evidence carefully and heard the argument of the learned Counsel of the workman as a result of which I am convinced and satisfied that the only just and proper punishment to be meted out to the workman in this case is one of dismissal from service. The management has exercised its discretion in the punishment is called for in the circumstances of the case. Taking into consideration all the circumstances of the case, I hold that the dismissal from service of Shi Janardan Sarma, Head Cashier. Shillong Branch of the Central Bank of India is justified. Therefore he is not entitled to any relief

An award is passed accordingly.

F. K MOIDU, Preskling Officer

Dated, Calcutta, The 30th April, 1977

## CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

#### Reference No. 9 of 1976

PARTIES:

Employers in relation to the Central Bank of India,

AND

Their Workmen

APPEARANCE:

On behalf of Employers.—Sri S. Sarkar, Labour Consultant.
On behalf of Workmen.—Sri P. K. Goswami, Advocate.

#### AWARD

The preliminary enquiry under the Reference dated 23-2-76 arises on account of the dismissal of Shri Janardan Sarma from the service of the Central Bank of India on the strength of the Order of dismissal dated 14-3-1975 (Ext. M-14) passed by the Assistant Zonal Manager, Gauhati after a domestic enquiry conducted against the said Janardan Sarma for his gross negligence resulting in financial loss to the concerned Bank to the tune of Rs. 81,700. Janardan Sarma was the Head Cashier of the Shillong Branch, Central Bank of India, While so, the Internal Auditor of the Bank one Sundara Raman visited the Shillong Branch on 15-8-1971 for inspection. On his direction Janardan Sarma and S. K. Guha, the Accountant of the Branch opened the Strong Room. The Cash Safe with the duplicate key which each of them had in their custody and the Internal Auditor checked the cash on hand in the Cash Safe in their presence. While checking the cash it was found that out of one thousand pieces of the Government currency notes of the denomination of Rs. 100 bound in a bundle of 10 packets of hundred pieces each, only 183 pieces were genuine and the remaining 817 were replaced by pieces of plain white paper accurately and suitably cut out to the size of the Government currency notes of the same denomination. The Internal Auditor found that on account of the malpractice and fraud practised by the Head Cashier who was the sole Cashier of the brauch the bank sustained a loss of Rs. 81,700. A report of the loss was sent to the Calcutta office immediately and police was also contacted. The police took Janardan Sarma into custody on the same day. Ext. M-5 dated 26-8-71 is the report of the Internal Auditor adressed to the Calcutta office. On 21-10-1971 vide Ext. M-7 Janardan Sarma was suspended from service.

2. Ext, M-8 show cause notice was sent to him to explain his conduct regarding the loss of bank's money, Ext, M-8 was issued on 17-5-1973. Exts, M-3, M-9 and M-11 were the replies which Janardan Sarma sent on each occasion alleging that parallel domestic enquiry shall not be held against him until the criminal case came to an end. However, the management issued Ext. M-1 charge sheet against the workman on 1-6-1974. The charges were (1) that he misappropriated an amount of Rs. 81,700 and (2) that he committed acts amounting to gross negligence which resulted in loss caused to the Bank or likely to be caused. Janardan Sarma did not give a satisfactory reply to the charges. Hence the management deputed S. M. Basu, Superintendent Calcutta Zonal office as enquiry officer. Ext. M-15 is his order of appointment as enquiry officer. Enquiry was conducted on the 14th and 15th of June, 1974. Ext. M-2 and Ext. M-4 were the enquiry proceedings. Janardan Sarma was present throughout the enquiry proceeding. He signed at every page of the proceedings, but he refused to cross-examine witnesses of the management and also failed to produce his evidence in defence. All the documents were produced and marked in his presence. He did not raise any objection either in the examination of witness or making the documents which were proved against him. The only ground alleged by the workman concerned that the domestic enquiry was invalid when a police case was pending had been found against him by the enquiry officer. PW-1 is the concerned enquiry officer. He proved that a proper and fair enquiry had been conducted against Janardan Sarma in his presence. S. K. Guha, the

Accountant and Mahendra Chandra Das were the two witnesses examined by PW-1 doing the domestic enquiry. At enquiry stage PW-1 asked the workman whether he wanted to cross-examine any of the management witnesses Janardan Sarma refused to cross-examine them. He had nothing to say against the enquiry. His only grievance was that the enquiry officer should have stayed the enquiry pending the disposal of the criminal case. On completion of the enquiry PW-1 prepared his report and finding. Ext. M-12 is the finding arrived at by PW-1 against the workman that he was guilty of gross negligence resulting financial loss to the bank to the tune of Rs. 81,700.

- 3. Cf the two charges levelled against the workman under Ext. M-1 chargesheet, the first charge of misappropriation was dropped during the enquiry and the enquiry officer concentrated on charge No. 2 which deals with the gross-misconduct of the workman resulting financial loss to the Bank. PW-1 had even in the beginning of the enquiry had informed the workman that he would enquire into charge No. 2 only. PW-1 found Janardan Sarma guilty under clause (j) of para 19.5 Chapter XIX of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966 and PW-1 recommended his dismissal from service under para 19.6(a) of the same Settlement. Therefore Ext. M-13 show cause notice was issued to him on 12-12-1974 directing him to appear to make his representation, if any, of the question of his dismissal from service. Since there was no response from the workman, the Asstt. Zonal Manager issued Ext. M-14 dismissal order on 14-3-1975.
- 4. We have to consider at this stage whether the enquiry is invalid on account of the management's alleged failure to tollow the principles of natural justice in the conduct of the domestic enquiry or the enquiry proceedings held in that connection or in any other manner on account of the failure to follow and Statute, Rules or law applicable to the case. Before considering the points urged on behalf of the workman it is necessary to answer the argument of the learned Advocate of the management. His argument is that the Central Bank of India being a nationalised Bank is a Corporation whose rules and regulations have force of law, thereby the employees getting a statutory status and as such the Statutory bodies are authorities within the meaning of Article 12 of the Indian Constitution. Therefore the employees have no remedy to move this Tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 since their remedy, if any, is to be found within the rules and regulations made by the Bank. And hence it is contended that the reference itself is invalid. In support of this contention reliance is placed upon the decision reported in Sukhdev Singh & others v. Bhagaram Sardar Singh Raghuwanshi & Another, 1975 Supreme Court Labour Judgement (Volume 12), page 48. That decision has no application to the facts of the present case. The beneficial social remedy provided for in the Industrial Disputes Act, 1947 is unaffected by the Rules and Regulations made by the Corporate Body. An industrial dispute is outside the purview of the rules and regulations so far as the benefits conferred upon the employees and employers. The fact that a Banking Company is included in the categories of institution under Sec. 2(a) (i) of the Industrial Disputes Act, 1947 is a circumstance to show that the appropriate Government has the right under Sec. 10 of the Act to refer any industrial dispute beween workmen and their employers to the concerned Industrial Tribunal for adjudication. I find that right has not been taken away on account of the Rules and R
- 5. The next point to be considered is whether it was obligatory on the part of the management to stay the proceeding of the disciplinary action on account of the misappropriation part of the workman's guilt which was sent to the police for investigation. It was true that the police arrested the workman on 25-8-1971 when the cash was found missing from the bank's safe. He was also released on bail in due course. But the police did not file any chargesheet against the workman. There was no criminal trial pending before any court when the domestic enquiry was held and completed. It was pointed out now at the hearing that he police had filed a chargesheet against the workman. That was not very material for he purpose of this case. Para 19.4 of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966 governs the case. The management was therefore correct in continuing with the domestic enquiry. The workman was not correct in his conduct in

refusing to participate in the enquiry. He was given every belp and assistance in defending the case. However, he was present throughout the enquiry proceeding and he had affixed his signature at every page of the enquiry proceedings regarding the fair and proper conduct of the enquiry. The contention of the workman that he did not get proper hearing therefore cannot be entertained.

- 6. It is relevant to point out that the enquiry was not conducted on the main question as to the misappropriation of bank funds. The charge on misappropriation was dropped by PW-1 when he started the enquiry. The charge was confined to para 19.5 (j) of the Bipartite Settlement, which provides that "doing any act prejudicial to the interest of the bank or gross negligence or negligence involving or likely to involve the Bank in serious loss". This forms charge No. 2 in the chargesheet levelled against the workman. It is designated as "gross misconduct" in para 19.5 of the Bipartite settlement. So the workman could not have contended before the enquiry officer that the enquiry shall be stayed. I find no substance in this argument.
- 7. It is then contended that the PW-1, who conducted the domestic enquiry had no jurisdiction to conduct the enquiry as he had not been properly appointed to conduct the enquiry. Para 19.14 of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966 provides for the appointment of enquiry officers. In this case there cannot be any dispute that Shri S. N. Basu is one of the officers appointed by the Chairman for the purpose. Ext. M-16 notice at page 8 specified the name of Shri Basu as an enquiry officer. That appointment by itself is sufficient to comply with the provisions of para 19.14 of the Settlement, His authority to enquire into the misconduct is also established by Ext. M-15 letter as well as by Ext. M-17 message. PW-1 has mentioned about Ext. M-17 message in his evidence. Taking into consideration the effect of Fxts, M-15, 16 and 17 together with the evidence of PW-1, it was established beyond dispute that the appointment of the enquiry officer was truely and validly made.
- 8. During the course of the domestic enquiry PW-1 suggested that he might make a local inspection of the spot in the branch where the occurence took place. But he did not make any such local inspection, much less he made any reference to it in the enquiry report upon which his finding was based. The learned Counsel of the workman argued that the PW-1 having made a suggestion for local inspection he should have made such inspection or at least he shall be deemed to have made it without giving an opportunity to the workman to put forward his case. I do not think the learned counsel could build up a case on assumptions MW-1 had declared categorically that he never made a local inspection. WW-1 workman had no case in his evidence—that MW-1 made any such local inspection. In the absence of any reference in the enquiry report regarding the local inspection the fact of a suggestion by MW-1 during the domestic enquiry that he would make a local inspection could not in any manner prejudice the workman. I find that this point of argument of the learned Counsel cannot be accepted.
- 9. MW-1 relied upon Ext. M-6 alleged admission of the workman in his enquiry report as an additional circumstance that he was guilty of the charge. The workman disputed the truth of Ex. M-6 admission on the ground that it was taken while he was in police custody. First of all Fxt. M-6 admission does not relate to the specific charge for which he was found guilty by the enquiry officer Secondly MW-1 came to the conclusion of the workman's guilt not on the admission (Fxt M-6) alone on the other hand he depended upon oral evidence of two witnesses as well as the entries in the books of account and registers. So the conclusion arrived at by the enquiry officer that the workman is guilty of the charge cannot be brushed aside as it was not based upon Ext M-6 alone. Any way, he emphasized the fact in his report that the evidence of the two witnesses he examined before him was sufficient to hold that the workman was entity of the charge. So even Fxt M-6 is excluded from the evidence there was sufficient material before MW-1 to hold the workman guilty of the charge. This point also is found against the workman.
- 10 The workman never raised any dispute before the enquiry officer when Ext M-5 was produced by the Presenting Officer and marked in the proceeding against him Ext M-5 is the report of the Internal Auditor which he prepared

on 25-8-71 at the Shillong branch of the bank in the presence of the workman himself. The Strong room and the Safe were opened by the workman in the presence of the Internal Auditor and thereafter be checked the cash. It was then he prepared Ext. M-5. The facts alleged in Ext. M-5 were within the special knowledge of the workman. Those facts were fully set forth in the show cause notice, Fxt. M-8 dated 17-5-73 which was sent to the workman before the charge was framed against him. On receipt of Ext. M-8 the workman sent a teply to it, Ext. M-9, dated 30-5-1973. But he never disputed the facts set out in Fxt. M-8, much less he gave any contrary version of the case. It was clear that the workman was not prejudiced at all on the enquiry officer admitting Ext. M-5 in evidence during the domestic enquiry. The workman did not raise any objection to it at any time. So, I cannot find that any prejudice had been cause to the workman on this account. The objection on this account is over-ruled.

- 11. It is admitted that the Assistant Zonal Manager passed Ext. M-14 order of dismissal. It was based upon the finding arrived at by MW-1 that the workman is guilty of the charge. The conclusion by the Zonal Manager that the workman shall be dismissed could not be disputed. He was the proper authority to pass the order of dismissal. He had accepted the finding of the enquiry officer. It cannot be said that he did not apply his mind to the facts of the case before the order of dismissal was passed. I find no invalidity or other defect in the order of dismissal.
- 12. The last question to be considered is whether the finding by the enquiry officer against is founded on evidence or whether the conclusion arrived at is preverse. The enquiry officer had based upon the evidence of the two witnesses examined before him. They were the Accountant and the Cash Peon, who were directly concerned with the Strong room and the Cash Safe along with the concerned workman. Enquiry officer had accepted their evidence. It has to be admitted that the workman being the Head Cashier of the Shillong branch was equally liable to account for the loss of a huge sum of money out of the Safe kept in the Strong room. Evidently he was to operate upon the Cash Safe just as the Accountant or Agent. The workman, however, could not throw the whole blame on either the Accountant or the Agent and say he is not guilty of any charge. The evidence of the two witnesses examined on the management side proved that the workman dealt with the Cash kept in the Safe during the relevant period. That evidence would be sufficient to hold the workman to be guilty of a charge under para 19(5)(j) of the Bipartite Settlement, Negligence involving or likely to involve the bank in serious loss is a gross misconduct under para 19(5) (i) of the above settlement. I find that the conclusion was based on evidence and it cannot be said to be perverse.
- 13. In the result, I find that the domestic enquity is not vitiated on any of the grounds alleged by th workman. So the domestice enquiry is found valid and binding on the workman.

The reference will be posted to be heard on 19th April, 1977 at the next Gauhati sitting of the Tribunal under Sec. 11A of the Industrial Disputes Act, 1947.

Dated, Calcutta,

The 1st March, 1977

[F. No. L-12012/175/75-D. II. A.]

R. P. NARULA, Under Secv.

## नर्र दिस्ली. 2 मई, 1977

का० आ० 1528 — भारतीय डाक श्रमिक विनियमन, 1948 के विनियम 26 के अनुमरण में और भारत सरकार के श्रम मनालय की श्रीधसूचना संख्या का० श्रा० 1598, तारीख 15 ग्रश्रैंस, 1971 का श्रीधकमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार कारखान। सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, श्राफ ईस्टर्न एक्सप्रैंस हाईवे, सायन, बस्बई-22(डी० डी०) के उप महानिवेशक को उक्त विनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी के रूप मे मनोतीन करती है।

[संख्या एम०-17013/1/27-फैंक्ट]

धै । चन्द्र भौली , निदेशक

## New Delhi, the 2nd May, 1977

S.O. 1528.—In pursuance of regulation 26 of the Indian Dock Labourers Regulations, 1948, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1598 dated the 5th April, 1971, the Central Government hereby nominates the Deputy Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Off Eastern Express Highway, Sion, Bombay-22(DD) as the authority for the purposes of the said regulations.

[No. S-17013/1/77-FAC.]
V. CHANDRA MOWI I, Director

#### नर्ड दिल्ली, 2 मर्ड, 1977

का० आ० 1529 — केन्द्रीय संग्कार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना ध्रपेक्षित था, ख्रौद्रोगिक विदाद श्रिविनयम, 1917 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक के उपखण्डों के धनुसरण में भारत संग्कार के श्रम मंत्रालय की श्रिधसूचना संख्या का० धा० 4536 तारीख 11 तबस्वर, 1976 द्वारा किसी तेल क्षेत्र में सेवा को उक्त ध्रिवियम के प्रयोजनों के लिए 22 तबस्वर, 1976 में छः मास की कालाविध के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

श्रीर केन्द्रीय गरकार की राय है कि उक्त कालावधि को श्रागे छ माम की कालावधि के लिए बढाया जाना लोक हिस में श्रोधित है;

श्रत, श्रव, श्रीसोगिक विवाद श्रीधनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ह) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक हारा प्रवच्च श्रीसियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को 22 मई, 1977 में धार्य छ माम की कालाविध के लिए लोक उपयोगी मेवा द्योदित करनी है।

[संख्या एस-11017/4/77-की-1 (ए)] एस०के० नारायणन, टेस्क श्राधिकारी

## New Delhi, the 2nd May, 1977

S.O. 1529 —Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section (2) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of I abour No. S.O. 4536 dated the 11th November, 1976, the service in any oil field to be a public utility service for the

purposes of the said Act, for a period of six months from the 22nd November, 1976;

And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period for six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 22nd May, 1977.

[No. S. 11017/4/77/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer.

## New Delhi, the 6th May, 1977

S.O. 1530.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th April, 1977.

BEFORF THIRU T. N. SINGARAVELU, B A.B.I.,

#### Presiding Officer

Industrial Tribunal, Madras.

(Constituted by the Central Government)

## Industrial Dispute No. 19 of 1977

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between a workman and the Management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem).

#### **BETWEFN**

Thirumathi Kumarayee, Pambankaradu, Vellakkalapatti P.O., Omalur Taluk, Salem Distric

#### AND

The Works Manager, Dalmia Magnesite Corporation P.B. No. 508, Salem-12.

#### REFERENCE

Order No. I-29011/40/76 DIHB, dated 27-2-1977 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for hearing, upon perusing the reference, and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal, T. S. Gopalan and P. Ibrahim Kaifulla, Advocates for the Management and the worker being absent, this Tribunal made the following.

#### AWARD

This is an Industrial Dispute between the Management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem and its worker in respect of the matter specified in the Schedule to the reference. This reference was made by the Covernment of India in its Order No. L-29011/40 76 DIIIB, dated 27th February, 1977 of the Ministry of Labour for adjudication.

## (2) The issue reads as follows:

Whether the action of the Management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem is justified in dismissing Smi. Kumarayee, Creche Mazdoor with effect from 4-5-1976 as a result of the findings of the domestic enquity proceedings? If not, to what benefits she is entitled?

- (3) Notice of the hearing of the dispute was personally served on the worker on 23-5-1977 and she was absent on the date of the hearing on 28-3-1977. However, the Tribunal adjourned the matter suo motto to 11-4-1977. The Management was represented by learned counsel Mr. T. S. Gopalan, On the adjourned date on 11-4-1977, the worker was again absent on 11-4-1977 and there was no representation. The Management was present and the matter posted for disposal on 12-4-1977.
- (4) Learned counsel for the Management produced the documents on his side and they were exhibited as Ext. M-1 to M-10. I have perused the same and heard learned connected for the Management. According to the Management, the worker Smt. Kumarayee was a Creche Mazdoor in charge of the children of the women employees coming for work. It is stated that she disobeyed the orders of the superiors in refusing to wash soiled clothes of the children. Fx. M-1 discloses the duties of the delinquent, and obviously. refusing to wash soiled clothes of the children. Fx. M-1 discloses the duties of the delinquent, and obviously, cleaning of clothes was one of the duties assigned to her. According to the Management, the delinquent refused to wash the clothes of the children on two occasions on 27-3-1976 and 31-3-1976 and she disobeyed the orders of the superiors. Thereupon, the Management gave a show cause notice under Ex. M-2. The delinquent gave an explanation on 1-4-1976 under Ex. M-3 denying the refusal. The Management was not satisfied with the explanation and therefore constituted a domestic enquiry and she participated in the enquiry. Witnesses were examined by the Enquiry Officer and the worker was given opportunity to cross-examine the witnesses. On the evidence, the Enquiry Officer came to a conclusion that she was guilty of misconduct-vide Fx. M-6.
- (5) The Management accepted the report of the Enquiry Officer and gave a second notice Ex, M-7 to the worker indicating the proposed punishment. Ex. M-8 was the reply by the worker Smt. Kumarayee and the Management took into consideration the explanation as well as the past conduct of the worker and it exercised its discretion to dismiss her from service. Ex. M-9 is the order of dismissal.
- (6) I have perused the records and I am satisfied that the delinquent had every opportunity to defend herself in the domestic enquiry. There is no irregularity or defect in the domestic enquiry nor are the findings perverse. It appears from the previous records, viz., Ex. M-10 that this was not the first occasion that the delinquent disobeyed the orders of the superiors and Ex. M-10 discloses that she has been warned for disobedience on seven previous occasions from 1973 to 1976. Therefore I see no ground to interfere with the order of the Management in dismissing her from service. As stated earlier, the delinquent herself (6) I have perused the records and I am satisfied that her from service. As stated earlier, the delinquent herself has not chosen to contest this case and left this matter to proceed ex-parte. For all these reasons, I hold that the delinquent-worker is not entitled to any relief. Consequently the claim is negatived. An award is passed in these terms. No costs.

12th April, 1977

THIRU T. N. SINGARAVELU.

Presiding Officer

## WITNESSES EXAMINED

For both sides: Nil.

## DOCUMEN'IS MARKED

For worker: Nil.

## For Management:

- Ex. M-1-List of duties of Creche Mazdeor.
- Ex. M-2/31-3-76—Charge sheet issued to Thirumathi R. Kumarayee.
- Ex. M-3/1-4-76-Explanation of Thirumathi R. Kumarayee to Ex. M-2,
- Ex. M-4/7-4-76—Notice of enquiry issued to Thiru R. Kumarayee.
- Ex. M-5/8-4-76—Enquiry Proceedings.

- Ex. M-6/9-4-76—Findings of the Enquiry Officer.
- Ex. M-7/14-4-76—2nd Show Cause Notice proposing the punishment of dismissal,
- Ex. M-8/17-4-76—Reply by Thirumathi R. Kumarayee to Fx. M-7.
- Ex. M-9/3-5-76—Dismissal order issued to Thirumathi R. Kumarayee,
- Ex. M-10—Disciplinary Action Chart relating to Thirumathi R. Kumarayce,

Note: Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the Award.

THIRU, T. N. SINGARAVELU, Presiding Officer

[No. L-29011/40/76-D IIIB]

V. VELAYUDHAN, Under Secv.

S.O. 1531.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bastacolla Colliery of Bharat Coking Coal Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd April, 1977.

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

## Reference No. 6 of 1976

(Ministry's Order No. L-20012/70/76/DIIIA, dt. 21-10-1976)

#### PARTIES:

Employers in relation to the management of Bastacolla Colliery of Bharat Coking Coal Limited, Post Office Dhansar, Dist. Dhanbad

#### AND

Their Workmen.

## APPEARANCES:

For the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate,

Shankar Bose, Secretary, For the Workmen-Shri Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE: Bibar. INDUSTRY: Coal.

#### AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal, namely :-

- "Whether the action of the management of Bastacolla Colliery, Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad in refusing to make the following casual Wagon Loaders as regular/Permanent is justified? If not, to what relief is each workman entitled and from which date?
- 1. Shri Lakhan Nonia
- 2. Shri Jagdish Nonia II
- 3. Smt. Sukeri Kamin

25 GI/77---25

- 4. Shri Mahendra Nonia-I
- 5. Smt. Fulmatia Kamin
- 6. Shri Dillu Ram
- 7. Shri Kamta Dusad
- 8. Shri Sita Dusadh
- 9. Shri Bineshwar Dusadh
- 10. Shri Bhichan Dusadh
- 11. Shri Nunu Jadav
- 12. Shri Ram Rachiya Chamar
- 13. Shri Chandrika Dusadh
- 14. Shri Ram Kishun Dusadh
- 15. Shri Ram Dutta Jadav
- 16. Shri Shiv Dutt Jadav
- 17. Shri Prahlad Dusadh
- 18. Shri Kailash Dusadh
- 19. Shri Deobrat Dhobi
- 20. Shri Rajendra Prasad
- 21. Shri Jagdish Nonla
- 22. Smt. Jirwa Kamin
- 23. Smt. Lakshpatia Kamin
- 24. Shri Mahendra Nonia-II
- 25. Smt. Piyaria Kamin
- 26. Shri Bishu Mahato
- 27. Shri Brahmadeo Dusadh
- 28. Smt. Parwatia Kamin
- 29. Shri Deonarayan Mahato
- 30. Shri Ramastray Jadav
- 31. Smt. Rajpatia Kamin
- 32. Shri Mahadeo Passi
- 33. Shri Jawahir Bhuiya
- 34. Shri Ramratan Bhuiya
- 35. Shri Bandhan Dusadh 36. Shri Ram Bilash Nonia-II
- 37. Shri Babulal Bhuiya
- 38. Shri Somar Dusadh
- 39. Shri Ayodhya Dusadh
- 40. Shri Shyamlal Bhuiya
- 41. Smt. Methi Kamin
- 42. Smt. Kunti Kamin
- 43. Smt. Bhabiya Kamin
- 44. Shri Jagrup Nonia
- 45. Smt. Somarin Bai
- 46. Shri Bisheshwar Kahar
- 47. Smt. Jalwa Kamin
- 48. Shri Mohan Turi
- 49. Shri Bandhau Chamar
- 50. Shri Jagdish Bhuiya
- 51. Shri Mangar Turi."
- 2. The Organising Secretary, Rashtriya Colliery Mardoor Sangh, in the written statement on behalf of the involved workmen, has pleaded that these 51 workmen are in the employment of the Bastacolla Colliery, as Wagon Loaders, for a large number of years from before nationalisation and they have continued on their jobs even after that; that the job of wagon loading is of a permanent nature; and since these 51 workers have been working on the job of a permanent nature for a large number of years, therefore, they should no longer be allowed to remain as casual loaders and should straightaway be made permanent wagon loaders. The Bharat Coking Coal Ltd., on the other hand, has pleaded that transport, marketing and allied operations in the coal mining industry have been constantly fluctuating because of erractic placement of wagons at coal mines, Railway sidings and also because of unstable market demand for different kinds of coal; that, in view of the above factors, Tribunals and Wage Boards have recommended the formation of a nucleus of permanent wagon loaders on the basis of average requirement and work-load and have left it to the discretion of the management to fix the permanent and casual strength of wagon loaders on the basis of permanent and casual strength of wagon loaders on the basis of permanent and casual need; that before nationalisation

the work of wagon loading used to be handled by contractors; that after nationalisation, the Bharat Coking Coal Limited abolished the contract system and absorbed the wagon loaders in a casual pool, as all of them could not be absorbed against permanent posts because the wagon loaders were surplus to requirements; that it (Bharat Coking Coal Limited), as a matter of its industrial relations policy, did not retrench the surplus wagon loaders to avoid inevitable hardship; that even the permanent wagon loaders are surplus to requirements and have to be given alternative jobs of truck-loading, soft-coke making, stacking, screening and other allied operations, to keep them busy; that the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh raised an industrial dispute that these 51 casual wagon loaders should be made permanent because many of them had put more than 240 days of work in the years 1974 and 1975; that it (Bharat Coking Coal Limited) could not accept this demand because of its grave repercussions throughout the coal mining industry in asmuchas casual workmen on jobs other than wagon loading would also have claimed similar concession; that acceptance of the demand of these 51 workers would have inflated the labour strength on the permanent roll which already had a surplus strength; that there would have been no option left to it (Bharat Coking Coal Limited) except to resort to retrenchment, as the way out of the trouble; that even the casual wagon loaders enjoy all the fringe benefits available to permanent wagon loaders except that of lay-off compensation; and that there is no statute or contract of service or rule or regulation which makes it obligatory on its part to make all the casual wagon loaders as permanent wagon loaders.

- 3. In the rejoinder to the written statement of Bharat Coking Coal Limited, the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh has introduced the plea that refusal to make these 51 permanent amounts to unfair labour practice.
- 4. Originally, Bastacolla, Victory, Liberty and Chandmari were four distinct and separate collieries. Chandmari was merged in the Bastacolla Colliery after nationalisation; and subsequently, Victory and Liberty collieries were also merged in the Bastacolla Colliery; so that there is now only one big colliery in place of four small collieries.
- 5. MW-1 Abhoy Kumar Srivastava, Assistant Manager of the Bastacolla Colliery has deposed that wagon loading is a work of casual nature and not of permanent nature. I regret I cannot accept this evidence. Coal-raising is a continuous process in a mine; and indeed, coal is raised in three shifts. No coal mine can allow the excavated coal to accumulate at its pit-heads. The coal has to be sold to various industries, railways and sundry consumers. This necessarily involves despatch of coal from pit-heads to various destinations. The despatch is made either in Rly. wagons or boves or in trucks. Like, the raising of coal, its loading and transport, therefore, is of a permanent nature.
- 6. A casual workman may be engaged either for work of a casual nature or for work of a permanent nature. The distinction between a permanent workman engaged on work of a permanent nature and a casual workman engaged on work of a permanent nature is in the fact that a casual workman is engaged to fill in a casual need of extra hands for permanent jobs.
- 7. Dealing with wagon loaders, the Coal Wage Board, in paragraph 52 of Chapter VIII, Vol. I of its report has not given the ratio of permunent wagon loaders vis-a-vis casual wagon loaders, but has given the work load and has stated that a wagon of 22 tonnes can be loaded by 5 wagon loaders, i.e., the norm of work load is 4.40 tonnes per wagon loader. The Joint Bi-Partite Wage Negotiating Committee has given the work load of wagon loading, as also of truck loading, as 4.5 tonnes per wagon loader. MW-1 Abhoy Kumar Srivastava has also deposed that a four-wheeled wagon with 22 tonnes capacity requires 5 wagon loaders and an eight-wheeler box of 45 tonnes capacity requires 12 wagon loaders for the purpose of loading; and a truck requires 3 wagon loaders. His evidence was not controverted by WW-1 Ram Dutt Yadav, one of the workmen involved in this reference. There is no reason, therefore, not to accept the evidence that 5 wagon loaders can load a four-wheeler, 12 an eight-wheeler and 3 a truck. This will give an idea as to the strength required for wagon/truck loading in the Bastacolla Colliery.

MW-1 Abhoy Kumar Srivastava deposed that the average number of wagons placed at the various railway sidings of the colliery, was 13 per day and the average number of trucks used was 20 per day

His evidence was not controverted by WW-1 Ram Dutt Yadav

However, I will prefer nature than oral evidence Ext M 1 is a Chart showing the placement of wagons/boxes at the various railway sidings during the period July 1, 1976 to December 31, 1976. The total number of wagons placed during the aforesaid period was 1732 and the total number of boxes placed was 753. The total number 1732 comprises 708 placed at the Bastacolla Sidang, 821 place at the Victory Siding and 203 placed at the Liberty Siding The figure 753 comprises 278 at the Bastacolla, 412 at the Victory and 63 at the Liberty Siding Ext M-7 is another Chart for the period January 1, 1975 to June 30, 1975 but it relates exclusively to the Victory siding. A total number of 1134 wagging and 440 bayes was placed at the Victory. of 1134 wagons and 440 boxes was placed at the Victory Siding during this period. The management did not file the Chart in respect of Bastacolla and Liberty sidings for the period January 1, 1975 to June 30, 1975 Abhoy Kumai Srivastava has admitted that the demand for coal was slack in 1976 and, therefore, it is not safe to rely wholly on Ext M-I to find out the actual position. It is because of this that I have taken into consideration Ext. M-7 also which is in respect of a period when the demand for coal was not slack but average If I compare the figures for Victory siding for the aforesaid two periods of times, it will be apparent that for a period of six months the total of 821 wagons had increased to 1134 and the total number of boxes had increased from 412 to 440. There was an increase of 39 per cent in respect of wagons and 7 per cent in respect of boxes. I will, therefore, apply the same ratio of increase to Bastacolla and Liberty sidings. By doing that the total number of wagons at Bastacolla would come to 1689 and the total number of boxes would come to 576. Likewise, the total number of wagons for Liberty would come to 484 and the total number of boxes would come to 131. It is true that these two periods of six months lie in two consecutive years but that will make no practical difference in calculating the average. The total number of wagons for Bastacolla for 12 months come to 1689, for Victory to 1955 and If I compare the figures for Victory siding calculating the average. The total number of wagons for Basta colla for 12 months come to 1689, for Victory to 1955 and for Liberty to 484, i.e., a grand total of 4128. The total number of boxes for 12 months for Bastacolla is 576, for Victory 852 and for Liberty 131, giving a grand total of 1559. The wagon, as has been seen above, requires 5 wagon loaders and thus the man-power needed to load 4128 wagons are 20640. The box requires 12 wagon leading to loaders and thus the man-power needed to load 4128 wagons comes to 20640. The box requires 12 wagon loaders to load it and, therefore, 1559 boxes would require a man-power of 18708. The evidence shows that 7,200 trucks require loading in a year. A truck is loaded by 3 wagon loaders and the man-power required to load 7200 trucks would be 21600. The total man-power comes to 60948 in one year; 5079 in one month, and 170 per day.

9 Ext M-2 has been filed by the management to prove the total number of permanent wagon/truck loaders. It shows that there are 270 permanent wagon loaders and 34 permanent truck loaders with a total of 304. However, a scrutiny of Ext. M-2 will show that the strength of 304 includes 39 coal stacking mazdoors, who are on the jobs of coal stacking and at times of wagon loading, 26 are Bhatta Mazdoors who either do the job of coal stacking or of soft coke making, and 35 are truck loading mazdoors who exclusively work as truck loaders. If we exclude these 3 cate gories of 39+26+35, the total number of permanent wagon loaders comes to 204. Abhoy Kumar Srivastava has stated that the total number of permanent wagon loaders is 205 instead of 204 but that hardly makes any difference. Fxt M-3 shows the strength of casual wagon loaders as 244+48=292. Thus, there are 204 or 205 permanent wagon loaders and 292 casual wagon loaders. The 51 workmen involved in this reference are within the 292.

10 The next question is as to what should be the proper ratio between permanent and casual strength. On the one hand, two factors should enter into the consideration of an industry in keeping a large number of workmen as casual, namely, (a) the apprehension of industrial unrest and (b) frustration caused to workman by remaining casual for a large number of years. On the other hand, it is well-estab-

lished that it is within the managerial discretion of an employer to organise and arrange his business in the manner he considers best. So long that is done bonafide it as not competent for a Tribunal to question its propriety. The management, therefore, has a right to determine the volume of its labour force, consistent with its business or anticipated business, and its organisation. If organisation of the business of the employer results in surplus age of employees, no employer can be expected to carry the burden of such economic dead-weight and he must and should have the liberty to keep a number of permanent employees to cope with the permanent need and a number of casual employees when extra hands are required to meet a special or casual need. It has been seen above that there is work only for 170 wagon loaders daily while the Bharat Coking Coal Ltd has a permanent labour force of this category reaching upto 204 or 205, 1e, about 30 wagon loaders are surplus even in the permanent strength. In addition, we have 292 casual wagon leaders. The Bharat Coking Coal Ltd. could easily have retrenched them but that would have been very unpalatable. That is the reason why when these 292 are required for wagon loading or truck loading, they do that job, and when they are not required for the said jobs, they stack coal or screen coal, or make soft coke, or work in any other allied operations, and when no work at all is available, they remain idle and are not paid wages. In respect of other fringe benefits, they are at par with the permanent hands. They only predicament is that when they are laid off, they are not paid lay-off compensation. The problem of de-casualisation of wagon loaders had been engaging the attention of Coal Wage Boards. Wagon leading being an irregular job, a majority of them have to remain casual and work on the basic of no work, no pay. It is a matter which should be looked into at the highest level by Coal India Ltd. or its subsidiaries. So far as the Tribunal is concerned, when there is a necess

10 My award is that the action of the management of Bastacolla Colliery in refusing to make these 51 casual Wagon Loaders as regular/Permanent is justified; and they are not entitled to any relief

Dhanbad,

19th April, 1977

K B SRIVASTAVA Presiding Officer.
[No 1,-20012/70/76 DHIA]
S H S IYER, Desk Officer.

New Delhi the 7th May, 1977

SO. 1532—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Fast Basuriva Colliery of Messrs Bharat Coking Coal I imited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th April, 1977

# BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

## Reference No. 21 of 1977

(Ministry's Order No L-20012/185/74/LRII/DIIIA, Dt. 16-7-75)

## PARTIES:

I mployers in relation to the management of East Basuriya Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, Dist Dhanbad.

AND

Then Workmen

## APPEARANCES:

For the Employers.—Shri K. C. Nandkeolyar, Senior Personnel Officer.

For the Workmen.—Shri B. Joshi, Advocate, and, Shri D. Mukherjee, Advocate.

STATE: Bihar

INDUSTRY: Coal.

## AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act referred the following dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No 2. Dhanbad by their adjudication Order No. L-20012/185/74/LRII/DIIIA, dated, the 16th July, 1975, namely:—

"Whether the management of East Basuriya Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusnda, District Dhanbad, are justified in stopping the under-mentioned workmen from their work with effect from 18th May, 1973? If not, to what relief are the sald workmen entitled?

#### Sl. No. Name.

- 1. Shri Bahadur Kurml
- 2. " Ramanand Singh
- 3. " Yotindra Kumar Sood
- 4. " Surendra Kumar Choubey
- 5. " C. K. Kacha
- 6. " Santosh Kr. Das
- 7. "Sitaram Singh
- 8. "Suresh Mallah
- 9. " Suresh Rewant
- 10., Rajendra Singh
- 11. " Suresb Rajak
- 12. " Sahabudin Mia
- 13. " Kashi Napit
- 14. " Ramjee Bhuia
- 15. "Sukhdeo Bhuia
- 16. "Somar Mahato
- 17. " Maheshwar Kumar
- 18. " Dilip Rewani
- 19. " Nepal Rajak
- 20. "Sukhu Mahato
- 21. " Bhubaneshwar Rewani
- 22. , Chalitar Shaw
- 23. " Jai Kishore Singh
- 24. ., Bisun Ram."
- 2. The same was received by transfer in, this Tribunal on March 18, 1977 vide Government of India, Ministry of Labour. Order No. S-11025(1)/77(i)-D. iv(B) dated the 22nd February, 1977.
- 3. The case of these 24 workmen, as disclosed in the written statement filed by the Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union on their behalf, is that they were workman in the East Basuriya Colliery for periods ranging from 3 to 4 years as permanent workmen; that when the management of non-coking coal mines was taken over by the Bharat Coking Coal Ltd. and a Screening Committee was appointed to screen the cases of suspected inductees, no representative of the Union was coopted as a member of the Committee and no formal enquiry was made by that Committee and no opportunity was given to the suspected inductees to show whether they were inductees or bona fide workmen; that the Bharat Coking Coal Ltd. nevertheless stopped these 24 workmen from working in the East Basuriya Colliery without any enquiry, and without any chargesheet, and without assigning any reason; that these 24 workmen were members of Coal Mines Provident Fund; that they were also members of Coal Mines Bonus Scheme and were paid bonus; that Bharat Coking Coal Ltd. was biassed

against the Bihar Colliery Kamgar Union; that it was also prejudiced against these 24 workmen on account of their active participation in trade union activities; that the action on the part of the Bharat Coking Coal Ltd. in stopping them from work was mala fide and the result of victimisation; that the act of stopping was in violation of the Certified Standing Orders applicable to the colliery and also of the provisions of the Coal Mines (Nationalisation) Act; that they are entitled to be reinstated with effect from May 18, 1973 with continuity of service and full back wages.

- 4. The Bharat Coking Coal Ltd., in its written statement, has averred that it took over the management of East Basuriya Colliery on January 31, 1973 under the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973; that before the date of take over, a substantial portion of the colliery operations was being performed by contractors; that when coking coal mines had been taken over on October 17, 1971, it was experienced that the previous owners and contractors and trade union leaders and interested employees had entered into a conspiracy and in pursuance of that had inducted a large number of persons as workmen even though they were not workmen; that, in view of that experience, the Bharat Coking Coal Ltd. appointed a Screening Committee to detect cases of induction and the Screening Committee found that there were 287 inductees in the East Basturiya Colliery; that this screening was done by a Tri-partite Advisory Committee which included representatives of trade unions; that the cases of the 287 workmen aforesaid, including the 24 workmen involved in this reference, were referred to the Area Advisory Committee for individual scrutiny and it was found by the Committee, after the examination of various documents, that 212 out of 287, including these 24 workmen, were inductees and were not bonafide workmen; that Form H Return indicated that Bahadur Kurmi was appointed on January 1, 1973 but allegedly commenced work in the week ending January 13, 1973; that Rama Nand Singh was shown as appointed on January 1, 1973 but he allegedly commenced work in the week ending January 27, 1973; that the date of appointment of Yatindra Kumar Sood, Surendra Kumar Choubey, C. K. Kacha, Santosh Kumar Das, Sitaram Singh and Suresh Maliah was show as January 8, 1973 but they allegedly commenced work in the week ending January 27, 1973; that the date of appointment of Suresh Rawani, Rajendra Singh, Suresh Rajak, Shahabuddin Mian, Kashi Napit, Ramjee Bhuia, Sukhdeo Bhuia and Somar Mahato was shown as January 15, 1973 but they and Somar Mahato was shown as January 15, 1973 but they allegedly commenced work in the week ending January 27, 1973; that the date of appointment of Maheshwar Kumar, Dilip Rewani, Nepal Rajak, Suku Mahato, Bhubneswar Rawani, Chalitar Shaw, Jai Kishore Singh and Bisua Ram was shown as January 16, 1973 but they allegedly commenced work in the week ending January 27, 1973 with the excention of Maheswar Kumar who allegedly commenced work in the week ending February 3, 1973; that salary or wages had not been paid to any of these 24 workmen because the paysheets were still under preparation on January 31, 1973 when the management of the colliery was taken over; that since the wage-sheets had not been prepared, there was consince the wage-sheets had not been prepared, there was considerable scope for he conspirators to insert the names of inductees and to manipulate their attendance in connected registers; that the management had to stop these 24 workmen from working in the mine with effect from May 18, 1973 when it was confirmed that they were inductees; that the Standing Orders or the Coal Mines (Nationalisation) Act will have no application in the case of inductees because they apply to persons who are really workmen; and that the Bharat Coking Coal Ltd. acted in a bonafide manner in stopping these 24 persons who are really workmen. ing these 24 persons from working and their action is justi-
- 5. The Union filed a rejoinder to the written statement of the Bharat Coking Coal Limited. In the rejoinder, pleas already taken have been reiterated and it has been alleged that the previous owners indulged in mal-practices inasmuchas they did not maintain proper records and inasmuchas they were maintaining double records; and that these 24 had become premanent workmen by completing three months of continuous service by the force of the Standing Orders and they could not have, therefore, being stopped from working in a arbitrary manner.
- 6. The Bharat Coking Coal Limited has examined M. K. Singh, Rup Narain Mahato and K. C. Nandkeolvar, MWs. 1, 2 and 3 to prove that these 24 workmen were inductees pure

and simple. The evidence in rebuttal was given by Rama Nand Singh and Sahabuddin Mian WW-1 and WW-2. Besides, both parties have placed reliance upon certain documents. It is on the basis of this oral and documentary evidence, that the matter has to be decided.

7. It is a matter of common experience of Tribunals, of which even judicial notice can be taken, that there was a scramble for employment by fair means and foul whenever a situation arose where a private undertaking was taken over for management or was nationalised. The impending taking over of management or nationalisation gave an impetus to unscrupulous owners, trade union leaders and eager seekers of job to combine and to induct new hands by manipulating records. It was usually done to accommodate a relative or a friend or their dependents. The manipulators had no-thing at stake. The undertaking would no longer continue to vest in the previous owner and would vest either in the Central Government or in a Government company and the liability to pay remuneration to the inductees would full on the Central Government or on the Government company There were cases, and there is evidence even in the present case, that just on the eve of taking over of management advance increments were allowed to some favourites ranging upto three increments. The spectacle of induction faced the authorities at the time when coking coal mines were taken over for management on October 17, 1971 and were nationalised on May 1, 1972. A similar situation arose when the non-coking coal mines were taken over for management on January 31, 1973 and were subsequently nationalised on May 1, 1973. The Government company had, therefore to an The Government company had, therefore, to appoint Hying Squads and Screening Committees to take stock of the situation and to find out which workman was a bona fide workman and which an inductee. In the process of screening, some mistakes did creep in when some bona fide workmen were treated as inductees or inductes were heated as bona fide workmen. Industrial disputes arose, and in each case the Tribunal had to come to a conclusion whether a particular workman was a bona fide workman or an inductee. Evidence has been given in the present case also to show that there was induction. K. C. Nandkeolvar MW-3 was the Senior Personnel Officer, Headquarters. He and B. N. Jha, Personnel Officer were deputed to screen the workmen in the East Basuriya Colliery in accordance with the procedure laid down by J. G. Kumarmanglam, the Custodian General. He has deposed that the Screening Committee and the Flying Squad were constituted by C. S. Iha, the Additional Custodian General. He has further deposed that the All India Radio had broadcast a news on January 30, 1973 itself that management of non-coking coal mines would be taken over on January 31, 1973 on the basis of an ordinance. He has further stated that the East Basuriya Colliery had three inclines and five quarries. Incline Zero was being directly worked by the previous owner and the other two inclines and all the five quarries were being operated by various contractors. He has then stated that wagesheets for the month of January, 1973 had not been prepared by the previous owner and thus there was scope to insert new names in the wage-sheets and also in attendance registers. There was even serious trouble between rival unions with regard to induction, and in-fighting resulted in three deaths, An attempt was made by the Custodian to scize all the documents of the colliery but several were not available and only such of them could be sized as readily came to notice. The screening was done on the basis of the scized books and on the basis of the siege of the mine, the production per day, and the hands required to produce the given quantity In this connection, he has referred to Ext M-2 and M-3 which me reports submitted by him soon after taking over of the management. His evidence remained unshaken It is true that he has no personal knowledge whether these 24 workmen were bona fide workmen or inductees but he was not examined on that aspect. He was posted at the Headquarters and not in Fast Basuriya Colliery and the purpose of his evidence was to prove that induction was a menace and a possibility which required screening. Ext. M-1 is a Chart prepared on the basis of the Register Form H and this shows that these 24 workmen were employed between January 1, 1973 to January 16, 1973. This, if correct, will show that their names could have been entered any time in Register B because the wage sheets were not ready even upto January 31, 1973.

8. I shall now look into the evidence given by the workmen WW-1 is Ramanand Singh whose name is mentioned at serial 25 GI/77—26

No. 2 in the Schedule to the reference. He has deposed that he joined the East Basuriya Colliery on June 23, 1972 as a Cap Lamp Issue Clerk. His leatned counsel urged that his name appears at serial No. 1384 in register Form B, Ext. W-2. That entry relates to one Shamapada Singh. His designation is given as Cap Lamp Attendant and the date of appointment is June 13, 1972. Now, ordinarily Ramanand Singh cannot be Shamapada Singh. He has, however, stated that he has read upto Class VII and his name entered in the school register is Shamapada Singh but he is known both as Shamapada Singh and as Ramanand Singh. I am not prepared to believe it. Ordinarily, one enters service by registering himself in the name which is given in his school certificate and does not change his name, unless there is some good and cogent reason. He has not cared to file the certified copy of the school register to show that he was really named as Shamapada Singh. There is a column in Register B which requires father's name to be given but that column in respect of Shamapada Singh has been left blank. He is shown as Cap Lamp Attendant but he has deposed that he was actually appointed as Cap Lamp Issue Clerk. His sworn tecumony is that he got appointment on June 23, but Ext. W-2 shows that he was actually appointed on June 13 and not on June 23. He says that he was a member of the Coal Mines Provident Fund Scheme but admits that no contribution was ever deducted from his salary towards that fund. He further says that he was a member of Coal Mines Bonus Scheme and used to be paid bonus, but the bonus register was also not called. Ext. W-6 is an appointment letter dated January 20, 1972 which mentions that Shamapada Singh (Ramanand Singh) was interviewed on June 14, 1972 and, as a result of that interview he was offered the post of Cap Lamp Incharge. that interview he was offered the post of Cap Lamp incharge. This also furnishes tell-tale evidence of mystery regarding his appointment. Register Form B Ext. W-2 mentions him as Cap Lamp Attendant; he described himself in evidence as Cap Lamp Issue Clerk, and the appointment letter offers the post of Cap Lamp Incharge. Again, when the interview itself took place on June 14, 1972 he could not have taken his appointment on June 13, as mentioned in Ext W-2. He has signed Ext. W-2 not as Ramanand Singh but as S. P. Singh. The appointment letter gives no number although it is com-The appointment letter gives no number although it is com-The appointment letter gives no number although it is common for an official letter to bear a number. Ext. W-9 is a letter dated August 5, 1972 signed by D. S. Kang, the then Manager, which mentions that on his inspection of the Cap Lamp Room on August 5, 1972 he had found 35 lamps lying in the room and not at their proper place in the rack and gave a warning to Ramanand Singh to avoid such negligence in future. Ext. W-13 dated January 1, 1973 is a general certificate given by D. S. Kang to Ramanand Singh which mentions that the latter had been working in the colliery as Cap Lamp Issue Clerk from June 23, 1972 and he was honest and hard working. It is not denied that D. S. Kang rither and hard working. It is not denied that D. S. Kang either resigned or was removed by Bharat Coking Coal Ltd. on April 2, 1973. It appears to me that Ramanand Singh was an inductee and that is the reason why there is no certainty about his name, designation and date of appointment which all differ from time to time. It further appears to me that the documents referred to above were forged subsequently by D. S. Kang to give support to Ramanand Singh. There was no point in giving a general certificate on January 1, 1973 while Ramanand Singh was still working in the colliery. Shahabuddin Mian WW-2 deposed that he joined the colliery as a Prop. Mazdoor on December 2, 1972 and was a member of the Coal Mines Provident Fund Scheme. He admits that he was not given any appointment letter; that he has no Bonus Card; that he does not know if his attendance was marked in Register B, C, D or E; that he further does not know if any amount was defucted from his salary towards the Coal Mines Provident Fund Scheme; and that he has no document to them that he was a marker of such a Scheme? to show that he was a member of such a Scheme. His name appears at serial No. 3221 in the Register Form B Fxt. W-1 but he is shown not as Prop-Mazdoor but as Timber Mistry. His father's name and even address is not given which is a must under the statue. In the circumstances, therefore, I am not prepared to believe his evidence. The other 22 workmen did not enter the witness box to give their service history. Fxt. W-5 is an appointment letter dated November 19, 1972 in respect of Chandra Kant Kacha whose name appears at serial No. 5 in the schedule to the reference. The letter mentions that he was interviewed on November 12, 1972 and was offered the appointment as Electric Helper. This letter also bears no official number. Ext. W-16 is a Bonus Card in his respect but it does not bear the Colliery seal or any other official seal. Ext. W-7 is a letter of appointment dated November 1, 1972 in respect of Yatindra Kumar Sood whose

name appears at serial No. 3 in the schedule to the reference. The letter mentions that he was appointed as Cap Lamp Incharge on purely temporary basis with an allowance of Rs. 150 per month. This letter also bears no official number Ext. W-10 is a letter dated January 5, 1973 inviting his attention to the fact that the maintenance of the Cap Lamp Room was no up-to-date. Ext. W-12 is a letter dated April 17, 1972 which is a general certificate mentioning that he had been working as Cap Lamp Fitter since February, 1972 and was still continuing. It is obvious that these documents are forged. Ext. W-7 shows that he was appointed as Cap Lamp Incharge and Ext. W-12 mentions him as Cap Lamp Fitter. Ext. W-7 would show that he was appointed sometime in November 1972 but Ext. W-12 mentions his appointment since February 16, 1972. Ext. W-14 is a Bonus Card but it bears no colliery seal or any official seal. Ext. W-17 is an inspection note made by the Service Engineer on May 11, 1973. No attempt was made to examine the Service Engineer. Ext. W-4 is Register Form B which mentions Y. K. Sood at Serial No. 2590 as Tub Checker since November 24, 1972. I am not satisfied in his case also that he was a boua fide workman. Ext. W-8 is an appointment letter dated December 4, 1972 without any official number. It mentions that Surendra Kumar Choubey had been interviewed on November 28, 1972 and was appointed as Cap Lamp Fitter. Ext. W-11 is a letter dated January 27, 1973 which shows that he was found sleeping on duty in the 3rd shift at about 4 p.m. on January 22, 1973. Ext. W-15 is the Bonus Card in his respect without

the colliery scal or any other scal. The Register Form B Ext. W-2 shows his date of appointment as January 13, 1972. Here again, there is a difference in the date of appointment. The names of Bahadur Kurmi, and Santosh Kumar Das appear in Registes Form B Ext. W-2 and those of Nepal Rajak and Bisun Ram in Register Form B Ext. W-1. There is no other evidence. All told, I am satisfied that all the 24 workmen were inductees and not bona fide workmen. The Certified Standing Orders apply to workmen and not to intare not. The Bharat Coking Coal Limited was under the statutory obligation to employ those who were in employment immediately before May 1, 1973 but this obligation attaches in respect of genuine workmen and not inductees. The Bharat Coking Coal Ltd. was, therefore, not bound to give any notice or reason for asking them to stop work.

9. My award is that the management of East Basuriya Colliery were justified in stopping these 24 workmen from their work with effect from May 18, 1973 and they are not entitled to any relief.

Dhanbad 21st April, 1977.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
 [No. L-20012/185/74-LRII/D III Λ]
 S. H. S. IYER, Desk Officer